

भारत में राजनीति

रजनी कौठारी

सदर पार द स्टडी

प्राफ डेवतपिंग सासाइटीज

अनुवादक

अशोकजी

(मपादक स्वातंत्र्य भारत वलनज)



ओरिएण्ट लॉगमैन

ओरिएण्ट लांगमैन लिमिटेड

रजिस्टर्ड कार्यालय ३/१, आसफ अली रोड, नयी दिल्ली १

१७, चित्तरजन एवेन्यू, कलकत्ता १३

निकल रोड बैलाड एस्टेट, बम्बई १

३६ ए मारुण्ट राड मद्रास २

बी २/७ आसफ अली रोड, नयी दिल्ली १

भारत में मुद्रित

मुजित पटवधन, सगम प्रेस लि, १७ वायफ्ट पूना २६

द्वारा मुद्रित और बा ह पटवधन मनेजर ओरिएण्ट लांगमैन लि
बी ३/७, आसफ अली राड नयी दिल्ली १ द्वारा प्रकाशित

रावजी भाई सी पटेल को
प्रेरणा के स्रोत और आलोचक

भारतीय राजनीति

मूल अंग्रेजी पुस्तक इण्डियन पॉलिटिक्स सन १९६८-६९ में लिखी गई थी। तब से भारतीय राजनीति में बहुत से नये अनुभव हुए हैं। इन अनुभवों से अधिकतर इस पुस्तक की सामान्य स्थापनाओं की पुष्टि ही हुई, जैसे राजनीति की स्वतंत्र सत्ता, भारतीय समाज में परिवर्तन लाने में शासन की सत्रिय भूमिका, भारतीय राजनीति की अपनी अलग शैली, जो पश्चिमी ढांचे के वगहिता के समुच्चयीकरण और आर्थिक शक्तियों की सावभौमता के मार्क्सवादी ढांचे, दोनों से भिन्न है, इसके सांस्थानिक विश्लेषण की जिसमें एक दल की प्रधानता को मुख्य स्थान है, देश में आनेवाले सकटों की चुनौती से राजनीति और शासन की कार्यप्रणाली में होने वाले बड़े परिवर्तन, लोकतांत्रिक पद्धति और राज्य की मुख्य नीतियों की सफलता के बारे में आशावादी दृष्टिकोण। यह ही पुस्तक की मुख्य स्थापनाएँ हैं।

भारत में इधर जो घटनाएँ हुई हैं इनसे भारतीय राजनीति की ये स्थायी विशेषताएँ और उदभासित हुई हैं। यदि १९६७ के आम चुनाव से इन विशेषताओं के बारे में कुछ नकाएँ उत्पन्न भी हुई थी, तो इन नई घटनाओं से उनका निराकरण हुआ है। इस पुस्तक में देश की व्यवस्था के जिन बुनियादी तत्वों का निरूपण किया गया था उनको बल मिला है, देश में आत्मविश्वास बढ़ा है तथा आगे जो काम करना है उनके प्रति अधिक चेतना और जिम्मेदारी का भाव आया है। यह भी ध्यान देने की बात है कि हाल में देश के नेतृत्व और नीतियों में जो परिवर्तन हुआ है वह कांग्रेस के प्रभाव में कमी होने से नहीं बल्कि उसकी अपने रंग ढंग को बदलने की क्षमता के कारण हुआ है, जिस पर इस पुस्तक में काफी विस्तार से विचार किया गया है।

साथ ही इन नयी घटनाओं के कारण इस पुस्तक में जिन बातों पर जोर दिया गया था और जो व्याख्याएँ की गई थी, उन में थोड़ा संशोधन भी करना पड़ेगा। जैसे कांग्रेस दल में जो सकट १९६८ में शुरू हुआ और १९७२ में समाप्त हुआ, उस से १९६२ में चीन के आक्रमण और नेहरू के दहात के बाद लाकतांत्रिक

पद्धति में जो सिपिलता आ गई थी, वह और भी उजागर हो जाती है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि पूरा एक दायें तरफ देना एक सहजिये के रूप में काम नहीं कर रहा था, यद्यपि इसी अवधि में गेती में कुछ बड़ी उपलब्धियाँ हुईं, देश की सुरक्षा-व्यवस्था मजबूत हुई और भाषा-समस्या के समाधान में प्रगति हुई। इस पुस्तक के दो और विवरणों में भी संशोधन आवश्यक है। एक नेहरू और सात महादुर शास्त्री के उत्तराधिकारी के चुनाव और दूसरे १९६३ में शमराज योजना के बाद उदित प्रादेशिक नताशा व गुट या समूह के बारे में। अब यह स्पष्ट हो गया है कि यद्यपि दोनों बार नए नेता के मुख्यस्थित उग से चुनाव से यह घना दूर हो गई कि नेहरू के बाद क्या होगा, किंतु जिस प्रकार सहमति की प्रक्रिया द्वारा य दोनों चुनाव हुए उनसे सर्वोच्च स्तर पर सत्ता के लिए ऐसा संप्रतिष्ठित किया गया, जिससे राष्ट्रीय मत्ता की अस्थिरता और दुर्गति का एक सम्बन्ध दोर भी गुरु हो गया। इसका अंत तभी हुआ जब इन्दिरा गांधी ने संप्रतिष्ठित और सफट मोल से कर केन्द्र और बायस के शासन रण की प्रधानता को पुन स्थापित किया।

इस दोहरी प्रक्रिया में भारत की अंतराष्ट्रीय स्थिति में नाटकीय परिवर्तन आया और यह प्रकट हो गया कि देश की आंतरिक शक्ति का उसकी बाहरी या अन्तराष्ट्रीय क्षमता से बिना घना सम्बन्ध है। इस पुस्तक के दसवें अध्याय में इस सम्बन्ध का विश्लेषण किया गया है किंतु इस में कुछ कमियाँ और अस्पष्टता रह गई हैं। अब से भारत के नेता लगातार ऐसी नीतियों के निर्धारण में लगे रहेंगे जिस से देश की स्वतन्त्रता सुरक्षित रहे, वह नई चुनौतियों का सामना कर सकें और अंतराष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका अदा कर सकें।

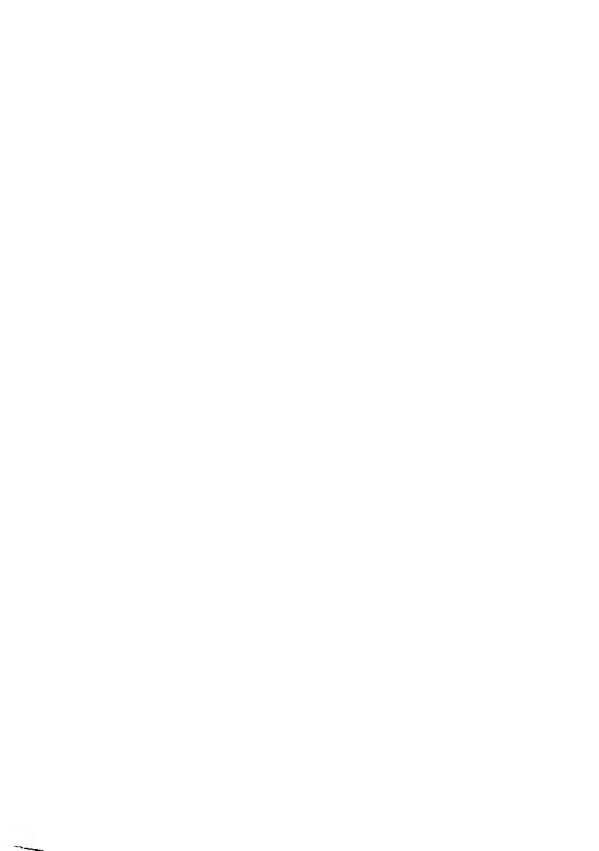
अंत में यह प्रश्न है कि व्यवस्था किस प्रकार काम करती है। इस विषय पर काफी विस्तार से (अध्याय ८ से ११) विचार किया गया है। वस्तुतः इसमें मुख्य चान यही है कि राजनीतिक प्रक्रिया के सफर सस्थानीकरण और सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में इसकी अपवाद्युत विफलता के कारण एक विराघाभाव या जतर पना हो गया है और यह समस्या अब बहुत तीव्र हो उठी है। देश के सामने जो विकट समस्याएँ उपस्थित हुई हैं उनको सुलझा सतने में भारत की लोकतन्त्री व्यवस्था कहा तक सफल होती है इसी पर इस व्यवस्था का और देश का भविष्य निर्भर है। मूल पुस्तक का यही मुख्य सदेश और स्थापना थी, परन्तु अब इसने ऐसा निश्चित रूप ग्रहण कर लिया है, जो पुस्तक के अंतिम अध्याय में निरूपित निष्कर्षों से आगे चला जाता है।

परन्तु पुस्तक की मुख्य स्थापना अभी भी कायम है और पिछली घटनाओं से उसकी और पुष्टि हुई है। स्थापना यह है कि राज्य और राष्ट्र के निर्माण का जो लोकतन्त्री ढांचा भारत ने निश्चित किया है वह सफल हो सकता है और इतिहास में एक उदाहरण कायम कर सकता है, वगैरें भारत के नेतृत्व ने जिस

पद्धति का स्वयं निर्माण किया है, उसकी वास्तविक गतिशील प्रकृति को वह समझे और उसी के अनुसार कार्य करे। सन १९६६ में जब मूल अंग्रेजी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उसके मुकाबल आज सन १९७२ में जब इसका हिंदी संस्करण निकल रहा है दश इस परीक्षा में सफल होने की कहीं अच्छी स्थिति में है। इसी प्रकार यदि यह विफल हुआ तो हम से ऐसी प्रवृत्तियाँ का जन्म होगा, जिनको सभालना कठिन होगा। इस सीमा तक इस पुस्तक में कुछ प्रश्नों पर जो सदिग्ध रख लिया गया था, उसकी बजाय भारत में लोकतन्त्र की परिणति या फलश्रुति को और स्पष्टता से समझना पड़ेगा।

इस पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण की जिन आलोचनाओं ने ध्यानपूर्वक समीक्षा की है, सावजनिक और विद्यालयों के जिन लोगों ने उपयोगी विचार प्रकट किए हैं और राजनीतिशास्त्र तथा अन्य विषयों के अध्यापकों ने इस कठिन पुस्तक का, जो पाठ्यक्रम में लगाने के लिए नहीं लिखी गई थी, अध्यापन में जो उपयोग किया है उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। इही अध्यापक मित्रों के प्रोत्साहन से इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद हो सका है। इस अनुवाद की व्यवस्था कराने में आरिएण्ट ब्लैकमैन के श्री बा. ह. पटवर्धन ने विशेष रुचि ली है और मेरे सहयोगी डा. रामाश्रय राय ने इसको ध्यान से देखा है, जिस से अनुवाद मूल के अनुरूप हो सके, मैं इन दोनों मित्रों का आभारी हूँ।

रजनी कोठारी



अनुक्रम

अध्याय	पृष्ठांक
१ सैद्धान्तिक विवेचन	१
२ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	१७
३ आधुनिकता की ओर	५८
४ समस्या-निर्माण	७४
५ पार्टीप्रणाली और गठजोड़	१०८
६ सामाजिक ढांचा	१४३
७ राजनतिक संस्कार और सामाजिककरण	१७१
८ राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण और राष्ट्रीय एकात्मता	२००
९ विकास की राजनीतिमूलक अर्थनीति	२३०
१० अंतरराष्ट्रीय स्थिति	२५५
११ भविष्य	२७८

सैद्धान्तिक विवेचन

यदि आधुनिकीकरण हमारे युग की मुख्य प्रवृत्ति है, तो राजनैतिकीकरण इसकी संचालक शक्ति है, और इस शक्ति पर मनुष्य अभी अधिकार नहीं कर पाया है, क्योंकि एक हद तक वह अभी भी दबिथानसी विचारा से अपना पल्ला नहीं छुड़ा सका है। १७ और १८ वीं शताब्दी में मनुष्य के सामने मुख्य चुनौतियाँ थी, प्रकृति की शक्तियाँ पर अधिकार और यामिक कट्टरता की और १९ वीं शताब्दी में जनसंख्या के और आर्थिक प्रवृत्तियों के नियंत्रण की। हमारे समय में मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है सरकार और राजनीति के फैलते हुए क्षेत्र को। राजनीति की कला और विज्ञान पर अधिकार के द्वारा ही मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। यह समस्या राजनीति या समाजशास्त्रियों की ही नहीं, सब श्रेणी के नेताओं और जनमत के निर्माताओं की भी है।

राजनीति की प्रक्रिया का सबंध अनेक वर्गों और समूहों से है—राजनैतिक दल और चुनाव तंत्र, जनमत के विविध माध्यम (प्रेस, रेडियो आदि), गैर सांप्रदायिक और सांप्रदायिक विभिन्न हिता के समूह, बुद्धिजीवियों तथा सफेदपंथा व्यवसायों और सरकारी नौकरों का बढ़ता हुआ वर्ग। आधुनिकता की प्रक्रिया से ये सब वर्ग प्रभावित होते हैं, और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, आकांक्षा और अवसर में जो अंतर है उसका ये अनुभव करते हैं, व्यवस्था से इस आकांक्षाओं की पूर्ति की मांग करते हैं और इस प्रकार उसकी क्षमता और कुशलता की परीक्षा करते हैं।

राजनैतिक विकास का सदर्भ

नये राष्ट्रों का पद पाने वाली पुरानी सभ्यताओं के विकास या परिवर्तन की प्रक्रिया बड़ी व्यापक, दूरगामी और विषम है। सामाजिक परंपरा और परिवर्तन जय उग्रवादिता में विरोधाभास से हम अनस्थिर स्थिति में स्थिरता का भ्रम नहीं करना चाहिए। मूल बात सामाजिक पुरानी रीति-नीति नहीं बल्कि परिवर्तन की विचारवारा का प्रभाव है। समाज का पुराना ढाँचा, जाति और कबीले की व्यवस्था

थोड़े समय के लिए उपयोगी हो सकती है (भारत में वे हैं भी) परन्तु अंत में उनको परिवर्तन की शक्तियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। जिन नए विचारों, सिद्धांतों और नयी समस्याओं को नए राष्ट्र में विद्या के द्वारा स्थापित किया गया है, उनमें फलिताय को स्पष्ट रूप से समझना और स्वीकारना होगा। तो देश पर परिवर्तन की योजना बनाने वालों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है क्या उन्हें इनके लिए समय मिलेगा? राजनैतिक और आर्थिक विकास का बाध एत दिना का नग्न है। इसमें समय लगता है और आवश्यक नहीं कि यह सीधे रास्ते पर चले और उत्तरोत्तर बढ़ना चने। दूसरी ओर नये मूल्यों और आनाझात्रों का प्रसार एक बार शुरू होने पर बड़ी तेजी से होता है और उस पर बाहरी वाता का प्रभाव पड़ता है। इस कारण आयुर्विचारण करने वाले सब नये राष्ट्रों के सामने स्थिरता और जन समर्थन की समस्या खड़ी होती है। वही अस्थिरता और उदल-मुड़न अधिक होती है वही कम।^१

स्थिरता या अस्थिरता इस पर निर्भर होती है कि राज्यनयन या व्यवस्था को क्या काम करना है और समाज की विभिन्न उपव्यवस्थाओं या वर्गों से उसका क्या संबंध रहता है। मुख्यतः दो प्रकार की व्यवस्थाएँ हो सकती हैं—एक अतिवेदित, जिसमें सारे अधिकार केन्द्रीय तैत्त्व के हाथ में रहते हैं, दूसरी अनेकारम्भ और साझेदारी वाली जिसमें अधिकार बँटे रहते हैं और मध्यम व निचले स्तर के नेताओं को भी अधिकार में भाग मिलता है। पर अपन गृह रूप में दोनों व्यवस्थाएँ क्या नहीं पायी जाती।

मुख्य समस्या यह है कि भारत जैसी अपसावृत सुली राजनैतिक व्यवस्थाओं को ऐसी काम उठाने पड़त है, जिनसे 'उन्नत' राज्यव्यवस्थाएँ भी हिचकिचाती हैं, जबकि इनके पास वे आर्थिक, प्रौद्योगिक और प्रशासनिक साधन नहीं हैं जो उन्नत देशों के पास होते हैं। गौर पश्चिमी राष्ट्रों ने पश्चिमी राष्ट्रों के आदर्शों और सामाजिक आकांक्षाओं को अपना लिया है, लेकिन पश्चिमी राष्ट्रों की तरह इनका पहले अपनी राजनैतिक व्यवस्थाओं को जमा लेने और आर्थिक और प्रौद्योगिक साधनों का निर्माण कर लेने का समय नहीं मिला। इस दृष्टि से ससार के सिमटने से इन देशों को कठिनाई हुई है, क्योंकि उन्नत देशों के संपर्क के कारण उनको इनकी सामाजिक, राजनैतिक विचार सरणियाँ अपनानी पड़ी हैं, जबकि उसी के अनुसार स्थिर और सुसंगत परिवर्तन के लिए भौतिक और संस्थागत साधन इनके पास नहीं हैं।

भारत में इस समस्या को स्पष्टतः देखा जा सकता है। यहाँ इतिहास के लंबे क्रम में ऐसे सामाजिक, धार्मिक आंदोलन हुए, जिनसे एक विविध भारतीय परंपरा

१ यहाँ हम अस्थिरता या उलझने का अर्थ है जो आकांक्षाओं का पूर्ति न होने से पैदा होती है परिवर्तन के विरोध या उसकी प्रतिक्रिया से नहीं। यद्यपि ये दोनों ही बातें साथ साथ भी चल सकती हैं।

का निर्माण हुआ, जिसने यहाँ फूट और पूराना की अतर्निहित प्रवृत्तियाँ पर अंकुश रखा। राजनैतिक स्थिरता की जुजी सामाजिक व्यवस्था थी। अब यह सामाजिक व्यवस्था विगड़ित हो रही है और बदल रही है। नेतृत्व के सामने यह समस्या है कि यदि टूटती हुई सामाजिक संस्थाओं की जगह नयी संस्थाएँ नहीं स्थापित की गयीं, नए व्यवस्था नहीं प्रस्तुत किये गये और नयी भावनाओं और मूल्यों की स्थापना नहीं की गयी तो राजनैतिक विकास के अवरोध होने के साथ-साथ राजनैतिक व्यवस्था के टूटने की नींव भी पक्की है। इस स्थिति में प्रशासन तंत्र और नई संस्थाओं के निर्माण की ओर ध्यान देना पड़ता है और इनके बिना व्यवस्था का टिकना पड़ता है।

भारत जो स्वतन्त्र राष्ट्र के राजनीति विकास का अर्थ यह होता है कि एक प्राचीन देश अपनी पुरानी परंपराओं और विविधता को बनाये रखता हुआ, आधुनिक युग की सब से अच्छी बातों का ग्रहण करने की राशि करता है। इस प्रकार भारत ने आधुनिक युग से जो कतरे के आदान-आग्रह किया है और इसके निष्पत्तीय स्तर में लेकर राष्ट्रीय स्तर तक गम्भीर स्थापित की हैं तथा पिछने का देश का स वह इसका मतलब अपनी पुरानी परंपरा से बिछाने का मतलब कर रहा है। स्वतंत्र राष्ट्र के महान नेताओं की पहली पीढ़ी अब समाप्त हो चुकी है और नयी पीढ़ी का उनसे विरासत में एक आर अग्रणी मुद्दा राज्यतंत्र और स्वीकृत लक्ष्य व आदर्श मिले हैं, तो दूसरी ओर न तो उसे मान्य है कि आवश्यक समस्याओं का सुलझाने के लिए इस राज्यतंत्र का उपयोग किम प्रकार किया जाए न ही उसमें इतनी शक्ति है। इस नए नेतृत्व में माओ या स्टालिन जैसी संघर्ष की दृढ़ता और क्रूरता से आगे बढ़ने की ताकत नहीं है, दूसरी ओर उसे बुद्धिवादी विचारधारा में अभी पूरी आस्था नहीं हुई है न वह निश्चय कर पाया है कि भारत का राजनीतिक लक्ष्य क्या हो, जिसमें सबका भला हो। भारतीय समाज का स्वरूप भी अभी तक गैर राजनीतिक है। इस स्थिति में यह नेतृत्व आंतरिक और वैदेशिक समस्याओं को सांस्थानिक कुशलता और विवेचित राजनैतिक व्यवस्थाजय अनुभवों से ही निपटाने का मतलब करता है।

भारत में राजनीति, मुख्यतः देश की एकता का बनाये रखने की राजनीति है। यह स्वीकारा जाता है कि देश के विकास का काम जरूरी है मगर देश की एकता से ज्यादा जरूरी नहीं। किसी भी परिवर्तन को इस दृष्टि से देखा जाता है कि उससे देश की एकता को बल मिलेगा या नहीं। नतीजा यह है कि विकास के काम में जल्दबाजी या व्यग्रता नहीं की जानी और हर काम में अनिश्चय, असमंजस और जल्दतर से ज्यादा समझौते की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। राजनीतिक दिशाएँ निर्धारित हो चुकी हैं सिर्फ उस ओर धीरे-धीरे बढ़ने के लिए समय की जरूरत है। मगर समय का ही तो अभाव है। समय का मिलना इस पर निर्भर है कि

सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा जनता में अभाव और गरीबी से उत्पन्न होने वाले क्षोभ और लोकतंत्र से उत्पन्न होने वाली आवाजाज़ों का विस्फोट का कब तक रोक सकेगी। मुख्य कसौटी यह है कि भारत की पुरानी परंपरा का उसकी नयी स्थापित व्यवस्था से कहाँ तक सामंजस्य या मेल हो रहा है। क्या इस प्रकार का सामंजस्य स्थापित होने के पहले ही आधुनिकता के आघात से पुरानी परंपरा ढह न पड़ेगी? क्या वह आर्थिक विकास में देश के सक्षम होने तक बनी रह सकेगा? नये व पुराने का मेल क्या रूप लेगा और क्या वह भविष्य में काममें रह सकेगा? भारत की नयी राज्यव्यवस्था की कसौटी सामाजिक परंपरा, राजनैतिक शक्ति और आर्थिक परिस्थितियों की परस्पर प्रतिक्रिया से होगी।

तुलनात्मक दृष्टिकोण

इससे स्पष्ट है कि भारत जैसे वैविध्यपूर्ण और प्राचीन परंतु आधुनिकता से प्रभावित समाज का विश्लेषण करने में अनेक दृष्टिकोणों का प्रयोग आवश्यक है। यह इन लिए और आवश्यक हो जाता है कि विश्लेषक एक पूर्ण सुसंगठित इकाई का विश्लेषण करता है न कि उसके खंडों का। इस विश्लेषण से ऐसे तथ्यगत निष्कर्ष निकटेंगे जो समस्त समाजों पर लागू होंगे। ऐसे विश्लेषण में एक समस्या यह होती है कि दृश्यमान वास्तविकता को सिद्धांतिक रूप देना तो आवश्यक है परंतु ऐसा करने में यह लाभ होता है कि निरूपित सिद्धांतों से तथ्यगत अनुमान किए जायें। ऐसे प्रलोभन से बचने के लिए सिद्धांतिक दृष्टिकोणों का सहारा लेना चाहिए।

हमने भारतीय व्यवस्था के विकास के विवेचन में तुलनात्मक विश्लेषण के यत्नात्मक संप्रदाय के तरीकों से काम लेने के अलावा अन्य कई दृष्टियों से भी विचार किया है—जैसे ढाँचे में परिवर्तन, राजनैतिक तथा सामाजिक संस्कार, और परंपरा की नयी व्याख्या। संस्थानिकरण और राजनैतिक गठबंधन के महत्त्व को दिखाने के लिए हमने केन्द्र और परिधि (अंतरंग और बाहरी) के संबंध की चर्चा की है और व्यवस्था की कसौटी विभिन्न स्तरों पर समस्याओं की सुनिश्चिता सक्कन की उसकी क्षमता को माना है। हमने अपने विवेचन में कुछ प्रचलित धारणाओं को भी अलाचना की है। हमने यह दिखाया है कि विकास के क्रम में प्राचीन और आधुनिक में कोई अंतर्विराघ नहीं है। हमने इस पर भी शका प्रकट की है कि अमुक प्रकार की राज्य व्यवस्था अमुक प्रकार के समाज और अमुक प्रकार की स्थितियों में ही संभव है। हमने इस धारणा पर भी शका की है कि इस विकासक्रम में दिशाहीनता का संकट भी उत्पन्न हो। हमने इस सिद्धांत से भी असहमति प्रकट की है जो राजनीतिक दला या मध्यस्थ समस्याओं को परस्पर असंबद्ध मानता है और इस दृष्टिकोण की त्रुटियों को भी दिखाया है जो यह मानता है कि राजनैतिक प्रक्रिया से सिक

विभिन्न वगहितो का समुच्चयन मान होता है। इस प्रकार हमने राजनैतिक विकास के भारतीय प्रयोग को ठीक ढंग से समझने की कोशिश की है। इससे अन्य विकासमान देशों के राजनैतिक विकास को समझने में भी कुछ मदद मिल सकती है।

जब हम किसी समाज के विकास की प्रक्रिया को अपने सामने होते हुए देखते हैं, तो हमें इसे इस समाज के सदस्यों की निगाह से, खासकर उन लोगों की निगाह से देखना चाहिए जो इस विकास-प्रक्रिया के संचालक हैं। इसमें हमें दो बातों पर ध्यान देना होगा, जिनकी अक्सर उपेक्षा कर दी जाती है, एक सस्यागत विश्लेषण और दूसरे नेता या अगुआ वर्ग की भूमिका। इस प्रकार भारतीय व्यवस्था का विवेचन करते समय हमें राजनैतिक संस्थाओं की मूल सामाजिक और आर्थिक गतिविधियाँ को समाविष्ट करने वाला एक तरह का ढाँचा मान न समझ लेना चाहिए। इसी तरह यह न समझ लेना चाहिए कि नेताओं का काम जनता की माँगों को सरकार तक पहुँचाना और उनकी पूर्ति कराना मात्र है। वास्तव में सारी प्रक्रिया की शुरुआत एक सार्वजनिक और राजनैतिक व्यापक ढाँचे की स्थापना से होती है, जो नेताओं के प्रयत्नों से समाज के विभिन्न स्तरों में प्रवेश करती है, और तब क्रमशः उसके जवाब में नीचे से नए गठबंधन या व्यूहों की रचना होती है। इस प्रकार अगुआ या नेता और संस्थाएँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन के माध्यम बन जाते हैं और विभिन्न स्तरों पर नयी चेतना का जन्म देते हैं और नयी शक्तियों का मैदान में लाते हैं। वे राष्ट्रीय व्यवस्था के एकीकरण, संगठन और विविधीकरण में सहायक होते हैं। इस स्थिति में राजनीति एक महान रचनात्मक शक्ति का काम करती है, जो प्रतिनिधित्व की मशीनरी या तंत्र मात्र नहीं होती जो बाहरी दबाव पर कार्य करे और विभिन्न हिता के समुच्चयन का मोका दे।

तुलनात्मक राजनीति के हाल के ग्रंथों में यह माना तो जाता है कि राजनैतिक प्रक्रिया का सामाजिक ढाँचे और मूल्यों को बदलने में बड़ा हाथ होता है, फिर भी पुरानी भ्रांतियाँ बनी रहती हैं। एक भ्रांति का मूल धर्मनिरपेक्षता का वह अस्पष्ट सिद्धांत है जो जातिसंस्था का स्वरूप ठीक से समझने में विफल हो कर यह मानता है कि विकास का क्रम अनिवार्यतः सांप्रदायिक से स्वच्छिक संगठन के रूप में परिवर्तन होने में निहित है।

राजनैतिक दलों को शासनप्रक्रिया से वियुक्त कर मात्र प्रतिद्वंद्वी संगठनों के रूप में देखने के कारण इस बात की उपेक्षा कर दी जाती है कि सरकारी व्यवस्था में भी उनका योग रहता है। सत्ताधारी दल केवल बोट जुटाने और चुनाव लड़ने का ही काम नहीं करते बरन् योजना के कार्यन्वयन और अन्य सरकारी गतिविधियों में योग देकर जनता में प्रवेश करने का यत्न करते हैं और जनता को राजनैतिक

प्रक्रिया में भाग लेने की प्रेरित करत है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि अतिमित या अल्पनिमित्त और सामाजिक दृष्टि में (जातिपाति में) बटे हुए देश में राजनैतिक गतिविधियों के कारण विघटन की प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं। इसका एक कारण यह है कि पश्चिम के लोग यह समझते हैं कि गैर पादशाह्य में चुनाव आदि की दलों की राजनीति में भाग लेने की क्षमता ही नहीं है और दास मनोवृत्ति से प्रभावित होकर गैर पश्चिमी राजनीति में आलोचक भी उपर्युक्त आशय प्रकट करते हैं। दूसरे, पश्चिमी विचारक यह समझते हैं कि जाति विकास और सामाजिक संस्कार होने के बाद ही आम लोगों को बोट देने और राजनीति में भाग लेने का अधिकार देना चाहिए। तीसरे, राष्ट्रीयता की ही धारणा का सबसे अधिक या एवमान महत्त्व रख कर इस बात की उपेक्षा कर दी जाती है कि प्रात, भाषा या जाति की अपेक्षाकृत सकीण भावना या निष्ठा भी राजनैतिक संगठन में और राज्य व्यवस्था को संस्थापित करने में सहायक होती है और राजनैतिक मांग पर अकुल रहती है। आजकल एक और नारा बहुत चल पड़ा है — बढ़ती हुई आकांक्षाओं की क्रांति। यह बात भी पश्चिमी देशों पर ज्यादा लागू होती है, जहाँ व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य मांगों की पूर्ति है।

विकसित या उन्नत देश, नव स्वतंत्र देशों के द्वार में, खासकर भारत के द्वार में क्या सोचते हैं इसे भी देखना चाहिए। पश्चिम में यह आम धारणा रही है और पश्चिमी देशों के संबंध में अब भी है, कि जनसाधारण के राजनीति में भाग लेने से व्यवस्था की लोकप्रियता और शक्ति बढ़ती है। लेकिन यह बात कम विकसित देशों के लिए ठीक नहीं समझी जाती और कहा जाता है कि इन देशों में यदि जनता को राजनीति में भाग लेने और मनमोद या विरोध की स्वतंत्रता दी गयी तो इससे विघटन की शक्तियों के उभरने और व्यवस्था के छिन्न भिन्न होने का खतरा है। यद्यपि इस धारणा के लिए बहुत कम प्रमाण हैं क्योंकि ऐसा नए राष्ट्रों की सरया ही इसी गिनी है, जहाँ जनता को राजनैतिक अधिकार प्राप्त हैं, फिर भी यह काफी व्यापक है। यह साम्राज्यवादी देशों की इस धारणा का ही दूसरा रूप है कि पराधीन देश स्वशासन के योग्य नहीं हैं। उपर्युक्त विचार के लोग यह भी समझते हैं कि अंत में भारत भी विघटन की शक्तियों का शिकार होगा।^२

भारत में जब तक लाकतंत्र कैसे चल रहा है और यहाँ की व्यवस्था क्या नहीं टूटी, इसके लिए मैं पादशाह्य आलोचक तरह तरह की सफाई देते हैं। पहले यह

२. मारिंस जोन्स के शब्दों में — भारत के विप्लव की भविष्यवाणी करने वालों का शायद यह खेकड़ बड़ा बुरा लगता है कि शतनी सारी कठिनाइयों के सामने भी वह कैसे टिका हुआ है। भारत में अपनी आलोचना की जो प्रशुति है उससे इन अशुभ चिंतकों को बल मिलता है। किंतु भारत की संप्रज्ञा इनकी भूठा सिद्ध कर देती है। "लेबेन ऐंड रिगन बिदिन इति यूनिटन" - फिलिप मेमन सभा "लेबेन ऐंड सीनेन यूनिटी ऐंड लाइविंग" (१९६०)।

कहा जाता था कि अंग्रेजा का छाडा हुआ 'नीकरशाही का फोलादी ढाचा' भारत को बचाये हुए है, फिर कहा जाने लगा कि यह नेहरू का चमत्कार है, इसके बाद यह कहा गया कि कांग्रेस दल देश को एक में बाँधे हुए है। जब ये सब बातें चूक गयीं, तो लागू चकरा गए। अब भी उनके मन में आशंका है कि भारत की व्यवस्था ज्यादा दिन चलने वाली नहीं और कोई न कोई समस्या ऐसी उठेगी, जो इसे तोड़ देगी, या तो केन्द्र और राज्या में संघर्ष या चीन अथवा पाकिस्तान से पराजय, और कुछ नहीं तो आर्थिक विकास में विफलता। इस प्रकार समझ या सहानुभूति के अभाव से (क्षेत्रीय विशेषज्ञता को छोड़ कर) ये जालोचन भारत की सफलता या विफलताओं का ठीक ठीक जायजा नहीं ले पाते। बल्कि शीत युद्ध की मनोवृत्ति से प्रभावित होकर पहले के प्रशमक भी अब विरोधी बन गये हैं।³ यह भी एक बिडबना है कि जब सारे ससार में बौद्धिक जागरण फैल रहा है, तब जिन दशकों उसका पहला प्रकाश फैला था, वे इतनी जटिलता और कुठार के शिकार हैं।

भारतीय विकास का स्वरूप

भारत के विकास का अनौपचारिक इस बात में है कि आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन और विकास की महत्वपूर्ण बात ऊपर से तब की जाने पर भी लाक्षणिक और स्वतन्त्र राजनैतिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती है। इसका अर्थ यह है कि कुछ प्रमुख विचारों के प्रभाव में जो राजनैतिक परिवर्तन हो रहे हैं, उनमें ऐसे तत्त्वों का हाथ है जैसे राजनैतिक स्पर्धा में तीव्रता, शक्ति और प्रभाव का विस्तार तथा राजनैतिक प्रक्रिया में बहुजन वर्ग का भाग लेना। इसमें लोगों को डंडे के जोर पर इच्छित दिशा में हटाने की वांछ नहीं की जाती, बरन् उन्हें निर्दिष्ट ढंग से खुद अपना विकास करने को प्रेरित किया जाता है। व्यक्तियों और समूहों को राजनैतिक प्रक्रियाओं और समस्याओं में भाग लेने का अवसर दिया जाता है जिससे व्यवस्था का आधार ज्यादा व्यापक होता है। राज्य के हित को ऊपर रख कर व्यक्ति के हित को कुचलने के बजाय व्यक्ति के हित का राज्य के हित से सामंजस्य किया जाता है। राज्य नेता जनता का समर्थन कर उसे साथ ले चलने का प्रयास करते हैं।

इसके अलावा अधिकार और शक्ति पर किसी अभिजात वर्ग या सीमित शासक

३ पहले आम चुनाव के दो वर्ष बाद मन्सेटर गार्जियन ने लिखा था—पश्चिम में समुद्रीय व्यवस्था सफल नहीं हो सकी है—पेरिस में वे कहा था कि एथेंस सारे यूनान का शिक्षक है। मि. नेहरू भी इसी तरह बिना दोषों के बताने हैं कि दिल्ली सारे पश्चिम का शिक्षक है। (जून ५, १९५४)। इसके करीब १३ वर्ष बाद टाइम्स के भारत स्थित संपादक ने नई लेखों में यह कहा कि चाहे आम चुनाव या भारत में आखिरी चुनाव होंगे। इस भविष्यवाणी का पश्चिम में सहानुभूतिपूर्ण स्वागत किया गया।

वर्ग का एकाधिकार नहीं है। 'ये' 'ये' तत्त्वा की सत्ता में भाग लेने का मौका दिया जाता है और सारे समाज की अधिकार का भागीदार बनाने की कोशिश की जाती है। इस विषय में भारत उन पश्चिमी देशों से भिन्न है, जहाँ तीव्र औद्योगिक क्रांति और सामाजिक परिवर्तन के युग में राजनैतिक सत्ता केवल उच्च वर्ग के हाथ में रही। इसी तरह वह उन कम्युनिस्ट तथा गैर कम्युनिस्ट अधिनायकवादी देशों से भी भिन्न है, जहाँ क्रांति के बाद पार्टी की आंतरिक गुटबंदी एवम सैनिक पडमंत्र के अलावा राजनैतिक दलों की गतिविधियाँ पर पाबंदी लगा दी गयी और उन्हें देश के विकास में राय देने या भाग लेने से वंचित कर दिया गया। भारत में न तो राजनैतिक गतिविधियाँ पर रोक है न उस पर अल्पसंख्यक उच्चवर्ग का कब्जा है। इसके विपरीत आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन सबंधी निम्न राजनैतिक वादविवाद और लोकतंत्री प्रक्रिया से किए जाते हैं।

कुछ समय तक यह बात इतनी साफ नहीं थी क्योंकि बालिग मताधिकार और अनेक दलों के होते हुए भी सत्ता या शासन वास्तव में एक छोटे और सुसंगठित समूह या गुट के हाथ में था। किन्तु क्रमशः राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता और चुनाव की प्रक्रिया के प्रसार के कारण अन्य समूह या गुट भी सत्ता के दावेदार हुए। शासन में जनप्रतिनिधित्व का तत्त्व आया, सीमित शासन के विवरण के लिए विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों से मांग बढ़ी सामाजिक वर्गों और राजनैतिक गुटों या दलों में समय बढ़ा, पुराने सामाजिक भेदों ने राजनैतिक रूप धारण किया और पद-प्रतिष्ठा के नये मानदंड स्थापित हुए। देश की राजनीति और विकास प्रक्रिया पर इन प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ रहा है।

साथ ही यह भी ध्यान रहना चाहिए कि भारत में विकास का काम प्रशासन के विकसित और सुगठित ढाँचे के अंतर्गत शुरू हुआ। जितने भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम बने, औद्योगीकरण सामुदायिक विकास, शिक्षा क्षेत्रों का विकास, यहाँ तक कि स्थानीय स्वाशासन — सब इसी नीकुरशाही या प्रशासन तंत्र के द्वारा संचालित थे। अब इसमें राजनैतिक तत्त्वा और मूल्यों का प्रवेश हो रहा है।

इस प्रकार भारत में राष्ट्र निर्माण की दो प्रक्रियाएँ चालू हैं। एक सरकारी प्रशासनिक प्रक्रिया है जो विकास योजना के कार्यों को बढ़ाने और उनमें एकसूत्रता रखने का यत्न कर रही है। दूसरी राजनैतिक प्रक्रिया है जिससे एक ओर केन्द्रीय सत्ता या राजनैतिक केन्द्र की स्थापना हुई है, दूसरी ओर सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ है और उसमें नए तत्त्वा का प्रवेश हुआ है तथा नये संगठन और संस्थाएँ सक्रिय हो उठी हैं। धीमे धीमे ये दोनों प्रक्रियाएँ एक दूसरे के समीप आ रही हैं और उनका स्वरूप बदल रहा है।

भारत में होने वाला परिवर्तन बहुत सीमा-तक राजनैतिक सरकारी परिवर्तन है। भारत इस सिद्धांत का अपवाद या विरुद्ध प्रमाण है कि आर्थिक — सामाजिक

शक्तियाँ राजनीति और सरकार की नियामक होती हैं। भारत में बहुत हद तक राज्य समाज का नियामक है। इसका यह अर्थ नहीं कि विकास की प्रक्रिया में सामाजिक और आर्थिक शक्तियों का कोई हाथ नहीं। प्रत्युत ऐसा संभव है कि सत्ता के विवेकीकरण से इन शक्तियों का प्रभाव बढ़े।^४ ध्यान देने की बात यह है कि सामाजिक हित अधिवाधिक राजनैतिक रूप ले रहे हैं और राजनीति के द्वारा ही संगठित हो रहे हैं।

अक्सर इसका यह अर्थ लगाया जाता है कि एक या अनेक सामाजिक समूह (जाति या संप्रदाय) राजनीति के द्वारा अपनी प्रधानता स्थापित करने और प्रतिष्ठा तथा प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। समय गुजरने के साथ साथ जिम व्यापक संगठन के अंतर्गत यह परिवर्तन-प्रक्रिया चलती है और राजनैतिक तथा प्रशासनिक मानदंड प्रतिष्ठित होते हैं उनके कारण राजनैतिकीकरण की प्रक्रिया परिपक्व हो जाती है। परंतु इससे अंत में समाज के राजनैतिकीकरण में मदद मिलेगी और सामाजिक मूल्य राजनैतिक मूल्य तथा सामाजिक पद-प्रतिष्ठा राजनैतिक पद-प्रतिष्ठा में बदल जाएंगे।^५

राजनीति का स्थान

भारत में समाज के विखंडित ढांचे में राजनैतिक संस्थाएँ, मूल्य और विचारों का प्रवेश हो रहा है। भारतीय समाज-व्यवस्था अराजनैतिक रही है, अब यहाँ एक राजनैतिक केंद्र की स्थापना हो रही है और समाज के विविध वर्गों को राजनैतिक व्यवस्था में स्थान मिला है, उन्हें इसका लाभ और अधिकार मिला है और उन पर इसकी जिम्मेदारियाँ भी आयी हैं। अब तक जो गांव राजनैतिक व्यवस्था से दूर रहे वे इसके पास आ रहे हैं।

यह एक नयी बात है। अपने हजारों वर्षों के इतिहास में भारत की सबसे बड़ी विफलता यही रही है कि वह एक टिकाऊ आधुनिक राजनैतिक सत्ता का निर्माण नहीं कर सका। वह राजनैतिक केंद्र या केन्द्रीय सत्ता का निर्माण नहीं कर सका। इसी से हम भारतीय समाज-व्यवस्था को अराजनैतिक समाज का नाम देते हैं, न कि उसके विशिष्ट साम्प्रदायिक तत्त्वों के कारण। इस पृष्ठभूमि में भारतीय नेता-वर्ग के कर्तृत्व और अभिन्नता की मौलिकता और महत्त्व स्पष्ट है। उनका काम एक केंद्र की स्थापना करना और इसे समाज के उपवेष्टा में फैलाना है। यहाँ

^४ अध्याय ९ में इस पर विस्तार से विवेचन किया गया है।

^५ इसमें न केवल विशेष हितों का संगठन होता है, बल्कि पुरानी निष्ठाएँ और आवश्यकताएँ भी बदलती हैं। एक बार हम प्रकार का राजनैतिक व्यवस्था का वादन होने के बाद हितों के ये संगठन राजनीति को प्रभावित करेंगे। इस बीच 'हित समूह' या 'हित विशेष' के दलों का अधिक महत्त्व नहीं।

सामाजिक परिवर्तन राजनैतिक रूप में हो रहा है।

इसके फलितार्थ को समझ लेना आवश्यक है। आर्थिक विकास का जो सिद्धांत उसने ऐसा मत प्रतिपादित किया है जो सामाजिक परिवर्तन को एकांगी, एकांगी और प्रमुखतः द्वैधात्मक रूप में देखता है। भारत की जटिल विकास-प्रक्रिया की व्याख्या ऐसे एकांगी सिद्धांत से संभव नहीं। क्योंकि यह स्पष्ट है कि पारस्परिक समाजशास्त्रीय और अर्थशास्त्रीय सिद्धांतों की सहायता से यहां की राजनैतिक प्रक्रिया को नहीं समझा जा सकता। हम एक ऐसे समाज का विश्लेषण कर रहे हैं, जहां परिवर्तन किसी विशिष्ट शक्ति-संतुलन का न तो परिणाम है न उसकी प्रतिच्छाया है। भारत जैसे समाज में राजनीति का आयाम सीमित भी है और स्वायत्त भी है। अनेक प्रकार से राष्ट्रीय लक्ष्य और साधना की प्राथमिकता का निर्धारण राजनैतिक निष्कर्षों से होता है। राजनीति के रूप भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि आधिकारिक संस्थाओं की तरह में जो राजनीतिक तत्त्व हैं उसका असली स्वरूप नेतृत्व के सामाजिक संस्कार और गठबंधन के तरीकों में प्रतिबिम्बित होता है। फिर भी राजनीतिक संस्थाओं का दृश्यमान रूप अपनी एक गतिशीलता और प्रमुखता प्राप्त कर लेता है और समाज के लक्ष्यों को स्पष्ट करता है तथा समाज की वास्तविकता को समाविष्ट करता है। ये दोनों पहलू घुलमिल जाते हैं। नेतृत्व का सामाजिक संस्कार सामाजिक वर्गों के राजनैतिक कारण से अभिन्न हो जाता है और राजनैतिक व्यवस्था भी आधिकारिकता, सामाजिक रूपों और निष्ठाओं के राजनैतिक स्वरूपों पर निर्भर करती है। इस कारण से पारस्परिक विकास के सिद्धांत के बजाय विश्लेषण के नए मानक आवश्यक हो जाते हैं।

भारत में लोकतंत्रीय राजनैतिक व्यवस्था के अंतर्गत एक प्राचीन और बड़े विविधतापूर्ण समाज का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसमें क्या सामाजिक और आर्थिक प्रवृत्तियाँ हैं, यह त्रिकुल स्पष्ट होना चाहिए। वरना देश ने जो संस्था योजना स्वीकार की है, उसका रूप विकृत हो जाएगा। दूसरे, इस पद्धति में विकास के जो परंपरागत लक्ष्य हैं, अर्थात् आर्थिक विकास की दर, विकास के शिक्षा जैसे सामाजिक साधन और नये विचारों व मूल्यों का प्रसार, वे भी काफी हद तक इस पर निर्भर हैं कि राजनैतिक व्यवस्था या राज्यतन्त्र कैसा काम करता है और विकास के द्वारा विभिन्न तत्त्वों की एकता के सूत्र में बांध पाना है या नहीं। इसके लिये यह आवश्यक है कि राज्य के नेता ऊँचे अधिकारों और जनमत के निर्माता वास्तविक स्थिति और लक्ष्यों का समझें। सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं की विकास की दिशा में मांड देना आसान काम नहीं है। इसका प्रतिरोध पुराने लोगों की ओर से ही नहीं होगा बल्कि शिक्षित पेशा, सरकारी नौकरों और बुद्धिजीवियों जैसे आधुनिक तत्त्वों की ओर से भी होता है। विकास के पुराने शास्त्रीय सिद्धांत

और पुराने राजनतिक और सामाजिक विचार विकास की उस पद्धति में बाधक होते हैं, जिसे देश ने अपनाया है। यह पद्धति द्वंद्व के जरिये एकता स्थापित करने की है। ध्यान यह रखना है कि इसमें वितापी सिद्धांत और सरकारी नौकरा की निरकुशता और जनता की भावनाओं की उपेक्षा बाधक न होने पाए।

भारत ने विकास की जिम पद्धति का अपनाया है उसके लिए अर्थिक विवेक पूर्ण संकल्पना की जरूरत है। जब यह अनुभव किया जा रहा है कि आर्थिक विकास महज एक आर्थिक प्रक्रिया ही नहीं है और उसकी सफलता अनेक मोर्चों पर की गई प्रगति पर निर्भर है। अभी तक इससे लिए आर्थिक विकास की आवश्यक पूर्वस्थितियों पर ही जोर दिया जाता है। समझने की मुख्य बात यह है कि जिस राष्ट्र और समाज का विकास अवचेताओं को करना है, अभी उनकी स्थापना नहीं हो पायी है। विकास का अर्थ जनता के कुछ या सब वर्गों की उन्नति ही नहीं करना है, बल्कि राष्ट्र का निर्माण भी करना है। लोगों को उत्पादनवृद्धि के काम में लगाने का मतलब बेचत बचत करना और उसे आर्थिक काम में लगाना नहीं है, इसमें जनता के प्रोत्साहन, मनोबल, दिलचस्पी और भावों की संतुष्टि के भी प्रश्न उत्पन्न हैं। इसमें समाज के वर्तमान ढांचे को बदलने, ऊपर और नीचे के तबका का जोड़ने वाले मध्यवर्तियों के संगठन की जरूरत पड़ती है और समाज को उत्पादन की ओर उन्मुख करना पड़ता है। राजनैतिक ढांचे की कसौटी इन्हीं कार्यों की संपादन-क्षमता होगी। इसके विवेचन के लिए वह धारणा काम नहीं देगी जो आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्रों में महज सबद्धता दिखाती है। विकास की यह ऐसी पद्धति है, जिसमें अब तक बड़े हुए और विभाजित ढंग से सोचने वाले समाज के सामने नये मूल्य प्रस्तुत होते हैं और उसका वास्ता ऐसी नहीं सस्थाओं के ढांचे से पड़ता है जिसका उद्देश्य राष्ट्र का एकीकरण और आयोजित उत्पादन है। बदले में समाज के विभिन्न वर्गों को विकास के कार्यों का लाभ और राजनैतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इससे प्रकट है कि सामाजिक परिवर्तन में राजनैतिक व्यवस्था की भूमिका कितने महत्व की है।

यह परिवर्तन आसान नहीं है। पश्चिम में राजनीति के विवेचकों को सरकार के रूप से ध्यान हटा कर समाज में शक्ति, सत्ता और हित के वास्तविक संगठन पर ध्यान देने में कई दशक लगे। भारत जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए और जटिल सामाजिक ढांचे वाले देश में नयी राजनैतिक व्यवस्था का विवेचन करते समय शक्ति या सत्ता के ढांचे और उसकी सोद्देश्यता के संबंध में और गहराई में जाना पड़ेगा। जब किसी समाज में विजातीय ढंग की सरकार या शासन-प्रणाली स्थापित की जाती है तो उसकी एक अनोखी प्रतिक्रिया होती है और समाज में नयी चेतना और नयी निष्ठाएं उत्पन्न होती हैं। कमश इनसे सरकारी काम के मूल्यांकन के नए मापदंड स्थापित होते हैं, जिनसे अक्सर स्थापित व्यवस्था की

स्थिरता सतर में पड़ जाती है। विकास के वास्तविक प्रथम पुरानी और नयी दोनों तरह की बात होती है। इसलिए पहले से यह रही निश्चित किया जा सकता कि संवैधानिक सरकार किस रास्ते पर चले।

सहवर्ती परिवर्तन की समस्या

तार्किक दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि समाज जिस प्रकार की समस्याओं को स्थापित करता है उन्हीं के अनुरूप उसे विकास के लक्ष्य भी अपनाने चाहिए। किंतु यह अनिवार्य नहीं। बल्कि भारत में विकास की आरम्भिक अवस्था में स्थापित संस्थाओं और उनके उद्देश्यों में मेल या अनुरूपता की कमी दिखाई पड़ी। स्वतन्त्रता के बाद भारत में जो राजनैतिक और आर्थिक विचारधारा स्फुर गई वह इन बातों पर केन्द्रित है— (१) देश में बालिग मताधिकार पर आधारित संसदीय शासन की प्रणाली की स्थापना करना और जनता को चुनावों के जरिये शासन में अधिक से अधिक भाग देना। (२) विकास की केन्द्रित सरकारी योजना बना कर तेजी से आर्थिक उन्नति करना। विराधाभास के दावजूद क्या ये दोनों लक्ष्य राष्ट्र निर्माण में सहायक होंगे, अथवा संस्थाओं का यह ढांचा इन लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक हो सकता है, यह कुछ महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर था।

एक तरीका था अधिनायकवादी ढांचा स्थापित करना जो प्रारम्भ से शासन की पूरी शक्ति विकास में लगाता। यह या तो नीवरसाही का फौलादी ढांचा हो सकता था, जिसे राजनैतिक दबाव की कोई परवाह नहीं होती, या एक दलीय ढांचा होता या दोनों का मिश्रण हो सकता था। यह केन्द्रीयकरण को राष्ट्रनिर्माण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग बना देता। इसमें समाज को नये लक्ष्यों की पूर्ति में लगाने के लिए उसका राजनैतिकीकरण किया जाता लेकिन राजनैतिक गति विधि दलों का संगठन और प्रतिद्वन्द्विता को अत्यन्त सीमित एवम् सकुचित कर दिया जाता। स्थानीय लोग और समूहों से परामर्श सिर्फ राजनैतिक कौशल का रूप नेता जिससे जनता को वृद्धि के कार्यों में लगाने की सुविधा होती पर इसको राजनैतिक व्यवस्था में भागीदारी का रूप नहीं दिया जा सकता था। इसी तरह सामाजिक न्याय और समता के लक्ष्य का स्वीकार हो जा सकता था और साधन उपलब्ध होने पर उनकी पूर्ति का आश्वासन हो दिया जा सकता था, किंतु देश की समृद्धि और प्रगति की भूमि तैयार करने की खातिर लोकहितकारी राज्य के आदेश और उपभोग बढ़ाने की नीति को तब मुनतवी रखा जाता।

भारत ने विकास के इस तरीके का नहीं अपनाया। एक राष्ट्रीय राजनैतिक मोर्चा बनाने और सामूहिक या नाक-समर्थित लोकतन्त्र की स्थापना करने के लिए नेताओं को सत्ता की राजनीति पर अर्थात् मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने की आवश्यकता पर ध्यान देना पड़ा और स्वतन्त्रता के बाद इसने त्याग और

सादगी के जिन आदर्शों पर जार दिया था, उन्हें नमश छोड़ देना पड़ा। अब यह स्पष्ट है कि देश की मध्यवर्गी और वंचित जनता को विकास के काय में लगाने के लिए नेतृत्व ने उनसे केवल अधिवाधिक धन और साधन खींचने के बजाय उनको विकास के लाभ और राजनैतिक अधिकारों में भाग देने की नीति अपनायी। जनता से देश के विकास के लिए अधिवाधिक धन लेना, अभी भी उसना एक मुख्य लक्ष्य है, मगर इस लक्ष्य की सिद्धि वह जबदस्ती, अथ सब मांगों को कुचल कर नहीं, बल्कि जनता के सामाजिक और राजनैतिक संगठन के द्वारा करना चाहता है।

इस काम में गलतियाँ भी हुई, क्योंकि ऐसा कोई उदाहरण न था, जिसका अनुसरण किया जाता। देश के राजनैतिक और आर्थिक विकास के साथ साथ समाज के पुराने कठुआए हुए ढाँचे को बदलने का काम एक अभूतपूर्व प्रयत्न था। दूसरी ओर यह भी निश्चित नहीं है कि अधिनायकवादी तरीका सफल हो जाता, खास कर भारत ऐसे देश में जहाँ केन्द्रीय सत्ता के पतियों का प्रवेश प्रायः या प्रदेशों में नहीं हो सका है और जहाँ प्रांतीय निष्ठाओं को अभी राष्ट्रीय निष्ठा का रूप देकर सब के स्थायी ढाँचे की स्थापना करना बाकी है। वास्तव में दिल्ली सारे देश पर शासन इसी प्रकार कर सकती है कि वह प्रदेशों का सत्ता में भागीदार बनाये और प्रदेश भी अपने अलग-अलग उपप्रदेशों या स्थानीय इकाइयों को साथ लेकर चले। इस स्थिति में लोकप्रिय राज्य और वार्षिक मताधिकार को केवल आदर्श और भावना की खातिर नहीं, बल्कि व्यावहारिक कारणों से स्वीकार किया गया, क्योंकि इसके द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण, सामाजिक संगठन और आर्थिक विकास का आधार मिलता था। स्वाभाविक था कि इस पद्धति पर चलने में शुरू में काफी दुविधा और गड़बड़ी होती। पर जैसा कि हम आगे व्यवस्था के काम की समीक्षा सवर्षी अध्याय में देखेंगे, इस पद्धति से न केवल राजनैतिक केन्द्र की स्थापना और संस्थानीकरण में और उसमें देश के विविध तत्वों को शरीक करने में सफलता मिली, वरन् जब जब आर्थिक और सामाजिक नीतियों में दोष दिखाई दिये, तब तब उन्हें सुधारने में भी मदद मिली।^६

इस सबब में एक बात और ध्यान देने योग्य है। राष्ट्र या राष्ट्र-निर्माण की धारणा अधिकतर पश्चिमी देशों से ली गयी है जहाँ राष्ट्रों की स्थापना साम्राज्यों, सामंती व्यवस्थाओं और ईसाई चर्च के आधिपत्य के टूटने से हुई थी। इससे सुदृढ़ और सशक्तिशाली केन्द्रीय सरकार का सिद्धान्त प्रचलित हुआ। इसीलिए राष्ट्र की भावना पर इतना जोर दिया जाता है और नये देशों में प्रांतीय या

६ पश्चिम में इस पद्धति के महत्व का कुछ कुछ अनुभव अब किया जाने लगा है। देखें-चार्ल्स ए. लिं-डन के दो अप्रकाशित निबंध 'पोलि डिमोक्रेसी ऐंड डिमिनिशिंग डेवेलपमेंट्स-द केम ऑफ इंडिया' और 'पोलिटिक्स, पोलिनी मेनिंग ऐंड प्लानिंग फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवेलपमेंट'।

भाषा आदि की सकीण प्रवृत्तियाँ पर चिन्ता प्रकट की जाती है। पर यह स्पष्ट नहीं है कि केन्द्रीय सत्ता की शक्तिमत्ता पर इतना ज़ोर देना और म्यानीय या प्रातीय प्रवृत्तियों का दमन नये राष्ट्र का हित में होगा। प्रत्युत इससे एकता के स्थान पर पृथक्ता उत्पन्न हो सकती है। नए देश के नेताओं के सामने काम है केन्द्र की स्थापना, उसके प्रतीका का प्रसार, दूसरे उपनेत्रों का आश्वासन और सुविधाएँ देकर उनको केन्द्र में शामिल करना और जनता में नयी व्यवस्था के प्रति निष्ठा और अपनापन फैलाकर उनका इसका भागीदार बनाना और इस क्रम में नए राजनैतिक संधीय रूपा की रचना करना। इस काम में राजनैतिक सूझबूझ और रचनात्मक प्रतिभा की बड़ी ज़रूरत है। इस दृष्टि से दखने पर भारत के विकास की पद्धति का सही महत्त्व और अर्थ समझ में आएगा।

जब राजनीति के द्वारा देश का आधुनिकीकरण किया जाता है तब सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ भी इनमें प्रभावित होती हैं और उनकी स्वायत्तता नष्ट हो जाती है। जिस हद तक राजनैतिक व्यवस्था व्यक्तिगत और समूहों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकती है उसी हद तक समाज और अर्थ व्यवस्था पर उसका प्रभाव उपयोगी होता है।

व्यवस्था की कसौटी काय-संपादन

किसी भी व्यवस्था की उपयोगिता की कसौटी, उसकी कार्यक्षमता है। ऐतिहासिक और सैद्धांतिक कारणों से ही व्यवस्था का औचित्य सिद्ध नहीं हो सकता। उसे लोगों की आकांक्षाओं और समय की माँग को पूरा कर सकने में भी समय होना चाहिए। एक गतिशील और बहुमुखी विकास की पद्धति का मूल्यांकन करने के लिए कुछ कसौटियाँ होनी चाहिए। विकास और परिवर्तन के क्रम में कुछ समस्याएँ स्वभावतः उठती हैं। मगर इनमें उन समस्याओं का भेद करना चाहिए जो नेतृत्व की भूलों और गलत तरीकों के कारण उठती हैं। हाँ सकता है कि शुरू में अटकलपच्चू काम हो, मगर यथाशीघ्र रास्ते में आने वाली कठिनाइयों की कल्पना की जानी चाहिए और उनका उपाय सोच रखना चाहिए। बेशक सभी समस्याओं और परिस्थितियों की कल्पना नहीं की जा सकती। मगर हर बात को रामझरोसे छोड़ देना और तदयत्ता से काम लेना अर्थात् यह सोच बैठना कि जो होगा सो देखा जाएगा, अव्यवस्था का निमज्जन देना और बुद्धि का तिलाजलि देना है। इसका अर्थ तो यह होगा कि यहाँ सबकुछ आने पर ही आगे खुलेगी और काम होगा, अथवा नहीं।

भारतीय राज्यतंत्र जिस हद तक वर्गहित के बदलते ढाँचे का अधपूर्ण और क्रमबद्ध गूँथना में सगठित और मुखरित करने में समर्थ है, जिससे अनुभूत सामाजिक विभेद और एकात्मकता के द्वारा निरूपित प्रश्न निणय का रूप लेते और देश के

विकास के लिए सहायक बनते हैं ?

राजनैतिक प्रक्रियाएँ और सस्याएँ समाज के लिए उपयोगी होनी चाहिए। उन्हें सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को समझ कर सरकार पर जोर देना चाहिए कि उनको सुलझाने के लिए ममुचित निणय ले और उन्हें ठीक ढंग से और समय से कार्यावित करे। दूसरी ओर लोगो को सही प्रेरणा देने और यथाथवादी दष्टि की समस्या है। जब एन जटिल और रुद्धिग्रस्त समाज—व्यवस्था में आधुनिक ढंग की राजनैतिक व्यवस्था काम करती है तो परिवर्तन और सामंजस्य या अनुकूलन की बड़ी नाजुक समस्याएँ उठती हैं, जिनको बड़े धीरज तथा दृढ़ सकल्प से सुलझाना पड़ता है। समता, विविधता और जनसहभाग की समस्याएँ नया अर्थ ग्रहण कर लेती हैं और उनको समझाने के लिए नये बौद्धिक संस्कार की जरूरत होती है। यदि व्यवस्था इन समस्याओं का सामना न कर सकी, तो इसका नतीजा या तो यह होगा कि या तो लोग विरक्त होकर समझें कि स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता, और जो चलता है उसे चलने दो या देश का जो स्वतंत्रता का वरदान मिला है, उसकी गहरी प्रतिनिया हो।

जब राज्यतंत्र के रूप में स्थापित्व आता है तो उसका प्रवेश समाज के हर स्तर में होता है और उधर से उसकी अनुकूल प्रतिक्रिया होती है। सरकार की सफलता की कसौटी यह है कि प्रचलित सस्याओं और वैधानिक तरीकों से वह समाज के विभिन्न वर्गों और स्तरों में मिलने वाले ममथन को संगठित करे और इच्छित दिशा में मोड़े। इसके लिए इन बातों का अध्ययन आवश्यक है — (१) राजनैतिक और सरकारी सस्याओं का समाज में प्रसार (२) समाज की ओर से इसकी प्रतिक्रिया और (३) समाज के विभिन्न स्तरों की आवश्यकताओं की पूर्ति में राजनैतिक व्यवस्था की सफलता। इस विवेचन का केन्द्र बिंदु यह होगा कि विकास का जो ध्यापक तरीका अपनाया गया है उसने कैसा काम किया है। इन विवेचन के लिए हमें कुछ गहराई में जाना पड़ेगा जैसे देश की ऐतिहासिक और सामाजिक परंपरा तथा राजनैतिक और सामाजिक संस्कार आदि की समीक्षा करनी पड़ेगी। इस पुस्तक में हम इन विषयों का उसी हद तक विवेचन करेंगे, जिस हद तक इनका संबंध राजनैतिक व्यवस्था से है। इसलिए हम उतने विस्तार में नहीं जा सकेंगे जितना विस्तार इन विषयों पर अलग लिखी पुस्तक में मिलेगा।

प्रस्तुत पुस्तक तीन खंडों में बाटी है — ऐतिहासिक सिंहावलोकन (अध्याय १ से ३), प्रचलित राजनैतिक व्यवस्था का विवेचन (अध्याय ४ से ७), व्यवस्था के बाय का मूल्यांकन (अध्याय ८ से ११)। हमारा केन्द्र बिंदु है सांस्थानिक विकास तथा सरकार की कार्यक्षमता में संबंध। भारत ने जिस प्रकार की पद्धति को अपनाया और जिसकी परिणति दला की पद्धति में हुई, उसने विवेचन पर हमने विशेष ध्यान दिया है। इसी से संबंधित विषय है पुरानी और नयी व्यवस्था का परम्पर संबंध

और इसमें अतिनिहित राजनैतिक संस्कार । पर इस सब विवेचन का मुख्य प्रयोजन है स्थापित व्यवस्था या पद्धति की क्षमता की परीक्षा ।

दूसरी तरफ हमने राजनैतिक विवेचन के कुछ रुढ़ विषयों पर कम ध्यान दिया है । जैसे हमने (अध्याय ५ में) भारत में विभिन्न हिता के सघों की चर्चा करत हुए, श्रमिक या अग्य प्रकार के संगठना या संस्थाओं का इतिहास देने की चेष्टा नहीं की है । इसी प्रकार सामाजिक सेवाओं के प्रसंग में हमने प्रचार के माध्यमों की (रेडियो, अखबार, फिल्म आदि) वसी समीक्षा नहीं की है जैसी पश्चिमो आलाचका के ग्रन्थों में मिलती है । इसी तरह हमने संविधान तथा न्याय और कानून की पद्धति के विकास का इतिहास भी नहीं दिया है । इस प्रकार हमारा विवेचन विकास की प्रक्रिया पर केन्द्रित है ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्रस्तावना वाले अध्याय में उठाए गए प्रश्न को अधिक अच्छी तरह समझने के लिए हमें भारतीय समाज की ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को देखना चाहिए और जिन विचारधाराओं और शिल्पिक विधियों ने उस प्रभावित किया है उन पर गौर करना चाहिए। किसी भी देश में लोकतन्त्र कितना सफल होता है या क्या रूप ग्रहण करता है यह इस पर निर्भर होता है कि उसकी परंपरा क्या रही है उसकी समाज-व्यवस्था और आदर्शों व विचारों में नई बातों को ग्रहण करने की कितनी शक्ति है, उस पर बाहर के क्या प्रभाव पड़े हैं और इतिहास को किन परिस्थितियों में उसने नए प्रभावों का ग्रहण किया है।

काफी लंबी अवधि से भारत पर जो विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़े हैं, उन्हीं से उसके वर्तमान राजनीतिक रूप की रचना हुई है। इसमें तीन बातें मुख्य हैं। एक है हिंदू समाज जो भारतीय जीवन की आधारशिला और उसकी एकता का सूत्र है। दूसरा है अंग्रेजी राज, जिसकी कानून और शासन व्यवस्था सारे देश का एक केन्द्रीय सत्ता के अधीन ल आई। यही नहीं इसने हमारी राजनीतिक विचारधारा और पद्धति पर भी गहरा प्रभाव डाला है। तीसरा है स्वतन्त्रता के पहले का हमारा रचनात्मक राष्ट्रवाद। यह राष्ट्रवाद विदेशी शासन के प्रभाव और उसके द्वारा संप्रेषित नए युग की चुनौती से उत्पन्न हुआ। इस राष्ट्रवाद का उद्देश्य लोकतन्त्री व्यवस्था के अंतर्गत देश की राजनीतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति और समाज का सुधार था। आगे हम इन्हीं तीन प्रभावों के अंतर्गत आधुनिक भारत के विकासक्रम का विवरण करेंगे।

हिंदू समाज

भारत का इतिहास हजारों वर्षों का है। यहां बड़े साम्राज्यों से लेकर छोटे राज्य और गणराज्य, जैसे अनेक प्रकार के राजतन्त्र रहे हैं। जिसे हम हिंदू युग कहते हैं वह ईसा से पहले १५ वीं शताब्दी और दसवीं शताब्दी के बीच स्थिर हुआ। इसी

अवधि में मध्य एशिया से आने वाली आय जातियां ने देश के उत्तरी और पश्चिमी भागों में अपनी बड़ी बड़ी बस्तियां स्थापित की। उन्होंने यहां के आदिम निवासियों को हराकर अपने अधीन कर लिया और बहुतों को दक्षिण की ओर धकेल दिया। ईसा पूर्व १५ वीं सदी से लेकर ईसा की १० वीं सदी के बीच यहां उत्तर में मौय, गुप्त वंश तथा हर्ष के और दक्षिण में चोल और पल्लव वंश के बड़े साम्राज्य कायम हुए। दसवीं सदी के बाद भी जब भारत में मुसलमानों के आक्रमण होने लगे तब के कुछ भागों में हिंदू राज्य बने रहे। पश्चिम भारत में १६ वीं सदी में मराठे मुगलों से लोहा तेते रहे और बाद में उन्होंने जंगलों से भी टक्कर ली। लेकिन १० वीं, ११ वीं सदी के बाद से देश में हिंदू शक्ति का क्षय होने लगा और धीरे धीरे देश में मुस्लिम आक्रमणकारियों की सत्ता कायम हो गई।

हिंदू युग में स्थापित बड़े बड़े साम्राज्यों के काल में देश में महान कलाकृतियां, मंदिरों, पुराण, इतिहास, काव्य और शास्त्रों की रचना हुई। महाभारत, रामायण और अन्य काव्य तथा कलाकृतियों ने भारतीय मानस पर गहरा और स्थायी प्रभाव डाला है। अतीत की इस गौरवमय परंपरा ने आधुनिक युग में देश के जागरण में योग दिया। इसका राजनीतिक महत्त्व है। किंतु इसका असली महत्त्व यह है कि इसने ऐसी सामाजिक व्यवस्था तथा ऐसी परंपरा और मूल्यों का निर्माण किया, जिन्होंने बाद के युगों पर भी स्थायी प्रभाव डाला।

इस हिंदू समाज-व्यवस्था के विकास के क्रम का हमें ठीक ठीक पता नहीं। विनाश क्षेत्र में फैले, राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के केंद्रों से दूर, तथा एक के द्वािप राजनीतिक सत्ता और परंपरा से विहीन भारतीय आर्यों ने ऐसी समाज-व्यवस्था का विकास किया जो उनकी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। यह थी चार पदानुक्रमिक वर्णों की व्यवस्था, जो आर्यों के आगमन के पहले से चली आई आदिम और ढीली ढाली जातियों की व्यवस्था के ऊपर स्थापित कर दी गयी थी। यह व्यवस्था विवाह और कुटुंब के संबंधों पर आधारित थी और बहुत से गौण कार्यों को सभालती थी। इसमें क्षत्रियों के निपटारे का बाय भी था जो राजनीतिक कार्यों की श्रेणी में आता है। यह वर्ण-व्यवस्था कम या कामधर्मे के बटवारे पर आधारित थी और प्रत्येक घरे के साथ उसकी मान-प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई थी। धीमे धीमे छोटी बड़ी जातियां और वर्णों का यह ढांचा बढोर होता गया और उसका एक दार्शनिक आधार और आचार भी विकसित हा गया।

जाति-व्यवस्था

सिद्धांत रूप में चार वर्णों, गुण-कर्म के अनुसार हैं। ब्राह्मण का कार्य ज्ञान-दान, क्षत्रिय का रक्षा, वैश्य का उद्योग और गूढ का श्रम है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। यथाथ स्थिति बहुत जटिल है। जाति या बिरादरी जन्मगत होती है और

विवाह-संवध जाति के अंदर ही होता है। ज्यादातर जातियाँ स्थानीय या एक क्षेत्र में सीमित होती हैं, यद्यपि अनेक जातियाँ दूर दूर तक भी फैली मिलती हैं। इस प्रकार जातियों की संख्या चार नहीं हजारों है। हर जाति की अपनी पंचायत होती है, जो जाति के नियम और आचार-विचार का नियमन करती है। गाँवों की पंचायत या पंच विभिन्न जातियों के भी हो सकते हैं। ऊँची जातियाँ से अलग, नीचा घटा करने वाले और अछूत समझे जाने वाले अत्यंत, हरिजन या अनुमूर्च्छित जातियों के लोग हैं। ये भी अनेक एक दूसरे से नीची-ऊँची जातियों में बँटे हुए हैं। अलग होत हुए भी ये हिंदू समाज के ही अंग हैं। हिंदुओं में ही नहीं आदिवासी बबोला, विशेष अल्पसंख्यकों (जैन, सिख आदि) यहाँ तक कि ईसाइयाँ और मुसलमानों में भी जाति-व्यवस्था पायी जाती है। सब मिला कर जाति की व्यवस्था ने भिन्न भिन्न वृत्तियों के और विभिन्न नस्ल के लोगों का—जैसे आदिवासी, बाहर से आकर बसने वाले या आक्रमण करने वाले और विभिन्न मजहबों के लोगों को, एक साथ, एक धर्मनिरपेक्ष या बहुधर्मी समाज और संस्कृति के ढाँचे में लाने का काम किया है। छठे अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार यह काम, अब राजनीतिन संस्थाएँ कर रही हैं। फिर भी जाति-व्यवस्था की इस भूमिका को ध्यान में रखना जरूरी है।

फिर भी अधिकांश जातियों को वर्ण के अनुसार बाँटा जा सकता है। इधर राजनीतिक उद्देश्य से कई जातियों का एक वर्ण से संगठित करने की प्रवृत्ति देखी पड़ी है। अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अनेक जातियाँ किसी ऊँचे वर्ण की होने का दावा करती हैं। इससे आधुनिक युग में भी जातिव्यवस्था के महत्त्व का पता चलता है।^१ ध्यान रखने की बात यह है कि जाति की व्यवस्था ने स्थानीय सामाजिक ढाँचा प्रस्तुत किया, जिसका संगठन प्रारम्भिक समूहों के आधार पर हुआ जिनकी जीविका और काम एक दूसरे पर निर्भर थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का पद और काम जन्म से ही निश्चित होता था और जिससे आपसी झगड़ा के निपटारे की व्यवस्था के द्वारा सामाजिक एकता को बल मिलता था। ऐसी ही व्यवस्था समय के धपेड़ों, निरंतर युद्ध, बाहरी जातियों और संस्कृतियों के आक्रमण और राजनीतिक परिवर्तनों को झेल सकती थी। सैकड़ों वर्षों में जातियों के परस्पर संघर्ष या पद-मर्यादा में परिवर्तन भी होते रहे। ये परिवर्तन कभी आर्थिक कारणों

१ छठे अध्याय में हमने आधुनिक लोकतंत्री राजन्याति के प्रभाव से जातिव्यवस्था में आने वाले परिवर्तन पर विचार किया है। १९ वीं सदी में भी जनगणना करने वालों और गजेटियर का संकलन करने वालों ने छोटी जातियों में अपने को ऊँचे वर्णों की बताने का प्रयत्न देखा था। वास्तव में वह प्रवृत्ति और भी पुरानी रही होगी। १९११ की संसद रिपोर्ट में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और सिक्किम के विवरण में बताया गया है कि गणना अधिकारियों के पास संस्कृत अर्थों में आने वाले छोटी जातियों ने अपने को क्षत्रिय या वैश्य जैसे ऊँचे वर्णों में दर्ज करने की प्रार्थना की थी।

से हुए व नी राजनीतिक कारणा से या युद्ध से, कभी प्रशासित कारणा से, जैम मुगला या अंग्रेजा के राज्य मे किसी जाति विशेष का राजस्व उगाटने का काम मिला, इससे उनकी प्रतिष्ठा बढ गयी । मगर जाति-व्यवस्था ने मेकडा वर्षों व इन परिवर्तना को बेला, बाहर स आने वाले नये तत्वा का, नए विचारो को, और नए विश्वासो को पचाया और आज भी यह ऐसी वास्तविकता है, जिसकी उपक्षा भारत की कोइ भी राजनीतिक व्यवस्था नही कर सकती ।

अराजनीतिक समाज

जाति-व्यवस्था पर ऊपर जा विचार किया गया, उसके पुराने भारत में समाज और राजनीति क परस्पर सम्बन्ध क एक महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश पड़ता है । इस पद्धति के द्वारा भारत में एक परिवर्तनशील और अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था तथा एक अत्यन्त स्थिर और पक्की समाज-व्यवस्था में एक हीता सामन्तव्य स्थापित किया गया । यह समाज-व्यवस्था (जाति-प्रथा) अधिकतर एक या अनेक गावा तक सीमित होन हुए नी स्थिरता तथा सुरक्षा प्रदान करती थी । दूसरी ओर राज्यतन्त्र विज्ञान क्षेत्र, विपुल सैन्यशक्त एवम् राजमहिमा से भडित हुए हान भी अस्थिर और अव्यवस्थित रहता था । जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा, भारत की एक बड़ी विफलता यह थी कि वह एक स्थिर बे-द्वीय राज्यतन्त्र की स्थापना न कर सका । इस दृष्टि से भारत की परंपरागत समाज-व्यवस्था अराजनीतिक ही कहो जाएगी ।

इसका अर्थ यह नहीं कि पुराने जमाने के भारत में राजनीति थी ही नही । गावा में राजनीति चलती थी, लेकिन दूसरी तरह की । यह राजनीति गाव की मुखियागिरी और दलबद्विया का था, और इसका आधार कुटुंब और बिरादरी होती थी । दूसरी राजनीति देश या प्रदेश के शासन या राज्य व्यवस्था में संबध रखती थी जिसमें अप्रत्याशित उत्पत्ति फेर हुआ करता था । शासन या राज्य का दमल गावा के मामलो मे होता था, यह झगडो का निपटारा करता था और जातियो का पद-पर्याय में समय समय पर परिवर्तन में भां इसका हाथ रहता था । इस प्रकार की व्यवस्था विभिन्न समूहो क परस्पर संबधा का नियंत्रण तो करती थी, किन्तु यह एकतापद्ध राजनीतिक ढांचे का निर्माण न कर सकी ।

स्थानीय एकता

इस प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था ने पुगने भारत में एक विशिष्ट प्रकार के आचार, प्रचलन विचार और मूल्यो का जन्म दिया, जो उहा से गति भी ग्रहण की । इससे स्थानीय एकता की दृष्ट शावना उत्पन्न हुई । इस एकता का दो रूप थे — एक प्राथमिक समूह के प्रति निष्ठा, अर्थात् अपने परिवार

और सबधियों का साथ देना और दूसरा इससे बड़े समूह, अर्थात् गाव, कबीले या जाति के प्रति निष्ठा। इस बड़े समूह का अधिनार और व्यवहार के प्रतिमान उस पर लागू होने के और वह रह मानता था। प्रत्येक व्यक्ति का स्थान जन्म से ही उसकी जाति और कुल के द्वारा निश्चित रहता था। बड़े समूह में भी उसका स्थान, उसके परंपरागत पक्ष, जाति और गाव के प्रति उनके सबंध और परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारी, के द्वारा निश्चित रहता था।

उसने कृतव्य भी सुनिश्चित थे। समाज ने उसे जो जिम्मेदारियाँ सौंपी थीं उनका पूरा करने के बदले उसे सुरक्षा मिलती थी। व्यक्तिगत कमजोरियों और विशिष्टता का समूह स्थान रखता था। समूह की स्थिति पर ही उसकी स्थिति निर्भर थी। उसी के साथ बट्ट उठती या गिरती थी। इस प्रकार समूह के अंतर्गत प्रकृतियों के पारस्परिक गान्धर्व एवम सहयोग का आधार निर्मित होता था। प्राथमिक समूह दानी परिवार और सबधियों के अलावा बड़े समूह या समाज से भी सबंध निश्चित थे। मध्यवर्ती समूह और नेता, जिस पंचायत राजस्व उगाहने वाला अधिकारी, गाव का मुखिया या पटेल और गाव के दम्तकार, जमींदार और बास्तकार, बनिया, धावी, भगी आदि विभिन्न वर्ग या व्यवसायी समूह भी अपना अपना काम करते थे। जिसका क्या क्या करना है यह किसी किताब में नहीं लिखा था फिर भी सबका मानम था। सामाजिक वर्तन बहुत मजबूत थे क्योंकि ये गून के रिश्ते पर आधारित थे, जो मनुष्य के सबसे मजबूत बंधनों में हैं। सामाजिक आचार या व्यवहार इन प्रकार रिवाज या परंपरा पर आधारित था। शताब्दियों तक राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारत में ऐसी स्थायी राजनीतिक व्यवस्था न कायम हो पाई, जिसे भारतीय जनता अपना सकती, इस कारण भारतीय समाज में छोटे छोटे समूहों का प्राधान्य स्थापित हुआ जो आज भी नष्ट नहीं हो सका है।

धर्म या नैतिक व्यवस्था

रीतिरिवाज और परिवार तथा समाज के वर्तन को धर्म या नैतिक व्यवस्था से और बल मिला। धर्म शब्द अंग्रेजी के "रिलिजन" से अधिक व्यापक है। इसमें व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक और धार्मिक सभी प्रकार के कृतव्य आ जाते हैं। इसमें यह सब आ जाता है कि किन स्थितियों में आदमी किस प्रकार व्यवहार करे, अपने रिश्तेदारों और अन्य लोगों के प्रति, बड़े और छोटे के प्रति, पति पत्नी के प्रति, गरीब, वृद्ध, असहाय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, जमींदार चमार, भगी, नौकर, धर्म, ईश्वर और स्वयं अपनी आत्मा के प्रति क्या व्यवहार करे। हर स्थिति का, हर व्यक्ति का निश्चित व्यवहार, धर्म है। सबके लिए और सब स्थितियों के लिए एक-सी नैतिक संहिता की कल्पना हिंदू जीवन पद्धति से मेन नहीं खाती। धर्म का अर्थ विभिन्न परिस्थितियों में सही व्यवहार है, यही सदाचार का आधार

के कारण इस व्यवस्था को बल मिला, क्योंकि इनके कारण देश में स्थिरता आई, उद्योग व गिराव को बढ़ावा मिला। मंडके और नहरें बनी, बला, साहित्य और धर्म व क्षेप में बड़े बड़े काम हुए। राजनीति और सांस्कृतिक उत्थप के इन युगा में ब्राह्मण का को शक्ति बढ़ी और मनुस्मृतिक साहित्य की समृद्धि में उसने बहुत योगदान किया। ब्राह्मण ही हिंदू समाज के नेता थे इसलिए इनके उत्थप ने हिंदू समाज-व्यवस्था की मजबूती बढ़ी।

उच्चका की भूमिका

गान और मनुस्मृति के प्रकार में ब्राह्मण की भूमिका अत्यंत महत्व की रही है। समाज में उच्चका स्थान सबसे ऊँचा था। यह परिवार का पुरोहित था, वही विद्या दान करता था, गान्धर्व, स्मृतियाँ और परंपरागत नियम और विधिविधान की वही व्याख्या करता था, पीढ़ी दर पीढ़ी यह पुरानी परंपरा और आचार विचार को जीवित रखता था। समाज के नेता, शिक्षक, स्मृतिगार और सामाजिक के रूप में ब्राह्मण का जो ऊँचा स्थान, प्रतिष्ठा और प्रभाव प्राप्त था, उससे विभिन्न जातियों के समूहों में बड़े अनेकार्थक हिंदू समाज का एक सामाजिक सामाजिक पद्धति, प्रतीक और परंपराएँ मिलीं। इस उच्चका की आंतरिक एकात्मता किसी शास्त्रीय सिद्धांत के बल पर नहीं, उनके विशिष्ट जन्म, शिक्षा-दीक्षा, समाज के नेतृत्व और इन कारणों से समाज में उच्चका उच्च स्थान और प्रतिष्ठा के बल पर थायम थी। उसकी प्रतिष्ठा ज्यादातर शास्त्र और दर्शन की व्याख्या में प्रकट होती थी। उसकी व्यवस्था या नियम का बहुत सम्मान किया जाता था। ऐसे बौद्धिक और शिक्षक का नेतृत्व के कारण सैकड़ों वर्षों तक हिंदू समाज आपस में घेरा रहा और सान सौ वर्षों के विदेशी शासन के धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व के घेरने को घेन सका।

सुधार और परिवर्तन

ब्राह्मणों ने हिंदू समाज को रखा की, किंतु उनमें कट्टरता और रुढ़िवाद की प्रवृत्ति भी आ गयी और वे समय के अनुसार आवश्यक परिवर्तन और सुधार की व्यवस्था न कर सका। यह काय और ने किया। इनमें क्षत्रिय जाति के बुद्ध और महावीर प्रमुख थे। इनके समय से लेकर आधुनिक काल तक धर्म सुधारकों की एक अटूट परंपरा चली आई है। धर्म-सुधार के इन आंदोलनों और इनके फल-स्वरूप स्थापित अगणित मतमतान्तरों ने भारतीय सभ्यता के संवर्धन में ही नहीं उसकी जीवित रखने में भी योग दिया है। इनसे हिंदू समाज की प्राणशक्ति बढ़ी है और उसे नई बातों और भिन्न विचारों को ग्रहण करने की सामर्थ्य मिली है। इससे हिंदू समाज के बुनियादी ढाँचे में मजबूती और लचीलापन आया है।

गामक जाग पुराहित वर्गों के प्रभाव से हिन्दू धर्म में जो कमकाड़ और आडंबर आ गया था उसमें विरुद्ध इन सुधारकों ने आवाज उठाई। इन आंदोलनों में आधुनिक काल के लिए सबसे महत्वपूर्ण भक्ति आंदोलन था। इस आंदोलन के नेता सत और भक्त थे जिनमें से अनेक बहुत गरीबी की जातियाँ के थे। ये सत देश के सभी भागों में हुए इनमें छोटे और गरीब लोग व स्त्रियाँ भी थी। इनमें मीरा वहाँ जसी राजरानी भी थी जो महता का छोटा भक्तों के साथ राह-वाट की खाक छानती फिरी। भक्ति-आंदोलन के फलस्वरूप अनेक नए पथ व संप्रदाय चले जिनमें बहुत बड़ी संख्या में साधारण जनता शामिल हुई। ऐसा ही एक पथ 'सिख' पथ था जिसने अत्याचारा का सामना करने के लिए सैनिक रूप धारण किया और जिसके जनसंख्या में भारत में आधुनिक अस्तित्व का प्रसार में बहुत योगदान किया है। भक्ति-आंदोलन के अनेक प्रवर्तक दक्षिण भारत में भी हुए जिनके उपदेश भारतीय मानस में जग मू। प्राथमिक सीमाओं का नाश और सभ्यता के बजाय लोकभाषा का सहारा देने के कारण भक्ति-आंदोलन ने सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता की भावना पैदा की जो विरोध के आंदोलन के लिए दुर्लभ बात है। जात-पात का विनाश करके और जनपथ की समानता पर जोर देकर भक्ति-आंदोलन ने आधुनिक युग के समानता के सिद्धांत का रचना तैयार किया।

इस प्रकार अपनी समाज व्यवस्था पुनर्गठित और महाकाव्यों के आदर्श ब्राह्मण वर्ग के नतत्व और महान धार्मिक आंदोलन के कारण हिन्दू धर्म में एकता और निरंतरता का भावना बनी रमा। भारत एक राष्ट्र बन ही न बन सका हो कि उसने एक समाज और सभ्यता का निमाण अवश्य किया और भारतीयों में यह भावना काफ़ी गहरी थी। इस गहरी एकता और आत्मबोध या अस्मिता के बिना अग्रज गामका और राष्ट्रीय नेताओं की राजनीतिक एकता की स्थापना आसान न होगी। दूसरी ओर इस एकता की भावना के बावजूद और इसके विशिष्ट स्वरूप के कारण पूरे हिन्दू युग के दौरान समाज और राजनीति का पाथक्य बना रहा। इसका अर्थ यह था कि राष्ट्रपरिवर्तन का प्रभाव समाज के जीवन पर ज्यादा नहीं पड़ा था। साम्राज्य का उत्थान और पतन होता रहा लेकिन भारतीय समाज का अधिकांश अपने रास्ते पर चलता रहा। एक के द्वितीय सत्ता और निष्ठा की स्थापना का कार्य अधूरा ही रहा।

मुस्लिम आक्रमण और उनके लंबे शासन ने इस व्यवस्था में गड़बड़ी जरूर पदा दी, किंतु बुनियाती तौर पर वह इस बदल न सका।

मुस्लिम प्रभाव

मुसलमानों (जैसे अफगान मुगल) के छिटपुट आक्रमण के बीच शताब्दियों में सिंध में गुरु हुए। १० वीं और ११ वीं शताब्दी में ये आक्रमण तेज हो गए और

१२०६ ई में दिल्ली सल्तनत कायम हुई। मुस्लिम सत्ता का चरम उत्कृष्ट मुगल साम्राज्य (१५२६ ई - १७०७ ई) में हुआ। १८५७ तक नाम के लिए मुगल बादशाह कायम रहे। सन् १८६२ में मुगल शासन का विधिवत अंत हो गया।

इस युग की चार बातें ध्यान योग्य हैं। पहली यह है कि मुस्लिम राज्य बुनियादी रूप में सैनिक शासन था, यद्यपि इमने देश में नागरिक शासन की भी अच्छी व्यवस्था की। मुस्लिम शासन काफी समय तक कायम रहा फिर भी यह सारे देश को एक राजनीतिक सत्ता के अधीन न ला सका। राज्य के विस्तार के लिए निरंतर युद्ध होते रह, जिससे बड़ी बरबादी और अन्यवस्था पैदा हुई। यद्यपि १६७७ से लेकर १७०७ तक मुस्लिम सल्तनत काफी मजबूत और स्थिर रही, किंतु इसके साथ ही गद्दी के लिए पड़यन और लड़ाइयां जारी रही और बादशाहत को राज-पूना और मराठा के अलावा विद्रोही मुस्लिम सूबेदारों की चुनाती का सामना करना पड़ा।

दूसरी बात यह है कि मुसलमानों का मजहब और समाज-व्यवस्था हिंदुओं से बिल्कुल भिन्न थी। यद्यपि अधिकांश मुस्लिम शासक चाहते थे कि दोनों मजहब साथ साथ रहें, शास कर अकबर हिंदू मुस्लिम में का सबसे बड़ा समायक था, फिर भी मुस्लिम मजहब अपनातेवालों को फायदा होता था और मुस्लिम धर्म-प्रचारक, सूफिय और मौलवियों को धर्मांतरण कराने की खुली छूट थी। खास कर उत्तर भारत में मुस्लिम धर्म का काफी प्रचार हुआ। बीच बीच में कटकर मुस्लिम शासकों के राज में धार्मिक अत्याचारों की लहर उठती थी और इनके कारण दोनों मजहबों में झगडा और नफरत फैलती थी। भारत की परंपरागत धर्म-सहिष्णुता को इससे धक्का लगता था। और दोनों मजहबों में सामाजिक व्यवहार और एकता स्थापित न हो सकी। फिर भी दोनों मजहबों ने एक दूसरे को प्रभावित अवश्य किया। मुसलमानों में भी खास खास पंगुवालों जातियां बन गईं और इससे वे हिंदुओं के ज्यादा नजदीक आए-खास कर मुस्लिम सत्ता के कमजोर होने के बाद। दूसरी ओर हिंदुओं ने भी मुसलमानों के बहुत से तौर तरीके, कला-कारीगरी, शासनपद्धति, दरबारी शिष्टाचार आदि अपनाए। मुगल शासन में राजपूत सेनानायकों और हिंदू दीवानों का बड़ा सम्मान था। शहर मुस्लिम साहित्य, स्थापत्य और कला के केन्द्र बन गए और शिक्षित हिंदुओं ने इन सम्प्रति में योगदान किया। लेकिन इसके बावजूद दोनों धर्म और समाज एक दूसरे से अलग रह, क्योंकि मुस्लिम सत्ता की नांव धर्मपरिचयन और सैनिक बल के ऊपर कायम थी।

तीसरी बात भारत में मुस्लिम शासन पद्धति के विकास से संबंध रखती है। इन्होंने एक विशिष्ट राजनैतिक पद्धति एक आधिकारिक केन्द्र और व्यापक एवं काय-कुशल शासन-प्रणाली स्थापित की जिसमें केन्द्रीय सत्ता के अंतर्गत सूबों और जिलों में राजस्व की वसूली और प्रशासन के लिए बड़े और छोटे अधिकारीतन्त्रों का

गा। इनका पद सैनिक होता था और इनको शासन में बाकी स्वतन्त्रता रहनी थी। इससे अक्सर ये अपनी ताकत बढ़ा कर खुदमुस्तार बन बैठते थे। अंग्रेजों ने मुस्लिम शासन-व्यवस्था को बहुत ही बातों का जारी रखा, लेकिन उन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। यह था सैनिक शासन को नागरिक शासन से अलग कर देना और नागरिक या दीवानों शासन में अधिक एकरूपता लाना। ये दोनों बात अंग्रेजों की राजनीतिक परंपरा में थी।

चौथी बात यह है कि मुस्लिम प्रभुत्व और शासन व्यवस्था का प्रभाव गांवों में रहने वाली जनता की रहन सहन, रीति रिवाज और उनकी सम्पदा पर बहुत कम पड़ा। अधिकतर पुराना सामाजिक और व्यावसायिक ढांचा बचपन रहा। गांव का प्रबंध पंचायतों के हाथ में बना रहा। नए शासन और मालगुजारी के बंदोबस्त से सरपंच होने के कारण कुछ जातियां और वर्गों की पद-मर्यादा घटी बढ़ी किन्तु इस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन पहले भी होता रहता था। इसने समाज और राज्य के ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होता था। वैदेशीय सत्ता स्थानीय सम्पदाओं के अधिकारों पर भी कोई दखल न देती थी। गांवों में रहने वाली मुस्लिम जनसंख्या ने भी इस पद्धति का अपना लिया और उनमें भी अलग अलग पैगों के हिस्से थे जातियां और पंचायत बन गई। मुसलमान शासकों ने मालगुजारी के बन्दोबस्त तहसील आदि के लिए प्रशासन की गांवों अच्छी व्यवस्था का विकास किया, फिर भी यह देश की जड़ तक या गांवों तक जनता तक न पहुंच सकी। परदेसी होने के कारण मुस्लिम शासन ज्यादातर शहरों में फैला रहता। दूसरे स्थानीय गांवों को जमीन मालिकों से जमीन हंडों की कि उन्होंने वैदेशीय शासन को अपने ऊपर हावी न होने दिया। तीसरे मुसलमानों ने शत्रुता जैसी पुरानी शासन जाति का विकास न किया। यह साक्षात् तिराज या कर लेकर, सूबा और जिला का शासन और पानी प्रबंध जमींदारों या सूबेदारों का मौखिक दत्त थे, जो समय समय पर बदला करते थे।

हिंदू धर्म पर प्रभाव

मुस्लिम शासन की स्थापना में हिंदू प्रजातंत्र का आंतरिक गुणन भग्न हो गया। देश में जो हिंदू राज्य कायम थे, गायक वंश और पंचिच म, उनमें गुणन बर्धमान के अंतर्गत युद्ध हो रहा था। इन युद्धों से और इनके फलस्वरूप होने वाली गुटबाज, अन्धकार मंत्रियों का तादृश आदि से गांवों तक जाया गया रहती था। राजा में अन्धकार और देश में अस्थिरता और भय बसाकर बना रहता था। अक्सर हिंदू समाज का शीर्षक अन्धकार ही बना और उनके धार्मिक या सामाजिक नेता अन्धकार-वर्धन या बंटे। इस स्थिति में जब हिंदू समाज की रक्षा करने वाली राजनीतिक शक्ति न रही और अन्धकार बरपाया गया। उस कुछ महाराजों ने।

परानजित और लाछिन हिंदू जाति ने भगवान का सहारा लिया और परनोक पर ध्यान लगाया। उसकी जीवनी शक्ति, दूसरा का आत्मसात कर लेने की क्षमता मारी गयी, जल-पात के ढाँचे में बड़ी कठोरता आ गयी और उसकी दृष्टि निराशावादी और भाग्यवादी हो गई।

मुस्लिम प्रभुत्व का घक्का बड़ा जबदमन या किनु इमसा प्रभाव स्थायी न रहा, सिवा इसके कि देश भर में मुसलमानों की संख्या बहुत बढ़ गई। गहरी प्रभाव या घक्के को झेलने का हिंदू समाज का अपना तरीका है। या तो वह बाहरी तत्वा को अपने भीतर पचा लेता है, या जहां ऐसा संभव नहीं है, यह उसका सीधा मुकाबला करने के बजाय अपने हाथ पांव सिकाड़ कर, उसके वेग को अपने आप खतम होने का इंतजार करता है। २ ब्रिटिश प्रभाव का भी उसने इसी प्रकार झेलने का प्रयत्न किया। मुस्लिम घक्के में जो अव्यवस्था और आंतरिक अगाति फैली थी उसको अंगरेजी राज ने अपनी सुव्यवस्थित शासन प्रणाली में दूर दिया।

मुस्लिम राज के स्थायी प्रभावों में एक ही सांप्रदायिक समस्या। मुसलमानों का प्रभुत्व के समय दोनों संप्रदायों के नेताओं में शत्रुता और द्वेष का भाव था, यद्यपि साधारण जनता एक दूसरे के पास आ रही थी। अंग्रेजी राज्य में स्थिरता आई, और हिंदू मुसलमान साथ साथ रहना सीख गये। उनके अपने अपने काम धंधे और प्रभाव क्षेत्र बन गए और अनेक क्षेत्रों में वे साथ मिल कर काम करने लगे। लेकिन अंगरेजी राज के उत्तराध में राष्ट्रीय स्तर पर विरोध और अन्याय पैदा हुआ और सांप्रदायिक संबंध बिगड़ गए। इसी में सांप्रदायिक अन्याय का समस्या पैदा हुई। इसका अध्ययन इसी अध्याय में हम करेंगे।

मुस्लिम प्रभुत्व का दूसरा परिणाम उसका पतन के बाद हिंदुओं में उसकी प्रतिक्रिया या हिंदू जागरण के रूप में प्रकट हुआ। इस जागरण में अंग्रेजी राज का भी योग था और पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता का भी प्रभाव था। अंग्रेजी शासन में शांति और स्थिरता कायम हुई और पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार हुआ। इसी के साथ साथ सम्वृद्ध अध्ययन का भी बल मिला और देश की प्राचीन सभ्यता के लिए गौरव का भाव बढ़ा। इसमें सभ्यता का मुरावीय विद्वानों ने भी योग दिया। हिंदू पुनर्जागरण के साथ साथ पाश्चात्य सभ्यता का भी प्रभाव बढ़ा। मुसलमानों जमाने की अव्यवस्था और दमन के बाद ये दोनों घाटाएँ हिंदू जागरण और पाश्चात्य सभ्यता का प्रचार, सुविधा और आशा का गंगा स्वर आदि।

अव्यवस्था का युग

कृत मिला कर मुस्लिम युग का प्रभाव बहुत गहरा या व्यापक नहीं रहा।

२ राजकीय वरों और जीविके की ओर से निरंतर बलि देने से ही इन प्रभुत्व का पता की है। शासकीय वर, 'हिंदू सौतेली' का संश्लेषण (पूना १९६१) 'दिल्ली' का संश्लेषण 'अरु सम' (दुर्गार, १९६६)

सामाजिक परंपरा या अधिकांग जनता के मन में इसरी जड़ गहरी न जा सकी।³ किंतु सामाजिक ढांच, शासनात्मक, कला व साहित्य तथा उच्च वर्ग की रहन सहन और सहजीव या शिष्टाचार पर इसका प्रभाव प्रयत्न है। वास्तव में मुगल साम्राज्य का अंत १७०७ में औरंगजेब की मृत्यु के समय हो गया और इसी समय से यूरोपीय गतिविधियाँ ने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। पुरी १८ वीं और १९ वीं शताब्दी के प्रथम भाग में राजनीतिक गड़बड़ी कायम रही, भारतीय गतिविधियों का पता जाय यूरोपीय गतिविधियों का उत्थान होना रहा। १५० वर्ष के मुगल शासन में केन्द्रीय सत्ता की शक्ति बढ़ी किंतु उसे लगातार चुनौतियाँ का सामना करना पड़ा और अंत में गंगठा ने प्रतिरोध ने उसे जबर कर दिया। उसके कमजोर पड़ने ही उसके प्रांतीय सूत्रेदारों और जागीरदारों ने भी मिर उठाया। इस प्रकार मुगल युग के अंत में भारत में बाई-बंदीय शक्ति न रही और वह आपन में लड़ने बाँट छूटने राज्यों में चला गया। इस स्थिति में यरासीय गतिविधियों की धन आई और मुगल साम्राज्य के गहरे पर अंग्रेजी साम्राज्य कायम हुआ।

ब्रिटिश प्रभाव

भारत में पश्चिमी प्रभाव कई चरणों में आया। (१) पहला चरण में १५ वीं, १६ वीं और १७ वीं शताब्दी में पुनर्गठनी, डच फ्रांसीसी और अंगरेज व्यापारियों ने हिंद महासागर में प्रवेश किया और अपनी व्यापारी कौटुह्य का बन्धित कायम का। (२) ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों का हरा कर (यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध से नाम उठा कर) महा अपनी प्रधानता कायम की। इसके बाद कंपनी ने जबर मुगल साम्राज्य से व्यापक व्यापारी गुंथियाएँ बड़े बड़े क्षेत्रों पर आधिकार और प्रशासनिक अधिकार प्राप्त किए। इसके बाद उसने कुछ भारतीय राज्यों से सहायक संधि कर के आर एव एव करके मराठा, टीपू सुलतान और अंत में सिंगा को हरा कर, भारत पर अपनी प्रभुता कायम की। (३) १८१७ के विद्रोह के बाद कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश सरकार का सारा शासन (रानी और पालामेंट) स्थापित हुआ। वास्तव में कंपनी और ब्रिटिश सम्राट के शासन को एक ही समझना चाहिए। फिर भी १८५७ के विद्रोह से एक नया युग शुरू होता है।

१८५७ का विद्रोह

१८५७ का विद्रोह न तो मात्र ब्रिटिश सेना के हिंदुस्तानी सिपाहियों का है इसमें कुछ अपवाद भी हैं। उत्तर पश्चिम भारत में जहाँ सभ्यता की परंपरा बहुत गहरी नहीं गई थी, इस्लाम के हिंदू सरहजनों को जड़ कर दिया और आज भी यहाँ मुस्लिम परंपरा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। देखिए छी आर चानन, 'सरहजान' नेशन, वेस्टर्न इंडियन रेंड इंडियाज नार्थ वेस्ट इंडियन वीकली, भाग १३, पृ. ९, भाग ४, १९६१

गदर था न यह स्वतन्त्रता का सपना था । ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने माल-गुजारी, अदालत, कानून, शासन और आर्थिक संगठन, व्यापार आदि की जो नई व्यवस्था चालू की थी, उससे नए अधिकार प्राप्त वर्गों का उदय हुआ और पुरानी सामंती व्यवस्था की चले हिल गई । इसकी गहरी प्रतिक्रिया १८५७ के विद्रोह में हुई । इस विद्रोह में अधिकतर उत्तर भारत के मुस्लिम, नवाब, जागीरदार और तालुकेदार वर्ग के लोग शामिल थे, जिनकी शक्ति और प्रभाव फिरंगियों ने छीन लिया था । अवश्य ही इस विद्रोह में अनेक हिंदू राजा और तालुकेदार भी थे । विद्रोह विफल रहा और अंग्रेजों ने बड़ी कूरता से विद्रोह का दमन किया, इससे अंग्रेजों के प्रति बहुत कटुता, खासकर मुसलमानों में पैदा हुई । अंग्रेजों ने भी १८५७ के तुरंत बाद मुस्लिम विरोधी रुख अपनाया । फिर भी इस विद्रोह का कितना प्रभाव अंग्रेजों के मन पर हुआ, उतना भारतीयों पर नहीं । उत्तर भारत के अलावा दोष भाग में इसका प्रभाव नहीं पड़ा था । इस विद्रोह से अंग्रेजों के मन में यह भाव आया कि उनका राज्य स्थायी नहीं है और वे भारतीयों पर शक और अविश्वास करने लगे । भारत में सुधार और नई व्यवस्था और सम्मति लाने में उनको उत्साह न रहा । भारतीयों के मन में भी १८५७ की याद बनी रही और वे भी यह समझने लगे कि अंग्रेज अजेय नहीं हैं । यद्यपि १८५७ का विद्रोह पुरानी सामंती व्यवस्था की पराजय का द्योतक था फिर भी उससे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के आंदोलन की प्रेरणा मिली । १८५७ के विद्रोह से अंग्रेजों ने भारतीयों की धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ न करने का मकसद सीखा और सन १८५८ में मलका विक्टोरिया की घोषणा में यह आश्वासन दिया गया कि भारतीय जनता की पर-पराया का सम्मान किया जाएगा और शासन को उदार बनाया जाएगा । मगर कितनी ही भारतीय जनता को सन्तुष्ट करने की कोशिश की उतना ही उसका असतोष बढ़ता गया । १८५७ के बाद अंग्रेजी शासन ज्यादा अच्छा और कुशल हो गया किन्तु जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया और उसकी जड़ें गहरी नहीं जा सकी । १८५७ के विद्रोह ने अंग्रेजी राज्य के विरोधाभास को स्पष्ट कर दिया । यद्यपि इसका प्रभाव प्रातिरारी था, फिर भी इसने प्रतिप्रियावाद और विद्रोह को जन्म दिया ।

अंग्रेजी शासन का प्रभाव

अंग्रेजी राज का प्रभाव प्रातिरारी था परन्तु वह गहरा न था क्योंकि वह विदेशी था । फिर भी यह बड़ा शक्तिशाली और स्थिर था । अगले अध्याय में हम भौतिक-वैज्ञानिक या विदेशी शासन के प्रभाव का विश्लेषण करेंगे । यहाँ हम देखेंगे कि भारत की उसकी क्या देन रही ।

राष्ट्रीय सत्ता की स्थापना — अंग्रेजों ने पहली बार मारे दंग में एक टिकाऊ

के द्वीय शासन स्थापित किया, जिसके जतगत बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से मुक्ति मिली। यद्यपि देश के एक तिहाई भाग में देशी राजाजा का राज्य कायम रहा, पर वे भी पूरी तरह ब्रिटिश प्रभुसत्ता के अधीन थे। यह बहुत बड़ी सफलता थी और अंगरेजी राज्य ने भारत में और जो कुछ किया, उसकी यही बुनियाद थी। भारत की राष्ट्रीय एकाता भी इसी बुनियाद पर निर्मित हुई।

कानून और व्यवस्था

मुस्लिम कानून में निरंतर लडाइयाँ के कारण देश में बड़ी अशांति और भय छा गया था। अंगरेजी शासन की स्थापना के बाद शांति और कानून की व्यवस्था हुई। इसलिए बहुत से लोगो ने और लेखकों व कवियों ने भी अंगरेजी राज का स्वागत किया।

प्रशासन और "पाय की नई पद्धति — अंगरेज पहली बार सारे देश को एक सत्ता के नीचे लाने में सफल रहे। मुगलों के समय में जिस तरह देश सूबों और जिलों में बंटा था, अंगरेजों ने उसको कायम रखा और उसे एक नया रूप दिया। सबसे महत्त्व का सुधार उन्होंने यह किया कि इसको उठाने नागरिक या अर्सेनिक रूप दिया। जिले का अधिकारी केंद्रीय शासन का नौकर था। उसे कोई सैनिक अधिकार न था, न वह प्रजा का शोषण करके अपना अधिकार बढ़ा सकता था। अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक ढंग की नौकरशाही या अधिकारीवर्ग कायम किया, जिसमें नियुक्ति योग्यता के आधार पर खुली परीक्षा लेकर होती थी। ब्रिटेन से भी पहले भारत में यह तरीका लागू किया गया। इसके फलस्वरूप आई सी एस (इंडियन सिविल सर्विस) की सृष्टि हुई। पहले इसमें सब अंगरेज अफसर होते थे, बाद में भारतीयों को भी लिया जाने लगा। इनका चुनाव बड़ी सावधानी से होता था और योग्यता तथा विद्या-बुद्धि के साथ ऊँचे कुल का भी विचार किया जाता था इन लोगों का जिला में अमन कानून बनाए रखने का, राजस्व वसूली का और "पाय का भार सौंपा गया।

आई सी एस के आदमी जिले के शासक ही नहीं थे वे "पाय भी करते थे। धीमे धीमे ब्रिटिश "पाय के सिद्धान्त, नियम नज़ीर और प्रक्रिया पर आधारित अदालतों की नई व्यवस्था स्थापित की गई। इसके बाद जनता की भलाई के उद्देश्य से सामाजिक और आर्थिक प्रशासन का भी ढाँचा खड़ा हुआ और अत्यधिक अन्धश्रद्धा विषमता का घटाने के लिए कुछ सुधार भी किए गए।^४ इससे शासन में नए विचार और नई दृष्टि आने लगी जो बदलते हुए समय के ज्यादा अनुरूप थी।

^४ यह धारणा ठीक नहीं है कि भारत में अंग्रेजी शासन का महत्व केवल शांति और कानून की व्यवस्था करने से था। इस शासन ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी बहुत से काम उठाए जिनका सभी वर्गों पर प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता के बाद जो काम हुए हैं उनमें से अनेक की शुरुआत अंगरेजी राज के समय में ही हो चुकी थी।

मध्यमवर्ग का जन्म—१८३५ में मैकाले के प्रसिद्ध नोट के फलस्वरूप ब्रिटिश राज ने अपना सबसे महत्वपूर्ण निणय किया। यह था अंग्रेजी माध्यम से हाईस्कूल और कालेजों में शिक्षा देने का। इसके पहले भी पाश्चात्य सभ्यता से आकर्षित होकर अनेक व्यक्ति अंग्रेजी सीखने और अंग्रेजी के काव्य, साहित्य, कानून और विज्ञान के प्रयास को पढ़ने लगे थे। अब ऐसे लोगों की समस्या बहुत बढ़ गई। ध्यान रहे कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने का फैसला जनता की इच्छा के खिलाफ नहीं किया गया। राजा राममोहन राय और अन्य बहुत से भारतीयों ने इसकी मांग की थी। इस शिक्षा ने अंग्रेजी पढ़े लिखे एक नए वर्ग की सृष्टि की, जो पाश्चात्य सभ्यता और राजनीतिक विचारों से प्रभावित था और अंग्रेजी अफसरों के नीचे काम करने को तैयार था। बहुत से अंग्रेजी शिक्षितों ने वकालत का पेशा अपनाया। कुछ अध्यापक हुए और कुछ व्यापार, उद्योग में गये। थोड़े में भारतीय उच्च शिक्षा प्राप्त करके आई सी एस बनने की आकांक्षा में इंग्लैंड भी पहुँचे। अनेक भारतीयों ने डाक्टरी और पत्रकारी की सृति शुरू की और कुछ ने राजनीति में प्रवेश किया।^५

यह भारत का नया मध्यवर्ग था। इस वर्ग के जरिये अंगरेजों ने भारत पर राज किया। इसी वर्ग के जरिये व्यक्ति की स्वतंत्रता और वैधानिक शासन के विचार फैले और इसी वर्ग से अंग्रेजी राज को चुनौती देने वाले राजनीतिक नेता उठे। इस वर्ग का देश पर व्यापक प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी शिक्षा की उपज और स्वतंत्रता, लोकतन्त्र तथा समाजवाद के विचारों से प्रेरित यह वर्ग ब्रिटिश राज की सबसे बड़ी विरोधता है। इसी वर्ग ने अंत में अंगरेजों से सत्ता ग्रहण की और भारत को स्वतंत्र लोकतन्त्री राष्ट्र घोषित किया।

सामाजिक सुधार—

भारत में आधुनिकता का प्रचार एक छोटे से अंगरेजी पढ़े लिखे वर्ग के द्वारा हुआ। इसी से देश की एक बहुत बड़ी समस्या—शिक्षित उच्च वर्ग और साधारण जनता में दूरी की समस्या—पैदा हुई। आगे हम इस पर विचार करेंगे। इस बीच यह बात ध्यान में रखने की है कि इसी वर्ग के साथ साथ भारत में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों की ओर अंत में अंगरेजी राज से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी उठी।

सबसे पहले हिंदू समाज की कुरीतियों को दूर करने का आंदोलन उठा। इस विषय में उदार अंगरेज शासकों के विचार भारतीय नेताओं से मेल खाते थे। वास्तव में ये सुधारक हिंदू समाज की बुराईयों को दूर करके उसके प्राचीन गौरव

^५ इस मध्यवर्ग के उदय के ऐतिहासिक विवरण के लिए देखें—बी बी मिश्र, 'द इंडियन मिडिल क्लासेज—देयर ग्रोथ इन माधुनिक इंडिया' (लंदन, १९६१)

का पुनरुद्धार करना चाहते थे। सुधार के सबसे पहले कदम लाड विलियम वैटिक के शासन में उठाए गए जो १८२८ से १८३५ तक यहाँ के गवर्नर जनरल रहे। इन सुधारों के लिए राजा राममाहन राय जैसे भारतीय सुधारका ने जोर दिया था। इन सुधारों में सती प्रथा और नवजात बच्चा की हत्या का अंत और ठगी का उन्मूलन था। लड़कियाँ का वध और नरबलि को अपराध घोषित कर दिया गया। अपराधों के फैसलों का काम पचायतों के हाथ से ले कर नवस्थापित अदालतों को सौंप दिया गया। स्त्रियों पर अत्याचार पर भी राक लगाई गई।

१८५७ के विद्रोह से अंगरेज शासकों और भारतीय सुधारकों के जोश पर रोक पड़ी। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में चल गया और उसने लोगों के नीति विवाज और आचार विचार में दखल न देने की नीति अपनाई। अब से यह नीति चली कि सुधार सरकारी कारवाई के द्वारा नहीं, स्वयं भारतीय नेताओं के प्रयत्नों से किए जाएँ। यद्यपि पहले भी सुधार की कारवाई, भारतीय नेताओं की माँग पर ही की गई थी परन्तु अब सामाजिक और धार्मिक सुधार के क्षेत्र में सरकारी कारवाई उत्तरोत्तर कम होनी गई।

विदेशी शासन का रवया

ध्यान रखना चाहिए कि भारत में विदेशी सरकार का कार्यक्षेत्र क्रमशः सिकुटता गया। विदेशी शासन के नातिकारी प्रभाव के बावजूद उसमें भारतीय समाज के पुनर्निर्माण की न तो क्षमता थी और न ही इच्छा। इसने आधुनिक नौकरागारी और कुशल शासन-तंत्र की स्थापना की तथा लोक-न्यायणकारी शासन के भी बीज डाले, किंतु व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों पर इसका रुख जुदाएँ और दकियानूसी ही रहा। और यह ऐसे समय जब समाज में बड़ी उथल-पुथल हाँ रही थी। १९ वीं सदी के उत्तरार्ध और २० वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ी मगर नेती की पैदावार उत्तनी नहीं बढ़ सकी। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय भी नहीं बढ़ी, बल्कि, कुछ गिर गई। पुराने घरेलू उद्योगधंधे, नई मिलों और बड़े कारखानों के कारण बरबाद हो रहे थे। इन सब से देश में अभाव और कष्ट बढ़ा। इसी अवधि में शहरों का विस्तार हुआ रेल और डाक-तार का सुविधाएँ बना, विचारों के प्रचार के साधन अखबार और छापाखानों की संख्या बढ़ी मध्यवर्ग का विकास हुआ और नई संस्थाएँ तथा संगठन बने। इस प्रकार समाज के पुनर्निर्माण की जमीन तैयार हुई।

देश में एन और अभाव और कष्ट बढ़ रहे थे तो दूसरी ओर उनको दूर करने के अवसर भी प्रस्तुत हो रहे थे, किंतु अंग्रेजी शासन ने कुछ न करने की नीति अपनाई। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि वह राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं सामाजिक क्षेत्र में भी, अकम्प्य और अनुदार है। ब्रिटिश सरकार का यह सीमावर्ष था कि

जनता के पक्ष और धर्मोप ने विद्रोह का मार्ग न पकड़ कर राष्ट्रीय आन्दोलन का मार्ग पकड़ा। ब्रिटिश सरकार ने तब सामाजिक मर्मन्त्राज्ञा की उपाय की, उन्हें मुनसिफों का भार १९८७ के बाद भारत की स्वतंत्र सरकार पर आया।

आधुनिकता के प्रयास

आधुनिकता के प्रयासों में राजा राममोहन राय (१७७४-१८३३) प्रमुख थे। ये अरबी, फारसी और मराठी का विद्वान थे तथा ग्रीक और हिब्रू भाषाएँ भी जानते थे। अंग्रेजी उठाने बाद में पढ़ी। वे सूफी मत और वास्तव में ईसाई धर्म से प्रभावित हुए। उन्होंने हिन्दू धर्मग्रन्थ, और ईसाई धर्म की अच्छी समझ और पारस्विक उदारवाद का तत्त्वा का मिलान का प्रयत्न किया। वे जातिपति और स्त्रियाँ का गाय दुग्धवहार के आलोचन थे। वे अंग्रेजी शासन के अपभक्त न थे, किंतु यह मानते थे कि उन्हीं भारत की जान हुआ है। उन्होंने अपने देशवासियों के बीच पश्चिमी उदारवाद के विचारों और राजनीतिक सिद्धांतों का प्रचार किया। मगर उनका सब से बड़ा काम धार्मिक सुधार में हुआ। उन्होंने ब्राह्म समाज की स्थापना की, जिसमें धार्मिक और उदार सामाजिक विचारों का मेल हुआ। ब्राह्म समाज ने भारत के बौद्धिक और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और उसकी दृष्टि देखी भारत में अनेक धार्मिक और सामाजिक संस्थाएँ स्थापित हुई।

संस्था और संगठनों की वृद्धि

राममोहन राय और ब्राह्म समाज के बाद भारत में विशेष कर १९ वीं सदी के उत्तरार्ध में अनेक समाज और धर्मसुधारक हुए और नई संस्थाएँ कायम हुईं। सब का नाम देने की यहाँ जगह नहीं। इनमें सन १८४८ में स्थापित ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन जैसी राजनीतिक संस्थाएँ भी थी। वक्तव्य, बर्बर और मद्रास में प्रेसिडेंसी असासिएशन स्थापित हुए। सन १८७६ में मुरदनाथ दाजी ने वलकटा में इंडियन असासिएशन स्थापित किया। सन १८८३ में इंडियन असोसिएशन ने एक नेशनल कांग्रेस (राष्ट्रीय सम्मेलन) का आयोजन किया। इससे एक अचिन्त भारतीय संस्था बनाने का विचार पैदा हुआ जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय (इंडियन नेशनल) कांग्रेस का जन्म हुआ।

दूसरा बड़ा सामाजिक संस्थायाँ का हैं। इनके संगठनरुत्ताओं का विश्वास था कि स्वराज्य के पहले समाज का पुनर्निर्माण जरूरी है जिससे लोग स्वशासन के योग्य बनें। इस आंदोलन के नेताओं में राजा राममोहन राय ईश्वरचंद्र विद्यासागर और श्रीनिवास अयंगर जैसे लोग थे। जस्टिस महादेव गोविंद रानडे भी समाज की कुरीतियों के बड़े आलोचन थे। इन्हीं के शिष्य कांग्रेस के नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गांधी हुए, किंतु उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र अपनाया।

तीसरे वग व सुधारक प्राचीन परंपरा के उतने विरोधी न थे, यद्यपि सुधार के लिए व भी उतने ही व्यग्र थे, अतः इनका प्रभाव भी अधिक पड़ा। इनमें सब प्रमुख स्वामी दयानंद सरस्वती थे। उन्होंने सन १८७५ में बंबई में आय समाज की स्थापना की। आय समाज ने अपनी मुख्य प्रेरणा वेदों से ग्रहण की और हिंदू समाज व धर्म में घुस आइ बुराईयों को दूर करके विशुद्ध वैदिक धर्म के पुनरुद्धार का आह्वान किया। राष्ट्रवादियों पर इसका प्रबल प्रभाव पड़ा और वे बड़ी सरया में इस में शामिल हुए। इसने हिंदू समाज की बुराईयों से असंतुष्ट विद्रोह पर उतारू तत्त्वा को आश्रय दिया। इसकी शाखाएं देश भर में फैली। इसने शिक्षा का प्रचार किया और देश तथा समाज के पुनरुद्धार के लिए युवक-युवतियों का दल तैयार किया। इसने राष्ट्रीयता की भावना को बल दिया और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कार्यकर्ता दिए। स्वामी रामकृष्ण के महान शिष्य स्वामी विवेकानंद सनातनधर्म के समर्थक थे। उनके स्थापित रामकृष्ण मिशन ने शिक्षा के प्रसार और समाज सेवा के क्षेत्र में बड़ा काम किया। बाद में कांग्रेस के नेताओं ने अनुभव किया कि राष्ट्रीयता व जातिवाद के रूप में धर्म का महत्व है। इन नेताओं में तिलक और गांधी मुख्य थे।

राजनीतिक चेतना

१८ वीं और १९ वीं सदी के समाज सुधारक वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रवर्तक थे। उन्होंने शिक्षित नागरिक वर्ग में जागृति फैलाई। उसी ने राजनीतिक चेतना को जन्म दिया जिससे राजनीतिक या राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन हो सका। रानडे से गोखले की पीढ़ी तक आते आते सामाजिक आंदोलन के सभी प्रमुख नेता राजनीतिक क्षेत्र में काम करने लगे थे। बंबई के प्रसिद्ध पारसी नेता दादा भाई नौरोजी जो ब्रिटिश पार्लामेंट के पहले भारतीय सदस्य हुए, अगरजी राज के कठोर आलोचक थे। उनका कहना था कि यह भारत का शोषण कर रहा है और उसे गरीब बना रहा है। वह राजनीतिक कार्य के समर्थक थे। (रानडे भी बोरे समाज सुधारक न थे। वह यह मानते थे कि स्वराज्य के पहले समाज सुधार आवश्यक है) इनके अलावा बंगाल और अन्य स्थानों में उग्र राजनीतिक आंदोलन कारिया के वर्ग का उदय हुआ जो विदेशी शासन को उखाड़ना चाहते थे। सारे देश में असंतोष की भावना सुलग रही थी और प्रकट होने का रास्ता चाहती थी।

यह रास्ता सन १८८५ में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से मिला। यह भारत की आधुनिक राजनीति की ऐतिहासिक घटना थी। इसकी स्थापना प्रायः आक्स्मिंक ही हुई और गुरु में इसे अंग्रेजों का सहयोग और अधिनारिया की सहभागिता मिली। इसने एक विराट संगठन का रूप धारण किया और राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित नेतृत्व प्रदान किया। कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रधारा की नरूप

और गरम दो विरोधी प्रवृत्तियों के बीच का रास्ता अपनाया (जीर अब भी इसका यही रवैया है) नरम दल के साथ जंगरेजी राज से समझौता करने के और नरम वैधानिक उपायों से राजनीतिक कार्य करने के समर्थक थे। गरम विचारधारा जंगरेजी राज्य के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन से लेकर नातिवारी कार्यों तक अनेक उग्र रूपा में प्रकट हुई। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं को ब्रिटिश विधानवादियों से भी समर्थन मिला। वैधानिक आंदोलन का रास्ता छोड़ने के बाद कांग्रेस की ब्रिटिश राज से सीधी टक्कर हुई। वैधानिक और प्रत्यक्ष संघर्ष दोनों उपायों से काम लेकर कांग्रेस ने अंत में अपना लक्ष्य सिद्ध किया। इस क्रम में उसने संसदीय कार्य का और विस्तृत देशव्यापी संगठन तथा कार्यकर्ताओं का दल बनाने का अनुभव प्राप्त किया तथा उसे विभिन्न वर्गों का समर्थन मिला और जनता में जड़ जमी।

भारत में स्वशासन की संस्थाओं का विकास जंगरेजी शासन और भारतीयों के आंदोलन दोनों के प्रभाव से हुआ। यदि यहाँ किसी ऐसी विदेशी शक्ति का शासन होता, जिसके अपने देश में लोकतंत्रीय संस्थाएँ न होतीं और जिसमें अंगरेजों की तरह राजनीतिक समझौते की प्रवृत्ति न होती तो यहाँ के राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप कुछ और होता। इसका साथ ही भारतीयों की जो बौद्धिक और सांस्कृतिक परंपरा थी, जिसने कारण उ होने अंग्रेजी शिक्षा तथा प्रशासनिक और राजनीतिक संस्थाओं को ग्रहण किया, उससे अंग्रेजों को भी यहाँ शासन चलाने में आसानी हुई।

प्रायः शुरू से ही यहाँ दूरदर्शी और उदार अंग्रेज अधिकारी भी रहे, जो भारतीयों की भावनाओं को समझते थे। ये लोग उस दिन का कल्पना करते थे जब भारतीय अपना शासन खुद करने लगेंगे और इस पर भी सावधानीपूर्वक विचार करते थे कि किस प्रकार नरम उन्हें इसने लिए तैयार किया जाए। किन्तु लगभग १९ बीसवीं के अंत तक इस पर कोई ठोस विचार नहीं किया गया, कि भारतीयों को किस क्रम से अधिकार दिए जाए। (मिफ स्थानीय स्वशासन या म्युनिसिपल शासन के क्षेत्र में कुछ कारवाई की गई और इसमें भी बाई खास सफलता नहीं मिली)।^६

स्वशासन की भाग - इस क्षति में भारत में संसदीय शासन के विकास के पीछे कई शक्तियाँ काम कर रही थीं। एक तो कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन से सहयोग और मित्रता का जो हाथ बढ़ाया, उसका उधर से उत्तर नहीं मिला, इससे कांग्रेस में क्षोभ बढ़ा और उसका रुख बड़ा होने लगा। गोखले जैसे नरम दली नेता के अलावा

६ लाउ रिपन स्थानीय स्वशासन को राजनैतिक शिक्षण का साधन मानते थे और उन्होंने स्थानीय स्वायत्त बोर्डों की स्थापना के लिए १८८२ का प्रसिद्ध प्रस्ताव किया। विजेन्द्रिकाण सक्ती राज्य कमिशन ने भी १९०२ में इस प्रस्ताव का समर्थन किया मगर कोई खास नतीजा नहीं मिला, यद्यपि गाँवों के मुखिया शहरों में स्थानीय बोर्डों की ज्यादा संख्या की माँग थी। लाउ रिपन उदार शासन समर्थक थे। मद्रास में पंचायती राज की स्थापना सक्ती रिपोर्ट में लाउ रिपन का प्रस्ताविक उल्लेख है।

कांग्रेस में वात गंगा
 गरम तब भा सगठित
 सगठन करने पर जो
 अधिकार है और म
 कांग्रेस तुरत राजनीति
 में वगान के विभाजन
 तीमरे, १८०८ में
 और बादमराय तथा
 लिए गए, उससे निर
 की माग पैदा हुई।
 जब सदस्या की ही
 बाद जय निलह छूटे
 भूल (स्वगामन) से
 और कांग्रेस में निलह
 नेता एक साथ जा ग
 प्रसिद्ध समझोता हुआ
 अधिकार' की माग
 युद्ध के कारण अंग्रेज
 उन्होंने स्वगामन के
 इसके फलस्वरूप
 रिश्वेनी शासन के अ
 सन्ना का विधान म
 साथ ही सामान्य जी
 प्राप्ति में स्वगामन की
 जिसमें कुछ विभाग
 बनाए गए। इन की
 की नीति यह थी कि
 यद्यपि अंग्रेजों सत्ता
 और प्रगति हुई।
 हिन्दु स्व ऐज
 हुआ। कांग्रेस ने द
 अप्रहृ शिया रि य
 सरकार की स्वायत्ता
 सरकार ने गत्याग

र निरत रिपिनचद्र पात और राजराजराज जन नेता सा रा
 ता। इस गरम तब न तब वाली राजनीतिग साधन वा
 शिया। निरत ने धारित शिया - स्वराज्य मरा उ मणि
 न तब रागा। इस तब ने गरम तब पर राग राता रि
 रा अरिहारा की माग कर। दूसरी बात यह थी कि १८०८
 ने राग अयज्ञा गरमरा का धार रिरोज हुआ।
 निरत रागिन ऐज क जगिए जी बाता गा सुधार हुआ
 गरमरा की कीमिता म पहनी मार कुछ निवारित राग्य
 रिन मरम्या लो मरपा उदान मार उहे उगाय अधिरार दने
 न रागिता म अरित मरम्या मरमारी अरिहारिया गीर राम
 ता। मन १८०८ न १८१४ तक अंग्रेजों का पैल म रने न
 ता नता क रूप म तब रागिन हा ता। उ एनीम- की राम
 ग म रागिन हा गा। १८१४ म रागिन रा उगाय रा गवा
 रा ता ता रागिन रागी। गरम तब गरम तब गीर मुग्तमान
 ता रागिन जीर मुग्तमान ता म रागिन परत रा नाम रा
 ता मरमरा रागिन माचें रा मार म स्वगामन क राफा
 ता गा। गीरी जीर मरमरा उदा बात यह थी कि प्रथम रिश्व-
 मी मारा ग मरयोग मगने का बात गु जीर उने में
 रा रा अरिहार दने का वाश शिया।
 १८१८ का गरममट आफ शिया एस्ट पात हुआ निगम
 गीर मरमरीय रागिन का मामूला गीर मरम्या ता। बाद में ता
 म रागिन हुआ निगम नामरम राग्य ता मोता रा मगर
 रिगद राग म निराचित राग्य ता भी बाकी मरमरा था।
 राग ता उ उदा मर जीर राग राग ता राग ता रा
 रिगता का राग राग ता रिगता परिषद ता रिग ताग्यी
 ता म रिगतिर राग्य ता राग ता ता। ता राग राग
 राग ता राग ता राग ता राग ता राग ता रिग ता ता।
 ता गी गीरी की रिग ता राग ता राग ता राग ता राग ता
 राग ता राग ता राग ता राग ता राग ता राग ता राग ता
 राग ता राग ता राग ता राग ता राग ता राग ता राग ता
 राग ता राग ता राग ता राग ता राग ता राग ता राग ता

बढ़ता हुआ अस तोप

इस शक्ती व शूर के दा दशको म भारत के राजनीतिज्ञ जनानवरण में जो परि-
वर्तन आया उस समयना जरूरी है । सामाजिक और राजनीतिक सुधार की भाग
अब स्वतन्त्रता की आकांक्षा में बदल गयी । अंगरेजों से सहयोग की प्रवृत्ति व बदले
लोगों में इस भावना ने जोर पकड़ा कि अंग्रेज निरकुश विदेशी शासक हैं जो जनता
की भावनाओं की कोई परवाह नहीं करते । बंगाल के विभाजन ने अंगरेजी नेताओं
का भी क्षुब्ध कर दिया । दादाभाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन पर भारत के शोषण
का जो दुरजाम लगाया, उसने मध्यवर्ग के नेताओं को बहुत प्रभावित किया और
इससे राष्ट्रीय आंदोलन को विदेशी शासन का विरोध करने के लिए प्रबल शक्ति
मिला । बंग भग ने स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया । तिलक ने इस आंदोलन का
बड़ी कुशलता से नेतृत्व किया और इससे स्वदेशी कपड़ा मिला की स्थापना को
सहायता मिली । इससे व्यापारी बंग ने इन आंदोलन का समर्थन किया । पहले
अंग्रेजों की यह दलील सही मानी जाती थी कि भारतीयों को स्वातंत्र्य देने के
पहले उनकी शिक्षा देनी जरूरी है, अब इस अपमानजनक समझा गया । भारतीय
राष्ट्रवाद ने अब ज्यादा उग्र रूप पकड़ा । कांग्रेस का रख पट्टे अंग्रेजी शासन से
सहयोग और समझौते का था अब वह स्वशासन के लिए सत्तारूढ़ का राष्ट्रीय मोर्चा
बन गई ।

यह सब स्वाभाविक था । पिछा और राजनीतिक विचारों के प्रसार तथा जन-
मान्यता से असंतोष के बढ़ने के साथ साथ भारत और अंग्रेजी सरकार के हितों
का विरोध स्पष्ट होना अनिवार्य था । वास्तव में कुछ ऐसी शक्तियाँ काम कर रही
थी, जिन्होंने भारतीय राजनीति का रूप ही बदल दिया । पहली बार भारत में एक
संगठित केन्द्रीय नेतावर्ग का उदय हुआ जो देश की समस्याओं पर व्यापक और
राष्ट्रीय स्तर पर विचार करने लगा । पहले अलग अलग स्थानों में प्रमुख व्यक्ति
सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए काम करते थे, अब इनकी जगह राष्ट्रीय
नेतावर्ग और राष्ट्रीय संगठन ने ली । कांग्रेस के रूप में देश को राष्ट्रीय मंच मिला ।
राष्ट्रीय चेतना और भावना का उदय और इसने प्रचार के लिए राष्ट्रीय संगठन
का जन्म भारतीय इतिहास की क्रांतिकारी घटना थी । ब्रिटिश राज ने भारत में
स्थिरता और प्रशासनिक एकरा स्थापित करके राष्ट्रीयता के विकास के लिए
आधार प्रस्तुत किया किन्तु भारतीय राष्ट्र का जन्म तब हुआ, जब विदेशी शासन
की प्रतिक्रिया में राष्ट्रीय नवजात का रूप दिया और राष्ट्रीय संगठन को जन्म
दिया ।

राष्ट्रीय संगठन के द्वारा जब राष्ट्रीय नेतावर्ग काम करने लगा, तब राष्ट्रीय
आंदोलन का राजनीतिक आयाम भी स्पष्ट होने लगा । प्रश्न केवल सुधार और
शिक्षा का नहीं बल्कि एक शक्तिशाली साम्राज्य से लड़ो और बड़ी बदौर्द का था ।

यह समझना मूल्यता की बात थी कि साम्राज्य अपने से अपना जन वर्गने को राजी हो जाएगा। इंग्लिश तिरक ने कहा कि स्वराज्य के लिए मध्य करना पड़ेगा। विदेशी शासन से राजनीतिक सुधार की मांग का नतीजा निराशाजनक रहा।

नए मतभेद

जैसे जैसे समस्या की विशालता का बोध हुआ, तब तब उसको सुलझाने के उपायों के बारे में मतभेद भी पैदा हुए। नरम दलकी नीति से असंतुष्ट होकर तिलक के नेतृत्व में गरम दल ने मंगठन पर बज्जा करने की काशिश की। यद्यपि मूरत कांग्रेस (१८०७) में उनकी हार हुई फिर भी राजनीतिक रूप में चेतन्य बग में उनका बढ़ता गया। तिरक के जेल से छूटने और १८१५ में गोखले के देहात के बाद गरम दल का प्रभाव स्थापित हो गया। तिरक भी उग्र राजनीतिक आदर्शनकारी से धनुर राजनीतिज्ञ के रूप में परिणत हुए। इसमें राष्ट्रीय आदर्शन में नए उग्र नस्वों का प्रभाव जम गया जोर इही के प्रभाव से कांग्रेस ने १८१८ के सुधार को ठुकरा दिया।

इस प्रकार बंगाल व विभाजन के बाद अग्रजों सरकार और राष्ट्रवादियों के बीच तनाव बढ़ता गया यद्यपि अग्रजों ने १८०८ और १८१८ में कुछ राजनीतिक सुधार देकर और १८११ में बंगाल व विभाजन का रद्द करके भारतीय जनमत को संतुष्ट करने की कोशिश की। भारत के राजनीतिक वातावरण में गरमी जा गयी। अग्रजों ने राष्ट्रीय नेताओं का जेल और निर्वासन का दंड बढ़ाकर और इससे भी अधिक रोलट ऐक्ट बना कर और १८१८ में जलियानवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर गोली चला कर भारत में असंतोष को मजबूत करने में योग दिया। देश की तरह कांग्रेस के भीतर भी तनाव था। १८०७ में नरम दल के कारण तिलक के दल का कांग्रेस से अलग होना पड़ा था। अब तिलक और गरम दलकी प्रधानता हो जाने के बाद नरम दली लिबरल लोग कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने अपनी अपनी समस्या निबरेन फेडरेशन बनाई।

मगर ऐसा लगता था कि न तो नरम दल की समस्या का कोई उपाय मूल्यता था, न गरम दल का। कांग्रेस महज वादविवाद सभा बन गई थी। सरकार को राजनीतिक सुधारों के लिए राजी करने की नरम दल की चेष्टा विफल हो गयी थी। दूसरी ओर गरम दल के आंदोलन से भी स्वायत्तता प्राप्त करने में कोई सफलता न मिल पाई थी। इनके इनके अग्रजों की हत्या और बम फेंकने का नतीजा यही हुआ कि सरकारी दमन और बढ़ गया। एक प्रकार का गतिरोध पैदा हो गया था। असल में कांग्रेस का मंगठन जनता में न फल सका था और उससे कोई शक्ति न प्राप्त कर सकता था। कांग्रेस के नेता बाहर के पंड लिखे लोग थे। उनकी मारी बातचीत अग्रजों भाषा में होती थी जिसे साधारण जन न समझता था। चिंताओं

जनता से उनको कोई व्यापक समर्थन नहीं मिल पाता था। नरम और गरम दोनों पक्षों के नेता जनता का संगठन करने में विफल रहे और इससे देश की राजनीति में एक खालीपन और गतिरोध आ गया था।

जनतायक का आविर्भाव

इस गतिरोध को दूर किया मोहनदास करमचंद गांधी ने। वह भारतीय राजनीति को जनता के समीप ले आए। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह^७ चलाया था। सन १९१५ में वे भारत लौटे। भारत की समस्या का अन्वयन करने के लिए उन्होंने सार देश का दौरा किया। गांधी ने अनुभव किया कि स्वराज्य की लड़ाई बहुत लंबी होगी और केवल अंग्रेजों से ही नहीं, भारतीयों को खुद अपने से भी लड़ना होगा। उन्होंने समझ लिया कि अकेले शहरी मध्यवर्ग में काम करने से जनता में जागरण नहीं आ सकता। जनता को आलस और अव्यक्तता से जगाना होगा, उनमें आत्मविश्वास और प्रगति की चाह पैदा करनी होगी। अंग्रेजों को यह दिखाना होगा कि उनका मुकाबला नरम दिल के थोड़े से दबू नेता और अंगरेजियत में डूबे शिक्षित वर्ग के लोगों से नहीं। भारत भर की करोड़ों जनता के संगठित आंदोलन से है। गांधी यह भी जानते थे कि उनका प्रतिपक्षी भौतिक बल से डरने वाला नहीं है, साथ ही उस पर नैतिक बल का प्रभाव पड़ सकता है, यदि उसके पीछे जनता का संगठन हो। इसलिए सब से पहला काम जनता को जागृत करके, संगठन की जड़ उनमें फैलाना है।

गांधी स्वयं असाधारण नैतिक व्यक्ति से प्रेरित थे। उन्होंने कांग्रेस को एक नई दिशा दी और उसे जनता का संगठन बनाया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के स्त्री-पुरुषों को एक सामान्य कार्यक्रम के लिए प्रेरित करने के लिए नए उपायों का सहारा लिया। उन्होंने जनता को सत्य और धर्म के लिए त्याग करने का ललकारा। उन्होंने सन १९२१, १९३० और १९३२ में सरकार के खिलाफ अहिंसात्मक असहयोग के जबदस्त आंदोलन चलाये। ये तोड़फोड़ या उपद्रव के नहीं, अत्याचार के नैतिक प्रतिरोध के रूप में चलाए गए और इनमें सरकार के आदेशों और कानूनों की शक्तिपूर्वक अवज्ञा की गई। यही सत्याग्रह का तत्त्व था। सरकार को अत्याचार से विरत करने के लिए उन्होंने कई बार आमरण अनशन ठाने। इसमें कई बार उनकी सफलता मिली और इनके द्वारा उन्होंने अपने दंगवासियों में गहरी भावना उत्पन्न की और विदेशों को भी प्रभावित किया।

गांधी स्थिति को देख कर उसी के अनुरूप उपाय निकालते थे। जब आंदोलन

^७ दक्षिण अफ्रीका के गैरे शासक भारतीयों से भेदभाव करते थे। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नो नेताओं ने भी अपने नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन में गांधीजी के सत्याग्रह के तरीके का प्रयोग किया। किंतु इसका प्रभाव अस्थायी रहा।

स्थगित हो गया तो उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किया। इसमें अस्पृश्यता निवारण खादी, ग्रामोत्थान, आदिवासियों की सेवा, पिछड़े लोग की भलाई, शिक्षा का प्रचार और कांग्रेस से संबद्ध स्त्रियां, युवा, मजदूर और दलित जाति मध्धी संगठन में काम शामिल था। पहले समाज सुधार हो या राजनीतिक संगठन इस ब्रह्म को गांधी ने खतम कर दिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों काम एक ही कार्यक्रम के अंग हैं। रचनात्मक कार्यक्रम कांग्रेस कार्यकर्त्ता का काम में लगाए रखने का बहुत अच्छा तरीका था, जो जयया आंदोलन स्थगित हो जाने से निखर जाते। इस प्रकार अगले आंदोलन के लिए कार्यकर्त्ता की फौज तैयार रही।

नए प्रतीक

गांधी ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत गहरा और व्यापक रूप दिया और उस नए शक्तिशाली प्रतीक दिये। जनता उन्हें महात्मा कहती थी। उन्होंने अपने महान व्यक्तित्व के जादू से जनता को एक ढाँचे में ढाला। उन्होंने अपने जीवन का राष्ट्र के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। उनके त्याग, सादगी और सत्य की साधना का देश पर गहरा प्रभाव पड़ा। दूसरे उन्होंने समाज की अत्यंत जटिल समस्याओं के लिए चमत्कारी सूत्र प्रस्तुत किए। उन्होंने अछूतों को 'हरिजन' नाम दिया और उनकी भलाई के काम को कांग्रेस कार्यक्रम का अंग बनाया। उन्होंने राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदुस्तानी (हिंदी और उर्दू का मेल) के प्रचार का देश-व्यापी कार्यक्रम चलाया, उन्होंने स्त्रियों की स्थिति सुधारने का आंदोलन चलाया और स्त्रियों को पुरुषों के समान पद देने की जबदस्त बकालत की, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का राष्ट्रीय एकता का साधन बनाया। गरीब जनता की जीविका देने के लिए उन्होंने चर्खे को प्रतीक बनाया और खादी को राष्ट्रीय पोशाक बनाया। नमक पर कर जैसी छोटी-सी बात को उन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरोध का प्रतीक बनाया और हजारों आदमियों ने नमक कानून तोड़ कर विदेशी सत्ता को चुनौती दी। हर रोज अपनी शाम की प्रार्थना में वह देश की समस्याओं पर अपनी राय देते थे। इस प्रकार अपनी प्रार्थना सभा की उन्होंने सांस्कृतिक महत्व को बस्तु बना दिया। अखबारों में उनकी प्रार्थना सभा की रिपोर्टों को, और सब खबरों से अधिक महत्व मिलता था। गांधी ने ब्रिटिश सरकार से अपनी सड़क को सत्य के प्रयोग का नाम दिया।

तीसरे, गांधी ने अहिंसा और सत्य जैसे धार्मिक शब्दों और प्रतीकों को साधन का हथियार बनाया और उनके द्वारा कांग्रेस को जबदस्त अनुशासनबद्ध संगठन और ठोस कार्यक्रम दिया। इस प्रकार वह विभिन्न विचारों, वर्गों और संप्रदायों के लोगों को कांग्रेस में ले आए। गांधी सभी वर्गों के लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन में साथ रखने को बहुत महत्व देते थे और इस खातिर वह मतभेदों को सहन करते

ये । इसने कांग्रेस में अनेक तरह की विचारों के लोग आए और उसने बहुत सच्ची-सच्ची चीजें अपने को डाल लीं जो शायद सही हैं । उनके देशों में स्वतंत्रता आंदोलन में जो मानें और कुछ उपाय हैं, उससे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन बचा रहा । तब ही हिंदू मुस्लिमों के बीच की गहरी भेदभाव की कोखों के बावजूद न रोने सके ।

प्राचीन परम्परा को नया रूप

गांधी ने सैकड़ों वर्ष पुरानी धारणाओं को नया आयु दिया । वे गांव और शहर के लोगों को एक साथ ले आए । आत्मश्रद्धा, अहिंसा, जैसे पुराने आदर्शों और सामाजिक तथा व्यक्तिगत कृत्यों की पुरानी धारणाओं को उन्होंने आयु दिया । स्थिति के अनुरूप नये ढंगों में राष्ट्रीय आंदोलन में प्रयोग किया । उन्होंने शहर के लोगों का प्रेरित किया कि वे गांवों में जाएं और सामाजिक जाति के लोग बनें, सादगी, पवित्रता और गरीबी या जीवन बिताएं और देश की जनता के सामने ऊंचा आदर्श पेश करें । उन्हें अपने व्यक्तिगत उदाहरण से मतलब ही गरीबों के ऊपर उठाने के लिए आत्मसमर्पण और अनुशासनपूर्वक राज की भलाई के लिए एक होकर काम करना चाहिए । अपनी जरूरत कम से कम और अपना परिवार छोटा रखना चाहिए । उन्होंने धन को ट्रस्ट या धरोहर समझते, पैसा धराने और धन से अपना धंधा करने के पुराने आदर्शों की दुहाई देकर व्यापारी और भ्रष्टाचारियों को अपने 'रचनात्मक' कार्य में सहयोग देने को प्रेरित किया । उन्हें सामाजिक और राजनीतिक कार्य में नैतिकता और धर्म का समावेश किया और इन प्रकार पुराने विचारों के लोगो को अपने आंदोलन में आकर्षित किया । छात्रों और गांधी में, पुराने और नए विचारों में मेल मिलाकर गांधी ने राष्ट्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योग दिया ।

गांधी ने केवल पुराने विचारों को नया रूप ही नहीं दिया । पुरानी गहरी गहरी रुढ़ियां पर भी उन्होंने निमग्नता से चोट की । एक बार उन्होंने आत्म संयम और धन को परमात्म में लाने के पुराने आदर्शों का प्रचार किया, दूसरी बार उन्होंने जात पात और ऊंच नीच के भेदभाव को अस्वीकार किया । शारीरिक श्रम का छोटा या नीचा और दिमागी काम को ऊंचा समझने का उन्होंने दावा किया । यह नहीं मानते थे कि मनुष्य को सामाजिक या गैर-सामाजिक कृत्यों का शिवांशित रूप अपनी आत्मा के कल्याण में लग जाना चाहिए और गरीबी का पूर्व जन्म का कर्म का परिणाम समझ कर बैठ जाना चाहिए । हिंदू विचारधारा की जो गहरी गहरी कमी थी नागरिक कृत्य और सामूहिक श्रमजीव भावना का अभाव, उस उन्होंने दूर किया । यह आत्मसमर्पण और व्यक्तिगत नैतिकता का सामाजिक कार्य में प्रतिष्ठित करने से भी बड़ा काम था । महात्मा और धर्म का अर्थों का उदा

हरण प्रस्तुत किया, उससे अधिक महत्व का काम, उन्होंने सस्था बनाने और संगठन के अनुशासन की शिक्षा देकर किया।

सस्था-निर्माण

गांधी ने देश भर में बड़े विशिष्ट कार्यक्रमों का दम तैयार किया और उनकी कांग्रेस के विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी। इन्हीं लोगों ने बाद में स्वतंत्रता प्राप्त होने पर सरकार और कांग्रेस संगठन की यागदोर समाली। उन्होंने कांग्रेस सस्था के विकास के लिए बड़ी बुद्धिमानी के कदम उठाए। उन्होंने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की स्थापना की और उसको बड़ी सक्रियता से सस्था बनाया। इसे कांग्रेस हाईकमांड कहा जाने लगा और यह राष्ट्रीय आंदोलन की सूत्रधार मानी जाने लगी। इसने सामूहिक नेतृत्व की परंपरा डाली और कांग्रेस महाममिति से अधिक महत्व प्राप्त कर लिया। कांग्रेस महाममिति (आल इंडिया कमेटी) में तो जबरन मतभेद दिखाई पड़ते थे, किंतु उसे अंत में कार्यसमिति की बात माननी पड़ती थी।

गांधी कांग्रेस कार्यसमिति को बहुत ऊंचा दर्जा देते थे (यद्यपि वह अभी उसके आकाशवादी सदस्य नही रहे) और अपने सभी निणयों की पुष्टि उसने कराते थे। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन का आचानक स्मरण कर दिया और उनके इस कार्य का चारा और से विराय और आलोचना होने लगी तब इसकी ओर ऐसे ही अन्य निणयों की पुष्टि वह हाईकमांड से कराते थे। १९३६ में जब गांधीजी की इच्छा के विरुद्ध कांग्रेस महासमिति ने सुभाष बाबू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना, तब गांधीजी से प्रभावित कांग्रेस हाईकमांड ने सुभाष से सहयोग नही किया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस गांधी की आनासाही कहा गया और उनकी कटु आलोचना हुई, मगर अंत में गांधी की ही चली। जैसा कि उन्होंने यों पहले कहा था, कांग्रेस को मेरे स्थान पर दूसरा नेता चुनने का अधिकार है, किंतु जब तक वह मुझे नेता बनाती है, जो मैं कहूँगा वही होगा। वह नेतृत्व की एकता और अनुशासन पर बेहद जोर देते थे। मगर वह अपनी आनासाही चलाने के बजाय हाईकमांड के जरिये काम करते थे। इससे जनता में हाईकमांड को बड़ी मान्यता और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। उसकी बात कानून मानी जाती थी। इस प्रकार भारत ने इतिहास में पहली बार ऐसी अधिकारी सस्था का निर्माण हुआ जो राष्ट्र की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती थी और उसकी ओर से काम करती थी। भारतीय राष्ट्र को सत्यागत रूप देना, गांधी का एक महान् कार्य था।

गांधी ने कांग्रेस संगठन का आधार व्यापक बनाने की कोशिश की। उन्होंने देश भर में जिला कांग्रेस कमेटिया स्थापित की और उनके जरिये जनसाधारण को कांग्रेस का सदस्य बनाया। जिला कांग्रेस कमेटियों की गांधी हमेशा जनता

का मुख्य सगठन मानते थे। इसके अलावा उन्होंने स्त्रियाँ, हरिजन, आदि-वासियाँ, मजदूरों आदि में काम करने के लिए जलजल सस्थाएँ बनाई। उन्होंने शुरू में ही ऐसी सस्थाओं की जरूरत का अनुभव किया, जिसमें कांग्रेस के कार्यक्रमों उस समय लगे रहें जब राजनीतिक आंदोलन न चल रहा हो। उन्होंने जनता में अपने विचारों के प्रचार और देश की समस्याओं पर निरंतर चर्चा जारी रखने के महत्व को भी समझा। उन्होंने यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन आदि पत्र निकाले। इनके जरिये वह अपने अनुयायियों का निरंतर पथप्रदर्शन करते रहते थे। इन तरीकों से गांधी राष्ट्रीय आंदोलन को सुसंयोजित करना चाहते थे। स्वभाव से वह दलित या कठोर पार्टी सगठन के विरुद्ध थे, किंतु अपने इन तरीकों से उन्होंने ऐसे जलजल सगठन का निर्माण किया, जिसकी शाखा-प्रशाखाएँ देश भर में फल गईं। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने जनता को संयोजित करने के लिए और भी अनेक एजेंसियाँ स्थापित की, किंतु उसका साधारण ढांचा वही रहा, जिसे गांधी ने बनाया था। आज भी उसका यही ढांचा ही है और अब राजनीतिक पार्टियाँ ने भी इसी को अपनाया है।^८

गांधी के नेतृत्व के प्रभाव

एक आदमी की इतनी अधिक प्रधानता से कुछ बुराईयाँ भी पैदा होती हैं। गांधी के एकल नेतृत्व का यह नतीजा तो नहीं हुआ कि उनके बाद देश को नेताओं का अभाव रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की एक बहुत बड़ी पूजा थी, हर स्तर पर देश भर में योग्य नेताओं की मौजूदगी। गांधी के नेतृत्व का बुरा असर अब दिशाओं में हुआ। एक तो यह था कि गांधीजी ने राजनीति में नैतिकता, सत्य, अहिंसा, आदि पर इतना जोर दिया कि वह असंभव से दूर हो गई। उन्होंने इतने ऊँचे आदर्श रखे कि वे व्यवहार में न आ सकें। राजनीति-ज्ञता का स्थान उपदेशवाजी ने ले लिया। गांधी की वास्तविकता की अच्छी पकड़ थी, फिर भी उन्होंने मनुष्य की कमजोरियाँ का बोझ ध्यान नहीं रखा। तात्कालिक राजनीति का गुरु गांधी की पकड़ में न आ सका और आज भी उनके बहुत से अनुयायियों की यही कमजोरी है। नेहरू में यह कभी न थी, क्योंकि उनका मानसिक और बौद्धिक वातावरण भिन्न था और यह उनकी विशेषता थी कि हम विषय में वे गांधीजी के प्रभाव से बचे रहें।

गांधी जी के जीवनकाल में भी उनके अनुयायियों के लिए अवसर उनकी बात या नीति को समझना बटिन हो जाता था। वह तात्कालिक प्रश्नों का अवसर सिद्धान्त की बातों से मिला देते थे। राजनीतिक प्रश्नों को नैतिक प्रश्नों से मिला

^८ कांग्रेस सगठन के विकास के लिए देखें - गोपालकृष्ण 'द टेक्निक ऑफ द इंडिया मोशन' कांग्रेस पत्र ए मास आर्गनाइजेशन, जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज, मार्च १९६६, पृ. ३।

दने से दूसरी पार्टिया चक्कर में पड़ जाती थी। उनके अनुयाई जार प्रतिपक्षी दल तथा अंग्रेजी सरकार नहीं समझ पाते थे कि वह क्या कर बैठेंगे। इसका नतीजा यह होता था कि अपने ही शब्दों में वह 'हिमालय जैसी गलतिया' कर बैठते थे और उनकी नीति अचानक पनदा खा जाती थी। इससे भी अधिक गंभीर त्रुटि यह थी कि उनकी रीति नीति से राष्ट्रीय आंदोलन में फूट पड़नी न रुकी बल्कि और बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रीय एकाता के लिए महान प्रयत्न किया पर राजनीतिक समझाते के दावपेंच में वे चूक जाते थे। उदाहरण के लिए सांप्रदायिक समस्या सुलझाने के लिए उन्होंने भावनाओं से काम लेने पर भरोसा किया और खिलाफत आंदोलन तथा हिंदुस्तानी प्रचार जैसे उपायों का सहारा लिया। लेकिन नींव से समझौता करने और उनको मिला कर मजबूत मोर्चा बनाने की ओर ध्यान न दिया। बातचीत के समय अक्सर उनका रंग बड़ा कटटर और अनम्य हो जाता था। उनकी बात दूसरे दल के नेताओं को पुराणपथी लगती थी और उनके मन में कांग्रेस की असली मशा के बारे में शक पैदा कर देती थी। मगर इस आलोचना का यह अर्थ नहीं कि गांधीजी की नीति बिगड़ चुकी थी। बहुत सी समस्याएँ तो अनिवार्य थी। कुछ समस्याएँ राष्ट्रीय जागरण के फलने के कारण उठीं। अनेक समस्याओं को सुलझाने में गांधीजी ने बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया, खास कर राजनीतिक समाज के निर्माण में। उनकी महामता यह थी कि वे अपनी विफलताओं का स्वीकार कर लेते थे और मुराब काय को जारी रखते थे।

४.५ राजनीतिक दल

सभी लोग गांधीजी की नीति को नहीं स्वीकार करते थे। जब गांधीजी लोणा को अहिंसात्मक प्रतिरोध के लिए तैयार करने पर जार द रह थे, कुछ प्रमुख कांग्रेसी न स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। ये लोग कोसिला का चुनाव लड़ कर डोमोनियन स्टेट्स (जीपनिवेशिक स्वराज्य) के लिए राजनीतिक आंदोलन करना चाहते थे। १९२७ में मद्रास के कांग्रेस अग्रिवेशन में उन्होंने एक प्रस्ताव पाम किया जिसमें कहा गया कि कांग्रेस का ध्येय 'स्वतंत्रता' है। स्वराज्य दल ने १९२८ में एक सब दली सम्मेलन आयोजित किया। इसमें एक कमेटी नियुक्त की, जिसने भारत में पूर्ण प्रतिनिधि शासन और स्वतंत्र ब्रिटिश उपनिवेशों के पद की मांग की। अवाहरलाल नेहरू और सुभाषचंद्र बोस के नेतृत्व में युवकों का एक दल पूर्ण स्वतंत्रता के लिए उग्र कार्रवाई करने के पक्ष में था। १९२९ में लाहौर कांग्रेस में इस दल को सफलता मिली और गांधीजी ने स्वयं 'पूर्ण स्वतंत्रता' का प्रस्ताव पेश किया। एक इससे भी ज्यादा उग्र वामपंथी दल ने कांग्रेस समाजवादी दल का गठन किया। इसी बीच कुछ प्रांतों में कांग्रेस से बाहर कुछ राजनीतिक दल काममें हुए। इनमें से कुछ अंग्रेजी सरकार से सहयोग

कर रहे थे। इनमें मद्रास की 'जस्टिस पार्टी' थी, जो वाद की 'द्रविड कजगम' और 'द्रविड मुनेत्र कजगम' की पूर्ववर्ती थी। दूसरी थी पंजाब की 'यूनियनिस्ट पार्टी'। इनके अलावा मुस्लिम नेता थे, जिनमें से अधिकतर गांधीजी और कांग्रेस के खिलाफ थे। मुस्लिम नेताओं में भी दो वर्ग थे, एक था पुराना कट्टर वर्ग जो समझता था कि हिंदू-मुसलमानों का फर्क बुनियादी है और इसलिए यह कांग्रेस के विरुद्ध था। दूसरा वर्ग जिन्ना जैसे प्रगतिशील मुसलमानों का था जो गांधी और उनके तौर-तरीके को दकियानूसी समझता था। इन दोनों को मिलाने की गांधीजी ने बड़ी कौशिशें की लेकिन वे विफल रही।

गांधीजी इस बात के विरुद्ध नहीं थे कि स्वराज्य हासिल करने के लिए और तरीके काम में लाए जाएं। कांग्रेस के द्वारा जनता को संगठित करने और असहयोग और सत्याग्रह आंदोलन चलाने के साथ-साथ वह वैधानिक सुधारों से उदासीन न थे और समय-समय पर ब्रिटिश सरकार से समझौते की बातचीत भी करते थे। आंदोलन के बीच-बीच कुछ सुस्ताने के लिए वह अंग्रेजी सरकार से सुलह भी कर लेते थे। गांधीजी अंग्रेजी सरकार के कुछ कानूनों को तोड़ने आंदोलन जरूर करते थे, लेकिन वह यह नहीं चाहते थे कि देश में अराजकता फैले, और जब कभी आंदोलन उनके नियंत्रण से बाहर जाता दीखता वह उसे रोक देते। कई बार अपने समयको के बड़ विरोध के बावजूद उन्होंने अंग्रेजी सरकार से समझौते किये।

इस प्रकार सन १९२८ में चोरीचोरा में पुलिस और जनता में संघर्ष के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को रोक दिया, यद्यपि जवाहरनाल और अन्य अनुयाइयों ने इसका घोर विरोध किया। इसी प्रकार १९३१ में जेल से छूटने के बाद उन्होंने ब्रिटिश प्रधान मंत्री के इस आश्वासन का स्वागत किया कि भारत को पूर्ण उत्तरदायी शासन की ओर अग्रसर किया जाएगा। इस आश्वासन के आधार पर वाइसराय लार्ड इरविन ने समझौता किया तथा कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में लंदन में दूसरी गोलमेज कान्फ्रेंस में भाग लिया।^९ मगर गांधीजी ने देखा कि अंगरेजी सरकार सांप्रदायिक समस्या को और उभाड़ रही है (इस विषय पर हम इस अध्याय में और विचार करेंगे) और वे खाली हाथ वहां से लौट आए। उनके लौटने के पहले ही अंग्रेजी सरकार ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को और हजारों अन्य आदिमियों को जेल में बंद कर दिया था।

घमनिरपेक्षता का प्रश्न

गांधीजी यह समझते थे कि अंत में अंग्रेजी सरकार से समझौता करना होगा,

^९ पहली कान्फ्रेंस १९३० में हुई थी जब गांधीजी और अन्य कांग्रेस नेता नमर सत्याग्रह के सिलसिले में जेल में बंद थे।

किंतु दुनियादी बाता पर झुबने को वह तैयार न थे। उन्होंने हरिजन। को पृथक् निर्वाचन का अधिकार देने के निरोध में आमरण अनशन छेड़ दिया और इसको बदलवा कर ही दम लिया।

अब गांधीजी और कांग्रेस के सामने सवाल था कि अगला कदम क्या है। सन १९३१ के गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट से बड़े मतुष्ट न थे, यद्यपि हममें बहुत बड़ी सरया को वोट का अधिकार दिया गया था और प्रांता में उत्तरदायी सरकार तथा केंद्र में संघ की व्यवस्था की गई थी। इसमें दली रिप्राइस भी शामिल हो सकती थी। परंतु इस ऐक्ट में राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक-मेलजोनों में कोई मदद न मिलती थी। फिर भी कांग्रेस ने इस ऐक्ट के अंतर्गत सन १९३७ के चुनावों में भाग लेने का फैसला किया और आठ प्रांता में उनके मंत्रिमंडल स्थापित हुए।

दा थप तक शासन करने के बाद प्रिन्स भारतीय नेताओं की राय लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को १९३६ के विश्व युद्ध में घसीटने के निणय के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने पदत्याग कर दिया। नेहरू और जय पारसिस्ट विरोधी लोग युद्ध के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन रोक देने और जमनी के विरुद्ध ब्रिटन और उनके मित्र राष्ट्रों की मदद देने के पक्ष में थे, लेकिन गांधीजी इसी क्षण पर मदद करने को तैयार थे कि भारत को तुरंत स्वतंत्रता दी जाये। ब्रिटिश सरकार ने गांधीजी और कांग्रेस के नेताओं को समझाने के लिए सर स्टैफर्ड क्रिप्स की भेजा और आश्वासन दिया कि युद्ध खतम होते ही भारत में संविधान सभा बुलाई जाएगी। लेकिन क्रिप्स को सफलता न मिली और कांग्रेस ने तुरंत पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। सन ४२ में कांग्रेस ने 'भारत छोड़ो' आंदोलन शुरू किया। कांग्रेस के सार नेता और हजारों आदमी बंद कर दिए गए। गांधीजी ने जेल में फिर अनशन छेड़ा, जिसमें उनकी जान जात जाते बची। सन १९४५ में इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार बनी और कांग्रेस नेता जेल से छोड़े गए। दुनिया की स्थिति एकदम बदल चुकी थी और अंग्रेज सरकार तथा कांग्रेस में फिर बातचीत बनी, लेकिन कोई समझौता न हो सका। इस पर और चर्चा करने के पहले हमें देखना चाहिए कि स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता के मांग में मुख्य बाधा क्या थी।

सांप्रदायिक समस्या और राष्ट्रीय एकता

राष्ट्रीय आंदोलन के मांग में सबसे बड़ी बाधा थी 'सांप्रदायिक समस्या'। राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति और दुनिया की बदली स्थिति का देखते हुए अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया था कि भारत की स्वतंत्रता मिल कर रहेगी। प्रश्न बचल यह था कि सत्ता किसको दी जाए और भारत की सरकार का भावी रूप क्या हो। मुख्य समस्या मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग की थी।

सांप्रदायिक समस्या की गुरुआत मुस्लिम युग से हुई। लेकिन पिछले कई सौ

वर्षों से हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहते आए थे और उनमें काफी सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान और एकता पैदा हो गई थी। आज भी देश के बटवारे के बाद भी एकता के ये बंधन टूटे नहीं। साथ साथ रहने से भाषा, साहित्य, इतिहास, संस्कृति और शिष्टाचार की उनमें एक सी परंपरा बनी। घम या मजहब का अंतर हात हुए भी, इस्लाम के 'सब मनुष्या के भाईवारे' और हिंदू धर्म के 'सब रास्ते एक ही मजिल की ओर जाते हैं' सिद्धांतों के कारण, यहाँ एक खास तरह की सहिष्णुता और मेलजोल पैदा हो गया था, जो भारत की अपनी विशेषता है।

ब्रिटिश शासन से जहाँ भारत को कई लाभ पहुँचे वहाँ एक नुकसान यह हुआ कि उससे सांप्रदायिक द्वेष को उत्तेजना मिली। इसमें ब्रिटिश राज, कांग्रेस और मुस्लिम राष्ट्रीयता के नेता सब का दोष है। यह भी एक विचित्र विडवना है कि प्रतिनिधि और सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष शासन के जिस सिद्धांत ने भारत में आधुनिकता का प्रचार किया उसी ने सांप्रदायिक समस्या को भी उभाड़ा।

असमान विकास

शुरु में अंग्रेजों का रव मुसलमानों के खिलाफ जान पड़ता था। चूँकि उन्होंने मुगलों से सत्ता छीनी थी इसलिए वे मुसलमानों को शक्ति या प्रभाव की जगह से दूर रखते थे। खास कर उन इलाकों में जहाँ अब भी उनका जोर था (इसी प्रकार का व्यवहार वे राजपूतों के साथ भी करते थे, जहाँ उन्होंने अंग्रेजों से टक्कर ली थी)। हमारे, अंग्रेजी शासन से हिंदुओं ने शुरू में ज्यादा फायदा उठाया। ब्राह्मणों और ऊँची जाति के हिंदुओं ने अंग्रेजी शिक्षा लेकर सरकारी नौकरियाँ और ऊँचे पदों में प्रवेश किया, जबकि मुसलमान अंग्रेजी शिक्षा से दूर रहे और नौकरियाँ आदि में पिछड़ गए। आर्थिक दृष्टि से भी पुरानी दस्तकारी और घघों की घर-घादी से मुसलमान कारीगरों को ज्यादा नुकसान हुआ। जमीन के नए बंटावस्त से मुसलमान जमीनदारों का हानि हुई। उधर हिंदू महाजनों और व्यापारियों ने तरक्की की। मुसलमानों को अपना अल्पसंख्यकों का दर्जा भी खलता था, क्योंकि उनको मुगलिया सल्तनत की याद आती थी जब सख्ता में थोड़े होने पर भी वे राज करते थे।

यह भी याद रखना चाहिए कि अंग्रेजों के राज्य में जो सुव्यवस्था कायम हुई उससे पुरानी संस्कृति, और संस्कृत विद्या तथा हिंदू धर्म में एक नया जागरण आया। हिंदू जो अब तक मुसलमानों के हुकूमत में दबे हुए थे, पुनः सिर उठाने लगे। उनके इस जागरण में अंग्रेजी शिक्षा और उससे प्राप्त होनेवाली सरकारी नौकरियाँ और वकालत, डाक्टरी आदि ने बड़ा योग दिया। इसका एक नतीजा यह हुआ कि शुरू में कई दशकों तक राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व हिंदुओं के हाथ में रहा जिनमें से अनेक प्राचीन हिंदू संस्कृति से प्रेरणा ग्रहण करते थे।

मुसलमानों में प्रतिस्पर्धा

दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा और राष्ट्रीय जागृति का प्रभाव बहुत थाड़े से मुसलमानों पर पड़ा।^{१०} ये शिक्षित मुसलमान अनुभव करते थे कि प्रशासन और राजनीति में हिंदुओं की प्रधानता से मुसलमानों को खतरा है। सर सैयद अहमद साद्वी में से थे। उन्होंने मुसलमानों को हिंदुओं से और कांग्रेस से अलग रहने और अंग्रेजी पढ़ने तथा अंग्रेजी सरकार से सहयोग करने को कहा। सर सैयद ने १८७७ में अलीगढ़ में ऐंग्लो जोरियटल कालेज कायम किया (बाद में अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी) और मुसलमानों का अंग्रेजी के पास लाने की कोशिश की। उन्होंने मुस्लिम एजुकेशनल कानफ्रेंस कायम की और हर साल उसका जलसा करने लगे।

मुसलमानों की अव्यवस्था रोकने का यह प्रयत्न १९ वीं सदी के दूसरे भाग में हुआ परंतु इसने किसी राजनीतिक विचारधारा या कार्यक्रम को जन्म नहीं दिया। मुसलमानों में सत्ता से सघप या विरोध की कोई जोरदार भावना न थी। सर सैयद आदि की कोशिशों से अंग्रेजी का मुसलमानों पर अविश्वास घटा और मुसलमान सरकारी नौकरियों में जाने लगे। अलीगढ़ आंदोलन से मुसलमानों में शिक्षा का प्रचार हुआ और लखनऊ, पटना, इलाहाबाद, अलीगढ़ और हृदराबाद जैसे पुराने सस्कृति-केन्द्रों में नयी स्फूर्ति पैदा हुई और शिक्षित मुसलमान यह हिंदू दोनों सामाजिक गतिविधियों में साथ साथ भाग लेते थे। अपने अपने रीतिरिवाज और परंपरा से उनका लगाव था, लेकिन वे एक दूसरे का ख्याल रखते थे और उनमें कोई द्वेष भाव न था।

फूट के बीज

फिर भी मुसलमानों के मुकाबले हिंदुओं की ज्यादा प्रगति, राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदुओं और हिंदू विचारों और प्रतीकों का प्रभाव और अंग्रेजी का साम्प्रदायिक पक्षपात, इनमें साम्प्रदायिक फूट के बीज बतमान थे। साम्प्रदायिक लोग इस बात को नहीं समझते कि आधुनिकता के विकास से खास कर शिक्षा और नगरीकरण के कारण अपनी अलग या विनिष्ट सत्ता या अस्मिता का बोध पैदा होना है, समाज में पद प्रतिष्ठा के पुराने पैमाने टूट जाते हैं, और सरवाबल तथा संगठित प्रयत्न आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। जैसे उनमें के नए अवसर गुलते हैं पुराने सघप और विरोध पुनर्जीवी हो जाते हैं नए गठजोड़ और जाड़तोड़ का महत्त्व ज्ञात होता है। भारत में राजनीतिक जागृति के साथ एकता के साथ साथ फूट की प्रवृत्तियाँ भी

१० यह प्रभाव सब जगह एक सा नहीं था। जहाँ मुसलमानों की अधिक संख्या गाँवों में रहती थी और रानी या माँ की बरती थी, वहाँ उनमें अंग्रेजी शिक्षा नहीं फैली। उत्तरप्रदेश और बंगाल में जहाँ मुसलमान अधिकतर शहरों में रहते थे और उनका बंधन था वहाँ उनमें अंग्रेजी शिक्षा ज्यादा होती थी क्योंकि उनकी नौकरियाँ जिनमें हिंदुओं में।

पैदा हुई और अतः में दूसरी प्रवृत्ति की ही जीत हुई। आइये, इन पर एक नजर डालें।

प्रतिनिधित्व की पद्धति

भारत में सांप्रदायिक भावनाओं को राजनीतिक रूप मिलने का एक कारण यहाँ प्रतिनिधि या निर्वाचित सस्थाओं की स्थापना थी। इसके साथ साथ प्रतिनिधित्व की ब्रिटिश धारणा भी इसके लिए जिम्मेदार थी। अंग्रेज लोग प्रतिनिधित्व का अर्थ, अलग अलग समूहों, वर्गों, हिंदु, क्षेत्रों, सस्थाओं और संप्रदायों का प्रतिनिधित्व समझते हैं। उनके यहाँ प्रतिनिधि सस्थाओं के विकास के पहले एक राष्ट्र बन चुका था, इसलिए वह राष्ट्रीय एकता को स्वयंसिद्ध मान कर चलते हैं। उन्होंने भारत के अनेक संप्रदायों और जातियों की समस्या को इनके स्वाभाविक अस्तित्वबोध और एक दूसरे से समझौते की समस्या समझा और उसका उपाय अलग वर्गों या समूहों को प्रतिनिधित्व देना समझा।

इसलिए उन्होंने भारत में सांप्रदायिक और विशेष वर्गों के प्रतिनिधित्व की पद्धति शुरू की। शुरू में ही उन्होंने गवर्नर की काउंसिलों में म्युनिसिपलिटियाँ और वाणिज्य सभों को प्रतिनिधित्व दिया। सन १९०६ में उन्होंने जमींदारों और मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया। १९१६ के विधान से सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों के ऊपर पंचक सांप्रदायिक और 'विशेष' निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए। १९३३ में अछूतों के अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव किया गया। इसके विरोध में गांधीजी ने अनशन किया, जिस पर इसमें संशोधन किया गया। इसके बाद १९३५ के विधान में और बाद में भारत की स्वतन्त्रता विषयक बातचीत में भी अंग्रेज सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और अल्पसंख्यकों को 'वेटेज' अर्थात् उनकी सख्या से अधिक स्थान देने पर ही जोर देते रहे। कांग्रेस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध थी, किंतु अंत में इसे मानना पड़ा।

यह जरूरी नहीं था कि मुसलमानों में राजनीतिक जागृति का परिणाम देना का बटवारा ही होता। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ यह था कि बहुसंख्य वर्ग अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीय ढाँचे में उचित स्थान दे। दोनों ओर से इसका रास्ता निकालने की लगातार कोशिशें भी हुई। सन १९०६ में मुस्लिम लीग की स्थापना 'मुसलमानों में अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी' पैदा करने के उद्देश्य से हुई।^{११} किंतु जल्दी ही लीग में एक वर्ग ऐसा भी उठ सड़ा हुआ जो अंग्रेजों की इस चाप-लूसी के खिलाफ था और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के पक्ष में था। मुहम्मद अली जिन्ना और मौलाना मुहम्मद अली और शीखजली जैसे प्रगतिशील नेताओं के प्रभाव से लीग ने सन १९१३ में यह प्रस्ताव पास किया कि हमारा मकसद,

११ लीग की स्थापना के समय आगा खॉं और अन्य मुस्लिम नेताओं की अनी से उद्धृत।

‘अंग्रेजी राज के अतगत स्वशासन प्राप्त करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना और इस मकसद के लिए दूसरे संप्रदायों से सहयोग करना है।’ कांग्रेस ने उसी वर्ष दिसम्बर के अधिवेशन में इसका स्वागत किया। दोनों संगठनों में मेल बढ़ा और १९१६ में दोनों के बीच प्रसिद्ध ‘लखनऊ पैक्ट’ हुआ। लीग के राष्ट्रीय हस्त के बदले कांग्रेस ने पथक संप्रदायिक निर्वाचन, अल्पसंख्यकों को अधिक स्थान और ऐसे कानूनों को रोकने का अधिकार देना स्वीकार किया, जो उनके हितों के विरुद्ध हैं।

कांग्रेस और भी आगे गई। उसने खिलाफत (तुर्कों के सुल्तान से राज्य और उनके मुसलमानों के खलीफा पद की रक्षा) आंदोलन का समर्थन किया। गांधी ने इस अवसर का उपयोग हिंदू मुसलमानों को एक झंडे के नीचे लाने में किया। नतीजा यह हुआ कि जब १९२१-२२ में गांधीजी ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध पहला जन आंदोलन या असहयोग शुरू किया तो मुसलमानों ने उसका पूरा साथ दिया। मौलाना, जवाहर, डाक्टर अन्सारी और दूसरे प्रमुख मुसलमान नेता आंदोलन में शामिल हुए। जिन्ना गांधी को पुराणपथी समझते थे और वह इस आंदोलन में नहीं शामिल हुए। लेकिन वे राष्ट्रीयता के समर्थक रहे और मुस्लिम लीग को आधुनिक राष्ट्रीय या सेकुलर लाइन पर चलाने की कोशिश करते रहे।

विरोध बढ़ा

मगर स्थिति ऐसी पैदा हुई कि कांग्रेस और लीग की एकता काम में न रह सकी और लीग को प्रगतिशील ढंग से चलाने की जिन्ना की चेष्टा भी विफल हुई। जब असहयोग आंदोलन पूरी तेजी पर था और जनता में गहरी उत्तेजना थी, भीड़ द्वारा चौरीचौरा में पुलिस थाने में आग लगा दिए जाने से क्षुब्ध होकर गांधीजी ने आंदोलन का रोक दिया। उनके इस निणय से लोग दुःख हुए। इसके बाद गांधीजी कैद कर लिए गए। असहयोग के साथ ही खिलाफत आंदोलन और हिंदू मुसलमानों का सहयोग भी खत्म हो गया। लिबरल और नरम दल कांग्रेस से पहले ही अलग हो चुके थे और उनका नया संगठन अभी दृढ़ न हो पाया था। एक ओर राजनीतिक दृष्टता थी, दूसरी ओर कई स्थानों पर हिंदू-मुसलमानों में दंगे हो गए। इससे स्थिति और खराब हो गई। १९२७ में जब साइमन कमिशन वैधानिक सुधारों के बारे में सुझाव देने के लिए भारत की स्थिति की जांच करने भारत आया, तब मुस्लिम लीग दो दलों में बंट गयी थी। एक दल के नेता जिन्ना थे, जो हिंदू-मुसलमानों के संयुक्त निर्वाचन के पक्ष में थे और साइमन कमिशन के वायकाट के कांग्रेस के साथ थे। दूसरा दल सर मुहम्मद शफी का था जो पृथक् निर्वाचन के पक्ष में था और साइमन कमिशन के काम में सहयोग देना चाहता था। सन १९२८ में स्वराज्य पार्टी वाला ने एक मक्दल सम्मेलन बुलाया। जिन्ना का गुट इसमें शामिल हुआ।

और भारत का रिपान बनाने के लिए इसने जो कमटी बनाई, उसके काम में हाथ बटाया। अपनी गुट ने इस कमटी की रिपोर्ट का नामजूर कर दिया। आगा खा की अध्यक्षता में दिल्ली में मुसलमानों का सत्रदा सम्मलेन हुआ, उसने भी इस रिपोर्ट को जस्वीतार किया। इन तरह जिन्ना अकेले पड़ गए और हताश होकर भारत छोड़ कर इंग्लैंड चले गये।

सांप्रदायिक समस्या का कोई समाधान नहीं दी जाता था। अब यह दो दलों के समनोने का प्रश्न न रह कर राजनीतिक एकरता का प्रश्न बन गया था। इस समस्या का उलझाने में अग्रज सरकार का भी हाथ था। अग्रज सांप्रदायिक समस्या की असंतियत का अनुभव करते थे, साथ ही अपनी सत्ता की रक्षा के लिए सांप्रदायिक विरोध का उभाड़ना भी चाहते थे। उनसे हाथ में अधिकार का इतलिए यह अल्प-संख्या का प्रलाभन देकर अपनी ओर खींच सकते थे। गिलाफत आंदोलन के एकाएक खतम हो जाने से मुसलमान भी कांग्रेस से निराश हो रहे थे। गांधीजी का साथ और अहिंसा पर अत्यधिक आग्रह था, जो बहुत अशा में हिंदू धर्म के आदर्शों में प्रेरित था और उह महात्मा या धार्मिक नेता का पद दिला चुका था। इससे बुद्धिवादी मुस्लिम नेता उनका खिलाफ हो गए। यह एक विडवना थी कि पुराने ग्यास के मुस्लिम नेता कट्टर मजहसी दृष्टि के थे और संकुलर या धर्मनिरपेक्ष राजनीति के विरुद्ध थे और जिन्ना जस प्रगतिशील मुसलमान गांधीजी के राजनीतिक तरीका और सामाजिक आदर्शों के विरुद्ध थे। इस प्रकार अंग्रेजों की राज-साजी, मुस्लिम कट्टरवादियों के दुराग्रह और कोई नया रास्ता निकालने में कांग्रेस की असमयता के कारण पूरी जिंज पैदा हो गई। अंत में हताश होकर भारत छोड़ने वाले जिन्ना ने ही नयी चाल बनी।

सांप्रदायिक निणय

१८२- में सांप्रदायिक राजनीति ने फलटा छाया। जिन्ना भारत लौटे। उनके विचार बदल चुके थे। जिस सांप्रदायिक विचारधारा का वह अबतक विरोध कर रहे थे उसे अब वह पूरी तरह अपना चुने थे। उन्होंने मुस्लिम लीग के सामने अपना १४ सूत्री कार्यक्रम पेश किया। इसमें मुसलमानों के जनन निर्वाचन, अधिक स्यान और अपने हितों के प्रतिकूल कानूनों का रोकने के अलावा नई बात यह थी कि कुछ प्राता का हमेशा के लिए मुस्लिम बहुमत क्षेत्र घोषित किया जाये। पहली और दूसरी गोलमेज कांफ्रेंस में मुस्लिम मांगा का आचार यही १४ सूत्री कार्यक्रम था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने सांप्रदायिक निणय (कम्यूनल अवाड) की घोषणा की। इसमें मुसलमानों की सब मांगें मान ली गयीं थी। जिन्ना के नये रूप ने भारत की सांप्रदायिक राजनीति को भी एक नया रूप दिया। अभी तक लीग का जनता में कोई सम्बन्ध न था। १९३७ के चुनावों में

उसे बंगाल और गु. पी. में कुछ स्थान मिले थे लेकिन वास्तव में वह बुरी तरह हारी थी। उसे चार मुस्लिम बहुमत प्रांत, बंगाल, पंजाब, सिंध और उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत, में से एक में भी बहुमत न मिल सका था। दूसरी ओर कांग्रेस ने मुस्लिम जन संपर्क आंदोलन शुरू किया था और मुसलमानों में पंजाब में युनियन-निस्ट पार्टी और सरहद में खा. अब्दुल गफ्फार खा. और उनके भाई खान साहब के खुदाई खिदमतगार संगठन का ज्यादा जोर था। ऐसा लगता था कि कांग्रेस और पंजाब, सरहद और बंगाल की मुस्लिम पार्टियाँ के मुकाबले मुस्लिम लीग टिक न सकेगी। जिन्ना को यह श्रेय है कि उन्होंने लीग को इस दयनीय स्थिति में उबारा और ताकतवर बनाया और १९४५-४६ के चुनावों में जबरदस्त सफलता दिलाई। इन चुनावों में लीग को ४९६ मुस्लिम सीटों में से ४४६ सीटें प्राप्त हुई।

पृथक निर्वाचन से पृथक राज्य

चुनावों में विफलता होने के बाद मुस्लिम लीग का दिमाग दूसरी दिशा में दौड़ने लगा। पृथक निर्वाचन से अब वह पृथक राज्य की मांग पर आ गई। इस मौके पर कांग्रेस की राजनीति भी चूब गई। १९३७ में कांग्रेस सरकारों की स्थापना के समय, उसमें मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात चली। जिन्ना भी इसके पक्ष में थे। किंतु जिन्ना के शब्दों में 'अधिकार के मद में' कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कांग्रेस ने यह शर्त लगायी कि लीग के सदस्यों को कांग्रेस की 'ड्रिप' को मानना होगा। इससे जिन्ना और उनका दल कांग्रेस से बहुत नाराज हो गया। यह सही है कि चुनावों के नतीजे से लीग के इस दावे का समर्थन नहीं होता था कि वह मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि है, किंतु इस दावे को कांग्रेस ने १९१६ में स्वीकार किया था और तभी से ऐसा माना जाता था। इस दावे को अब न मानने का अर्थ यह होता था कि मुसलमानों को अपना राजनीतिक संगठन करने का हक नहीं है।^{११}

लीग के नेताओं ने अब अपनी नीति एकदम बदल दी और मुसलमानों के लिए संरक्षण या विशेषाधिकार के बजाय मुसलमानों के अलग राज्य की मांग पेश की। इस मांग ने हिंदू-मुस्लिम संबंधों के सदम को ही एकदम बदल दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रांतीय सरकारों में हिंसा न मिलने के कारण मुस्लिम लीग का रुत उग्र और लड़ाकू बन गया। इसी समय से जिन्ना दो राष्ट्रों के सिद्धान्त और देश के बंटवारे के बटूर समय बन गये। जिन्ना की तीव्र और मजबूत हुई धुड़ के नेतृत्व में लीग का सारा ध्यान एक ही बात में केन्द्रित हो गया और पिछले बीस वर्षों के असमंजस से निकल कर उसने नयी ताकत पकड़ी।

^{११} इस विषय के लिए देखें, भी अब्दुल बख्श आज़ाद, 'शिया बिस्स प्रीडम' (कम्प्यूट, १९५९)

पाकिस्तान की माग

पाकिस्तान की बात सबसे पहले डा मुहम्मद इकबाल ने इनाहावाद में मुस्लिम लीग के सालाना अधिवेशन में सन १९३० में छेड़ी थी। उन्होंने पंजाब, उत्तर-पश्चिम सीमाप्रांत, निध और बलूचिस्तान को मिला कर अलग मुस्लिम राज्य कायम करने का प्रतिपादन किया था। मगर बहुत दिनों तक पाकिस्तान का यह विचार धुंधला विचार मात्र रहा। अब चुनावों में कांग्रेस की सफलता और अपनी विफलता के कारण लीग को एक नये प्रोग्राम की जरूरत थी और उसने पाकिस्तान के विचार को आंदोलन का रूप दिया। इस बीच आधुनिकता की प्रक्रिया ने मुसलमानों को भी प्रभावित किया। शिक्षा के प्रसार, शहरीयता के विकास और अखबारों व साहित्य की प्रगति ने मुसलमानों में आत्म गौरव और अपनी विशिष्टता का भाव फैलाया। लोकतंत्री राजनीति से निराशा के कारण उनमें पथ्यता का भाव बढ़ा। १९४० में लीग ने मुसलमानों के अलग स्वतंत्र राज्य का प्रस्ताव पास किया और जिन्ना ने साफ कहा कि हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के अंग नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि न केवल हिंदू और मुसलमानों का अलग धर्म और संप्रदाय है बल्कि उनकी सभ्यता, उनका इतिहास, उनका समाज और उनका राष्ट्र अलग अलग हैं। उन्होंने कहा, मुसलमानों की अपनी मातृभूमि, अपना इलाका और अपना राज्य अलग होना चाहिये। यही उनका दो राष्ट्रों का सिद्धान्त था जिसके आधार पर देश के विभाजन की मांग उठी और विभाजन हुआ।

यह नहीं कहा जा सकता कि १९३७ और १९४० के बीच लीग की नीति में जो परिवर्तन हुआ उसी ने आगे आने वाली घटनाओं का क्रम नियंत्रित किया, क्योंकि अभी भी देश की सबसे बड़ी और तात्कालिक समस्या कांग्रेस थी और विभिन्न वर्गों में उसी का सबसे अधिक प्रभाव था। लेकिन लीग ने ऐसे मौकों पर अपनी नयी नीति और आंदोलन चालू किया जब घटनाएँ बड़ी तेजी से घट रही थीं और कांग्रेस मुसलमानों के इस नये आंदोलन का कोई प्रतिकार न कर सकी। सन १९३९ में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और कांग्रेस मंत्रिमंडल ने पदत्याग कर दिया। इसके बाद कांग्रेस की अंग्रेजी सरकार से टक्कर हुई, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का समझौता का प्रयत्न विफल रहा, भारत छोड़ो आंदोलन चला और कांग्रेस के सारे नेता युद्ध की समाप्ति तक जेलों में बंद कर दिये गये।

इससे भारत में राजनीतिक शक्तियों का संतुलन बदल गया। देश भर में कांग्रेस का संगठन अस्तव्यस्त हो गया। कांग्रेस के नेताओं के जेल में बंद हो जाने से मुस्लिम लीग का मैदान खाली मिल गया। इस अवधि में उसने अपना संगठन और बल काफी बढ़ा लिया। जब लार्ड वेवेल अंग्रेजों से राजनीतिक बातचीत शुरू हुई तब लीग का स्थिति और सीढ़ा करने की शक्ति काफी मजबूत हो चुकी थी।

बहुत से लोग का स्याल है कि १९३८ में पदत्याग करने कांग्रेस ने गलती की।

वी पी मेनन ने अपनी किताब 'ट्रांसफर आफ पावर इन इंडिया' (भारत में सत्ता परिवर्तन) में लिखा है कि यदि प्राता में कांग्रेस मनिमंडल इस्तीफा न देते तो भारत के इतिहास का रुम कुछ दूसरा ही होता। पदत्याग करके कांग्रेस ने दूरदर्शिता और राजनीतिक वृद्धि के शोचनीय अभाव का प्रदर्शन किया। ^{१३} यदि कांग्रेस के लोग जेल में होने के बजाय सरकार में और निर्वाचित क्षेत्रों में रहते तो अगले चुनावों के समय, उनको लाभ होता, खास कर बंगाल और पंजाब में जिनकी विधान सभाओं में बटवारे की योजना का फैसला हुआ। यह बात कुछ हद तक सही है, लेकिन जिन बातों ने घटनाओं का भ्रम निर्धारित किया, वे कुछ और थी।

ब्रिटिश नीति

अमली बात दो थी - कांग्रेस के प्रति अंग्रेजों का रुख और भारतीय राष्ट्र के भविष्य की कांग्रेस की अपनी कल्पना। युद्ध के बाद भारत की स्वतंत्रता के बारे में जो बानचीत शुरू हुई उससे यह स्पष्ट हो गया। सन १९४५ में लाइ देवल ने मिमला में देश के प्रमुख राजनीतिक दलों का सम्मेलन बुलाया। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग में पूरा मनमोद दीक्षा और कोई नतीजा न निकला। जनवरी १९४६ में ब्रिटिश पार्लामेंट का प्रतिनिधि मंडल आया। मान में ब्रिटिश मनिमंडल का मिशन आया। लीग और कांग्रेस में समझौता न हो सकने पर कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना प्रस्तुत की। इसमें देश के बटवारे की बात नहीं मानी गयी और यूनिफ़ा आफ इंडिया नाम से एक ढीले सच की व्यवस्था की गई। इसको रखा, परराष्ट्र सच और संचार के विषय सीधे गए। दोप सारे विषय और अधिकार प्राता के हाथ में रहे। प्राता को यह भी अधिकार दिया गया कि दस बप बाद विधान सभा के साधारण बहुमत से वह इस व्यवस्था में परिवर्तन की मांग कर सकता था। प्राता को समूह बनाने का अधिकार दिया गया। इन समूहों की विधान सभा और बाप बारिणी अर्थात् सरकार हो सकती थी। हर प्रात के हर सप्रदाय के प्रतिनिधियों की संविधान सभा की व्यवस्था की गई, जिसके प्राता के तीन समूहों के अनुसार तीन खंड हाने और यह देश का संविधान बनाएगी। यह योजना बहुत कुछ सन १९३५ की सच व्यवस्था से मिलती थी। इसमें श्रुति यह थी कि वे दीप सच बहुत कमजोर था और इससे किसी भी समय यह व्यवस्था ठप हो सकती थी। स्पष्ट था कि प्रस्तावित संविधान सभा जो व्यवस्था करती वह बहुत कमजोर सच था अथ- सच (बानकै-रेन) होता। अंग्रेजों की यह याचना कांग्रेस के विचारों के बिल्कुल विपरीत थी। स्पष्ट था कि वास्तविक समस्या का सामना करने के बजाय ब्रिटिश मंत्रियों ने उगे संविधान सभा के माथे टाल दिया। इसमें भय यह था संविधान सभा सचप का जराजा बन जाती और उसी भ्रम होने की नीजत जा जानी। यद्यपि

कांग्रेस ने इस योजना को मित्रात रूप में स्वीकार कर लिया पर इसका कोई अर्थ नहीं था। क्योंकि कांग्रेस के सामने देश के बटवारे या कमजोर और पगु, राष्ट्र का प्रश्न आता तो वह बटवारे को ही पसंद करती जैसा उसने अंत में किया भी। लीग ने इस योजना को पहले स्वीकार करके बाद में अस्वीकार कर दिया और १९४६ में निर्वाचित सविधान सभा का बहिष्कार किया (यद्यपि वह जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में शामिल हुई)। यह भी अच्छा हुआ। इससे देश उस वैधानिक गतिरोध, अराजकता और सेना के बल पर सरकार पर कब्जा करने के सतरे से बच गया, जो इस स्थिति में दूसरे कई देशों में हुआ।

अंतिम दौर बड़े तनाव का रहा। ब्रिटिश प्रधान मंत्री एटली ने पार्लियामेंट में फरवरी २०, १९४७ को घोषित किया कि वे ज्यादा से ज्यादा जून १९४८ को भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंप देंगे। उसने यह भी घोषित किया कि लाड लुई मोंटवेटन यादसराय बना कर भारत भेजे जा रहे हैं और उनको इस घोषणा को कार्यान्वित करने का अधिकार सौंपा गया है। इस प्रकार जिम्मेदारी भारतीय नेताओं पर आ गयी। दूसरी ओर इस घोषणा से लीग का हींसला बढ गया क्योंकि इसका अर्थ साफ था कि यदि भारतीयों में समझौता न हो सके तो अंग्रेज उसके विभाजन के लिए तैयार हैं। इससे लीग की अलग राज्य की मांग ने और भी जोर पकड़ा। लाड केवल अंग्रेजों के हटने की कोई तारीख तै करने के विरुद्ध थे। वर्षों बाद में मौ० आजाद ने लिखा 'शायद इतिहास यह सिद्ध करेगा कि लाड केवल की बात ज्यादा समझदारी की थी।' १४

एटली की जल्दी निपटारा करने की इच्छा को लाड मोंटवेटन की जबदस्त कर्मठता और दृढ़ निश्चय का बल मिला। उन्होंने कांग्रेस और लीग दोनों पार्टियों को कोई निणय पर पहुँचने को बाध्य किया। मोंटवेटन में दूसरों को प्रभावित करने की अपूर्व क्षमता थी। उन्होंने प्रत्येक कठिनाई को सर किया और देश के बटवारे की शल्यक्रिया को बिना समय खोए या आसू गिराए पूरा किया। उन्होंने महात्मा गांधी को एक तरफ कर दिया और वह ऐसे राजनीतिक तत्त्वा को सामने ले आए जो वास्तविक स्थिति को देख कर आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा बटवारा करने को तैयार हो गए।

रक्तपात

एटली सरकार का निश्चय और मोंटवेटन का निमम सक्ल्प भी शायद कांग्रेस नेताओं को देश के बटवारे के लिए तैयार न कर पाता, यदि धटनाज्ञान ने भयानक रख न पकड़ा होता। पहले बंगाल में, फिर पंजाब में और बाद को देश के अन्य भागों में अभूतपूर्व सांप्रदायिक दंगे, सामूहिक हत्याकांड और अराजकता ने कांग्रेस

१४ मौ० आजाद-पूर्ववर्त।

नेताओं को देश का विभाजन स्वीकार करने की विवश कर दिया। इस प्रकार दो राष्ट्रों के सिद्धांत की जीत हुई। गांधीजी ने विभाजन का जोरों से विरोध किया मगर उनका न चली। उनके मधमे बड़े अनुयाई नेहरू ने दुखी दिल में और पटेल ने दब सक्त्पूवक् गांधीजी की धान न मानी।^{१५} महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक दंगों की आग को शान करने लिए प्राणा की बाजी लगा दी। उन्होंने पूव बंगाल के दगाग्रन्त नाजाग्वाली इलाकें में पदयात्रा करके हिंदू-मुसलमानों को शांति का संदेश दिया, दिल्ली में मुसलमानों की रक्षा के लिए पटेल और नेहरू की सरकार के विरुद्ध अनशन किया और मुसलमानों का पक्ष लेने के कारण अंत में एक क्षुब्ध हिंदू आतंतायी की गाली के शिकार हुए। उनके बलिदान ने देश को विभोड कर रख दिया और सारे देश में सांप्रदायिक दंगा को एकदम से शांत कर दिया।^{१६}

एक जोर अंग्रेज भारत से जल्दी हटने पर तुले हुए थे, दूसरी ओर वह कांग्रेस-नियंत्रित केन्द्र को सत्ता सौंपने के अनिच्छुक थे। वित्तु भयानक दंगा ने देश को बटवारे की अनिवार्य बना दिया। कमजोर और ढीला ढाला मध्य देश में और अराजकता पदा करता। मुसलमानों का कड़ाई से दमन करने का मनीषा भी अंत में अच्छा न होता। दोनों में से किसी भी हालत में राष्ट्र-निर्माण का वह काम संभव न होता जो भारत में सन १९४७ से हो रहा है।^{१७} तथ्य यह है कि घटनाओं ने, जो कुछ हुआ उनके अलावा और कोई रास्ता छोड़ा नहीं।

बटवारे में देर न लगी। भारत और पाकिस्तान की सीमा का निश्चय करने के लिए विधान सभाओं में वाट लिए गए और विवादग्रस्त क्षेत्रों में जनमत लिया गया। दोना राज्या में मैना, सरकारी सेवाओं, संपत्ति तथा दाने पावने का बटवारा हुआ। यह सब काम बड़ी शीघ्रता से हुआ। ब्रिटिश पार्लामेंट में भारत स्वतंत्रता बिल ४ जुलाई १९४७ को पेश हुआ और १२ दिन के अंदर पास कर दिया गया। १४ अगस्त १९४७ को इंडिया (साविजनल वास्टिचूगन) आडर १९४७, पास हुआ और दूसरे दिन भारत और पाकिस्तान दो नए उपनिवेशों की स्थापना हुई और उनकी सत्ता सौंप दी गई। अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य अनायास वापस किया

~ ~ ~ ~ ~

१५ इस फैसले पर भी आजाद के क्षोभ के लिए उगी पूर्वोक्त पुस्तक को देखें।

१६ महात्मा गांधी के जीवन के अंतिम ६ महानों में उनके व्यक्तित्व का चमत्कार दिखाई पड़ा। जिस निमयता से उन्होंने मित्रि सरकार की शक्ति को चुनौती देने के लिए दोनी वृत्त किया था उमा निमयता से सांप्रदायिक दंगों को शांत करने के लिए नोआराम्नी, कलकत्ता और बिहार में वह रत्नपान के बीच बूट पड़े। आइन्सटायन के राष्ट्र में आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए यह विश्वास करना बटिन होगा कि वास्तव में ऐसा आदमी क्या धरती पर था।

१७ बटवार के इस पहलू के बारे में, जिसमें संवृत केन्द्र की स्थापना और राज्य मशीनरी तथा राष्ट्र के निर्माण में सहायता मिली, आठवें अध्याय में 'अनेकता की भाषा' शीर्षक से विचार किया गया है।

था और बड़ी जल्दबाजी में उसे खतम कर दिया, मानो उन्हें शका थी कि कहीं भारतीय लाय उनसे यह न कह कि आप न जाइए ।

दो राष्ट्र

भारत की समस्या के समाधान के बारे में अत मे जो बातचीत और फैसले हुए वे सब अभी प्रकाश में नहीं आए हैं । मगर मुख्य बातें स्पष्ट है । देश के बंटवारे से हवा तो साफ हुई, मगर इसके परिणामस्वरूप बड़ी सांप्रदायिक कटुता और अनेक राजनीतिक समस्याएँ बनी रही । दोनों देशों की और उनकी हिंदू मुस्लिम जनसंख्या को अभी बहुत दिनों तक इन समस्याओं का सामना करना होगा । दूसरी ओर जिस प्रकार ब्रिटिश मजदूर दल की सरकार ने ब्रिटिश साम्राज्य का खातमा किया उससे भारत में उसके प्रति बड़ा सद्भाव पैदा हुआ और उसने ब्रिटिश कामनवेल्थ में बने रहने का फैसला किया । बाद में भारत ने गणतंत्र का रूप धारण करने पर भी ब्रिटिश महारानी को कामनवेल्थ के प्रधान रूप में स्वीकार किया । इस पर ब्रिटिश कामनवेल्थ से ब्रिटिश विशेषण हटाकर उसे 'कामनवेल्थ ऑफ नेशन्स' या राष्ट्रमंडल का नाम दिया । इस परिवर्तन का श्रेय जवाहरलाल नेहरू को है ।

इस प्रकार भारत का बंटवारा हुआ और भारत तथा पाकिस्तान के दो राज्य कायम हुए । भारत में कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई और ब्रिटिश राज का उत्तराधिकारी कांग्रेस राज हुआ ।

आधुनिकता की ओर

वर्तमान भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विचार करने से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि उगवा राजनीतिक विरासत किन परिस्थितियों में हुआ। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य पहलुओं पर विचार करने के पहले यह समझना चाहिए कि इस पृष्ठभूमि का भारत का वर्तमान और भविष्य की कल्पना के लिए क्या महत्व है। जैसा पहले कहा जा चुका है भारत ने अपने विरासत का ऐसा ढंग धुना है जिसमें अनेक स्रोतों से प्रेरणा ग्रहण की गई है और जिसमें अनेक सद्भावों को एक साथ सिद्ध करने की कोशिश की गई है। इसमें परंपरा और आधुनिकता के सामंजस्य की भी कोशिश की गई है। हमें देखना है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ने विकास की इस पद्धति का किन प्रकार प्रभावित किया है।

पृष्ठभूमि का महत्व

इस पृष्ठभूमि का मुख्य तत्व है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की लंबी अवधि और गहराई। इस बात में भारत एशिया और अफ्रीका के सभी नव स्वतंत्र देशों से अलग है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना सन १८८५ में हुई थी, और यह उन्नीसवीं शताब्दी में होने वाले बौद्धिक जागरण और सामाजिक सुधार की प्रवृत्ति का परिणाम है। परीक्षा रूप से यह अंग्रेजी शासन, शिक्षा, कानून और संचार की प्रणाली का भी परिणाम था।

कांग्रेस की स्थापना के ६० वर्ष बाद भी भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन जारी रहा। इस आंदोलन ने देश को बहुत बड़े बड़े नेता दिए और भारतीयों को सामाजिक और आर्थिक सुधार तथा राजनीतिक संगठन की शिक्षा और राजनीतिक विचारधारा दी। इस लंबी अवधि में आंदोलन कई चरणों में गुजरा। शुरू में करीब ३० वर्ष का समय बौद्धिक आंदोलन और वादविवाद का था। इसी अवधि में आंदोलन के आधुनिकतावादी लक्ष्य निश्चित हुए। गुरु में यह आंदोलन शहर के मध्यवर्ग में चला, फिर यह देश भर में फैला, इसका संगठन व्यापक बना,

इसके हजारों कार्यकर्ता तैयार हुए और उन सबको एक सूत्र में बांधने वाले आदर्श, प्रतीक और विचारधारा विकसित हुईं। इन कार्यकर्ताओं की राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य का व्यावहारिक शिक्षण और अनुभव मिला। हमने पिछले अध्याय में बताया है कि तिलक और गांधी जैसे महान नेताओं ने इस आंदोलन को शक्तिशाली विचार दिए, जिनसे इसका सबब भारत के शानदार अतीत से जुड़ा और जिससे समाज के परंपरावादी और नए विचार वाले, दोनों प्रकार के लोग इस आंदोलन की ओर आकृष्ट हुए। देश के सभी भागों में, शहरों और गांवों में सैकड़ों कार्यकर्ता तैयार हुए जो तिलक और गांधी, नेहरू और पटेल के मधु संस्करण थे। उनके आत्मत्याग और निस्वार्थ प्रयत्नों से यह आंदोलन जनता में फैला। इस आंदोलन की विचारधारा, आदर्श, तथ्यों और साधनों को सबने स्वीकार किया। गांधीजी ने साधनों की शुद्धता पर जोर देकर जनता और सरकार दोनों पर इसके औचित्य का सिक्का जमा दिया। अगर आंदोलन इतना दीर्घकालीन न होता और केवल शहरों तक सीमित रहना ना इसमें इतनी शक्ति और व्यापकता न आ पाती।

मगर कांग्रेस के गांवों तक पहुंचने के प्रयत्नों के बावजूद, बहुत बड़ी जनसंख्या फिर भी इससे अप्रभावित रही और राजनीति से उदासीन रही। कांग्रेस की सफलता यह थी कि वह देश में इतनी दूर तक पहुंची जितनी दूर तक हिंदू या मुगल साम्राज्य नहीं पहुंच सका था। इसमें यह बात भी सहायक हुई कि सारे देश में एक ना अंग्रेजी प्रशासन कायम हुआ। स्कूल, अदालत, डाकघर खुले और रेल पहुंची। आवागमन के साधनों के विकास के फलस्वरूप भौगोलिक दूरी कम हो गई। १८ वीं सदी के अंत तक सारा देश अंग्रेजी सत्ता के अधीन आ चुका था। इसके बाद अंग्रेजों का शासन दृढ़ होता गया। उन्होंने जमीन का बंदोबस्त किया और राजस्व की वसूली का नया प्रबंध किया। प्रांतीय और जिला के प्रशासन का पुनर्संगठन किया, प्रशासन में भारतीयों को भी स्थान दिया, नयी शिक्षा की व्यवस्था की तथा एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था के मूल्यों द्वारा नैतिकता का संस्कार हुआ। अंतिम चरण में भारतीयों को नौमिलो आदि के चुनाव का और पदग्रहण का भी अवसर मिला और शिक्षा, उद्योग तथा अन्य व्ययसाधनों में भी ऊंचे स्थान मिले। अंग्रेजों ने जो व्यवस्था विकसित की उसका प्रभाव भारतीयों के राजनीतिक संगठन और आंदोलन पर पड़ा। अंग्रेजी शासन-व्यवस्था और भारतीयों में उसकी राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतिक्रिया दोनों में एक प्रौढ़ता आ गई जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रौढ़ता प्रदान की। बहुत कम नए स्वतंत्र देशों में इसे प्रकार की परिस्थिति थी।

आंदोलन की लंबी अवधि से कुछ और लाभ हुए। राजनीतिक चेतना के सारे मुख्य तत्त्वों के कांग्रेस में संगठन से संस्था और उसके नेतृत्व तथा उसके कार्यक्रम और उसकी विचारधारा के प्रति निष्ठा पैदा हुई। गांधीजी का जनता पर जो

क्षेत्रों में दूसरी जातियाँ भी आये जाईं। किंतु आधुनिक काल के भारतीय पुनर्जागरण के प्रारंभ में ब्राह्मणों के इस नेतृत्व ने नये राष्ट्र को एक मूल में बाँधे रखा और पुरानी परंपरा से संबंध ताँडे बिना परिवर्तन को आने दिया।

भारतीय परंपरा की कुछ और विशेषताओं की भी संक्षेप में चर्चा जरूरी है। जाति प्रथा में शासक से लेकर साधारण जनता तक के काम बँटे हुए थे। शासक वर्ग का काम शासन करना और दूसरा का काम राजकीय मामलों में उनका अधिकार मानना था। इस प्रकार उच्च वर्ग या नेता और शासक वर्ग के अधिकार को परंपरा से मान्यता मिली हुई थी। इनके अलावा भारतीय विचारधारा में त्याग और आत्मसमर्पण का काम से कम उपभोग को सदा से ऊँचा स्थान दिया गया है और इसे आत्मोद्धार या आत्मोपलब्धि का साधन माना गया है। इस कारण भारतीय जनता अपने कामों से ज्यादा माँग या अपेक्षा नहीं करती थी। ब्राह्मण परंपरा के प्रभाव से ज्ञान को हमेशा ऊँचा स्थान दिया जाता था। इससे साथ ही जो वर्ग राजनीतिक या प्रशासनिक मत्ता प्राप्त करता था, उसका समाज में ऊँचा स्थान मिलता था। इससे राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार और दृढ़ हुआ। अन्य धर्मों की तरह हिंदू धर्म का कोई कलमा या अपरिवर्तनीय परिभाषा नहीं थी। इस कारण नेता वर्ग धर्म और नीति की व्याख्या देश काल के अनुसार कर सकता था, और जो बातें नये युग के लिए उपयोगी थी, उनका से सकता था और शेष को छोड़ सकता था। इसी कारण धर्म और समाज में सुधार संभव हो सका और सभ्यता की धारा में किसी व्यक्तिक्रम के बिना उसमें नयी बातें जुड़ती गईं।

इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन और हिंदू सभ्यता की लंबी परंपरा नए भारत की एकता में सहायक हुई और उसने नयी व्यवस्था को गहराई और परिवर्तन तथा ग्रहण करने की शक्ति दी। पुरानी परंपरा और लोकतंत्री व्यवस्था में निरंतर आदान-प्रदान होता रहा। पुरानी परंपरा विभिन्नता और मतभेदों के प्रति सहनशीलता धरती थी और नई लोकतंत्री व्यवस्था विचार तथा काम की स्वतंत्रता का समर्थन करती थी और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहती थी, फलस्वरूप दोनों के मेल में कोई कठिनाई नहीं हुई। यदि राष्ट्रीय आंदोलन इतना लंबा न चला होता और जनता में इतनी अँडें गहरी न गयी होती, तो स्वतंत्रता के समय नई और पुरानी परंपरा में यह सामंजस्य न हो पाता।

दूसरी बार राष्ट्रीय आंदोलन के इतना लंबा चलने के कारण कुछ कठिनाइयाँ भी पैदा हुईं। स्वतंत्रता के मिलने का नतीजा यह हुआ कि भारत ने जब देश के आर्थिक और राजनीतिक निर्माण का काम उठाया, उस समय आंतरिक और बाहरी दोनों समस्याएँ काफी उग्र हो उठी थीं। दूसरे देशों को अपने विकास का और अपनी व्यवस्था को आधुनिक रूप देने का काफी समय मिला। भारत को यह समय नहीं मिला कि वह

करे। उसे सब काम एक

साथ बरन पड़े। सब काम एक साथ करने का अर्थ यह हुआ कि आर्थिक समस्या पर सब से अधिक ध्यान देना पड़ा जबकि और समस्याएँ कम महत्त्व की न थी। इस कारण काफी गड़बड़ी हुई। अतः मैं एक रास्ता निकाला गया और कौन से काम पहले किए जाएँ इसका एक क्रम भी निर्धारित हुआ पर इस बीच बहुत-सा समय और साधन बरबाद हुए, जनता की आशा और विश्वास को धक्का लगा, जिससे सरकारी ढाँचे में बड़ी अस्थिरता आई। अतः मैं विकास का जो ढाँचा बना उस पर हम वाद में चर्चा करेंगे।

इसी प्रकार अंग्रेजी शासन की लंबी अवधि से लाभ और हानि दोनों हुए। अंग्रेजी शासन के दौरान प्रशासन आदि का जो ढाँचा बना, वह स्वतन्त्रता के बाद देश की राजनीतिक एकता और आर्थिक विकास का भी आधार बना। किंतु अंग्रेजी शासन में जो नौकरशाही का ढाँचा, शिक्षा व्यवस्था, कानूनी मशीनरी, कानून बनाने की पद्धति, कारवाई में ढीलापन और सुस्ती तथा कुछ स्वार्थी वर्गों का निर्माण हुआ, वह तेजी से परिवर्तन लाने में बाधक हुआ। समस्याओं को सुलभाने, निणय लेने और नीति निर्धारित करने में यहाँ जो अत्यधिक देर लगती है और बाल की छाल निकाली जाती है, उसका कारण अंग्रेजी शासन बाल में पड़ी सोचने की आदत, शिक्षा की पद्धति और प्रशासक का ढग है।

इसी तरह हम यह भी कह सकते हैं कि हमारी प्राचीन सभ्यता की परंपरा जहाँ नये और पुराने के सामंजस्य में सहायक हुई, वहाँ उसकी कुछ त्रुटियाँ भी हैं। शास्त्रों की ग्रन्थवाक्य समझने की हमारी आदत, हमारे सामाजिक ढाँचे की कठोरता या जड़ता, सामूहिक चेतना का अभाव, सांसारिक या लौकिक कार्यों की उपेक्षा, राष्ट्रीय भावना और संगठन का अभाव, समस्याओं और अप्रिय प्रश्नों का सामना करने के बजाय उसको टालने की प्रवृत्ति, हमें इसी प्राचीन परंपरा से मिली है और इसी कारण से हमारे यहाँ सबल लौकिक, गैरमजहूरी राष्ट्रीय सृष्टि कायम नहीं हो सकी है।

हिंदू सृष्टि, राष्ट्रीय आंदोलन और विदेशी औपनिवेशिक शासन की अनेक बातें स्वतन्त्रता के बाद भी चली आई हैं और आधुनिक विचारा, मूल्य और समस्याओं से इनकी परस्पर प्रतिक्रिया हुई है। हम स्वतन्त्रता के पहले और बाद में इस प्रतिक्रिया का विश्लेषण करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि प्राचीन परंपरा की आधुनिक प्रवृत्तियों ने किस प्रकार प्रभावित किया है और आधुनिकीकरण की चुनौती के प्रति भारत का रुख सामान्यतः क्या रहा है।

आधुनिकीकरण का स्वरूप

भारत में आधुनिकता के प्रभाव से जो प्रतिक्रिया हुई, उन्हीं पुरानी परंपरा और सृष्टि के प्रति नया बोध उत्पन्न हुआ, उनकी पुनर्व्याख्या और पुनरुद्धार के प्रयत्न हुए तथा उन्हें नया रूप देने की कोशिश की गयी। आधुनिकता के प्रतिक्रिया-

स्वरूप भागीयता की भावना बढ़ी और इसे नया अर्थ और रूप देने का यत्न किया गया।

भारत में यह बात नहीं स्वीकार की गई कि आधुनिकता का अर्थ पुरानी बातों को जड़मूल से काट करके एकदम नई बातों को अपनाना है। दूसरी ओर यहाँ यह दस भी नहीं रहा कि नई बातों में कोई तत्त्व नहीं और पुरानी परंपरा और पुराने मूल्य ही शास्वत और सही हैं।^१ अगर कहें कि भारत ने मध्यमांग ग्रहण किया और कुछ पुरानी बातों को बनाए रखने के साथ साथ नई बातों को भी स्वीकार किया यह भी भारत में हुई प्रतिक्रिया का गही यथार्थ नहीं। कुछ लोगों ने इनका यह कहना है कि भारत में प्राचीन परंपरा को सांस्कृतिक रूप दिया गया।^२ अगर इस मत में प्राचीन परंपरा को अत्यधिक महत्व दिया गया और इस पर सही ध्यान नहीं दिया गया कि आधुनिक मूल्यों और संस्थाओं ने पुरानी परंपरा का प्रतिगौरव के भाव को जगाने और उसे आधुनिक अर्थ देने में कितना योग दिया। पुरानी परंपरा या ही स्वयं नहीं जीवित हो गई। इसलिए हमें पुरानी परंपरा और आधुनिकता को अलग अलग न लेकर उनके परस्पर संबंध पर, उस प्रक्रिया पर, जिस से ये संबंध बने और एक दूसरे के लिए उनकी उपयोगिता पर विचार करना चाहिए। जब एक प्राचीन समाज अपनी समृद्ध परंपरा और विविधता को त्यागने बिना, जहाँ से नये युग के अनुरूप परिवर्तन करके अपने का जीवित रखने का प्रयत्न करता है तो नए और पुराने का यह मिश्रण क्या रूप धारण करता है, इसे समझना आवश्यक है।

परिवर्तन कब शुरू हुआ इसकी कोई तारीख या समय बताना कठिन है। यह कर भारत के लिए, क्योंकि यहाँ के समाज की यह विशेषता है कि इसका कुछ अंश तो एकदम जड़ हो गया और कुछ अंश गतिशील था रहा। यह कहना हान्यस्पद है कि भारत का समाज एकदम जड़ और निर्जीव हो चुका था, और विदेशी शासन के धक्के से इसमें फिर चेतना आई। हमने देखा है कि मुस्लिम शासन और मुगल शासन की स्थापना ने पुरानी व्यवस्था को गहरा धक्का दिया।^३ बाद विदेशी अंगरेजों का औपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ, जिसने अंततः ६ देश में एक केन्द्रीय सत्ता स्थापित हुई, बांग्ला और व्यवस्था कायम हुई।^४ सामाजिक और बौद्धिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए, जिससे विदेशी शासन

१. मैने इन विरोधी मतों पर अपनी 'ट्रेडिशन ऐंड माडर्निटी रिभिन्डर' गवर्नेट डेड में लिखन, ३, स. ३, १९६८ अध्याय, में विचार किया है।

२. देखें एच.एच. स्कोल्ड और एडमंड स्टोल्ड, 'माडर्निटी ऐंड ट्रेडिशन (१९६७) स. मान्यता इस विचार से अनुरूप रखने पर भी हम इसकी बहुत सी बातों से है, खास कर जाति-प्रथा और नस्ल संबंधी। परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व को हम ५ नहीं स्वीकार किया गया, यह एक अच्छी बात है।

लेकर आधुनिकता की पूरी पद्धति को स्वीकार कर लिया गया। वास्तव में देश के सामने जो नए आदर्श और लक्ष्य रखे गए, वे भी एक नहीं थे। उनमें से अनेक विकल्प परस्पर विरोधी भी थे। उदाहरण के लिए, देश में व्यवस्था रखने और अनुशासनपूर्वक विकास के लिए शक्तिशाली एकतंत्री व्यवस्था बनाम व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर आधारित प्रतिनिधित्वपूर्ण लोकतन्त्र, मजबूत केन्द्रित सत्ता बनाम स्वायत्त इकाइयाँ का ढीला ढाला सघ, दल की प्रतिद्वंद्विता और बहुमत का राज्य अथवा अल्पमह्यका या विशेष हितों का प्रतिनिधित्व, अव्यवस्था पर सरकारी स्वामित्व या राष्ट्रीयकरण बनाम निजी उद्योग, उन्नत औद्योगिक देशों के लिए कच्चे माल का उत्पादन और निर्यात करके उनसे सहायता और विशेष व्यवहार प्राप्त करना या खुद पूरी तेजी से उद्योगीकरण करना, और ऊँचे सुसंस्कृत वर्ग की शिक्षा-प्रणाली या समाज में समानता को बढ़ावा देने वाली सब साधारण की शिक्षा। भारतीयों में सद्व्यवस्था लोकायुक्त की पेचीदा प्रणाली को चलाने की योग्यता है या नहीं, इस पर भी अंग्रेजों को संदेह था और कुछ भारतीय भी उनसे सहमत थे। महत्त्व की बात यह है कि जतन में भारत ने कौन-सा रास्ता चुना और किस विचारधारा की जीत हुई।

इस चुनाव को ब्राह्मण की उदार विचार की प्रवृत्ति और विचारों की विभिन्नता के प्रति सहिष्णुता की हमारी परंपरा दोनों ने प्रभावित किया। कुछ पुरानी दूषित परंपराओं को त्याग दिया गया, जैसे समाज में ऊँच नीच, धोर असमानता तथा कट्टर सक्तीयता की। दूसरी ओर पुरानी परंपरा ने यह आत्मविश्वास उत्पन्न किया कि भारत के लोगों में विवेक और बुद्धि का माग ग्रहण करने की क्षमता है। इस बात पर भी सहमत थी कि भारतीय सम्यता की समृद्ध परंपरा का बनाये रखने के लिए ऐसी शासन व्यवस्था को अपनाना चाहिये, जिससे देश के सभी मतों और संप्रदायों की स्वतन्त्रता सुरक्षित रहे। आधुनिक अधिनायकतन्त्र या तानाशाही की व्यवस्था न तो इतने बड़े देश की एकता कायम रख सकती थी और न उसकी भाषा, धर्म और संस्कृति की विविधता की धरोहर की रक्षा कर सकती थी।

यह चुनाव सहज ही या स्थायी रूप से नहीं हो गया। उदाहरण के लिए बहुत से नेता मजबूत केन्द्रित एकात्मक सरकार के पक्ष में थे (और हैं) जो देश की केन्द्र-विरोधी गतिविधियों पर अकुल रह सकें। देश के विभाजन ने ढीले ढाले सघ के पक्ष में (जिसमें हिंदू बहुमत और मुस्लिम बहुमत प्रांतों का बहुत स्वायत्तता होती) सबसे बड़े तक का खतम कर दिया, और 'शक्तिशाली केन्द्र' का पक्ष और मजबूत कर दिया। लेकिन दूसरी ओर विकेंद्रित व्यवस्था की धारणा भी बड़ी मजबूत थी और प्रभावशाली प्रांतीय नेता जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत बनाया या केन्द्र का सारे अधिकार दे देने से विरुद्ध थे। विवादी परम्परा केन्द्रीकरण से विरुद्ध थी और गांधी का राष्ट्रीय शासन बनाना या गरीब और

घोषित ग्रामीण जनता को देश की स्वतंत्रता से हाने वाले लाभों का उचित हिस्सा देना चाहनी थी। देश के नविधान के निमानाओं को इन दावा विराधी विचार-धाराओं में सामंजस्य करना था, जत उन्होंने ऐसी व्यवस्था की जिसमें केन्द्र को व्यापक क्षेत्र और शक्ति-साधना में प्रमुख भाग और अवशिष्ट अधिकार दिये गए। साथ ही राज्यों का भी काफी अधिकार प्राप्त हुए। आगे चल कर एक ओर बात की गई जिससे भारतीय राज्यव्यवस्था के सदीय स्वरूप को और बल मिला। यह थी पंचायती राज (लोकतंत्री विकेन्द्रीकरण) की व्यवस्था। इसका आधार पुरानी परंपरा और गांधी-विचारधारा में था, लेकिन इसे लागू करने का श्रेय जवाहरलाल नेहरू को था। इस पद्धति पर और भारतीय सभ्य व्यवस्था के साधारण स्वरूप पर हम आगे के अध्यायों में विचार करेंगे। यहां हम यह देगे कि केन्द्र और परिधि (राज्य) के संबंध को निश्चित करने में, परंपरा और आधुनिकता की प्रवृत्तियां, उनके प्रभाव से निर्मित राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा, देश की परिस्थितियां तथा नेताओं की दूरदर्शिता और विचार-इन सब का प्रभाव पड़ा।

इस नई व्यवस्था का चलाने में सबसे महत्वपूर्ण भाग था एक मध्यवर्ती नेतृत्व का जो सबसे ऊपर के राष्ट्रीय नेताओं में और सबसे नीचे के ग्रामीण नेताओं में संबंध जोड़ता है। इन बीच के आंदोलन ने प्राचीनता और आधुनिकता में समझौता कराने में बड़ी योग्यता का परिचय दिया है। भारत में राजनीतिक सौदेबाजी या मोल भाव की इस नई प्रणाली को कुछ राजनीतिक आलोचक सम्य नहीं कर सके।^४ ऊपर के नेताओं और जनता के जगुआ में यह मोलभाव सीधा नहीं, उपर्युक्त मध्यस्थ वर्ग के जरिये होता है। यह मध्यस्थ वर्ग जिला या निवाचन क्षेत्र के स्तर पर काम करता है। ये मध्यस्थ दलाना की भांति सहज सौदा हो नहीं पड़ता, बल्कि ये दोनों पक्षों का एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, और बताते हैं कि उन्हें क्या अवसर मिल रहे हैं। इस तरह वे नई व्यवस्था के सर्वोत्तम संचालक और सगठक सिद्ध होते हैं।

पश्चिमी लोकतंत्र में विभिन्न हिता का समुन्वयन या एकीकरण राष्ट्रीय स्तर पर होता है जबकि पुराने ढंग की राजनीतिक व्यवस्था में हित व निष्ठाएं अलग अलग खंडों में बंटी होती हैं। भारत में जो नई प्रणाली विकसित हुई है, वह इस से भिन्न है। इस में शक्ति बिखरी हुई या अकेन्द्रित है और विकसित हुई है एक व्यापक व्यवस्था के अंतर्गत अनेक स्वतंत्र छोटी व्यवस्थाओं का रूप धारण करता है।

४ माइरन वानर, 'द पोलिटिक्स ऑफ स्केयर्स'। पब्लिक प्रेस एंड पोलिटिकल रेस्पॉन्स इन इंडिया (दिमागो १९६२)। इसका सारांश देते हुए भूमिका में मेथियल आमंड का कहना है कि भारत में सौदेबाजी का प्रणाली का प्रभाव है। मगर वानर ने इस बात पर जोर दिया है कि यहाँ सामुदाय की परिपाटी नहीं। इन्होंने इस विषय पर अ थाय ५ में सविस्तर विचार किया है नेचुरल में साथी सौदेबाजी का उभरती हुई प्रवृत्ति के लिए देख अ थाय ८।

इन छोटी व्यवस्थाओं से स्थानीय हिता की रक्षा हाती है। पुराने समय में स्थानीय सामंत या मुखिया और उनकी जायित प्रजा में जो सन्ध होता था कुछ बसा ही इस मध्यवर्ती व्यवस्था का भी है। इसके साथ ही जायुनिक राजनीतिक क्रिया-कलाप में भी ये हाथ बढाती है। इस प्रणाली का हम मध्यवर्ती समुच्चयन कह सकते हैं। आगे के अध्याय में हम प्रशासनिक और दलीय प्रणाली में इस मध्यवर्ती गत्य के स्थान पाने पर विचार करेंगे। इस समय इतना ही कहना काफी है कि पुराने और अनेकात्मक समाज में राष्ट्रनिमाण की क्रिया इस प्रकार की मध्यवर्ती प्रणाली का जन्म देती है, जो केन्द्र और इकाइया में पुरानी और नई व्यवस्था में सन्ध जोडती है। ५ इस मध्यवर्ती प्रणाली का मुख्य काम नेता और जनता, सरकार और प्रजा, केन्द्र और प्रदेश या जिला के बीच मध्यस्थता करना है।

परपरा और परिवर्तन की प्रवृत्तियाँ की परस्पर क्रिया पर विचार करते समय राजनीतिक विकास सन्धों कुछ और प्रश्न उत्पन्न हैं। एक तो यह कि परपरा और जायुनिकता की इस दुहरी प्रणाली की केन्द्रीय प्रतीक कहा तक प्रभावित कर सकते हैं। नई शिल्प विधियाँ और राजनीतिक तन्त्र के सामने पुराने आदर्श और प्रतीक डगमगा रहे हैं। इस स्थिति में यह प्रश्न महत्व का है। दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसे अनेकात्मक समाज में राष्ट्रीयता का सन्ध बोध कहा तक हो सकता है। तीसरा, यदि नई अस्मिताएँ या निष्ठाएँ उदय होती हैं तो उसके साथ कौन से नए सन्ध और अन्तर उत्पन्न होते हैं। तीसरे, ऐसी दोमूही (आगे और पीछे देखने वाली) व्यवस्था में भविष्य की ओर देखने की प्रवृत्ति कैसे लाई जा सकती है, जिससे आगे उठने वाली समस्याओं को देखा जा सके और उनका उपाय किया जा सके और उनको भविष्य के भारोंसे न छोड़ा जाए।

राजनीतिक संस्कार और नई व्यवस्था की सफलता सन्धों अध्याय में हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे। यहाँ हम कुछ संकेत करेंगे।

केन्द्र और परिधि

प्रत्येक सम्यता में कुछ केन्द्रीय प्रतीक होते हैं जो पूरे समाज को बाँधे रहते हैं। भारत में भी इसी प्रकार के संस्कारों की एक जटिल परपरा थी, जो विभिन्न प्रदेशों

५ बर्क, दुखान, टागविक, टोनाग तथा अन्य ऐजमा के ग्रंथों में मध्यवर्ती समूहों और उप व्यवस्थाओं का महत्व स्थापित किया है। इधर एडवर्ड शिल्स तथा राबर्ट टाल ने इस विषय पर विचार किया है। भारत में आर. आस्करन ने इस विषय पर काफी लिखा है। परिचय के इस साहित्य की समीक्षा के लिए देखें गारिस पिना, 'मास सोसाइटी एंड पालिटिक्स मूवमेंट्स-ए यू फामुलशन (द एनुअल अमेरिकन नैशन ऑफ सोसायोलॉजी, मई १९६८) तथा आर. आस्करन 'सोसियोलॉजी ऑफ पालिटिक्स' (बर्क १९६८)

मे विभिन्न स्थानीय समाजा की विचारधारा का निमाण करती थी। भारत की यह विशेषता थी जि यहा की परंपरा के निमाण करने वाले ये प्रतीक कि सी राज नीतिक व्यवस्था से ध्ये नहीं थे।^५ इस परंपरागत व्यवस्था पर जाधुनिकता की प्रवृत्तिया का प्रभाव पडा जिसके साथ नई संस्थाएं, मूल्य और प्रतीक आए। इन नए प्रतीका ने पुराने विश्वासा को बिना नष्ट किए, पुरानी निष्ठाआ और प्रतीका का नया रूप दिया और पुरानी और नई व्यवस्थाओं मे मेल मिलाया। इस प्रक्रिया ने नए मध्यस्थ वर्ग को जन्म दिया, जो राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था और स्थानीय समाजा का जोड़ता है। य मध्यस्थ वर्ग नए राजनीतिक प्रतीका का जनता में प्रचार करता ह। जमा कि कहा जा चुका ह ये नए प्रतीक बिलकुल नए नहीं हैं, इन्होंने पुराने प्रतीका और विचारा मे से बहुत कुछ ग्रहण किया ह। इस प्रकार भारतीय समाज की विविधता नई व्यवस्था मे भी बनी रही। यह प्रक्रिया अभी भी जारी ह, इसके द्विआत्मक रूप की उमेक्षा नहीं की जा सकती। नए केन्द्रीय प्रतीक उत्ती हद तक साधक होत हैं, जिस हद तक वे परंपरागत विविधता को बनाये रखत ह। यह जरूरी नहीं कि परंपरा हमेशा पुरानी ही हो। नई परंपरा भी तजी से बनती रहनी ह। स्मरण रखना चाहिए कि एक लगातार चली आई सम्यता में जाधुनिकता तभी जीवित रह सकती ह जब वह स्वयं परंपरा बन जाए।^६ पुराने प्रचलित परंपरा के ढांचे में मिल कर ही नए केन्द्रीय प्रतीक पूरे समाज में व्याप्त होत हैं। इसी प्रकार वे केन्द्रीय बनते हैं।

जो बात प्रतीको पर लागू होती है, वही राष्ट्रीय निष्ठा पर भी लागू होती है। इस विषय में भारत का तरीका पश्चिम में भिन्न है। यदि पश्चिम की तरह महा भी सब लागू पर एक ही निष्ठा लादने की कागिश की जाती, ता या तो यह चेष्टा विफल हाती या यह देश को टुकड़े टुकड़े कर देती। छोटी छोटी आदिम निष्ठाएं राष्ट्रीय व्यवस्था पर तनाव कम करती ह। साथ ही राष्ट्रीय निष्ठा, विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी नि ठाआ पर ही आधारित होती है। भारत जग विशाल और विविधतापूर्ण देश में ही नहीं, किसी भी देश में एक अस्पष्ट और अमूर्त राष्ट्र के प्रति तादात्म्य या निष्ठा समभव नहीं। भारत क राष्ट्रीय आंदोलन को लवी अवधि और गहराई ने यहा राष्ट्रीय निष्ठा के निर्माण के लिए आधार

५ राजन् रेडफोर्ड 'सिविलाइजेशन ऐन कंवरल स्टूडियस' 'समर फार एडवार्ड स्टडी इन बिहेवियरल साइम स्टानफोर्ड में दिया गया भाषण तथा बनावट प्रम कोन और मेरकिन मैरियट 'नेटवर्क ऐंड सम्स' इन द इंडियन आफ इंडियन सिविलाइजेशन, जर्नेल आफ मासल रिस्च (रांचा) १ सित १९९८

७ राजन्नाति और सरकृति के इन अलगभाव पर बताया ७ में विचार दिया गया है।

८ आधुनिकता के परंपरीकरण पर मेरे, 'ट्रैडिशन ऐंड माडर्निटी सिंथेसिड' में विचार दिया गया है।

रामा । राष्ट्रिय आदालत पुरानी निष्ठाओं और प्रतीकों का सहारा न ले कर ही सदा ही सदा । स्मरता व बाद भी यही बम जारी है ।

जब हम इन निष्ठाओं के स्वरूप पर विचार करते हैं तो हम परंपरा और परिवर्तन का परस्पर क्रिया का ज्ञान होता है । अगर यह कहा जाता है कि पुराने समाज में काया का विभाजन ठीक नहीं होता, जबकि नए समाज में यह विभाजन बूझने और जटिल होता जाता है । पर भारत के उदाहरण से इस धारणा का खंडन होता है । छठे अध्याय में हम देखेंगे कि न सिर्फ भारत की प्राचीन समाज व्यवस्था में काया का बदलाव बूझने और जटिल था, बल्कि यह व्यवस्था स्थिति के अनुसार बदलती भी रहती थी । आधुनिक युग में एक तरह की जाति, मजदूर भाषा और प्रजा व पुराने विभाजनों ने जातीय प्रादेशिक और भाषिक साठना और संस्थाओं का रूप लिया है दूसरी ओर नए नए नए विस्मय के विभाजन भी पदाए गए हैं और नई संस्थाओं और पदों की व्यवस्था के जग बने गए हैं । ये नए विभाजन नए जग के व्यवसायिक गठन के आधार पर और विप्लवकारी राजनीति का आधार हैं । अगर इन नए वर्गों के संघर्ष युगों पर परंपरागत वर्गों के ही वर्गपर हाव है । जग देने के बाद तो मनुष्य पहले राजशाही ने नए पैदा हो अपनाया, पुराने धार्मिक धारणा के खंडन ने नए उद्योग-प्रतिष्ठान कायम किए और वाणिज्य मंडलों की स्थापना की संस्था में पुराने राजा वर्गों के साम्राज्य का प्रमुख स्थान रहा । जहां इन प्रकार का विचारिता रहा और बिलकुल नए लोगों का उदय हुआ, वहां उनकी भी समाज के पुराने ढांचे में जग स्थान दिया गया ।

इस प्रकार जो वर्ग संस्थाओं और पदों के दायरे में बाहर रहते थे उनका भी अंदर आने का मोह मिलता । पिछड़े जातियों के लिए सरकारी नौकरियां, शिक्षा सम्मानों और विधानसभाओं में स्थान सुरक्षित किए गए । सभी राजनीतिक संगठन विभिन्न जातियों का जग रखने का महत्त्व समझते हैं । इससे पुरानी व्यवस्था की यह त्रुटि दूर हुई कि सारी जातियां एक ऊंची जातियां हैं या गणों में रक्षा या और सारी जातियों का दूध का दूध निराला था तथा व एक तरह से राष्ट्र की मर्यादा में बंटे रहती थी । मनुष्य राज्य आगामी जैसा उग्र राष्ट्रों में भी मनुष्य बुराई था । भारत में वर्ग-संघर्ष के घट स्वरूप के परिवर्तन का एक कारण यह भी है कि यहाँ बहुत-सी जातियां हैं जिन कारण रही बाह्य मनुष्यों को अंदर आने का मोह मिलता रहा और व्यवस्था की तोरत रही जान गई । जाति प्रथा के अभाव में यह है एक विशेषता बाहर से आने वाले मनुष्यों का । इस संभावना तथा विचारों के अभाव में अनेकों प्रवृत्तियां रही हैं । भारत में पुराने और नए तरीकों में का वैज्ञानिक और नए वैज्ञानिक व्यवस्था के अभाव में जग वर्गों का टकराव रहा हुआ पाई । आधुनिकीकरण और परिवर्तन के प्रक्रिया का प्रारंभ पहले ही हुआ था का बहुत बड़ा हाव था । मनुष्य के लिए

नेहरू के वस्तुनिष्ठ और सचीले दृष्टिकोण और प्रतिनिधित्व की प्रणाली में उनकी
 वास्था से भी इस प्रक्रिया में बहुत मदद मिली।
 मगर उग्र सघर्ष या छद्मवीर्य के जमान का सारा श्रेय पुरानी अनेकनिष्ठ
 समाज-व्यवस्था को ही नहीं है। स्वतंत्रता के बाद शुरू से ही राष्ट्रीय नेता वग ने
 भी सघर्ष और जसतीय के कारणों का दूर करने का प्रयत्न किया। यह उनकी
 दूरदर्शिता का द्योतक है। इस प्रकार उन्होंने जमींदारी और सामंती अधिकारों
 का अंत किया, मजदूरों के हित के कानून बनाये पिछड़े वर्गों और हरिजनों को
 विशेष सरदान और अधिकार दिये, हिंदू कोड बना कर स्त्रियों की स्थिति सुधारी
 संपत्ति के अधिकारों को सामाजिक न्याय के ऊपर स्थान मिले इस उद्देश्य से
 सचिवालय में सचोवन किये, भाषाओं के विवाद को मुनधाने के लिए राज्यों का
 पुनर्गठन किया। सघर्ष से अलग होने के आंदोलन पर राक लगाई तथा राष्ट्र
 में ही की गई और इनसे सघर्ष और तनाव दूर होने में बड़ी मदद मिली। हो
 सकता है कि इन सभी कदमों का पहले से न सोचा गया हो, परंतु इन सब की
 जड़ राष्ट्रीय आंदोलन और नेताओं की विचारधारा में थी। इस प्रकार राष्ट्रीय
 सगठन में नेताओं की राष्ट्रीय विचारधारा और दूरदर्शिता का भी उनका ही हाथ
 था जितना पुरानी सहिष्णुता और समन्वय की परंपरा का।

परिवर्तन के प्रेरणा स्रोत

परंपरा और परिवर्तन की चर्चा खतम करने से पहले हम चार बातों पर
 जोर देंगे। एक तो यह कि भारत से सामाजिक और राजनतिक ढांचे न जो
 परिवर्तन आया उसकी प्रेरणा नये विचारों, संस्थाओं, शिल्प व उद्योग और संचार
 के नए साधनों के सघर्ष से मिली। परंपरा के लचीलेपन और ग्रहणशीलता पर
 जोर देते हुए, कुछ लोग पुरानी परंपरा को ही परिवर्तन का स्रोत समझ बैठे हैं।^९
 हम इस धारणा का खंडन करते हैं। परंपरा पर परिवर्तन की प्रतिक्रिया होती है
 वह परिवर्तन को जन्म नहीं देती। इसके प्रमाण हैं कि जब अंग्रेजी राज की
 शुरुआत हुई उस समय समाज में कुछ परिवर्तन होने लग गये, किंतु इसमें कोई
 संदेह नहीं कि परिवर्तन का मुख्य स्रोत पश्चिम का प्रभाव ही था।^{१०}
 दूसरी बात यह है कि इस परिवर्तन को प्रगल्भ करनेवाला एक नया नेता या
 सुधारक वग था, यह समाज की केन्द्रीय परिचालक शक्ति था। समाज के निचले
 और बीच के स्तरों पर भी इसी प्रकार के नेतृत्व का उदय हुआ और इसी ने देश

^९ रणलाल पेंड हड़वल्ल, पूर्वोक्त और सिंगर, पूर्वोक्त।

^{१०} पश्चिमीकरण के नृशास्त्रीय विवेचन के लिए देखें, श्रीनिवास सोशल चेंबर इन माइन्स
 इंडिया (वर्कले १९६६) अध्याय-२।

पर आधारित न थी, साथ ही वह अस्पष्ट भी न थी इसमें परंपरा और जायनिक्ता
 धुली मिली थी। महान नेताओं की तरह इस संगठन का भी जनता पर चमत्कारी
 प्रभाव पड़ा। १२ भारत को जायनिक्ता की ओर ले जाने वाली यह ऐतिहासिक
 शक्ति थी। इस राष्ट्रीय संगठन ने मामले में ही भारत अन्य जनक देशों से अधिक
 भागवान रहा।

इस प्रकार भारत की प्राचीन सृष्टि ने जायनिक्तीकरण में उपयुक्त कई बातें
 सहायक हुई। ये थी इतिहास के अत्यंत दीर्घजीवी और शक्तिशाली विदेशी शासन
 के साथ जाया जायनिक युग का जबदस्त प्रभाव तथा राष्ट्रीय आंदोलन जायनिक
 विचारों से ज्ञातप्राप्त देशव्यापी प्रभाव वाला राष्ट्रीय नेतावर्ग चमत्कारी व्यक्तित्व
 वाले महान नेता और व्यापक राष्ट्रीय संगठन। इसका साथ ही हमारी पुरानी
 रंपरा का लचीलापन और गई बाता को ग्रहण करने की शक्ति ने भी भारत के
 जायनिक्तीकरण में जबदस्त योग दिया।

१२ इस विषय के सैद्धांतिक विवेचन के लिए देखें - एम्बेड्जि सिंग, "द कॉन्फ्रेंसेशन येंड ऑफ़
 ईस्ट आरू वैरिइटा", बंबई ५ एप्रिल १९५८, १, अक्टूबर १९५८। इसी प्रकार कांग्रेस के बारे
 में विवेचन के लिए देखें - मेरा निबंध "नेशन मेकिंग येंड कॉन्सेप्स द नेस ऑफ़ द इंडियन
 नेशनल काँग्रेस - सेवेंथ वर्ल्ड काँग्रेस ऑफ़ द इन्टरनेशनल पोलिटिकल साइंस असासिएशन,
 मुंबई १९६७।

मे नये विचारा ना फलाया और पुराने समाज को नई दिशा और नये उद्देश्य दिये । नई सम्मेलन नए मूल्य और नए तरीका का चालू करने का मुख्य कार्य नए नेताओं ने किया और स्थानीय प्रमुखा और जनसाधारण ने इनका राजनीतिक समर्थन दिया और इनके नेतृत्व को स्वीकार किया ।^{११} इस प्रक्रिया का दम दान से भी बल मिला कि नेताओं अचिरतर परंपरागत प्रमुख वर्ग से ही आए थे और उन्होंने पुरानी परंपरा और मूल्य को ही नए रूप में जारी रखने का प्रयत्न किया था । नई शिक्षा का मजस उत्साहपूर्वक पुराने ब्राह्मण और ऊंची जातियां ने ही जपनाया (संस्कृत माहिंय और चर्दिक अध्ययन की परंपरा नई शिक्षा में भी आई) इस प्रकार परंपरागत विद्या के संरक्षक नई विद्या के भी संरक्षक बने । इससे परिवर्तन की क्रिया सहज हुई । फिर भी देश के विभिन्न भागों में इस आधुनिकतावादी शहरी, पौर्व और अग्रणी शिक्षित प्रमुख वर्ग का उदय हुआ, जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता था उसी के कारण आधुनिकीकरण में एकमूढता आई । बाद में निचली और बीच की श्रेणियों में गांधी और वस्त्रा में भी आधुनिकतावादी नेताओं का उदय हुआ जिनके कारण आधुनिकता का प्रसार हर स्तर पर हुआ ।

तीसरी बात यह थी कि आधुनिकता और सुधार के आंदोलन का कुछ अत्यंत प्रभावशाली और महान व्यक्तित्व के नेता मिले और सामान्यतया ये नेता दीपगोत्रीय थे और उन्होंने लगे जबकि तब देश का नेतृत्व किया । गांधी के महान नेतृत्व की अवधि सन १९२० से १९४८ तक थी, नेहरू को १९४७ से १९६४ और पटेल की १९३० से १९६० तक । इनके अलावा भी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक प्रभावशाली नेताओं ने इनके कार्य को जारी रखा और फैलाया । गांधी में नेताओं के निमाण की बड़ी खूबी थी और उन्होंने देश का सफाई कमठ कार्यकर्ता दिए, जिन्होंने पुराने विचार के लोगों को भी अपने आंदोलन में खींच लिया । कम देशों को ऐसे महान नेता और उत्साही कार्यकर्ताओं का दल मिलने का सामान्य हुआ ।

अतः में, इंडियन नेशनल कांग्रेस का महान संगठन भी आधुनिकता की प्रमुख शक्ति सिद्ध हुई । न केवल आधुनिक काल में देश का ऐसे महान नेता मिले जो पुराने इतिहास के वीरा की श्रेणी में रखे जा सकते हैं, बल्कि एक ऐसा महान राष्ट्रीय संगठन भी मिला जिसका ८० वर्ष से ऊपर देश पर अग्रिम प्रभाव रहा । बहुधा नेहरू आदि नेताओं को जिन बातों का श्रेय दिया जाता है, वे बिना इस महान संगठन का सहारा मिले संभव न हो पाती । कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जिसने अनेक स्रोतों से प्रेरणा ग्रहण की । इसकी विचारधारा किसी कट्टर मतवादी

^{११} दक्षिण, इंग्लैंड, पोलिटिकल साइंस असोसिएशन की सातवीं वरल्ड कांग्रेस (सेप्टेम्बर १९६७) में मेरा निबंध 'इण्डियन आफ नेशन बिल्डिंग फार द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोलिटिकल सिस्टम्स' ।

७
८
९

पर आधारित न थी, साथ ही यह अस्पष्ट भी न थी, इसमें परपरा और जाधुनिकता
धुली मिली थी। महान नेताओं की तरह इस संगठन का भी जनता पर चमत्कारी
प्रभाव पड़ा। १२ भारत की आधुनिकता की ओर ले जाने वाली यह ऐतिहासिक
शक्ति थी। इस राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से ही भारत जय जन्म देना संभव
मान्यमान रहा।

इस प्रकार भारत की प्राचीन संस्कृति के आधुनिकीकरण में उपयुक्त कई बातें
सहायक हुई। ये थी इतिहास के अत्यंत दीर्घजीवी और शक्तिशाली विदेशी शासन
के साथ आया आधुनिक युग का जबदस्त प्रभाव तथा राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक
विचारा से आतप्रातः देशव्यापी प्रभाव वाला राष्ट्रीय नेतावर्ग, चमत्कारी व्यक्तित्व
वाले महान नेता और व्यापक राष्ट्रीय संगठन। इसके साथ ही हमारी पुरानी
परपरा का लचीलापन और नई बातों का ग्रहण करने की शक्ति ने भी भारत के
आधुनिकीकरण में जबदस्त योग दिया।

१२ इस विषय के सैद्धांतिक विवरण के लिए देखें - एडवर्ड शिश, 'द कम्युनिस्ट प्रिंसिप-
ल ऑफ पैरिडमा' बल्लू पब्लिशिंग १९९८, १, अक्टूबर १९९८। इसी प्रकार कामस के बारे
में विवरण के लिए देखें - मेरा निबंध 'नेशन मेकिंग ऐन्ड कान्सेप्स द वेस ऑफ द इंडियन
नेशनल कांफ्रेंस - सेवेंथ बल्लू कांफ्रेंस ऑफ द इंडियन नेशनल पोलिटिकल साइंस असेसिएशन,
सुलेस १९६७।

पर लोकतन्त्री सत्स्थाथा का लबा चौड़ा ढाचा नी खडा कर दिया गया जो अत तक काम कर रहा है। इसका कारण यह है कि मूल बातों पर सत्यश्रुता के पहले की पीढ़ी एवमत थी और स्वतन्त्रता के बाद की पीढ़ी में भी इही विचारा को मायता मिली। हम दख चुके हैं कि राष्ट्रीय आन्दोलन के लंबे क्रम में किस प्रकार सिद्धांता और उद्देश्या पर सुल कर विचार हुआ और उह कांग्रेस के प्रस्तावा में ठास रूप दिया गया। सन १९२८ में ही कांग्रेस द्वारा आयोजित सवदल सम्मेलन ने मातीलाल नेहरू कमेटी को नियुक्त किया* जिम्मे स्वतन्त्र भारत के राजनितिक ढाचे की रूप-रेखा बनाई। इसने मसदीय और सधीय ढाचे की मिफारिश की थी और मूल अवि-कारा की विस्तृत सूची बनाई थी। इस सूची के १६ में म १३ अधिकार १९१० में तैंगार सविधान के मौलिक अधिकार आर निर्देशक सिद्धांत सवधी अध्याय में करीब करीब उनी रूप में ले लिए गए। १९३१ में कराची कांग्रेस में मोतीलाल के पुत्र जवाहरलाल ने प्रसिद्ध कराची प्रस्ताव पेश किया जिसमें कांग्रेस के उद्देश्या को विस्तार से निरूपित किया गया था। कांग्रेस के इतिहास-लेखक डा० सीतारामय्या के शब्दा में जवाहरलाल का कहना था कि इन बातों पर राष्ट्र का दिमाग बिलकुल साफ होता चाहिए और जनता में इन्ही का प्रचार होना चाहिए।^१

इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पहले से विचार स्पष्ट होने के कारण सविधान सभा में (१९४७-४९) इस पर बहुत ज्यादा बहस-मुबाहसे की जरूरत नहीं पडी।

फिर भी इस समय सोचने का मौका था कि देश में किस प्रकार का राज्यतन्त्र कायम हो। सविधान सभा में कुछ लोगो ने कहा कि देश का पुरानी सत्स्थाथा को नए युग के अनुरूप कुछ परिवर्तन के साथ स्थापित किया जाय। कुछ लोगो का स्थान था कि अनपढ जनता को वाट और चुनाव का अधिकार देना ठीक नहीं, और ये चीज देश की पुरानी परंपरा के प्रतिकूल हैं। परन्तु आधुनिकतावादिया की सल्ला अधिक थी और उनका कहना था कि भारत का इधर केवल मसदीय लोक-तन्त्र का ही अनुभव हुआ है, और मध्यकालीन या प्राचीन राज्य का अनुभव अब काम नहा दे सकता क्योंकि आधुनिक युग का तकाजा है कि जनसमूह का दश के शासन में हिस्सा दिया जाय और आर्थिक व सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा की जाय। गरीबी और निरक्षरता के आधार पर जनता को अधिकार से वंचित रखना अंगरेजों के तर्कों को स्वीकार करना है जो स्वयं अपने देश में ता लाकतन्त्र की दुहाई देत थे परन्तु भारतीयों को स्वशासन के अयोग्य मानत थे।^२

* सम्मेलन में ३४ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। देखें - ग्रेन विथ आस्टिन

^१ द इंडियन कान्टिन्ट्यूशन कार्नेर स्टोन आफ द नेशन (१९२९-३०)।

^२ पर्याप्त सातारमैया, 'द इस्ट्री आफ द इंडियन नेशनल कायस' (वर्ग १०४६) - १, पृष्ठ ४६३।

^३ देखें - ई. स्टोस, 'द इंग्लिश युनिव्ज़ेरिबन्स पेंड इंडिया' (आत्मनाराई १९५६)।

संस्था-निर्माण

स्वतंत्रता के साथ भारत में परिवर्तन और पुनर्निर्माण का नया दौर शुरू हुआ, किंतु इससे राजनीतिक परंपरा के विकास का चलता हुआ क्रम टूटा नहीं। हिंदू परंपरा पाश्चात्य विचारधारा और राष्ट्रीय पुनरुद्धार की भावना की परस्पर प्रति क्रिया से परिवर्तन का जो प्रथम स्वरूप हुआ उसने भारतीय समाज की नींव को अघात पहुँचाए बिना उसे एक नयी दिशा दी। अगस्त १९४७ में सत्ता देश के पुराने और नए नेताओं के हाथ में हो आई। जिस कांग्रेस ने अब तक राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था उसी ने अब देश का शासन सभाला।^१ विचारों और अनुभवों में नया शासक वर्ग बहुत सी बातों में पुराने शासक वर्ग से मिलता था। ब्रिटिश शासन के अंत के बाद भी, उसके आदमी, संस्थाएँ और विचार बने रहे। इन विचारों और परिपाटियों को संवैधानिक और संस्थागत रूप दिया गया।

संविधान का निर्माण

एशिया और अफ्रीका के नए स्वतंत्र देशों को अपना संविधान बनाने और उस अमली रूप देने में बहुत कठिनाई हुई है।^२ भारत में ऐसी कोई कठिनाई नहीं हुई। न सिर्फ यहाँ तेजी से विस्तृत संविधान बना लिया गया^३ बल्कि उसने आधार

१ गांधी स्वयं इसके विरुद्ध थे। वह चाहते थे कि राजनीतिक संगठन के रूप में कांग्रेस को भंग करके उसे लोक सभा संस्था का रूप दिया जाए। यद्यपि यह उनके आदर्श के अनुरूप था, पर यह राजनीतिक वास्तविकता की न समझ समझे वा शोचक था और इसी लिए विनी ने इस पर ध्यान न दिया।

२ एन्वर्ड शिल्स का निबंध 'द फाचून्स आफ कांस्टिट्यूशनल गवर्मेंट इन द पोलिटिकल डेवलपमेंट आफ द न्यू स्टेट्स' ज्ञान इन्स्टीट्यूट द्वारा दिये 'डेवलपमेंट फार इंडिया' (दरहम १९४९) तथा सेमुएल पी. हंटिंगटन 'पोलिटिकल डेवलपमेंट ऐंड पोलिटिकल ठिंके वर्ल्ड पोलिटिक्स, १७, स ३ अप्रैल १९६५।

३ दिसंबर १९४६ से नवंबर १९४९ तक १६५ दिन संविधान सभा ने काम किया। जनवरी २६, १९५० को नया संविधान स्वीकार किया गया और भारत को पूर्ण प्रभुतामान्य शोक्तता तक गणराज्य घोषित किया गया।

पर लोकतन्त्री समस्या का लवा चौड़ा ढांचा भी खड़ा कर दिया गया जो अब तक काम कर रहा है। इसका कारण यह है कि मूल बातों पर स्वतन्त्रता के पहले की पीढ़ी एवमत ही जोर स्वतन्त्रता के बाद की पीढ़ी में भी इन्हीं विचारों को मायता मिली। हम देख चुके हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे क्रम में किस प्रकार सिद्धांत और उद्देश्यों पर खुल कर विचार हुआ और उन्हें कांग्रेस के प्रस्तावों में ठोस रूप दिया गया। सन १९२८ में ही कांग्रेस द्वारा आयोजित संवदल सम्मेलन ने मोतीलाल नेहरू कमेटी को नियुक्त किया^४ जिसने स्वतंत्र भारत के राजनैतिक ढांचे की रूप-रेखा बनाई। इसने संसदीय और संधीय ढांचे की सिफारिश की थी और मूल अधिकारों की विस्तृत सूची बनाई थी। इस सूची के १६ में से ११ अधिकार १९५० में तैयार संविधान के मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत संघी अध्याय में करीब करीब उन्ही रूप में ले लिए गए। १९३१ में कराची कांग्रेस में मोतीलाल के पुत्र जवाहरलाल ने प्रसिद्ध कराची प्रस्ताव पेश किया जिसमें कांग्रेस के उद्देश्यों को विस्तार से निरूपित किया गया था। कांग्रेस के इतिहास-लेखक डा० सीतारामया के शब्दों में जवाहरलाल का कहना था कि इन बातों पर राष्ट्र का दिमाग ज़िलकुल साफ होना चाहिए और जनता में इन्हीं का प्रचार होना चाहिए।^५

इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पहले से विचार स्पष्ट होने के कारण संविधान सभा में (१९४७-४८) इस पर बहुत ज्यादा बहस-मुवाहसे की जरूरत नहीं पड़ी।

फिर भी इस समय सोचने का मौका था कि देश में किस प्रकार का राज्यतन्त्र कायम हो। संविधान सभा में कुछ लोगों ने कहा कि देश की पुरानी संस्थाओं को नए युग के अनुरूप कुछ परिवर्तन के साथ स्थापित किया जाय। कुछ लोगों का खयाल था कि अनपढ़ जनता को वोट और चुनाव का अधिकार देना ठीक नहीं, और ये चीजें देश की पुरानी परंपरा के प्रतिकूल हैं। परन्तु आधुनिकतावादियों की संस्था अधिक थी और उनका कहना था कि भारत को इधर केवल संसदीय लोकतन्त्र का ही अनुभव हुआ है, और मध्यकालीन या प्राचीन राज्य का अनुभव अब काम नहीं दे सकता क्योंकि आधुनिक युग का तकाजा है कि जनसमूह को देश के शासन में हिस्सा दिया जाय और आर्थिक व सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा की जाये। गरीबी और निरक्षरता के आधार पर जनता का अधिकार से वंचित रखना अंगरेजों के तक को स्वीकार करना है जो स्वयं अपने देश में तो लोकतन्त्र की दुहाई देते थे परन्तु भारतीयों को स्वशासन के अयोग्य मानते थे।^६

^४ सम्मेलन में ३४ राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। देखें - ग्रैन विल आस्टिन 'द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कार्मर स्टोन नाफ ए नेशन' (लंदन १९६६)।

^५ पट्टाभि सीतारामैया, 'द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस' (बंबई १९४६) - १ खण्ड ४६३।

^६ देखें - ई. स्टोक्स, 'द इंगलिश सुटिज़ियेरियन्स पेंट इंडिया' (आक्सफोर्ड १९५६)।

बहुम के दारान इस बात पर जार दिया गया कि जावनवा सस्थाजा का विदेशी या बाहर की चीज नही समजना चाहिए, क्याकि प्राय एग गोदा स देश में प्रतिनिधि सस्थाए ताम बरती रही ह और जननि राष्ट्रीय नेता तहत् ये कि इा मस्थाजा के अधिकार बढ़ाए जाए तब अगरेज सरकार इमता विरोध करती थी। कांग्रेस लगातार वालिग मताधिकार और समदीय गाताजन की माग करती जाई थी। इससे देश की प्राचीन परंपरा का भी काई खतरा नहा था। जैसा कि एग मदस्य ने कहा — समदीय प्रणाली पर किसी एक् देश का एताधिकार नहा है और इसको ग्रहण करे स हमारी 'भारतीयता' में काई फरक नही पडता। भारत को आधुनिक युग की सभी नई विधिया का ग्रहण करव अपने विविष्ट राष्ट्रीय व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। इन विचारा को सदस्या का अत्यधिक समर्थन मिला और जब जवाहरलाल ने सभ विधान समिति की रिपोर्ट की धारा १० का पग किया जिसमें भारत म मजिमडल दासन जार समदीय सावतत्र की स्थापना की सिफारिस की गई थी, तो इसका काई विरोध नही हुआ और यह ऐतिहासिक निणय बिना शोरगुल के जासानी स ले लिया गया।*

किंतु राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान केवल सामान्य सिद्धान्ता पर सहमति हुई थी, जब इनका ठोस रूप देने का प्रश्न आया तो काफी मतभेद खडे हुए और सविधान निभाताजा का विरोधी विचारा में सामंजस्य करना पडा। जिन महत्त्वपूर्ण प्रश्ना पर मतभेद हुए उनमें राज्य और केन्द्र में अधिरारा का बढावा, सविधान की व्याख्या करने म 'यापालय की भूमिका, उचित विधिया जातु की परिभाषा, नागरिक की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और राष्ट्र की सुरक्षा में 'सामंजस्य, संपत्ति के अधिकार की सामाजिक 'याय और जायिक विकास स सगति, सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा अल्पसंख्यका, हरिजना और आदिम जातिया को विशेष संरक्षण के विषय थे।

राष्ट्रीय आंदोलन के समय कुछ विशेष परिस्थितिया थी जिनके कारण कुछ सिद्धान्त स्वीकृत किए गए, अब वे परिस्थितिया बदल गई थी। जैसे पहले देश के विभाजन की बात नही सोची गई थी, इसलिए मुसलमाना को भरोसा दिलाने के लिए व्यक्तिगत अधिकारा और प्रातीय स्वायत्तता पर बहुत जार दिया गया था। देश के विभाजन और भयावर खतना के अनुभव के बाद देश का और विभाजन रोकने के लिए केन्द्रीय सत्ता का राज्यो पर नियन्त्रण रखने का अधिकार देने की आवश्यकता प्रतीत हुई। इसी तरह राष्ट्रविरोधी गतिविधियो को रोकने के लिए सरकार का एहतिवादी नजरबंदी का अधिकार दिया गया यद्यपि यह लोकतंत्र के

७ सविधान सभा में इस विषय पर बहस के विवरण के लिए देखिए - डब्लू एच मारिस-जोन्स, 'पार्लामेंट इन इंडिया' (छदन १९५७)

नागरिक की अत्यंत बुनियादी स्वतंत्रता के प्रतिकूल था। “ इसी तरह न्यायालयों को बुनियादी अधिकारों की रक्षा के अधिकार देते समय यह भी जरूरी समझा गया कि राज्य को अधिक और सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए कारवाई करने का भी अधिकार रहे। इस उद्देश्य से उचित विधि (ड्यू प्रोसेस) सबकी प्रस्तावित धारा में संशोधन किया गया। ये सारी व्यवस्थाएँ बड़ी लंबी बहस मुवाहसे के बाद ही की गईं। ”

संविधान बनाने में सभी वर्गों की सहमति प्राप्त करने की कोशिश की गई। देश के विभाजन के बाद कांग्रेस का प्रचंड बहुमत हो गया था फिर भी उसने संविधान सभा में सभी मुख्य संप्रदायों और राजनीतिक मतों को प्रतिनिधित्व दिया। उसने सबूत हिंदुओं के अलावा हरिजनों, मुसलमानों, सिखा, ईसाइया, ऐंग्लो इंडियनों और पारसियों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में निर्वाचित कराया। सभा के ३१ हरिजन सदस्यों में से २६ कांग्रेस के नामजद थे। इसी तरह उसने ऐसे लोगों को भी लिया जिनका कांग्रेस से कभी संबंध न था। इनमें डा. सवपल्ली राधाकृष्णन और गोपाल स्वामी अयंगर जैसे लोग थे। यही नहीं उसने कांग्रेस के विरोधियों को भी स्थान दिया। इनमें जनसंघ के संस्थापक डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी और हरिजन नेता डा. अम्बेडकर जैसे लोग थे। डा. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के समापति चुने गए और संविधान के रचयिता के नाम से प्रसिद्ध हुए। वास्तव में ड्राफ्टिंग कमेटी के ६ सदस्यों में केवल एक कांग्रेसी श्री क. भा. मुशी थे। अल्पसंख्या सबकी कमेटी में न केवल अल्प संख्याओं को पूरा प्रतिनिधित्व दिया गया बल्कि इसमें तो वे लोग भी लिये गये जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, जैसे श्री पी. के. साल्वे (ईसाई), रूपनाथ ब्रह्म (आदिम जाति), एम. बी. एच. चालिस (ऐंग्लो इंडियन) और एम. रत्नस्वामी। मुस्लिम लीग के टिकट पर चुने गए तीन सदस्य भी इस कमेटी में लिए गए। यह संकुलवाद का दिखावा मान नहीं था। कांग्रेस की ईमानदारी इससे प्रकट है कि संविधान सभा का सून संचालन करने वाली अंतरंग मंडली में भी निंदनीय सदस्यों को स्थान दिया

८ देखें - डेविड एच. बेरी, ‘पब्लिक लिबरलिज्म इन न्यू स्टेट’ (शिकागो १९६४) पृ. २६-३५, तथा डॉ. का. प्रिंसेटिन टिडगन इन शडिया, ए वेम स्टडी ‘न उमोनेटिक सोशल कंट्रोल’ (मलक्का १९६२)

९ आस्टिन (पूर्ववर्त) न- रत्नका बहुत अच्छा वर्णन किया है। संविधान के इतिहास के लिए देखें - शिवराव का ‘द प्रेसिंग आफ् शिन्यान वांस्टिडूशन - ५ खण्डों में (नई दिल्ली १९६६-२८)

१० इस विषय में श्री बहादुरान अहमद के साथ हुए विचार-विनिमय से काफी लाभान्वित हुआ हूँ।

सविधान सभा में बहुमत के बल पर निणय लेने के बजाय सबकी सहमति प्राप्त करने की काँग्रेस की गई। नेहरू ने सदस्या से कहा था, 'जाप तत्समाजी न कर और जहा तक सम्भव हो एक राय से फमले कर।' इसी भावना से प्रेरित होकर सविधान सभा के अध्यक्ष डा राजेन्द्रप्रसाद बहुमत्त स्वयंसेवक समिति के लिए समय दिया करते थे ताकि 'बिस्मिल पर जमदस्ती न हो।' नेता लोग यह समझते थे कि बहुमत के बल पर बना सविधान टिकाऊ नही होता। इस प्रकार राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर मार्गगमन बहुत कम समय राजेन्द्र बाबू ने सदस्या से कहा कि—'इस विषय पर जा निणय हो, वह यदि पूरे देश को स्वीकार्य न होगा तो उस अमल में लागू बहुत कठिन होगा।' ११ सविधान सभा का सारा काम इसी भावना से ओतप्रोत था। नेताओं का यह मान था कि वे महज कोई दस्तावेज तैयार बना रहें हैं बल्कि एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने नाम का मजबूत बनाने में पूरा जोर लगाया।

हमने इस प्रसंग पर कुछ विस्तार में बर्णन किया क्या कि इससे पता चलता है कि नए राष्ट्र की संस्थापना का ढांचा तैयार करते समय किस प्रकार निणय लिए गए। यह सविधान भारत के भविष्य की आधार-शिलावत् था और इसका रचना में नेताओं ने पुराने और नए विचारों में अंतर से अधिक सामंजस्य लाने का प्रयत्न किया। परिणामस्वरूप संसदीय शासन का संघीय ढांचा स्वीकार किया गया, जिसमें केन्द्र जीतु राज्या में मन्त्रिमंडल सरकार बनाई गई और सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के लिए उत्तरदायी बनाने का काम करने का निर्देश दिया गया। १२ राज्य की संस्थापना का जो ढांचा तैयार हुआ, वह स्वरूप में आधुनिक है किन्तु राष्ट्रीय एकता और सामाजिक साम्य के ह्याल से उसमें कुछ विशेष व्यवस्थाएँ की गई जिससे वह पश्चिमी नमूने से भिन्न हो जाता है। भारत का राष्ट्रपति केवल नाम का पद है, किन्तु भी उसकी राज्यों में कानून और व्यवस्था

१० आर्स्टिन-पृ १८-१९ अंतरंग मंडली के ११ सदस्यों का नाम देता है। इनमें ७ कांग्रेसी थे—राजेन्द्रप्रसाद आजाद, पटेल, नेहरू, पंत, सावरभैया और सत्यनारायणसिंह। अवेडकर, व. कृ. अय्यर और गोपालबहादुर अय्यंगर गैर कांग्रेसी थे। अवेडकर तो कांग्रेस के बहुत विरोधी थे। क. मा. मुंशी भी बाद में कांग्रेस से अलग हो गए।

११ यह भ्रम पैदा किया गया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का निणय केवल एक वोट के बहुमत से किया गया था। यह झूठबुल गप है। केवल कांग्रेस असेंबली पार्टी में अंग्रेजी अकों को रखने का निर्णय एक वोट के बहुमत से हुआ था। देखें—आर्स्टिन-पृ २९९-३००। भाषा के प्रश्न पर निर्णय लया रहस्य और छेन-देन का बाद किया गया।

१२ इनका वर्णन 'निर्देशक सिद्धांत' के अध्याय में किया गया है। इसमें बड़े ऊंचे आदर्शवाद का संलक्ष है।

भग होने की स्थिति में बहुत अधिक आपत्कालीन अधिकार दिए गए।^{१३} राज्या के गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्य की जनता या विधान मंडल नहीं। केन्द्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति आपत्कालीन अधिकारों का प्रयोग और नियुक्ति करता है। केन्द्रीय सरकार को देश के राजस्व का अधिकांश भाग और राज्यों पर प्रशासनिक और निर्देशक अधिकार दिये गये। समवर्ती विषयों पर जोर अथवा कई मामलों में केन्द्रीय संसद के अधिकार राज्यों से ऊपर हैं और राज्यों में सार्वजनिक मशीनरी के टूट जाने पर, संसद उनके विधानमंडल और शासन के अधिकार ले सकती है। केन्द्र को अवशिष्ट अधिकार भी दिये गये। इस प्रकार केन्द्र को बहुत शक्तिशाली बनाया गया। दूसरी ओर गांव पंचायतों और स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की स्थापना के द्वारा और राज्यों को शासन के बड़े काम सौंप कर, शासन व्यवस्था को मध्यम रूप दिया गया और शासन में जनता को तथा प्रांत, जिला और गांवों का भी हिस्सा दिया गया।

संविधान की एक विशेषता अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों की संरक्षण देना है। इनके लिए सरकारी नौकरियाँ और विधान मंडल में स्थान सुरक्षित किए गए हैं। इसी तरह देश की सभी मुख्य भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं का पद दिया गया है। यद्यपि हिंदी का राजभाषा का पद दिया गया किन्तु अहिंदी भाषी राज्यों के विरोध के कारण इसको लागू नहीं किया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया सरल रखी गई ताकि सामाजिक स्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सके। वित्त आयोग और चुनाव आयोग जैसे स्वायत्त प्राधिकरणों को कार्यविधि में महत्वपूर्ण परिवर्तन के अधिकार प्राप्त हैं। यदि यामालय समय के विपरीत चले तो संसद को उनको नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है। विशेष अधिकार-प्राप्त सम्मेलन और आयोगों के जरिये केन्द्र और राज्यों के मतभेद दूर करने की व्यवस्था की गई है।^{१४} इसके बावजूद भी सार्वजनिक कठिनाइयाँ उठ सकती हैं। इन पर हम राजनैतिक व्यवस्था के काया काल सवर्धन अध्याय में विचार करेंगे।

स्थिरता और परिवर्तन की समस्याएँ

संविधान की रचना और १९५० में भारत गणराज्य की स्थापना देश में राज-

^{१३} इस विषय पर संविधान निर्माताओं के विचारों की डा. डा. कृष्णमाचारी ने इस प्रकार प्रकट किया "राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के सत्रों के बारे में हमने *मॉडेल* की शासन-प्रणाली का अनुकरण किया। हा, हमने अपने सलाह दानों के कारण कुछ विशेष व्यवस्था की है।" संविधान सभा के डिवेंट-१०, पृ. ९५६। परन्तु इस मत का भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसाद तथा कुछ और लोगों ने खंडन किया है।

^{१४} आस्टिन - आखिरी अध्याय - 'कॉमन्स ऑन ए सक्सेसफुल कान्स्टिट्यूशन', पृ. ३०८-३१०।

नीतिक समस्याओं के निर्माण और जनता की सहमति प्राप्त करने की लगातार चाल क्रिया के ही अंग थे। राष्ट्रीय एकमत के और विकास के क्रम में संविधान, नई संस्थाओं के विकास और 'राजनीतिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण' के प्रश्न उठे हैं।^{१५} नई संस्थाओं की स्थापना से नए जाचारविचार, तीर तरीके व परंपराएँ तथा सत्ता की नई श्रृंखलाएँ विकसित होती हैं और राजनीति के सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन होता है। भारत में सत्ता की यह श्रृंखला और जनता व शासन में संपर्क दो माध्यमों में स्थापित हुआ। एक है प्रशासन या सरकारी अमला, जिसका विकास मुगला और अंग्रेजों के राज के समय हुआ और राष्ट्रीय योजना के तकाजे से जिसका और विकास हुआ। दूसरा है कांग्रेस दल का ढाँचा, जिसका विकास राष्ट्रीय आंदोलन के समय हुआ। स्वतंत्रता के बाद सरकारी सत्ता व अधिकार तथा चुनावों के कारण इसका बहुत विस्तार हुआ है। इन दोनों के द्वारा और इनके परस्पर प्रभाव के कारण भारतीय राज्यतंत्र का वर्तमान रूप स्थिर हुआ। इस बीच संविधान द्वारा स्थापित ढाँचे में भी परिवर्तन हुए हैं, कुछ तो वर्तमान ढाँचे की छामियों सुधारी गईं और कुछ सामाजिक पुनर्निर्माण और प्रतिनिधि शासन के नए विचारों के प्रभाव से नये उपाय किये गये।

स्वतंत्रता के साथ नई समस्याएँ आईं। सांप्रदायिक दंगों और उपद्रवों के शमन के साथ साथ पाकिस्तान से उदवासित लाखों आदिमियों का बसाने का कठिन कार्य तथा तेलंगाना में कम्युनिस्ट प्रेरित किसानों का बलवा, निजाम हैदराबाद के खिलाफ पुलिस कारवाई। सरकार को अंग्रेजी जमाने के सरकारी नौकरों और सेनाओं का विश्वास और वफादारी प्राप्त करनी थी। इसके अलावा सांप्रदायिक शक्तियों को भी दबाना था, जो देश के विभाजन के बाद उमड़ आई थी। असंतुष्ट प्रादेशिक और राजनीतिक समूहों को संतुष्ट करना था। सबसे बड़ा काम था देशी रियासतों को मिलाने का।^{१६} इसमें राजनीतिक कुशलता और सगठनपटुता की जरूरत थी। संक्षेप में नेताओं के सामने यह काम था कि देश को विघटित होने से बचाएँ और उसके विभिन्न भागों और तत्त्वों को मिला कर एक राष्ट्र की रचना करें।

नेताओं की समझदारी और दूरदर्शिता की तारीफ है कि उन्होंने इन कठिन समस्याओं को काफी जल्दी सुलझा लिया। भारत के प्रथम गृहमंत्री बल्लभभाई पटेल

१५ यह जयप्रकाश नारायण के एक लेख में शीर्षक है। हम इस पर दोनों में सहयोग विषयक अ. याच. में विचार करेंगे।

१६ भारत का जो भाग अंग्रेजों के साथे शासन में था उसे ब्रिटिश भारत कहा जाता था। इसके अलावा देशी राजाओं के शासन में करीब ५०० छोटी बनी रियासतें थी। ये स्वतंत्र राज्य नहीं, ब्रिटिश आधिपत्य के अंतर्गत थे। किंतु अंग्रेजों के हटने से भारत और पाकिस्तान का अपने आप इनके ऊपर आधिपत्य नहीं मिला। इसलिए देशी रियासतों को दोष देश में मिलाने की देशी समस्या पैदा हुई।

ने देशी रियासतों को भारत में मिलाने का काम बड़ी सूबसूरती से पूरा किया। इससे भी बड़ी सफलता उन्होंने देश में शांति और व्यवस्था स्थापित करने और प्रशासकीय और सैनिक सेवाओं की निष्ठा प्राप्त करने में पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारतीय अधिकारियों को देशद्रोही और जगरेजा का गुलाम कहा जाता था, इस कारण स्वतंत्रता आने पर वे लोग घबराए हुए थे। पटेल ने सरकारी नौकरी को आश्वासन दिया कि उनकी स्थिति वही रहेगी जो पिछले शासन में थी और उन्होंने राजनीतिक लोगों से कहा कि वे सरकारी कर्मचारियों के काम में दखल न दें। उन्होंने देश में स्थिरता कायम करने में भारतीय सिविल सर्विस की योग्यता का बहुत अच्छा उपयोग किया। सेना के प्रति भी उनका यही रुख था।

नेताओं ने बड़े प्रश्नों पर दृढ़ता दिवाने के साथ साथ विरोधी और भिन्न मतों के साथ समाधान करने की भी कोशिश की। इस नीति से उन्हें उपर्युक्त समस्याओं को सुलझाने में बड़ी मदद मिली। स्वतंत्रता के बाद के दशक में उनकी यही सामान्य नीति रही। अपना कार्यक्रम निवारित करने में वे जहाँ तक हाँ सके सघन वचात थे। नेहरू ने सन १९५२ में इस बात को या कहा था, “इस नाजुक समय में मैं देश की एकता को सर्वोपरि समझता हूँ। जब तक इस एकता की नींव पक्की न हो जाए, हमें ऐसी कारबाई से बचना चाहिए जो इसमें बाधक हो”।^{१७}

देश की एकता और मजबूती के साथ साथ नेतावा सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए भी उत्सुक था। तात्कालिक समस्याओं के समाधान और नये संविधान के लागू होने के बाद भारत सरकार ने योजना कमीशन की स्थापना की। इसका पंचवर्षीय योजनाएँ बनाने, सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम की प्राथमिकता निर्धारित करने और आर्थिक विकास की रूपरेखा तैयार करने तथा उसको कार्यान्वित करने के लिए साधन जुटाने के उपाय सुझाने का काम सौंपा गया। बहुत थोड़े समय में ही विकास के आयोजन मूल्यांकन और सलाह माँगिरे के लिए केन्द्रीय मशीनरी का विकास कर लिया गया।^{१८} स्मरण रहूँ कि संविधान में योजना आयोग का जिक्र भी नहीं था। इसकी स्थापना नेहरू के इस दृढ़ विचार के कारण हुई कि राजनीतिक को मजबूत बनाने के लिए शुरू में ही देश में आर्थिक

१७ ‘स्पेसिज आफ जवाहरलाल नेहरू १९४९-५३’ (भारत सरकार, दिल्ली १९५४) सघन वचनों के विषय पर ‘सेमिनार’ (नई दिल्ली) ६३, नवंबर १९६६ में देखिए। गिरीन्द्र सिंह का लेख ‘ए न्यू लेनिनिस्म’।

१८ सरकार का योजना और तथ्य-संकलन की मशीनरी के बारे में देखिए - विलफ्रेड मैटल-वाम, ‘हू डूज द प्लानिंग?’ और मेरिल बार गुडल का लेख - आर्गनाइजेशन आफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंडरशिप इन द फाइव थर्ड प्लान, रिचर्ड एल पार्क और इरेन टिकर द्वारा संपादित ‘एडरशिप एंड पोलिटिकल इस्टाब्लिशमेंट्स इन इंडिया’ में (प्रिंटन १९५९), पृ. २०१-२८। राजनैतिक प्रक्रिया के रूप में योजना के विशद अध्ययन के लिये देखें - एच. ई. सन ‘द प्रोसेस आफ प्लानिंग’ (लंदन, १९६६)।

विकास की नीति से कर लेनी चाहिए। इसी के साथ केन्द्रीय सरकार ने ससद स अस्पश्यता निवारण जस अनेक समाज हित और सुधार के कानून नी पास कराए। राज्यों में भी जमींदारी उन्मूलन के कानून बनाए गए और गरीब व दलित वर्गों को सरक्षण व सुविधाएँ दी गई। इन कानूनों को अदालत में चुनौती न दी जा सक इस हेतु सविधान में संपोधन किए गए। इससे प्रकट होता है कि नेताओं को यह ध्यान था कि राष्ट्रीय एकता केवन झगड़े की बातों को टालते रहने से नहा बनी रह सकती उसके लिए सघष के कारण को दूर करने के लिए रचनात्मक कारवाई करनी भी जरूरी है जिससे एकता की शक्तियाँ न बल बढे।

स्वतन्त्रता के तुरत बाद की इस अवधि में कुछ काय ऐसे हुए, जिनसे एकता को बल मिला। यद्यपि ये काय आर्थिक और सामाजिक विकास के उद्देश्य से किए गए, फिर भी इनसे सघष के कुछ ऐसे कारण दूर हुए, जो उपग्र होकर देश की एकता को नुकसान पहुंचा सकते थे। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए जो कानून बनाए गए तथा कांग्रेसजनों ने मजदूर सघा के काय में जो रुचि ली, उससे जातीय सघषों को रोकने में मदद मिली। इसी तरह अनुपूचित जातियाँ और पिछड़े वर्गों की शिक्षा और सरकारों की करियों में जो विशेष सरक्षण दिए गए और उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने की जो कारवाइयाँ की गई, उससे ऊँची जातियाँ से उनका सघष टला। जमींदारी और मामती अधिकारों के उन्मूलन से भी सघष का एक बड़ा कारण दूर हुआ।

स्वतन्त्रता के प्रथम दशक में देश के सुत्रधारों ने एक और महत्वपूर्ण काय किया। यह था भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। अंग्रेजों ने सामाजिक और सांस्कृतिक आधारों की उपेक्षा करके केवल शासन की सुविधा के दयाल से प्रांतों का निमाण किया था।^{१९} राष्ट्रवादियों को यह बात पसंद न थी और राष्ट्रीय अदालत के समय कई बार कांग्रेस ने भाषावार प्रांतों की स्थापना का निश्चय प्रकट किया था। १९२१ में कांग्रेस ने अपनी प्रदेश सभाएँ इसी आधार पर स्थापित की थीं। लेकिन स्वतन्त्रता के बाद जो कठिन समस्याएँ आईं उनके कारण कांग्रेस राज्यों का इस प्रकार पुनर्गठन पर ध्यान न दे सकी और कुछ यह भी ऊहापोह होने लगा कि भाषावार राज्यों को बनाना उचित है या नहीं। यद्यपि नवंबर १९४७ में नेहरू ने सविधान सभा में भाषावार राज्यों के सिद्धांत को स्वीकार किया था, लेकिन सविधान सभा द्वारा नियुक्त भाषावार प्रांत समीक्षा (घर समीक्षा) ने भाषा के

१९ इस सलाह में अंग्रेजों ने प्रांतों का रचना भाषा और सांस्कृतिक के आधार पर करके सिद्धांत के महत्त्व को स्वीकार किया और बिहार, उड़ीसा, आसाम और सिंध (अब पाकिस्तान में) के नए प्रांत इसी प्रकार बने। १९१८ का मॉन्टेगु-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट और १९३० की साइमन कमिशन की रिपोर्ट में भाषा आधार प्रांतों की स्थापना की सिफारिश की गई थी।

प्रांत स तलुगु भाषी जिला को जलम करके आध्र प्रदेश की स्थापना के जादोलन
 ने उग्र रूप पकड़ा। अतः १९४६ म कांग्रेस कायसमिति ने इस माग को स्वीकार
 कर लिया। लेकिन केन्द्रीय सरकार जब भी हिचक रही थी क्योंकि उस डर था
 कि इससे इसी प्रकार के और राज्या की स्थापना की माग उठेगी। सरकार का
 याल था कि एस राज्या व निर्माण से भाषावाद जार पकड़ेगा और राष्ट्र की
 कता बमजार होगी। इस प्रश्न पर कांग्रेस म मतभेद हो गया। कांग्रेस ने जादेश
 या कि कांग्रेसजन भाषावार राज्या के आदालतन स जलम रहें किंतु इस जादेश
 पालन नहीं किया गया और सभी दल इस आदालतन म शामिल हुए। आध्र
 की माग क समयन म पोस्ती श्रीरामलु न अनशन करके प्राण दे दिये। इससे
 ार को यह माग स्वीकार करनी पड़ी और अक्टूबर १९५३ म तलुगु भाषी
 प्राण का निर्माण हुआ। इससे भाषावार राज्या की माग ने जोर पकड़ा।
 ा। पर विचार करन व लिए सरकार ने निसर १८/३ म राज् पुनगठन
 की नियुक्ति की। इसने खूब जाच पडताल क बाद सन १८५५ म अपनी
 शी। इसने भाषा के आधार पर राज्या के पुनगठन का सिद्धांत स्वीकार
 'र राज्या के तदनुसार पुनगठन की सिफारिश की। कुछ हेरफेर के साथ
 'रा स्वीकार की गई और १९५६ म इसके अनुसार राज्या का पुनगठन
 'कुछ बहुभाषी राज्य अब भी छूट गए। सन १९६० म द्विभाषी बवई
 'गडकर महाराष्ट्र और गुजरात राज्या की स्थापना की गई और १८६६
 'र हरियाना को जलम किया गया।
 'र भारत स सहानुभूति रखने वाले राजनीतिक पयवेक्षका की आश-
 'वावजूद पुनगठन स भारत का राजनीतिक नफरा अधिक सुसगत
 'राष्ट्र की एकता को भी खास नुकसान नहीं पहुंचा। ११ वलिक इसस
 'गेन्स अते यदार्थवाश आलाचक्र को ना इस निषय में आरना थी। आन
 'क्षेत्रों के शग दास पद। देख वनर्वा पार्लमेंट इन शदिया (१९५७)।
 'प्रत्नों में ऐ नहा काप्रत का प्रभाव है जो इन यगटा पर अरुड रखता है।
 'कारण आध्र म किसान बग के नताओं को उमरन का नीका मिला है। इसस
 'में में पवराइट है जो अना को देश की पनता का सन ममता है। इस
 'के लिए शेरिए-सलिंग हरिसन 'शदिया द मोरु डेनरम निम्स
 'ान में राज्यों की तान थगिया थीं - ए म भूतपूर्व अय-ए शमन ए
 'देशा रियासतें तथा सी म केन्द्र शासित प्रदेश। राज्यों के पुनगठन के
 'ए रा-व और सपशासित क्षेत्र।

साम यह हुआ, कि पण्डे का एक कारण दूर हुआ और राज्या का वास्तव ऐसी भाषा में होना समझ हुआ, जिस जागाधारण समझ था। अतिशय त अन्तर्भव से तो यह कहा जा सकता है कि भाषा जाडनेवाली गति निम्न है।^{११} यदि इसन कोई जागना की बात है तो यही कि उपनामाजा और स्थानीय प्रवृत्तियाँ का आधार पर राज्या के टुकडे न हो जाए।^{१३}

इस प्रकार पहले दशक में भारतीय राष्ट्र का समग्रानिर्वाह प्राद्वित और विकास का ढांचा तैयार किया गया। जहाँ सन्निधान की व्यवस्था में संशोधन का ज्वरत पड़ी रहा संशोधन किए गए जैसे राज्या का पुनर्गठन याचना आयोग की स्थापना और भूमिनुसार के लिए संपत्ति संपत्ति अनुच्छेद का संशोधन। ब्रिटिश युग तकली आई और विपन्नता का अंत किया गया। योजनापूरक विकास का प्रथम चरण किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना १९५६ में पूरी हुई और दूसरा उनस वनी योजना शुरू की गई। १९५५ में जावडी अधिवेशन में कांग्रेस दल ने समानवादी ढांचे का ध्येय स्वीकार किया। उद्योग के दार में पहले १९६० में नीति का घोषणा की गई। १९५६ के उद्योग नीति प्रस्ताव में इस आरंभ काय तथा व्यापक रूप दिया गया। इससे साथ ही गावा के विकास और ग्रामीणा को राजनीतिक काय की शिक्षा देने के लिए १९५२ में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किये गये और दस नर में विकास सभा का जाल बिछाया गया। बाद में पंचायती राज का लोकतंत्री विकेंद्रीकरण का सूत्रपात हुआ। इस विषय के लिए नियुक्त अध्ययन बोली की रिपोर्ट सन १९५७ में प्रस्तुत हो चुकी थी।^{१४} इस बीच (१९५७-५७) दो आम चुनाव और बीसिया स्थानीय चुनाव हो चुके थे और कांग्रेस पार्टी की प्रधानता स्थापित हो चुकी थी।

१२ भाषा का प्रश्न क कुछ और पहलू हैं जो राष्ट्र की एकता के लिए खतरनाक हैं। इनने सभ से महत्व का प्रश्न है राजभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं का द्वंद्व और अग्रता का स्थान। इस विषय का विवेचन आठवें अध्याय में है।

१३ राज्य पुनर्गठन आयोग ने जनभावना का खाल रखते हुए एक भाषा के एक राज्य का सिफारिश की (। नदी भाषा राज्यों को छोड़कर)। वास्तव में इसका कोई कारण नहीं कि हिंदी राज्यों की तरह अन्य भाषा-क्षेत्रों में भी एक से अधिक राज्य क्यों न हों। बाद में अनुभव से पता चला है कि भाषा के अलावा अन्य बातें भी हैं जो राजनीतिक एकता, प्रशासनिक कुशलता और आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं। इस विषय पर देखें- श्रीनिवास, 'द फ्यूचर आफ पिशन', टाइम्स आफ इंडिया नवंबर २६ १९६७ और रजनी कोठारी, 'नेशनल यूनिटी इन डार वेस फार स्मालर यूनिट्स', टाइम्स आफ इंडिया, फर १०, १९६८। हम इस प्रश्न पर अध्याय ८ में विचार करेंगे।

१४ योजना कमिशन - 'कमेटी ऑन ग्रान प्रोजेक्ट्स, रिपोर्ट आफ द ग्रीम फार द स्टडी आफ कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स ऐंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस' (नई दिल्ली १९५७) इस बलवत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट भी कहा गया। इस रिपोर्ट का ग्राम - विकास और ग्राम - लोकतंत्री सभी विचारों पर काफी प्रभाव पड़ा है।

इस प्रकार इस अवधि में राजनीतिक एकता और संस्थाओं की स्थापना की दिशा में काफी काम हुआ, जिस कारण देश जागे जाने वाले दशक में और कठिन समस्याओं का सामना कर सका। तनाव और कठिनाइयों के बावजूद देश में एक हृदय की स्थिरता बनी रही। विकास जारी रहा और संविधान द्वारा जा संस्थाएँ कायम हुईं उन्हें जड़ जमाने का मौका मिला। जागे जो विकास हुए, वे इसी ढाँचे में हुए। उनसे ये संस्थाएँ गतिशील हुईं और जनता के सपने में जाई। हम इस विकास की मुख्य धारा की चर्चा करेंगे।

केन्द्र और परिधि

संविधान द्वारा स्थापित संघीय शासन-प्रणाली के अंतर्गत केन्द्र राज्य और जिलों के संबंध में स्थापित है। केन्द्र और राज्यों में शासन का ढाँचा करीब करीब एक ही तरह का है। एक यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्यों के विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा होता है जबकि राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संवैधानिक शासन के पिछले अनुभव, ब्रिटिश राजनीतिक परंपरा, जनमत और केन्द्र तथा राज्यों के प्रभावशील नेताओं की राजनीतिक समझ ने केन्द्र और राज्यों के संबंध का प्रभावित किया है। इन संबंधों पर मिस्र राजनीतिक प्रवृत्तियों नेताओं और विभिन्न हितांशों का संगठन का भी प्रभाव पड़ा है। सबसे बड़का इन पर इस बात का प्रभाव पड़ा है कि स्वतंत्रता के बाद के दशकों में केन्द्र में तथा लगभग सभी राज्यों में लगातार एक ही दल का शासन रहा है।

राज्यों के हाथ में देश के शासन का बहुत बड़ा भाग है। यद्यपि उन्हें आर्थिक साधनों के लिए केन्द्र पर निर्भर रहना पड़ता है और विकास कार्यों का संचालन भी केन्द्र करता है, फिर भी राज्यों में अपने अधिकारों पर जोर देने की प्रवृत्ति है और देश के शासन में अधिक हाथ चाहते हैं। सबसे मुख्य बात है राज्यों के मुख्य मंत्रियों की महत्वपूर्ण स्थिति। मुख्य मंत्री न केवल राज्य का सबसे अधिकारशील व्यक्ति होता है, बल्कि राष्ट्रीय क्षेत्र में भी उसका महत्व बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव जैसे महत्वपूर्ण मामलों में उनकी राय ली जाती है।^{१५} इस प्रकार उन्होंने राष्ट्रीय नेताओं की स्थिति प्राप्त कर ली है। मुख्य मंत्रियों का यह महत्व उनकी क्षमता और उनके महत्वपूर्ण पदों के कारण प्राप्त हुआ है।

शासन दल के भीतर भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति काम कर रही है। राज्य कांग्रेस कमेटी और राज्य चुनाव कमेटी का महत्व बढ़ रहा है। राज्य कांग्रेस का

१५ १९९९ में मेहरून कायम अन्धका पद हटा दिया। तब से एक बार भी छोड़कर अब शक्ति प्राप्त कर रही, कायम के अन्धका राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने भी चुन जाने रहे हैं। प्रधान मंत्री के चुनाव में मुख्य मंत्रियों के हाथों के बरने में अन्धका भाग दंडित है।

जन्म या अन्य नाम का हुआ तो कांग्रेस का जसली सरदार^{२६} बड़ा शक्तिशाली होता है और जयभी वान के द्रीय नेताओं से भी मनवा लेता है । कांग्रेस के अलावा जय दला में भी इसी प्रकार राज्य के सघटना की सक्ति बढ़ी है ।

भारत में सरकारी नीतियाँ और विकास कार्यक्रम को जमल में लाने का काम राज्य सरकार और नीचे के अधिकारियों का है । संविधान में केवल और राज्यों के कार्यों का जो बंटवारा किया गया है वह बंधाव स्थिति का बोधक नहीं है । संविधान की आठवीं अनुसूची में कार्यों की तीन सूचियाँ दी गई हैं - (१) संघ सूची (२) राज्य सूची और (३) समवर्ती सूची । इन तीनों सूचियों में बहुत पासमल है साम कर कई काम समवर्ती और राज्य सूची दोनों में मिलने हैं । संविधान में यह भी व्यवस्था है कि कुछ स्थितियों में संसद समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है और राज्यसभा दो तिहाई बहुमत से संसद को राज्य सूची के भी किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है । केन्द्रीय सरकार को अनेक विषयों पर राज्य सरकार को निर्देश देने का भी अधिकार है । इनमें से कुछ विषय राज्य सूची के भी हैं । इसके अलावा राष्ट्रपति को कुछ हालातों में राज्यों के शासन में हस्तक्षेप का अधिकार है । वह राज्य का विधान सभा को भंग कर सकता है, राज्य के शासन को अपने हाथ में ले सकता है और राज्य के विधान-मंडल में विचारधीन विधेयकों पर राज्यपाल स रिपोर्ट माग सकता है । इन प्रकार केंद्र को राज्यों के क्षेत्र में हस्तक्षेप का अधिकार है । इस कारण कुछ प्रमुख जालों चक्रों ने यहाँ तक फैल डाला कि भारत नाम के लिए संघ है ।^{२७}

परन्तु स्वतंत्रता के बाद से जब तक भारत में प्रशासन और सरकार की गति विधि का समीक्षा से इस विचार का सङ्ग होता है । अक्सर राज्य सरकारें केंद्र पर दबाव डालने में और उससे अपना बात मनवाने में सफल रही हैं । केंद्र के लिए सुरक्षित क्षेत्रों में भी राज्यों ने घुसपट्टी की है और दूसरों देशों से व्यापारमय भी स्थापित किए हैं ।^{२८} कई राज्यों के मुख्य मंत्री बड़े शक्तिशाली हैं और प्रधान मंत्री

२६ बंगाल कायम पर एक दशक से भी अधिक समय तक (१९६२ तक) अनुत्पन्न था का राज्य रहा । अनुत्पन्न घोषणा राज्य सरकार या राज्य कांग्रेस में कोई पद नहीं था किन्तु बंधाव नेताओं पर उनका बड़ा प्रभाव था ।

२७ संविधान विशेषज्ञ के सी. हीयर ने भारत की अर्थ सत्र कहा है - 'फेडरल गवर्नमेंट (वर्दन १९५३) । वेद द्वारा राज्यों के अधिकारों के अवसरण के बारे में दोषों - 'द डिवन जर्नल ऑफ पोलिटिक्स साइंस अक्टूबर-नवंबर १९३३ में के सी राव का 'सेक्टर-स्टेट रिलेशनस इन थियरी ऐंड प्रैक्टिस' ।

२८ पश्चिम बंगाल के शक्तिशाली मुख्य मंत्री बा. विधानधर राय ने एक विज्ञापन के साथ अपने राज्य का भारत से व्यापार समझौता किया था । पश्चिम पर, विशाल कर नेहरू पर उनके प्रभाव के कारण इस मामले की नजरअंदाज किया गया । छविन श्वर जयकेरल के एक मंत्री और मद्रास के मुख्य मंत्री ने तारात तथा कुछ पश्चिमी देशों के साथ व्यापार के बारे में बात-बात की, तब स्वयं वित्तमन मुरारत नेसाई ने कहा कि राज्य सरकारें यदि अपना व्यापार बढ़ाने का प्रयत्न करना है तो इसमें कोई उराह नहीं ।

को इनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जैसा कि पाल ऐपिनजी ने कहा है कि, भारत की शासन प्रणाली ऐसी है जिसमें प्रशासन के सार महत्वपूर्ण कार्य राज्य सरकारें करती हैं, और योजना की कार्यविधि के लिए केंद्र को उही पर निर्भर रहना पड़ता है। केंद्रीय सरकार में सब जफ़सर है, कोई मिपाही नहीं इसका मतलब यह है कि क्षेत्र में काम करने वाले सब अधिकारी राज्य सरकारों के अधीन हैं। राज्य सरकारें समझती हैं कि केंद्र खर्चमार कर उन्हें आर्थिक सहायता देगा और उनके घाटे को पूरा करेगा। अनुदान देने की प्रणाली में केंद्र को राज्यों के काम की जाच और देखरेख का जो अधिकार रहता है इससे वह व्यथ-सा हो गया है। एपिलबी यहाँ तक कह गए कि भारत में राज्य सरकारों के सामने केंद्रीय सरकार की कुछ नहीं चलती। २०

ये दोनों ही विचार एकांगी हैं। सघ प्रणाली की समस्याओं को हमेशा सघ और राज्य के द्वंद्व के चरमों से न देखना चाहिए। भारत में तघीय प्रणाली का विकास यहाँ की राजनीतिक स्थिति के अनुसार हुआ है। ३०

भारत में राजनीतिक शक्ति के वटवारे को प्रभावित करने वाला एक नया तत्व है, निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं और स्थानीय नेताओं का बढ़ता हुआ महत्त्व। इसके कारण राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति का विभेदीकरण हुआ है। जिला और राज्यों के नेताओं की शक्ति गढ़ी है और राष्ट्रीय नेता उनसे सलाह करने लगे हैं। योजना आयोग की राष्ट्रीय विकास समिति में सभी राज्यों के मुख्य मंत्री सदस्य हैं और योजना बनाते समय और उसे कार्यविधि करते समय राज्यों के नेताओं से पूरा पूरा सलाह मशविरा किया जाता है और उनकी बात काफी मानी जाती है।

कांग्रेस के चुनाव-यंत्र पर राज्य और जिलों के नेताओं का बहुत हद तक नियंत्रण रहता है। इसका एक कारण तो यह है कि इतने बड़े देश में केंद्रीय नेता अविकाश जनता के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आते। दूसरा, चुनाव की जीत हार बहुत हद तक गावों के प्रमुख लोगों पर निर्भर होती है। इस कारण राज्यों की कांग्रेस कमेटियों का महत्त्व बढ़ गया है, जसे योजना और विकास कार्यों के कारण राज्य सरकारों का महत्त्व बढ़ा। नये नेता भी स्वभावतः राज्यों से ही आते हैं। राजनीति

२९ पाल एच. पेपिलवा, 'पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया-रिपोर्ट्स आफ ए सवे' (दिल्ली १९५३)

३० वाद-राज्य संबंध के बारे में इन विरोधी मतों का समीक्षा के लिए मेरे काम रेंड सरस्टेंस इन इंडियन पालिटिक्स शर्पक पढ़के लेख को देखें-इन्फ़ामिक चार्ल्स १३, स १७ और १८, अप्रैल २९ और मई ६, १९६१। वाट्स के मत से मा प्रणाली रखना और विभिन्नता का प्रवृत्तियों में समुलन लाती है। 'न्यू पटर्न-एडमिनिस्ट्रेशन इन द कामनवेल्थ' (आक्सफ़ोर्ड १९५२)। वाट्स ने भारत की सघीय प्रणाली पर विस्तृत विचार किया है।

का जनता में फैलाव और नए राजनीतिक दला का उदय राज्या में हुआ है और राज्या से ही राष्ट्रीय क्षेत्र में नये नये नेता आए हैं।

इसके साथ ही एक प्रवृत्ति भी चालू है। राष्ट्रीय नेता वग, राज्या में होने वाले राजनीतिक झगडा में प्रगुपर बीच-बचाव और निपटारा करते रह रहे हैं। कांग्रेस कायवारिणी (हाईकमान) और केंद्रीय सरकार के प्रमुख सदस्य राज्य कांग्रेस क वगडा में समग्रीता बरात हैं और यह त करत हैं कि नेतृत्व का सहारा जिसके सिर पर बंधे। कांग्रेस हाईकमान की दक्षिण का यही सात है। कांग्रेस की दलबदिया पर गौर करने से पता चलेगा कि राज्या के वगडा को निपटाने या भडकाने में केंद्रीय नेताओं का बडा हाथ होता है। राज्या के नेता जक्सर यह शिकायत करत हैं कि यदि ऊपर से इशारा न मिले तो ये वगडे इतने न बढें। वास्तव में इन हथकडा से केंद्रीय नेता प्रातीय राजनीति पर अपना नियन्त्रण और प्रभाव कायम रखते हैं और इसी पर कद्राय और प्रातीय नेताओं की दक्षिण निर्भर रहती है। साधारणतः केंद्रीय नेतृत्व का रुख यही रहता है कि विरोधी गुटा का बराबर रख। उह जापस में निपटने दे, जब कोई गुट बहुत प्रबल होने लगे तब बीच बिचाव करे, हवा का रुख देखते रह और हर हालत में आखिरी फसला हाईकमान के हाथ में रहे। राज्या में नए राजनीतिक दला के प्रादुर्भाव के कारण, अस्थिरता पैदा हो गई है और केंद्रीय नेताओं को हस्त रेप और मध्यस्थता के, जिसमें राष्ट्रपति और ससद द्वारा सबधानिक कारवाई भी शामिल है, और मौके मिल गए हैं।

कहा जाता था कि केंद्र और राज्या में एक ही पार्टी के सत्तारूढ होने के कारण केंद्रीय सरकार की सत्ता बहुत बढ गई थी और जहा यह स्थिति बदली केंद्रीय सरकार की सत्ता कम हो जाएगी। किंतु केंद्र राज्य सबधा पर पार्टी के प्रभाव के जरा गहरे अध्ययन से पता चलेगा कि बात उलटी है। जब तक राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी मुख्य मंत्रियों का केंद्र पर बहुत अधिक प्रभाव था और आज भी जहा कांग्रेस मुख्य मंत्री हैं, उनका केंद्र पर प्रभाव है। दूसरी ओर जहा दूसरे दल की सरकार होती है, उसके मुख्य मंत्री का केंद्र पर वह प्रभाव नहीं होता और चाहे वित्तीय सहायता हो, या विकास परियोजनाओं को लगाने का प्रश्न हो, या खाद्य की सप्लाई हो, राज्य को केंद्र का मुह जोटना पडता है। केंद्रीय सरकार पर गैर-कांग्रेसी मुख्य मंत्रियों का उससे बहुत कम प्रभाव पडता है, जितना कांग्रेसी मुख्य मंत्रियों का, जो कांग्रेस मण्डल में भी प्रभाव रखते हैं।

राज्यों की राजनीति

पार्टी प्रथा के विकास के सिलसिले में हम राज्या की राजनीति और केंद्र-राज्य सन्धा पर जगले अध्याय में विस्तार से विचार करेंगे। यहां हम प्रादेशिक

राजनीति के मुख्य तत्त्वा पर एक नजर डालेंगे तब तो राष्ट्रीय राजनीति का भी सन्ध था।^{३१}

राज्या की प्रवृत्तियाँ को चार मुख्य बातों ने प्रभावित किया है - स्वतन्त्रता के पहले का राजनीतिक स्वरूप, कांग्रेस के विराधी या प्रतिपक्षी तत्त्वा का स्वरूप और गान्धि, राज्या की कांग्रेस की राजनीति पर प्रभाव डालने वाले जातिविकीर विरोध या विभिन्नता और विभिन्न प्रदेशों के सामाजिक ढाँचे में अंतर।

यह याद रखना चाहिए कि कांग्रेस को जनता का समर्थन मिलने के बावजूद अनेक क्षेत्रों में इसका जोर नहीं फल सका था। इन क्षेत्रों में दूसरे दला का जोर था। इनमें बंगाल, पंजाब और मद्रास प्रधान थे। अनेक क्षेत्रों में रियासतों में छिड़पुट आदान-प्रदान चल रहे थे, मगर मजबूत दला का विकास नहीं हुआ था। इनमें केरल, मैसूर राजस्थान, मध्यप्रदेश का बड़ा भाग, पटियाला और पंजाब की रियासत, सौराष्ट्र थे। उड़ीसा और आसाम के आदिवासी-बहुल प्रांत भी इसी श्रेणी में आते थे। १९४७ के बाद यहाँ की राजनीति अलग-अलग ढंग से विकसित हुई। बंगाल और पंजाब का देश के विभाजन से गहरा घबका लग गया था, किंतु विधानसभा राय और प्रतापसिंह कौरा जैसे विशिष्ट नेताओं के कारण यहाँ कांग्रेस की सत्ता स्थापित हुई और खूब आर्थिक उन्नति हुई। मद्रास (तमिलनाडु) में कांग्रेस की मुख्य प्रतिद्वंद्वी ब्रह्मण्य जस्टिस पार्टी थी। कामराज के नेतृत्व के उदय से मद्रास कांग्रेस ब्रह्मण्य का हाथ से निकल गई। राजस्थान सौराष्ट्र और मैसूर के प्रजा आंदोलनों का कांग्रेस से निकट संबंध रहा और स्वतन्त्रता के बाद राजाओं के विरोध के बावजूद इनमें कांग्रेस की प्रधानता कायम हो गई और केन्द्रीय सत्ता को इनसे बल मिला। दूसरी ओर मध्यप्रदेश, उड़ीसा और आसाम में अस्थिरता रही तथा कांग्रेस में बलवदी और आदिवासियों और सामंती तत्त्वा की ओर से विरोध बना रहा। केरल में वामपक्षी प्रवृत्तियाँ का जारी रहा और कांग्रेस वहाँ जड़ न जमा सकी।

प्रांतों के राजनीतिक विकास पर मजबूत और योग्य नौकरशाही के होने या न होने का भी असर पड़ा। मद्रास और पश्चिम बंगाल बहुत दिनों तक अंगरेजी प्रशासन में रहे और वहाँ नौकरशाही शासन की मजबूत परंपरा थी, इससे राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास में मदद मिली। मैसूर और बड़ोदा जैसे रियासतों में भी प्रशासन प्रगतशील और अच्छा था। किंतु मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश

३१ प्रादेशिक राजनीति के अध्ययन के लिए अनेक ग्रंथ हैं। माइसन वानर द्वारा संपादित 'स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया' (प्रिंटन १९६७), इरवाल नारायण, संपादित 'स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया' (मेरठ १९६७) पाल ब्राम्, 'फैशनल पॉलिटिक्स इन ऐन इंडियन स्टेट-द कांसेप्ट ऑफ़ इन उत्तर प्रदेश' (बुल्ले और लॉस ऐंजेल्स १९६६) बलदेवराज नायक 'माइनारिटी पॉलिटिक्स इन पंजाब' (प्रिंटन १९६६) एफ. जे. बेली, 'पॉलिटिक्स ऐंड सोशल चेंज-उड़ीसा इन १९५६' (बुल्ले ऐंड लॉस ऐंजेल्स १९६२) सेलिग एस. हैरिसन, 'कास्ट ऐंड द आर्थ कंजुनिस्ट्स' - अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू, ५०, नं० जुलाई १९५६।

और उड़ीसा में इस प्रकार की अच्छी प्रशासन पंथरा न थी, इसलिए वे बिछड़े रहे और वहाँ राजनीतिक अनवय भी रहा ।

महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र जस प्रदेशों में जहाँ कांग्रेस का जार रहा, उसने जल्दी जड़ जमा ली और उसका शासन भी लगातार रहा । इनमें नए क्षेत्र शामिल हुए, जैसे गुजरात में सोराष्ट्र और आंध्र में हैदराबाद और तेलंगाना, इनमें विकास काय भी अच्छा हुआ । इन राज्यों में जो सघष ह, उनकी जड़े स्वतन्त्रता के पहले से चली आ रही हैं, जैसे गुजरात में सोराष्ट्र और आंध्र में तेलंगाना का जादोलन । बिहार और उत्तरप्रदेश में यद्यपि हाल तक कांग्रेस सत्तारूढ़ रही, लेकिन सामंती परंपरा और राजनतिक अनैक्य के कारण वहाँ गुटबंदी और व्यक्तिगत राजनतिक प्रतिद्वंद्विता का जोर है, जिसका नतीजा राजनतिक अस्थिरता है और जल्दी जल्दी सरकार बदलती रही ।

इन प्रांतों की स्थिति पर वहाँ के सामाजिक ढांचे का भी प्रभाव पड़ा । मद्रास और महाराष्ट्र में ब्राह्मणों के संगठन, गुजरात और आंध्र में बीच की जातियों की राजनतिक शक्ति और मसूर में भी जातिविशेष के जोर के कारण, वहाँ की राजनीति और शासन में स्थिरता रही । दूसरी ओर उत्तर में बिहार और उत्तर प्रदेश और दक्षिण में केरल जैसे राज्यों में जातियों में स्पर्धा के कारण राजनतिक गठजोड़ न हो पाए और अस्थिरता बनी रही । पश्चिम बंगाल के ऊपर कलकत्ता छाया हुआ है, इसलिए वहाँ की राजनीति में शहरीपन आ गया । वहाँ वामपंथी दला का जोर है और बजाय एक दल की प्रधानता के संयुक्त दल की राजनीति का चलन है । इसके विपरीत आंध्र प्रदेश में खेती की प्रधानता है और भूस्वामी बग का जोर है । इसने छोटी किसान जातियों का अपने साथ मिला लिया है और इस प्रकार वहाँ आश्रयदाता — आश्रित वर्गों का गठजोड़ बन गया है । मध्यप्रदेश, आसाम और उड़ीसा में कांग्रेस और गैरकांग्रेस दला की जोड़ तोड़ में आदिवासी कबीलों का हाथ रहा है ।

इस प्रकार इन प्रांतों की सामाजिक, प्रशासनिक पृष्ठभूमि का राज्य की राज नीति और केन्द्र-राज्य संबंधों पर प्रभाव पड़ा है । पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सर कार कायम होने पर भी वहाँ शहरी वामपंथी दला की ओर से संयुक्त विरोध की परंपरा रही । इसी प्रकार केरल में भी दलित एजवा जाति से कम्युनिस्टों को सम-चन मिला । इसके साथ शिक्षितों की सरया बढ़ने के साथ साथ उनमें बेकारी भी बढ़ी, वहाँ गांवों और नगरों में भी घना सघष बना रहा । बंगाल और केरल दोनों जगह कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेतृत्व में संयुक्त मोर्चे के बीच सीधा मुकाबला या ध्वी-करण हुआ । आंध्र प्रदेश में कम्युनिस्टों का जोर था, इसे रेडडी और कामा जातिया के द्वाद से बल मिला । बाद में कांग्रेस की गठजोड़ नीति के कारण दोनों जातिया कांग्रेस सरकार और संगठन में आ गई और विरोध हैदराबाद और तेलंगाना

जैसे क्षेत्रों से उठा, जो राज्य में बाद में शामिल हुए वे जोर अभी तक उसमें घुल-मिल न सकें थे। पंजाब और मद्रास में कांग्रेस के पुराने विरोधी अकाली और अग्रहण तत्त्वा ने पुनः सिर उठाया और राजनीति का प्रभावित किया। उड़ीसा आगाम और मध्यप्रदेश के आदिवासी-बहुल प्रदेशों में और सामंती पूर्वी यू० पी० और बिहार में चाहें कोई पार्टी उत्ता में रहे, वहां व्यक्तिगत स्पर्धा और जाड़तोड़ चलता रहता है।

इस प्रकार हमने देखा कि राज्या में राजनीति की गतिविधि का सध की राजनीति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यह बात भी ध्यान योग्य है कि केन्द्रीय सरकार का, विशेषकर राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय समाज के विरुद्ध तत्त्वा को राष्ट्रीय राजनीतिक ढांचे में एक साथ लाने में बहुत हाथ रहा है। इसी के साथ ही सघीय शासनतंत्र का विकास और सत्ता का विकेंद्राकरण हुआ है। जगले अध्याय में हम यह देखेंगे कि एक दल कांग्रेस के चलाय अनेक दल के चोर पकड़ने से किस प्रकार केन्द्र-राज्य संस्था का और स्पष्टीकरण हुआ है और सघीय व्यवस्था किस प्रकार विभिन्न प्रदेशों और जातियों के राजनीतिक दलों का सामना कर रही है।

विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया

स्वतन्त्रता के बाद स शासन की सत्ता का और राजनतिक अधिकार का प्रसार नीचे तक हुआ है। चार बातों ने इस क्रिया को प्रभावित किया है। पहली बात यह है कि योजना के कार्यक्रमों की पूर्ति नीचे के लोगों पर निर्भर है। राज्य का प्रशासन केन्द्र एवम् राज्य के नीति निर्णय का विशेष कार्यक्रम देने और जिले और उससे निम्न स्तर पर वायावयन के लिये इन कार्यों का वितरित करने के जलावा कुछ अधिक नहीं करता। अंग्रेजों ने भी इसी प्रकार जिला के प्रशासन को राज्य की इकाई बनाया था। स्वतन्त्रता के बाद विकेंद्रीकरण के और कदम उठाए गए। योजना को चलाने के लिए जिला विकास बोर्डों की स्थापना की गई, सामुदायिक विकास खंड, विस्तार एजेंसियां, ऋण सहकारी समितियां और पंचायतें स्थापित की गईं। ये प्रशासनिक और राजनतिक विकेंद्रीकरण की नई सस्थाएं थीं।^{३२}

दूसरे लोगों को लाभ पहुंचाने और इस प्रकार अपना प्रभाव जमाने के जरिया

३२ स्वतन्त्रता के पहले भी स्थानीय बोर्ड और सहकारी संगठन मौजूद थे और बरबस व मद्रास जैसे उन्नत प्रांतों में अच्छा काम कर रहे थे। अवश्य ही ये सरथाए प्रारंभिक अवस्था में थीं और अधिकार - विभाग के उत्साह पर निर्भर रहता था। जनता का सहयोग भी इनमें कम था। इस विषय पर देखें - बावे कोआपरेटिव इस्टाब्लिशमेंट्स के 'फिफ्थ इयर्स आफ कोआपेरेशन' - म के बा नाथन का - इनाशियल स्ट्रेज ऑफ आर्गनाइजेशन (१९०४-१९१२)। स्थानाय स्वायत्त संस्थाओं के विकास के बारे में देखिए ह्यु टिंकर 'द फाउन्डेशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया पाकिस्तान पेंड बमा' (लंदन १९५४)।

की रखला स्थापित हो गई। नए राजगार व नौकरिया तथा ऋणों का बटवारा, गावा में ऋण और मिट्टी के तेल, शक्कर आदि बाटने वाली संस्थाएँ तथा स्कूलों के खुलने से पहुँच व प्रभाव तथा अर्थोन्नति के नए जरिये प्रस्तुत हो गए। इनमें सरकारी मशीन को नया महत्व मिल गया और पुराने समाज का नई राजनीतिक व प्रशासनिक संस्थाओं से रोज और प्रशिक्षण काम पड़ने लगा।

राज्या के नेताओं ने लाभों के वितरण का यह सिलसिला शुरू किया। अपना पद बनाये रखने के लिए, इनको गावा के बोटा का ज़रूरत थी। इसलिए इन्होंने अपने प्रभाव का जाल फैलाया और स्थानीय संस्थाओं, स्कूलों, विकास की संस्थाओं आदि पर कब्ज़ा किया, जिससे लोगों को नौकरी दे कर और फायदा पहुँचा कर, उनका समयन प्राप्त किया जा सके। नतीजा यह हुआ कि सत्ता नीचे का ओर जाने लगी और जिला व नगरों में ऐसे लोग ऊपर आए जिन्होंने लाभकारी संस्थाओं पर और राजनीतिक दलों के पदा पर कब्ज़ा जमाया और धीमे धीमे प्रभाव और शक्ति प्राप्त की। ये लोग छोटे बच्चा और तहरीना के नेता थे, और जनता के बीच से आए थे। ये देश के परंपरागत समाज से उठे थे और उसकी मनोवृत्ति को समझते थे। ये व्यावहारिक और दबंग आदमी थे। नए विचारों से इनको बहुत मतलब न था, परंतु इन्होंने नई व्यवस्था को फैलाने में योग दिया। ये लोग स्थानीय गुटबंदी और दावपक्ष में माहिर हैं और अपनी शक्ति को जानते हैं। चुनाव के समय राज्य के नेताओं का इही स्थानीय नेताओं पर भरोसा करना पड़ता है, जिनके हाथ में स्थानीय संस्थाओं की बागडोर हानी है और जो आर्थिक और सामाजिक शक्ति रखने वाले वगैरे हैं। इनमें से कुछ लोकप्रिय नेता होते हैं और कुछ दादागिरी में माहिर, लेकिन जनता के बोट इनके हाथ में होता है। इन लिए शक्ति भी इनके हाथों में जा गई है।^{२३}

तीसरी बात है चुनाव प्रणाली का ज़रूरी विस्तार। भारत में अनेक स्तर पर निर्वाचित संस्थाएँ हैं — राष्ट्रीय संसद, राज्य विधान सभा, जिला परिषद, ब्लॉक और गांव पंचायत। इसके अलावा वे निर्वाचित संस्थाएँ हैं जिनके हाथ में थोड़ी आर्थिक शक्ति होती है, जैसे जिला महक़ारा बैंक, नक़दी फसलों के उत्पादन और बिक्री की सहकारियाँ, और जिला पंचायत की आर्थिक समितियाँ।^{२४} इनमें से कुछ का सीधा जनता द्वारा चुनाव होता है, कुछ नीचे की संस्थाओं के प्रति-

२३ मैं ने राष्ट्रीय और राज्य नेताओं में स्थानीय नेताओं के हाथ में जाने के कारणों का विवेचन इकनामिक बीकन १४, विश्वास जुलाई १९२२ में अपने एच 'इ'थि, १ पोलिटिकल टर्म्स आफ में किया है।

२४ राजनीति और राजनीति में सदस्यी संस्थाओं के महत्व के लिए देखिए-ए एम नाथियर, 'कोऑपरेटिव ऐंड पोलिटिक्स' इकनामिक ऐंड पोलिटिकल बीकन-१२ न १२, मार्च १९२३, १९२८।

निधिया द्वारा चुनी जाती है, और कुछ के सदस्य ही चुनते हैं जा विभिन्न श्रेणिया में आते हैं। कुछ लोग रईस सस्याजा व सदस्य होते हैं लेकिन साधारणतः राज्य की विधान सभा के उम्मीदवार नीचे की सस्याजा के नेताओं पर भरोसा करते हैं।

चौथे, वालिा मन्त्रिपरिषद् के कारण राजनीति में नए नए वर्गों का प्रवेश हुआ है। जा जानिया अब तक राजनीति को ग्राह्य और क्षत्रिय जैसे ऊँची जातिया का क्षेत्र समझती थी, उनको अब सम्भावित या महत्त्व प्राप्त हो गया है और वे भी संगठित हो रही हैं। उनकी समस्याएँ और नेता भेदान में आ रहे हैं। राजनीतिक दलों की स्पर्धा और जायिक योजनाओं व जनता का भलाई के कामों के चालू होने से जातियों के मुखियाओं का महत्त्व बढ़ गया है और राजनैतिक नेताओं को इनसे व्यवहार करना पड़ता है। इस प्रकार गाँव के सामाजिक ढाँचे का राजनीतिवीकरण हो रहा है और शासन तथा राजनीतिक दलों का नीचे की ओर फटना हो रहा है, जिससे भारतीय समाज के शक्ति के ढाँचे में परिवर्तन आ गया है।

लेकिन गाँव के इस फटना से गाँवों की कलरना के स्वावन्त्री ग्राम समाज का स्थापना नहीं हुई है। राजनीति संगठन या शासन की इकाई के रूप में गाँव का महत्त्व घटा है। ग्राम सुधार या सामुदायिक विकास योजना की इकाई भी गाँव न होकर विकास खंड है। शिक्षा प्रचार, यातायात, जातीय संगठनों आदि के द्वारा गाँव ऊपर के स्तर से प्रभावित होते हैं। गाँव के सगड़ों को छोड़ कर गाँव की राजनीति क्षेत्र की राजनीति का अंग होती है। नेतृत्व के लिए केवल गाँव का समयन नहीं, गाँव के बाह्य से समयन प्राप्त करना जरूरी है। केवल बहुत बड़े गाँव इसके अपवाद हैं, जैसे केरल में। जो गाँव बाहर से मतलब नहीं रखते और अपने में ही सिमटे रहते हैं, उनका राजनीति में ज्यादा महत्त्व नहीं।

जिले का महत्त्व

क्षेत्र की गतिविधियाँ का केन्द्र जिला होता है। बहुत वर्षों से जिला प्रशासन का आधार रहा है। जिले की जनसंख्या करीब १५ लाख, प्रशासन के लिए आदर्श है। इसी प्रकार उसका रकबा भी अच्छे प्रशासन और विकास कार्य के लिए आदर्श होता है। सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के लिए भी जिला अच्छा कार्यक्षेत्र होता है। योजना के कार्य जिले के स्तर से ही शुरू होते हैं। मुगला के जमाने से लेकर आज तक शासन की इकाई के रूप में जिले ने राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी एक व्यक्तित्व प्राप्त कर लिया है। जिले का कलेक्टर जनता की आँखों में शासन और अधिकार का प्रतीक होता है।

राजनीति में भी जिला कांग्रेस कमेटी शक्ति की धुरी होती है। जिलों के नेताओं के बल पर राज्य के मंत्रिमंडल और राज्य कांग्रेस का संगठन निर्भर होता है। महाराष्ट्र

और गुजरात में एक एक मंत्री के जिम्मे कई जिले लगा दिए हैं वह लोगों के प्रतिनिधियों से मिलता है, उनकी शिवायते सुनता है और जिले के हित की देखरेख करता है। राज्या के मंत्रिमंडल में जिले प्रतिनिधित्व का दावा करने लगे हैं। यद्यपि सभी जिला का दावा स्वीकार नहीं किया जाता, पर राज्य की राजनीति में उनका महत्त्व स्पष्ट है।

जिला आर्थिक और सामाजिक जीवन का भी केंद्र बन गया है। लोग अपना परिचय देते समय अपने जिले का नाम लेते हैं। जातियों के संगठन भी जिलावार होते हैं। राजनीतिक और जातीय गुट भी जिला के हिसाब से बनते हैं। जिलों के केंद्र में नगरों का रूप लिया है। जिलों के केंद्र में ही कचहरी, स्कूल, कालेज, बाजार, जिला सहकारी बैंक, भूमिबचक बैंक, लाइसेंस के दफ्तर, खेती और वन विभाग के दफ्तर, जिला पुलिस, जिला बोर्ड और जिला कलेक्टर होने के कारण क्षेत्र की सभी गति विधि वहां केन्द्रित हो जाती है। इसमें जिला मजिस्ट्रेट और जिला कांग्रेस नेता का भी प्रमुख स्थान होता है।

कलेक्टर या जिलाधीश के पद का भारत में अपना अलग महत्त्व है। स्वतंत्रता के बाद बढ़ते हुए वातावरण में जिलाधीश के महत्त्व को कम करने का प्रयत्न हुआ, लेकिन ब्रिटिश शासन की यह ऐसी परंपरा है जो टूट नहीं सकी। इधर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष विकास अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। हो सकता है इससे जिला कलेक्टर का एकछत्र प्रभाव कम हो जाए, किन्तु जिले का प्रशासनिक महत्त्व तब भी बना रहगा।

जिले का सबसे बड़ा महत्त्व राजनीतिक संस्थाओं और नेतृत्व के विकास में है। जिले में अनेक नई संस्थाएँ और विभाग खोले गए हैं। गुरु में बहुत सी विकास की और अर्ध-सरकारी एजेंसियाँ स्थापित की गईं। इनमें कज देने की संस्थाएँ, स्वास्थ्य की एजेंसियाँ, स्कूल और कालेज थे, जिनसे नेताओं के हाथ में लोगों का फायदा कराने के साधन आए। इसके बाद सामुदायिक विकास और पंचायती राज की संस्थाएँ कायम हुईं। इनसे स्थानीय नेताओं में प्रभाव और शक्ति की वृद्धि हुई। यद्यपि सामुदायिक विकास खंड जिला से छोटे थे लेकिन इनको टेक्निकल सलाह और साधन जिले से ही मिलते थे। जिला और ब्लॉक अधिकारियों को महत्त्वपूर्ण पाय और अधिकार सौंपे गए। इससे जिले के नेताओं की शक्ति और बढ़ गई। जिले के निर्वाचित प्रमुख होने लगे, जिनको सावजनिक कोष से वेतन मिलता था। ये लोग ज्यादातर दली भूस्वामी वर्ग के होते हैं, इनको अपने क्षेत्र का राई रत्ती हाल मालूम होता है और ये जनता का नेतृत्व करने तथा संस्थाओं को चलाने में निपुण होते हैं। ये जनता से ही नहीं, जिले के और ऊपर के अधिकारियों से भी बड़े विश्वासपूर्वक व्यवहार करते हैं। इस प्रकार शासन के विवेकीकरण और नई स्थानीय संस्थाओं की स्थापना से जिलों के बाड़े से प्रमुख व्यक्तियों के हाथ में

आर्थिक और राजनैतिक शक्ति भी आई है, पार्टों की मशीन का विस्तार हुआ है और स्थानीय आंदोलनों और मधर्पा के संचालन की पद्धति विकसित हुई है।

इस प्रकार भारत में स्वतंत्रता के बाद एक पीढ़ी के अंदर ही शासन और राजनीति का तन अनेक स्तरों पर काम करने लगा। स्थानीय स्तर पर विकास और राजनीतिक संगठन की अनेक संस्थाएँ काम करने लगी, स्थानीय लोगों से सलाह, जांच पड़ताल और नियम लेने की व्यापक प्रणाली विकसित हुई, जो एक राष्ट्रीय शखला से जुड़ी हुई है। इससे आधुनिकता और परंपरा, पुरानी और नई राजनीतिक व्यवस्था का अंतर मिट रहा है।^{३५}

पंचायती राज का महत्त्व

राष्ट्रीय नेतृत्व का एक दूरदर्शितापूर्ण कार्य था पंचायती राज की स्थापना। इसका व्यापक महत्त्व भाषावार राज्यों के गठन और योजना कमिशन की स्थापना से अधिक है। इससे भारतीय राज्यव्यवस्था का विकेन्द्रीकरण हो रहा है और देश में एक ही स्थानीय संस्था के निमाण से उसकी एकता भी बढ़ रही है। संभव है कि इस कदम का दूरगामी महत्त्व नेताओं ने उस समय न समझा हो। प्रशासनिक और वौद्धिक क्षेत्रों में इसकी सफलता में संदेह था और इसका भ्रम उड़ाया गया था। इसकी शुरुआत का श्रेय जवाहरलाल नेहरू को है।^{३६} उनका लोकतन्त्र के तरीका में अटूट विश्वास था। उन्होंने पंचायती राज और सामुदायिक विकास दोनों पद्धतियों का जोरा से समर्थन किया था।^{३७}

सामुदायिक विकास कार्यक्रम १९८५२ में आरंभ हुआ। इसमें काफी सरया में सरकारी कर्मचारी रले गए और लवे छोडे दावे किए गए। पर वह सरकारी तन और ग्रामीण जनता के बीच की दूरी कम करने के मुद्दे में विफल

३५ इसके लिए देखें-सी एम मिलिप्स संपादित-‘पोलिटिक्स एंड सोसाइटी इन इंडिया’ (न्यूयॉर्क १९३६) में नारिस जोन्स का ‘इंस्टिट्यूट पोलिटिकल इंडियन’। उन्होंने सा देखिये-‘पार्लियमेंट इन इंडिया’ पृ ३७-४०। और भा उशिशन पाई और सिटनी बर्नो-सपा ‘पोलिटिकल कल्चर एंड पोलिटिकल डेवलपमेंट’ (प्रिंसटन १९५५) में मास्टर धानेर का ‘इंस्टिट्यूट पोलिटिकल डेवलपमेंट’।

३६ लेफ्ट का ना इन्तर्नल संदेह था। देखिये-पूर्वोक्त ‘पार्थ एंड सबस्टेस’ में मेरा विचार लेख। इसमें इस कार्यक्रम की संरचना की समीक्षा भी की गई है और इस विषय के संदर्भ-सूत्रों का उल्लेख किया गया है।

३७ ‘गावा के लोगों को अधिकार संपिना चाहिए। उनकी काम करने दो चाहे वे दारों गतिता करें। इसमें पराने की जरूरत नहीं। पंचायती को अधिकार दा’। कुन्नेव-‘ए सिपिओ बियम’ (दि १९६१) में जवाहरलाल नेहरू।

रहा। ३८ इस विफलता का एक कारण यह था कि इसे सरकारी महकमे की तरह चलाया गया और गावों के विकास के बजाय सामुदायिक विकास की मशीनरी के विस्तार पर ही ज्यादा जोर दिया गया। ३९ सरकारी तंत्र के जरिए गावा के लोगों की मनोवृत्ति को बदलने की आशा की गई, नतीजा यह हुआ कि गावा की उन्नति के लिए खुद प्रयत्न करने के बजाय ग्रामीण जनता सरकार का मुंह जोहती रही। ४०

दूसरी बात यह थी कि इस कार्यक्रम के सारे कमचारी और माधन जुटाने का काम सरकार ने जोड़ लिया और सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता उद्योगों के विकास को दी इसलिए इस कार्य के लिए बहुत कम साधन और कमचारी जुटाए जा सके। तामरे, सरकारी तंत्र की प्रचुरता और साधनों की कमी के कारण सामुदायिक विकास कार्यक्रम में प्राथमिकता का क्रम बिल्कुल उल्टा हो गया। ब्लाकों में कार्यालय की इमारत बनाने और सरकारी कमचारी भर्ती करने में तो बड़ी तत्परता दिखाई गई पर खेती की तरक्की और जनता में स्वावलंबन और स्वयं बान बनने की भावना पैदा करने पर कम ध्यान दिया गया। ४१ चौथे, आर्थिक विकास की व्यापक रीतिनाति में इस कार्यक्रम के लक्ष्य गावा के कार्यावली का कोई तबय नहीं स्थापित किया गया। इस कार्यक्रम पर काफी खर्च हो चुकने और इसकी सफलता के लंबे चौड़े दावों के बाद इसकी जाच के लिए एक कमेटी नियुक्त की

३८ सामुदायिक विनास का सबसे बड़ा कमचारा उसका सरकारी स्वरूप और नेताओं का कर्णपाज था। एक तरफ इस कार्यक्रम के सूत्रधार जनता से आगे आने का आशा करते थे, दूसरा ओर उनका विश्वास था कि सरकारी कारवाई से ही नतीजा निकल सकता है। कार्यक्रम जनता को चलाना था लेकिन वे बनाये ऊपर से जाते थे। इस समस्या पर रेनहाड बन्किंस, 'नेशन बिल्डिंग एंड मिटिगनशिप' (न्यूयार्क १९६८) पृ २६६-८३ में बहुत अच्छा विचार दिया गया है।

३९ जितना तेजी से सामुदायिक विनास छड़ और विस्तार पकड़सिया खोली गई उनसे इसके सरकारी रूप का पता चलता है। सन १९५३ में सारे देश में इसे फैलाया जा निर्णय हुआ और १९५६ तक १२०० ब्लाक खोले दिए गए जिनके अलगत देश की एक चौथाई ग्रामाण जनसंख्या आता था। १९६३ तक सारे देश में यह फैल गया। संयुक्त राष्ट्र के एक मिशन ने यह राय दी कि इतने तेज विस्तार से सपन विनास नहीं हो पाएगा। यू एन कमिशनर फार टेक्निकल अमिस्टैस, रिपोर्ट आफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट एवैलुएशन मिशन इन इंडिया १९५८-५९ (दिल्ली-१९६१)

४० स्वयंसेवक साठन की जिम्मेदारी भी सरकार न ली। योजना कमिशन की जनसंयोग वमेटी और आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नन्दा की प्रेरणा से भारत सेवक समाज को जिसके सरक्षक नन्दा और नेहरू थे, लोक-वार्थक्षेत्र खेलन के लिए रूपया दिया गया। इसके मूल्यांकन के लिए दक्षिण-योजना कमिशन एस्टाब्लिशमेंट ऑफ कायक्षेत्राल आफ दभारत मेवक समाज' (नई दिल्ली-१९६०)

४१ मेहता वमेटी रिपोर्ट, खंड १, पृ ४ प्लानिंग कमिशन, प्रोग्राम एवैलुएशन आर्गनाइजेशन, एवैलुएशन रिपोर्ट आन वॉरिंग आफ कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स पैड एन ६ एस ब्यूरोम (दिल्ली-१९५९)

गई। इसने सरकार को बताया कि इस कार्यक्रम की बुनियादी नुति यह है कि जनता का इस में सहयोग नहीं मिला। इस रिपोर्ट में तथा अप जांच रिपोर्टों में यह कहा गया कि जब तक स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी और अधिकार नहीं सौंप जाते, संविधान के निर्देशक सिद्धांतों का राजनैतिक और विकास संबंधी लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। ४२

इसलिए लोकतंत्रीय प्रणाली के विकेंद्रीकरण और विकास कार्यक्रमों में जनता का सहयोग लाने का उद्देश्य स पंचायती राज की दुरुआत की गई। इसके स्वरूप में विभिन्न राज्यों में कुछ अंतर हैं, मगर कुछ बात एक सी है। ४३ एक तो पंचायती राज की तीन सीढ़ियाँ हैं - गाँव पंचायत, खंड में पंचायत समिति और इसके ऊपर जिला परिषद। इनके लिए विकास कमचारियों की शखला है जो राज्य स्तर से शुरू हो कर गाँव तक फली हुई है। इस प्रणाली में स्थानीय लोग को काम करने की आजादी है और दूसरे ऊपर से है। अर्थात् इसका वही ढंग है जो केन्द्र और राज्य के संबंध का। दूसरे, सामुदायिक कार्यक्रमों की तरह यह सरकारी मालिकारी का जग नहीं है। पंचायती राज की संस्थाएँ निर्वाचित होती हैं और इसके कमचारी निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधीन काम करते हैं। ४४ तीसरे, साधन जुटाने और जनसहयोग संगठित करने का भी इन संस्थाओं को अधिक अधिकार है। य कार्य ले कर केन्द्रीय सरकार तक निरंतर प्रशासनिक और राजनीतिक परंपरा सुचारु रूप से नहीं काम कर रही है, परंतु प्रवृत्ति स्पष्ट लक्षित होती है। पंचायत बहुत पुराने जमाने में भी वनमान थी, मगर वर्तमान पंचायती संस्था इस माने में नई है कि उनको काफी अधिकार, साधन और जिम्मेदारियाँ सौंपी

४२ योजना कमिशन द्वारा प्रकाशित प्रोग्राम एवेड्युएशन रियोगें को देखिए - कमिशन ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम से असंतोष प्रकट किया और राष्ट्रीय विकास परिषद से उसका जांच कराने को कहा। तदनुसार मेढता कमिटी नियुक्त हुई और १९५७ में इसने बहुत बनी रिपोर्ट दी। इसका मुख्य मुद्दा यह था कि विकास कामों में स्थानीय जनता को लगाने के लिए एक प्रतिनिधि संस्था का स्थापना की जाए।

४३ इस प्रणाली के विविध रूपों के बारे में देखें - सेंटर फार द स्टडी आफ डेवेलपिंग सोसाइ- टाइज - 'ए माफ लिक्विडेशन आफ लोकल सर्विस गवर्नमेंट सिस्टम इन गुजरात, महाराष्ट्र, पेंड उत्तरप्रदेश (मिथि १९६६)।

४४ ज्यों की पंचायत समितियों में ग्राम पंचायतों के प्रधान होते हैं। अधिकांश राज्यों में विशेष परिषदों का चुनाव पंचायत समितियों करता है। बाद में महाराष्ट्र और गुजरात में निष्पक्ष परिषदों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होने लगा। इन संस्थाओं में अधिकारियों का उपस्थिति या शिरकत के बारे में भी अलग अलग परिपाटी है। पूरे विवरण के लिए देखें उपर्युक्त पुस्तक।

गई है। नाम पुराना है मगर सस्था नई है। ४५ इन सस्थाओं ने नए स्थानीय नेताओं को जन्म दिया है जो आगे चल कर राज्य और केन्द्रीय सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। कांग्रेस और अन्य दलों के राजनीतिक इन सस्थाओं के महत्व को समझने लगे हैं। अब वे राज्य विधान मंडल के वजाय पंचायत समिति और जिला परिषदों और जिला सहकारी बैंक और जिला परिवहन अधिकरण के पदों को तरजीह देने लगे हैं। इन पदों पर रहकर वे प्रशासन और प्रबंध में निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। ये सरकारी पदाधिकारी स्थानीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था के बीच की कड़ी हैं। ४६ इन स्थानीय पदाधिकारियों के बिना ऊपर से प्रारम्भ किए हुए राष्ट्रनिर्माण के क्रियाकलापों का चलना मुश्किल हो जाता। इन लोगों के सहयोग के बिना सरकारी अधिकारियों का काम भी मुश्किल हो जाता। गैर सरकारी कार्यकर्ताओं की शक्ति केवल प्रशासनिक और वितरण सस्थाओं के पदों के कारण नहीं, बल्कि समाज के शक्तिशाली वर्गों के समर्थन के कारण है। इस प्रकार पुरानी व्यवस्था धीमे धीमे नई व्यवस्था के पास आ रही है।

विचवई लोग

इस क्रिया ने एक दलाल विचवई वर्ग को जन्म दिया है। गैर सरकारी राजनीतिक, स्थानीय समाज के समर्थन के बल पर ही अपना काम कर सकता है। उसे विभिन्न तत्वों के प्रभावशाली लोगों का समर्थन प्राप्त करना पड़ता है। इन प्रभावशाली लोगों में जातीय और धार्मिक नेता, विभिन्न सस्थाओं के नेता, शिक्षक, वकील, डॉक्टर आदि व्यवसाय के प्रमुख, राजनीतिक पेशेवर या चुनाव के दलाल और स्थानीय गुंडे भी होते हैं जो लोगों को वश में रखते हैं और सौदा हो जाने पर दगाबाजी नहीं कर सकते। हो सकता है कि कहीं एक जादूगी विभिन्न हिता और वर्गों को काबू में रखता है और कहीं कई विभिन्न हिता के अलग-अलग नेता

४५ योजना कमिशन, 'द विलेन पंचायत एंड पैटर्न ऑफ विलेन डेवलपमेंट' जुलाई १९५४-अक्टूबर १९५५ तरलोवसिंह (मामियो)। किंतु इन सस्थाओं के कार्यों के बारे में कुछ दुविधा थी। कुछ अफसरों के विचार थे कि वे स्थानीय स्वशासन की वास्तविक सस्था होनी चाहिए और कुछ वी राय थे कि वे केन्द्रावलित योजनाओं को चलाने की एजेंसी मात्र होना चाहिए। देखें - मेहता वमेरी रिपोर्ट। विदेशी विशेषज्ञ में भी मतभेद था। डेनियल थार्नर १९६० केन्द्रीय एजेंसी बनाने के पक्ष में थे और अल्बर्ट मेयर स्थानीय स्वायत्त शासन सस्था के पक्ष में। देखिये नान दी हिचमन, 'संश्लेषण रूढ़ डेवलपमेंट इन इंडिया' इकनामिक वॉचमैन १३ मार्च, १९६१।

४६ गैर सरकारी शब्द अमेरीकियों ने बनाया था, जब महत्व सरकारी लोगों का था।

होत ह । हर हालत म य महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं । ४७

सबध की य शखलाए पुगने जाति-विरादरी के मुखिया, सरकारी अधिकारि-या से काम निकलवाने वाले चुनाव के दल और गुट, सब एक सावजनिक व्यवस्था के अंग बन गए ह । ससद और विधानसभाओ के चुनाव से राजनीतिक गतिविधि मे भाग लेने का सबसे बड़ा मौका मिलता है । पचायती राज के चुनाव कांग्रेस के उम्मीदवारों का चयन और कांग्रेस कमेटिया के चुनाव से राजनीतिक गतिविधिया मे भाग लेने का और मौका मिलता है । इसके अलावा भी और मौके ह, जैसे विकास, अनुदान और खेती के लिए ऋणों के वटवारे चीनी, तेल आदि के वितरण, स्कूल, सड़क, ट्यूबवेल, दवाखानों आदि के निर्माण मे बातचीत और जोर दबाव के मौके मिलते है । इन सब गतिविधियों का स्थानीय महत्त्व बहुत अधिक होता है । पचायती राज के चालू होने से जनसहयोग की इन शखलाओ का सबध ऊपर के राजनीतिक और आर्थिक निणय लेनेवाले स्तरा से जड़ जाएगा और गावा के लोगो का महत्त्व बढ जाएगा । भारत की पुरानी ग्रामीण समाज-व्यवस्था का शासन और राजनीति म सहयोग, भारत के विकास की पद्धति मे निहित है ।

यहा आधुनिकतावादी और आधुनिकता के प्रचारक मे जो फर्क है उस को जान लेना चाहिए । आधुनिकतावादी शहरो के बौद्धिक और राजनीतिक विचारक लोग हैं । ये आधुनिक भारत के आदर्श और विकास के लक्ष्यो का निरूपण करत हैं । ये सैद्धांतिक बात करते ह, जनसाधारण की आकांक्षाओं और मांगो से ये मतलब नहीं रखते । दूसरी ओर आधुनिकता के प्रचारक जनसाधारण म काम करते ह । ये सिद्धांत के प्रजाय व्यवहार पर ज्यादा ध्यान देत ह, ये आधुनिक लक्ष्या के लिए जनता का समयन प्राप्त करते है । साथ ही वे नीति-निमाता लोगो का असलियत की जानकारी देत ह । वे ही राष्ट्र निर्माण के काय को गति देत है । कालांतर म ये आधुनिकता-वादिया का स्थान ले लेते ह । लोकतंत्रीकरण की इसी व्यापक प्रक्रिया को सरल रूप में शहर से गावा की ओर शक्ति के परिवहन का नाम दिया जाता है ।

४७ यह परिवहन या सन्नान्ति काल की विशेषता है । बेरल, मद्रास महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में जहा राजनीतिक दल और सरकारी एजेंसिया एकदम नीचे तक पहुच गई हैं, बिच वश्यों का जरूरत कम होती जा रही है । लोग सीधे राजनायिगों या अपसरों से व्यवहार करते हैं । लेकिन कम विरसित श्लकों में बिचवश्यों के जरिये ही, यह बातचात होती है । देखें-आर चंदीदाम 'द फोर्थ जनरल इलेक्शनस मध्यप्रदेश, ए वेस स्टडी' इस्नामिक ऐंड पोलिटिकल वाक्की २, स ३३-३५ विशेषांक अगस्त १९६७ । इस विषय पर सामान्य विचार के लिए जयत लेटे, 'लोकल मोवर्स ऐंड नेशनल एडर्स ए स्टडी ऑफ सपोर्ट डिफेजें इन द डेवलपिंग पालिसा, अमेरिकन पोलिटिकल साइंस असोसिएशन की वार्षिक बैठक में पढ़ा गया लेख, सितंबर १९६८ (मीमियो) ।

राजनीतिक विकास और नौकरशाही

भारत सरकार ने गांधी तक पहुँचने और देशव्यापी संस्थाओं की शक्ति बनाने का जो विशाल प्रयत्न किया उससे यह पता चलता है कि जनता का समर्थन मिलने के बावजूद राष्ट्रीय आंदोलन समाज में गहरा नहीं जा सका था। गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को शहरी मध्यम वर्ग के सकीण दायरे से निकाल कर जनता में पहुँचाया था और ग्रामों के पुनर्निर्माण को उसका लक्ष्य बनाया था। लेकिन इस पर काम स्वतंत्रता के बाद ही शुरू हुआ।

दूसरे, स्वतंत्रता के बाद जो कुछ काम हुआ है उसके बावजूद भारत में एकरूप राजनीतिक समाज का निर्माण नहीं हो सका है। अभी भी यहाँ बहुत विषमताएँ और अंतर हैं। अभी बहुत दिनों तक यहाँ का समाज अनेकात्मक रहेगा, जिसमें अनेक स्वायत्त उपसमाज बने रहेंगे।

अब तक हमने जनता में राजनीतिक संस्थाओं के प्रसार पर जोर दिया है। साथ ही हमने बताया है कि प्रशासन और आर्थिक योजना का इस प्रक्रिया में क्या हाथ रहा है। बिना इन के राजनीतिक संस्थाओं का प्रसार न हो पाता। यहाँ हम इस विषय पर और विचार करेंगे।

अंग्रेजों की विरासत

अंग्रेजों ने इस महादेश का शासन करने के लिए एक नमूने की जिला शासन प्रणाली की रचना की थी जिसके अधिकारी एक अखिल भारतीय सिविल सर्विस के सदस्य होते थे और जो शासन के समान सिद्धांत पर चलते थे। यही शासन प्रणाली हमको अंग्रेजों से विरासत में मिली।^{४८} अंग्रेजी शासन में महत्वपूर्ण राजनीतिक और विकास संबंधी निश्चय सरकारी ढंग से किए जाते थे। यही परिपाटी भारतीय नेताओं ने भी अपनाई। इस परिपाटी को चार बड़े परिवर्तनों का मुकाबला करना पड़ा। एक तो शासन के कार्यों में बेहद विस्तार हुआ, दूसरे शासन के हर स्तर पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं का प्रभुत्व हुआ और नीति तथा नियम इन के हाथों में आया। तीसरे, जिले और नीचे के स्तरों पर लोकतंत्रीय संस्थाओं को अधिकार दिया गया, और चौथे, आर्थिक आयोजन, नियंत्रण और संयोजन की अनेक संस्थाएँ कायम हुई तथा सामाजिक क्षेत्र का अपार विस्तार हुआ।

हमने देखा है कि स्वतंत्रता के पहले सहकारी अधिकारियों और राष्ट्रीय नेताओं में विरोध और कटुता के संबंधों के बावजूद स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने सरकारी नौकरों की स्थिति बरकरार रखी और इस प्रकार उनका विश्वास प्राप्त किया। यही नहीं उन्होंने भविष्य के सारे परिवर्तनों और नई नीतियों का भार भी सर-

^{४८} हमने अध्याय २ में आई एस एस पर विचार किया है। आई सी एस की उत्तराधिकारी नई आई एस एस है, जिसके अधिकार प्रायः पूरे सेवा जैसे हैं।

कारो सवाजा पर डाल दिया । सारी आर्थिक जोर राजनीतिक गतिविधिया का संचालन सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है । देशव्यापी चुनावों का प्रबंध, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सरकारी संगठनों की स्थापना व संचालन स्वयंसेवक संस्थाओं का भी संगठन, विशालकाय सरकारी कारखानों और कारपोरेशनों की व्यवस्था, बड़ी बड़ी परियोजनाएँ जिस में बहुत रुपये और टेकनिकल ज्ञान लगता है, अनुसंधान और विकास की बहुत बड़ी योजनाएँ, पंचायती राज जैसी राजनैतिक संस्थाओं के संगठन और संचालन और दुर्लभ वस्तुओं पर कंट्रोल और वितरण, यह सारा सरकारी नौकरों के जिम्मे है, और हम हेतु स्वतन्त्रता-पूव नौकरशाही का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है ।

परिवर्तन में जो पुराने ढाँचे का बनाए रखने का कुगरिणाम भारत के प्रशासन तंत्र में नज़र आता है । फिर भी आश्चर्य है कि गाड़ी चलती रही । याद रहे कि भारतीय प्रशासन सेवा की ऊँची श्रेणियों में अधिकारियों की संख्या अधिक नहीं । आई ए एस के करीब केवल ३००० आदमी केंद्र और राज्यों के प्रायः सारे शासन का चलाते हैं । दूसरे यह विकेंद्रित सेवा है (नियंत्रण पर अमल का काम केवल जिला स्तर पर गुरु होता है) । तीसरे, इस सेवा के सदस्य विशेषण न होकर एक काम से दूसरे काम पर जाते रहते हैं । इससे यह प्रश्न और महत्व का हो जाता है कि प्रशासनिक ढाँचे का नए सिरे से पुनर्गठन करने बजाय, पुराने ढाँचे को ही क्या बनाए रखा गया । *९ भारत ने न तो समाजवादी देशों की भाँति शासन व ममानांतर राजनैतिक मशीन का निर्माण किया, न पश्चिमी देशों की भाँति आर्थिक विकास को निजी उद्योग के हाथ में छोड़ दिया । उसने देश के प्रशासन को विकास प्रशासन से अलग भी नहीं किया और कट्टोरा की पेचीदा प्रणाली से काम चलाया ।

नए विकास

स्वतन्त्रता के बाद आर्थिक गतिविधियों के समन्वय के लिए क्विन्ट सचिवालय से लेकर नीचे के स्तर तक अनेक संस्थाओं का निर्माण हुआ । एक ओर योजना कमिशन और उसकी समितियाँ तथा जांच पड़ताल की एजेंसियाँ तथा दूसरी ओर

४९ पुनर्गठन का शान बराबर चलती रहता है । सरकार ने इम्प्लेमेंटेशन वर्रार जांच पड़ताल कराई है । डेटें, गाल एपिलडा, पूर्वोक्त, और 'रिपब्लिकमिनेशन आफ इंडिया एटमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम' (दिनांक १९६६) और ए. डी. गोरवाल, 'रिपोर्ट ऑन पब्लिक एटमिनिस्ट्रेटेशन' (दिल्ली १९५९) । जमा हाल में प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस विषय पर कई रिपोर्टें दा हैं । इनमें भारतीय प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी और उसके पुनर्गठन के लिए यापक सुझाव दिए गए हैं । उन पर अमल किया जाएगा या नहीं यह और बात है । हमारे बारे में पिछला अनुभव अच्छा नहीं रहा है ।

केन्द्रीय मन्त्रालय ने सरकारी कपनिया और तारसारना तथा विनामीय उद्योगों का एक जाल बिछा दिया। केन्द्र और राज्या में सत्ताह मशविरों की प्रणाली चालू की, तथा आर्थिक और मानवीय साधनों के उपयोग के लिए जांच पड़ताल, दख रेख और नीति निर्धारण की व्यवस्था की। विकास समर्थी अनेक मन्त्रालयों के मंत्री विशेषण लागू हैं, ५० और विभागों में विशेषज्ञ और टेक्निकल कार्यकर्ता रहे गये। राज्या में भी यही हो रहा है। यहां समस्त अनुभवों अधिकारी मुख्य सचिव और विकास आयुक्त जैसे सबसे महत्व के पदा पर रखे जाते हैं और वे राज्य का आर्थिक और प्रशासनिक सूत्र संचालन करते हैं। इसी अधिकारियों पर और इनके राजनैतिक मालिकों या मंत्रियों पर, जो काफी समय तक उनी महकमें को सभालते हैं, विकास कार्यों का मुख्य भार पड़ता है। ये लोग एक-सा दृष्टिकान और टेक्निकल बातों का गहरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इन लोगों पर इतना अधिक भार सादना सुगमवस्था के सिद्धांतों के खिलाफ है, मगर इससे लाभ यह होता है कि नीति और कार्य में एक रूपता बनी रहती है। ५१

जिला के स्तर में अधिकार दो अधिकारियों के हाथ में रहते हैं। साधारण प्रशासन और जिले की देखरेख का काम जिले का कलेक्टर करता है और उसी के समबन्ध पद का विकास अधिकारी जिला, ब्लॉक और गांवों के विकास कार्य की देखरेख करता है। ५२ वे अधिकारी निर्वाचित गर सरकारी पदाधिकारियों के मातहत काम करते हैं जो स्वयं निर्वाचित ब्लॉक व जिला परिषदों के प्रति जिम्मेदार होते हैं। केन्द्रीय सरकार, योजना कमिशन और राष्ट्रीय विकास परिषद यह अनुभव कर रहे हैं कि प्रशासन के निचले स्तर से ढिलाई है, अतः इन सस्याजों की स्थापना शासन की निचली श्रेणियों को चुस्त बनाने के उद्देश्य से की गई है। ये सम्याए अपने उपर अनेक काम ले लेती हैं और प्रशासन को जनता की जरूरतों के मुताबिक चलाने की कोशिश करती हैं। स्थानीय प्रशासन राष्ट्रीय और राज्य सरकार की नीकुरशाही पर स्थानीय विकास के कार्यों और आर्थिक जरूरतों

५० उदाहरण हैं सी ला देशमुख, के एल राव एम सी चागला, वि कर व राव एस चन्द्रशेखर और त्रिगुण सेन। अशोक मेहता भी इसी श्रेणी में हैं। सा शुभमनिदम भाबदे टेक्निकल विषयों के मंत्री रहे, इत्यादि तथा राध, कृपि और इनमें उ होने राजनीतिज्ञ के बगैर विशेष की भांति काम किया।

५१ भारत में बहुत थोड़े ऊपर के आदमी बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं इस आगेचना के लिए दें—पाल एपिल्ली, 'पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन'। लोयतन की म्बिरता के लिए स्पष्ट विचार वाले संगठित अधिकारी वर्ग के महत्त्व के लिए देखें—एडवर्ड शिल्म, 'पोलिटिकल डेवलपमेंट्स इन द यू स्टेट्स' कम्पैरेटिव स्टडीज इन सोसाइटी ऐंड डिस्ट्री, २, २९६०।

५२ प्रशासनिक और विकास समर्थी कार्यों में अंतर करना कठिन है। कलेक्टर के हाथ में भी विकास के अनेक कार्य होते हैं, जैसे नये उद्योगों का विकास और बन तथा खनिज संपदा की रक्षा।

की पूर्ति के लिए दबाव डालता है।

इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ऊपर के अधिकारी नीचे के स्तरों को अधिक प्रभावित कर पाते हैं, और अभाव या कष्ट के समय जनता की सहायता करते हैं, खेती की उन्नति और अन्य सुझावों की प्रेरणा देते हैं और आर्थिक सहायता और अन्य प्रकार के समयन का आश्वासन देकर उनके निणयों को प्रभावित करते हैं। दूसरी ओर ऊपरके लोगों को स्थानीय हालतों की जानकारी मिलती रहती है और जनता की भावनाओं का पता चलता रहता है।^{५३} इससे सरकार और जनता में परस्पर संपर्क बढ़ता है।

व्यवहारिक कठिनाइयाँ

नई समस्याओं की स्थापना या पुरानी के सुधार के साथ साथ उनका उपयोग भी ठीक ढंग से होना चाहिए और नीति भी परिस्थिति के अनुरूप गतिशील होनी चाहिए। जब प्रगतिशील नेतृत्व का साविका अप्रगतिशील समाज से पड़ता है तो अक्सर नीतियाँ अव्यावहारिक हो जाती हैं। नेता लोग विकास की अपनी धारणा बना लेते हैं और ठोस कार्रवाई के बजाय कितनी बातों, सिद्धांतों और नाराओं से सतोंप कर लेते हैं और समय बैठते हैं कि उनके अमुक कदम का अमुक परिणाम होना ही चाहिए। जब उनको गहरी विफलता मिलती है, तब स्थिति पर पुनर्विचार किया जाता है और नीति बदली जाती है। भारत में यही बात हुई।

पहली पंचवर्षीय योजना की सफलता के बाद बड़े पैमाने पर भारी उद्योगों के विकास की योजना बनाई गई। गांवों के लिए सामुदायिक विकास, भूमि सुधार के कानून और सहकारी खेती की बड़ी कितानी या अव्यावहारिक योजना बनाई गई।^{५४} भारी उद्योगों के विकास में ही देश के अधिकांश साधन — जो पहले

५३ सभी जगह इस प्रकार का परस्पर संपर्क नहीं स्थापित हो सका है। अक्सर पंचायतों में जाति या वर्ग का बोलबाला रहता है और सब वर्गों के हितों की देखरेख नहीं हो पाता। निश्चित पदाधिकारी सरकारी अधिकारियों पर गलत दबाव भी डालते हैं। फिर भी कुछ बातें स्पष्ट हैं। एक तो चुनावों के कारण ऊंची जाति वालों को नीची जातियों से मेल करना पड़ता है। दूसरे, ऊपर की शक्ति का अंग होने के कारण पंचायतों में ज्यादा जिम्मेदारी आ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारों नौकरशाही को अब जनता की मांगों पर ध्यान देने और मनबूर होना पड़ता है। देखें — ए. हेन्सम। इस प्रणाली की संभावनाओं और चुनावों का भूमिका के लिए देखें — एस. सी. जैन 'कम्युनिटी डेवलपमेंट बेंच पंचायतों राउंड इन इंडिया' (कलकत्ता और बंबई १९६७)।

५४ इस में शास्त्राल अधिक था, ठोस कार्रवाई कम। भूमि सुधार कानूनों में भी राजनीतिक कारतव्यता की उपेक्षा की गई। सहकारी खेती के मामले में भी वास्तविकता का ध्यान नहीं रखा गया। नागपुर प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस दल ने 'सहकारी खेती' की स्थापना का ऐलान [आगे के पृष्ठ पर]

ही से कम थे - लग गए और खेती पर बहुत कम ध्यान दिया जा सका। ५५ जब कि खेती की उन्नति के बिना, देश की दशा में कोई वास्तविक सुधार न हो सकता था। नतीजा यह हुआ कि योजना के लक्ष्य पूरे न हो सके। राज्य सरकार ने, जो योजना कमिशन के पोथी पड़िता के मुकाबले, वास्तविकता को ज्यादा समझती थी भूमिसुधार के कानून बनाने और सरकारी खेती को चालू करने में उत्साह न दिखाए और जनता ने सामुदायिक विकास योजना के निर्माताओं के उपदेशों पर कोई ध्यान न दिया। इस से स्पष्ट हो गया कि केवल लक्ष्य निर्धारित कर देने से ही विकास का काम पूरा नहीं हो जाता।

सामुदायिक योजना की विफलता को शब्दजाल से ढकने का प्रयत्न किया गया और नए नए मुद्दावा की झड़ी लगा दी गई, जो कभी पूरे नहीं हो सके। ५६ योजना बनाने वालों तथा प्रशासकों ने अपना दोष स्वीकार करने के बजाय किसानों पर अकर्मण्यता का दोष मड़ा। देशी और विदेशी समाज शास्त्रियों ने भी भारतीय जनता की अकर्मण्यता और भाग्य के भरासे रहने की मनोवृत्ति को ही दोष लिया। ५७ इन लोगों ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया कि खेती के साधनों के अभाव और अधिकारियों की खामियाखालों और कूटमंजरी के कारण किसान नए तरीकों की जोखिम उठाने को तैयार न था।

इस बीच लोकतंत्री प्रणाली ने अपना असर दिखाया। राष्ट्रीय व्यवस्था, स्थानीय नेता और पार्टी संगठन की गतिविधि जोरा से चालू होने के फलस्वरूप ऐसे नेता

[पिछले पृष्ठ से]

किया, मानो वक्त्र की नोक से इसी स्थापना हो जाएगी। इस प्रस्ताव की गहरी प्रतिक्रिया हुई और फलस्वरूप स्वतंत्र पाटा का जन्म हुआ। प्रस्ताव की अव्यावहारिकता स्पष्ट हो गई और इसको धोरे से खनम कर दिया गया। इस चक्कर में खेती की उन्नति के लिए कोई ठोस काम न किया जा सका।

५५ नेता-कोविकास की उपेक्षा और आयोजन की सामान्य त्रुटियों के लिए देखें - डॉ. भार गान्धिल, 'प्लानिंग ऐंड इकनामिक पालिस्सी इन इंडिया' (पूना १९६१)।

५६ इन सुझावों में सबसे साहसपूर्ण वा नीचे से आयोजन का, अर्थात् गांवों की योजना को राज्य और राष्ट्रीय योजना का आधार बनाने का। इस पर कभी अमल नहीं किया गया, यद्यपि इसे त्यागा भी नहीं गया। देखिए - ह्यून्सन, पूर्वोक्त का अध्याय 'थ्रूट्स रुट्स'। इसमें यह भी बताया गया है कि इस सुझाव को अमल में लाने के लिए क्या कदम उठाए गए।

५७ भारत के नौकिक नेताओं के भाषणों और लेखों में भारतीय किसान की अकर्मण्यता की बहुत शिंशायत की जाता है। यू. एन. मिशन रिपोर्ट में भारत के गांवों की प्रगति-हानतता के अनेक कारण बताये गये हैं। इस विषय पर विदेशी पाठकों में कुसुम जायर की किताब - 'थमम्स इन द टरट' (लंदन १९६१) काफी मशहूर हुई। भारतीय किसानों की अकर्मण्यता का प्रचार करने वालों में एक डेविड सी. मेकक्लेरेंड भी हैं - 'द नवीबिंग सोसाइटी' (यूजस १९६१)। भारतीय जनता की उद्यमशास्त्रा के बारे में बहुत अवयन किए गए हैं, इनमें से अधिकांश अमेरिकन संस्थाओं द्वारा कराए गए।

ऊपर आए, जो जनता के वोटों का महत्त्व समझते थे और उसकी प्रारम्भिक जरूरतों को जानते थे। इसलिए उन्होंने विकास के तरीकों के बारे में नए सिरे से सोचने का तैयार था। राज्यों के मुख्यमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष कामराज, प्रधान मंत्री लालबहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी तथा कांग्रेस के अन्य यथार्थवादी लोग ने इन पुनर्विचार में योग दिया। सी सुब्रमण्यम जैसे कल्पनाशील मंत्री और उनके निष्ठावान अधिकारियों ने 'नई आर्थिक नीति' की तफसील तैयार की। लगातार दो बार के अकाल और देश की जनता को भोजन देने के लिए विदेशों से भिक्षा मांगने की जलालत ने नीति-परिवर्तन को बाध्य कर दिया।^{५८} योजना का कार्यक्रम बदल दिया गया, आर्थिक नियंत्रण ढीले किए गए, योजना कमिशन का पुनर्गठन किया गया। (उसको जो ज़रूरत से ज्यादा महत्त्व मिला गया था, उसे उचित स्तर पर लाया गया।) प्रशासन को निश्चित काम और दिशा दी गई और वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम बनाया गया और प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण किया गया।

अब कांग्रेस में आर्थिक नीति पर राजनैतिक विवाद होने लगे और आर्थिक तथा सामाजिक प्रश्नों को गुटबंदी का आधार बनाया गया। १९६६ में श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस संगठन के नेताओं में जो विरोध हुआ, उसके कारण इंदिराजी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का निश्चय किया और नृण तथा पूँजी नियोजन के क्षेत्र में राज्य को बहुत अधिक शक्ति मिली। यह कारवाई तेज विकास में याग देगी या सिर्फ नारेबाजी का रूप लेगी, यह तो जाने पता चलेगा, किन्तु इतना तो स्पष्ट हो गया कि राजनैतिक सघर्ष की नीति के प्रश्नों से जोड़ने की प्रवृत्ति की शुरुआत हो गई। इस के कारण देश के लक्ष्यों 'ब' उद्देश्यों को ठोस रूप मिलने की आशा हो गई है। इस राजनैतिक सघर्ष से नीति में जो परिवर्तन होंगे उनसे भारत के विकास का राजनैतिक नमूना क्या होगा।

इन प्रश्नों पर हम अध्याय ६ में अधिक विस्तार से विचार करेंगे। यहाँ इतना ही कहना काफी है कि देश ने जिन समस्याओं का विकास किया है और उनसे जो राजनैतिक प्रवृत्तियाँ चालू हुई हैं, उनके कारण देश के लक्ष्यों को अधिक ठोस शकल मिलती जा रही है और जनता की भावनाओं और ज़रूरतों के अनुसार नीति में संशोधन किए गए हैं, तथा शासन जनता के अधिक निकट आया है। अभी भी व्यवस्था में बहुत-सी नुटियाँ हैं, ठोस कार्य के बजाय नैक इरादों से सतोंप कर लेने

^{५८} नीति रीति का यह परिवर्तन केवल नीचे से दबाव के कारण नहीं हुआ। ऊपर के लोग भी ऐसी ही उन्नति की प्राथमिकता देने की ज़रूरत समझ रहे थे। अंतरराष्ट्रीय दबाव भी पड़ रहे थे। विश्व बैंक, संयुक्त राज्य अमेरिका और सहायता मिशन भी भारत सरकार पर जोर दे रहे थे कि वह विकास की नीति को सुधारे। मगर जैसा कि एक पड़ रिपोर्ट में स्वाक्षर किया गया उसी के विकास को सब से अधिक राजनैतिक समर्थन भारत के अंदर से मिला।

की प्रवृत्ति बनी है और पुरानी रुढ़िया तथा स्वायत्त राष्ट्रीय प्रगति के आड़े आत है। सर्वसम्मत राजनैतिक विचार अभी सस्था का रूप नहीं ले पाये हैं। विकास काय के लिए सस्थाओं में क्या परिवर्तन होने चाहिए, अभी इसको नेतागण ठीक समय नहीं पाए हैं। फिर भी ठोस यथार्थ का सामना करने और समस्याओं को सुलवाने के लिए नीति और प्रशासन के तन्त्र में यथोचित संशोधन करने की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से लक्षित होती है। राजनैतिक विकास की और दिशाओं पर विचार करने के बाद, हम अध्याय ८ से ११ में विचार करेंगे कि विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में शासन को कितनी सफलता मिली है।

सस्या निर्माण और जनता की स्वीकृति

कहा गया है कि विकास प्रक्रिया की कठिनाइयाँ और दवावों के बावजूद भारत में स्थिरता बनी रही इसका मुख्य कारण यहाँ शुरू में ही सस्था निर्माण काय का हो जाना है।^{५९} स्वतंत्रता के पहले और बाद में भारतीय लोकतन्त्र की सस्थाओं के निर्माण का हमने जो अध्ययन किया है उससे इस मत की पुष्टि होती है। परन्तु भारत के राजनैतिक नेताओं ने सस्थाओं के निर्माण में क्या नीति नीति अपनाई इसका तफ़्तील से अध्ययन जरूरी है। हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा कि सस्थाओं के निर्माण के पीछे क्या प्रेरणा थी और सस्थाओं के विकास और उनके मायता व स्वीकृति प्राप्त करने में जनता के सहयोग और संगठन का क्या हाथ रहा।^{६०}

चार बातें स्पष्ट हैं। एक तो यह कि भारत में सस्थाओं के विकास की प्रक्रिया काफी समय तक चलती रही। लंबे विदेशी शासन में प्रादेशिक और प्रशासनिक ढाँचे की रूपरेखा निर्मित हुई। फिर राष्ट्रीय आंदोलन भी लंबा चला और उसके लक्ष्यों का विकास हुआ और जनता में उन्हें मायता मिली। फिर दो दशकों तक कांग्रेस का शासन चला जिसमें संविधान के ढाँचे और उसकी प्रक्रिया का निर्माण हुआ और जनता में उनकी जड़ जमी। इन सब से लोकतन्त्र की सस्थाओं का ढाँचा मजबूत हुआ। यह प्रक्रिया कभी टूटी नहीं, निरंतर जारी रही और लंबे अनुभव के साथ प्रशासन और राजनीति की लंबी परंपरा भी बतमान रही। मशीन टूटने नहीं पाई।

५९ सैमुअल एच हर्टिगमन, 'पोलिटिकल डेवलपमेंट एंड पोलिटिक्स टुडे'। इनका मत है कि जनता के सहयोग के साथ ही सस्थाओं का निर्माण नहीं हो जाता तो राजनैतिक हास होने लगता है। दूसरों का मत है कि बहुत जल्दी संस्थाएँ बन जाती हैं तो इससे संस्था बढ़ती है और प्रणाली के टूटने की नींव पड़ती है।

६० देखिए मेरा - द्रैडिशनल बेंड माडर्निटी रिनिचिटेड, गवर्नमेंट बेंड अपोनिशन ४, पृष्ठ ३, १९६८ ग्राम।

लंबाई के साथ ही इस प्रक्रिया में गहराई भी रही। राष्ट्रीय जादोलन और उसी से उत्पन्न राष्ट्र निर्माण का जादोलन दोनों जनता के समर्थन पर आधारित थे और इसी उद्देश्य से वे जनता में फैलाए गए। राष्ट्रीय नेता अधिक से अधिक जनता को राष्ट्रीय राजनीति में भाग देने से कभी हिचके नहीं। सत्याग्रहों के विकास के हर चरण पर जनता को उसमें शामिल होने का जोर उससे लाभ उठाने का मौका दिया गया। इससे सत्याग्रहों की गतिशीलता बनी रही और उनमें जड़ता नहीं आने पाई।

देश में जो विचारों और आदर्शों की एकता फैल सकी, उसका कारण यही था कि नेताओं को भी कुछ आदर्शों में विश्वास था, और इन पर आचरण कर के उन्होंने पहले अपने साथी कार्यकर्ताओं में और फिर जनसाधारण में इनका प्रचार किया। गांधीजी के लेखों और भाषणों के विशाल संग्रह को पढ़िए तो आप यही पाएंगे। उनमें थोड़ी-सी बातों को बार-बार दोहराया गया है, जब तक कि वे राष्ट्र के मन में न समा गई और उसकी विचारधारा का जग न बन गई। नेहरू ने भी यही किया। लोकतन्त्र समाजवाद, योजना और गुटों से अलग रहने की वह लगातार रट लगाते रहे जिससे इन विचारों ने स्वयंसिद्ध तथ्य का रूप धारण कर लिया और वे राष्ट्र के बुनियादी सिद्धांतों में शामिल हो गए। कुछ समय तक इन बातों ने ही ठोस काय का स्थान लिया। किंतु यदि इन बातों का प्रचार न हुआ होता तो राजनीतिक सभ्यता में जड़ता आ जाती और वह सिद्धांतहीन गुट-बंदी के दलदल में फस जाती। इसी विचारधारा के कारण दलगत राजनीति देश की एकता का साधन बन गई।

हमने यह भी देखा है कि संविधान द्वारा जो ढांचा स्थापित हुआ, भारतीय नेता उसमें लगातार नई बातें जोड़ते गए। यह बहुत जरूरी है क्योंकि सत्याग्रहों का ढांचा जड़ नहीं होता कि एक बार हमेशा के लिए बन गया और उसमें कोई सुधार न हो सके। जैसे जैसे नई समस्याएँ उपस्थित हो, उनमें आवश्यक परिवर्तन होना चाहिए। नए राष्ट्र के एकीकरण और स्थानीकरण का काम एक बार में नहीं होता, उसे बार-बार करना होता है। पुराने मूल्यों और उनके सत्यागत रूप, जातिप्रथा, स्थानीय राजनीति प्रादेशिक संगठन, बदलते रहते हैं। यह काम वर्षों तक चलता रहता है। वास्तव में यह कभी रुकता नहीं। यह धारणा कि सत्याग्रहों को स्थिर होना चाहिए और अस्थिरता की प्रक्रियाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए, भारत जैसे नए और विकासमान राष्ट्र की असंलियत से मेल नहीं खाती।

अतः हम यह कहना चाहते हैं कि यह न समझना चाहिए कि सत्याग्रहों के निर्माण की यह प्रक्रिया पहले से बनाए गए नमूने के अनुसार होती है। इसकी साधारण रूपरेखा कुछ आदर्शों व प्रयोजना से निर्धारित होती है लेकिन इसका भावी विकास नई परिस्थितियों के अनुसार होता है। नेतावर्ग जो कदम उठाता

है उसका परिणाम क्या होगा यह हमेशा नहीं सोच पाता। यदि सब परिणामों, विफलताओं, सघर्षों और कठिनाइयों की कल्पना पहले से ही कर ली जाए तो बहुत से कदम उठाए ही नहीं जाते। ११

नसोच परिणामों के बारे में दाविद — बलवर्त ओ हर्शमैन, "डेवल्पम" प्राज्ञ। स
(वार्शिंगटन डी सा १९६७) ।

पार्टीप्रणाली और गठजोड़

अब तक हम देख चुके हैं कि भारत को इतिहास से क्या विरासत मिली है, उसने किस प्रकार पुरानी और नई बातों में समन्वय किया और किस प्रकार इसके आधार पर अपने संविधान की और आर्थिक व सामाजिक नीतियों की रचना की। हमने यह भी देखा है कि इन नई समस्याओं और विचारों तथा कुछ प्रतीकों और विधियों के जरिए देश की राजनैतिक व्यवस्था किस प्रकार अपना एक स्वरूप ग्रहण कर रही है।

प्रश्न यह है कि ये समस्याएँ किस हद तक समाज में प्रवेश कर पाई हैं और राजनैतिक व्यवस्था कहाँ तक जनता की स्वीकृति पा सकी है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें इस व्यवस्था के उन अवयवों या तत्त्वों को देखना होगा जो इसे गति देते हैं। ये तत्त्व तीन हैं। एक है दल की पद्धति और किस प्रकार यह विभिन्न तत्त्वों या गुटों से गठबंधन करके सहमति प्राप्त करने की काशिश करती है। दूसरा है जाति का ढाँचा, जो इस पद्धति का सामाजिक आधार बन गया है और तीसरा है वे राजनैतिक संस्कार और सामाजिक प्रवृत्तियाँ जो प्रथम दोनों तत्त्वों से उत्पन्न होते हैं। इस और अगले दो अध्यायों में इन्हीं तीनों तत्त्वों का विवेचन किया गया है।^१

^१ भारतीय पार्टी पद्धति पर मेरे पहले के अध्ययन ये हैं—'पार्टी सिस्टम', 'फार्म ऐंड सबस्टेंस इन इंडियन पोलिटिक्स' का पाचवाँ लेख, द इकनामिक वीकली, १३, जून ३, १९६१। 'द कॉम्रेस सिस्टम इन इंडिया'—इंडियन सर्वे ५, नं० १२ दिसम्बर १९६४। 'पार्टी पोलिटिक्स ऐंड पोलिटिकल डवलपमेंट' इकनामिक ऐंड पोलिटिकल वीकली, वार्षिक अंक, फरवरी १९६७। नेशन मेनिंग ऐंड फानक्शंस—द केस आफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस—सेवेंथ वल्ड कांग्रेस आफ द इटरनेशनल पोलिटिकल साइंस असोसिएशन, मुम्बई। 'अपोजिशन इन इंडिया परपेक्टिव ऐंड चिक—राइट डाक संपादित 'द एमर्जेंस आफ अपोजिशन (न्यू हेवेन १९७०)। 'कांग्रेस सिस्टम इन इंडिया' शीर्षक लेख, 'पार्टी सिस्टम ऐंड एक्जिशन स्टडीज' में छपा है अकेजनल पेपर्स १, सेंसर फार द स्टडी आफ द डेवलपिंग सोसाइटीज (नई दिल्ली—१९६७)। इस अध्याय में इन सब लेखों में प्रस्तुत विचारों को और भी विवक्षित किया गया है।

प्रतिस्पर्धी प्रमुखता

स्पष्ट है कि भारत की वर्तमान राजनतिक सस्थाभा की धुरी कांग्रेस है। हमने देखा कि कांग्रेस ने देश को एक समठित नेतृत्व दिया, जा उसकी आर से बालने का दावा कर सकता था। इस क्रिया म कांग्रेस वा अपना स्वरूप निखरा और उसने जनता की निष्ठा प्राप्त की। यह भी याद रसना चाहिए कि कांग्रेस ने न केवल विदेशी शासन का विरोध किया बल्कि इसने भारतीय समाज म घुस आई बुराईया का भी विरोध किया। समाज का सुधार और पुनर्निर्माण उसको उतना ही प्रिय था, जितनी देश की आजादी।^२ कांग्रेस नेता बार बार यह कहा करते थे कि समाज का पुनगठन आजादी हासिल करने का उपाय है। कांग्रेस की यह दाहरी भूमिका—राष्ट्र की ओर से बोलने की और राष्ट्र की कमजोरियाँ को आलोचना करने और उस बदलने की—आजादी क बाद शासन सभालने पर नी कायम रही। इससे यह जाहिर होता है कि आजादी की प्राप्ति राष्ट्र निर्माण क बाय की शुरुआत है। इसके लिए वर्तमान स्थिति से अमतीप और उसको बदलने की प्रवृत्ति उत्तनी ही जरूरी है जितनी स्थापित शासन-व्यवस्था को बनाए रखने की। ऐसा न करने के कारण ही एशिया और अफ्रीका की बहुतेसी राष्ट्रीय पार्टियाँ आजादी के बाद छिन निन हो गईं। पार्टी या दल तन वा विकास तभी हो सकता है जब राष्ट्र के एकीकरण के साथ साथ उसके पुनर्निर्माण का भी प्रयत्न चालू रह। कांग्रेस पार्टी एक विशिष्ट पार्टी है। इसका संगठन चुनाव लड़ने के उद्देश्य से नहीं विदेशी शासन के विरोध के लिए किया गया था और इसे जनता म फलाने के साथ साथ विभिन्न विचारधाराआ और हिता को नी इसम लाने का प्रयत्न किया गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस संगठन म प्रधान या सत्ताधार गुट के अलावा विरोधी गुट भी रहत थे। जब इसने शासक दल का रूप ग्रहण किया, तब भी इसम विरोधी गुट बने रहे। इससे संगठन की शक्ति ही बढी साथ ही इसके नेतावग को विरोधी गुटा की आलोचना का भी लगातार सामना करना पडा। यह आलोचना राजनतिक और सामाजिक प्ररना को ले कर की जाती थी। बालिय मताधिकार के द्वारा कांग्रेस ने हर स्तर पर प्रतिद्विद्धता के लिए अवसर दिया। चुनावो से केद्र म कांग्रेस की प्रधानता स्थापित हुई, और राज्या तथा स्थानीय चुनावो मे भी उसकी शक्ति दृढ हुई। उसे देहात क लोगा का समथन मिला। चुनावो और योजना के कार्यक्रमो के द्वारा पहली बार देश की सरकार का गावा

^२ कांग्रेस एक और अर्थ मे विरोध वा प्रतिनिधित्व करता था। इसके अंदर अनेक विचारों के छोटे छोटे दल या समूह थे। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट सभी पार्टियाँ एक समय कांग्रेस के अंग थे। कांग्रेस के सत्ताधारी दल से मतभेद हो जाने पर लोग इससे निराश कर अलग पार्टी बना लेत थे और इससे वापस भा जा जाता करते थे।

म प्रवर्ण हो सका। इसके साथ ही विपक्षी दल भी संगठित होते गए और उन्होंने अनेक स्तरों पर कांग्रेस को चुनौती दी।

प्रचलित धारणाएँ

उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्र के प्रमुख निर्माता भी कांग्रेस संगठन की इस भूमिका को ठीक तरह से नहीं समझ पाए थे कि यह सरकार के समानांतर जनता में राजनैतिक कार्य करने वाला एक व्यापक संगठन है जिसमें विराधी विचारों और गुटों को भी स्थान है। इसका पता इस बात से चलता है कि गांधीजी ने सन १९४८ में यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस का राजनैतिक रूप समाप्त कर दिया जाए और उसके स्थान पर जनता में रचनात्मक कार्य करने के लिए लोक सेवक संघ की स्थापना की जाए। उनका कहना था कि जो लोग संसद या सरकारी पदों के इच्छुक हैं उन्हें कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए और अपना अलग राजनैतिक दल बनाना चाहिए। कांग्रेस को सत्ता और पद की होड़ से अलग रखा चाहिए। इस प्रस्ताव के पीछे यह विचार निहित था कि कांग्रेस जिस आंदोलन की प्रतीक थी वह जारी रहना चाहिए। परंतु कांग्रेस का राजनैतिक रूप समाप्त कर देने का विचार नितांत अव्यावहारिक था और कांग्रेस के नेताओं ने उसको नहीं माना।^३

दूसरे छोर पर सरदार पटेल थे जो कांग्रेस से सब राजनैतिक गुटों को निकाल कर उसे एक मत का सदृश अनुशासनबद्ध दल बनाना चाहते थे। उन्होंने ही सन १९४८ में कांग्रेस के विधान में संशोधन कराया, जिससे संगठन के अंदर ऐसे दलों के रहने पर रोक लगा दी गयी जिनकी अलग सदस्यता, विधान और कार्यक्रम हो।^४

इसी संशोधन के कारण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को कांग्रेस से निकलना पड़ा। मगर पटेल के संशोधन का अभिप्राय इससे भी जागे जाना था। वह कांग्रेस के व्यापक (सब विचारों को समेटने वाले) स्वरूप को बहाल कर इसे अनुशासित कार्य-

३ गांधीजी की यह बर्खास्त उनकी मृत्यु के एक दिन पहले लिखा गया था और यह भारतीय राजनीति के नैतिक स्तर का प्रतीक है। एक ओर इससे दुःख है कि कांग्रेसजन देते हैं जो दलबंदी से लिप्त होकर कांग्रेस से अलग हो गए, दूसरी ओर जनसचिव और स्वतंत्र दल भी इसी साक्षी देकर यह कहते हैं कि यदि गांधीजी की अन्त्येष्टि का पालन किया गया होता तो देश में दो या तीन दलों का पद्धति कायम हो सकती थी।

४ १९३० के दशक में कांग्रेस से हिंदू समाज को निकाला जा चुका था और युद्ध के समय कम्युनिस्टों से, क्योंकि उन्होंने भारत छोड़ो आन्दोलन का विरोध किया था और युद्ध प्रयत्नों में सहयोग किया था। अब कांग्रेस में मुख्य संगठित गिरोह कांग्रेस सोशलिस्ट हो रहा था। मगर कुछ और नए गुट भी उभर रहे थे जैसे कांग्रेस डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस सोशलिस्ट फारम।

कर्ताओं का सुमगठित दल बनाना चाहते थे।^५ वह यथायवादी व्यावहारिक आदमी थे और वह सब विचारों को साथ लेकर चलने के बजाय, एक नेतृत्व और विचार के मानने पर जोर देते थे। पटेल इस बात को नहीं समझ सके कि शासक दल के रूप में भी कांग्रेस को कई दशकों तक अनेक तत्त्वों को साथ लेकर चलना होगा।^६

नेहरू वचारिक मतभेदों से कम घबड़ाते थे और इस बात को ज्यादा समझते थे कि शासक दल के रूप में कांग्रेस को आंदोलन और राजनीतिक पार्टी, दोनों रूपों में काम करना है। इसका एक कारण यह था कि उनको भरोसा था कि राष्ट्र को किस ओर जाना चाहिए। साथ ही उन्हें यह भी विश्वास था कि इस विषय में उनके विचारों को कांग्रेस स्वीकार कर लेगी। दूसरे, वह पार्टी में खुले मतभेद या झगड़ा से बचते थे।^७ जैसा हम देख चुके हैं, उनकी नीति अभिय प्रश्ना या मगडे की बातों को टालने की रहती थी। गांधी या पटेल के बजाय नेहरू इस बात को ज्यादा समझते थे कि कांग्रेस में विभिन्न विचारों के लोग ह और उसे सहमति से चलना चाहिए। लेकिन नई स्थिति में कांग्रेस संगठन की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसे वह भी ठीक न समझ सके। यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संगठन के बजाय सरकार का स्थान प्रमुख हो जाए और सरकार को देश के राजनीतिक संगठन के नये काम करने पड़े, साथ ही सरकार और जनता की कड़ी के रूप में कांग्रेस संगठन का भी महत्व अभी भी कम नहीं हुआ था। एक तो देश में सशक्त विपक्षी दलों का अभाव था, दूसरे सदन में भी अभी विरोधी मत और लोपो की शिकायतें ठीक ढंग से अभिव्यक्त नहीं हो पा रही थी इसलिए कांग्रेस संगठन को यह काम करना था। नेहरू ने संगठन को यह काम नहीं करने दिया,

५ पटेल का उद्देश्य इतना स्पष्ट नहीं था। वह वाम पक्ष के कट्टर विरोधी थे। सन १९४९ में जब नेहरू देश के बाहर थे तब कांग्रेस कार्यकारिणी ने यह निश्चय किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी कांग्रेस के सदस्य हो सकते हैं। पटेल ने इस निश्चय का विरोध नहीं किया। बाद में नेहरू के लड़ने पर यह निश्चय रद्द हुआ।

६ १९४७ में कांग्रेस के प्रधानमंत्री था सुमरराव देव को कांग्रेस के असली स्वरूप की अधिक समझ था। एक सत्रोत्तर में उन्होंने कहा कि आने वाले कठिन समय में देश की एकता और सिरता को बनाये रखने और सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन और विकास के पड़ले से चले आए अधूरे काम को पूरा करने के लिए एक बड़े राजनैतिक दल के शासन में बने रहने की जरूरत है और कांग्रेस का यही काम करना है।

७ नेहरू सोशलिस्टों को कांग्रेस से निवाले के इच्छुक न थे। यद्यपि उन्होंने पटेल को ऐसा करने से नहीं रोका (आंदोलन के दिनों में गांधीजी से भी वह इसी तरह दब जाते थे और वाम पक्ष का साथ छोड़ देते थे)। लेकिन बाद में उन्होंने सोशलिस्टों को कांग्रेस में फिर से आने की बातचीत चलाई और समय-समय पर कुछ सोशलिस्ट कांग्रेस में वापस आते भी रहे। नेहरू प्रगतिशील तत्त्वों के नेता माने जाते थे। नेहरू और पटेल की प्रवृत्ति और विचारों में अंतर था और कांग्रेस शासन व पार्टी के बारे में उनकी धारणाएं भी भिन्न थीं।

क्योंकि वह अपनी ही प्रमुखता कायम करना चाहते थे। सगठन में अपने विरोधिया या भिन्न मत वालों को उहोने शुरू में ही दबा दिया और सगठन को स्वतंत्र हो कर काम न करने दिया। राज्या में वह सगठन पक्ष को सत्ताधारी पक्ष के प्रति द्वेदी के रूप में काम करने देते थे और इस प्रकार सत्ताधारी गुट पर अकुश रखन थे, किंतु केन्द्र में वह सगठन को अपने प्रतिद्वेदी के रूप में काम नहीं करने देते थे और वागडार अपने हाथ में रखना चाहते थे। उनके अंतिम समय में ही फिर एक बार सगठन की शक्ति बढ़ने लगी और उसमें प्रभावशाली नेता सगठन के पदाधिकारी बने, लेकिन तब तक सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तनों की सूत्रधार के रूप में सरकार की शक्ति स्थापित हो चुकी थी।

स्वतन्त्रता के बाद कांग्रेस की भूमिका क्या हो जाए कांग्रेस सरकार से उसका क्या संबंध हो, इसके साथ ही यह प्रश्न भी था कि उसकी कांग्रेस की प्रमुखता का सामने विराधी दला का क्या स्थान हो। इस विषय पर भी गंभीरता से नहीं सोचा गया। शुरू में विरोधी दलों को आशा थी कि वे कांग्रेस को अपदस्थ कर सकेंगे। लेकिन पहले और दूसरे चुनाव के बाद विराधी दला की बड़ी निराशा हुई और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा बनाने की बात शुरू हुई। बुद्धिजीवी वग द्विदलीय प्रणाला को ही सब से अच्छी समझते थे और प्रमुख कांग्रेसजन भी आशा करते थे कि धीरे धीरे यहा ऐसी पद्धति का विकास होगा। इस बीच कुछ प्रमुख लोग, जिनमें श्री जयप्रकाश नारायण भी थे, इस नतीजे पर पहुँचे कि दलगत राजनीति भारत के लिए उपयोगी नहीं, और व राजनीति से जलग हा गए।^८ दूसरी ओर अशोक मेहता का कहना था कि देश की गरीबी का देखते हुए, देश की सारी प्रतिभा उसे दूर करने में लगनी चाहिए, इसलिए विरोधी पक्षों का कांग्रेस से इस काय में सहयोग करना चाहिए, उनका कांग्रेस का विरोध नहीं, स्वस्थ आलोचना द्वारा उसको नीतिया में सुधार करना चाहिए।^९ मगर उनकी बात का 'अगूर खट्टे हैं' का उदाहरण समझा गया। नेता लोग यह नहीं समझ पाए कि देश की सत्ता के ढाँचे में विरोधी दला का महत्वपूर्ण स्थान है। ये विराधी दल क्षेत्रीय स्तर पर शक्तिशाली हैं और स्वयं कांग्रेस की आंतरिक स्पर्धा का सरक्षक हैं।

^८ जयप्रकाश नारायण, 'सोशललिज्म टु सर्वोदय' (वाराणसी १९५६) 'दुवार्स ए न्यू सोमा १९५१' (नई दिल्ली १९५८), 'ए प्लॉ फार रिक्स्ट्रक्शन आफ इंडियन पालिटि' (वाराणसी १९५९), 'स्वराज फार द पीपुल' (वाराणसी १९६१)।

^९ अशोक मेहता, 'पॉलिटिक्स आफ प्लांड इमानामी' (द्वैदरावाद १९५९), 'द अनोबिशन इन द न्यू स्टेट्स-पैपर्स आन द इंडियन सनिनार आन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड पब्लिक लिबर्टी इन द न्यू स्टेट्स' (नई दिल्ली, १९५८)। मेहता ने अपने दल के विरोध सन्मेलन में अपने निरूप पोलिटिक्ल कम्युनिज्म स आफ बैररुट इमानामी में अपने विचार प्रस्तुत किए। देखिए, रिपोर्ट-१९५९ जनरेशन आफ द प्रजा सोशललिज्म पा। (न्यू १९५९)।

१९६० के बाद ही कांग्रेस में फूट पड़ने से जोर डा राममनोहर लोहिया क कराये
व्यंगा से उत्तेजित हो कर विरोधी दला ने विरोध ही एन गुप्तगत पद्धति का विकास
किया ।

दलीयप्रणाली का विद्वलेयणात्मक स्वरूप

इस प्रकार हमारे देश में भी अन्ध जनता का तरह दलीय राजनीति में प्रभुता
सुप्रधार इस क विभिन्न जगह के आपसी गठबंधन की ठीक ठीक समझ नहीं सक।
इसका एन कारण राजनीति की वगड़ित-गापन का जरिया समझने की धारणा है
जिसमें दल शासन या सरकार के ढांचे से जलन चीज समझा जाता है जो मुतर
वर्गों का हित-गापन करता है। इन्हें मसगीय शासन में चुनाव का ए
जग समझा जाता है जिसका नाम समाज में प्रचलित वर्गों या विचार सवय -
वाच उठा कर थोड़ा जोर मीठा का प्राप्ति करने की वांछित करता है।
इस धारणा में इस बात की नुमा दिया जाता है कि सत्ताधारी और विरोधी
पक्षा क ढांचे का मुसरित करने का निग सरकार और पार्टी या दल दाना एक साथ
मिल कर काम करते हैं। स्थानीय प्रांतीय और राष्ट्रीय विभिन्न स्तर पर विभिन्न
दलाका में सरकार का समयन और विरोध संगठित करने में लोगो को राजनीति
और सावजनिक मामला में लगाने में तथा सरकार या सत्ता से सवय जोड़ने में पार्टी-
पद्धति का जो हाथ होता है उसकी भी उगा कर दी जाती है। यह बात भी भुला
दी जाती है कि पाटिया समुच्चयन और गिड्डन दोनों काम करती हैं और जनेक
बीच की मस्याओं और मगठना के जरिये काम करती हुई सपनों का फैलने में
राजनीति और जनता का शासन की विभिन्न सस्थाओं और क्षेत्रों में जैम
स्थानीय शासन शासन को आपरेटिव जादि में दितवसी लेने को प्रवत्त करती है।
पार्टी या दल सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में बारवाई करने को भी प्रवत्त करती हैं।
पाटिया केवल एक दूसरे से स्पर्धा और जनता का प्रतिनिधित्व ही नहीं करती, वे
इस प्रकार सरकार के पक्ष या विपक्ष में सापन भी प्रस्तुत करती हैं।
यदि इस बात का समय लिया जाए तो यह भी समझ में आ जाएगा कि केवल
दो दला की पद्धति से समाज के विभिन्न हिस्सा और मता को शासन में नाग लेने
और अपनी आवाज बुलंद करने का पूरा अवसर नहीं मिलता। पश्चिम के देशों
में भी दो दला की पद्धति से असतोष बढ़ रहा है और उससे अल्पमता को अभि-
व्यक्ति और प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। यदि पाटिया कइ हों, और विभिन्न
स्तरों और क्षेत्रों में काम करें तो अल्पमता का प्रतिनिधित्व ज्यादा अच्छा हो
सकेगा। फिर भी नए राज्या में भी दो दल पद्धति का ही दोहराव है। आगे हम
पार्टी पद्धति का अध्ययन इस दृष्टि से करगे कि सरकारी क्रियाकलाप को उसने
किस प्रकार प्रभावित किया है, विभिन्न स्तर पर उसने कैसा काम किया है और

समाज की ओर से इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है।^{१०}

मुख्य विशेषताएँ

पहले हम यह देखेंगे कि पार्टी पद्धति के विकास की पृष्ठभूमि क्या है और उसमें सहमति और मतभेद का क्या रूप रहा है।

(१) पार्टी पद्धति का विकास एक सुपरिचित केन्द्र से हुआ, जिसका उदय स्वतंत्रता से अनेक दशक पूर्व हुआ। इस सुपरिचित केन्द्र की अभिव्यक्ति इंडियन नेशनल कांग्रेस के देशव्यापी संगठन और प्रभावशाली नेतृत्व के द्वारा हुई।

(२) ये नेता मुख्यतः अंग्रेजी पढ़े ऊँची जाति के और इस प्रकार सामाजिक रूप से समरूप एक छोटे से वर्ग के थे।^{११}

(३) विरोधी दल भी इसी वर्ग से निकले। स्वतंत्रता के पहले भी कांग्रेस के अंदर विरोधी दल या समूह थे। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के अंदर गुटबंदी बढ़ने के साथ-साथ उसके बाहर भी विरोधी पार्टियाँ का संगठन हुआ। अधिकतर विरोधी दलों के नेता पहले कांग्रेस में रह चुके थे और उनकी सामाजिक-शैक्षिक पृष्ठभूमि एक-सी थी।

(४) इस प्रकार राजनीतिक दलों का विकास एक मध्यवर्ती दल के फूटने से हुआ, सामाजिक और आर्थिक हितों के आधार पर नहीं। यह विरोध ससदीय लोकतन्त्र की नई संस्थाओं और शालीन मताधिकार के माध्यम से संगठित हुआ और शासन तथा विकास कार्यों के विभिन्न स्तरों पर प्रकट हुआ। यह विरोध सामाजिक या वर्ग संघर्ष का परिणाम नहीं था बल्कि राजनैतिक फट या संघर्ष का परिणाम था।

(५) विरोध की इस पृष्ठभूमि का एक नतीजा यह हुआ कि भारत में सरकार, सरकारी दल में विरोधी या असंतुष्ट गुट, विरोधी दल और विरोधी दलों में असंतुष्ट गुटों में स्पष्ट अंतर नहीं था और विभाजन-रेखा अस्पष्ट थी। सत्ताधारी और विरोधी दोनों दलों में वैचारिक स्पष्टता और एकता का अभाव है। इससे सरकार और पार्टी या दल के बीच रेखा खींचना भी कठिन हो गया।

१० देखें, मेरा 'इन्ट्रडक्शन टु कंटेस्ट आफ एलेक्टोरल चेंज इन इंडिया' (नई दिल्ली - सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज १९६०)। मार्विन बीनर ने भारतीय पार्टियों का विस्तार से अध्ययन किया है, देखें - उनका 'पार्टी पोलिटिक्स इन इंडिया, डेवलपिंग ऑफ ए मल्टी पार्टी सिस्टम' (प्रिंसटन १९५७) और 'पाटी विडिंग इन एन्डोनेशिया, द इंडियन नेशनल कांग्रेस' (शिकागो १९६७), बीनर के मत की सरकार के कार्य की दृष्टि से आलोचना के लिए देखें - फ्रांसीस बार फ्रैकल, 'डेमोक्रेसी ऐंड पोलिटिकल डेवलपमेंट, पसपेक्टिव फ्रॉम द इंडिया प्रक्सपीरिएंस', वॉशिंग्टन पोलिटिक्स, ११ स ३, अग्रेष्ठ १९६९।

११ गोपाल कृष्ण, 'वन पार्टी डोमिनंस - डेवलपमेंट्स, पाटी सिस्टम एंड एलेक्शन स्टडीज, अमेरिकन पोलिटिक्स, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (नई दिल्ली-१९६७)।

(६) सत्ता और अधिकार का बल पर पार्टी या यह ढांचा टिका हुआ है। सरकारी तन्त्र से सबध रख कर ही नेतावग अपनी स्थिति बनाये रख सकता है। इसके लिए किसी दल और गुट से सबध रखना जरूरी है। जो लोग ऐसा सबध नहीं रख सके, वे प्रभावहीन हो गए, भले ही व्यक्तिगत रूप से उनका कितना ही प्रभाव रहा हो। इसी कारण पार्टी या दल का स्पष्ट वंचारिक आधार न होते हुए भी सदस्य या नेता पार्टी की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय राजनीति का केन्द्रबिंदु सरकार है इस लिए यहाँ वे ही जीवित रह सकते हैं, जो सरकारी दल में हों या सरकार विरोधी दल में।^{१२}

(७) इससे भारतीय राजनीति में बड़ी स्वतन्त्रता आ गयी है। न किफ यहाँ नए दल बनाने और दल परिवर्तन की स्वतन्त्रता है बल्कि सत्ताधारी दल के विभिन्न गुटों से विरोधी दलों का परस्पर संबंध बना रहता है। जब कोई दल बहुत दिनों तक सत्ता में बना रहता है, जैसे कि कांग्रेस, तब उसमें कई स्पष्ट गुट बन जाते हैं। ऐसा होने पर विरोधी दलों का प्रभाव बढ़ जाता है। विरोधी नेता विधान सभा के भीतर और बाहर आलाचना द्वारा, या सत्ताधारी दल के गुटों या सदस्यों पर अपने व्यक्तिगत प्रभाव के द्वारा (कई नेताओं का कांग्रेस से अलग हो जाने पर भी कांग्रेस जना पर बड़ा प्रभाव है) सरकारी नीतियाँ और निष्पक्षता का प्रभावित कर लेते हैं। १९६७ तक विरोधी दलों का बहुत कम प्रभाव था और कांग्रेस के अंदर विरोधी गुट विरोधी दलों का काम करते थे, उनमें से अनेक तो अक्सर विरोधी दलों की नीतियाँ और विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे और कांग्रेस दल के अंदर विरोधी दलों की भाषा में बात करते थे। इन गुटों के द्वारा सरकार और विरोध पक्ष में कड़ी जुड़ी रहती थी और उनमें काफी खूब कर राजनैतिक व्यवहार चलता था।^{१३}

(८) जब सरकारी दल का स्थिर और स्पष्ट बहुमत रहता है तब विरोधी पक्ष उसकी नीतियों को ज्यादा प्रभावित कर पाते हैं, वनिस्वत उन समय के जब

१२ अनक अत्यंत प्रभावशाली नेता कांग्रेस या अन्य दलों को छोड़ने के बाद अस्त हो गए। कांग्रेस ने दल छोड़ने वालों के साथ बड़ी कड़ाई का बर्ताव किया। ऐसे लोगों में चन्दाजी राज गोपालाचारी, अन्नादुरै कृष्णन्, एन बी रंगा, हरेकृष्ण महापात्र, कृष्णमेनन और टी टी कृष्ण माचारी हैं, यद्यपि कृष्णमाचारी कांग्रेस से अलग नहीं हुए। जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ने के बाद दूसरे दल स्थापित किए, उनका प्रभाव बना रहा, जैसे अन्ना सुप्री, चण्डीसिंह और गुरनाम-सिंह। पार्टी का महत्व इससे सिद्ध है कि निर्दल सदस्यों का, उनकी छोड़ कर जिनका सरकार से संबंध है, कोई राजनैतिक महत्व नहीं।

१३ दंग, मेरा 'पार्टी सिस्टम'। डब्ल्यू. एच. मारिश जेम्स ने, गवर्नमेंट ऐंड अपोजिशन १ म ४, अगस्त १९६६ में अपने निबंध 'डायमिनेस ऐंड डिस्टेंड' में यही मत प्रकट किया है। विरोध पक्ष के सुत्रे या बंद रूप के बारे में देखिए, पदबंध शिन्स का निबंध 'अपोजिशन इन द न्यू स्टेट्स ऑफ इंडिया ऐंड अफ्रीका', गवर्नमेंट ऐंड अपोजिशन, १, स २, फरवरी १९६६।

सरकारी बहुमत अस्थिर होता है। कारण जब सरकार मजबूत होती है, तो दल के भीतर विरोध को छूट दी जाती है। विरोधी दल भी इस स्थिति में लोकतन्त्रीय पद्धति से चलते हैं लेकिन जब सरकार का बहुमत बहुत थोड़ा रहता है, तब विरोधी दल की प्रवृत्ति तोड़फोड़ करके सरकार को उलटने की रहती है। अस्थिर बहुमत से सत्ताधारी दल में ज्यादा एकता और अनुशासन आने के बजाय, गुटबन्दी और फूट को प्रोत्साहन मिलता है। विरोध के ये दोनों ही रूप भारत में देखने का मिलते हैं।

(८) यहाँ केवल राजनैतिक दल का संगठन करने और चुनाव लड़ने की ही छूट नहीं है, बल्कि सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने की भी छूट है। राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों से ही इस प्रकार के विरोध, सीधी कारवाही, सत्याग्रह, अनशन आदि की परंपरा चली आई है। लोकतन्त्र के सिद्धांत से जनता के नाम पर आंदोलन करने का समर्थन किया जाता है। साधारणतः ऐसे आंदोलनों को उचित समझा जाता है और सरकार भी इन पर ध्यान देती है। इनकी उपेक्षा करना सरकार के लिए कठिन हो जाता है। १४

(१०) साधारणतः कुछ उग्रवादियों को छोड़कर सरकारी दल के अन्दर विरोध और जन आंदोलनों का उद्देश्य सरकार को उलटना नहीं बल्कि उसमें प्रवेश पाना रहता है। इसलिए उन्नत या अमीर देशों के ऐसे आंदोलनों के विपरीत यहाँ ये आंदोलन छिटपुट और असंगठित रहते हैं और तात्कालिक उद्देश्य सिद्ध होने के बाद वे खतम हो जाते हैं।

(११) विरोधी तत्वा का उद्देश्य सत्ता या व्यवस्था को उलटना नहीं, उस पर कब्जा करना है। अक्सर विरोधी दल सत्तारूढ़ दल के सिद्धांतों या लक्ष्यों का विरोध नहीं करते, बल्कि यह कहते हैं कि सत्ताधारी दल उन पर अमल नहीं करता। इसका एक कारण यह है कि विरोधी दल के नेता भी उसी बग के हैं जिसके कांग्रेस वाले हैं। उल्लेखनीय है कि १९६७ के आम चुनाव के बाद, देश के जाड़े राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकार कायम हुई, किंतु ८ में से ६ मुख्यमंत्री भूतपूर्व कांग्रेसी थे। इस तरह न केवल व्यक्तियों में, बल्कि विचारधारा और कार्यक्रम में भी कांग्रेस और विरोधी दल में कड़ी बनी रही। इस प्रकार विरोध को राजनीतिक व्यवस्था में मायता मिली।

(१२) व्यवस्था की घुरी सरकार है। पार्टियों की अधिकतर गतिविधि सरकार या शासन के जरिये चलती है। सरकारी शक्ति और साधना, खास कर विकास कार्यक्रमों के साधना के जरिए सत्ताधारी दल अपने संगठन को फैलाता है। इसलिए

१४ संसदीय लोकतन्त्र में सरकार के लिए अपनी प्रतिष्ठा के नाम पर कड़ा रख अपनाना संभव नहीं होता। देखिये, मेरा 'डाइरेक्ट ऐक्शन - ५ पैटर्न ऑफ पोलिटिकल बिहेवियर', न्वेस्ट (१९६६), नं. २४, जनवरी १९६०।

विरोधी दल भी सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। राजनैतिक व्यवस्था, अधिकांशतः सरकारी नौकरशाही और विकास की मशीनरी पर चलती है, इसलिए राजनैतिक अस्थिरता या एक दल के सत्ताच्युत होने पर भी काम चलता रहता है। राजनैतिक अस्थिरता या सरकार के पतन की स्थिति में काम चलाने के लिए संविधान में व्यवस्था है। इस के अलावा अंगरेजों के समय में जब दलतन्त्र नहीं था, प्रशासन का जो ढांचा बना था, वह राजनैतिक अस्थिरता के समय में काम करता रहता है। कांग्रेस के हाथ में जब सत्ता आई तो उसने सरकार और राजनैतिक तंत्र को समाज व राष्ट्र के विकास का मुख्य साधन बनाया। केन्द्रीय सरकार की सत्ता राष्ट्र के अस्तित्व का आधार बनी। इसलिए न सिर्फ केन्द्रीय सरकार को दब बनाया गया, बल्कि उसके अधिकार और शक्ति को बहुत बढ़ाया गया। राष्ट्रीय सरकार के प्रति निष्ठा, राजनीति का मुख्य सिद्धांत और कसौटी बन गई और सरकार तथा सरकारी दल राष्ट्र और राष्ट्रीयता के प्रतीक बन गये। सरकार के नेता छोटी के राष्ट्रीय नेता थे, इससे स्थापित व्यवस्था को जनता की निष्ठा और समर्थन मिला। बाद में जब विरोधी पक्ष का उदय हुआ तब विरोध का अर्थ सरकार का विरोध हो गया। इस प्रकार चुनाव का उद्देश्य सरकार का विरोध या समर्थन हो गया।

(१३) इसका यह अर्थ नहीं कि प्रचलित राज्यव्यवस्था का बुनियादी विरोध नहीं किया गया या इसकी बुनियाद को चुनौती नहीं दी गई। प्रत्युत भारत के अनेक प्रमुख व्यक्तियों ने भी इस व्यवस्था की उपयोगिता पर शका प्रकट की है। फिर भी इससे हम व्यवस्था के चलने में कोई गहरा व्याघात नहीं आया। लेकिन अभी इस व्यवस्था की जड़ बहुत गहरी नहीं गई है, और आर्थिक क्षेत्र में इसका कार्य सतोपजनक नहीं रहा है। इस भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है और जैसे जैसे राष्ट्रीय प्रश्न स्पष्ट होते गए हैं, इस व्यवस्था की जांचोचना भी बढ़ती गई है। खास कर शहरी बुद्धिजीवी वर्ग इसकी बहुत टीकाटिप्पणी करता है और इसके प्रति अनास्था प्रकट करता है। शहरी बुद्धिजीवी वर्ग की यह जांचोचना मौखिक विरोध तक ही सीमित है।

(१४) व्यक्ति का महत्त्व राजनीति में अभी भी बहुत है। व्यक्तिविशेष को लेकर गुट बनते हैं। एक ओर बात यह है कि एक ही संगठन के विभिन्न जग अलग अलग काम करते हैं। एक ही दल की राष्ट्रीय और राज्य शाखाएं विपरीत दिशाओं में चलती हैं और ऐसे गुटों और तत्त्वों से हाथ मिलाती हैं, जो विचारधारा और नीति में उनसे भिन्न हैं। इस प्रकार व अवसरवादिता का परिचय देती हैं। प्रदेशों या राज्यों की स्थिति और समस्याओं में भिन्नता होने के कारण एक ही दल को भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न ढंग से काम करना पड़ता है। वही दल एक जगह सरकार बनाता है और दूसरी जगह विरोधी दल के रूप में काम करता है। इससे दल

का एक निश्चित स्वरूप और नीति नहीं निखर पाती। केवल कांग्रेस ही अपने लंबे इतिहास और देशव्यापी संगठन के कारण अपनी एक तस्वीर या स्वरूप बना पाई है। कुछ और दल जो ऐसा कर सके हैं, महज प्रांतीय दल हैं, जैसे मद्रास में द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम्, पंजाब में अकाली दल और असम तथा उड़ीसा में आदिम जातियों के दल। कम्युनिस्ट दल भी जो बड़ा अनुशासित माना जाता है, बजाय एक अखिल भारतीय दल के, बंगाल और केरल के प्रांतीय दल के रूप में ही काम कर सकता है। राजनैतिक सरगर्मों बढ़ने के साथ-साथ राष्ट्रीय दला के प्रांतीकरण का प्रवृत्ति भी बढ़ी है, घटी नहीं, और स्थानीय दलों तथा व्यक्तियों का महत्त्व भी बढ़ा है।

(१५) इससे राजनीति में व्यक्तियों का महत्त्व बहुत बढ़ा है यद्यपि गांधी और नेहरू जैसे महान और चमत्कारी व्यक्तियों की परंपरा खतम हो रही है, फिर भी समय-समय पर कुछ व्यक्तियों ने राजनीति को प्रबल रूप से प्रभावित किया है, और अवतर प्रभावशाली व्यक्तित्व के हटने पर दल की हालत बिना पतवार की नाव जसी हो जाती है, जैसी डॉ॰ राममोहन सोहिया के देहांत के बाद स. सो. पा. फी हुई। यद्यपि कम्युनिस्ट दल का अनुशासन कठोर रहा है, फिर भी उसमें, पी. सी. जोशी, रणदिवे और डांगे के सत्ताच्युत होने से फूट पड़ी है। स्वतंत्र पार्टी तो शुरू से ही संगठित नहीं रही और शायद राजाजी के न रहने पर वह इस रूप में जीवित भी न रह सके। जनसंघ राष्ट्रीय रूप ग्रहण करने की काशिश कर रहा है, मगर इस फेर में, उसका वन राज्या में कम हो रहा है। कांग्रेस में भी उसके बड़े नेताओं के चले जाने के बाद टूट फूट शुरू हो गयी। १९६६ में उसमें सर्वोच्च स्तर पर खुले आम गहरी फूट पड़ गई। फिर भी जय दला की अपेक्षा अपनी स्थिति को संभालने में कांग्रेस ने ज्यादा क्षमता दिखाई है। साथ में सत्ता होने के कारण भी, कांग्रेस को आंतरिक फूट और झगडा के धक्के संभालने में मदद मिली है और संभवतः इसी कारण केरल और बंगाल में माक्सवादी कम्युनिस्ट दल भी अपने संगठन की एकता को कायम रख सका है।^{१५}

(१६) गर कांग्रेसी दला में भी काफी फूट रही है, मगर १९६७ के बाद उन्हें भी सत्ता ग्रहण का मौका मिला है और इससे उनकी शक्ति बढ़ी है। यद्यपि उनमें से अधिकांश बहुत दिना तक सत्ताछूट नहीं रह पाए, फिर भी उनका पुनः सत्ता प्राप्ति की आशा उतनी क्षीण नहीं है, जितनी सन १९६७ के पहले थी। कांग्रेस अब उतनी अजेय और अटल नहीं रही जितनी पहले समझी जाती थी। इससे दूसरे दलों में भी प्रचलित व्यवस्था के प्रति लगाव पैदा हुआ है और उनका रुख भी

१५ मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन के गायन रहने का एक कारण नवद्वीपाद और ज्योति बसु जैसे नेताओं का प्रभावशाली व्यक्तित्व भी है। इसी प्रकार अनादुर के व्यक्तित्व के कारण मद्रास में द्र. मु. क. मा. इ. ड. का संगठन और नेता की भूमिका पर इस पुस्तक के अध्याय ८ में विस्तार से विचार किया गया है।

पहले जैसा उग्र और अव्यावहारिक नहीं रहा। एक तरफ कांग्रेस की शक्ति घटने से, भारतीय राजनीति में अब उन प्रश्नों और समस्याओं पर बहस होने लगी है, जिनको अब तक टालने की कोशिश की जाती थी। इससे एक बात राजनैतिक दलों के सामने और स्पष्ट हो गई कि अब केवल सत्ता ग्रहण करने से काम न चलेगा, कुछ करके दिखाना भी होगा। इसका यह अर्थ है कि अब यह परीक्षा हो जाएगी कि वर्तमान राज्यप्रणाली चल सकती है या नहीं।

प्रणाली का विकास

अब हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद से वर्तमान प्रणाली में क्या परिवर्तन या विकास हुआ है। राजनैतिक सत्ता के लिए दलों में किस प्रकार गठजोड़ हुए हैं और इससे किस हद तक नई परंपराएँ स्थापित हुई हैं।

शुरु का अध्याय

गांधीजी की मृत्यु के बाद सत्ता नेहरू और पटेल दो आदमियों के हाथों आई। यह गठजोड़ अजीब था। इन दोनों के विचार, स्वभाव, राजनैतिक सबंध, सब बिल्कुल अलग अलग थे। नेहरू की बौद्धिकता, जनता पर गहरा प्रभाव और प्रगतिशीलता के मुकाबले पटेल की ठोस व्यावहारिकता और संगठन-कुशलता थी। यद्यपि दोनों एक-दूसरे की जरूरत और महत्त्व अनुभव करते थे और आपस में टक्कर बचाने की कोशिश करते थे, फिर भी दोनों का अंतर इतना स्पष्ट था और कांग्रेस के सामने नीति के ऐसे आवश्यक प्रश्न उपस्थित थे जिन पर निणय लेने में देर नहीं की जा सकती थी, कि इस द्वंद्व का निपटारा होना ही था। सन १९५० में कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव के प्रश्न पर नेहरू और पटेल का द्वंद्व खुल कर सामने आया, जब पटेल के उम्मेदवार पुराने खेव के कांग्रेसजन पुरुषोत्तमदास टंडन ने प्रगतिशील समर्थन देने वाले कृपालानी को हरा दिया। इसके थोड़े ही दिनों बाद पटेल की मृत्यु हो गई और केंद्रीय सरकार में नेहरू का एकछत्र अधिपत्य हो गया। कांग्रेस संगठन अर्थात् टंडनजी से नेहरूजी की टक्कर होने में देर न लगी। कृपालानी और उनके कांग्रेस डेमोक्रेटिक फ्रंट को कांग्रेस से हटना पड़ा। कांग्रेस की रीतिनीति से नेहरू असंतुष्ट थे। उनका आरोप था कि संगठन पक्ष केंद्र और राज्य सरकारों के काम में अनुचित हस्तक्षेप कर रहा है। न सिर्फ कांग्रेस सरकार के बीच में यह विरोध नेहरू को असह्य था, वे यह भी चाहते थे कि १९५२ के चुनाव में सही किस्म के आदमी चुने जाएं और विधान मंडल तथा सरकार में जाएं।

अतः नेहरू ने संगठन को हाथ में लेने का निश्चय किया। उन्होंने टंडन से यह कहा कि या तो मुझे कांग्रेस कार्यकारिणी का पुनर्गठन करने दो, वरना मेरा इस्तीफा लो। इस अल्टिमेटम के फलस्वरूप स्वयं टंडन जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद

से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष बन गए और अगले चार वर्ष तक वह सरकार और संगठन दोनों के प्रधान बने रहे।^{१६} इस बीच उनका एकछत्र प्रभाव हो गया। पहले आम चुनाव में उनके नेतृत्व में कांग्रेस की पूर्ण विजय मिली। घरेलू और विदेशी नीति के मामले महत्वपूर्ण निश्चय उन्हीं के थे। इस प्रकार उन्होंने तै कर दिया कि देश किस रास्ते पर चलेगा। इसके बाद उन्होंने दूसरा को कांग्रेस का अध्यक्ष बनने दिया, परन्तु लगाम अभी भी उनके हाथ में थी।^{१७}

कांग्रेस संगठन और कांग्रेस सरकार के बीच इस द्वंद्व को समझना जरूरी है। अधिकांश नव स्वतंत्र देशों में अधिकार प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय नेताओं में इस प्रकार का द्वंद्व उठता है। जहां इस द्वंद्व का जल्दी निपटारा कर लिया जाता है, वहां विकास का क्रम जल्दी शुरू हो जाता है। भारत में नेहरू के नेतृत्व में यह काम १९५० के बाद ही शुरू हो गया। अगले दस वर्षों तक नेहरू का प्रताप-सूय मध्याह्न पर रहा। उनके जीवन के दो उद्देश्य थे—लोकतंत्र और आर्थिक विकास, और उन्होंने सारी शक्ति से देश को इन लक्ष्यों की ओर ले जाने का यत्न किया। पिछले अध्याय में पचासवें राज आदि जिन समस्याओं का जिक्र किया गया है, उनका उद्देश्य यही था और वे इसी अवधि में विकसित की गईं।

चुनाव द्वारा जनता में प्रवेश

इन समस्याओं की स्थापना का उद्देश्य जनता में प्रवेश करना था। महत्त्व केवल कांग्रेस महासमिति के प्रतिनिधियों का न था, जो हर साल नेहरू और उनके बादियों का समर्थन कर दिया करते थे, बरन देश के जनसाधारण का था। कांग्रेस संगठन पर नेहरू के कब्जा करने के बड़े ही दिना बाद देश का पहला आम चुनाव फरवरी सन १९५२ में हुआ जिसमें प्रत्येक बालिग स्त्रीपुरुष को वोट देने का अधिकार था। ज्यादातर राजनीतिक चेतना शहरों तक ही सीमित थी और यही कांग्रेस को विरोध का सामना करना पड़ा। कोई भी निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकता था कि गांधी की अशिक्षित जनता का क्या रुख होगा और वह चुनाव की इस नई विधि में कितनी दिलचस्पी लेगी। इतने बड़े चुनाव का प्रबंध करना और सांप्रदायिक तथा कम्युनिस्ट तत्त्वों को, जो उस समय काफी सक्रिय थे, उपद्रव करने से रोकना, कोई छोटा काम न था। कांग्रेस भी हाल के आंतरिक संघर्ष से

१६ दूसरे देशों में भी इस प्रकार शक्ति का सभा स्रोतों को एक ही हाथ में लेने के प्रयत्न हुए, जैसे धाना में एन.एम. और इन्फेन्सिया में सुकार्णों द्वारा। एक शतना ही था कि नेहरू इन दोनों की तरह तानाशाह नहीं बने।

१७ यद्यपि १९५४ में नेहरू ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया, लेकिन जो भी अध्यक्ष चुने गए वे सब उन्हीं की मार्ग से चलते थे। दूसरी ओर राज्यों में उन्होंने संगठन और कांग्रेस मार्ग-मंडलों में प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा दिया।

निल चुकी थी और कहा नहीं जा सकता था कि यह एकावद्ध होकर चुनाव क
मदान में उतर सकी या नहीं। १९२ पाटिया और १७०० उम्मेदवार मैदान में प
जोर करीब १७३० लाख मतदाता १८६००० मतदान का मत में उठ हुए थे। इनक
रन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था।

चुनाव व नतीजा ने उा रागा को न्यूनित कर दिया जा वाला तनावितार की
सफलता में सहाय करत थे। १८ वाप्रेस का मत और राज्या में भारी बहुमत प्राप्त
हुआ। १९ लाखभा में ७८८ मीठा में स ३६८ अर्थात् ७८४ प्रतिशत सीटें
मिली। राज्या की विधान सभाजा की ३२८३ सीटा में स उस २२४६ अर्थात्
६८४ प्रतिशत सीटें मिली। अगले १५ वर्षों तक ३ आम चुनाव और अनेक छोटे
या मध्यावधि चुनाव म भी समाजवा रात्रे की दली प्रभार सत्तता मिली।
१९६७ के बाद भी, जब अनेक राज्या में दूसर दला की सरकार बना, वाप्रेस ही
रा का प्रधान और सबसे गतिमान दल है, जिसका प्रभाव सत्तर में है (दखिए
सारणी पाच १, २ और ३)

लेकिन यह कहना गलत होगा कि भारत म सत्ता पर रात्रे का एकाधिकार
रहा है। सन १८६७ के पहले भी यह था तही नहीं थी। दूसरा एा कारण यह
है कि कांग्रेस का विराप करने वाली पाटिया अनेक थीं और उनम स कुछ ने वाप्रेस
को अपदस्त भी किया। सारणीया स यह भी पता चलेगा कि तराजिरी पाटिया
को मिले सब वोटो को जोड़ दिया जाए तो उनकी सख्या वाप्रेस का मिले वोटो स
हमेशा अधिक रही। सीटा म भी हर राज्य म कांग्रेस का पूण बहुमत नहीं रहा।
१९५२-५३ और १९६३-६४ म दो बार बड़े बड़े समय को छोड़ कर कांग्रेस
ने अकेले सारे देश पर राज्य नहीं किया। १८५२ म उसे चार राज्या म पूण बहु
मत नहीं मिल सका। ये थे - मद्रास, प प पू, उड़ीसा और तिरुवापुर-कोचीन।
राजस्थान म उसे किसी तरह बहुमत मिल गया। मद्रास म उसकी स्थिति इसलिए
बन गई कि आंध्र प्रदेश उससे अलग हो गया। आंध्र म कम्युनिस्टा ने १८५४ के
नरवर म कांग्रेस सरकार को गिरा दिया और वहा राष्ट्रपति का शासन लागू करना
पना। ये प सू (१९५४), तिरुवापुर-कोचीन (१८५४) और आंध्र (१८५४)
म फिर से चुनाव कराने पड़े क्योंकि वहा वाप्रेस सरकार अपना बहुमत वापस न
रस सकी। ये प सू म कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल गया और आंध्र म भी उसने
कम्युनिस्टा की शक्ति तोड़ दी, किंतु तिरुवापुर-कोचीन में वह ऐसा न कर सकी
१८ द टाक्स आफ इंडिया, परवरी ६ १९५२।

१९ मद्रास, ये प सू और तिरुवापुर कोचीन म कांग्रेस की पूण बहुमत नहीं प्राप्त हो सका।
लेकिन दूसरे दलों की हालत और भी खराब थी। इसलिए अंत में इन रात्रा म भी कांग्रेस की
सरकार बन गई। केरल को छोड़ कर रोप सभी राज्या में तथा केन्द्र में १९६७ तक कांग्रेस सत्तासूद
रही। उड़ीसा में १९५७ से १९६१ तक कांग्रेस ने गणतंत्र परिषद से मिल कर सरकार बनाई और
केरल में १९६० से १९६४ तक उसका प्रभो था तथा मुस्लिम लीग से गठबांड रहा।

बाद वह अनेक पार्टियों में महज एक पार्टी रह गई। यह ठीक है कि १९६७ में कांग्रेस की प्रतिद्वंद्वी पार्टियाँ तगड़ी हो गईं पर इसके पहले भी कांग्रेस को बड़े मुकाबले का सामान करना पड़ रहा था और १९६७ के बाद भी यह भारतीय राज्यव्यवस्था में सबसे बड़ी ताकत है। दूसरे अब कांग्रेस को अपना सही 'केन्द्र' या 'मध्य' का स्थान मिल गया। यह दो अर्थों में। एक इस अर्थ में कि इसी केन्द्र से जय पार्टियाँ निकली हैं और दूसरे, इस अर्थ में कि यह दक्षिण और वामपथ के बीच या मध्य में है। भारत का यह अकेला मध्यवर्ती दल है।

तीसरे, कांग्रेस को महज सत्ताधारी या प्रधान दल के रूप में नहीं देखना चाहिए जैसा कि मारिस दुवर्जे आदि ने किया है। उसे समाजीकरण या समाज के परिवर्तन की एजेंसी और दूसरे दलों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने वाले के रूप में देखना चाहिए। इस दृष्टि से कांग्रेस के आंतरिक संघर्ष भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितना बाहर से उसके विरोधी दलों का विकास। १९६७-६९ में भारत में एक खास तरह का घ्रवीकरण हुआ। कांग्रेस बनाम गैर-कांग्रेसी दल, सरकार बनाम सरकार विरोधी दल। इस घ्रवीकरण से विरोध की शक्ति बढ़ी। दूसरी ओर अब भी सारी जिम्मेदारी कांग्रेस नेताओं पर धरी जाती है और उसे सरकार समझा जाता है, यद्यपि अनेक राज्यों में वह सरकार नहीं है। इसका एक नतीजा यह हुआ है कि सरकार से कुछ ठोस काम करने की अपेक्षा की जाती है और केन्द्र से अधिक मांग की जाती है।

१९६७ के पहले के विरोधी दल

कांग्रेस की आन्तरिक फूट से विरोधी दलों का विकास हुआ। हम देख चुके हैं कि कांग्रेस एक दल नहीं अपितु एक राष्ट्रीय मारचा थी। एक ओर इसके हाथ में सत्ता आ गई जिससे इसके हाथ में केन्द्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर बहुत साधन आ गए। दूसरी ओर इसके संगठन का विस्तार हुआ और उसके अंदर बहुत से विचित्र नेता तथा साधारण लोग भी आए। पद और अधिकार की आकांक्षा से कांग्रेस के अंदर गुटबाजी और सौदेबाजी की प्रवृत्ति बढ़ी। परिणामस्वरूप हर स्तर पर विविध प्रकार के संगठन कायम हो गए। इनमें दल के अंदर के गुट, जातिबिरादरी के संगठन प्रांतीय, क्षेत्रीय और आदिमजातीय संगठन तथा विभिन्न वर्गों और पेशों के संघ, सभी थे। ये सभी कांग्रेस तंत्र के भीतर अधिकार चाहते थे। इनकी अपनी शिकायतें और मांगें थीं। ये गुट और फिरके समाज के मुख्य हिता और वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे, तथा कांग्रेस के अंदर के गुटों और कांग्रेस के बाहर विरोधी दलों के जरिये ये संगठित हुए।

कांग्रेस के अंदर की गुटबंदी राज्य और जिला स्तर पर भी कायम रही। राज्य और जिला कांग्रेस में सरकारी और संगठन गुट बन गए। संगठन गुट सरकार के

विरोधा दल के रूप में काम करता था और कई बार सरकारी गुट का अपदस्थ भी कर देता था। १९५६ में मद्रास राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज ने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जैसे प्रमुख नेता का मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और अपनी सरकार बनाई। इसी प्रकार यू पी में चंद्रभान गुप्त, उड़ीसा में बीजू पटनायक, मैसूर में निजलिंगप्पा तथा गुजरात में मन्निमडल विरोधी गुट ने पहले सगठन पर कब्जा किया, फिर विधानसभा के बहुमत को अपनी ओर करके इन्होंने सरकारी गुट का अपदस्थ कर दिया। हर राज्य में (केरल को छोड़ कर) कांग्रेस सरकार के होते हुए भी नेतृत्व में, जिसमें मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री पद भी शामिल थे, काफी हेरफेर होता रहा (सारणी पाठ ४)। मतभेद तो नीति को लेकर होत थे, कभी यह पुरानी और नई पीढ़ी का द्वंद्व हो जाता था और कभी विचारा का, मगर यह सब राजनैतिक जोड़तोड़ और गुटबंदी का रूप ले लेता था। कांग्रेस हाईकमान बीच-बचाव करके कभी कभी अपने मन के व्यक्ति का नेता चुनवा देती थी, मगर अधिकतर यह उसीका समर्थन करता था, जिसका दल ज्यादा होता था, और महज नेता परिवर्तन की क्रिया का खूबमूरती से सपना करा देता था^{११}

नेतृत्वपरिवर्तन

कांग्रेस के सगठन पक्ष के सरकारी पक्ष पर दबाव का एक उदाहरण १९६१ में मिला जब कांग्रेस अध्यक्ष सजीव रेड्डी ने यह प्रस्ताव किया कि जो लोग लगातार १० वर्षों से मंत्री रहे हैं, वे पदत्याग कर सगठन में काम करें। इसके बाद कामराज योजना के अंतर्गत कांग्रेस के कुछ उच्चपदस्थ नेताओं को अपने पद से हटाना पड़ा। इस योजना से नेहरू को उच्चपदस्थ लोगों को खिसकाने का बहुत अच्छा मौका मिला, साथ ही इसके द्वारा यह दिखाने की कोशिश भी की गयी कि सगठन और सरकार पक्ष का दर्जा बराबर का है।

मगर इस योजना का एक नतीजा यह भी हुआ कि जब नेहरू बीमार पड़े उस समय से १९६६ तक, जब कि इंदिरा गांधी ने एक बार फिर सगठन के सरगना पर प्रधानमंत्री के पद की उच्चता स्थापित की, कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं में पद और शक्ति के लिये बड़ी गंदी लड़ाई चलती रही। इस बीच इस योजना ने सग

२२ उत्तरप्रदेश में सपूर्णानंद आर चंद्रभान गुप्त के द्वंद्व में नेहरू ने गुरु से दिलचस्पी दिखाई और कुछ समय तक सपूर्णानंद का समर्थन करते रहे परंतु अंत में उन्हें वास्तविकता स्वीकार करना पड़ी और चंद्रभान गुप्त को मुख्यमंत्री बनाने की राखी होना पड़ा। इसी तरह गुजरात के मुख्यमंत्री डा. जवाहर मेहता से गहरी सद्गुणभूति होने पर भी हाईकमान को गुजरात कांग्रेस सगठन दल द्वारा उनकी पद्धति को मानना पड़ा। देखिए, माकस फांटा 'द आगना इजेशनल डेवलपमेंट आफ इंडियन कांग्रेस पार्टी', पैसिफिक अभिप्रेत, ३५ फाल्गु, १९६२। ए. कोचा नेक, 'द कांग्रेस पार्टी आफ इंडिया - द इन्फ्लुएंस आफ वन पार्टी डेमोक्रेसी' (प्रिंटिंग, १९६८)।

ठन और सरकार को बराबरी के दर्जे पर ला दिया और नेहरू के उत्तराधिकारी के चुनाव में संगठन के नेताओं की निर्णायक भूमिका रही (इस विषय पर अध्याय ८ में विस्तार किया जाएगा)। इस प्रकार एक ही दल के सत्तारूढ़ होते हुए भी उसमें नेताओं के परिवर्तन का क्रम चालू रहा।

अन्य दल

कांग्रेस के अंदर के शक्तिसंघर्ष पर अन्य दलों का भी प्रभाव पड़ता था। जब कांग्रेस के बाहर के वामपक्ष की शक्ति बढ़ती थी तो कांग्रेस के अंदर भी वामपक्ष की ताकत बढ़ जाती थी। शुरू में जब समाजवादी दलों का प्रचार बढ़ा तब कांग्रेस में भी समाजवाद का जोर बढ़ा। बाद में जब स्वतंत्र पार्टी ने जमींदार वर्ग का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की और सहकारी खेती जैसी वामपंथी कांग्रेस नीतियों का विरोध किया तो कांग्रेस के अंदर भी दक्षिण पक्ष को दल मिला। इस प्रकार मध्यवर्ती दल कांग्रेस के अंदर के संतुलन पर बाहर के दलों का दबाव पड़ता रहा।^{२३} दूसरे, कांग्रेस के असंतुष्ट लोग दूसरे दलों में शामिल होकर, उनके जरिये सत्तारूढ़ गुट से संघर्ष करते थे और अक्सर अपने विरोधियों के पतन के बाद कांग्रेस में लौट भी जाते थे।^{२४} तीसरे, कभी कभी किसी विशेष या तात्कालिक प्रश्न का ले कर नए दल खड़े हो जाते थे, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात के अलग राज्य बनाने के प्रश्न को लेकर हुए। ये दल अस्थायी होते थे और प्रश्न के तह हो जाने के बाद इनको कांग्रेस में स्थान मिल जाता था।^{२५} इसके अलावा ऐसे लोग जिनको कांग्रेस के अंदर कोई आशा नहीं रह गई थी, लगातार उससे अलग हो कर विरोधी दलों में मिलत गए। ऐसे लोगों में जे बी कृपालानी, राजगोपालाचारी और कृष्ण मेनन उल्लेखनीय हैं। प्रमुख व्यक्तियों के अलावा गुजरात में क्षत्रिय और राजस्थान में जाट और हरियाणा में अहीर जैसे वर्ग भी कांग्रेस से अलग हुए।

१९६२ और १९६६ के बीच कांग्रेस से व्यक्तियों और समूहों के अलग होने की प्रवृत्ति जादा रही। यह समय बड़ी कठिनाई का था। इसी अवधि में चीन और पाकिस्तान से युद्ध हुए, जिससे देश का बहुत धन-जन नष्ट हुआ, नेहरू और लाल-बहादुर शास्त्री का देहांत हुआ और उनके उत्तराधिकार के मामले पर कांग्रेस के सर्वाच्च स्तर पर बड़ी खींचतान और जोड़ताड़ हुई। दो बार सूखा पड़ने के कारण

२३ कोठारा, 'द कांग्रेस सिस्टम इन इंडिया'।

२४ देखिए - असीददीन अहमद, 'कांग्रेस डिफाई इन अमोर्टल - द वेम स्ट्रेंथ इन वन पार्टी डेमोक्रेसी', पार्टी मिलियन पेंट एलेक्जंडर स्टडीज।

२५ ऐसे दल राजनीति में नया खून ल आते हैं। जिस प्रश्न को लेकर वे खड़े होते हैं उनके तह होने के बाद वे पतन हो जाते हैं, लेकिन कुछ नए आदर्शीय राजनीति में बने रहते हैं। अक्सर कांग्रेस इनको अपने अंदर खींच लेती है। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र कांग्रेस ने किया।

जनसाधारण को घोर वृष्ट, अभाव और महंगाई का सामना करना पड़ा, भारत को सहायता देने वाले देशों के दबाव के कारण रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा और कांग्रेस नेताओं का जिल्लत उठानी पड़ी। इस स्थिति में कांग्रेस नेताओं की स्थिति कमजोर हुई और उसके लिए कांग्रेस संगठन में एकता और अनुशासन बनाए रखना कठिन हो गया, फलस्वरूप कांग्रेस त्यागने वालों की संख्या बढ़ी।

१९६७

कांग्रेस दल की इस फूट के सदृश में फरवरी १९६७ का आम चुनाव हुआ। चुनाव के बाद भी कांग्रेस की फूट जारी रही। जबकि चुनाव में ५ राज्यों में कांग्रेस की हार हुई, चुनाव के बाद दलबदल की क्रिया शुरू हुई, जिसके कारण तीन राज्यों में कांग्रेस सरकार का पतन हुआ।^{१५} इस दलबदल में दो बातों का मुख्य हाथ रहा। चुनाव के पहले टिकट का बंटवारा और चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का गठन। ये कोई नए कारण न थे। नई बात सिर्फ यह थी कि १९६७ में और बाद में जितनी आसानी से लोग कांग्रेस छोड़ देते थे, उतनी पहले कभी नहीं देखी गई थी। कांग्रेस में उनको बाध कर रगने की शक्ति बहुत कम हो गई थी। अब तक चुनाव का टिकट या मंत्रिमंडल में स्थान न मिलने पर भी असंतुष्ट गुट कांग्रेस के अंदर ही बने रहते थे, अब वे कांग्रेस से अलग होने लगे।^{१६} अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ कि ये लागू स्थायी तौर पर कांग्रेस में अलग हुए हैं या स्थायी तौर पर। दोनों ही प्रवृत्तियाँ देख पड़ती हैं।^{१७}

१६ चुनाव में कांग्रेस की हार मद्रास (यहां अनेक एक दल द्र मु क की जीत हुई), बंगाल, बिहार, पंजाब और उड़ीसा में हुई। (इसमें विरोधी दलों के साक्ष्य और चा की जात हुई। इन और चा में कम्युनिस्ट मार्क्सवादियों से लेकर जनसम तक थे)। चुनाव के बाद हरियाणा, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में दलबदल के कारण कांग्रेस सरकार का पतन हुआ। हरियाणा और उत्तरप्रदेश में संयुक्त दल की सरकार भी न चल सकी और मध्यावधि चुनाव हुए। हरियाणा में कांग्रेस सरकार कायम है, किंतु उत्तरप्रदेश में पुन कांग्रेस में फूट हुई और पहले नई कांग्रेस और भारतीय क्रांतिदल और बाद में पुराना कांग्रेस, आ आ दल, जनसम, सतोषा की संयुक्त सरकार बनी।

१७ कांग्रेस दल में चुनाव टिकट बंटने के समय जो खोजबान होता है, वह कभी कभी चुनाव से भी ज्यादा महत्व की होता है। इसमें चुनाव से भी ज्यादा जनसाधारण में प्रसार का मौका मिलता है। देखिए रा राम, "सेलेक्शन आफ कॉन्ग्रेस कैंडिडेट्स - द्रुनामिक एंड पोलिटीकली, दिसम्बर, ३१, १९६६, जन ७ और १८, पर ११ और १८, १९६७। १९६७ में उम्मेदवारों के चुनाव के ऊपर राय और मारिंस मोन्स का अध्ययन अभी अप्रकाशित है।

१८ गैर कांग्रेसी संयुक्त सरकारों के गिरने के बाद अनेक भूतपूर्व कांग्रेसी कांग्रेस में या कांग्रेस से संबंधित दलों में लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्यप्रदेश में ऐसा ही हुआ। मध्य-प्रदेश में तो कांग्रेस टाड़ने वालों का पूरा गुट कांग्रेस में लौट आया और कांग्रेस की सरकार [अगले पृष्ठ पर]

फूट की प्रवृत्ति कांग्रेस में ही नहीं अग्र दत्ता में भी है। कुछ राज्या में कांग्रेस के असंतुष्ट गुट ने प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस बना लिया है। २९ इसी प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी भी दो और वही तीन तीन है। समाजवादी पार्टी भी टूट कर समोपा और प्रसोपा में बंट गई है और समापा में भी कई गुट हो गए हैं जो एक दूसरे से बग डते रहते हैं। जनसम में भी उग्र और नरम दो घंड हो गए हैं और स्वतंत्र पार्टी में तो लगातार आंतरिक झगड़े मच रहे हैं और जनक लोग दल भी छोड़ गए हैं। पिछड़े वर्ग हरिजना और जादिवासिया में भी अनेक घड़े हैं। इसके अलावा १८-१७ के बाद गैर-कांग्रेसी दत्ता में गठजोड़ होत रहे हैं। अनेक बार ये गठजोड़ बिल कुल विरोधी और विपरीत दत्ता में भी हुए हैं। य गठजोड़ मानमती के कुनवे जैस हैं। फलस्वरूप ये गैर-कांग्रेसी सयुक्त सरकारें ज्यादा दिन न चल सची और एक क बाद एक गिरती चली गई। ३०

स्वतंत्रता क बाद शक्ति ग्रहण करने क लिए कांग्रेस सभी तरह के लोगो को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती थी। सन १९६७ से १९६८ क बीच गैर-कांग्रेसी दत्ता की भी यही नीति थी। हिंदू समाज की भाति कांग्रेस भी भिन्न और विराधी विचार और रीतिरिवाज वाले समूहा को एक साथ लाने की कोशिश करती थी और विचारा की एकस्पना क बजाय विचार-बभिय को सहन करती थी। कांग्रेस शुरू से समूचे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करती आई है और भारतीय राष्ट्र क अधिकांश तत्व उसमें पाए भी जात थे। विराधी दत्ता ने देखा कि सयुक्त मोचा बना कर व कांग्रेस का हटा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस को कभी भी देश के ५४ प्र सा से अधिक वाट नहीं मिले। इस नीति के मुख्य प्रतिपादक

[पिछले पृष्ठ से]

बनाने में उसने सहायता दी। कांग्रेस छोड़ने वाल जो लोग मुख्यमन्त्री बने उनमें से अनेक का केन्द्र सरकार और कांग्रेस नेताओं से बड़ा अन्ध झगड़ा सच रहता। दूसरी ओर कांग्रेस हार्दिकमान विरोधियों को वापस लेने की बहुत इच्छा न था, क्योंकि इस्से नया गठजोड़ उलटने का डर था। २९ १९६४ में केवल कांग्रेस की स्थापना हुई और १९६६ में बंगाल में कांग्रेस बना। १९६७ के चुनाव से पूर्व उत्तर के कई राज्यों में जन कांग्रेस बना। अस्तुष्ट कांग्रेसियों ने भारतीय भाति दल बनाया और बिहार में अस्तुष्ट कांग्रेस जनो के एक दल ने विनोदानंद झा के नेतृत्व में जनतांत्रिक कांग्रेस बनाई। ३० दिसंबर १९६७ से फरवरी १९६८ के बीच हरियाणा, पश्चिम बंगाल पञ्जाब, उत्तरप्रदेश और बिहार में पंच राज्यों में सयुक्त सरकारें गिरा। बिहार में दो बार ऐसा हुआ। सयुक्त सरकार के टूटने पर बिहार और बंगाल में कांग्रेस के समर्थन से सयुक्त मोरचे के अल्पमर्याद दल ने सरकार बनाई किन्तु वह चल न सकी। पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस खुद मिली जुली सरकार में शामिल हुई। मगर पिक न सका। न यप्रदेश में मार्च १९६६ में सयुक्त दल की सरकार से कांग्रेस विद्रोहियों का गुट निर्मूल कर फिर कांग्रेस में आ गया और सयुक्त सरकार गिर गई।

ये डा राममनोहर लोहिया। लोहिया जन्मजात विद्रोही थे और उनका व्यक्तित्व चमत्कारी था। उन्होंने शीघ्र ही समझ लिया कि थाये विद्रोह से कुछ होना जाना नहीं, इसलिए उन्होंने का सत्ता पर एकाधिकार खतम करने के लिए विरोधी दला को एक साथ लाने की कोशिश की। कांग्रेस के विरोधी किसी भी तत्त्व से वह हाथ मिलाने को तयार रहते थे। कांग्रेस को उखाड़ने के तात्कालिक लक्ष्य में उन्हें सफलता मिली, किन्तु इसका कोई स्थायी नतीजा नहीं निकला। यह बात उन्हें १९६७ में अपनी मृत्यु के पहले खुद स्वीकार की थी।

दला में फूट और पुनर्गठन

१९६७ और १९६९ के बीच राजनीतिक दला ने अपने अनुभव से नए सबक सीखे और जो जाव उसको ले लेने की नीति में परिवर्तन किया। इस अवधि में दलबदल और अवसरवादिता का जो जोर रहा, उससे लोग विरक्त हुए और नए गठबंधन करते समय और नए लाया को दल में लेंते समय कुछ अधिक सावधानी बरतने लगे। १९६७ के बाद से कांग्रेस की नीति यह रही है कि पार्टी से विद्रोहियों का जाने दो और वह एक स्पष्ट नीति और विचारधारा ग्रहण करने तथा दल में अनुशासन रखने की बात करने लगी है।^{३१} इस नीति से कांग्रेस को १९६८ के हरियाणा के मध्यावधि चुनाव में अच्छी सफलता मिली। और १९६९ में उत्तर प्रदेश के मध्यावधि चुनाव में भी लाभ हुआ।

दूसरी ओर यह भी स्पष्ट हो गया कि गैर-कांग्रेसी दलों के मोर्चों में १९६७ के बाद केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट मोर्चा, मद्रास में द्र मु क का मोर्चा और उड़ीसा में स्वतंत्र जन कांग्रेस मोर्चा ही टिकाऊ रहा क्योंकि ये दल अपने क्षेत्र में ज्यादा संगठित और एकरूप थे और इनको काफी स्थानीय समयन भी मिला।^{३२}

३१ वायस ने अपना आंतरिक स्थिति को दृढ़ करने के लिए क्या प्रयत्न किए इसके लिए देख मारिस जॉन्स 'द इंडियन वायस पार्टी-ए टिलेना इन कमिनेस' माइन एशियन स्टडीज १ नं २, १९६७।

३२ केरल में नवद्वारापद और बंगाल में ज्योति बसु के नेतृत्व में मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी अपने प्रदेश में बड़ा ताकत रखनी है और अपनी अखिल भारतीय पार्टी या अ य राज्यों का मार्क्सवादी कम्यु पार्टीयों से भिन्न तरीके से काम करता है। यद्यपि इन राज्यों में वे मिलानुसार सरकार में हैं लेकिन प्रधानता उन्हीं की है। उदाहरण की स्वतंत्र पार्टी पुरानी गणतंत्र परिषद का है दूसरा रूप है। असतुष्ट कांग्रेसजन के दल उन कांग्रेस से मिल कर उसने टिकाऊ सरकार बना ली है। वास्तव में यह पुराने कांग्रेस-गणतंत्र परिषद के गठबंधन का है दूसरा रूप है जिसने १९५७ से १९६१ तक उगीसा में राज्य किया और जिसे विजयानंद पटनायक के नेतृत्व में कांग्रेस के नए गुट ने अपदस्थ किया। पुराना गुट कांग्रेस से निकल कर जन कांग्रेस बन गया और गणतंत्र परिषद राज्य की स्वतंत्र पार्टी बन गई। सबसे ज्यादा महत्व मद्रास का द्र मु क (डा एम के) है। यह एक प्रानाय आंदोलन का राजनैतिक रूप है। इसे दूसरे दल के समर्थन का जरूरत नहीं। अंगन है कि पंजाब में अयाला दल भा येमा हा स्थिति प्राप्त कर ले।

इनके मुकाबले खिचड़ी दलों और भूतपूर्व कांग्रेसियों की संयुक्त सरकारें टिकाऊ नहीं मिळी हुई। १९६९ में चार राज्यों में मध्यावधि चुनाव हुए (जिसे छाटा आम चुनाव भी कहा गया) इसमें क्षेत्रीय पार्टियाँ के मजबूत मोर्चे बंगाल और पंजाब में विजयी हुए और खिचड़ी दलों का मोर्चा बिहार और उत्तरप्रदेश में हार गया (सारणी पांच - १)

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस-विरोधी संयुक्त मोर्चे (युनाइटेड फ्रंट) का उल्लेखनीय सफलता मिली। चुनाव के पहले ही इस मोर्चे के सदस्य दलों ने आपस में बातचीत करके चुनाव समन्वित कर लिया था। इससे वोटों को एक स्पष्ट विवृत्य मिल गया। पश्चिम बंगाल में तथा अनेक अन्य राज्यों में भी, कांग्रेस को कभी बड़ा का पूरा बहुमत नहीं मिल सका था। उसके विरोधी बोट कई दलों में बंट जाय करते थे। इन बार विरोधी दलों ने तगड़ा मोर्चा बना कर कांग्रेस की कमजोरी का लाभ उठाया। ध्यान रहे कि १९६९ के मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त बोटों की संख्या में कमी नहीं हुई फिर भी उसकी सीटें बहुत कम मिलीं। इस प्रकार पश्चिम बंगाल का संयुक्त मोर्चा अन्य राज्यों के लिए भी नमूना बन गया, भव्यपि इसमें संदेह है कि और जगह ऐसा मारचा बन सकता है या नहीं।^{३३} पंजाब में अकाली दल ने अपने आपसी झगड़ों को भिन्न कर अपना तगड़ा मोर्चा बनाया। इसमें उसके पुराने प्रतिद्वंद्वी जनसंघ ने भी उसका साथ दिया। केरल में १९६७ में कम्युनिस्टों ने भी इसी प्रकार अपने आपसी झगड़ों को एक करके अपना मोर्चा बनाया था।

इस समय १९६७ की स्थिति बदल चुकी है। एक तो अधिकांश राज्यों में खिचड़ी या परस्पर विरोधी दलों के मोर्चे टूट चुके हैं। मद्रास में एक ही दल की सरकार है। उड़ीसा में स्वतंत्र और जन कांग्रेस का गठबन्ध भी गड़बड़ा रहा है। पंजाब में अकाली जनसंघ जोड़ टूट चुका है और अकाली दल में भी फूट पड़ गई है। सब से अधिक अस्थिरता मध्यप्रदेश, बिहार और उत्तरप्रदेश जैसे कांग्रेस प्रभुता वाले राज्यों में ही देख पड़ती है। समग्र है कि यहाँ कांग्रेस और भाग्यद जैसी क्षेत्रीय और जनसंघ जैसी राष्ट्रीय दलों की राज्य शाखाओं में छद्मकरण हो जाए और फिर से चुनाव होने पर स्थिति अधिक साफ हो जैसा पश्चिम बंगाल, केरल

३३ १९६९ में बंगाल में दो विरोधोत्थाप लक्षित हुईं। एक तो संयुक्त मोर्चे के विभिन्न दलों के अपने अपने अलग प्रभाव क्षेत्र बना लिए वे जिससे दलों के बीच साटा के बदवार में भासनी हुई। दूसरे, बंगाल में संयुक्त मोर्चे का विचार बहुत दिनों से चला आ रहा था और जनता में १९६० और १९६९ के बीच इसका जोर बढ़ा। इस कारण विभिन्न दलों को भी जनता की इच्छा का आदर करना पड़ा। केरल में भी यही प्रवृत्ति १९६५ और १९६७ के बीच काम कर रही थी। दूसरी ओर जहाँ विभिन्न दलों के प्रभाव क्षेत्र बड़े नहीं हैं और संयुक्त मोर्चे का विचार जनता में जोर नहीं पकड़ पाया है वहाँ संयुक्त मोर्चे की जतनी सफलता नहीं मिल सकती। बंगाल और केरल में भी संयुक्त मोर्चा अंत में टूट गया।

हरियाणा और पंजाब में १९६६ के चुनावों में हुआ। ३४ भारतीय जनता ने ज्यादा राजनीति में मग्नकारी दिखाई है और १९६६ के मध्य चुनाव में कांग्रेस तथा उत्तर-प्रदेश और बिहार में जनसंघ और संसोधन जैसे गैर कांग्रेस दलों का स्थिर सरकार बनाने का दंड दिया है।

चुनाव परिणामों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि गैर कांग्रेसी दलों के उम्मेदवार बजाय एक दूसरे के कांग्रेस के बाटों को ज्यादा काटते हैं। यद्यपि जहाँ अधिक उम्मेदवार खड़े होते हैं वहाँ कांग्रेस को फायदा होता है और उसका उम्मेदवार जीत जाता है लेकिन उसका बाटों की संख्या घिर जाती है। दूसरी ओर जहाँ कांग्रेस का दूसरे दल या संयुक्त उम्मेदवार से सीधा मुकाबला होता है, वहाँ उसके बाटों तो बढ़ जाते हैं मगर जरूरी नहीं कि उसका उम्मेदवार जीत जाए। इस प्रकार केरल में १९६६ में और बंगाल में १९६६ में जहाँ कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिलीं, वहाँ उसके बाटों कम नहीं हुए और केरल में तो बढ़ भी गए। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने अपने बाटों ३५ से ४० प्रतिशत तक कायम रखे हैं। केरल और पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों को और मद्रास में द्रमुक छोड़कर शेष गैर कांग्रेसी दलों का बाटों इतना स्थिर नहीं रहा है। इसी बात पर निम्न हागा कि अगले चुनावों में राज्यों में किस दल या दलों के जुटों की जीत होती है और टिकाऊ सरकार बनती है या नहीं।

भविष्य का रस

लेकिन यह भी स्पष्ट है कि कांग्रेस अपने स्थिर ४० प्रतिशत बाटों के बल पर हमेशा सत्ता कायम नहीं रख सकती। केन्द्र में भी इसके बल पर उसकी सत्ता सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार विरोधी दलों ने उसकी इस दुबलता का लाभ उठाकर राज्यों में उसे हराया है उसी प्रकार केन्द्र में भी वे इसे हराने का यत्न करेंगे, और विधानसभाओं के साथ-साथ संसद के चुनावों में भी साझे उम्मेदवार खड़े करेंगे। इसमें उह इस बात से सहायता मिलेगी कि विधानसभा और संसद के चुनाव साथ-साथ होते हैं। जाधे राज्यों में हारने पर भी केन्द्र में कांग्रेस की जीत हुई इसका कारण यह था कि उसकी विरोधी अधिकांश पार्टियाँ उसका मुकाबला केवल

३४ देखिए मेरा 'इंडियन पोलिटिकल ट्रांजिशन', इकॉनॉमिक पोलि० वावल विशेष अंक, अगस्त १९६७। इसमें मैंने राजनीतिक स्थिरता को दूर करने के लिए मयावि चुनाव का समर्थन किया है।

३ यह विश्लेषण ऐन हावर मिशिंगन में हुए टाटा कन्फ्रेंस सेमिनार (अप्रैल, १९६९) में हुआ था। इसके लिए आवेष्टें सेंटर फॉर स्टडी ऑफ टेक्नॉलॉजिक सोसाइटीज, दिल्ली ने प्रयत्न किए थे। मारिंस जोस और बा दासगुप्त ने भी यहाँ निष्कर्ष निकाला था। इंडियन पोलि० एरियाज इतिहास रिपोर्टें आन एन इकोनॉमिकल एलेक्टोरल इनवेस्टिगेशन' एशियन सर्वे ९ नं० ६, जून १९६९।

होगा, जितना देश में परिवर्तन लाने की उपेक्षा करना। यह काम आसान नहीं है और यदि इसमें समझदारी से काम न लिया गया और देश के इतिहास के सबक को भुला दिया गया, तो या तो देश में अस्थिरता पैदा हो जाएगी और प्रगति रुक जाएगी या ऐसा वैचारिक संघर्ष होगा, जिसमें अराजकता भव जाएगी।

इसलिए राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में देश तभी अच्छी तरह काम कर सकता है, जब देश की राजनैतिक विभिन्नता के ऊपर केन्द्र में एक सुदृढ़ शक्ति हो। फिन्हाल अगले दशक तक कांग्रेस के अलावा और कोई ऐसी केंद्रीय शक्ति नहीं नजर आती। कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती है। एक तो ऐसी नीति ग्रहण करना, जिससे उसे शहर और दहात के अब तक पिछड़े हुए, और अब 'राजनैतिक' रूप से सचेतन तथा उन्नति के इच्छुक वर्गों का समर्थन मिल सके। दूसरा काम कांग्रेस संगठन को ऐसा रूप देना है जिससे उसकी शाखाएं निर्वाचन क्षेत्रों में जनता के बीच में पहुंच जाए और चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस को सिर्फ बड़े या प्रभावशाली लोगों के भरोसे न रहना पड़े।^{३०} पहला काम केंद्रीय सरकार के नेताओं का है और दूसरा काम संगठन के नेताओं का। तात्पर्य यह है कि कांग्रेस को नीति और संगठन दोनों मोरचों पर काम करना है और इसके लिए केंद्र में एकता और एक राय जरूरी है।

यदि अगले एक दो साल के भीतर सरकार और संगठन दोनों क्षेत्रों में ठोस काम न हुआ तो कांग्रेस के लिए आसार अच्छे नहीं। पहले तो जमा ऊपर कहा, यदि गैर कांग्रेसी दला ने लोकसभा के चुनाव में भी भाग बनाया तो कांग्रेस की हालत खस्ता हो जाएगी। दूसरी संभावना यह है कि दक्षिण और वाम पक्ष के दला की स्थिति राज्यों की विधानसभा में दब हा जाएगी। वाम पक्ष में पश्चिम बंगाल और केरल में कम्युनिस्टों के मोरचे और मद्रास में द्रमुक तथा दक्षिण पन्थ में। उत्तर में जनसंघ, उड़ीसा में स्वतंत्र और पंजाब में अकाली। सन १९६७ में मजबूत केंद्र का राज्या में विपरीत विचारों के दला की खिचड़ी में मुकाबला करना था। इस से ज्यादा खतरनाक स्थिति हाथी जब केंद्र कमजोर व अस्थिर हो और राज्या में दक्षिण या वाम पक्षी मजबूत मोरचे या गठजोड़ हो। तीसरे, यदि ऐसा मुकाबला हो और राजनीति नीतिसंबंधी प्रश्ना पर केंद्रित होने लगे तो संभावना यह भी है कि कांग्रेस के भीतर भी वाम और दक्षिण पन्थ का छर्बीकरण हो जाए और फूट हो जाए। १९६६ में वाम के राष्ट्रीयकरण के ऊपर और डा० जाकिर हुसैन व दहात के बाद राष्ट्रपति के चुनाव को तो गैर कांग्रेस के अंदर जो मतभेद पैदा हुआ, उस से अब भी कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए। इस मतभेद में इंदिरा गांधी

^{३०} मद्रास में द्रमुक के चुनाव आंदोलन में हमारा परिचय मिला। द्रमुक का यह नारा था कि वाम के पास वोट दलाने वाले हैं, और हमारे पास वोट हैं। हम विषय पर दोस्ती रामाश्रय राय और चन्द्रमम, 'कम्युनिज्म ऑफ इंडिया' (संस्करण १९६० ई. सी.)।

असम की सीढ़ी पर बर रही थी, मगर की सीढ़ी पर नहीं। बाटा व विद्वान् से पना घना कि करीब ३३ प्र स मद्रासा ने मगर में एक दल का वाट दिया और राज्य विधानमभा में दूसरे दल को। लेकिन द्रमुक ने मद्रास में ताव समा की ये सब सीढ़ें जीत ली, जिन्हें लिए उगते उम्मावार गये किए ये और स्वतंत्र पार्टी को भी मोक गया व चुनावों में सफल मिली। इससे पना घना है कि मगर व चुनावों में भी बांग्रम उगी ही समझार है जिनकी विधानसभा के चुनाव में।

राष्ट्रीय क्षेत्र में बांग्रम व दल में कई बने हैं। राज्य के स्तर पर दल की जाम्बिनि है यह राष्ट्रीय स्तर पर रहा है। एक ताभिन्न भिन्न राज्या म भिन्न भिन्न स्त हैं। दूसरे, राज्या म ओक छोटे छोटे दल और निम्न उम्मावार हैं, जिन ता राष्ट्रीय स्तर पर काम करने व दृष्टान्त हैं व उन म मगर का चुनाव लड़ने को क्षमता है। दूसरे कई राज्या म क्षेत्रीय दल न अनिज भारतीय दल को पुर्नमान पचाया है। उगा हरण व लिए उगा प्रदेश में धर्मगिह के ना ता द में जनम व दूतर नवर से हटा दिया। ग गा पा ने नी बिहार और उत्तर प्रन्ध म अपने बहुत-म ध्यान रखी लिए। एक ओर कम्युनिस्ट दल ने मगाव और बरन म अपनी ध्विनि गुन्ड कर ली ता दूसरी ओर उत्तर प्रन्ध पञ्जाव और अज राजा म उनकी ताकत पट भी मद्र। दल व इस क्षेत्रीयकरण के कारण जना पुछ जिना सब बांग्रम की प्रधानता बनी रहगी। तीसरे, गैरबांग्रमी दल म आपन ग ही गहरी प्रतिद्विष्टता है, इससे भी बांग्रम को फायदा होता है। चौथे, अनेक क्षेत्रीय दल केन्द्र में बांग्रम की प्रधानता स्वीकार करने को तैयार हैं, बाते बांग्रम नी उनसे क्षेत्री म उनकी प्रधानता स्वीकार कर और राज्या में उनके गाय सहयोग करे। यह स्वाभाविक है, क्वाकि भारत की मध प्रणाली म कन्द्र के हाथ में बहुत शक्ति और साधन हैं।

फिर भी यह स्पष्टतर होता जा रहा है कि महुज ४० प्रतिशत वोटर के बल पर बांग्रम की स्थिति सुरक्षित नहीं रह सकेगी। इस म केवल सख्या का ही प्रश्न नहीं है, नीति और विचारधारा का भी है। बांग्रम धीरे धीरे शानि या पम्बिनन की पार्टी से यथास्थितिवादी पार्टी बन गई है। धीमे धीमे इसम गहर और दहात के अधिपारप्राप्त बग का जोर बढ़ता जा रहा रहा और वह प्रगतिशीलता कम होती जा रही है जा आजादी के पहले इसमें थी। जब तक इसम कुछ पुरानी जान चापस नहीं आती, इसकी पुरानी स्थिति बनी रहनी कठिन है। बांग्रम के पथ में यह बात है कि इसकी परंपरा विभिन्न वर्गों को एक साथ ले आने की और विभिन्न मता मे समन्वय की रही है और अभी भी इसका स्थान लेनेवाली दूसरी पार्टी नजर नहीं आती। मगर किसी नई क्रांतिकारी नीति या विचारधारा को अपना के साथ साथ बांग्रम को देश के विभिन्न क्षेत्रीय दल को अपने साथ ले आने का भी उपाय करना पड़ेगा। देश की एकता की उपेक्षा करना उतना ही सतरनाक

होगा, जितना दश म परिवर्तन लाने की उपस्था करना । यह काम जासान नहीं है और यदि इसमें समथदारी से काम न लिया गया और देश के इतिहास के सबक को भुला दिया गया, तो या तो देश में अस्थिरता पैदा हो जाएगी और प्रगति रुक जाएगी या ऐसा वैचारिक सधप होगा, जिससे अराजकता मच जाएगी ।

इमलिए राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रा म देश तभी अच्छी तरह काम कर सकता ह, जब देश की राजनैतिक बिभिन्नता के ऊपर केन्द्र म एक सुदृढ शक्ति हो । फिनहाल अगले दशक तक कांग्रेस के अलावा और कोई ऐसी केन्द्रीय शक्ति नहीं नजर आती । कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती ह । एक तो ऐसी नीति ग्रहण करना, जिससे उसे शहर और दहात के अब तक पिछडे हुए, और अब राजनैतिक रूप से सचेतन तथा उन्नति के इच्छुक वर्गों का समथन मिल सके । दूसरा काम कांग्रेस सगठन को ऐसा रूप देना ह, जिससे उसकी शाखाएं निर्वाचन क्षेत्रों में जनता के बीच में पहुंच जाए और चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस को सिर्फ बडे या प्रभावशाली लोगों के भरोसे न रहना पडे । ³⁶ पहला काम केन्द्रीय सरकार के नेताओं का ह और दूसरा काम सगठन के नेताओं का । तत्परय यह है कि कांग्रेस की नीति और सगठन दोनों मोरचा पर काम करना ह और इसके लिए केंद्र में एकता और एक राय जरूरी है ।

यदि अगले एक वा साल के भीतर सरकार और सगठन दोनों क्षेत्रा में ठोस काम न हुआ तो कांग्रेस के लिए आसार अच्छे नहीं । पहले तो जसा ऊपर कहा, यदि गैर कांग्रेसी दला ने लोकसभा के चुनाव में भी भागा बनाया तो कांग्रेस की हालत खस्ता हो जाएगी । दूसरी सभावना यह ह कि दक्षिण और वाम पक्ष के दला की म्थिति राज्या की विधानसभा में दब हो जाएगी । वाम पक्ष म पश्चिम बंगाल और केरल में कम्युनिस्टों के मोरच और मद्रास म द्रमुक तथा दक्षिण पक्ष में । उत्तर में जनसध, उड़ीसा में स्वतंत्र और पंजाब में अकाली । सन १९६७ में मजबूत केंद्र का राज्या में विपरीत विचारा के दलों की म्थिचडी से मुकाबला करना था । इस से ज्यादा खतरनाक स्थिति होगी जब केंद्र कमजोर व अस्थिर हो और राज्या में दक्षिण या वाम पक्षी मजबूत मोरचे या गठजोड हो । तीसरे, यदि ऐसा मुकाबला हा और राजनीति नीतिसबधी प्रश्नों पर केन्द्रित होने लगे तो सभावना यह भी ह कि कांग्रेस के भीतर भी वाम और दक्षिण पक्ष का छेदीकरण हा जाए और फूट हो जाए । १९६६ में वका के राष्ट्रीयकरण के ऊपर और डा० जाकिर हुसैन व देहात के बाद राष्ट्रपति के चुनाव को ले कर कांग्रेस के अंदर जो मतभेद पैदा हुआ उस से जत म कांग्रेस के दो टुकडे हो गए । इस मतभेद म इंदिरा गांधी

^{३६} मद्रास में द्रमुक व चुनाव आंदोलन में दसना परिणय मिला । द्रमुक का यह नारा था कि वाम-पक्ष के पाम वोट इकट्ठे करने हैं और हमारे पास वोट हैं । इस विषय पर दोहिप रामा राय और चण्दास, 'कैम्पूट आफ एलेक्गोरल चेंज' (सेंगर फार स्टडी डेव सो) ।

ये नेतृत्व में 'यंग तुन' हैं, जो चाहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ें, और दूसरा यह उन लोगों का है, जो कांग्रेस संगठन की शक्ति को कायम रखना चाहते हैं। ये लोग इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि अब तक उपेक्षित और अधिनायकित वर्गों में राजनीति जागृत हो रही है। चुनाव के रूप को देखने में पता चलता है कि इस उपेक्षित वर्ग का — जिस में नव गिनिश और छोटे किसान तथा खेत मजदूरों का बाहुल्य है — समर्थन कांग्रेस के विजय दूर तक की मिल रहा है। ३० कांग्रेस के सामने यह प्रश्न है कि वह कम अपना मध्य में कुछ काम पथ की ओर रुख कायम करें।

यदि कांग्रेस उन वर्गों में नहीं प्रवेश कर पायी, जो अब तक उसमें अलग रहे हैं, तो क्या होगा? ऐसा लगता है कि भविष्य में राज्या ही नहीं केन्द्र में भी मिनीजुली सरकार बनेगी। हो सकता है कि कुछ राज्या में एक ही दल की, या एक दल के प्रभुत्व में संयुक्त सरकारें रहें और केन्द्र में मिनीजुली सरकार बने। इसमें भी संदेह नहीं कि केन्द्र की मिनीजुली सरकार में अभी कुछ जिनका सब प्रधान भागीदार कांग्रेस ही रहेगी क्योंकि अब तक अभी इतना सावधानीपूर्ण रुख नहीं ग्रहण कर पाए हैं कि मजदूरों में अधिक सदस्य भेज सकें। यह भी संभव है कि राज्या में ये अधिक सदस्य भेज सकें। यह भी संभव है कि राज्या में जो साक्षी सरकार बनें उनमें प्रधान भागीदार कांग्रेस से भिन्न कोई दल हो, जैसे बंगाल और केरल में माकन० कम्युनिस्ट, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में जनसंघ और पंजाब उड़ीसा, मद्रास में बहा के प्रांतीय दल। या दल में सबसे बड़ा दल कांग्रेस ही रहने की संभावना है, बने ही वह सभी स्तरों पर सरकार बन सकें। यदि वह पुनः अपने संगठन में एकता स्थापित कर सकी और अपनी गति प्राप्त कर सकी तो उस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी।

सविद सरकारों का दौर

जल्द ही नहीं कि सविद या संयुक्त सरकारें एक दल की सरकारों से कम कारगर और सोहेन्द्र्य हों। केरल की साक्षी सरकार आंध्र की एकदली सरकार से, उड़ीसा की आसाम में या पंजाब की हरियाणा से कम कारगर नहीं रही। बहुत कुछ सरकार में शामिल गुटों या तत्त्वों पर निर्भर होता है। आखिर कांग्रेस में भी अनेक गुटों का ही मेल हुआ था, और ये गुटों का गठन कांग्रेस से अपना सीधा

३० चार चुनावों में जलमर्त्या के वर्गों और क्षेत्रों के विस्तार में तथा सेंटर पर स्टैन ऑफ डेवलपिंग सोमास्ट्रीन द्वारा १९६६ और १९७७ में क्षेत्रों की पट्टाल से पता चलता है कि जहां कांग्रेस के समर्थकों का अनुपात स्थिर रहा है और १९६७ में कुछ गिरा है, वहां अन्य दलों के समर्थकों की संख्या बढ़ी है और इनमें अधिकांश उपेक्षित वर्गों के लोग हैं। मई १९६७ की पट्टाल के कुछ आंकड़े हमें यह बात में दिए हैं। किंतु विस्तृत आंकड़े बाद में प्रकाशित होंगे।

पटाया करने थे। प्रतिद्विष्टता के जमाव और लगातार सत्तारूढ़ होने से सरकार में लागायी भागा के प्रति उन्मुखता की प्रवृत्ति आ जाती है। और जब दूसरे दल स मुखावना रहता है और चुनाव महारने का डर रहता है तो सरकार ज्यादा सावधान होती है और लागा की धान पर अधिक ध्यान देती है। भारत में जहां सरकार और सरकारी साधन का इतना महत्व है आर जाता की बुनियादी जम्-रता का पूरा करने के लिए बहुत कुछ करना है, विभिन्न समुक्त सरकारें निष्प्रिय हो कर रही बँट सकती।

इसलिए हो सकता है कि एक बार जब समुक्त सरकार की पद्धति स्थापित हो जाए, और विभिन्न दल का उसमें काम करने का अनुभव हा जाए तो सरकारें विदेशी नमूनों की नकल करने के बजाय दल की जाना की गरूरता को समझने और उन्हें पूरा करने पर अधिक ध्यान देने लगे, और ठोस काम करने लगे। यह स्वीकार करना होगा कि जब सरकार में नेहरू की तृती वालनी थी, उस समय से अब सरकार अधि सचेत हो गई है और गरूरत के अनुमार नीति बनाने और ठोस काम करने पर ज्यादा ध्यान देने लगी है। गुरु में सानी या मिलीजुनी सर-कारें भले ही ठीक से काम न कर पाए, पर धीरे धीरे जैसे मिल कर काम करने की परंपरा स्थापित होने लगेगी, ये सरकारें जनता के ज्यादा सपन में रहगी और ज्यादा काम करने को बाध्य होगी। इस बिता में इस मत का प्रतिपादन किया गया है कि बालिग मताधिकार की प्रणाली और फलस्वरूप राजनैतिक अधिकारों में जनता के ज्यादा भाग लेने और सत्ता के विवेकीकरण में सरकार की नीतिया अधिक समायवादी और जनता की इच्छा के गरूरतों के अनुकूल बनेंगी। १९६७ और १९६९ के चुनाव इसी दिशा में बढम हैं।

सरकार ही केन्द्रबिंदु

ऊपर बताया गया है कि भारत में राजनैतिक दल की बढती हुई विभिन्नता में एकता की बिंदु सरकार है। सरकार को ले कर ही सारी राजनीति घूमती है। विरोध का अर्थ सरकार का विरोध है, चाहे वह दल के भीतर हो या बाहर, चाहे सरकारी दल कांग्रेस हो या अन्य पार्टी। विरोध का यह रूप काफी पहले से रहा है। सन १९५४ से १९६७ तक कांग्रेस अंदर विरोधी गुटा का लक्ष्य सर-भारी या सत्तारूढ़ गुट था। केरल में १९५९ में कम्युनिस्ट-विरोधी आंदोलन कम्युनिस्ट सरकार के विरुद्ध था। १९६७ के बाद सरकार-विरोधी आंदोलन कांग्रेस के ही नहीं, गंद कांग्रेस सरकारों के विरुद्ध भी रहा है। जैसे १९६८ में केरल के म्युनिमिल चुनाव में विरोध का लक्ष्य कम्युनिस्ट दल की समुक्त सर-कार थी, और उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में मध्यावधि चुनाव में जनसंघ तथा

के नेतृत्व में 'यंग तुक' है, जो चाहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में कांग्रेस जागे बढ़े, और दूसरा पक्ष उन लोगों का है, जो कांग्रेस संगठन की शक्ति का कायम रखना चाहते हैं। ये लोग इस बात की अपेक्षा कर रहे हैं कि अब तक उपेक्षित और अधिकारवंचित वर्गों में राजनैतिक जाग्रति हो रही है। चुनाव के रख को देखने से पता चलता है कि इस उपेक्षित वर्ग का — जिस में नव गिणित और छोटे किसानों तथा रेत मजदूरों का बाहुल्य है — समर्थन कांग्रेस के वज्राय हमारे दल को मिल रहा है। ३० कांग्रेस के सामने यह प्रश्न है कि वह कैसे अपना मध्य से कुछ वाम पक्ष की ओर रुख कायम रखें।

यदि कांग्रेस उन वर्गों में नहीं प्रवेश कर पायी, जो अब तक उससे अलग रहे हैं, तो क्या होगा? ऐसा लगता है कि भविष्य में राज्यों ही नहीं केन्द्र में भी मिलीजुली सरकार बनेनी। हो सकता है कि कुछ राज्यों में एक ही दल की, या एक दल के प्रभुत्व में संयुक्त सरकारें रहे और केन्द्र में मिलीजुली सरकार बने। इसमें भी संदेह नहीं कि केन्द्र की मिलीजुली सरकार में अभी कुछ दिना तक प्रधान भागीदार कांग्रेस ही रहेगी, क्योंकि अन्य दल अभी इतना सावदशिक रूप नहीं ग्रहण कर पाए हैं कि संसद में वे अधिक सदस्य भेज सकें। यह भी संभव है कि राज्यों में वे अधिक सदस्य भेज सकें। यह भी संभव है कि राज्यों में जो साक्षी सरकारें बनें उनमें प्रधान भागीदार कांग्रेस से भिन्न कोई दल हो, जैसे बंगाल और केरल में माक्स० कम्युनिस्ट, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में जनसंघ और पंजाब उड़ीसा, मद्रास में वहाँ के प्रांतीय दल। जो देश में सबसे बड़ा दल कांग्रेस ही रहने की संभावना है, भले ही वह सभी स्तरों पर सरकार न बना सके। यदि वह पुनः अपने संगठन में एकता स्थापित कर सकी और अपनी गति प्राप्त कर सकी तो उस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी।

सविद सरकारों का दौर

जल्द ही नहीं कि सविद या संयुक्त सरकारें एक दल की सरकारों से कम बार गर और सोद्देश्य हो। केरल की साक्षी सरकार आंध्र की एकदली सरकार से, उड़ीसा की आसाम से या पंजाब की हरियाणा से कम कारगर नहीं रही। बहुत कुछ सरकार में शामिल गुटा या तत्त्वों पर निर्भर होता है। आखिर कांग्रेस में भी अनेक गुटा का ही मेल हुआ था और ये गुटा व वग वरावर कांग्रेस से अपना सीना

१७ बार चुनावों में उनसंख्या के वर्गों और वोटों के विक्षेपण से तथा सेंटर पर स्थानीय आफ डेवलपिंग सोमाइजील द्वारा १९६६ और १९६७ में वोटों की प्रत्यास से पता चलता है कि जहां कांग्रेस के समर्थकों का अनुपात स्थिर रहा है और १९६७ में कुछ गिरा है, वहां अन्य दलों के समर्थकों की संख्या बढ़ी है और इनमें अधिकांश उपेक्षित वर्गों के लोग हैं। सन १९६७ की पड़ताल के कुछ आंकड़े हम मायाय में दिए हैं। किंतु विस्तृत आंकड़े बाद में प्रकाशित होंगे।

पड़ाया करत थे। प्रतिद्वंद्विता के अभाव और लगातार सत्ताम्य होने से सरकार में लोगों की भागी के प्रति उदासीनता की प्रवृत्ति आ जाती है। और जब दूसरे दला से मुकाबला रहता है और चुनाव में हारने का डर रहता है तो सरकार ज्यादा सावधान होती है और लोग की बात पर अधिक ध्यान देती है। भारत में जहाँ सरकार और सरकारी साधना का इतना महत्व है और जनता की बुनियादी जरूरतों का पूरा करने के लिए बहुत कुछ करना है, विभिन्न संयुक्त सरकारें निष्पन्न हो कर नहीं बठ सकती।

इसलिए हो सकता है कि एक बार जब संयुक्त सरकार की पद्धति स्थापित हो जाए, और विभिन्न दलों को उसमें काम करने का अनुभव हा जाए, तो सरकारें विदेशी नमूना की नकल करने के बजाय देश की जनता की जरूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने पर अधिक ध्यान देने लगे, और ठोस काम करेंगे। यह स्वीकार करना होगा कि जब सरकार में नेहरू की तूती बोलती थी, उस समय से अब सरकार अधिक सचेत हो गई है और जरूरत के अनुसार नीति बदलने और ठोस काम करने पर ज्यादा ध्यान देने लगी है। शुरू में साधी या मिलीजुली सरकारें भले ही ठीक से काम न कर पाए, पर धीरे धीरे जैसे मिल कर काम करने की पद्धति स्थापित होने लगेगी, ये सरकारें जनता के ज्यादा संपर्क में रहेंगी और ज्यादा काम करने को बाध्य होंगी। इस विताव में इस मत का प्रतिपादन किया गया है कि बालिंग मताधिकार की प्रणाली और फलस्वरूप राजनैतिक अधिकारों में जनता के ज्यादा भाग लेने और सत्ता के विकेंद्रीकरण से सरकार की नीतियां अधिक यथायवादी और जनता की इच्छा व जरूरतों के अनुकूल बनेंगी। १९६७ और १९६९ के चुनाव इसी दिशा में बंदम हैं।

भरकार हो के द्रविड

ऊपर बताया गया है कि भारत में राजनितिक दल की बढ़ती हुई विभिन्नता में एकता की विंदु सरकार है। सरकार को ले कर ही सारी राजनीति घूमती है। विरोध का अर्थ सरकार का विरोध है, चाहे वह दल के भीतर हो या बाहर, चाहे सरकारी दल कांग्रेस हो या अन्य पार्टी। विरोध का यह दृष्टिकोण पक्ष में रहा है। सन १९५४ से १९६७ तक कांग्रेस अंदर विरोधी दलों का अन्तर्गतकारी या सत्तारूढ़ गुट था। केरल में १९५६ में कम्युनिस्ट-मिश्रित अश्विन कम्युनिस्ट सरकार के विरुद्ध था। १९६७ के बाद कांग्रेस के अंदर अश्विन कांग्रेस के ही नहीं, गैर कांग्रेस सरकार के विरुद्ध भी है। सन १९६८ में केरल के म्युनिसिपल चुनाव में विरोध का अर्थ कम्युनिस्ट दल की नुक़्त सरकार थी, और उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में मजदूर-कृषक दल की नुक़्त सरकार थी, और उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में मजदूर-कृषक दल की नुक़्त सरकार थी।

विहार में ससोपा और उसके साथी दल थे। १९६७ के बाद कांग्रेस और अन्य दलों के प्रति प्रबुद्ध वग का जो रुख बनता या बदलता रहा और चुनावों में इनको जा सफलता या विफलता मिली, [उनमें इस बात का बहुत हाय था कि इन दलों की सरकार के प्रति जनता का क्या रुख रहा। यद्यपि अभी पक्की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, फिर भी आसार यही है कि अगले चुनाव में वोटरो का रुख सरकार के काम से निर्धारित होगा। सरकार ने कैसा काम किया है विभिन्न दलों ने मिलीजुनी सरकार में कसा व्यवहार किया है, किन दलों पर भरोसा किया जा सकता है कि वे टिकाऊ साथी सरकार बना पाएँगे और किस दल की जनता में कहा तक पहुँच है, इन बातों पर भविष्य में चुनाव का परिणाम बहुत निर्भर होगा। इस बीच कांग्रेस केन्द्र में सत्ताह्व है और देश की सबसे बड़ी तथा ताकतवर राष्ट्रीय पार्टी है और राज्या की राजनीति को प्रभावित करने के उसके हाथ में बहुत सारे ज़रिये हैं। जब राज्य में कोई साथी सरकार टूट जाती है तो केन्द्रीय कांग्रेस के नेता राष्ट्रपति-शासन राज्यपाल और संसद के ज़रिये राज्य में हस्तक्षेप करते हैं। इसने अनेक राज्या की गैरकांग्रेस सरकार के साथ बहुत अच्छे संबंध रखे हैं, कभी कभी राज्या की कांग्रेस सरकार से भी अधिक अच्छे।

समयव्यवस्था में शिरकत

दला का प्रांतीयकरण का एक प्रभाव यह हुआ कि देश के शासन में अब कांग्रेस के अलावा अन्य दलों का भी भाग लेने का मौना मिला और इस प्रकार सघ-प्रणाली के वे भी जग बन गए। प्रायः प्रत्येक प्रमुख दल की सरकार कही न कही है। हमने देखा है कि जब कांग्रेस भी सव जगह सत्ताह्व थी, तब भी उसकी जातरिक गुटबंदी के ज़रिये बाहरी अन्य दल उसकी नीतियों को प्रभावित कर पाते थे और इस हद तक राज्य तथा केन्द्र की सत्ता की राजनीति से वे विलकुल कटे नहीं थे। फिर भी पराजित रूप से प्रभाव डालना एक बात है और सत्ता में भाग लेना, चाहे साक्षीदार क रूप में ही, और बात है। पहली स्थिति में मजबूरी का भाव रहता है जबकि दूसरी स्थिति में अधिकार का। सत्ताग्रहण से सरकार की समस्याओं

३८ कुछ राज्यों में कांग्रेस ने पुनः शक्ति प्राप्त की। इसका कारण मतदानार्थों का वर्तमान सरकार से अनौपचारिक और सरकारी दलों में घूट रहा। कम्युनिस्टों के गढ़ केरल में १९६८ के स्थानीय चुनावों में कांग्रेस की बड़ी सफलता मिली। उत्तरप्रदेश और गुजरात तथा राजस्थान में जयपुर की महाराजों के क्षेत्र में उपचुनाव में प्रतिष्ठा की रक्षा में कांग्रेस की सफलता मिली। १९६९ के मध्यावधि चुनाव में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का स्थिति में गुआर ड्यूआ और उसकी सरकार बन गई, उसके मुख्य प्रतिद्वंद्वी जनमत की पार्टी नुस्मान हुआ। बिहार में कांग्रेस की सीटें और नाम हो गईं कि उनमें विरोधी दल उड़ी तरह से कटे हुए थे, इसलिए उसने सरकार बना ली लेकिन वह बंगाल और पंजाब में हमारी उड़ी तरह हार हुई यद्यपि हमकी बोट सरया में कभी नहीं आई।

और कठिनाइयाँ की जानकारी होती है। इससे जिम्मेदारी जोर यथावत्वादिना बजती है और लगातार अल्पमत में रहने के कारण जो विरोध की प्रवृत्ति आ जाती है, वह दूर हो जाती है।

दूसरे, विभिन्न दल द्वारा सरकार बनाने से समझौते और एक दूसरे के मत का आदर करने की प्रवृत्ति पैदा होती है। १९६७ के बाद एक उल्लेखनीय बात यह हुई कि केन्द्र तथा राज्य की गैरकांग्रेसी सरकारों में समझौते की भावना बढ़ी है और वे शासन की सामान्य समस्याओं को मिल कर सुलझाने की कोशिश करने लगे हैं। १९६७ में राज्या में कांग्रेस और गैर-कांग्रेस सरकारों की स्थापना के बाद ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चार गृहमंत्री श्री चव्हाण आदि न गैर कांग्रेसी मुख्य मंत्रियों से ऐसे सन्ध स्थापित किए जिससे शासन के मामले में दोनों में सहयोग हो सके। वास्तव में गैर कांग्रेसी मुख्य मंत्रियों से बरतना केन्द्रीय कांग्रेस सरकार के लिए ज्यादा आसान सिद्ध हुआ, बजाय कांग्रेसी मुख्य मंत्रियों के जो कांग्रेस दल और राष्ट्रीय सरकार के मामलों में भी दखल देने की कोशिश करते थे क्योंकि वे अपने को महज मुख्यमंत्री नहीं कांग्रेस के अगिल भारतीय नेता भी मानते थे। श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री चव्हाण को मद्रास के श्री अन्नदुराई, उड़ीसा के आर. एन. मिहदेव, उत्तरप्रदेश के चरणसिंह और पंजाब के गुरनार्त सिंह जैसे गैर-कांग्रेसी मुख्य मंत्रियों का विश्वास प्राप्त करने में सफलता मिली। यहाँ तक कि अक्सर वे मुख्यमंत्री अपनी कठिनाइयाँ में और अपने सान्नीदारों से मतभेद पैदा होने पर इनसे सलाह लेते थे। इससे उनके दल वाले और उनके कांग्रेस प्रनिष्ठों को सकोच होता था। जो लोग यह समझते थे कि राज्या में भिन्न दलों की सरकारों के बनने से दल या पार्टियाँ प्रणाली टूट जाएगी, उन्होंने एक ही कांग्रेस और प्रतिपक्षी दलों के नेताओं के पुराने सवधों का नुला दिया और इस बात की भी उपस्था कर दी कि भारत की दल-प्रणाली में हतनी परिवर्तनशीलता है कि वह नए नेताओं और नए दलों को भी अपने अंदर स्थान दे सकें।

यही नहीं कि विपक्षी दलों के नेता और कांग्रेस के नेता पटन राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस में साथ काम कर चुके थे, बल्कि विपक्षी दल की सरकारों का नीति और कार्यक्रम भी—स्वतंत्र और कम्युनिस्ट जैसे भिन्न दलों के भी— कांग्रेस सरकार से ज्यादा भिन्न नहीं थे। इन सरकारों ने भी अपनी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तरह बीच की नीति अपनाई। यही नहीं इनमें कुछ ने—मद्रास में द्रमुक और केरल में कम्युनिस्ट— यह दावा किया कि वे उही नीतियों पर चल रही हैं जो कांग्रेस की हैं, मगर जिनको कांग्रेस पूरा नहीं कर सकी। ३९ इन संयुक्त सरकारों

३९ कांग्रेस व श्री श्री सुमन्यम की इस आलोचना का भी द्रमुक सरकार की कोई अपनी भाँति नहीं है और वह कांग्रेस की ही नीतियों पर चल रही है श्री अन्नादुरे ने यह जवाब दिया

[अगले पृष्ठ पर] ।

का आधार एक न्यूनतम कार्यक्रम था, जो उस न्यूनतम कार्यक्रम से भिन्न न था, जिस पर कांग्रेस के दक्षिण और वाम पक्ष सहमत हुए थे। इन गैर-कांग्रेसी दलों की राजनीति और दूसरे दलों से जोड़तोड़ का तरीका भी वही था जो कांग्रेस वालों का था। नतीजा यह हुआ कि जब साझी सरकार के टूटने पर कांग्रेस वापस आई तो उसे स्थिति और सरकारी कामकाज का तरीका वैसे ही मिला, जैसा उस समय था, जब वह अपदस्थ हुई थी।

लेकिन कांग्रेस और भिन्न दलों की यह सहमति नेहरू या लालबहादूर शास्त्री के समय से बहुत भिन्न है। नेहरू के समय कांग्रेस के अंदर ही विरोधी विचारधाराओं का समन्वय हुआ था। लालबहादुर शास्त्री कोई बड़ा फैसला करते समय विरोधी दलों से सलाह करते थे। अब इंदिरा गांधी के समय न केवल विभिन्न दलों की राज्य सरकारों, राज्य कांग्रेस के नेताओं और काफी सशक्त सदन से ही मशविरा किया जाता है, बल्कि ऊंचे और अनुभवी सरकारी अधिकारियों की राय भी बहुत ध्यान रखती है। ४० अब राजनैतिक तंत्र के ये विभिन्न अंग राजकाज में ज्यादा प्रत्यक्ष भाग लेते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।

सहमत नीतियाँ

सबस्वीकाय कार्यक्रम और नीतियों की खोज अभी भी जारी है। हमने देखा है कि यद्यपि कांग्रेस का झुकाव कुछ वाम पक्ष की ओर रहा है ४१ फिर भी समय समय पर दक्षिण और वाम दोनों पक्षों का प्रभाव घटता बढ़ता रहा है। इस पर एक

[पिछले पृष्ठ से]

४१ काग्रम को चाहिए कि वह द्रमुक को धन्यवाद दे कि वह उसकी नाति को प्रायाचित कर रहा है। (हिंदू वीक्ली रिव्यू जुलाई ११ १९६८) केरल के माक्स मुरयमत्रा नवदरीपाद का भी यही दावा था। ध्यान रहे कि १९६७ के चुनाव की नमूने की पटताल में जब लोगों से पूछा गया कि विभिन्न दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में क्या अंतर है तब ६५ में ३ ने इसका उत्तर दिया और इनमें से ४१ में ३ ने कहा कि कोई अंतर नहीं है।

४० देखें, अध्याय ८।

४१ जोत और शहरी संपत्ति की अधिग्रहण सहायता योजना और गुप्त निवेशन की नीति पर जनसाधारण और विविध लोगों की राय लेने से इस बात की पुष्टि होती है।

४२ प्रथम लोकसभा के ६० से ८० प्रतिशत सदस्य और स्वतंत्र पार्टी को छोड़ कर देश के समस्त इन नातियों के पक्ष में थे। सदन सदस्यों के मत के बारे में देखिए - गुरिंदर मूरी, 'पेसिंग फेस आफ लोकसभा' लिख (नई दिल्ली, अगस्त, १५, १९६१) और अलबर्ट एम. बट्टिल, 'द इन्डियन परमेयान आफ द सिनो इन्डियन वोटिंग ब्लाक - ऐन इनक्वायरी इनटु पोलिटिकल साइकोलॉजी' (प्रिन्सटन १९६३)। जनमत के बारे में देखें - 'इंडि हिस्ट्री आफ पब्लिक ओपीनियन' मधुसूदन पब्लिक ओपीनियन सर्वे (नई दिल्ली, जन १९६४)। इस सरघान द्वारा जनमत की पटताल के विवरण के लिए देखें - सेमुअल जे. हार्टमैकेन्ट, डेवॉपिंग पैटर्न आफ पार्टी प्रेफरेंसेस - मधुसूदन पब्लिक ओपीनियन सर्वे (जन १९६४)।

तो राष्ट्रीय स्तर पर जिन दलों का जोर बढ़ा है वे दोनों कम्युनिस्ट पार्टियाँ हैं, दूसरे बहुत से राष्ट्रीय प्रश्नों पर क्षेत्रीय दलों ने कोई निश्चित रुख नहीं ग्रहण किया है। इससे कांग्रेस की नई पीढ़ी के वामपक्षी झुकाव को बल मिला है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो संभव है कि देश में कुछ प्रश्नों पर एक निश्चित नीति को सहमति मिल जाए।

इस सिलसिले में दो बातें ध्यान योग्य हैं। एक तो दक्षिण पश्चिमी दल कोई स्पष्ट दक्षिणपक्षी विचारधारा या नीति पर जोर नहीं दे रहे हैं। जनसब ऐसा दल भी घमनिरेपेक्ष और राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण करना चाहता है और उसने अनेक प्रश्नों पर, जैसे गोरक्षा और भाषा पर अपना पहले का कटु रुख नरम कर दिया है। साथ ही स्वतंत्र दल का जोर भी राजस्थान, बिहार, गुजरात आदि में गिर रहा है, और उड़ीसा में स्वतंत्र दल की सरकार अनेक प्रश्नों पर केन्द्रीय नीतियों के समीप है। दूसरे, भारत जैसे देश में जहाँ विकास के लिए सरकार को इतना काम करना है वामपक्षी नीतियों के बिना काम नहीं चल सकता।

इस वामपक्षी झुकाव में बड़ा हाथ राज्यों और प्रदेशों के दलों और जनता के स्थानीय मुद्दों तथा निंदल या स्वतंत्र विधायकों और सदन सदस्यों का रहा है। जैसे जैसे राजनैतिक व्यवस्था का जनता में प्रवेश और विस्तार होता है अब तक उपेक्षित वर्ग राजनीति में आते हैं। मद्रास में द्रमुक, पंजाब में अकाली, उत्तरप्रदेश में भा० का० द०, उड़ीसा में पुरानी गणतंत्र परिषद और केरल तथा पंजाब में कम्युनिस्टों के क्षेत्रीय दल, सभी काफी मजबूत और टिकाऊ सरकार बनाने में समर्थ हैं, और भारत के दल-तंत्र में उनके अधिक भाग लेने की संभावना है। यद्यपि अभी कुछ दिनों तक केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनी रहने की पूरी संभावना है, किंतु राज्यों में भिन्न दलों की सरकार होने के कारण भारत की संघीय व्यवस्था में अकेले कांग्रेस का ही नहीं सभी दलों का भाग हो गया है और इस प्रकार उसे सभी दलों की स्वीकृति मिल गई है।

राजनैतिक व्यवस्था के स्वरूप की ठीक परख

इस प्रकार जो बहुदली व्यवस्था विकसित हो रही है उसमें केन्द्र को या कांग्रेस को राज्यों में भिन्न दलों की सरकार के साथ बराबर व्यवहार करना चाहिए, अभी इसकी परिपाटी या नियम नहीं बन पाए हैं। संघीय व्यवस्था अथवा केन्द्र-राज्य संबंध को ठीक ढंग से बनाए रखना आसान नहीं सिद्ध हुआ। केन्द्र का राज्यों से व्यवहार भी हमेशा उचित और यावपूर्ण नहीं रहा। अबसर इसने राज्य के बगड़े में अपने दल या गुट का पक्ष लिया है। सन १९५६ में केरल में कम्युनिस्ट सरकार की बर्खास्तगी और केन्द्र का शासन लागू करने में और १९५७ में बंगाल में राजनैतिक संकट के समय गर कम्युनिस्ट दलों का समर्थन करने में केन्द्रिय सरकार

का आधार एक 'यूनितम' कार्यक्रम था, जो उस 'यूनितम' कार्यक्रम जिस पर कांग्रेस के दक्षिण और वाम पक्ष सहमत हुए थे। इन की राजनीति और दूसरे दलों से जोड़तोड़ का तरीका भी वालो का था। नतीजा यह हुआ कि जब साथी सरकार ने टूट आई तो उसे स्थिति और सरकारी कामकाज का तरीका उस समय था, जब वह अपदस्थ हुई थी।

लेकिन कांग्रेस और भिन्न दलों की यह सहमति नेहरू या समय से बहुत भिन्न है। नेहरू के समय कांग्रेस के अंदर ही का समन्वय हुआ था। लालबहादुर शास्त्री कोई बड़ा फैसला से सलाह करते थे। अब इंदिरा गांधी के समय न राज्य सरकारों, राज्य कांग्रेस के नेताओं और काफी सारा किया जाता है, बल्कि ऊँचे और अनुभवशील सरकारी अधिकारियों रखती है। ४० अब राजनैतिक तंत्र के ये विभिन्न प्रत्यक्ष भाग लेते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते

समयन और विरोध

भारत की राजनीति कांग्रेस के इदगिद घूमती रही है। कांग्रेस की प्रधानता का कारण उसके हाथ में सरकार की शक्ति होना तथा उसका प्रभावशाली नेतृत्व रहा है। इसके साथ ही उसके संगठन की जनता में भी पहुँच रही है। इस प्रकार सरकार की शक्ति और जनता में पहुँच दोनों उसकी प्रधानता की जड़ में हैं। राजनीति में भाग लेने के इच्छुक मुख्यतः कांग्रेस में ही प्रवेश करते थे। अय दलों का प्रभाव तो अभी ही पड़ना शुरू हुआ है। १९६७ के चुनाव के दौरान किये गये एक राष्ट्रीय अध्ययन से यह पता चला कि ७० प्रतिशत लोग किसी न किसी राजनीतिक दल को पसंद करते थे (और ३४ प्र० श० निदल या स्वतंत्र उम्मेदवारों के पक्ष में थे।) और इनमें से ४३१ प्र० श० कांग्रेस के पक्ष में थे, बाकी अय दलों के। (देखिए सारणी ५-६।)

यदि यह भी मान लिया जाए कि सत्तारूढ़ दल के पक्ष में कुछ लोग ने या ही नाम लिखा दिए होंगे और कांग्रेस-समयक प्रतिशत में कुछ कमी कर दी जाए और भिन्न दलों के समयका की संख्या कुछ बढ़ा भी दी जाए, तब भी इस पड़ताल से कांग्रेस ही सबसे परिचित और समर्थित पार्टी सिद्ध होगी है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार की पड़ताल से वास्तविक मतदान काफी भिन्न होता है, क्योंकि मतदान पर बहुत-सी बातों का प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर यह भी ध्यान रहे कि २६७ उत्तरदाताओं ने या तो किसी पार्टी के पक्ष में राय नहीं दी, या इस प्रश्नका उत्तर नहीं दिया जबकि चुनाव में वोट न देने वाला की संख्या ३८ प्र० श० थी। वोट न देने वाले भी बहुत-से लोग किसी पार्टी की ओर होते हैं। मजे की बात यह है कि केवल ११८ प्र० श० लोगों ने बताया कि उन्होंने वोट नहीं दिया। लोग यह कहने से हिचकते हैं कि हमने वोट नहीं दिया।^{४५} यह भी उल्लेखनीय है कि पड़ताल करने वाले ने स्वयं किसी दल का नाम नहीं लिखा था, उत्तरदाताओं ने ही बताया कि वे अमुक दल के पक्ष में हैं। इससे यह पता चला कि लोगों को विभिन्न दलों के बारे में काफी जानकारी थी और सबसे ज्यादा उत्तरदाता कांग्रेस के पक्ष में थे।

भगर कांग्रेस के समयन के साथ साथ उससे असंतोष भी अधिक है। शासक दल की हैसियत से कांग्रेस के काम की काफी आलोचना की गई और इस कारण लोगों ने इसके विरोध में वोट दिए। उपर्युक्त पड़ताल में कांग्रेस के विरुद्ध जो शिकायतें

^{४५} यह पड़ताल सेंटर फार स्टडी आफ डेव सोसल की ओर से की गई थी। हमें देश भर के ४७ समूहों के और ९४ विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र चुने गए और उनमें २२८७ व्यक्तियों से प्रश्न किए गए (ऊपर जो विवरण दिया गया वह सब पुरुषों के उत्तर हैं। स्त्रियों के उत्तरों का विवेक्षण अभी नहीं हुआ।) हम पड़ताल का विवरण हो रहा है। इसके निष्कर्षों का प्रकाशन शीघ्र होनेवाला है।

के नेताओं पर पक्षपात का आरोप किया गया है। कांग्रेस के नेता अभी इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाए हैं कि उन्होंने दस में सदस्यीय या प्रतिनिधि शासन की जो व्यवस्था स्थापित की है वह तभी सत्र की स्वीकृति या सवेगी और जड़ जमा सवेगी जब सभी दलों को सरकार में भाग लेने का मौका मिले। इसी से गैरवापसी दलों का भरोसा होगा कि वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में उनका साथ भी चला होगा और उन्हें भी सत्ता ग्रहण करने का पूरा मौका मिलेगा।

दूसरी ओर मन १८६७ के बाद से कांग्रेस की सर्वोच्च या केन्द्रीय नेता मञ्ची में जो फूट दिखाई पड़ी है, उससे केरल और पश्चिम बंगाल के कम्युनिस्टों की हिम्मत बढ़ी है और वे के द्र से मुकाबला करने और वर्तमान व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने में लगे हैं। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में प्रवेश पाने और उसे जनता की आकांक्षाओं के अधिक अनुकूल तथा क्रांतिकारी बनाने की बात करने में कोई बुराई नहीं। मगर यह कहना कि इस व्यवस्था को उलट करके या ध्वस्त करके ही जनता का भला किया जा सकता है, खतरनाक बात है और इस खतरे का बचाव, इसे अधिक प्रतिनिधि और सबसे अधिक बनाने से अर्थात् इसमें सभी दलों को मौका देने से किया जाना चाहिए।

लक्ष्य करने की बात यह है कि भारत में एक दल की प्रधानता का स्थान अनेक दलों की स्पर्धा या प्रधानता के लिए स्थापित हो रही है।^{४२} इसका एक रूप सच के क्षेत्र में देखने का मिलता है जहाँ के द्र में कांग्रेस की प्रधानता है और राज्यों में भिन्न दलों के जुटा की। दूसरा रूप है राज्य बनाम राज्य। अर्थात् एक ओर महाराष्ट्र, आंध्र आदि में कांग्रेस की सत्ता है और दूसरे राज्यों में कम्युनिस्ट या द्रमुक (मद्रास) या अकाली (पंजाब) प्रधान है।^{४३} तीसरा रूप निर्वाचन क्षेत्रों में देखने का मिलता है। अब ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कम होनी जा रही है जहाँ एक पार्टी वाली सब दलों से मजबूत पड़ती है। फिर भी अभी औसत निर्वाचन क्षेत्र में एक दल की प्रधानता बनी है, अर्थात् जहाँ सफल उम्मेदवार को करीब ४५ प्रतिशत वोट मिलने हैं और दूसरे नंबर को उससे १२ से १६ प्रतिशत कम।^{४४}

४२ सन १९६७ में राजनीति में जो सहसा परिवर्तन दिखाई पड़ा वह पत्र-पत्र से १९६२ में ही आरंभ हो गया था, यह बात वोटों के विवेचन से पता चलता है। सन १९६२ के चुनाव के महेश्वर के बारे में देखिए—मेरे 'इंडियन पोलिटिकल टेक आफ' और 'द टेक आफ प्लेगमन', द इकनामिक वाक्की वार्षिक अंक परवरा १९६२ और विशेषांक जुलै १९६२।

४३ बंगाल आदि में १३१ कम्युनिस्ट दलों की गत हुई है, उन्हें अनेक छोटे दलों से सम्मिलित करने पड़े हैं। इनमें छोटे दलों को भा जीवित रहने का मौका मिला है। कांग्रेस की सफलता में भी यही बात है। कांग्रेस का एक भा उम्मेदवार दूर अनेक वर्गों या गुणों को स्थान देने में है। यही भी प्रधान गुण है चारों ओर अनेक छोटे छोटे गुण बने रहते हैं।

४४ पाटल मैक दोनों का निबन्ध दलों के बारे में (युनिवर्सल आफ मिशनर डिस्टेंशन १९६०)।

समयन और विरोध

भारत की राजनीति कांग्रेस के इदगिद घूमती रही है। कांग्रेस की प्रधानता का कारण उसके हाथ में सरकार की शक्ति होना तथा उसका प्रभावशाली नेतृत्व रहा है। इसके साथ ही उसके संगठन की जनता में भी पहुँच रही है। इस प्रकार सरकार की शक्ति और जनता में पहुँच दोनों उसकी प्रधानता की जड़ में हैं। राजनीति में भाग लेने के इच्छुक मुख्यतः कांग्रेस में ही प्रवेश करते थे। जय दलों का प्रभाव तो अभी ही पड़ना शुरू हुआ है। १९६७ के चुनाव के दौरान किये गये एक राष्ट्रीय अध्ययन से यह पता चला कि ७० प्रतिशत लोग किसी न किसी राजनीतिक दल को पसंद करते थे (और ३४ प्र० श० निरदल या स्वतंत्र उम्मेदवारों के पक्ष में थे।) और इनमें से ४३१ प्र० श० कांग्रेस के पक्ष में थे, बाकी अन्य दलों के। (देखिए सारणी ५-६।)

यदि यह भी मान लिया जाए कि सत्तारूढ़ दल के पक्ष में कुछ लोगों ने यो ही नाम लिखा दिए होंगे और कांग्रेस-समयक प्रतिशत में कुछ कमी कर दी जाए और भिन्न दलों के समयका की सख्या कुछ बढ़ा भी दी जाए तब भी इस पड़ताल से कांग्रेस ही सबसे परिचिन और समर्थित पार्टी सिद्ध होगी है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार की पड़ताल से वास्तविक मतदान काफी भिन्न होता है, क्योंकि मतदान पर बहुत-सी बातों का प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर यह भी ध्यान रहे कि १९७७ उत्तरदाताओं ने या तो किसी पार्टी के पक्ष में राय नहीं दी, या इस प्रश्नका उत्तर नहीं दिया जबकि चुनाव में वोट न देने वालों की सख्या ३८ प्र० श० थी। वोट न देने वाले भी बहुत-से लोग किसी पार्टी की आर होते हैं। मजे की बात यह है कि केवल ११८ प्र० श० लोगों ने बताया कि उन्होंने वोट नहीं दिया। लोग यह कहने से हिचकते हैं कि हमने वोट नहीं दिया।^{४५} यह भी उल्लेखनीय है कि पड़ताल करने वाले ने स्वयं किसी दल का नाम नहीं लिया था, उत्तरदाताओं ने ही बताया कि वे अमुक दल के पक्ष में हैं। इससे यह पता चला कि लोगों को विभिन्न दलों के बारे में काफी जानकारी थी और सबसे ज्यादा उत्तरदाता कांग्रेस के पक्ष में थे।

मगर कांग्रेस के समयन के साथ-साथ उससे असंतोष भी अधिक है। शासक दल को हैसियत से कांग्रेस के काम की काफी आलोचना की गई और इस कारण लोगों ने इसके विरोध में वाट दिए। उपयुक्त पड़ताल में कांग्रेस के विरुद्ध जो शिकायतें

^{४५} यह पड़ताल सेंटर फार स्टडी ऑफ डेव सोसा की ओर से की गई थी। इसमें देश भर के ४७ समूहों के और ९४ विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र चुने गए और उनमें २२८७ व्यक्तियों से प्रश्न किए गए (ऊपर जो विवरण दिया गया वह सन पुरुषों के उत्तर हैं, स्त्रियों के उत्तरों का विश्लेषण अभी नहीं हुआ।) इन पड़ताल का विवरण हो रहा है। इसके निष्कर्षों का प्रकाशन आगे होनेवाला है।

है उनका उल्लेख करके पूछा गया कि आप उनसे सहमत हैं या नहीं ? उल्लेखनीय है कि ७० स ६० प्र० श० उत्तरदाताओं ने इस पर अपनी राय दी और अधिकार ने कांग्रेस के काम को असतोषजनक बताया । (सारणी पाच-७) ।

मगर फिर याद रहे कि इस विषय में पड़ताल के नतीजा पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता और कांग्रेस से इतना असतोष होने पर भी १९६७ के चुनाव में उसको प्राप्त वोटों में कोई खास कमी नहीं हुई । फिर भी यह बात महत्व की है कि उत्तरदाताओं ने कांग्रेस के काम के बारे में निश्चित राय दी और उसके विरुद्ध शिकायतों में सही या गलत होने के बारे में काफी समझबूझ कर उत्तर दिये । शासक दल के रूप में कांग्रेस के काफी समर्थन के साथ साथ उसके काम से इतना असतोष भी होने से पता चलता है कि जनता की दृष्टि में सरकार और दल का कितना घना संबंध है ।

यह भी उल्लेखनीय है कि शिक्षा की इतनी कमी हाते हुए और चुनाव तथा पार्टी राजनीति का अधिक ज्ञान का अनुभव न होत हुए भी, ६० प्र० श० से अधिक जनता को पार्टियों और उनकी रीति नीति के बारे में जानकारी है । फिर भी याद रखना चाहिए कि पार्टी, सरकार और राष्ट्र के प्रतीक अभी जनता के मन में बहुत गहराई से नहीं प्रतिष्ठित हो सके हैं । अभी राजनीति में जनता की अधिक दिलचस्पी नहीं हुई है और राष्ट्र, सरकार या दल को जनता स्थानीय नेताओं या अधिकारियों के ही माध्यम से जानती है ।^{४६} अधिकांश जनता अपने रोज के धंधे से ही मतलब रखती है और उसका लगाव अपने परिवार और बिरादरी से है, दल या सरकार से नहीं । इस अध्याय में और इससे पहले के अध्याय में राजनीति, सरकार और दल तथा जनता में उसके प्रवेश के बारे में जो कहा गया है, उसे राजनैतिक विकास के इस सीमित सदर्भ में ही समझना चाहिए ।^{४७} परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि इस सीमा के भीतर दल और सरकार दोनों परिवर्तन और विकास के शक्तिशाली माध्यम के रूप में सामने आ रहे हैं, और उनके जरिये जनता राजनैतिक व्यवस्था तथा सरकारी कार्यों में दिलचस्पी ले रही है तथा चुनाव में सरकार के काम से अपना असतोष भी जाहिर करने लगी है ।

दल का सामाजिक गठन

इन दलों के नेता और पदाधिकारी लोगों की सामाजिक स्थिति क्या है और

^{४६} उपर्युक्त पड़ताल में केवल १७ ८ प्र० श० उत्तरदाता अपने राज्य के मुखमंत्रियों का सही नाम बता सके । लेकिन २४ १ प्र० श० ने मुखमंत्रियों के दल का नाम ठीक बताया । इसमें पता चलता है कि जनता स्थानीय नेताओं को ज्यादा जानती है । राज्य या केंद्र के नेताओं की तरफ बहुत धुंधली है ।

^{४७} अध्याय ८ में राजनैतिक व्यवस्था के नए बमाने के विषय में विचार किया गया है ।

समाज के किस वर्ग या वर्गों से उनकी समझ मिलता है ? पहले हम दल के नेताओं और जनता के प्रतिनिधियों की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करेंगे फिर उनके समझ की ।

समस्त सदस्य

अभी हाल में समस्त सदस्यों की सामाजिक स्थिति का एक अध्ययन किया गया है जिससे पता चलता है कि उनमें कमीला की संख्या घट रही है और उनका स्थान कृषक और जमींदार वर्ग के लोग ले रहे हैं^{४८} । पहली लोकसभा में कमीला की संख्या ३५ प्र० ६० दूसरी लोकसभा में ३० प्र० १० तीसरी में २४५ थी और चौथी में १७५ प्र० ६० है । इसके मुकाबले कृषक की संख्या २२४ प्र० ६०, २८१ प्र० ६०, २७४ प्र० ६० और ३११ प्र० १० रही । कृषक वर्ग में बड़े जमींदारों व सरदारों से लेकर छोटे जमींदार व किसान सभी हैं, लेकिन वे उस शहरी पेशेवर वर्ग के मुकाबले, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन का भी नेतृत्व किया था और स्वतंत्रता के बाद सरकार का भी, देहाती जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

कांग्रेस के अंदर बहुत से वर्गों और पेशों के लोग हैं, जबकि अन्य दलों का आधार इतना व्यापक नहीं है, और इसीलिए उसमें भिन्नता भी कम है जैसे (सारणी पांच-८) । स्वतंत्र दल और दोना कम्युनिस्ट दल में । स्वतंत्र दल में एक जोर बड़े जमींदार और भूतपूज राजा हैं, तो दूसरी ओर व्यापारी और रिटायर्ड ऊंचे सरकारी अधिकारी । स्वतंत्र दल में बड़े जमींदार और भूमिपति का जमघट है जबकि मध्यम वर्ग के किसान कांग्रेस, जनसंघ, द्रमुक और दोना समाजवादी पार्टियों में अधिक हैं । इसी तरह यद्यपि जनसंघ और द्रमुक दोना में व्यवसायी और उद्योग के लोग हैं, जो अधिकतर दूबानदार हैं, किंतु स्वतंत्र पार्टी में बड़े व्यवसायी और उद्योगपति हैं ।^{४९} दूसरी ओर कम्युनिस्ट पार्टियों में अधिकांश ट्रेड यूनियन और पेशेवर राजनीतिक तथा पत्रकार आदि हैं ।

जनसंघ और द्रमुक की शुरुआत शहरी और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों से हुई, किंतु धीरे धीरे ये भूमिधारी या कृषक तथा अन्य वर्गों में भी फैले । सुरुआत से देखने से पता चलता है कि अधिकांश राज्यों में जहां इसका प्रभाव है जनसंघ मुख्यतः शहरी पार्टी है, किंतु उत्तरप्रदेश में इसने गांवों में भी प्रवेश किया है और कांग्रेस को धक्का दिया है । जनसंघ के आधे समयक उत्तरप्रदेश के हैं और वहां उसका आधार काफी व्यापक हुआ है । इसी तरह द्रमुक की शुरुआत मद्रास के नगरों से हुई, पर इसने बाद में देहाती इलाकों में भी कांग्रेस को अपदस्थ कर दिया

^{४८} रत्ना दत्त, 'द पार्टी रिप्रेजेंटेटिव इन फोथ लोकसभा,' इक एंड पोलि वाकली ४, संख्या १ व २, जन १९६६ ।

^{४९} वही ।

और राज्य भर में फैल गई। जनसंघ और द्रमुक की विचारधाराएं विपरीत हैं, परंतु दोनों की शक्ति का स्रोत भाषा और प्रदेश की भावना है और दोनों के समर्थक मध्यम और निम्न मध्यवर्ग के लोग हैं।^{१५०}

ससोपा और प्रसोपा दोनों ही पुरानी समाजवादी पार्टियाँ से निकले हैं किंतु दोनों की विचारधारा और सामाजिक आधार भिन्न है। प्र. सो. पा. ने मूल समाजवादी पार्टियों की लोकतांत्रिक समाजवाद और कट्टर धर्मनिरपेक्षता की परिपाटी को बनाये रखा। इसके अधिकतर कार्यकर्ता ट्रेड यूनियन वाले, वकील (अभी भी इसमें सबसे बड़ा वर्ग यही है) और पत्रकार हैं और यह महाराष्ट्र, मैसूर, उत्तरप्रदेश तथा आसाम के कुछ देहाती क्षेत्रों में काम करता है। दूसरी ओर डा. राममनोहर खोहिया के नेतृत्व में ससोपा ने अधिक आतिकारी कार्यक्रम अपनाया और जनता में प्रवेश किया। देहाती इलाकों में इसने पिछड़ी जातियों का पक्ष लिया और शहरों में इसने भाषा जैसे प्रश्नों को उठा कर राष्ट्रीय स्वाभिमान को नई दिशा दी। नतीजा यह है कि जबकि प्र. सो. पा. में अनेक वर्गों के लोग हैं और उनका सामाजिक आधार अधिक विस्तृत है, स. सो. पा. में समाजवादी कार्यकर्ताओं और छोटे व मध्यम श्रेणी के किसानों का बाहुल्य है। वहन-सी बानों में इसका और जनसंघ का रख मिलता है और दोनों का प्रभाव भी एक ही इलाकों में है।

भारत की संसद में बहुत से निंदल सदस्य भी हैं। इनके बारे में भ्रातृ धारणा है कि ये सब रईस और धनवान वर्ग के हैं। वस्तुतः यह बात नहीं है। इनमें स. जो. भूमि वाले हैं वे रईस या राजा वर्ग के हैं, परंतु ७० प्र. श. लोग अथर्व विविध वर्गों से आए हैं।

युव अनुभव

संसद के सदस्यों के बारे में देखने की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद में आने के पहले राजनीति में उनका क्या अनुभव रहा है। सारणी पांच ६ में चौथी लोकसभा के सदस्यों के बारे में ऐसी सूचना दी गई है।

इससे पता चलता है कि केवल २६३ प्र. श. सदस्य ऐसे हैं, जिनको पहले किसी भी स्तर पर विधानसभा का कोई अनुभव नहीं रहा। नए या अनुभवहीन सदस्यों की संख्या कांग्रेस में कम और अन्य पार्टियों में ज्यादा है। कांग्रेस में केवल १५६ नए सदस्य थे जबकि प्रसोपा में ३०८ प्र. श. और द्रमुक में ३३३ प्र. श. ससोपा में ४२१ प्र. श., माक्स कम्यु. दल में ४५ प्र. श., कम्युनिस्ट पार्टी में ४७४ प्र. श., जनसंघ में ४८४ और स्वतंत्र पार्टियों में ६४३ प्र. श.।

दूसरी ओर दोनों कम्युनिस्ट दलों और दोनों सोशलिस्ट दलों के सदस्यों का स्वयंसेवक ट्रेड यूनियनों से ज्यादा रहा। कांग्रेस के केवल २२२ प्र. श. सदस्य मजदूर

सभा से संचालित थे। परन्तु सहकारी आंदोलन में कांग्रेस के प्रतिनिधियों का अधिक योग रहा है, यद्यपि सिवा महात्माजी जैसे कुछ इलाकों को छोड़ कर शेष भारत में यह आंदोलन कमजोर है। यद्यपि स्वतंत्र दल के कुछ सदस्य सहकारी समितियों से संचालित रह चुके हैं और जनसंघ के कुछ सदस्य गांव और जिले की राजनीति में भाग लेते रहे हैं, फिर भी सब मिला कर इन दोनों दक्षिण पंथी दलों के सदस्यों का राजनैतिक अनुभव कम रहा है। इसके मुकाबले कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट समूहों का राजनैतिक अनुभव अधिक रहा है। सासकर कम्युनिस्ट और समाजवादी सदस्यों का राज्य स्तर पर राजनीति का काफी अनुभव है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दल के ४० प्र० श० सदस्यों को राज्य स्तर का राजनैतिक अनुभव था। साधारण तौर पर समझा जा सकता है कि वामपंथी दलों में नए आंदोलनों की सराया अधिक हानी चाहिए थी, परन्तु चूंकि ये दल काफी दिनों से सक्रिय रहे हैं और इनमें राजनैतिक अध्ययन और मंडान में काम करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है, इसलिए इनके सदस्यों का काफी राजनैतिक अनुभव रहा है।

दलों के अनुपात

यह संचालित है कि नए राष्ट्रा में राजनैतिक नेता और विचारक साधारण जनता से कई श्रेणी ऊंचे वर्गों से आते हैं। नेताओं और प्रतिनिधियों की सामाजिक स्थिति के साथ ही यह देखना भी जरूरी है कि उनके दलों में समाज के किन वर्गों का प्रतिनिधित्व हुआ है और निर्वाचन क्षेत्रों में उनको कितना और किस प्रकार का समय प्राप्त है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस का स्वरूप अविल भारतीय है और करीब ४० प्र० श० मतदाता हमेशा इसके साथ रहे हैं। अथवा दलों की शक्ति प्रदेश या क्षेत्र विशेष में है। इसलिए विभिन्न दलों के समयका के आकड़ों पर विचार करते समय कांग्रेस से भिन्न दलों के क्षेत्रीय स्वरूप को ध्यान में रखना चाहिए।

सारणी पांच-१०-११ में यह बताया गया है कि विभिन्न दलों को किन पेशों से कितना समय प्राप्त है। कांग्रेस के सावदेशिक रूप को देखते हुए, इसमें आश्चर्य नहीं कि उसे सभी पेशों का समय प्राप्त है। व्यवसायिक भी कांग्रेस को ४० प्र० श० के करीब वोट मिले हैं। परन्तु सफेद पोश घघा में, और खासकर बेरोजगार वर्ग में कांग्रेस कमजोर दिख पड़ी है। परन्तु खेतियार तथा कुशल और अनुशासित मजदूर वर्गों में यह सब से ज्यादा मजबूत है।

सारणी पांच-११ से पता चलता है कि सफेदपोश तथा अथवा शहरी वर्गों में जनसंघ का काफी जोर है और गांव वालों में भी, खासकर भस्वामी किसानों में भी इसका बल बढ़ा है। मगर शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार के श्रमिकों में यह बहुत कमजोर है। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट दलों का श्रमिकों में ज्यादा जोर है

और गहरी श्रमजीवी वर्गों में दक्षिण के मुकाबले वामपंथी कम्युनिस्टों का प्रभाव ज्यादा है। दक्षिण कम्युनिस्टों का मुख्य प्रभाव विमानों और गेहूं मजदूरों में है। द्र० मु० व० का भी यही हाल है।

संसोध गरीबों और पिछड़े हुए लोगों की पार्टी जान पड़ती है। इसके ४४ प्र० श० से अधिक समय तक खेत-मजदूर, अकुशल शहरी मजदूर और बेरोजगार लोग हैं। यह इस दल की प्रातिनिधी विचारधारा के अनुरूप है और इसके इस दल से सत्ती सरकार में इसके साथी दल को काफी परेशानी हुई है।

इन सारणियों में यह भी पता चलता है कि स्वतन्त्र पार्टी का सामाजिक आधार बहुत सरीण है। इसका उत से अधिक समय तक भूस्वामी वर्ग में मिला है और याडा खेत मजदूरों से। इन खेत मजदूरों ने अपने मालिकों के प्रभाव में आ कर स्वतन्त्र दल को बोट दिये हंगे, ऐसा माना जा सकता है। प्रायः सभी दल का देहान से बोट मिते हैं पर स्वतन्त्र और जनसंघ के समय तक मुख्यतः अमीर विमान हैं जबकि वामपंथी दल ने समय तक छोटे या गरीब किसानों और भूमिहीन वर्ग। जनसंघ अपने प्रभाव का विस्तार साधारण लोगों में कर रहा है, जनरल स्वतन्त्र का प्रभाव अभी भी वर्ग विशेष में सीमित है। इसका एक नतीजा यह हुआ है कि इसके राष्ट्रीय नेताओं - ममानी या रंगा - तथा इसके विधायकों में सबध अच्छे नहीं हैं।

निदल सदस्या का भी जनेक वर्गों से समय तक प्राप्त हुआ है पर स्वतन्त्रपक्षा लोगो से कम छोटे दल को भी शहरों से ही अधिकतर समय तक मिला है, क्योंकि गांवों से बोट लेने के लिए काफी अच्छे संगठन की जरूरत हानी है। अविकान छोटे दल किसी तात्कालिक या अस्थायी प्रश्न को लेकर खड़े होते हैं और उनका प्रभाव टिकाऊ नहीं होता फिर भी सत्र मिलकर के दूसरे दल से काफी बोट खींच ले जाते हैं।

दलों की विचारधारा

ऊपर के विश्लेषण से विभिन्न दलों के रूप और विचारधारा का मोटे तौर पर पता चलता है। यह नहीं है कि एक कृषिप्रधान देश में दक्षिण, वाम और मध्य शब्दों का उतना महत्व नहीं जितना उद्योगप्रधान देश में। इसका प्रमाण यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऐसे वाम दल को अधिक समय तक भूस्वामी किसानों से मिला और स० सो० पा० जैसे प्रातिनिधी दल का भाषा के प्रश्न पर जो रुक है, वह दक्षिण पंथी दल से मिलता है। द्र० मु० व० की शुरुआत प्रातीयवादी और उत्तर विरोधी दल के रूप में हुई थी किंतु इसने अनेक मामलों में समाजवादी नीति का अपनाया है। इसके अलावा जरा हम पहले कह चुके हैं इन दलों के स्थानीय और राज्य सरकारों में भाग लेने के कारण सरकारी कार्यक्रम और नीतियों के मामले पर

सत्ताधारी कांग्रेस दल से इनका मतैक्य भी हुआ है। फिर भी अपने समयको और नेताओं की सामाजिक स्थिति की भिन्नता के अनुसार इन दलों में स्पष्ट भेद दिखाई देता है।

ऊपर के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अपनी विचारधारा और समयका की सामाजिक स्थिति, दोनों के अनुसार स्वतंत्र पार्टी दक्षिणपथी पार्टी है। यह आर्थिक नीति में निजी या गैरसरकारी उद्योग का समर्थन करती है, पश्चिमी लोकतंत्री शक्तियाँ से घनिष्ठ संबंध रखना चाहती है और उदार या लिबरल राजनीति के पक्ष में है। इसका समर्थन बहुत ही छोटे वर्ग, भूस्वामी और उद्योगपतियों में है। जनसघ हिंदुआ और शहर के छोटे दूकानदारों और व्यापारियों का दल माना जाता है और इस रूप में दक्षिणपथी है, किंतु यह अखिल भारतीय दल बनना चाहता है और इसलिए यह दक्षिण के राज्यों में और उत्तर में मुसलमानों में भी प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है तथा उत्तरप्रदेश के गाँवों में इसे काफी समर्थन भी प्राप्त हुआ है। ऐसा लगता है कि जागे चलकर जनसघ कांग्रेस के मुकाबले अधिक दक्षिण नहीं होगा और इसका कार्यक्रम भी उससे अधिक भिन्न न होगा तथा अनेक राज्यों में यह कांग्रेस का स्थान लेने में सक्षम हो सकेगा। इसी प्रकार द्रमुक, अकाली दल और अन्य ऐसे प्रादेशिक दलों की भी दक्षिण वाम की परिभाषा में फिट करना कठिन होगा। फिर भी यह महत्व की बात है कि गैर कांग्रेसी दलों में सबसे अधिक सफलता दोनों कम्युनिस्ट दलों को ही प्राप्त हुई है। उन्होंने श्रमिक वर्ग, बढ़ते हुए निम्न मध्यम वर्ग और शहरी बेरोजगारों में तथा गाँवों में छोटे और भूमिहीन किसानों में अपना स्थायी प्रभाव स्थापित किया है। इनकी मुख्य समस्या यह है कि इनका मुख्य प्रभाव कुछ ही राज्यों में है — जैसे, बंगाल, केरल और आंध्र प्रदेश में। बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों में भी इनका कुछ प्रभाव है। हो सकता है कि उद्योगों के विस्तार के साथ साथ उनकी शक्ति और कुछ राज्यों में भी बढ़े, बशर्ते वे अपनी आपसी फूट दूर कर सकें, अपने कार्यक्रम को अधिक स्वीकार्य बना सकें और वे दूसरे वाम पथी दलों के समयका को अपनी ओर खींच सकें। इस काम में हो सकता है कि वे कांग्रेस के ज्यादा निकट आवें और उनके वामपथी कार्यक्रम को स्वीकार कर लें और इस प्रकार देश में वाम पक्ष का बल बढ़ाएँ। ५१

रहितों या वर्गों का संगठन

जब हम विभिन्न आर्थिक वर्गों और हिन्ना के संगठन और उनकी राजनीति पर विचार करते हैं तो हम स्थिति पश्चिमी देशों से भिन्न पाते हैं।

५१ कम्युनिस्टों के ग्लिबक 'दूमेरे देगा के प्रति निष्ठा' का आरोप बढ़ा मूल्यतापूर्ण है। इस आरोप का आधार बड़ा कमजोर है। लेकिन सद्भावनात्मक प्रश्नों पर यह बार-बार करके कम्युनिस्टों ने स्वयं इस आरोप का मौज दिया है।

(१) जैसा कि पहले कहा जा चुका है राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास का मुख्य माध्यम यहाँ सरकार रही है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण या प्रमुख हिता का प्रतिनिधित्व राजनीतिक दला, सरकारी नौकरियों और सरकारी पार्टी के विभिन्न गुटों के द्वारा हुआ है। वस्तुतः इस देश में इतने अधिक और विविध प्रकार के हित आर वग है कि उनकी अभिव्यक्ति विभिन्न दला और उनके क्षेत्रीय व स्थानीय गुटा के द्वारा ही हो सकी है। इन दलों का आधार चाहे व्यापक हो या सीमित, फिर भी विभिन्न वर्गों का राजनैतिक प्रतिनिधित्व इही दला के द्वारा होता है अलग संगठना के द्वारा नहीं।

(२) इसका एक नतीजा यह है कि इन वर्गों का संगठन स्वतंत्र और अलग अलग नहीं बल्कि राजनैतिक दलों के गठजोड़ों की तरह मिलाजुला होता है। यद्यपि हिंदी या व्यवसायों के प्रादेशिक और सांदेशिक मण और मस्याएँ भी हैं, किंतु राजनीतिक स्तर पर वे मिलेजुले संगठना या दला में शामिल होते हैं। वाणिज्य संधी मजदूर संधी या अध्यापक संधी आदि की राष्ट्रीय मस्याएँ भी हैं, किंतु राष्ट्रीय राजनीति में वे कारगर नहीं, उनके सदस्य भी विभिन्न राजनैतिक दलों में ही शामिल होते हैं।

(३) वर्गों या हिंदों की इस मिलावट में पुराने पारिवारिक और रिश्तेदारी या विरादरी के मंत्रों का भी हाथ रहा है। जब कि अधिकांश नए देशों में व्यापार और उद्योग पर परदेशियों का कब्जा रहा है, भारत में इनका विकास परंपरागत व्यापारी परिवारों और समूहों के द्वारा हो हुआ है। इन परिवारों ने अपनी पुस्तनी व्यापारी प्रतिभा को आधुनिक व्यापार-उद्योग में लगाया है। मैनैजिंग एजेंसी की प्रणाली के द्वारा आधुनिक व्यापार व उद्योग पर इही पुराने व्यापारी परिवारों का कब्जा रहा है, इस कारण यहाँ पश्चिमी देशों जैसे पूँजीपति या उद्योगी वर्ग का विकास नहीं हो पाया। ५१

ट्रेड यूनियनों का अध्ययन करने पर इनमें भी पुरानी पारिवारिक और जाति-विरादरी की भावना काम करती दिखाई देती है। यद्यपि आधुनिक ढंग के सव-हारा आर पूँजीपति वर्ग के सघष का विचार यहाँ भी उदय हुआ है, फिर भी पश्चिमी देशों के ढाँचे पर अलग वर्ग या शक्ति के रूप में इनका संगठन अभी नहीं हुआ है। इसी तरह राजनैतिक दला ने भी अभी वर्ग विशेष का स्वरूप नहीं ग्रहण किया है। पश्चिम के विपरीत यहाँ चालिख मताधिकार और राजनैतिक अधिकार शुरू में ही द दिए गए, इससे हर वर्ग और हित को राजनैतिक व्यवस्था में स्थान

५१ देखिए-हेलेन का लेख 'द इंडियन बिजिनेस कम्युनिटी देव द फोर्स्वूशन आफ ऐन इंडस्ट्रियल क्लास पैमिफिकल अफेयर्स ३७, स २, जून १९५५ और बर्नोर्ट ई. माउन 'आगना इज बिजिनेस इन इंडियन पार्लियस' द इंडि वर्नेल आफ पोलि साइम २३-२ अप्रैल-जून, १९६२।

मिल गया और भारतीय राजनीति का स्वरूप एकवर्गी न होकर अनेकवर्गी हो गया ।

(४) मुख्य बात यह है कि भारत में वग या हित का संगठन आर्थिक या सामाजिक आधार पर न होकर पुरानी जाति-पाति के आधार पर हुआ है ।

(५) स्मरण रहे कि यहाँ सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की प्रेरक सरकार है, इसलिए यहाँ आर्थिक और सामाजिक हितों की अभिव्यक्ति राजनैतिक दलों और सरकारी तंत्र के जरिए हुई, अलग सस्था या संघटनों के द्वारा नहीं । दूसरे, वग विशेष या हित विशेष के संगठना का राजनैतिक महत्त्व नहीं दिया जाता और राजनीति में उनका भाग लेना भी पसंद नहीं किया जाता । व्यापार या उद्योग और किसान संघ, यहाँ तक कि मजदूर संघा से भी राजनैतिक भोलभाव या समझौता करने को उचित नहीं समझा जाता । यदि इन वग विशेष के संगठनों को राजनीति में भाग लेना हो तो वे राजनैतिक दलों के जरिये ले, स्वतंत्र रूप से नहीं । तीसरे, परिवर्तन और आधुनिकीकरण का माध्यम सरकार है, इसलिए विभिन्न हित या वग राजनैतिक दलों या गुटों के जरिए ही सरकार को प्रभावित कर सकते हैं । इनका यह अर्थ नहीं कि सरकार या राजनैतिक दल से विभिन्न वर्गों का सर्वप्रस्थापित करने वाली मध्यस्थ संस्थाओं का यहाँ कोई स्थान नहीं । उल्टे ऐसी संस्थाओं की बहुत बड़ी संख्या है । मगर ये सब राजनैतिक ढंग से काम करती हैं । पश्चिम की भांति वग या संगठन के ढंग से नहीं (इसीलिए जहाँ पश्चिम में राजनैतिक मांगों के लिए आर्थिक कारवाइ या हड़ताल की जाती है वहाँ भारत में आर्थिक शिकायतों व मांगों राजनैतिक हड़ताल या प्रदर्शनों के जरिए प्रकट की जाती हैं ।)^{५३}

(६) इससे नुकसान भी होता है । क्योंकि आर्थिक मांगों को तभी माना जाता है जब वे राजनैतिक ढंग से उठायी जाएं, इस कारण ये आंदोलन उग्र और हिंसात्मक रूप से लेते हैं । जिन हितों को कोई राजनैतिक दल उठाने को नैयार नहीं होता, वे प्रत्यक्ष कारवाइ और उपद्रव करने लगते हैं । यह ख़ुला प्रश्न है कि सरकार के लिए अधिक सुभीता इसमें है कि कभी कभी उपद्रव हो जाए, या इसमें कि वग संगठनों का बल बड़े और वे सरकार से सीधा कर और उसे अपनी मांग मानने को बाध्य करें और इस प्रकार उस पर स्याई बोझ बढ़ाएँ ।^{५४} लगता है कि भारत में पहले ही रास्ते को कम अनिष्ट कर समझा जाता है ।

विरोध का स्थान

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भारत की राजनीति में विरोध के आंदोलनों का एक खास स्थान है । यह विरोधी संसद या विधान सभा आदि के जरिये नहीं

^{५३} राल्फ जेम्स, 'पार्लियामेंट ऐंड ट्रेड यूनियन्स इन इण्डिया' चार ईस्टर्न सर्वे ३७, नं. ३, मार्च १९५८ ।

^{५४} देखिए मार्लन बीनर - 'द पार्लियामेंट आफ रीप्रेजेंटेटिव्स, पब्लिक प्रेशर ऐंड पोलिटिकल रेस्पॉन्स इन इण्डिया' (शिकागो, १९६२) ।

सीधे आदोलन जर्थात् हड़ताल, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, बंद, घेराव, घरनो आदि का रूप ले लेता है। इनमें से अनेक स्वतंत्रता आदोलन के युग की विरासत है। ये आदोलन कभी राज्य सरकार के विरोध में होते हैं तो कभी के द्र सरकार के और कभी किसी विशेष अधिकारी या प्रबंधक वग के विरुद्ध। इनका आधार कोई सास शिकायत होती है, जैसे राशन पूरा न मिलना, कम मजदूरी या सरकारी दफतर, कारखाना या कारखानों में काम की खराब स्थिति आदि। अक्सर वे अपने आप गुरु हो जाते हैं फिर इनको छात्र सघ, ट्रेड यूनियन, राजनैतिक दल और कभी कभी स्थानीय और राज्य सरकारों का भी समयन मिल जाता है। इसका एक नाटकीय उदाहरण प्रधानमंत्री की बोटी पर केरल के कम्युनिस्ट मंत्रियों का धरना था। अधिकांश ये आदोलन कांग्रेस सरकार के विरुद्ध होते हैं, यद्यपि कांग्रेस ने भी भिन्न दलों की सरकारों के खिलाफ इस प्रकार के आदोलन चलाए हैं और प्रमुख कांग्रेसिया ने इनको उचित बताया है। ५५

ऐसे प्रदर्शन या आदोलन को यहाँ अनुचित नहीं समझा जाता। यद्यपि जब ऐसे आदोलन उग्र या हिंसात्मक रूप लेने लगते हैं तब बंगाल और केरल की वामपंथी कम्युनिस्ट सरकारें भी इन के विरुद्ध कारवाई करने में नहीं हिचकिचाती मगर अपक्षा यह भी जाती है कि इनके खिलाफ ज्यादा कड़ाई न करती जाए और जहाँ ऐसा होता है, वहाँ पुलिस व अधिकारियों की कड़ी निंदा की जाती है और अक्सर इन की अदालतों या मजिस्ट्रेटी जांच कराई जाती है। यह साधारणतः स्वीकार किया जाता है कि स्वतंत्र देश में इस प्रकार के प्रदर्शनों व आदोलनों का स्थान है और इनको दबाने या सभालने में समय से काम लिया जाना चाहिए। ५६ इन आदोलनों का कड़ाई से दमन किया जाए ऐसा कहने वाले लोग कम हैं।

५. सी. गुप्तस्वयं, अध्यक्ष तमिलनाडु कांग्रेस कांग्रेस ने द्रमुक सरकार के विरुद्ध १० ००० आदर्शियों के प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। उन्होंने इस आधार पर इसे उचित बताया था कि हमने जनता को अपना शिकायतों को दूर कराने के लिए आदोलन करने का शिक्षा मिलती है। उनका कहना था कि अमेरिका जैसे उन्नत देश में रेडियो टी वी ने प्रचार के जबदस्त साधन हैं, किंतु भारत में जलून आर प्रदर्शन ही सामूहिक अभि यक्ति के उपाय हैं। हिंदू वाकला रिव्यू, अगस्त १२, ६८।

५६ भारत में पुलिस को नागरिक जिम्मेदारी की शिक्षा देनी जरूरी है। दूसरे राजनैतिक आदोलनों और गुना तत्वों के कारण उस पर भारी दायित्व भी आ गया है। पुलिस में भी इसमें क्षोभ हुआ है और उन्होंने भी आंदोलन और हड़ताल का सहारा लिया है। सन १९६९ के अगस्त में पश्चिम बंगाल सरकार की कुछ कारवायों से शुरू होकर पुलिस वालों ने विधान सभा पर हत्या कर दिया था। सब मिला कर पुलिस ने दंगा किमाद के अवसरों पर काफी धारन से काम लिया है, परंतु उनकी भी कुछ शिकायतें हैं जिन पर ध्यान न दिये जाने पर उन्होंने विरोध प्रश्न किया है। भारतीय पुलिस व्यवस्था का बहुत अच्छा अध्ययन डेविड एच बेन्नी ने अपनी पुस्तक 'द पुलिस ऐंड पोलि डेवलपमेंट इन इंडिया' (प्रिन्सटन १९६९) में किया है।

ये आदालत बहुत खतरनाक रूप नहीं ले पात इसके कई कारण हैं। एक तो देश इतना बड़ा है कि सारे देश में उग्र आंदोलन समझा करना कठिन है। दूसरे सरकार के हाथ में इतनी शक्ति है कि वह इन का काबू से बाहर न होने दे (सरकार इनका राबता न चाहते, जैसे उगाल में १९६७ और बाद में १९६९ में हुआ, तावान और है)। तीसर, देश से लोग आम तौर पर हिंसा को पसंद नहीं करते। इस कारण जादल या नेता हर बात पर आदालत छेड़ दिया करते हैं, उनसे लाग विरक्त हा जात है। फिर भी घेराव, वद या घरन भारतीय राजनीति से बहिष्कृत नहीं किए जा सकत।

काग्रेस के असतुष्ट वग आर भिन्न राजनतिक दना के भी सत्ता में जाने से और सास तिकायता या ममला का लेनर आदोलन हाने से काग्रेस पर भी बडा दबाव पडा और इनका एक नतीजा यह हुआ कि राजनीति में वास्तविक प्रश्ना पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। नेहरूजी के जमाने में हवाई बाते ज्यादा होती थी और आयाजन को जादू की छडी समझा जाता था, मगर एक और काग्रेस के अंदर और बाहर विराघ बडा और दूमरी और जाधिक और विशेषकर कृषि के क्षेत्र में सरकार का काम असतापजनक रहा। इस के साथ ही देश की राजनीति में गाव के लोग का जार बडा और उन में स नए नेता सामने आए। इन सब वानों के कारण सरकार स कुछ ठोस काम कर दिखाने की माग बढी, आर सत्ताहट नेताजा को भी डर हुआ कि सत्तापजनक काम न करने का नतीजा चुनाव के समय भुगतना पड़ेगा। इसलिए अब सरकार के काम पर ज्यादा कडी नजर रखी जाने लगी है।^{५७}

बौद्धिक वग में शका

जिस प्रकार समुक्त सरकारें टूटती रही हैं और दल बदल की प्रवृत्ति बढी है तथा सरकार की बयनी और करनी में जितना अंतर है और जनता के असतोष का दवाने के लिए सरकार को जिस प्रकार दमनकारी कारवाई करनी पडी है इसको देखकर देश के कुछ बौद्धिक वर्गों को यह शका होने लगी है कि बालिंग मतानधिकार पर आधारित लोकतन की यह प्रणाली देश की जाधिक समस्या सुलझाने और एकता कायम रखने में समथ हो सकेगी या नहीं। अभी ऐसे लोग कम हैं, जा लोकतन का हटाकर सनिक शासन स्थापित होने का स्वागत करे। मगर कुछ लोग इस के पक्ष में हैं कि वतमान मविमडली शासन प्रणाली के बजाय अमेरिका या फ्रांस जैसी राष्ट्रपति शासन की प्रणाली देश के लिए ज्यादा उपयागी होगी। कुछ लोग पश्चिमी दग की प्रणाली और पार्टों या दल प्रणाली में बहुत विरक्त हो गए हैं। देश में हमशा स एक उच्च शिक्षित, स्वतंत्रता प्रेमी वग रहा है जो यह

कहता है कि सरकार के बजाय प्रतिभाशाली निदल या दलपदी से अलग व्यक्ति या की सरकार हानी चाहिए। दूसरा बग है जो जनता का सीधा शासन चाहता है। वास्तव में इन विचारा के पीछे गदी राजनीति का दलपदी से विरक्त और शुद्ध, ईमानदार शासन की इच्छा है। इस प्रकार की बात करने वाले बड़े आदर्शवादी और सम्मानित व्यक्ति हैं, किन्तु न तो उनके पीछे कोई संगठन है, न उनका कोई राजनैतिक प्रभाव है। ५८

देश में राजनैतिक विरोध और आलोचना करने वालों का बहुत बड़ा दल है। किन्तु वे संगठित नहीं हैं। वे वर्तमान प्रणाली की टीका-टिप्पणी करते हैं, किन्तु कोई विवर्ण नहीं प्रस्तुत करते। वे या तो सरकारी या सरकार-विरोधी दला में शामिल होते हैं और अपने विचारा और आलोचनाओं से उन्हें प्रभावित करते हैं और उन्हें अपनी रीति-नीति सुधारने का प्रेरित करते हैं। इस से नुकसान यह होता है कि विरोध और अमर्त्य दलों या प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से न प्रकट होकर कभी कभी गडबडी और अस्थिरता पैदा कर देता है। दूसरी ओर लाभ यह है कि राजनीति में नए तत्व और नए रक्त के लिए रास्ता खुला रहता है, व्यवस्था में ग्रहणशीलता बनी रहती है और राजनीति बहुत गरम नहीं होने पाती। मूल प्रश्न यह है कि जैसे जैसे अब तक उपेक्षित या व्यवस्था के बाहर रह चुके राजनीति में प्रवेश करते हैं और सरकार का साबित ठोस समस्याओं से पड़ता है वह वैसे वैसे वर्तमान प्रणाली नए वर्गों को अपने में खपा सकेगी और उनकी निष्ठा प्राप्त कर सकेगी या राजनैतिक ध्वंसीकरण और बग मधुप सींच हागा।

५८ इनमें सब में सम्मानित पुराने क्रांतिकारी और समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण हैं जो अब 'संवाद' विचारधारा के समर्थक हो गए हैं और आमसुधार पर आधारित लोकतंत्र चाहते हैं। जयप्रकाश बाबू ने जामाईड कश्मीर और भारत पाक विवादों में मध्यस्थता की भी कोशिश की। उनके विचार उनका पुस्तक 'प्ली फार रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पोलिटि' में दिए।

सामाजिक ढाचा

हमने देखा कि भारतीय लोकतंत्री प्रणाली का प्रादुर्भाव समाज के आधुनिकतावादी प्रमाण में हुआ और यही से विकसित होकर जनसाधारण में विस्तृत हुआ। देखना यह है कि यह प्रणाली किस प्रकार परंपरागत समाज में जड़ पकड़ती है। इस समाज की जड़ें उस पुरानी सम्यता में हैं, जिसमें विविध जीर विभिन्न तत्वों, वर्गों और जातियाँ का समावेश हुआ है और इसके आचार-विचार और मूल्यों की अपनी परंपरा है। दूसरी ओर ससदीय शासन, तथा सत्तासूट जीर विरोधी दला का द्वंद्व आधुनिक युग की चोजें है। इन दोनों का मेल कैसे होगा ? यह ऊपर से घोषी हुई विदेशी और विजातीय व्यवस्था है, या दोनों में सम-वय के आसार दिखाई पड़ रहे हैं ? सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस नई राजनीतिक प्रणाली और परंपरागत जाति प्रथा की एक दूसरे पर क्या प्रिया-प्रतिप्रिया हुई है ? इस विषय पर विस्तार से विचार करना जरूरी है।^१

प्रचलित धारणाएँ

जाति जीर राजनीति विषय पर विचार करते समय अवसर यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या जाति प्रथा खतम हो रही है ? इस प्रश्न के पीछे यह धारणा है कि जाति जीर राजनीति परस्पर विरोधी सस्थाएँ हैं। ज्यादा सही सवाल यह होगा कि जाति-प्रथा पर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ रहा है और जातिपाति वाले समाज में राजनीति क्या रूप ले रही है। जा लोग राजनीति में जातिवाद की शिकायत करते हैं वे न तो राजनीति के प्रवृत्त स्वरूप को ठीक समझ पाएँ ह न जाति के स्वरूप को (कुछ लोग जाति-प्रथा और राजनीति दाना को खतम करना चाहते हैं)। राजनीति की प्रक्रिया से प्रचलित सस्थाओं के जरिये जनता का समयन या स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। चूँकि देश की जनता जातियों

^१ इस अध्याय का प्रारम्भिक रूप रचना मोठारा के लेख 'कास्ट इन इंडियन पालिटिक्स' (नई दिल्ली - १९६९) का मूडिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

मे सगठित है, इसलिए राजनीति को जाति-संस्था का उपयोग करता ही पड़ेगा। अतः राजनीति में जातिवाद का अर्थ जाति वा राजनतिकीकरण मात्र है। जाति को अपने दायरे में खींचकर राजनीति उसे अपने काम में लाने का प्रयत्न करती है। दूसरी ओर राजनीति के द्वारा जाति या विरादरी को देश की व्यवस्था में भाग लेने का माका मिलता है। राजनैतिक संगठन और जातीय संगठन दोनों के असली पात्र वे लोग हैं जो सत्ता और अधिकार चाहते हैं। राजनैतिक नेता सत्ता प्राप्त करने के लिए जातीय संगठन का उपयोग करते हैं। जातियों के रूप में उनको बना बनाया संगठन मिल जाता है जिससे राजनैतिक संगठन में आसानी होती है। जहाँ और प्रकार के समूह हूँ वहाँ राजनैतिक लोग उनका भी उपयोग करते हैं और इस तथ्य में वे पुराने संगठन या संस्थाओं को नया रूप देते हैं। इसी प्रकार जाति संस्था का भी रूप बदल रहा है।

सामाजिक और राजनैतिक विचारका का एक बग है जो राजनीति का ऐसा अस्त या साधन मानता है जिसके जरिये कोई बग या जाति अपनी प्रधानता और शक्ति को कायम रखने का प्रयत्न करता है।^१ वह यह भूल जाता है कि राजनैतिक शक्ति या प्रक्रिया के द्वारा भी आर्थिक और सामाजिक ढाँचे को बदला जा सकता है। ये विचारक अपनी एक धारणा बना लेते हैं और राजनैतिक व आर्थिक प्रवृत्तियों के घात-प्रतिघात से होने वाले परिवर्तनों की उपेक्षा कर देते हैं। जहाँ जाति स्वयं एक राजनैतिक तत्त्व का रूप धारण कर लेती है वहाँ यह प्रश्न बेकार हो जाता है कि जाति राजनीति का उपयोग (अपनी प्रधानता बनाए रखने का) कर रही है या राजनीति जाति का उपयोग कर रही है।

दूसरी ओर कुछ ऐसे विचारक हैं जो जाति-संस्था के बारे में कोई दुराग्रह नहीं रखते, किंतु वे भी राजनीति के द्वारा जाति-संस्था के कार्यापालन होने की बात करते हैं। एक अमेरिकन विचारक ने इसे जाति का लोकतंत्री अवतार कहा है।^२ ये सब विचारक जाति और राजनीति को परस्पर विरोधी तत्त्वों के रूप में देखते

१ केवल भारत और पश्चिम के मार्क्स शास्त्र ही नहीं बल्कि सोवियत रूस, चीन और पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट राजनीति के बारे में यह गलत धारणा नहीं रखते, अमेरिका के कुछ समाजशास्त्र भी यहाँ सोचते हैं। यथा वैरिंगटन मूर जूनि - सोशल ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप ऐंड डेमोक्रेसी (बोस्टन १९६७)। भारत में राजनीति को बग या जाति की प्रतिष्ठित मानने वाले विचारकों में मुरार ह - ए. आर. देसाई - सोशल बकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म।

२ लायड अ. इ. रडफोर्ड - द माउन्टीन ऑफ ट्रेडिशन - द डेमोक्रेटिक इनकारनेशन ऑफ कास्ट इन इंडिया - द अमेरिकन पोलिटिकल साइन्स रिव्यू-दिस १९६५। जाति और होल्डिंग सम्प्रदायों के विरोधी स्वरूपों की ओर इंगित लायड रडफोर्ड और सुजन डेनर रडफोर्ड ने हमारे पहले अपने निबंध 'द पोलिटिकल राउंड ऑफ इंडिया कास्ट असोसिएशन - पैसि अनेयस जिल्द ३३ सं १, मार्च १९६० में किया था। इन लेखकों का विश्लेषण अन्य विचारकों से ज़रा सही है। हमारा कहना यही है कि उन्होंने अतिशयोक्ति की है।

है। व यह नहीं समझ पाते कि यहाँ राजनीति और जाति में पूरा घुसीकरण कभी नहीं हुआ और भारत में जो परिवर्तन हो रहा है, उसका यह अर्थ नहीं है कि नई लानतनी प्रणाली के रूप में पुरानी जाति-प्रथा और ऊँची जातियाँ की प्रधानता और नीची जातियाँ की अधीनता का ढाँचा ही कायम है अथवा पुरानी जाति-प्रथा का स्थान नई राजनैतिक प्रणाली ने ले लिया है। जाति-प्रथा और ऊँच-नीच की धारणा में कुछ परिवर्तन हुआ है, जैसे अब जाति की ऊँचाई या निचाई छुआछूत के ऊपर उतनी निर्भर नहीं रही और पुरानी जजमानी प्रथा भी टूट रही है, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इससे जाति की प्रथा टूट रही है। बस सामाजिक विचारों में कुछ परिवर्तन हुआ है।

जाति का राजनीति से क्या संबंध है, इस विषय पर विचार करते समय हम इस बात पर ध्यान देंगे कि राजनैतिक कार्य में इसका कितना और किस प्रकार हाथ है न कि इस बात पर कि राजनैतिक कार्य में भाग लेने से जाति प्रथा में क्या परिवर्तन हुए हैं। यद्यपि इन प्रश्नों की हम बिल्कुल उपेक्षा भी नहीं कर सकते, क्योंकि राजनैतिक उद्देश्यों से जातियों के संघ आदि कार्यम हुए हैं, और इस प्रकार राजनीति ने उनके ढाँचे को प्रभावित किया है।

जाति का राजनैतिक रूप

हमें जातिप्रथा के तीन रूपों पर ध्यान देना है। एक है इसका लौकिक रूप। जातिप्रथा की कुछ बातों पर सबका ध्यान गया है—जैसे जाति के अंदर विवाह, छुआछूत और रीतिरिवाजों के द्वारा जाति की पृथक् इकाई को कायम रखने का प्रयत्न। लेकिन इस बात को उपस्था कर दी जाती है कि जातियों में आपस में प्रतिद्वंद्विता भी रहती है और वे लगातार अपनी प्रतिष्ठा और पद बढ़ाने का भी प्रयत्न करती रहती हैं।

जाति के लौकिक संगठन के दो रूप थे—एक शासकीय रूप यानी जाति की ओर गांव की पंचायत और चौधराहट। दूसरा रूप राजनैतिक था यानी जाति की आंतरिक गुटबंदी और अन्य जातियों से गठजोड़ और प्रतिद्वंद्विता। इन संगठनों का बलवर्धन या बलह्रास इस बात पर निर्भर था कि स्थानीय नेताओं के समाज की वैद्वस्थ सत्ता से किस प्रकार के संबंध थे। घम, व्यवसाय और प्रदेश के आधार पर जातियों की स्थिति बनती या बिगड़ती थी। अब भी इन बातों का महत्त्व है, यद्यपि सदन बदल गया है। जाति या संप्रदाय को किसी राजा से संबंध रखना पड़ता था और स्थानीय मामलों का प्रबंध जाति या गांव की पंचायत स्वयं करती थी। अब राजा के स्थान पर राष्ट्रीय सरकार है और जातीय पंचायतों के बजाय स्थानीय और प्रांतीय विधायक सभाएँ हैं। यह परिवर्तन एकदम से नहीं बल्कि क्रमशः हुआ है।

अनेक स्थानों में पहले ब्राह्मणों ने अंगरेजी शिक्षा को अपनाया और नई प्रगति-
निक और राजनैतिक व्यवस्था से लाभ उठाया। धीमे धीमे शिक्षा का और बाढ़
का प्रसार और लोगों में भी हुआ। कुछ प्रदेशों में ब्राह्मणों के बजाय अन्य जातियाँ,
मुख्यतः जमींदार और बड़े किसान वर्ग प्रबल थे और नई राजनैतिक व्यवस्था का
लाभ उन्होंने उठाया और उनके जरिये अन्य लोगों में उसका प्रसार हुआ। इसलिए
देश की राजनीति पर किसी एक जाति का प्राधान्य नहीं हो सका।^४ कुछ प्रदेशों
में जैसे गुजरात और मारवाड़ में जैन, वज्जव जैसे संप्रदायों के हाथ में आर्थिक शक्ति
थी, इसलिए नई व्यवस्था को पहले इन्होंने ग्रहण किया।

अंग्रेजी शासन के पहले भी जातियों के नए संबंध या जोड़ बनते थे और अपक्षा
घृत्त नीची जातियाँ अपना व्यवसाय या स्थान बदलती थी और ऊँची जातियों में
मिल जाया करती थी। इसका एक जरिया या अनुलोम विवाह यानी नीची जाति
या कुल की कन्या का अपने से ऊँची जाति में विवाह। उदाहरण के लिए सौराष्ट्र
की पशुपालक जाति गुजरात में आकर खेती करने वाली कुम्बी जाति बन गई और
अपनी लड़की अपने से ऊँची पाटीदार जाति में देने लगी। इस संबंध से उसका पद
भी बढ़ा। इसी तरह सौराष्ट्र की माची जाति गुजरात में आकर दर्जी जाति बन
गई। एक और उदाहरण है, महाराष्ट्र की देशमुख जाति का, जो मालगुजारी की
बसूली और भूमि व्यवस्था से सघिंत होने के कारण अन्य मराठा जातियों से कुछ
ऊँची हो गई। इस प्रकार नई उपजातियों के जन्म और अनुलोम-प्रतिलोम
विवाह के कारण जातियों के ढाँचे में परिवर्तन होते रहे। इससे एक ओर नई जातियों की
संख्या बढ़ी तो दूसरी ओर जातियों का तीक्ष्ण अंतर कम हुआ। अनुलोम-प्रतिलोम
विवाह के आधार पर जातियों की तुलनात्मक ऊँचाई-निचाई निर्धारित होती रही
और इससे बाद में राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में जातियों के परस्पर संबंध
बनने और संगठन कायम होने में मदद मिली।

जाति का दूसरा पहलू व्यक्ति को समाज से बांधने का है। जातिप्रथा न केवल
जन्म के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का समाज में स्थान नियत कर देती है इससे ऊँचे
से ऊँचे से लेकर नीचे से नीचे व्यक्ति का अपने समाज में लगाव पैदा हो जाता है
और वह आपस में भी एक दूसरे से बंधा रहता है। अवश्य ही व्यक्ति का लगाव
और निष्ठा अपने छोटे से समूह, बिरादरी या जाति से रहती है। बड़ी निष्ठाओं
की प्रेरणा भी उस जाति के ढाँचे से ही होती है। जातिप्रथा पर लाकतबी राष्ट्रीय
निर्माण के प्रभाव को समझने के लिए उपर्युक्त बात को ध्यान में रखना चाहिए।
लोकतंत्र के अंदर विभिन्न समूहों में शक्ति के लिए प्रतिद्वंद्विता हाती है, साथ ही

^४ देखिये—कोठारी संपादित—‘वास्ट इन इण्डियन पोलिटिक्स’ में कैरोलान इलियट का
आंध्रप्रदेश के बम्मा और रेड्डा जातियों पर निबंध।

^५ देखिए—शरावता कर्वे—हिंदू सोसाइटी-एन इंट्रोडक्शन (पूना, दक्कन कॉलेज, १९६१)।

या सत्सृष्टीकरण की है और दूसरी पारम्परिकीकरण और लौकिकीकरण की ।^७ आर्थिक उत्पत्ति, राजनैतिक एकात्मता और बुद्धिवाद की सावजनीन प्रवृत्तियों के प्रभाव से अक्सर अन्ध्राह्मण जातियाँ ब्राह्मणों की नकल करनेकी प्रवृत्ति का छोड़ देती हैं और अन्य अन्ध्राह्मण जातियाँ से मिलकर राजनैतिक व सामाजिक अधिकार प्राप्त करने और अपनी स्थिति सुधारने की चेष्टा करती हैं । इसके अलावा कभी कभी कोई जाति अपनी उच्चता सिद्ध करने के लिए अपना समग्र पौराणिक पुरापा से जोड़ने का प्रयत्न करती है जैसे गुजरात के पाटीदार, बंगाल के माहिष्यजीर राजस्थान आदि के जाट । कुछ इलाका में जहाँ ब्राह्मणों ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व नहीं किया, अधिकार सीधे कुछ शक्तिशाली वृषक जातिमा के हाथ में आए । इसलिए यहाँ ब्राह्मणीकरण या अन्ध्राह्मणवाद की जरूरत नहीं पड़ी और ये जातियाँ सीधे आधुनिक राजनीति में भाग लेने लगी और इस प्रकार इन्होंने समाज में भी उच्च स्थिति प्राप्त की । जाय प्रदेश और बिहार इसके उदाहरण हैं । यहाँ राजनीति जातियाँ की गुटबंदी या गठजोड़ पर आधारित है ।

सत्सृष्टीकरण की प्रवृत्ति कुछ सामाजिक तनाव और अस्थिरता भी उत्पन्न करती है । जैसे यहूदी और निग्रो गोरे या यूरोपीय लोग की नकल करते हुए भी मन में उनके प्रति विरोध ईष्या या नफरत का भाव रखते हैं, उसी प्रकार छोटी जातियाँ भी ब्राह्मणों के प्रति रखती हैं । दूसरे, जब तक उनका उच्च पद का दावा स्वीकार नहीं कर लिया जाता, उनकी स्थिति सदिग्ध रहती है । अक्सर ऊँची जातियाँ की ओर से उनका विरोध भी होता है । वास्तव में हिंदू समाज में प्रतिष्ठा की आकांक्षा बड़ी क्षामकारी और दुःखदायी सिद्ध होती है ।

फिर भी छोटी या नीची जातियों के ऊपर चढ़ने की यह क्रिया जारी रहती है और यह हिंदू समाज की शक्ति की धोतक है । ऊपर चढ़ने में सफलता सामाजिक, राजनैतिक या आर्थिक क्षेत्र में सफलता पर निर्भर होती है । वास्तव में हिंदू समाज में लौकिक शक्ति के आधार पर जातियों की स्थिति उठती और गिरती रहती है और इस प्रकार उसमें परिवर्तनशीलता बनी रहती है ।

इस प्रकार जातिप्रथा की लौकिक, सामाजिक और भावनात्मक परंपरा ने इसे आधुनिक प्रभावों और परिवर्तनों को ग्रहण करने योग्य बनाया ।

७ एम एन श्रीनिवास ने ये नाम दिए हैं । सत्सृष्टीकरण में छोटी जातिश सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों के रानिस्त्रिवाचों की नकल करने लगता है । देखिए—श्रीनिवास 'सोशल चेंज इन मायन इंडिया' (बम्बल १९६६) तथा 'द कोलेमिव रोल आफ सरूताइशन' (मामयो आफ दिव्य यूनिवर्सिटी १९६९) । लौकिकीकरण की प्रवृत्ति के अंदर सरूताकरण और पारम्परिकीकरण दोनों प्रवृत्तियाँ इस प्रकार बन जाती हैं, जिनके लिए देखिए—'कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स' । श्रीनिवास की पुस्तक में भी एक अध्याय लैस्त्रिवाच पर है ।

आधुनिकता का प्रभाव

भारतीय समाज पर आधुनिकता का प्रभाव धीरे धीरे पड़ा। नई शिक्षा, सरकारी नाकरिया, बालिग मताधिकार और व्यवसाय के विस्तार का प्रभाव पुरानी जातपात वाली समाजव्यवस्था पर पड़ा। नई शासनव्यवस्था के अनगन सरकारी नौकरी, व्यापार, डाक्टरी, बवालत आदि व्यवसाय तथा प्रतिष्ठा व अधिकार के जो अवसर प्रस्तुत हुए, उनका लाभ समाज के शिक्षित और प्रभुग वर्गों ने उठाया और उनमें आधुनिकता का प्रसार हुआ। नए सामक वर्ग ने भी स्थानीय भावनाओं का आदर किया और ऊँची जातियाँ के प्रभाव का स्वीकार किया और उनको राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था में भाग दिया। इस प्रकार पुराना समाज नई राजनैतिक व्यवस्था के बरिय आया।

इस प्रक्रिया को तीन चरणों में बाँटा जा सकता है। सबसे पहले शक्ति और प्रभाव को स्वयं समाज की प्रतिष्ठित या जमी हुई जातियाँ तक सीमित रही। "सबसे नई शिक्षा का लाभ पाँडे में ऊँची बुद्धिजीवी जातियाँ के लोग ने उठाया। ये जातियाँ परंपरा से विद्या और सम्पत्ती में अग्रणी रही। जहाँ नई शिक्षा और समे प्राप्त होने वाली पदप्रतिष्ठा केवल एक जाति या उपजाति तक सीमित रही, वहाँ अन्य ऊँची जातियाँ में, जो पहले समाज में प्रतिष्ठित और प्रभावपूर्ण स्थान रखती थी, उनमें प्रति ईर्ष्या पैदा हुई। और इन ऊँची जातियों ने अधिकार और पद प्राप्त करने के लिए अपना राजनीतिक संगठन किया। इससे दो ऊँची जातियों में प्रतिद्वंद्विता खड़ी हो जाती है।" यह प्रतिद्वंद्विता बड़ा नहीं उठती जहाँ प्रतिष्ठित जाति अन्य सब जातियों से बहुत ऊँची होती है या जहाँ अन्य जातियाँ भी अलग अलग क्षेत्रों या स्तरों में प्रतिष्ठित रहती हैं, और इस प्रकार मिल कर शक्ति और प्रभाव का उपयोग करती हैं।

दूसरा अवस्था यह है जब पद और शक्ति के अवसरों की संख्या बढ़ जाती है और भिन्न जातियों में स्पर्धा के साथ साथ जाति के अंदर भी प्रतिस्पर्धा गुट बन

८ 'प्रतिष्ठित या जमी हुई' (इन्स्टैबल) जाति शब्द का प्रयोग हम एक मानिवास ने किया। यह प्रधान (टामिन) जाति से भिन्न है। प्रधान जाति न केवल राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से ही शक्तिशाली शक्ति है, बल्कि संस्था में भी गांव या इलाके में ज्यादा होता है। ('द टामिनेट कास्ट इन रामपुरा' - अमेरिका पत्रिका १९१६ फरवरी)। प्रतिष्ठित जाति ऊँची और राजनैतिक रूप से प्रभावशाली होने पर भी संस्था में होती होती है। निम्न शक्तियों में दृढ़मूलक उपजात जातियाँ प्रतिष्ठित होती हैं वहाँ 'प्रतिष्ठित' और 'प्रधान' का अंतर स्पष्ट नहीं रहता।

९ मद्रास और महाराष्ट्र में ब्राह्मण-अब्राह्मण, गुजरात में बनिया आहवा-पार्श्वार आदि में बन्ना-टोआ और केरल में पन्ना-नाथर द्वाद इसके उदाहरण हैं। इस विषय में अन्तर्गत एक जाति के प्रधानता प्राप्त कर लेने पर दूसरे से उभरे द्वाद गड़े हो जाते हैं। जैसे गुजरात में पार्श्वार - अन्नेप द्वाद और महाराष्ट्र में मराठा - महार द्वाद। अन्तर्गत इन द्वादों के परिवर्तनरूप नए और पुराने गठबंधन बन जाते हैं।

जाते हैं।^{१०} प्रतिद्वंद्वी नेताओं के पीछे गुट बन जाते हैं। इन गुटों में विभिन्न जातियों के लोग होते हैं। अपना गुट मजबूत करने के लिए उन जातियों की भी सहायता ली जाती है, जो अब तक दायरे से बाहर थी। जाति व्यवस्था की शक्ति और पद का ढांचा अब ज्यादा जटिल हो जाता है। पारम्परिक आर्थिक साहाय्य जैसे अपने परिजनों को काम घंघा या नौकरी दिलाना या विपत्ति में सहायता करना, आश्रय—आश्रित संबंध तथा जातियों के सघ और महासघों का संगठन इस नई व्यवस्था के अंग होते हैं।

जिन इलाकों में जमीन या अन्य आर्थिक आधार पर कई जातियाँ पहले से संबंध रहती हैं या आश्रय—आश्रित संबंध मौजूद रहते हैं, या अनुलोम विवाह का संबंध रहता है जहाँ एक वर्ण की अनेक उपजातियों का आपस में संबंध रहता है, वहाँ राजनीति को बना बनाया रास्ता मिल जाता है और नए जातीय संगठन बनाने की आवश्यकता उतनी नहीं रहती। पहले से बतमान जाति—शखलाएँ ज्यों की त्यों राजनीतिक क्षेत्र में आ जाती हैं। दूसरी जातियों से प्रभावशाली लोगों को दल या संगठन में लेने में आसानी होती है। दूसरे शब्दों में राजनैतिक शक्तों का विस्तार के लिए पहले से बनी शखलाएँ मिल जाती हैं, या नई शखलाएँ आसानी से बन जाती हैं।

नई राजनैतिक समस्याओं को स्थापना से जातियों की गुटबंदी और प्रतिद्वंद्विता नए नए रूप लेती है। जिले और प्रांत की राजनीति में प्रभावशाली जातियों में प्रतिद्वंद्विता प्रकट होती है जैसे, आंध्र में कम्मा और रेड्डी, गुजरात में पाटीदार और अनाबिल, मैसूर में लिगायत और वोक्कलिय, तथा मद्रास और बिहार की विभिन्न जातियों में। हर स्तर पर राजनीतिक गुटबंदी और जाति या वर्ण संबंधों के कारण नए संगठन जन्म लेते हैं। इनके कारण नेताओं और प्रमुख व्यक्तियों का प्रभाव बढ़ता है।

मगर शक्ति और प्रभाव की यह होड़ थोड़ी सी ऊँची जातियों तक ही सीमित रही। छोटी जातियाँ ऊँची या शक्तिशाली जातियों के प्रभाव में बनीं रहीं। किंतु दूसरे चरण में प्रतिस्पर्धी नेताओं ने अपना गुट मजबूत करने के लिए नीची जातियों को भी राजनीति में खींचा। चुनाव में समयन प्राप्त करने के लिए इन नीची जातियों के प्रमुख लोगों को छोटे राजनैतिक पद और लाभ में कुछ हिस्सा दिया गया। जहाँ इस प्रकार मुखिया को इनाम और पद देकर इन जातियों का समयन प्राप्त करना संभव नहीं हुआ, वहाँ विभिन्न जातियों और उप-जातियों में आपसी प्रतिस्पर्धा पैदा कर के, उनका संगठन बनाने की ओर उन संगठनों से मध्यस्थ या

^{१०} यह गुटबंदी जाति के अंदर प्रचलित पुराना खानदाना गुटबंदी से भिन्न है। यह नई गुटबंदी लौकिक या राजनैतिक आर्थिक शक्ति के लिए होता है और इसमें अनेक व्यक्तिगत गुट प्रतिस्पर्धी होते हैं।

विचवइया द्वारा समझीता वर्गने की बासिन्ध की गई। अर्थात् जहा कुछ मुखिया को साथ लेने स काम चल गया, वहा जनता 'या जाति के साधारण लोगा की परवाह नहीं की गई। जहा यह तरीका नही चल सकी वहा सगठन क नए तरीके निवाले गए। यह भी ममय है कि कागानर में य नवादित नेता आपत म मिल कर पुरानी जाति के नेताआ का अपदम्य कर द। यह उनकी आर्थिक शक्ति और कुशल सगठन पर निर्भर ह। इस क नाय उनम राजनीतिक चेतना और जातिया द्वारा छाटी जातिया क शापण क प्रति क्षोभ और अलग अलग जाति के बजाय वग की भावना भी होनी जरूरी ह। यह भी कहना जरूरी ह कि गजनीति क इस सामाजिक प्रकार क नेतृत्व और सगठन सामाजिक स्थिति आधारित

प्रकार के नेतृत्व और सगठन शक्तों की जरूरत है। सामाजिक सगठन में कुछ भिन्न स्थिति आएंगी जब नए नेता पुराने नेताओं को या समाज का एक बग दूसरे बग से सगठन का था। इस युग में राजनीति और सांख्यिक जागरण और सहारा देती थी, जो अंगरेज अधिनियमों से व्यवहार कर सकें। वानूनी वहस मुवाहल में सगठन कर सकें। एस साग ब्राह्मण और कायस्थ आदि जातियों में उपलब्ध थे, के पास विद्या और प्रशिक्षण और कायस्थ आदि जातियों में उपलब्ध थे, वानूनी और विज्ञान आदि में कुशलता प्राप्त की थी। जब आंदोलन का जन के बजाय व्यवसायी और कृषक जातियों के नेताओं और कायस्थों के जाति के लोगों का नेतृत्व कर सकते थे। अपनी जातियों का सगठन करने से जातिविमान और ऊंची जातियों की प्रधानता के विरोध की भावना राजनीति के नए व्यवसायी थे। ये पुराने जाति के नेतृत्व को अपदस्थ करके नए नेतृत्व को स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे थे।

ये लोग राजनीति के नए व्यवसायी थे। ये पुराने ऊँची जातियों के राजनीतिक पुरातनता से जिन का इन्हीं ने अपदम्य विमर्श, विचारा में कम आधुनिक थे और उठाने की प्रवृत्ति, सगठनपटुता और आधुनिक शिल्प या टेक्नीक और सगठन की प्रवृत्ति थी। वह उनकी जातिगत विशेषता थी न कि नई सभ्यता या राजनीति से उधार ली गई थी। एक बार जब यह नया सामाजिक बग और नई राजनीति और सगठनात्मक कुशलता आगे आ गईं तब न केवल राजनीतिक प्रवृत्तियाँ ने नया आयाम ग्रहण किया और समाज की जय प्रवृत्तियाँ से अलग हो गईं, बल्कि अपना एक स्वल्प और जीवन भी ग्रहण कर लिया। परिवर्तन की यह प्रक्रिया तीसरे

चरण म पूणता पर पहुँची, जब राजनीति का आधार बहुत व्यापक हो गया और जाति के अलावा अन्य बहुत-सी बात भी उस में आ गई ।

प्रभावशाली और प्रतिष्ठित जातियों में फूट और गुटबंदी, दूसरी जातियों से भेद और उनके मुखिया को अधिकार में भाग देने से जातिव्यवस्था में काफी बिखराव आया, फिर भी जाति का आधार बना रहा । यद्यपि इसने राजनैतिक और व्यक्तिगत शक्ति की प्रवृत्ति को भी जन्म दिया । तीसरे अध्याय या चरण में एक जोर राजनैतिक मूल्यों की प्रधानता हुई और जातिपाति से लगाव कम हुआ, दूसरी ओर शिक्षा, नये शिल्प प्रतिष्ठा के परिवर्तित पैमाने और शहरीकरण के कारण समाज में परिवर्तन आया । नई आकांक्षाओं और भौतिक उन्नति की नई धारणाओं का जोर बढ़ा, पुराने परिवार टूटने लगे और लोग कामधंधे के लिए देशांतर जा कर बसने लगे । इस के साथ जातिविरादरी की भावना ढीली पड़ने लगी । सामाजिक व्यवहार अपनी जाति तक सीमित न रहा । राजनीति में भी व्यापकता आई । नई शिक्षा और नये सामाजिक व्यवहार से उत्पन्न होने वाली नई प्रवृत्तियाँ फैलने लगी । देखने में आया कि एक ही जाति के अंदर अधिक अंतर या विषमता के कारण अनगाव पैदा हुआ और जाति का बंधन ढीला पड़ा । यह प्रवृत्ति केरल के एजवा या हरिजना में भी लक्षित हुई । आधुनिकता का एक आवश्यक तत्त्व है, विभिन्न क्षेत्रों और कार्यों का स्पष्ट पथकरण । पहले राजनैतिक, नैतिक और बौद्धिक संचार के कार्य सामाजिक बग या जाति के अंदर ही होते थे अब इन का अलग अलग क्षेत्र बन गया है ।

राजनीति अभी भी प्रभावशाली तत्त्व है परंतु अब इस की आधुनिकता के एक साधन के रूप में देखा जाता है । इसे जाति को नष्ट करने या उसका स्थान लेने वाली शक्ति के बजाय नए समाज की स्थापना में सहायक के रूप में देखा जाता है । जब राजनीतिक समस्याओं का ठाँव व्यापक होता जा रहा है, जिसमें जाति की भावना को नया रूप मिलता है और उस का पुराना रोटी-बेटी मंत्र धाँसा आधार कमजोर हो गया है । दूसरी ओर राजनीतिक प्रवृत्तियाँ ने नए संगठनों और नई निष्ठाओं को जन्म दिया है, जो पुरानी निष्ठाओं का काटती हैं । जाति अब राजनीतिक समयन या शक्ति का एक मात्र आधार नहीं रही, यद्यपि राजनीति में इसका अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है । यह एक व्यापक सबंध गृहस्था का अंग बन गई है । काम के विभाजन के हिसाब से हर व्यक्ति की समाज में पदमर्यादा निर्धारित करने पहले जमाने में जातिप्रथा ने समाज को बाँधे और बनाए रखने का काम किया था । आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने के कारण पहले तो जातिप्रथा पर पुनर्वृत्ति की प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ा, बाद में जाति भावना का सामंजस्य हुआ और इसने राजनीतिक संगठन में सहायता दी ।

आधुनिक राजनीति में भाग लेने में जाति की दृष्टि में परिवर्तन हुआ और

उह उन्नति के नए मावे मिले। इसके साथ उनको यह भी समझ में आ गया कि आज के युग में केवल जाति और संप्रदाय में काम नहीं चल सकता। जहाँ जाति बड़ी होती है, वहाँ भी उसमें एकता नहीं होती। उसमें उपजातियाँ के भेद होते हैं, और जब सग्या में छाटी होती है, तब तो अपने बल पर वह चुनाव जीत नहीं सकती। फिर यदि कोई मदस्य या उम्मीदवार अपनी ही जाति का पक्ष करता है तो दूसरी जातियाँ उसके खिलाफ हो जाती हैं। इसलिए चुनाव की राजनीति में अनेक जातियाँ का गुट बनाना पड़ता है। इसमें विभिन्न जातियाँ में एका होता है। तीसरे, राजनतिक दल की शक्ति सभी कायम रहती है, जब समाज के सभी प्रमुख वर्ग ज्यों सभी जातियाँ के लोग उसका समर्थन दें। अन्तु राजनीति में आने के कारण जाति की भावना ढीली पड़ जाती है और अनेक नई निष्ठाओं का उदय होता है। इस प्रकार जाति लोबिक राजनतिक व्यवस्था का एक अंग बन जाती रही है।

एकीकरण या समुच्चयन के नए रूप

आजकल राजनीति में जातिवाद और संप्रदायवाद का जोर बढ़ने की शिकायत की जाती है। समाजशास्त्री भी इस भ्रांति में पड़ जाते हैं। ऐसा समझा जाता है कि शिक्षाप्रसार, गृहरो के विस्तार और औद्योगिकरण के कारण संप्रदाय और जाति के जा बंधन ढीले पड़ रहे थे, वे चुनाव की राजनीति के कारण फिर से जोर पकड़ रहे हैं और इससे देश में फूट बढ़ेगी जिससे धर्मनिरपेक्ष लाक्षण का ढांचा खतर में पड़ जाएगा। इसके समर्थन में उदाहरण दिया जाता है कि किस प्रकार विभिन्न राजनतिक दल संप्रदाय और जाति के नाम पर बाँट लेने की कोशिश करते हैं। इसमें शक नहीं कि ऐसा किया जाता है, किन्तु इससे जो निष्पन्न निकाला जाता है, वह उपयुक्त नहीं। वास्तव में जाति और राजनीति के मिश्रण से दूसरे ही परिणाम निकलते हैं।^{११} बजाय राजनीति पर जाति के हावी होने के जाति का राजनतिकरण हो जाता है। राजनीति ने जाति को लीक से हटा कर नया सदर्भ दे दिया है, जिसमें उसका पुराना रूप बदल रहा है। जब किसी विशेष जाति को ही राजनतिक सत्ता का अधिकारी नहीं माना जाता इसलिए प्रतिद्वंद्वी दल का उम्मेदवार चुनने में यह देखना पड़ता है कि किम जाति का कितना सख्या बल है, किस जाति में कितने गुट हैं, उसका आर्थिक अवयव किन जातियों से है आदि। यह बात किसी भी राजनतिक पद्धति और किसी भी सामाजिक व्यवस्था के लिए

११ इसके विपरीत दृष्टिकोण के लिए और सामाजिक एकीकरण में जाति का भूमिका के विषय में देखें - सुरनाथ मिन्हा, 'कास्ट एंड इन्डिया इन्स एसेंशल पैग्स आफ सोशियो - कल्चरल इन्वेस्टिगेशन'। एगोना ड रियूक संपादित - 'कास्ट एंड रैस कम्पेरेटिव अध्यवेज' (लंदन - १९६७)।

स्वाभाविक है। जाति का विचार उस अवस्था में जम्हरी नहीं था, जब राजपूत कुष्ठ विशिष्ट जातियाँ के लिए सुरक्षित होत थे। अब राजनैतिक अधिकार और पद सब जातियाँ के लिए खुल गए, इसलिए राजनीति में अंध वाना व साथ जाति का विचार भी आ गया। हरल्ड गोल्ड के शब्दों में — राजनीति का आधार होने के बजाय, जाति उसको प्रभावित करने वाला एक तत्त्व है।^{१२}

वास्तव में यह भी कहा जा सकता है कि जाति के बंधन का स्वीकार कर ले और राजनीतिक सौदवाजी और गठबंधन में उनकी सहायता लेने के कारण उसका देश की राजनैतिक व्यवस्था में स्थान देना तथा उसे राजनैतिक संगठन का साधन बनाना आसान हो गया। अगर ऐसा न करके उनकी उपेक्षा की जाती और उनकी भावना को अस्वीकार किया जाता तो राजनैतिक संगठन में बाधा पड़ती। स्वतंत्रता के पहले कांग्रेस ने इसी तरह मुसलमानों के अपने समाज के प्रति लगाव को महत्व नहीं दिया था, और यह मान लिया था कि राष्ट्रीय भावना जातीय और साम्प्रदायिक भावना से अधिक बलवती है उसकी यह भूल सिद्ध हुई। आधुनिकतावादी नेता जातिपाति पर भले ही नाक सिकाड़ें परंतु इनके द्वारा राजनैतिक शक्ति उन वर्गों या समूहों के हाथ में पहुँच सकी जो जब तक उससे वंचित थे।

इस अध्याय में हमने सामाजिक राजनैतिक संगठन की बड़ी पचीसा प्रक्रिया का वर्णन किया है। इसके दो रूप हैं। पहले रूप में उच्चवर्ग के नेता सामने आते हैं। भिन्न भिन्न जातियों के हाते हुए भी इनके राजनैतिक या लौकिक विचार एक स होते हैं। ये समाज के उच्च या प्रतिष्ठित वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वभावतः ये वर्ग आधुनिकता को पहले ग्रहण करते हैं। इस बीच समाज के साधारण या कम उन्नत वर्गों को धीमे धीमे नए विचारों और नई बातों को अपनाने का मौका मिलता है।

दूसरे रूप में लौकिक या राजनैतिक उद्देश्यों से जाति अपना संगठन करती है। जैसे जाति विशेष के कलकत्तावास आदि संस्थाएँ, पूरे प्रांत या भाषा क्षेत्र के जातियों के सम्मेलन या संस्थाएँ, तीसरे एक—से सामाजिक स्तर या वर्ण की विभिन्न जातियों के संघ या एक खास प्रयोजन के लिए विभिन्न जातियों का एक संघ। यह विशेष उद्देश्य या प्रयोजन ही इन संघों को विशुद्ध जातीय संघों से पृथक् करता है।^{१३} यह प्रयोजन आर्थिक या शिक्षा संबंधी भी हो सकता है या यह भी हो

१२ देखें इसकी — 'ब्रिटिश पोलिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स इन रूरल इंडियन सोसाइटी', इक ऐंड पाली वाकर्स २, स ३३-३५ विशेषांक, अगस्त १९६७।

१३ जातीय संगठनों के बारे में काफ़ी साहित्य तैयार हो रहा है। रबाल्स का 'द पोलिटिकल रोल ऑफ़ इंडियन वास्ट असोसिएशन' अभा भी इस विषय का सबसे अच्छा निबंध है। जाति-संगठनों के बारे में और देखें 'वास्ट इन इन्डि पालिटिक्स' में रचना केठारी और मधुपेक्ष [मूल पृष्ठ पर]

सत्या दल तथा जाति विरादरी की भावना के महत्त्व को गमयन थे जातीय सगठनों को राजनीति में लाना चाहते थे। शिक्षा-प्रभार आदि के उद्देश्य से विभिन्न जातियों के जो अलग अलग सगठन थे, उनका ये राजनैतिक उद्देश्य के लिए सघ बनाना चाहते थे, जिससे राजनीति में उनका प्रभाव बड़े और व्यक्तिगत के बनाम पूरे समूह का फायदा पहुँच सके।^{१८} कालान्तर में इसी प्रवृत्ति ने जार पकड़ा, यद्यपि अभी भी देश की सभी मुख्य जातियाँ का इस प्रकार सगठित नहीं किया जा सका है। मगर जो जातियाँ इस प्रकार सगठित नहीं हो सकी, वे राजनैतिक सोदेवाजी में सफल नहीं रही और उनके सदस्या की अपनी आवाज उठाने के लिए उपद्रव और तोड़फाड़ का सहारा लेना पड़ा।^{१९} सब मिला कर जातीय सगठना ने भारत में राजनीति में वही भाग लिया है जो पश्चिमी देशों में विभिन्न हिता व वर्गों के सगठना ने।

अथ जातीय समूह

भारतीय राजनीति के ढाँचे में जातिव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण स्थान का हमन ऊपर बणन किया। दो और इससे संबंधित बिषय हैं। एक है अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की स्थिति, जिन पर भारतीय संविधान के निर्माताओं ने विशेष ध्यान दिया है और दूसरा अल्पसंख्यक संप्रदायों, खासकर मुसलमानों की स्थिति।

यद्यपि हरिजन और अनुसूचित आदिम जातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति अभी भी बहुत खराब है किंतु राजनीति में उनकी भूमिका, अथ छोटी जातियों से भिन्न नहीं है, जिनका ऊपर जिक्र किया गया। उनको समद व विधान सभाओं और सरकारी नौकरियों में जा सुरक्षित स्थान दिये गये हैं।^{२०} उससे उनका राजनैतिक सगठन में बहुत प्रेरणा मिली है। सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में भी राजनैतिक दल व ऊँची जाति के नेता या उम्मेदवार इनका समर्थन लेने के लिए इनमें सोदा व समझौता करते हैं। भ्रमिभंडाल व दला के नेतृत्व में इनके आदमी साग्रह लिये जाते हैं। इस प्रकार सामाजिक स्थिति हीन होते हुए भी

१६ वदा।

१७ आश्चर्य नहीं कि पश्चिम बंगाल तथा बने नगरों में उपद्रव और तोड़फोड़ की राजनीति का जशादा जार रहा है बनिस्वन उन शायों के चहा जाति के आधार पर राजनैतिक गुट या गठनों बने हैं।

१८ कसा ५ वें अयाय में बताया गया है, भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों व आदिम जातियों के लिए अनेक विशेष व्यवस्था की गई है। सरकार ने इनमें विस्तार किया है। सबसे महत्त्वपूर्ण व्यवस्था समद आदि सब निराश्रित सम्भाव्यों में स्थान सुरक्षित करने की है। सभी सभी तो सुरक्षित स्थान इनके अनुपात से अधिक होने हैं।

अनुसूचित जातियाँ व आदिवासियों का राजनैतिक महत्त्व बहुत है।^{१९} इन अनुसूचित जातियों ने राजनैतिक उद्देश्य से अपने संगठन बनाए हैं और अपने लिए विशेष स्थान प्राप्त किए हैं, जैसे आसाम में आदिम जातियों ने।^{२०} इनकी विशेष सवधानिक स्थिति होने के कारण इनके संगठनों को 'जातीय' या 'सांप्रदायिक' नहीं समझा जाता। बल्कि प्रायः सभी प्रमुख राजनैतिक संगठनों ने अपने विशेष 'हरिजन' और आदिमजाति विभाग खोल रखे हैं। इस प्रकार राजनैतिक मायता मिल जाने से स्कीण या जातीय भावनाएँ लौकिक रूप ग्रहण कर लेती हैं और समाज के अन्य वर्गों के साथ मिल जाती हैं।

मगर यह बात मजहबी अल्पसंख्यकों पर लागू नहीं होती, खासकर मुसलमानों पर (अथ गैरहिंदू संप्रदाय बहुत छोटे हैं और जहाँ उनकी संख्या अधिक है, जैसे केरल में कैथोलिक या पंजाब में सिख, वहाँ उनको वही राजनैतिक महत्त्व प्राप्त है, जसा ऊपर उल्लिखित जातियों को)। अध्याय दो में हमने देखा कि किस प्रकार कांग्रेस के नेता मुसलमानों के पृथक् राजनैतिक संगठन और सांप्रदायिक राजनीति के विरुद्ध थे। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के दो राष्ट्रों के सिद्धांत का विरोध किया और स्वयं सभी संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया, परंतु उसने संप्रदायों के अलग अलग संगठनों के द्वारा इनको एक मंच पर लाने का प्रयत्न नहीं किया और सांप्रदायिकता का मुकाबला करने में सफल नहीं हुई। पाकिस्तान की स्थापना के कारण सांप्रदायिक संगठनों के विरुद्ध भावना और मजबूत हुई। इसलिए जब लोकतन्त्र की राजनीति ने समाज के बड़े समूहों को संगठित होने की प्रेरणा दी तब मुसलमान दुविधा में पड़े। उनमें दो प्रवृत्तियाँ दिख पड़ीं। एक की प्रतिनिधि जनियत उलमा है, जो मुस्लिम संगठनों को राजनैतिक उद्देश्यों के बजाय शिक्षा और सामाजिक और मजह्मी कार्यों तक सीमित रखा चाहती है। दूसरी विचारधारा जमाते इस्लामी, और मजलिस मुशव्वरात की है, जो राजनीति में भाग लेने के पक्ष में है और जा चुनावों में अपने उम्मीदवार खड़े करती है तथा अपनी राजनैतिक भाग्य पैदा करती है।

इस प्रकार का मतभेद ऊपर उल्लिखित जातीय संगठनों में भी प्रकट हुआ था, यद्यपि राजनैतिक नैराश्य के कारण मुसलमानों में इस मतभेद ने कटुता धारण

१९. रॉबर्ट ए. राइल ने इसको विषमता के बिखराव या अंतर का नाम दिया है। पहले ये जातियाँ एकत्रित या पुनः स्थापित विषमताओं में वीक्षित थीं। देखिए हू. गबन्स (न्यू हेवेन—१९६१)।

२०. सर्वदल पदाधीन नेता सम्मेलन के आंदोलन के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार ने आसाम के अंतर्गत उनके उपराज्य की स्थापना का निश्चय किया। अब 'मेघालय' उपराज्य को पूरे राज्य का दर्जा स्वीकार कर लिया गया। नागाओं का भी अलग राज्य बन गया। बिहार और उड़ीसा में आदिम जातियों को सभी दलों की सरकार में महत्वपूर्ण हिस्सा दिया गया। मध्य प्रदेश में उन्हें मन्त्रालय नहीं मिला है और मंत्र मिला कर आदिवासी अभी भी बहुत गरीब व पिछड़े हैं। अयाय ८ में इस विषय पर और विचार किया गया है।

कर ली है और राजनीति में भाग लेने के समर्थक हमेशा वैधानिक उपायों की बात नहीं करते। लेकिन जहाँ मुसलमानों ने राजनीति में भाग लिया है, वहाँ उनकी सकीणता व पृथक्ता कम हुई है और अन्य जातियों की तरह उन्हें भी राजनैतिक जोड़तोड़ में भाग मिला है। उदाहरण के लिए केरल में मुस्लिम लीग राजनीति में बनी रही और उसे राजनैतिक गठबंधनों में स्थान प्राप्त हुआ, राजनैतिक पदाधिकार में हिस्सा मिला और उसका दृष्टिकोण अन्य राज्यों के मुस्लिम संगठनों के मुकाबले ज्यादा असाप्रदायिक और लोकिक है। दूसरे तीसरे और चौथे चुनाव में देश के अन्य भागों में भी मुस्लिम राजनैतिक संगठन राजनीति में सक्रिय हो उठे हैं और इस प्रकार घेरे-घेरे के लोकिक क्षेत्र में आ रहे हैं। यद्यपि मुसलमानों के लिए स्थान सुरक्षित नहीं किए गए हैं, किंतु नाग्रम तथा अन्य राजनैतिक दलों ने उनको कुछ स्थान देने की परिपाटी बना ली है। इससे मुस्लिम संप्रदाय राष्ट्रीय राजनीति की ओर खिंच रहा है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मुसलमानों की काफी संख्या है, वहाँ मतदान का अध्ययन करने से पता चलता है कि मुसलमानों के अंदर भी कई फिर्के हैं तथा उन्होंने दूसरे संप्रदायों और संगठनों के साथ भी मिल कर काम किया है अर्थात् मुस्लिम भावना का घनाए रखत हुए भी उन्होंने लोकिक या असाप्रदायिक प्रवृत्ति दिखाई है।^{२१} यद्यपि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अभी भी गिरावटें और गिरावटें बनी हैं फिर भी राजनैतिक स्तर पर उनका सहयोग और शिरकत बढ़ रही है। राजनैतिकीकरण के क्रम में सत्ता और विवाद भी होते हैं परंतु यह सद्यः अधिकारप्राप्ति और नए उठने वाले वर्गों में भी होता है। इस प्रकार, जातियों के राजनीति में प्रवेश करने की गति प्रक्रिया का विश्लेषण ऊपर किया गया, वह कुछ अंतर के साथ अल्पसंख्यक समुदाय और अनुसूचित जातियों और जादिस जातियों पर भी लागू होती है।

नव्य एकीकरण की प्रक्रिया

मुख्य प्रश्न निम्न पर हमने विचार किया यह है कि किंग हॉम उन विभिन्न जातियों और संप्रदायों में राजनीति में भाग लेने के फलस्वरूप सामूहिक या राष्ट्रीय

२१. माइरा बोथर और रानी बोथरी संपादित—'इण्डियन बोमिंग विहेविअर' (वर्ग १९६५) में रानी बोथरी और तरुण शाह 'प्रासिडेंट पेंड मिनिमम ऑफ डेयुनिटी बोमिंग द केम ऑफ बोथर' १२१। पृ. १७३-७४ में 'फेडरल पार्लियामेंट इन एन इंडियन स्टेट-द कांफ्रेंस पार्टी इन उत्तर प्रदेश' (बकले, १९६६)। अ. पा. ६-७, वरीरुदीन अहमद। 'कांफ्रेंस पार्टी इन अमरकोश-ए केम स्टडी इन वन पार्टी डेमोक्रेसी' (पार्टी सिस्टम ऑफ इण्डिया, अमेजन पेपर्स) सेंटर फॉर स्टडी ऑफ देन सोसा नरिंदरी १९६७। इनके मूल के विवेचन के लिए केंब्रिज ऑफ एनेटोरल रीज इन इंडिया' में 'एनफोरस पार्टी सिस्टम ऑफ बोमिंग इण्डियन' (नरिंदरी सेंटर फॉर स्टडी देन सोसा १९६९)।

भावना का उदय हुआ है और ऊँची पृथक्ता कम होकर उनका राजनैतिक एकीकरण हुआ है। अक्सर राष्ट्रीय भावना से और जाति या संप्रदाय की भावना के द्वंद्व या टकराव की बातचीत जाती है। लेकिन हमने देखा कि जहाँ जाति या कबीले की भावना का दबाने के बजाय उनको राजनैतिक दिशा देने की काशिश की जाती है, वहाँ राजनैतिक एकीकरण की संभावना बढ़ती है और जहाँ जाति या संप्रदाय के संगठन की अनुमति नहीं दी जाती वहाँ ये गलत रास्ते पर जाती हैं। हमने देखा कि किस प्रकार जाति के संगठन राजनैतिक रूप धारण कर लेते हैं और समाज व राजनीति में बाधा जोड़ते हैं।

समाज और राजनीति में बाधा जोड़ने की इस प्रक्रिया को नीबिकीकरण का नाम दिया जा सकता है। राजनीति के प्रभाव से भारतीय समाज में जो जड़बस्त परिवर्तन हुआ है, वह इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। जिस प्रकार 'संस्कृतीकरण' की प्रक्रिया के द्वारा समाज के दबे हुए समूह आगे आए और संस्कृत जातियाँ पाश्चात्त्यकरण के द्वारा आधुनिकता के ढाँचे में चली, उसी प्रकार नीबिकीकरण की प्रवृत्ति उन दोनों वर्गों को राजनीति में खींच रही है, जिससे पुरानी व्यवस्था खलम हो रही है और नये नीबिक संगठनात्मक आधार पर पुनर्गठित हो रही है। नई व्यवस्था का रूप अभी भी अस्पष्ट और विकासशील है।^{२२} परिवर्तन की इस प्रक्रिया में स्थानीय या सर्वोपयोगी और व्यापक निष्ठा का नया मिश्रण तैयार होता है, पुरानी जातिपंक्ति, व्यक्ति और समूह के हित में बाधक सिद्ध होती है और अशिक्षित जनसमूह को बोध होता है कि वह एक राजनैतिक पद्धति का अंग है और उसका उगम लगाव पैदा होता है।

दूसरी ओर कोई भी राजनैतिक व्यवस्था या पद्धति तभी स्थिर हो सकती है जब जनसमूह उसकी प्रक्रिया और प्रतीका का ग्राह्यता या काम निभालने के लिए नहीं, बरन वास्तव में अच्छा और उपयोगी समझकर अपनावे। अर्थात् नई विधियाँ और नए मूल्य परंपरा का रूप धारण कर लें। बिना रूढ़ियों या परंपरा के कोई समाज जीवित नहीं रह सकता और आधुनिकता के लिए वास्तविक चुनौती यह नहीं है कि वह परंपरा को कैसे नष्ट करे, बल्कि यह कि कैसे स्वयं परंपरा बन जाए।^{२३} जाति और राजनीति के प्रसंग में इससे दो अर्थ हैं। एक यह कि जाति के जो तत्त्व अनुपयोगी और मकीनता बढ़ाने वाले हैं वे खतम हों और वे तत्त्व

^{२२} पुनर्गठन की प्रक्रिया और जाति या परिवर्तन की भावना के सैद्धांतिक विवेचन के लिए देखें, डॉ एल मेठ और रजनी कोठारी 'सोशल चेंज पोलिटिकल इंटरग्रेशन ऐंड द वैल्यू प्रोसेस' इन्टरनेशनल राउटledge ऑन वैल्यू इन पोलिटिक्स में निबंध दुर्गोबिनिक, युगोस्लाविया (मीमियो, १९६५)।

^{२३} रजनी कोठारी, 'ट्रांजिशन ऐंड माडर्निटी रिवॉल्यूशन' - गवर्नमेंट ऐंड अपोनिशन, २, स ३ (मार्च १९६८)।

राजनैतिक संस्कार और सामाजिककरण

पिछले अध्यायों में हमने राजनीति विज्ञान की तुलनात्मक प्रणाली द्वारा भारत के ऐतिहासिक एवं साम्यात्मक आधुनिकीकरण की व्याख्या करने का प्रयत्न किया। किन्तु बिना भी राष्ट्र का राजनीतिक अनुभव उत्तरों परंपरा एवम प्रवृत्ति में निहित होना है। उसके स्थायी राजनीतिक संस्कार और उसकी बदलती हुई राजनीतिक असंतुलित के परस्पर मेल की व्याख्या करने पर ही हमें देश के विकासक्रम में योगदान यात्री दृष्टि को समझने का सारा मिल सकता है और उसकी सफलता या विफलता को ठीक से जानने में सहायता मिल सकती है तथा और अच्छे ढंग से उसकी भावी संभावनाओं का अनुमान किया जा सकता है।

हमें ये प्रश्न पूछने हैं — क्या देश के आधुनिक विकास से इसका युगा पुरानी पृष्ठ समस्याएँ हल हो सकेंगी? क्या इसका युगा पुराने देश की अपनी कमजोरियाँ दूर करने और आधुनिक मनार में स्थायी ग्रहण करने में सहायता मिलेगी या इसकी सांस्कृतिक और मानसिक स्थिति इसमें बाधा होगी। हमें एक ओर व्यक्तिगत और सांस्कृतिक परिवर्तन को देखना है और दूसरी ओर यह देखना है कि आधुनिक राजनीति और आर्थिक प्रवृत्तियों से क्या सम्यक्तत्त्व परिवर्तन हो रहे हैं और व्यवहार की क्या परिपाटियाँ बन रही हैं और क्या आवश्यक समस्याएँ सामने आई हैं जिनका मुलभूत जगह है।

हम भारत में होने वाले राष्ट्रनिर्माण के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर एक नजर डालेंगे और इसके विशिष्ट राजनीतिक संस्कार के बारे में कुछ सिद्धांत उपस्थित करेंगे तथा इनका मूल सामाजिक और सांस्कृतिक संस्कारों से जोड़ेंगे। इसके साथ ही विचार करेंगे कि किस प्रकार एक नयी राजनैतिक संस्था के उदय से प्राचीन परंपरा की नयी व्याख्या की जा रही है और प्राचीन व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन हो रहा है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत शायद एकमात्र देश है, जिसने बिना किसी विशिष्ट राजनैतिक व्यवस्था का सहारा लिए अपनी सांस्कृतिक परंपरा को बचाया रखा है। अथ प्राचीन समय ताजा के विपरीत भारत की एकता किसी राजनैतिक सत्ता या व्यवस्था पर आधारित नहीं रही, प्रत्युत वह इस बात पर आधारित रही कि उसके सांस्कृतिक प्रतीक, आध्यात्मिक मूल्य और आचारविचार जनसाधारण के जीवन में व्याप्त हो गए। भारत की जात्मा राजनैतिक नहीं सांस्कृतिक रही। अवश्य ही भारत के सांस्कृतिक रूप के साथ साथ उसका एक लौकिक या राजनैतिक रूप भी रहा। सांस्कृतिक और राजनैतिक आध्यात्मिक और लौकिक अंगों की परस्पर प्रतिप्रिया के द्वारा ही वह बदरते युग के साथ अपने का बदलता रहा। फिर भी भारत के इतिहास में सरकार और समाज के बीच सदा एक पाथक्य रहा और भारतीयता का भाव राजनैतिक नहीं सांस्कृतिक रहा।

कोन-से ऐसे ऐतिहासिक तत्त्व हैं जिनके कारण लगातार राजनैतिक उथलपुथल के बावजूद भारत की संस्कृति अविच्छिन्न चलता रही, इसका ठीक पता नहीं।^१ परन्तु एक बात स्पष्ट है कि बहुत पहले ही भारत में आध्यात्मिक और लौकिक या शासकीय क्षेत्र अलग जलम हो गए थे। साथ ही यहाँ धर्म और राज्य में वह संघर्ष नहीं हुआ जो पश्चिम के देशों में इतना देखने को मिलता है। साथ ही दोनों में बराबर व्यवहार और परस्पर संघर्ष भी रहा। इसका कारण कुछ तो यह था कि यहाँ राजसत्ता विदगिया की रही और साधारण जनता अपने रास्ते चलती रही। साधारणतः विदेशी विजेता भी यहाँ सामाजिक और धार्मिक रीतिरिवाज में दखल नहीं देते थे।

राजनैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र एक दूसरे का प्रभावित करते थे और शासक तथा धर्मगुरुओं में संघर्ष रहता था। इस प्रकार भारतीय संस्कृति ने तत्त्वों को ग्रहण करती रही। कुछ मूल तत्त्वों को बनाए रखते हुए, विशिष्ट क्षेत्रों में परिवर्तन का विरोध यहाँ कभी नहीं किया गया। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में बौद्ध, वैष्णव, सिख मत के साथ साथ पुरानी परंपरा के समर्थन के संकराचार्य के जैसे आंदोलन यहाँ होते रहे। इन दोनों प्रकार के आंदोलनों के द्वारा भारतीय संस्कृति के कुछ मूल तत्त्वों का पुनः प्रतिपादन होता रहा। इस कारण जब १९वीं शताब्दी में यहाँ सुधार के आंदोलन चले तो उनको समाजकी व्यवस्था में उथल-पुथल लाने के प्रयत्न के बजाय हिंदू समाज में घुम आइकुरीतिया का दूर करने का प्रयत्न समझा गया, जैसे पुराने जमाने के धार्मिक आंदोलन थे।

पुरानी जड़ समाज व्यवस्था की टक्कर जब जाधुनिकता की शक्तियाँ से होनी

^१ फिर भी देखें *इन्दू नामन ग्राउन*, "द वेस्ट ऑफ कल्चरल कंस्टिचुरल द शिफ्ट", जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज़, २० अगस्त ६१।

है, तो उथलपुथल होना स्वाभाविक है। परन्तु भारत में परंपरा और परिवर्तन की प्रवृत्तियाँ बग़ैर साथ-साथ चलती रही हैं और परंपरा नए तत्त्वों का ग्रहण करती रही है। एक विदेशी पक्षधर का कहना है कि भारत की आधुनिकता को उसकी परिवर्तनशील परंपरा के सदृश में देखना पड़ेगा।^२ भारत की सांस्कृतिक परंपरा की अविच्छिन्नता के कारण ही यहाँ तात्त्विक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन होने में कठिनाई नहीं हुई। क्योंकि यहाँ की मस्तिष्क किसी विशिष्ट राजनैतिक व्यवस्था के साथ बंधी नहीं थी। दूसरे, तीव्र या राजनैतिक परिवर्तन का बीच में यहाँ की संस्कृति अविच्छिन्न बनी रही। तीसरे राज्य व्यवस्था व परिवर्तन का यहाँ महत्त्व न देने की प्रवृत्ति रही। इस कारण राजनैतिक परिवर्तन का विरोध करने के बजाय, उनका स्वीकार करने और उनके जनरल हूर फोर कर लेने की प्रवृत्ति रही। इन परिवर्तन का भारतीयता के लिए खतरनाक नहीं समझा जाता था, क्योंकि भारत तीयता का मूल तत्त्व राजनैतिक नहीं था। दूसरी पुरानी समस्याओं में जहाँ राजनैतिक व्यवस्था को लंबी परंपरा रही और जहाँ समस्या राज्यव्यवस्था में अभिन्न रही, वहाँ राजनैतिक परिवर्तन का विरोध बहुत समय तक चला और जब विरोध विफल हुआ, तो परिवर्तन के साथ राष्ट्रीय अपमान और पराजय की भावना भी आयी।^३ दूसरी ओर भारत में आधुनिक समय में भी विदेशी राजनैतिक और आर्थिक संस्थाओं और विधियों का ग्रहण राष्ट्रीय स्वाभिमान के विरुद्ध नहीं समझा गया।

भारत में सांस्कृतिक और राजनैतिक क्षेत्रों को जलजल रखने के साथ विभिन्नता को स्वीकार करने की भी परंपरा थी। जाचार-विचार की विभिन्नता को यहाँ बरा नहीं समझा जाता था। इसलिए लोकतंत्र की विचारधारा, यहाँ की सामाजिक क्षेत्र में स्वतंत्रता, स्थानीय रीतिरिवाज को बनाए रखने की आजादी, तथा सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में स्वतंत्रता की परंपरा से मेल खाती है।

अब नए देश में लोकतंत्र और चुनाव के कारण बड़ी-बड़ी और जातियाँ में द्वंद्व को प्रोत्साहन मिला है। लेकिन भारत में यह नौबत नहीं आई, क्योंकि जहाँ जाति विरादरी या संप्रदाय के प्रति निष्ठा काफी समय तक राजनैतिक निष्ठा में भिन्न रही। जब अंत में यहाँ राष्ट्रीय राजनैतिक व्यवस्था स्थापित हुई, तो यह एक नई अखिल भारतीय व्यवस्था थी, किसी पुरानी जाति या क्षेत्रीय व्यवस्था का

२ जे सी हेस्टर मान, "ट्रेंडिंग इन आदर्न इंडिया"। इस लेखक का कहना है कि पश्चिमी विचारक अपने यहाँ के अनुभव को भारत पर लागू करते हैं, "संसार के परंपरा और आधुनिकता में विरोध या द्वंद्व की कल्पना करते हैं।

३ ज्ञान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देखें- लुशिंग डब्ल्यू पार- "सिपिटि आफ चार्नीज पोलिटिक्स ए माइक्रोलाजिकल स्टडी आफ अगारिटी क्रॉनिम इन पोलिटिकल टेक्स्चर्स" (केंब्रिज-मैसा १९६८)।

विस्तार नहीं थी, जैसा कि अग्रे कुछ नए दशों में हुआ।^४ बाद में जब इस नयी राजनैतिक व्यवस्था का विस्तार और विवेकीकरण हुआ तब प्रात और भापा की भावना विकसित हुई। किंतु तब तक नयी अखिल भारतीय व्यवस्था भी अच्छी तरह स्थापित हो चुकी थी। नयी प्रातीय या भाषिक निष्ठा पुरानी जातीय और सांप्रदायिक निष्ठा से भिन्न है। पहली निष्ठा नेताओं की राजनीति को प्रभावित करती है, जबकि दूसरी जनसाधारण का राजनीति को। जो पर्यवेक्षक प्रात और भापा के आग्रह को राष्ट्रीय एकता की भावना में बाधक मानते हैं वे पश्चिम की स्थिति का दृष्टि में रखते हैं जहां राष्ट्रीयता के अलावा और कोई निष्ठा स्वीकार नहीं की जाती।^५ जबकि भारत में राष्ट्रीय निष्ठा स प्रदेश या भाषा के प्रेम या निष्ठा का विरोध नहीं समझा जाता।

भारत में व्यापक निष्ठा राजनैतिक नहीं सांस्कृतिक थी, इस कारण नयी राजनैतिक व्यवस्था को अपनी जड़ जमाने में आसानी हुई। नयी व्यवस्था ने नए नेतृत्व को जन्म दिया जो नये युग के विचारा और आदर्शों से प्रभावित थे और अपने देश का उत्ती के अनुसार पुनर्स्थापन करना चाहते थे। परंतु भारत के ये आधुनिक मस्कर्ता पुरानी परंपरा के शत्रु या विरोधी न थे। गांधी का शहर का बौद्धिक वर्ग को यही संदेश था कि गांधी में जाओ और गांधी का शहर से, नई व्यवस्था से संबंध जोड़ो। आज भी इस बात का महत्व कम नहीं हुआ है। आर्थिक विकास और वित्तीय अस्वाधिकार ने इससे महत्व को और बढ़ा दिया है।^६ भारत के परंपरागत उच्चवर्ग ने सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की आजादी को कायम रखते हुए, नयी राजनैतिक व्यवस्था को स्वीकार किया है।

पुरानी रीढ़-वेदी के संबंध पर आधारित जाति की पंचायत का स्थान नए जातीय संगठनों और सभा ने लिया। इस प्रकार पुरानी व्यवस्था का रूप धीरे धीरे व्यापक बना। इसके फलस्वरूप देश में एक लोकिक या राजनैतिक व्यवस्था विक

४ इसका कारण यह था कि अंगरेजों ने भारतीय नेताओं से व्यवहार रखा और सत्ता उन्हींको सौंपी, जब कि अफ्रीका में उन्होंने क्वाकशी सरदारों का दावा माना। यदि भारत में भी पुराने रानाओं के मंडल को सत्ता सौंप जाती तो यहाँ भी पुराने झगड़े फिर शुरू हो जाते। १९३५ के ऐक्ट में अंगरेजोंने यही करना चाहा था।

इस ऐक्ट की व्यवस्था को अस्वीकार करके कांग्रेस ने सही काम किया और देश की एकता का रक्षा की।

५ ल. डब्लू. पाइ 'द पोलि कल्चर ऑफ इंडिया फ्रॉम आरिना-क्राइमिंस ऑफ आरिनिटा ऐंड अवारिटी कपीकेश माल और रजनी कोठारी संपादित 'इंडिया फ्रॉम आरिना कंट्रस्ट इन डेवलपमेंट'।

६ नेहरू के शब्दों में राष्ट्रनिर्माण के काम में गांधीजी की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि शहर के शिक्षित लोगों की सुदृढ़ता को बने दूर करे। देखें-आर्द्रे मालरूम, 'एंगी-मेमायस' (न्यूयाक १९६८)।

सित हो रही है, जो जाति या मगप्रदाय की गौण व्यवस्थाओं के बीच में दखल नहीं देती। इस प्रकार भारत उम्र उथल-पुथल से बच गया जो उन देशों में हुई, जहाँ राजनैतिक क्षेत्र को सबसे ऊँचा स्थान दिया गया और अन्य क्षेत्रों के महत्त्व को उतम करने की कोशिश की गयी।

परन्तु स्थानीय और जातीय निष्ठाओं का अधीनता में रगने वाली एक व्यापक राजनैतिक निष्ठा के अभाव में कुछ नुस्खान भी हुआ। मासुटिक क्षेत्र को महत्त्व देने और राजनैतिक क्षेत्र में उदासीन रहने के कारण भारत में ग्रामीण कृषिप्रधान व्यवस्था का बहुत महत्त्व दिया गया। (बाबजूद पुराने बड़े नगरों की उपस्थिति के) केन्द्रीय राजनैतिक सत्ता के न होने से नाग स्थानीय और जातीय निष्ठाओं के दायरे से निरत बन गावदेशिक निष्ठा का विकास करने में असमर्थ रहे। उनमें नागरिक या राजनैतिक जिम्मेदारियों का स्वीकार करने, राजनैतिक व्यवस्था को समायोजन देने की ओर जानिपाति और गांव में ऊपर उठकर राष्ट्र या देश की बात मानने की प्रवृत्ति न पैदा हो सकी। हमारे माथ ही सामूहिक और निर्व्यक्तिक सत्ता के प्रति उनके मन में शंका और अविश्वास भी बना रहा। जय चौकिय राजनैतिक सम्पत्ताओं की तरह यहाँ राष्ट्रीय इतिहास के प्रति गौरव और हमसे उत्पन्न होने वाले राष्ट्रीय स्वाभिमान के भाव की भी कमी रही। हम देखेंगे कि यहाँ पारिवारिक जीवों और आध्यात्मिक तथा धार्मिक परंपरा में यह प्रवृत्ति कैसे बढ्मूल रहा।

नागरिकता की कमजोर भावना के साथ साथ यहाँ न तो राजसत्ता से अधिक अपेक्षा की जाती है और न उसकी समायोजन देने की प्रवृत्ति है। इसी से यहाँ सरकार और राजनैतिक व्यवस्था की त्रुटियों की साधारणतः उपेक्षा की जाती है।

सरकार के प्रति उदासीनता का एक और परिणाम यह भी होता है कि सत्ता के बाहर के वर्गों में मध्यम सुलगता रहता है और इन संघर्षों और विवादों का सुलझाने की राजनैतिक मशीनरी नहीं स्थापित होती। विवादों और मतभेदों का सुलझाने के उपाय उनका सहन करने की भारतीय प्रवृत्ति हानिकार सिद्ध होती है।

जब ऐसे समाज पर आधुनिक राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय प्रभाव पड़ने लगते हैं तो राष्ट्र के विभिन्न अंगों में, जो अब तक काफी स्वायत्तता का उपभोग करते रहे हैं सामंजस्य बैठाने और एकता लाने की समस्या तीव्र रूप धारण कर लेती है। अर्थात् जहाँ भारत में ऐसी राजनैतिक व्यवस्था का निमाण सरल है, जिसमें विभिन्न अंगों को काफी आजादी रहे वहाँ राजनैतिक एकता और दश की सरकार के प्रति वक्तव्य की भावना का विकास कठिन हो जाता है।^७ साथ ही यह लक्षण

^७ एस एन आर्सेनस्टाट, ट्रेडिशन ऐंड मोडर्न आफ रेस्पान्स टु माइनरिटी - 'इन्डिया टु-दाय' , पृ. १११।

भी दिखाई दे रहे हैं नि जातिव्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहे हैं, राजनैतिक दल तथा अन्य मध्यवर्ती संस्थाओं का जो विनाश हो रहा है और राजनैतिक नेताओं और मुखियाओं की जो परपरा कायम हो रही है, उससे देश के राजनैतिक केन्द्र का बल मिले। तथा इस बीच जाति-विरादरी जैसी आदिम संस्थाओं के स्वतन्त्र अस्तित्व और उसने फलस्वरूप सरकार पर कम दबाव के कारण नयी व्यवस्था को जड़ जमाने में सहायता मिले।

राजनैतिक संस्कार के तत्त्व

हमने देखा है कि इस विशाल देश में एकता का गूँथ सांस्कृतिक समानता और उससे उत्पन्न होनेवाले आचारविचार रहे हैं। हम अब यह देखना है कि इस सांस्कृतिक और सामाजिक समानता में कौन से तत्त्व हैं जिनका राजनैतिक महत्त्व है और जो आधुनिक राजनैतिक प्रवृत्तियों को प्रभावित कर सकते हैं।

(१) विचारभेद और अस्पष्टता के प्रति सहिष्णुता

भारत में विचार-बहुल्य की स्वीकार करने की प्रवृत्ति रही है। भारतीय समाज में बहुत-से विरोधी विचार वाले और भिन्न भिन्न रीतिरिवाज वाले तत्त्वों को स्थान दिया गया है। विभिन्न तत्त्वों को समाज में स्थान देने के लिए यहाँ विभिन्न जातियों या वर्गों के विभिन्न धर्म या कायों को स्वीकार किया गया है और उसी हिसाब से समाज में उनका पद निर्धारित किया है। आध्यात्मिक या दार्शनिक रूप से यहाँ यह सिद्धांत माना गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने काम के धूल पर आत्मविकास करता है और मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करता है। भारत पर विभिन्न विचार धाराओं और संस्कृतियों का आक्रमण होता रहा है और फलस्वरूप यहाँ विचारों की भिन्नता का स्वीकार किया गया। यहाँ नये मता और विचारों का प्रवर्तन होता रहा और भिन्न भिन्न राजनैतिक व्यवस्थाओं का भी प्रचलन होता रहा। इसके फलस्वरूप यहाँ व्यक्तियों और समूहों को आचार विचार की काफी स्वतन्त्रता रही। यहाँ नविकृता और धर्म को देशकालसापेक्ष माना गया। यहाँ यह बात नहीं मानी गई कि सब समझ और सब धर्मों की वृत्ति के लोगों के लिए एक ही धर्म या नैतिक नियम है। इससे बजाय यहाँ यह माना जाता है कि विभिन्न स्थिति और व्यवसाय अर्थात् विभिन्न वर्ण और जाति का विभिन्न नैतिक कर्तव्य या धर्म है। "इस दृष्टिकोण के कारण विचारों के सघटन में बड़ी अस्पष्टता रही है और इस अस्पष्टता तथा द्वैधता का सहन और स्वीकार करने की प्रवृत्ति रही है। वास्तविक जगत की अनिश्चितता और वैविध्य के परिप्रेक्ष्य में जीवन को टालने

या सामाजिक स्थिति का घम माना गया। जब ऊँच-नीच का स्वाभाविक समझा गया तो नीची जातियों के लिए ऊँची जातियों का सम्मान करना, सामान्यव्यवस्था को स्वीकार करना और बिना विरोध या विद्रोह किए, अपना टोटा या नीचा काम करते जाना भी स्वाभाविक हो गया। इससे सामाजिक विप्लव की रोक हो गई परंतु इसका परिणाम यह भी हुआ कि सामूहिक जिम्मेदारी की भावना न रही। लोग भाग्यवादी और अवगम्य हो गए। साधारण आदमी का हल यह रहा कि 'कोउ नप हाय हमें का हानी।' राज्य या राष्ट्र के प्रति कृत्य की भावना न विकसित हो सकी। समाज के अधिकारियों या व्यवस्था के प्रति उदासीनता और अनास्था उत्पन्न हुई। लोग का भाव था कि 'समय को नाह दोस गुसाई'। 'राजनैतिक' उल्लसपुल्ल के समय यह भाव स्पष्ट हो उठता था।

ऊपर कहा जा चुका है कि यहाँ विचारों की स्वतंत्रता और समाजव्यवस्था की बढोढ़ता रही। परंतु जब आधुनिक युग के प्रभाव से जातिपाति का ढांचा और आचार की कट्टरता टूटने लगते हैं तब विचारों की सहिष्णुता, चाहे अस्थायी तौर पर ही सही, भी टूटने लगती है और सब पर एक विचारधारा लादने की प्रवृत्ति उभरती है। भारत में शाहरी शिक्षित और राजनैतिक रूप से नचेतन वर्ग में यह प्रवृत्ति लक्षित हो रही है।

फिर भी, ऐसा लगता है कि विचारों की सहिष्णुता की प्रवृत्ति नए राष्ट्र के विकास को भी प्रभावित करेगी। अल्पसंख्यकों के प्रति उचित व्यवहार, भिन्न-दलों से जोड़ और राजनैतिक मतभेद और विरोध की स्वतंत्रता देने में यही प्रवृत्ति काम कर रही है। हो सकता है कि पुरानी व्यवस्था के परिवर्तन और नयी 'राजनैतिक' संस्थाओं और प्रथाओं के निर्माण के कारण अस्थायी रूप से लोगों में अरक्षा और अस्थिरता की भावना उत्पन्न हो और इस कारण असहिष्णुता की प्रवृत्ति प्रकट हो, पर अंत में सहिष्णुता और अपने-अपने ढंग पर चलने की स्वतंत्रता की पुरानी परंपरा की ही जीत होगी, जिससे कारण भारतीय संस्कृति युग के थपड़े लाकर भी जीवित रही है। वास्तव में आधुनिक राजनैतिक परिवर्तन को स्वीकार करने में यही प्रवृत्ति सहायक हुई है। एक सम्भाव्य सहयोगी के शब्दों में—देखना यह है कि लोगों को राजनैतिक परिवर्तन का जो ऐतिहासिक अनुभव रहा है, वह इस नयी राजनैतिक व्यवस्था को अपनाने में वहाँ तक सहायक होता है और उनकी जातिविवादों और संप्रदाय आदि के प्रति निष्ठा कैसे राष्ट्रीय निष्ठा में परिणत होती है। परिवर्तन की चुनौती का किस प्रकार सामना किया जाता है यही राजनैतिक संस्कार का तत्त्व है।^{१२}

^{१२} आशीस नन्दा, द कान्फ्रेंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट एरान्ड टर्विंग पाहुल्लि (दिल्ली-सेंटर फार द स्टडी ऑफ डेव सोसा १९६८)।

(२) विखंडित अधिकार

जीवन की इस पद्धति का एक आवश्यक तत्त्व यह माना गया है कि सत्ता विखंडित, विवेचित और अस्थायी या आवतक है। भारतीय कुटुंब, नातेदारी, जाति और गांव के जीवन में यही बात लागू होती है। भारत की समाजव्यवस्था में ऊंच-नीच की श्रेणियां बनी हुई हैं और हर श्रेणी के अधिकार और बत य बटे हुए हैं। जत्र अधिकार क्षेत्र के त्रार में संशय या विवाद पैदा होता है तभी किसी बाहरी सत्ता को इसके निणय के लिए बुलाया जाता है। बाहरी सत्ता का यह हस्तक्षेप इस प्रकार स्थिति विशेष में और अस्थायी होता है लगातार नहीं।

सत्ता का काम निणय या निपटारा करना है। (जिसका अर्थ यह होता है कि विचार या नियमनिणय का कार्य राजनीति का सार तत्त्व है)। यह वारणा राज्य के क्षत्र में भी लागू की गयी। राजा या उसके प्रतिनिधि का मुख्य राजकीय काम परियाना को सुनना और उनका फैसला करना था। शेष बातें म वह दमन न दता था और समाज अपने रास्ते चलता था। मुखिया या नेता का भी यही काम था^{१३} अर्थात् विवाद का निपटारा करना, चाहे वह मुखिया धर्मगुरु हो या विरादारी या गांव का चौधरी। गावा के अंदर और दूसरे गावा से जो झगडे होत रहते हैं, उसको देखते हुए यह काम बड़े महत्त्व का था लेकिन इस सत्ता या अधिकार का प्रयोग लगातार नहीं होता था और इमने सस्यागत रूप नहीं धारण किया था।^{१४} समाजव्यवस्था अर्थात् जातिविरादरी और गांव के विधि विधान लोगों के जीवन में ऐस अंगोष्ठित हो चुके थे कि रोजमर्रे के झगडे बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप क निपटत रहते थे। जब कभी स्थिति हाथ के बाहर हो जाती थी या विधि विधान के बारे में अनिश्चय या संदेह रहता था, खास कर परिवर्तन के काल में तभी बाहरी सत्ता की दुहाई दी जाती थी।

ऊँचे अधिकारी या सत्ता के हस्तक्षेप की परंपरा आधुनिक युग में भी चली आई है और राजनीति में जिलाधीश या कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जैसे राजनीतिक नेताओं की मध्यस्थता का काफी महत्त्व है।^{१५} अंग्रेजों के जमाने में भी यही स्थिति थी और आज भी है। इसी परंपरा के कारण औद्योगिक विवाद संवधी कानूना में भी

^{१३} सेट्टलर अमेरिका में प्रयुक्त 'लीडर' शब्द का भारतीय भाषाओं में बोल प्रयास नहीं। अर्थकाल 'नेता' शब्द को छोड़कर इसके अन्य पर्यायवाची शब्द आदिम विरादरी या धर्म से संबंधित हैं।

^{१४} भारतीय गांव की दलबंदी या भगना—तम्रार के बारे में देखें—बनाइ ने सींगल और अलन बाल्म, 'द पर्वनिव पैक्शनलिज्म' अमेरिकन एन्थ्रोपॉलॉजिस्ट, ६२ स ३, जून १९०० और भी, अलन बाल्स, 'गोपालपुर—ए माउथ इन्विजन विथिन' (न्यूयार्क १९६२)।

^{१५} देखिए—माइरन बानर 'टेडिशनल रोल परफार्मेंस ऐंड द डेवेलपमेंट ऑफ माइन पॉलि पांन'—द इंडियन कैम कनल ऑफ पॉलि २६ स ४ १९६४।

मध्यस्थता को ऊँचा स्थान दिया गया है।^{१६}

अशत इसी परंपरा या मतावृत्ति के कारण ऐसे मामला का निपटान में भी सरकार या सरकारी नेताओं के पास गुहार की जाती है, जो अन्य देशों में सरकार के कार्यक्षेत्र के बाहर समझे जाते हैं।^{१७} चूंकि सरकार की कल्पना मध्यस्थ या न्यायाधीश के रूप में की जाती है इसलिए स्थानीय विवादों को ऊँचे अधिकारियों के सामने पेश किया जाता है और उनसे फैसले को स्वीकार किया जाता है। इसलिए यह उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के अंदर लगातार झगड़े—लड़ाई बजाय ऐसा बहुत कम हुआ है कि स्थानीय विवादों में ऊँचे स्तर के नेताओं का फैसला न माना जाए (झगड़ा को इस प्रकार निपटाने की पूरी मशीनरी है)। इससे स्थानीय समुदायों को व्यापक राजनीतिक क्षेत्र में आने का मौका मिलता है। ऊँचे नेता भी ऊपर से फैसले सुनने के बजाय समझौता कराने पर ज्यादा और बजाय एक पक्ष को दबाने के, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। संगठित वर्गों और हिता के संघर्ष के बजाय दो पक्षों में समझौता कराने की यही प्रवृत्ति भारत में मौलभाव या सौद बाजी का स्थान लेती है।^{१८}

कौन-से झगड़े कहा ले जाए जायें, इस विषय में काफी छूट है। इस कारण सत्ता बिलंबी रहती है और उसका प्रयोग भी लगातार नहीं होता। इससे सरकार के क्षेत्र का विस्तार भी चुपचाप होता रहता है। इस प्रकार वर्तमान व्यवस्था के अंदर ही काम करते हुए और बिना जबदस्ती किए सरकार काफी परिवर्तन लाने में सफल होती है। सत्ता बिकेंद्रित या बिलंबी रहती है और समाज की वास्तविक स्थिति के अधिकाधिक अनुरूप बनी रहती है।

(३) आदेश और राजनीति

झगड़ा को निपटाने के साथ साथ प्रमुख वर्ग की समाज में एक भूमिका रही। उसका काम नैतिक मानदंडों की प्रतिष्ठा करना भी था। चीन जैसी अधिक केंद्रित व्यवस्था में राज्य का नैतिकता का सराफ और नागरिकों को नैतिक मार्ग पर

१६ चार्ल्स ए. मायर्स—'लेबर प्राब्लम्स इन इन्डियाना' जर्नल ऑफ इंडिया (नेत्रिज मसा १९५८)। अमेरिकी के विचारों में मध्यस्थता के महत्व के बारे में डॉ. वा. गिरि—'लेबर प्राब्लम्स इन इंडिया' (नवंबर १९५८) और अशोक मेहता—'द मीडिएटिंग रोल ऑफ द ट्रेड यूनियन इन अन्डर डेवेलपिंग इकोनॉमिज' टेबल एंड रैंड क्लब ऑफ अक्टूबर १९५७) झगड़ों के सामान्य कानूनी पक्ष के बारे में बर्नार्ड एस. बोहान—'एथ्रोपॉल नोट्स ऑन डिस्प्यूट्स ऐंड ला इन इंडिया' अमे. एथ्नो ६७ स. ६ दिस १९६४।

१७ अशत इसलिए कि सत्ता की ओर देखने की आदत के कारण स्थानीय मामलों में उच्चतर नेताओं का प्रभाव बड़ा है। सरकार और ऊँचे स्तर के नेताओं ने जो महत्वपूर्ण भाग लिया है उस पर यहाँ विचार किया गया है।

१८ मादरन चीनर ।

चलाने वाला माना गया है । १° लेकिन भारत में समाज को राजा या शासन स्वतन्त्रता की परंपरा रही है और यहाँ राज्य को नैतिक मामला में इतनी शक्ति नहीं दी गई (कौटिल्य के वाक्य) । २° इसके बजाय यहाँ एक विशेष प्रमुख वग अर्थात् ब्राह्मण वग को नैतिकता या धर्म का संरक्षक व प्रवक्ता माना गया । इसके साथ ही शासक या राजा से भी अपेक्षा की गयी कि वह ऐसे महान और वीरता के कार्य करे, जिस से उनकी प्रतिष्ठा अवतार या देवताओं के समान हो । ऐसे राजा या लोकनायक की प्रतिष्ठा और प्रभाव ब्राह्मणों या ऋषियों से कम नहीं होता था । ऐसे राजा ब्राह्मण ऋषियों के समकक्ष होते थे ।

उल्लेखनीय यह है कि आज के राजनीतिक नेताओं के रूप में परंपरागत ब्राह्मण और आधुनिक लोकिक नेताओं के तत्त्वा का मेलन देखने को मिलता है । आज के राजनीतिक नेता एक अर्थ में आधुनिक भारत के ब्राह्मण हैं । इनकी इस प्रतिष्ठा का कारण कुछ तो यह है कि इन्होंने महान परिवर्तनों को लाने में कारिणी भूमिका अदा की है । दूसरे, महात्मा गांधी और नेहरू जैसे नेताओं का महान व्यक्तित्व है । तीसरे, आज के सामाजिक जीवन में इन नेताओं का अप्रतिम प्रभाव है । इसका एक परिणाम यह है कि नेता को नैतिकता का भी संरक्षक माना जाता है और उसे उपदेश की भाषा में ऊँची ऊँची बात करनी पड़ती है और ऐसे सब चीजें आश्वासन देने पड़ते हैं, जो सभी जानते हैं कि असंभव हैं । भारतीयों की दृष्टि में आदर्श नेता वह है जिसमें ज्ञान और क्रम दोनों का संगम हो जो विचारक होने के साथ साथ क्रम भी हो । इसीलिए यहाँ नेहरू जैसे व्यक्तियों की इतनी प्रतिष्ठा और प्रभाव है । इसलिए यहाँ आज के नेताओं से ऐसी बातों की अपेक्षा की जाती है जो राजनीतिक क्षेत्र के लोगों से नहीं की जानी चाहिए । दूसरी ओर इसके कारण आदर्श और यथार्थ में नेता की कथनी और करनी में जो अंतर है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दी जाती । इसीलिए हर क्षेत्र में गुटबंदी और फूट हाने पर भी ऊपर से सहमति या आम राय पर जोर दिया जाता है । इसीलिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध बेहद शोरगुल मचाने पर भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने की या उसे रोकने की कोई खास कोशिश नहीं की जाती ।

१९ रीनकोट-पूर्वोक्त । पृष्ठ - ' द रिपब्लिक ऑफ आधुनिक पाकिस्तान ' ।

२० कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य को सर्वशक्तिमान जैसा माना है । यदि राजा चाहें कि मित्रों के हमले के बाद फैला अराजकता में मग्न शासक का आवश्यकता बहुत अधिक थी । इस अर्थ में अर्थशास्त्र की तुलना हॉम्स के ' लेविथियान ' से की जा सकती है । परंतु हॉम्स का कल्पना, जिसमें राज्य एक सजीव मनुष्य है, जो अपने अंगों से भाग स्वतंत्र है, प्राचीन भारत में जोर नहीं पकड़ पाया । पृष्ठ वाक्य - ' द बहरी डेट वाच इंडिया ' (एडन १९५४) । रत्नसामी - ' एमशम ऑफ गवर्नमेंट - क्राफ्ट ' (एडिजियन अर्थशास्त्र फार कम्पेरेरी रीजम ' (१९६२) ।

नैतिक वृत्ति से सबधित एक प्रश्न यह भी है कि समान उद्देश्य से एक साथ काम करने में व्यक्ति और समूह एक दूसरे पर कहा तक भरोसा कर सकते हैं। यहाँ हिंदू मनोवृत्ति की एक विचित्र विशेषता है, एक दूसरे पर सदेह और अविश्वास की। मिल कर कोई काम किया जा सकता है, इसमें हिंदू के मन में हमेशा दूसरों के प्रति संशय रहा है, पास कर सरकार या शासन के प्रति शका और अविश्वास।^{२३} ऊँचे तबके के लोग भी चाह राजनीति में या अन्य ऊँचे पेशा में लोगो को अपने सहयोगियों की ओर से शक रहता है। यहाँ लोगो के लिए बराबरी के दर्जे पर दूसरे सहयोगियों के साथ काम करना बर्तन है, मातहत या ऊपर रह कर काम करने में उन्हें आसानी रहती है। सहयोगी दलों के साथ गठबंधन में हमेशा अविश्वास और अनिश्चय बना रहता है कि कब तक यह सहयोग चलेगा, सहयोगी या दूसरा व्यक्ति अपना करार पूरा करेगा या नहीं। इस परस्पर अविश्वास का कारण एक बड़े या श्रेष्ठ व्यक्ति, नेता और गुरु के अनुगत होने की प्रवृत्ति रहती है।

लेकिन आधुनिक युग की आवश्यकताओं, और बड़े पैमाने पर चलन वाले सामूहिक कार्यक्रमों के कारण यह मनोवृत्ति बदल रही है। फिर भी यह ध्यान योग्य है कि सहयोग और मिलकर काम करने की भावना ज्यादातर वही प्रकट हुई है, जहाँ एक चमत्कारी या महान व्यक्ति के नेतृत्व में काम किया जाता है, बजाय वहाँ जहाँ एक बराबर के लोग मिल कर काम कर। गांधी और नेहरू के नेतृत्व में यही स्थिति देखने को मिलती है। गांधी को अपना स्थान छिने का भय नहीं था। मगर नेहरू दूसरे नेताओं का प्रभाव बढ़ते देख कर, उनसे अपना स्थान छिने का प्रतिशक्ति हो जाते थे।^{२४} नेहरू के बाद जब सामूहिक नेतृत्व का दौर आया तब ऊँचे से ऊँचे नेताओं में परस्पर अविश्वास और एक दूसरे से शंका की यही प्रवृत्ति दोख पड़ी। वास्तव में केन्द्रीय नेतृत्व के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है कि वे बराबर के साथी और सहयोगी के रूप में एक दूसरे का कहा तक भरोसा कर सकते हैं।

आज के भारत में सामूहिक मनोवृत्ति के विकास की चर्चा हम आगे फिर करेंगे। यहाँ हमें यह देखना है कि वचन में घर और समाज के संस्कारों से और बड़े होकर शिक्षा-दीक्षा से किस प्रकार उस विशिष्ट भारतीय मनोवृत्ति का विकास होता है जिसकी चर्चा हमने ऊपर की है।

२३ इस मनोवृत्ति का चित्रण फोस्टर के प्रसिद्ध उपन्यास 'ए पैमेज टु इंडिया' में हुआ है। और भी देखिए-मारिंस कार्टेयर्स- 'द टूनाम वान (छन्द १९५७)।

२४ टटनजी के कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने पर नेहरू की नाराजी और उनका विरोध और बरने अंतिम दिनों में कामगार योजना द्वारा सम्भावित प्रतिद्वंद्वियों की सफाई, इनके प्रमाण हैं, यद्यपि दोनों ही बार नेहरू की स्थिति की कोर वास्तविक खतरा न था।

लकी चौड़ी वाते करने की यह प्रवृत्ति आज सिद्धान्त बधारेने की प्रवृत्ति के रूप में प्रकट हुई है। याद रखना चाहिए कि भारतीय परंपरा में ऊँचे आदर्शों पर हमेशा जोर दिया गया है, भले ही वे चरितार्थ न हो सकें, और आदर्शों को व्यवहार में न ला सकने के कारण लोगों को ज्यादा दोष भी नहीं दिया जाता। इसके फलस्वरूप सावजनिक जीवन में जो ढोंग और पाखंड जा गया है, नेताओं को कहने और करने में, जादश और व्यवहार में, जो अंतर है, उसकी भारतीय लोग ज्यादा परवाह नहीं करते। व्यक्तिगत जीवन में भी व्यवहार के मानदंड बहुत ऊँचे रखे जाते हैं, परंतु उनका पालन न कर पाने पर ज्यादा परंपरागत नहीं अनुभव की जाती। इसी कारण भारतीय राजनीति में बात तो लकी लकी की जाती है, मगर उन पर जमल करने की ज्यादा कोशिश नहीं की जाती और इस पर कोई शम और विफलता या निराशा का बोध नहीं होता।

(४) विश्वास और अविश्वास

जादश और व्यवहार के बीच इस अंतर और भारतीय मानस की इस द्वधता से एक बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि जनसमाज ने सामाजिक और राजनैतिक मानदंडों को कहा तक ग्रहण किया है और सामूहिक प्रयत्न में कहा तक एक दूसरे पर विश्वास या अविश्वास किया जा सकता है। ध्यान रहे कि मनुष्य के स्वभाव के प्रति भारतीय दृष्टि ईसाई और कनफ्यूसी दृष्टि से भिन्न है। न तो यहाँ ईसाइया की तरह मनुष्य को स्वभाव से बुरा माना गया है, न कनफ्यूसी की भौतिकस्वभाव से अच्छा। इसलिए यहाँ यह नहीं समझा जाता कि समाज को व्यक्ति की स्वभावगत दुष्ट प्रवृत्तियों पर अकुश रखना चाहिए न यह कि समुचित सामाजिक संस्कार से मनुष्य की स्वाभाविक सद्प्रवृत्तियों के प्रकट होने का अवसर मिलेगा। भारतीय दृष्टि में धर्म या नैतिकता का सबंध मुख्य रूप से व्यक्ति से स्वयं है और उसका उद्देश्य आत्मोन्नति या मोक्ष है। यहाँ पाश्चात्य धारणा के अनुसार नैतिक कर्तव्य दूसरों के प्रति नहीं बल्कि 'मिल' के शब्दों में अपने प्रति है।^{२१} कम के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का कल्याण या मोक्ष उसके कर्मा पर निर्भर है इसलिए यहाँ कोई ऐसा कर्तव्य नहीं जो दूसरों के प्रति हो, सभी नैतिक कर्तव्य अपने ही प्रति हैं।^{२२}

^{२१} पाश्चात्य दार्शनिकों का यह अवश्य अपने प्राणि नैतिक कर्तव्यों की चर्चा की है, परंतु सब मिला कर, जैसा कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है, पश्चिम में नैतिक कर्तव्य की धारणा मुख्यतः सामाजिक है। इस विषय पर आधुनिक विचार के लिए देखें पॉल डी आइसनबर्ग, 'ज्यूटीन डू वनने' एंड द कमेन्स आफ़ मारोलेटी एनक्वायरी, २, स २, मीडम १९६८।

^{२२} इस सिद्धांत का सम्यह विवेचन एल के मैत्र के एथिक्स आफ़ द हिंदू (कलकत्ता-१९२५) में देखें। राजनीतिक सत्कार के लिए कर्म-सिद्धांत की उपयोगिता के लिए देखें- नंदी, पूर्वोल।

नैतिक वृत्ति से सबधित एक प्रश्न यह भी है कि समान उद्देश्य से एक साथ काम करने में व्यक्ति और समूह एक दूसरे पर कहा तक भरोसा कर सकते हैं। यहाँ हिंदू मनोवृत्ति की एक विचित्र विशेषता है, एक दूसरे पर संदेह और अविश्वास की। मिल कर कोई काम किया जा सकता है, इसमें हिंदू के मन में हमेशा दूसरा के प्रति संशय रहा है, भ्रम कर सरकार या शासन के प्रति शंका और अविश्वास।^{२३} ऊँचे तबके के लोगों में भी चाहे राजनीति में या अन्य ऊँचे पेशों में लोगो को अपने सहयोगियों की ओर से शंका रहता है। यहाँ लोगों के लिए बराबरी के दर्जे पर दूसरे सहयोगियों के साथ काम करना कठिन है, मातहत या ऊपर रह कर काम करने में उन्हें आसानी रहती है। सहयोगी दलों के साथ गठबंधन में हमेशा अविश्वास और अनिश्चय बना रहता है कि कब तक यह सहयोग चलेगा, सहयोगी या हमारा व्यक्ति अपना करार पूरा करेगा या नहीं। इस परस्पर अविश्वास के कारण एक बड़े या श्रेष्ठ व्यक्ति, नेता और गुरु के अनुगत होने की प्रवृत्ति रहती है।

लेकिन आधुनिक युग की आवश्यकताओं, और बड़े पैमाने पर चलन वाले सामूहिक कार्यक्रमों के कारण यह मनोवृत्ति बदल रही है। फिर भी यह ध्यान योग्य है कि सहयोग और मिलकर काम करने की भावना ज्यादातर वही प्रकट हुई है, जहाँ एक चमत्कारी या महान व्यक्ति के नेतृत्व में काम किया जाता है, बजाय वहाँ जहाँ एक बग़बान के लिए मिल कर काम कर। गांधी और नेहरू के नेतृत्व में यही स्थिति देखने को मिलती है। गांधी को अपना स्थान छिनने का भय नहीं था। मगर नेहरू दूसरे नेताओं का प्रभाव बढ़ते देख कर, उनसे अपना स्थान छिनने के प्रति चिंतित हो जाते थे।^{२४} नेहरू के बाद जब सामूहिक नेतृत्व का दौर आया तब ऊँचे में ऊँचे नेताओं में परस्पर अविश्वास और एक दूसरे से शंका की यही प्रवृत्ति देख पड़ी। वास्तव में केन्द्रीय नेतृत्व के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है कि वे बराबर के साथी और सहयोगी के रूप में एक दूसरे का कहाँ तक भरोसा कर सकते हैं।

आज के भारत में सामूहिक मनोवृत्ति के विकास की चर्चा हम आगे फिर करेंगे। यहाँ हमें यह देखना है कि बचपन में घर और समाज के संस्कारों से और बड़े होकर शिक्षा-दीक्षा से किस प्रकार उस विशिष्ट भारतीय मनोवृत्ति का विकास होता है, जिसकी चर्चा हमने ऊपर की है।

२३ इस मनोवृत्ति का चित्रण फोर्डर के प्रसिद्ध उपन्यास 'ए पीपल टु रीडिया में हुआ है। और भी देखिए-मॉरिस कार्रैयस- 'द टू वाश् मान' (लंदन १९५७)।

२४ टल्कनी के वॉशिंग्टन आगस्ट चुने बान पर नेहरू की नाराजी और उनका विरोध और अपने अंतिम दिनों में कामगार योजना द्वारा समाजिक प्रतिद्वंद्वियों की समझ, इसके प्रमाण हैं, यद्यपि दोनों ही बार नेहरू की स्थिति को कोई वास्तविक खतरा न था।

परिवार में बच्चे पर देवदा माता-पिता का ही रंगी नाना, मामा, चाचा, बुआ, मौसी आदि अनेक रिस्तेदारों का प्रभाव पड़ता है, बल्कि पिता के लिए बच्चे में बहुत अधिक दिनचर्या लाना उचित नहीं समझा जाता। पश्चिम की संभ्यता में पिता का आग्रह अधिकांश के फलस्वरूप पिता-पुत्र में प्रतिद्वन्द्विता की जा भावना उत्पन्न हो जाती है, वह भारत में अधिक दगने का नहीं मिलती। यहाँ अधिकांश ज्ञान के बजाय एक दूसरे का प्रति बतव्य का बाध रहता है।

दूसर, बच्चे के मामने एक पिता का ही नमूना नहीं रहना, चाचा नाना, दादा, मामा आदि अनेकों रिस्तेदार रहने हैं, जिनसे वह स्नेह पाता है और जिनका वह नमूना बना सक्ता है। इससे भी अहं भाव के बजाय जादशवात् का ज्यादा प्रल मिलता है।

तीसर, जहाँ एक आर बच्चे को बहुत प्यार किया जाता है और जहाँ वह रोया उसे दूध पिलाया या गाना गिलाया जाता है और उसकी जरूरतें पूरी की जाती हैं, वहाँ यह भी है कि हर वस्तु उसको नेवर परगान भी नहीं हुआ जाता। वह पालने पर पडा रहता है। जब रोया तो उसकी जरूरत पूरी कर दी गयी, फिर उन अकना छोट दिया गया।^{२८} बच्चा सभी एकमात्र ध्यान का केन्द्रबिंदु नहीं रहता।^{२९} घर में बहुत से लोगो के रहने से बच्चे का ज्यादा जादशवात् और सुरक्षा का बोध होता है, किंतु इसी के साथ किसी एक ही व्यक्ति से उमका बहुत अधिक लगाव या तादात्म्य नहीं होता।^{३०} बड़े होने पर बच्चा दूसरों को दखना और सीखना शुरू करता है। यहाँ ऐसा मायता है कि बच्चा सिखाने से उतना नहीं सीगता जितना दूसरा को देखकर स्वयं सीगता है। इससे बच्चे की अधिक छूट और आजादी रहती है, साथ ही उसके ऊपर अधिकांश और अनुशासन का अकुश भी डीला रहता है।

चौथे भारत में एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में या बड़ा छोटा में बड़ा अंतर या पायबय नहीं है। जैसे ही बच्चे कुछ बड़े हात हैं, आर चलने फिरने और घालने लाते हैं, वे बयस्को के क्रियाकलाप में भाग लेने जाते हैं। पश्चिमी समाज की तरह उह जल्दी मुनाने और बड़ा की गोष्ठिया में जलन रखने की कोशिश नहीं की जाती। जसा कि एक भारतीय अफसर ने एक विदेशी मनोशास्त्री से कहा — आप लोग बच्चा का पालन करते हैं, हम उनके साथ रहते हैं।^{३१} यहाँ बालक को ऐतिहासिक चक्र की सनातन क्रिया का जग माना जाता है, और उसे जीवन के जादश और मूल्य चुनने की बहुत आजादी रहती है। दूसरी संभ्यताओं के देशवालों से

२८ मिर्ज़े ऐड दिक्काक-पूर्वोक्त पृ १७।

२९ वही-३१।

३० नारायण, पूर्वोक्त पृ १७०।

३१ मर्फी-पूर्वोक्त पृ ५१। उक्त अधिकारी भतपूर्व शिक्षा सचिव आ प्रेम कृपाल ये।

राजनैतिक-सामाजिक संस्कार

भारतीय समाज में व्यक्तित्व व विकास और सामाजिक संस्कारों के बारे में बहुत न अध्ययन हो रहा है। २५ यहाँ हम कुछ निष्कर्षों को प्रस्तुत करेंगे।

(१) हम आलोचक ने यह बात लक्ष्य की है कि भारत में बच्चा को उनकी माता ही नहीं कुटुंब के और लोगों की ओर से भी बहुत-लाड प्यार और छट मिलती है। इससे बच्चा को निराशा और घबराहट नहीं लगते, इस कारण उनमें सधप ही प्रवृत्ति, सत्ता या अधिकार के प्रति विद्रोह या प्रतिरोध की वृत्ति नहीं पैदा होती और बलिष्ठ व्यक्तित्व या वह वा विकास नहीं होता। दूसरी ओर उस में आत्मविकास की सबल प्रेरणा होती है और एक आत्मनिष्ठा विकसित होती है। इसका यह नतीजा होता है कि उनकी नैतिक शक्ति का सत्ता वह अपराध या कुछ भावना नहीं होती जो सबल व्यक्तित्व प्राप्त न कर पाने के कारण उत्पन्न होती है। उसे नैतिक शक्ति मिलती है एक व्यक्तिगत आदर्श से जिसका विकास वह स्वयं करता है। उस कार्य की प्रेरणा समाज और बाहरी सत्ता के प्रति दायित्व के भाव से नहीं बल्कि आत्मविकास और अपने से ग्रहण किये आदर्श से मिलती है। इससे आसत आदमियों को ऊँचा काम करने के लिए प्रेरणा अधिक नहीं होती।

पूणता का उसका आदर्श वह स्वयं स्थिर करना है कोई बाहरी सत्ता नहीं। उसके नैतिक पमाने उसका अपन विकसित किए होते हैं। दूसरी ओर भारतीय संस्कृति कुछ सावधानी के आदर्शों का भी विकास करती है जो उच्चाकांक्षी और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को प्रेरित करते हैं। जीवात्मा परब्रह्म परमात्मा से अभिन्न है। इससे यह भाव उत्पन्न होता है कि उस ऊँचाई और पूणता को प्राप्त करना मामूली आदमी के बस की बात नहीं है। २० इसी कारण यहाँ गुरु, सयासी या महान पराक्रमी और चमत्कारी व्यक्तियों का इतना महत्त्व और प्रभाव पड़ता है जिससे उपयुक्त प्रवृत्तियों को बल मिलता है। एक तो यह है कि मनुष्य या बड़े

- २५ देखें - पी एम नाथ 'मिस्टर ऑफ द माइ' (आध्यात्म १९४४)। गार्नेर
मर्फी - 'इन द माइन्ड ऑफ मैन्' (न्यूयार्क १९५३) अथवा, बही मार्लिन बार्टेंस
थीरेटर नारायण - 'हिंदू केल्डर ऑफ द फ्यू निम्पसेन' (बर्क १९५७) अध्याय ७, वीडियो बा-
डिंग, स्यापित - निक्स कल्चरल स्टडीज ऑफ वाइल्ड रीयर्स (न्यूयार्क १९६३) में - द
राजपूत ऑफ रा लोपूर - ले मिन्ने और नान दिवसान तथा फिलिप रीगे - 'हिंदू कल्चर
एंड पर्सनैलिटी - ए माइको अनालिटिक स्टडी' (बर्क १९६६)।
२६ स्मैट स्मे - 'बहिमुली निज' (प्रोफेक्टिव एक्सप्लोरेशन) बहता है अध्याय स्वयं का
सारे विश्व से सामान्य की प्रवृत्ति।
२७ बार्टेंस-पूर्ववर्त ५५।

परिवार में बच्चे पर केवल माता-पिता का ही नहीं नाना, मामा, चाचा, बुआ, मौसी आदि अनेक रिश्तेदारों का प्रभाव पड़ता है, बल्कि पिता के लिए बच्चे में बहुत अधिक दिलचस्पी लेना उचित नहीं समझा जाता। पश्चिम की संस्कृति में पिता के आक्रमक अधिकार के फलस्वरूप पिता-पुत्र में प्रतिद्वंद्विता की जो भावना उत्पन्न हो जाती है, वह भारत में अधिक देखने की नहीं मिलती। यहाँ अधिकार जताने के बजाय एक-दूसरे के प्रति कृतव्य का बोध रहता है।

दूसरे, बच्चे के सामने एक पिता का ही नमूना नहीं रहना, चाचा, नाना, दादा, मामा आदि अनेकों रिश्तेदार रहने हैं, जिनसे वह स्नेह पाता है और जिनको वह नमूना बना सकता है। इससे भी वह माँ के बजाय आदर्शवाद का ज्यादा बल मिलता है।

तीसरे, जहाँ एक ओर बच्चे को बहुत प्यार दिया जाता है और जहाँ वह रोया उस दूध पिलाया या खाना खिलाया जाता है और उसकी जरूरतें पूरी की जाती हैं, वहाँ यह भी है कि हर वक्त उसको लेकर परेशान भी नहीं हुआ जाता। वह पालने पर पड़ा रहता है। जब रोया तो उसकी जरूरत पूरी कर दी गयी, फिर उस अकेला छोड़ दिया गया।^{२८} बच्चा कभी एकमात्र ध्यान का केन्द्रबिंदु नहीं रहता।^{२९} घर में बहुत से लोगों के रहने से बच्चे का ज्यादा आश्वस्त और सुरक्षा का बोझ होता है किंतु इसी के साथ किसी एक ही व्यक्ति से उसका बहुत अधिक लगाव या तादात्म्य नहीं होता।^{३०} बड़े होने पर बच्चा दूसरा का देखना और सीखना शुरू करता है। यहाँ ऐसी मायता है कि बच्चा सिखाने से उतना नहीं सीखता जितना दूसरों को देखकर स्वयं सीखता है। इससे बच्चे को अधिक छूट और आजादी रहती है, साथ ही उसके ऊपर अधिकार और अनुशासन का प्रभाव भी ढीला रहता है।

चौथे भारत में एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में या बड़ा छोटा में बड़ा अंतर या पाथक्य नहीं है। जिस ही बच्चे कुछ बड़े हाथ हैं, जो चलने फिरने और खेलने लगते हैं, वे वयस्का के क्रियाकलाप में भाग लेने जाते हैं। पश्चिमी समाज की तरह उन्हें जल्दी मुलात्ते और उड़ा की गोष्ठियाँ में जनम रखने की कोशिश नहीं की जाती। जैसा कि एक भारतीय अफसर ने एक विदेशी मनोशास्त्री से कहा — आप लोग बच्चा का पालन करते हैं, हम उनके साथ रहते हैं।^{३१} यहाँ बालक का ऐतिहासिक चक्र की सनातन प्रिया का अंग माना जाता है, और उस जीवन के आदर्श और मूल्य चुनने की बहुत आजादी रहती है। दूसरी संस्कृति के देशवालों से

२८ मिटर्न ऐन् हिचमक-पूर्वोक्त पृ १७।

२९ वडा-३१८।

३० नारायण, पूर्वोक्त पृ १७९।

३१ मार्क-पूर्वोक्त पृ १। उक्त अधिकारी भूतपूर्व शिक्षा सचिव श्री प्रेम शर्मा थे।

सीमित प्रतीकों व कारण जो रोक या सीमाएँ रहती हैं, भारत में उनका अधिक प्रभाव नहीं रहता। इस कारण भी यहाँ आक्रमक व्यक्तित्व या अहं का विकास नहीं होता।

(३) बालक के पूर्वोक्त संस्कारों में भारतीय व्यक्तित्व की एक और विशेषता लक्षित होती है। यह है अनेकता और विभिन्नता का स्वीकार करने की प्रवृत्ति। चूँकि आक्रमक अहं और महत्वाकांक्षा कम होती है, इसलिए एक ही मूल्या और मानदंड के अनुरूप बनने की मजबूरी या दबाव नहीं होता। चूँकि मुख्य नतिक आदर्श आत्मविकास होता है इसलिए किसी एक आचार या नमूने पर चलने की मजबूरी भी नहीं होती। वचन में जो संस्कार पड़े होते हैं उससे भी इस विश्वास को बल मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति का उद्धार और मोक्ष उसके ही हाथ में है। इसीलिए आदर्श और व्यवहार में जनर होने पर आकांक्षा या ध्येय में विफलता या भ्रष्टि हो जाने पर अतिरिक्त ध्यान नहीं दिया जाता। अतः सभी मनुष्य एक समान नो नहीं। इस प्रकार बचपनी और रानी की ईर्ष्या, आदर्श और आचार की भिन्नता मोक्ष-विचारने के अन्तर, का स्वीकार किया जाता है। कुटुंब में व्यक्तित्व के जो अनेक नमूने बच्चे के सामने रहते हैं उससे भी इस प्रवृत्ति को बल मिलता है।

(४) दूसरी ओर इस विभिन्नता और अनिश्चितता में एकरूपता और निश्चितता स्थापित करने की प्रवृत्ति भी लक्षित होती है। इसके लिए विधिविधान और कर्म-कांड के कठोर नियम बनाए गए हैं और बड़े-छोटे आचार्य-अनुगत सबंध स्थापित किए गए हैं। यहाँ भी कौटुंबिक और सामाजिक संस्कार महामक होते हैं। मध्य वर्ग के हिंदू घरों में बालक को माना और बड़ी बूढ़ियाँ स इतना प्रेम और सार सभाल मिलती हैं कि बड़े होने पर भी उसमें दूसरों पर आश्रित रहने की आदत पड़ जाती है। इसके साथ ही उमर में माँ बाप और बड़ा के आज्ञापालन की भी आदत पड़ जाती है। जब वह समाज में आता है तब वहाँ भी उसकी यह आदत बनी रहती है। बजुर्गों और बड़ा की बात मानने, उनकी इज्जत करने और निर्धारित विधिविधान और रीतिरिवाज पर अमल करने की उसमें सहज प्रवृत्ति होती है। विदेशी आलोचकों ने लक्ष्य किया है कि भारतीय अधिकारियाँ और राजनीतिका के साथ मातृहृत् अनुग्रहता अपराधियाँ, बच्चों का कितना बड़ा सवाजमा रहता है और जीवन के हर क्षेत्र में वरिष्ठ या सीनियर का कितना अदब किया जाता है। इसके फलस्वरूप ऊँचे अधिकारियों की क्षमता में अधविश्वास—सा उत्पन्न हो जाता है।^{१२} और अपने स ऊँचे अधिकारों पर जिम्मेदारी और नियंत्रण टालने

१२ इमार्थ भारत में महान नेता की पीछे चञ्चे की प्रवृत्ति है और उसमें अनेक गुणों का आरोप कर दिया जाता है। यहाँ नेता का अर्थ श्रेष्ठ नहीं बल्कि अतिमानुष योगी या अवतार का है, जिसमें साधारण जन की कमतरियाँ नहीं होतीं। जबकि बाहर गांधी को महान शान्तिवादी समझा जाता था, यहाँ वह चमत्कारी पुरुष माने जाते थे जिन्होंने अनेक दम शक्तिशाली विद्रोह समाप्त होने से छोड़ा लिया।

की प्रवृत्ति रहती है तथा अपने बराबर के आदमियाँ से व्यवहार करते समय एक खटका-सा लगा रहता है। (भारतीय कुटुम्ब में भादया-बहना में प्रतिद्वन्द्विता देखने को नहीं मिलती। क्योंकि अपने में बड़े भाई या बहन का अदब सहज स्वभाव बन जाता है। इसी बड़े-छोटे सन्ध और अदब-लिहाज के कारण बराबरी का व्यवहार करने में अनुसूच लगता है)।

(५) इससे एक बात यह निम्नलती है कि कोटुविक और बड़े-छोटे सन्ध को छोड़कर बाकी सब व्यवहार में भारतीय दूसरा का शक और अविश्वास की निगाह से देखते हैं। यह सब इस बात से उत्पन्न होता है कि एक ओर भारतीय समाज में बालक को बेहद प्यार दिया जाता है और हाथ हाथ लिया जाता है और दूसरी ओर वयस्क जीवन का आदम आत्ममयम और आत्मविश्वास का है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है इस आदम पर जोर दिया जाता है और वयस्क लोगो का सब उससे प्रति अप्रत्याशित रूप में मर्यादा और कठोर होता जाता है। इससे उसके मन में अरक्षा और अस्थिरता का भाव पैदा हो जाता है।^{३३} पहले तो बहुत दिनों तक बालक पर माता की छाया रहती है, फिर एकदम वह हट जाती है। पहले तो वह दूध पिलाना बंद कर देती है पिता की आर या उससे छोटे बहन-भाई की आर ज्यादा ध्यान देने लगती है, और कामा में फस जाती है। लेकिन यह स्थिति तो सभी समाज में आती है। विशेष बात यह है कि भारत में वयस्क के जीवन में यह स्थिति काफी देर में आती है, जिसमें वह बहुत परेशान हो जाता है। जिस दुनिया पर वह राजा की तरह शासन करता था, वह एकदम से बदल जाती है। इससे मन में अस्थिरता, अविश्वास और ऐस प्रतीक और सहारा ढूँढने की प्रवृत्ति आ जाती है जिस पर भरोसा किया जा सके।

बचपन में हाथ हाथ लिए जाने के कारण जीवन में आशावाद का दृष्टिकोण उत्पन्न होता है जो अकस्मिक यथायथ में घरे होता है। (इसी आशावादी दृष्टिकोण के कारण विदेशियों को यह प्रतीत होता है कि भारतीय व्यवहार में बड़े उदार और भल होते हैं, मगर इसका साथ ही उनमें अपने का सही समझने और दूसरो का उपदेश देने की जादत भी होती है)। बने होने पर माता का आश्रय सहसा छिन जाने पर उसके मन में निराशा का भाव आ सकता है। आत्मा की उन्नति का अत्यन्त ऊँचा आदम भी उसमें, विशेषकर अधिक प्रतिभाशाली और भावक व्यक्तियों में अपनी अपूर्णता और निराशा का भाव भर देता है। इस कारण आत्मालोचन और आत्मनिग्रह की प्रवृत्ति पैदा होती है। यहाँ तो व्यक्ति का सबसे ज्यादा स्वस्ति या तो अपने कुटुम्ब से मिलती है या अपने निकट के नातेदारों और विरादरी से। परिवार के बाहर जाने पर भी वह लोगो से कोटुविक सन्ध स्थापित करने की कोशिश करता है। गांधीजी का 'बापू' का रूप इसका उदाहरण है। बड़े-छोटे

का सवध भारतीया के सस्वार में ऐसा मिला हुआ है कि यह समानता के आदस के चरिताथ होने में बाधक बन गया है।

मगर इससे साथ ही हम यह भी मानते हैं कि वचनन के सस्वार ही सब कुछ नहीं है। हमने साथ ही ध्यमित अपने अनुभव से और सामाजिक जीवन से लगातार सीखता रहता है। भारतीय सस्वृति की विशेषता नए तत्वा को ग्रहण करने की रही है। इसी से यह जीवित रह सकी है। अस्तु हमें देखना यह है कि आधुनिकता की महान चुनौतिया का इसने किम प्रकार सामना किया है।

परपरा का आधुनिकीकरण

हमने देखा है कि किस प्रकार विभिन्नतामयी और राजनीतिनिरपेक्ष भारतीय सस्वृति ने आधुनिक राज्य-व्यवस्था को अपनाया। अब हमें यह देखना है कि आधुनिक राज्यव्यवस्था और उसके निर्माताओं ने किस प्रकार इस राजनीति-निरपेक्ष सस्वृति की परपराओं या रूढ़ियों का सामना किया। भारत जैसी प्राचीन सस्वृति का पारवार नयी चुनौतियाँ और नयी सम्यताओं के हमलों का सामना पड़ा। इसके लिए उसने जरूर कुछ ऐसी परिपाटियाँ का विकास किया होगा जिनके बल पर वह इन चुनौतियों को बेल सकी। इनने अधिक विविध तत्वा को वह एक सांस्कृतिक सूत्र में बांध सकी इससे सिद्ध है कि विविधता को पूरा स्थान देते हुए भी उसने कुछ ऐसे मानदंडों का विकास किया होगा, जिन्हें सब स्वीकार करते हों। एकता के ये मानदंड भारतीय मनीषा के अंग बन गए हैं। किस प्रकार आधुनिकता के प्रतिपादकों ने इन मानदंडों को ग्रहण किया या बर्खास्त इसे समझने के लिए हम पहले उन मानदंडों की खोज करेंगे जो आधुनिकता की राह में बाधक प्रतीत होते हैं।

परपरा की नयी व्याख्या

भारतीय सम्यता की मायता है कि विभिन्न जाति, लिंग, धर्म और पद के अनुसार घम या नस्ल मानदंड भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए मतभेद या क्रांतिकारी आंदोलनों का विरोध या दमन करने के बजाय उनको सहन करने का रुख रहता था। यह समझा जाता था कि प्रत्येक तम या भिन्न मत उसी एक मूल सत्य की भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति है। इस धारणा के कारण अपने ही मत को सही और बाकी सबको गलत समझने की कट्टरता नहीं आती थी और समझौता व सह-मति को अच्छा समझा जाता था। राजनीति में यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं सिद्ध हुई, क्योंकि इसके कारण यहाँ चाणक्य के एकतन्त्र और प्राचीन गणराज्यों के लोकतन्त्र, प्रवृत्तियों को स्थान दिया गया। पिछली दो शताब्दियों की क्रांतिकारी राजनैतिक विचारधारा के बावजूद प्राचीनता

और परंपरा को भी मान्यता देने की उक्त प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई। इस स्थिति का सामना आधुनिकता के प्रवर्तकों ने किस प्रकार किया ? पहले तो राजा राममोहन राय से लेकर गांधीजी तक सुधारका ने पुरानी मान्यताओं को नया रूप देने की कोशिश की और व्यक्ति के विवेक तथा राजनैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी व कर्तव्य की भावना का प्रतिपादन किया। भारतीय संस्कृति की परंपरागत ग्रहणशीलता के बल पर पाश्चात्य संस्कृति के तत्त्वा का भी ग्रहण करने की कोशिश की गयी।

पुरानी परंपरा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के अलग मूल्य और मानदंड स्वीकार करने की थी। इस प्रवृत्ति के बल पर राजनीतिक क्षेत्र के अलग मूल्य और नैतिक मानदंड निर्धारित किए गए। इस प्रकार पहले ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता के बाद नयी राजनैतिक सत्ता का जन स्वीकृति और मान्यता मिली। देश में सांस्कृतिक विभिन्नता की परंपरा चली आ रही थी, इससे भी नयी राजनैतिक सत्ता नए राष्ट्रीय राजनैतिक संस्कारों का प्रतिनिधि और प्रतिष्ठापिका के रूप में स्वीकृत हुई। इस प्रकार नयी लोकिक सत्ता, देश का विभिन्न प्राचीन संस्कृति धाराओं को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इस प्रक्रिया में आधुनिकता के नए नेताओं की विचारधारा और मूल्य नयी राजनैतिक व्यवस्था में सबद्ध हुए और जनता में फैलने का मौका पा सके। दूसरी ओर ये नए नेता पश्चिम की भौतिकतावादी संस्कृति से अनेकता में एकता की पुरानी भारतीय परंपरा का ऊँचा वतात रहें और इस प्रकार भारत की महानता बखानते रहें। श्रद्धा की इस भावना में पश्चिमी राजनीति अथ और समाज तंत्र के विधिविधान को ग्रहण करने में जो अपमान या छोटेपन का भाव होता, वह धुल सा गया। ३४

विरोधाभासों में एकता स्थापित करने की अद्वैतवादी परंपरा राजनीति में भी सहायक हुई। नयी राजनीतिक व्यवस्था समाज के विभिन्न तत्त्वों के बीच मध्यस्थता और बीचबिचाव की भूमिका अदा करने लगी और इस प्रकार समाज में फैलने लगी। एक ओर गांधी में पंचायत की परंपरा थी जो स्थानीय मतभेदों का निपटाती थी, दूसरी ओर व्यापक सांस्कृतिक एकता की परंपरा थी। इन दोनों के बीच अब मध्यवर्ती राजनीतिक व्यवस्था विकसित हुई, जो क्षेत्रों और अनेक समूहों को

३४ लुसिफन पाइ - द रिपब्लिक ऑफ चान्सीज पॉलिटिक्स - में कहता है कि चान को इस बात से बहुत अपमान का बोध हुआ कि उसे राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्र में परिणाम की भ्रष्टाचार की स्वीकारना पड़ा। पश्चिम अथ और राष्ट्रों की विधियों को ग्रहण करने में भारत के परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों पर खम अलग नहीं पड़ा इसीलिए राष्ट्रीय भावना की वह भावना यहाँ नहीं बोध हुई।

मनभेदा के प्रति सहिष्णुता की पुरानी परंपरा नए नेताओं के हाथ में भिन्न भिन्न भाषा और धर्म के अनुयायियों के बीच एकता स्थापित करने और सेकुलर (धर्म-निरपेक्ष) समाज की रचना में महायत्न की ।^{३०} इसी प्रकार पुरानी त्याग और माध्यवाद की प्रवृत्ति के द्वारा जनता को कष्टसहन, अपनी आकांक्षा का दमन और आवश्यकताओं को सीमित करने का प्रेरित किया जा सका । इतिहास के प्रति उदासीनता की पुरानी प्रवृत्ति नए इतिहास के निर्माण में सहायक हुई, क्योंकि इससे नेताओं को देश के निर्माण का, अपनी आर्थिक व राजनीतिक नीतियों का कार्यान्वित करने का और जनता पर अपना प्रभाव जमाने का समय मिला । धीमे धीमे जैसे राजनीतिक और आर्थिक नीतियाँ फलित होने लगी, पुरानी मनावृत्ति और दृष्टि को बदलने में भी आसानी होने लगी । इसके लिए पुरानी परंपरा की नयी व्याख्या की जाने लगी । आध्यात्मिक शक्तों के बजाय आर्थिक और राजनीतिक शक्तों में भारत की गानदार सफलता पर जोर दिया जाने लगा प्राचीन भारत के गौरवशाली साम्राज्य और उद्योग-व्यापार में समृद्धि का वर्णन किया जाने लगा । भिन्न भिन्न जाति और भाषा वर्गों ने अपनी उच्चाकांक्षा का सहारा देने के लिए अपने गौरवमय अतीत के इतिहास की शोध की । इस प्रकार भारत के मानस में परिवर्तन हुआ और लोगो का इस बात का बोध होने लगा कि हम एक नए युग का, इतिहास का निर्माण कर रहे हैं ।^{४०}

धर्म और धर्म के दो सिद्धांत भारतीय जीवन के आधारस्तम्भ थे । आधुनिक काल में इनके भी सदम बदले । जबकि प्रत्येक जाति, वर्ण या पेशा के धर्म या कर्तव्य निश्चित थे, धर्म के सिद्धांत में मनुष्य को पूर्वनिश्चित कर्तव्य या धर्म के बंधन से स्वतंत्रता की गुंजाइश थी, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का प्रारब्ध उसके कर्मों से ही निर्मित होता है । नए युग के विचारों के प्रभाव से व्यक्ति के कर्तव्य और अधिकारों पर जोर दिया जाने लगा और पुरानी जाति-व्यवस्था के बंधन ढीले हुए और धर्म या कर्तव्य की पुरानी धारणा बदली ।

पुरानी ऊँची जातियों का प्रयत्न यही था कि राजनीति उन्हीं के अधिकारक्षेत्र में रहे । किंतु बहुसंख्यक छोटी जातियों के लिए राजनीतिक कार्य ऊपर चढ़ने का साधन हो गया । गांधीजी तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने विदेशी शासन के साथ साथ सामाजिक अत्याय, ऊँचनीच, छुआछूत के विरोध को दबी हुई जनता का धर्म माना । इस प्रकार धर्म के सिद्धांत का प्रयोग उस पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने

३९ नदी-पूजाकर्त ।

४० भारतीय मानस के इस परिवर्तन में नैतिक कर्तव्य का पुरानी धारणा भी बदला । जैसा हम पहले कह चुके हैं, भारत में नैतिक कर्तव्य या धर्म का संबंध स्वयं अपने से था दूसरों से नहीं । धर्म या नैतिकता का ध्येय आत्मोन्नति या मोक्ष था । अब गांधीजी ने इस सिद्धान्त का प्रवर्तन किया कि समाज या लोकसेवा आध्यात्मिक उन्नति का द्वार है ।

जाइती है।^{३५} इस प्रकार विगधी पन्ना में समर्थ लाने की प्रयत्ति जारी रही। आधुनिक राजनैतिक दत्ता की पद्धति में इसी प्रवृत्ति का निदर्शन है। इन दत्ता में सहमति का आधार नीति या कायनम नहीं गुटा या घडा में समझौता करान की आवश्यकता हाती है। बहुमत और जनता व प्रतिनिधित्व के नए सिद्धान्त, समझौता और सौहार्दात्मक नयी राजनीति व तत्त्व है। विरोधी नत्वा में एकता स्थापित करने का पुरानी प्रवृत्ति नयी राजनीति में भी आयी है और इस प्रकार आधुनिक लोकतन्त्रा राजनीति भारतीय समाज में स्वीकृति पा सकी है। स्वीकृति पान का दूसरा कारण इसकी उपयोगिता और तत्काल अनुत्पत्ता भी है।^{३६}

अर्द्धन या अनकता में एकता की इस धारणा के साथ इतिहासचक्र और समय चक्र का भारतीय धारणा भी है। इस धारणा व अनुसार इतिहास और समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है और भूत भविष्य और वर्तमान काल के निरंतर घूमने वाल चक्र व जाने जम है। उत्थान पतन और परिवर्तन के इस अनादि और अनन्त क्रम को रोकने की शक्ति मनुष्य में नहीं। मनुष्य इतिहास का बना नहीं सकता, वह इतिहासचक्र की अनिवार्य परंपरा का मूक और विवश दशक है। इसलिए निवृत्ति और त्याग का माग ज़ेयम्बर है। भाग्यवाद की इस प्रवृत्ति का आधुनिक भारत के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि व तो इतिहास का निर्माण करना चाहते थे और भारत को महान राष्ट्र व बराबर स्थान मिलाना चाहते थे। परंतु जब गांधी ने इस निवृत्ति और त्याग का प्रवृत्ति को अपने सत्याग्रह में स्थान दिया तब भारतीय राष्ट्रीयता में एक नयी शक्ति आयी। गांधी ने त्याग और तपस्या का प्रयोग इतिहास को बदलने वाल अपन आंदोलन में किया।^{३७} विदेशी राज्य की कठोर वास्तविकता की निष्क्रिय उपेक्षा के स्थान पर गांधी ने सत्य और अहिंसा पूर्वक उत्तम अमृत्याग का रास्ता अपनाया। अपन आत्मबल और त्याग तथा सवा-मय जीवन से उन्होंने राष्ट्र के समक्ष बहुत ऊंचा आदर्श प्रस्तुत किया और अपने आंदोलन का बहुत नैतिक शक्ति और उच्चता प्रदान की।^{३८}

३५ अर्थात् ४-५ में वाणत 'मध्यवर्त व्यक्ती'।

३६ इन प्रसंगों में मैंने आशीस नदी के निबंध का उपयोग किया है और इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ।

३७ गांधीजी का समयपालन का आग्रह, बालचन की इस गति को प्रभावित करने की इच्छा का प्रतीक है। गांधी हर चीज को समय से नापते थे। उनकी कमर से हर समय घण घण छटपटी रहती थी। प्रो. निर्मल वगु के कथनानुसार, समय पालन को गांधीजी सत्य का साधना का अनिवार्य अंग मानते थे।

३८ देखें- एरिक एच. एरिकसन 'गांधीन आटोबायोग्राफ' - द एयर एन ए चार्ल्स "द अन-स्टाथर १५ स ४- सरद १९६६। तथा सुमित्रा होवर स्टाल - द न्यू करेज - एन एन एन गांधीन सायकोलॉजी' वल्ट् पात्रिक्स १९ न १ अक्टू १९६३।

मतभेदा के प्रति सहिष्णुता की पुरानी परंपरा नए नेताओं के हाथ में भिन्न भिन्न भाषा और धर्म के अनुयायियों के बीच एकता स्थापित करने और सेकुलर (धर्म-निरपेक्ष) समाज की रचना में सहायक बनी ।³⁹ इसी प्रकार पुरानी त्याग और माध्यवाद की प्रवृत्ति के द्वारा जनता को कष्टसहन, अपनी आकांक्षा का दमन और आवश्यकताओं को सीमित करने को प्रेरित किया जा सका । इतिहास के प्रति उदासीनता की पुरानी प्रवृत्ति नए इतिहास के निर्माण में सहायक हुई, क्योंकि इससे नेताओं को देश के निर्माण का, अपनी आर्थिक व राजनीतिक नीतियों को कार्यान्वित करने का और जनता पर अपना प्रभाव जमाने का समय मिला । धीमे धीमे जैसे राजनैतिक और आर्थिक नीतियां फलित होने लगी, पुरानी मनोवृत्ति और दृष्टि को बदलने में भी आसानी होने लगी । इसके लिए पुरानी परंपरा की नयी व्याख्या की जाने लगी । आध्यात्मिक क्षेत्रों के बजाय आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्रों में भारत को गानदार सफलता पर जोर दिया जाने लगा प्राचीन भारत के गौरवशाली साम्राज्यों और उद्योग-व्यापार में समृद्धि का वर्णन किया जाने लगा । भिन्न भिन्न जाति और भाषा वर्गों ने अपनी उच्चाकांक्षा को सहारा देने व लिए अपने गौरवमय अतीत के इतिहास की दोष की । इस प्रकार भारत के मानस में परिवर्तन हुआ और लोगो को इस बात का बोध होने लगा कि हम एक नए युग का, इतिहास का निर्माण कर रहे हैं ।⁴⁰

धर्म और धर्म के दो सिद्धान्त भारतीय जीवन के आधारस्तम्भ थे । आधुनिक काल में इनके भी सधम बदले । जबकि प्रत्येक जाति, वर्ण या पणो के धर्म या कर्तव्य निर्दिष्ट थे, धर्म के सिद्धान्त में मनुष्य को पूर्वनिर्दिष्ट कर्तव्य या धर्म के बंधन से स्वतंत्रता की गुंजाइश थी, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का प्रारम्भ उसके कर्मों से ही निर्मित होता है । नए युग के विचारों के प्रभाव से व्यक्ति के कर्तृत्व और अधिकारों पर जोर दिया जाने लगा और पुरानी जाति-व्यवस्था के बंधन ढीले हुए और धर्म या कर्तव्य की पुरानी धारणा बदली ।

पुरानी ऊंची जातियों का प्रयत्न यही था कि राजनीति उही के अधिकारक्षेत्र में रहे । किंतु बहुसंख्यक छोटी जातियों के लिए राजनीतिक कार्य ऊपर चढ़ने का साधन हो गया । गांधीजी तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने विदेशी शासन के साथ साथ सामाजिक अत्याय, ऊंचनीच, छुआछूत के विरोध को दबोच दिया जनता का धर्म माना । इस प्रकार धर्म के सिद्धान्त का प्रयोग उस पुरानी व्यवस्था का बनाए रखने

³⁹ नदा—पूर्वान्त ।

⁴⁰ भारतीय मानस के इस परिवर्तन में नैतिक कर्तव्य की पुराना धारणा भी बदली । जैसा हम पहले बता चुके हैं, भारत में नैतिक कर्तव्य या धर्म का सर्वथ स्वयं अपने से या दूसरों से नहीं । धर्म या नैतिकता का अर्थ आत्मोन्नति या मोक्ष था । अब गांधीजी ने नम सिद्धान्त का प्रदर्शन किया कि समाज या लोकसेवा आध्यात्मिक उन्नति का द्वार है ।

क वजाय, उसे नष्ट करने व लिए किया गया जिसके नीचे लागू सदिया से दबे हुए थे।^{४१} इन दबी हुई और उन्नति की आर उभूत जातिवा ने ऐसे प्रय और जातीय इतिहास खोज निराले जिससे उनके ऊच पद क दावा का समपन होता था।^{४२} पुरानी बीजा का पुनर्जीवित करने की इस प्रवृत्ति को आधुनिकतावादी अच्छा नहीं समझते, किन्तु इस क्रम म पुराने प्रतीका के अथ और मूल्य भी बदल रहे हैं।^{४३} इससे पता चलता है कि पुरानी परंपरा को किस प्रकार नए प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और नए विचार व मूल्य किस प्रकार पुरानी बातों को प्रभावित कर रहे हैं।

एक बात यह ध्यान देने की है कि राष्ट्रीय आंदोलन व दौरान और स्वतंत्रता व बाद भी पुराने पाश्चात्य रंग म रंगे नेताओं का स्थान प्राचीनतावादी आधुनिकतावादी नेता से रहे हैं। अध्याय ५ म हम इसकी घर्षा कर चुके हैं। गांधी और उनके महान अनुयायी भारतीय परंपरा के प्रेमी होने के साथ साथ पुरातनत्व-नवियानुसीपन से मुक्त थे, इससे साथ ही व अंगरेजितपक्षद बौद्धिक नेताओं व भाति जनता से दूर दूर नहीं रहते थे। इसी कारण के राष्ट्र को प्रभावित कर सक और एक ही देश के अंदर समूचे राष्ट्र की विचारधारा और उसके इतिहास का बदल सके।

स्वतंत्रता के बाद वालिग मताधिकार दिए जाने के फलस्वरूप पुरानी पीढ़ी के नेताओं के हाथ से निकल कर शक्ति राज्य, जिला और गाव स्तर के नेताओं, जातीय मया ग्राम पंचायतों और सहकारी संघों के हाथ में चली गयी। ये नए नेता भी नेहरू की ही भाषा में बोलते हैं और लोकतंत्र व समाजवाद की दुहाई देते हैं, परंतु उनका संगठन और ढोलने का ढंग जनता के ज्यादा करीब है। धार्मिक और जातीय प्रतीकों की उनकी व्याख्या जनता को ज्यादा प्रभावित करती है। वे धार्मिक और लौकिक धर्मों का जोड़ते हैं और इस प्रकार राष्ट्रीय राजनैतिक संस्कार का साधन हैं।^{४४}

~
^{४१} स्वतंत्रता के बाद नेहरू ने बार बार यह बात पर जोर दिया कि गांधीजी पहले कह चुके थे, अर्थात् भारत को स्वयं अपना उद्धारणों से मुक्त करना है।

^{४२} इस प्रवृत्ति में पुराने माट और चरणों की रखाते संशयक हुई। देखें-ए एम शा और थाफ 'द वडीवाचा वारोठस आफ गुनरात-ए वास्ट आफ जीनियाल्थिजिस्ट्स एंड माइ बीयाफर्स मिल्टन सिगर संपादित-दैनिकानल इंडिया स्ट्रक्चर ऐंड चर्च' (किल्डेरिया १९५९)।

^{४३} इसी प्रकार पुरानी न्याय की धारणा की भी नयी व्याख्या का गद। इसका अर्थ मनुष्यमान की समानता और वरुणा माना गया। संयोजनकारों ने भुवइया और भरोहर या दूरी के सिद्धांत का भी प्रयोग सामाजिक न्याय के प्रतिपादन के लिए किया।

^{४४} देखें-मारिम चोस 'इन्वियन पोलि इन्विज्म' - फिलिप्स संपादित - पालिटिक्स एंड सोसाइटी इन इंडिया' (एडन १९६३)

नए केंद्र का निर्माण

नेतृत्व में इस परिवर्तन के साथ साथ उससे भी बड़ा परिवर्तन सस्यागत और समाज व राज के ढांचे में है। हमने देखा है कि विभिन्नता से भरे इस देश में एकता का सून समाज की बड़े छोटे की सोपानपरंपरा और उससे संबंधित विधिविधान रहे। अघ्याय दो से पांच तक हमने इस ढांचे में जो परिवर्तन आए हैं, उनकी चर्चा की है। पहले तो ब्रिटिश शासन ने पुगने ऊच-नीच के सामाजिक ढांचे में परिवर्तन किया, फिर राष्ट्रीय आंदोलन ने और भी अधिक परिवर्तन किए। स्वतंत्रता के बाद नयी सरकार ने जो बदल उठाए उससे पुरानी व्यवस्था और उसके विशेषाधिकार को गहरा धक्का लगा।

ये परिवर्तन प्रत्यक्ष हैं। पुराने सामाजिक अधिकार और ऊच नीच संबंध खतम कर दिए गए। गांवों का एकाकीपन या राष्ट्रीय जीवन में अलगाव दूर कर दिया गया और नयी अधिकारयुक्त सस्था का निर्माण किया गया।^{४५} पुरानी व्यवस्था, जिसमें हर जाति या समूह के काय, अधिकार और मानमर्यादा निश्चित थी, नष्ट हो गयी और उसके बजाय हजारों लाखों समूहों व समुदायों को सरकार, चुनाव, राजनीतिक दल और शासन के अधिकारीवर्ग में शामिल होने का मौका मिला।

बालिंग मतधिकार और समय समय पर होने वाले चुनावों ने ऊचनीच की धारणा को नष्ट करके सबको बराबरी की श्रेणी में ला दिया। एक विख्यात विद्वान का गुब्दा में—

“ बिना संपत्ति या शिक्षा की शर्त के हर बालिंग को बोट देने का अधिकार आधुनिक राजनीतिक समाज की स्थापना का सबसे जबदस्त साधन है। इसके साथ और परिवर्तन भी जरूरी हैं, लेकिन जब बार बार देश की पूरी बालिंग जनता को देश की सरकार का बनाने या बनाने का मौका मिलता है, तब उनमें अपनी शक्ति का भान होता है और पूरे राष्ट्र के प्रति का स अपनाने का भी धोब हाता है। ”^{४६}

मारिम कार्मैयस ने भारत की ऊंची जानिया के बारे में महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। देवली गांव के अध्ययन से उन्हें पता चला कि राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन का गांव की जातीयवस्था की मानमर्यादा की धारणा पर कैसा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने लिखा है कि केवल सभा समितियां ही नहीं, हाट-बाजार में भी लोग नित्य पुरानी और नई बातों की तुलना करते हैं और लपट करते हैं कि

“ प्राचीन ग्राम पंचायतों की परंपरा और प्रथाओं पर आधारित होते हुए भी नवी पंचायतें उनमें एकदम भिन्न हैं। ”

“ पञ्चवत् शिम—पोलि देव इन द न्यू स्टेट्स—कम्प्रेहेंसिव स्टडी इन सोमादरी ऐंड हिस्ट्री—ने म ३ अप्रैल १९६० पृ २८७। ”

कितना परिवर्तन हो गया है। हर जाति के बड़े और बच्चे सब इस परिवर्तन से प्रभावित हुए हैं।

परिवर्तन की इस व्यापक प्रक्रिया की चार बाता पर लक्ष्य करना चाहिए। प्रथम, पुरानी व्यवस्था के इन परिवर्तन के समयन में पुराने प्रमाणों और प्रतीकों का हवाला देने के साथ, नयी लौकिक (सेकुलर) विचारधारा या तर्कों का भी हवाला दिया जाता है। दूसरे, नये परिवर्तन चलन में तो आ ही रहे हैं, इसके साथ साथ लोग पुरानी बाता से नयी बाता की बराबर तुलना भी करते हैं और इस प्रकार उनका सोच समझ बर ग्रहण कर रहे हैं। तीसरे—इस तुलना से यह धारणा पक्की होती है कि पुरानी व्यवस्था में जड़ता और सड़ाप अगयी थी और उसे बदलने की जरूरत है। चौथे—इस नए परिवर्तन का भान। पहले जा परिवर्तन हुए थे, वे मत या विचार के क्षेत्र में हुए थे। समाज का छोटी बड़ी जातियों का ढाचा ज्या का त्या बना रहा और हर नया तत्त्व उसी ढाचे में स्थान पा जाता था। अब सब का इस बात का भान है कि इसी ढाचे में परिवर्तन आ रहा है, भले ही वह बहुत धीमे हो। इस परिवर्तन से सब को प्रसन्नता नहीं है। कुछ लोग तो इसके धीमेपन से अम तुष्ट हैं। फिर भी यह परिवर्तन फैल रहा है और आधुनिक भारत के विचारों का और सामाजिक गतिविधि को प्रभावित कर रहा है।

इस परिवर्तनबोध को फैलाने में सरकार और उसकी एजेंसिया का मुख्य हाथ रहा है। न केवल सामाजिक विकास में सरकार का अधिकाधिक हाथ रहा है और जीवन के हर क्षेत्र में सरकारी तंत्र का प्रवेश हुआ है बल्कि लोगों के मन पर भी सरकार छा गयी है। इस विषय में अध्ययन करने के लिए कुछ लोगों से प्रश्न किए गए कि अकाल आदि विपत्ति पड़ने पर किस हद तक रिश्तेदारी से और सरकार से मदद की आशा है और आप किससे मदद लेना पसंद करेंगे। ४० स्वभाविक यही था कि लोग रिश्तेदारों से ज्यादा उम्मीद करें और उनको पसंद करें, लेकिन वास्तविकता इससे उमटी थी, जैसा कि सारणी सात १ और सात २ से मालूम होगी।

४१ यह अध्ययन, सर फार स्टडा डेव सोसा दिल्ली टोकियो वि वि, स्टैनफोर्ड युनि और नादजारिया की इवादान युनि का और से किया गया। भारत में यह प बगाल, उ प्र, गुजरात और आंध्र में किया गया। प्रश्न ये थे — (१) मान लानिए आपके परिवार पर सकुट आ जाए और उसे भरण-पोषण के लिए मदद दरकार हो। आप किसे मदद मंगिगे? क—ऐसे रिश्तेदार हैं, जो मदद कर सकें। ख—क्या सरकार या कोई सरकारी पैसा है, जो ऐसी स्थिति में मदद दे? (२) इस रिश्ते में जब आपकी पैसे की कमी हो और रिश्तेदार और सरकारी जेबसा दोनों हा एक-सी मदद देने को तैयार ह आप किससे मदद लेना पसंद करेंगे?

सारणी सात - १ क - अनग रहने वाले रिश्तेदारों से मदद की अपेक्षा ।
ख-सरकार में मदद की अपेक्षा ।

	प्रतिशत हा	नही	पता नही
स० रा० अमेरिका			
क-रिश्तेदार	६५ ४	३२ ०	२ ६
ख-सरकार	६६ ४	२० ३	१० ३
जापान			
क-रिश्तेदार	६८ ७	२४ १	६ २
ख-सरकार	४१ ४	४० ०	१४ ६
भारत			
क-रिश्तेदार	३१ ८	६६ ६	१ ६
ख-सरकार	५० १	४२ ४	७ १
नाइजीरिया			
क-रिश्तेदार	५४ २	४१ ०	४ ६
ख-सरकार	४३ ८	३६ १	२० ०

भारतीय लोग रिश्तेदारों के बजाय सरकार से ज्यादा मदद की आशा करते हैं और सरकार में ही मदद लेना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह है कि रिश्तेदारों से मदद लेने में हेतुन का बोध होता है जब कि सरकार से मदद लेने में ऐसा कोई भाव नहीं होता। दूसरे, सरकार से तकाबी जार सहकारिता से नृण खेत रहने के कारण उनका सरकारी ऋण लेने में सुभीता मालूम होता है। जो भी हो ऊपर की पड़ताल से इतना ता स्पष्ट है कि भारतीय जनता सरकार को विश्वास के साथ देने लगी है।

सारणी सात - २ सरकार और रिश्तेदार किससे मदद लेना पसंद है - प्र० ग०

	रिश्तेदार	सरकार	दानों	किमी से नहीं	पता नहीं
स रा अमेरिका	४२ ६	५३ १	—	—	४ ३
जापान	४७ ८	३१ ०	३ ३	४ ८	६ १
भारत	२४ २	६६ ००	२ ५	१ ४	२ ८
नाइजीरिया	३३ ३	५३ ०	७ १	० ७	५ ५

जना का दृष्ट मातृत्व एगिजन को हन गरकारीकरण का नाम द सकते हैं।
 दग बात का मता नाति लय रिपा ना सरता है रि तागा को मनायुति, मामा
 जिम जीरत तया सत्याश्रम म गरहाण का हाम बना ना र्हा है। गरहाण राज-
 नतिन और आधिरा वायवमा जोर मन्ना का रिपिटा करती है तया शक्ति तया
 गरिहार के रायवना को प्रभावित करती है।
 गरकारीरण की मन्ना

मरकारोत्थन की यह प्रवृत्ति एक तब चीज नहीं है। राजा या मरकार मर्द
 था है यह पारणा युन पुरान जमान व भारत में रही है और इसी कारण
 सरकार इन कम समय में देश को ब्यापक परिवर्तन कर रही है। दूसरी ओर
 राजनीति विराम की मुख्य बात यही नहीं है कि जनता सरकार का स्वीकार कर
 और उस पर अगुआ बदे, बल्कि यह अनुभव भी कर कि सरकार से अपना काम
 कराया जा सकता है और उगाह उगाह काम का जवाब तब दिया जा सकता
 है। जनता व राजनीति में अधिकाधिक मात्रा तक व जनस्वरूप उसमें यह भावना
 है। जनता यह है कि इस परिवर्तन में जनता का हित व जनस्वरूप उसमें यह भावना
 है। जनता यह है कि इस परिवर्तन में जनता का हित व जनस्वरूप उसमें यह भावना

प्रश्न यह है कि इस परिवर्तन का क्या तत्त्व दिया गया है । भारत में परिवर्तन तभी बिना किसी अनिवार्य उपलब्धता के हो रहा है । यही नहीं बल्कि जो धर्म धीमे जाता वो ज्यादा ही है । जोर जबदस्ती से किए गए परिवर्तन बहुत स्थायी नहीं होते । ४८ तबिले बाहरी लोग इस प्रक्रिया को प्रक्रिया का तत्त्व नहीं कर पाते और यह समझ बैठते हैं कि भारत में कुछ हो ही नहीं रहा है । ४९ इस भ्रम पर धारणा को फैलाने में कुछ हद तक हमारे अंगरेजी शैक्षिक और कुछ अप्रगामी वर्ग का भी हाथ रहा है । हमारे संस्कार भी ऐसे हैं कि परिवर्तन की प्रक्रिया में भी स्थिरता का अन्यास होता है जबकि कुछ देश ऐसे हैं जहाँ काद प्रगति नहीं हो रही है फिर भी आभास परिवर्तन का होता है । इसलिए जब तक हमारे यहाँ सामाजिक और राजनैतिक पर्यवेक्षण और विवेचन नहीं दिया जाता, हमारे अप्रगामी वर्ग भी राजनैतिक परिवर्तन की गति और रुतबों को नहीं समझ पाएंगे और जनस्वरूप अनिश्चय में पड़े रहेंगे । इस विषय में हमारे समाजशास्त्रियों पर विशेष जिम्मेदारी है ।

४८ इस विचार का नेतृत्व में नेहरू का बहुत हाथ रहा। यद्यपि वह दूसरे लोगों में हुए परि-
वर्तन से बहुत प्रभावित थे, फिर भी उनका शक्तिशाली तथैतिक में अत्यंत विश्वास था। उन व्यक्तियों
में पंचायती राज का मज़लना में सौहार्द प्रकट किया और कहा कि हमें विकास का काम करना
पड़ जायेगा तो नेहरू ने यही कहा कि अंत में हमें विकास प्रगति होगी।

४१ अल्प आदर्शमान अरदेवलयमें, आरमोकिम डूद परीक्षण आफ बेर ऐड लीन
शिन, डी थात स १७७ न ३, सार १९६८।

कुछ प्रवृत्तियाँ बनी रहों

आधुनिकता के प्रवक्तव्यों ने अनेकान्तवाद की पुरानी भारतीय प्रवृत्ति का सहारा लेकर नए विचारा और सस्याआ का प्रवर्तन किया फिर भी कुछ पुरानी प्रवृत्तियाँ बनी रही। इनमें से कुछ नए परिवर्तन में बाधक हैं।

भारतीय जनता का स्वभाव शास्त्रीय या निर्धारित विधिविधान पर आलू मूढ़ बन चलने का है। इसका नतीजा यह हुआ है कि सरकारी कामकाज में नियम-कायदा को महत्त्व दिया जाता है कार्यकुशलता का नहीं। नौकरशाही या दफ्तरशाही के शिक्के में सामाजिक जायिक और प्रशासनिक गतिविधि कुठित हो गई है।

भारतीय समाज में भिन्न भिन्न वर्गों या श्रेणियों का स्थान और अधिकार निश्चित रहा। यह प्रवृत्ति आधुनिक काल में भी बायम है। अभी आधुनिक सस्याआ का रूप स्थिर नहीं हुआ है। इस संक्रातिकाल में आधुनिक शिक्षा या अन्य क्षेत्रों में भी पुराने ऊँचे नीचे वर्गों की तरह स्थानीय श्रेणियाँ बन गई हैं। विरोधी तत्त्व भी अधिकार और पद की श्रेणी में स्थान पाने की काशिश करते हैं। इस प्रकार अधिक और कम अधिकार और मानमर्मादायक नए वर्ग या नयी 'जातियाँ' उत्पन्न हो रही हैं।

दूसरी ओर जसा कि पहले कहा जा चुका है, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्रों में सामूहिक रूप से काम करना भारतीयों के लिए बठिन हाता है। इन क्षेत्रों में भी पुरानी जाति उपजाति की तरह गुट बन जाते हैं जैसे स्थानीय राजनैतिक और अधिकारी वर्ग के गुट। इस प्रकार विकेन्द्रीकरण व्यवहार में छोटे छोटे स्थानीय गुटों या उपसमूहों का रूप धारण कर लेता है जो बड़े हुए ढंग से काम करते हैं।

बड़े पैमाने पर संगठन की चलाने का अनुभव न होने और पुराने जमाने से कुटुंब और बिरादारी जैसे छोटे समूहों में रहने की आदत के कारण, भारतीयों को बहुत बड़े सामूहिक संगठनों में रहने और उनका अनुशासन में चलने से स्वाभाविक विरक्ति है। इसलिए जसा हम कह चुके हैं जब तक कोई चमत्कारी व्यक्ति का नेतृत्व न हो, भारतीय लोग सामूहिक या बड़े पैमाने पर काम करने से बचते हैं।

इस कारण भारतीयों की मनोवृत्ति ऐसी बन गयी है कि वे अपने बग़ल वाले के साथ व्यवहार करने में असुविधा अनुभव करते हैं। इसी प्रकार वे विरोध या संघर्ष की स्थिति का फरियाने के बदले लीपापोती करने या टालने की कोशिश करते हैं। यह भी सभी विचारा और मतांतरों को स्थान देने की पुरानी प्रवृत्ति का ही अंग है। इसका नतीजा यह होता है कि ऊपर से समझौता या एकता के पर्दे के नीचे मतभेद और विरोध सुलगते रहते हैं। ५० इस के फलस्वरूप हारने

१० भारत में यह प्रभावशाली वर्ग समझौते को बहुत महत्त्व देता है। यह वर्ग प्रत्यक्ष चुनाव को नापसंद करता है क्योंकि इससे झगड़ा और विरोध पैदा होता है और इसके बजाय [अगले पृष्ठ पर]

वाले या अल्प मत वग में बड़ी कटुता और अनास्था भर जाती है और उनका क्षोभ भीतरही भीतर सुलगता रहता है।

हमारी इस चर्चा का निचोड़ यह है कि जहाँ भारतीय लोगा में आधुनिक युग की विभिन्न समस्याओं को चलाने और मतभेद और आलोचना को सहन करने की अच्छी क्षमता है, वहाँ बहुत बड़े सामूहिक उद्यमों का चलाने में जिस सगठन और अनुशासन की जरूरत होती है, उसमें वे कमजोर पड़ते हैं।

निष्कर्ष

सम्यता का एक प्रकार यह है जहाँ केन्द्रीय सत्ता की समस्या प्रधान रहती है और तणातार चली आती है। दूसरे प्रकार की सम्यता यह होती है, जिसमें केन्द्रीय सत्ता जनता से दूर होती है और लगानार संपर्क में नहीं रहती है और जहाँ स्थानीय समस्याएँ स्वायत्त होती हैं तथा राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र अलग रहते हैं।

पहली सम्यता में जब आधुनिकता की प्रक्रिया गुरु होती है तो उसका प्रभाव सत्ता के पूरे ढाँचे पर पड़ता है जिसमें व्यक्ति और उसके समूह का सबंध होता है। दूसरी सम्यता में केन्द्रीय सत्ता में परिवर्तन होता है पर पूरी व्यवस्था पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। पहली सम्यता ज्यादा लौकिक होती है और मनुष्य मुख्यतः राजनैतिक व्यक्ति होता है और उसका मुख्य लगाव केन्द्रीय या राज्यसत्ता में होता है। दूसरे में व्यक्ति का लगाव अपने समूह से और आत्मविकास से होता है। यहाँ सत्ता बंटी रहती है और राज्यसत्ता जो अस्थायी होती है तथा सृष्टि जो स्थायी होती है दोनों में काफी दूरी होती है। यहाँ व्यवस्था या समष्टि अपनी व्यक्तिगत इच्छा का जोड़ या इच्छा से ऊपर नहीं समझी जाती बल्कि एक सबंध शृंखला की प्रक्रिया समझी जाती है।

भारत में राजनैतिक नेतावर्ग ने देश में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भाग लिया है। फिर भी सामाजिक जीवन में राजनीति ही सबसे मुख्य तत्त्व नहीं है। अब तब जो काम समाज या बिरादरी में मुखिया करते थे, वह काम अब राजनैतिक नेता करने लगे हैं। इस प्रकार समाज के जीवन में राजनीति का प्रवेश हुआ है।

लौकिक या केन्द्रीय सत्तावाली सम्यताओं के मुकाबले गैरलौकिक सम्यता में राजनीतिका प्रवेश आसान होता है। यह प्रवेश लोगों का लाभ पहुँचा कर होता है

[पिछले पृष्ठ से]

एकमत या आम राय या नेपाल की तरह के अप्रत्यक्ष चुनाव को पसंद करता है। त्रयप्रकाश नारायण - एका पार रिक् सट्टेशन ग्राफ दह डिवन पालिटि (दिल्ली १९५६)। स्टेन होवर स्मार्थ ने कानफ्लिक्ट ऐंड कानमेशन इन नॉ पालि में इस पर विचार किया है (वर्ल्ड पालिटिक्स - अप्रैल १९६१)।

उन पर सरकारी मशीनरी लाद कर नहीं । इस प्रकार की सम्यता में राजनैतिक तन्त्र को लोगो की भावनाओं का ख्याल रखना होता है जबकि केन्द्रीय सत्तावाली सम्यताओं में सरकार लोगो को जबदस्ती अपने रास्ते पर चला सकती है । ५१ गैर राजनैतिक सम्यता में सरकार को लोगो की भावना का ख्याल रखने के साथ साथ परिवर्तन लाने में सक्रिय हाथ लेना पड़ता है । यदि यह दोनों में से किसी भी काम में विफल हो, तो उसका विराघ होने लगता है ।

५१ ज्ञान में यही हुआ । देखिए—जूमिन पाद—स्पिरिट ऑफ चाइनीज पोलिटिक्स ।

राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण और राष्ट्रीय एकता

पिछले अध्याय में भारत में होने वाले राजनितिक परिवर्तन का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। इसमें बताया जा मट्त्व पूरा प्रश्न है उसका सबसे इसमें है कि यह व्यवस्था किस प्रकार काम कर रही है।

हाल के वर्षों में राजनितिक विवादों का मूल्यांकन के लिए कुछ सिद्धान्त प्रस्तुत किए गए हैं।^१ किन्तु साधारणतः राजनितिक विवादों ने इस बात की उपेक्षा की है कि राजनितिक व्यवस्था क्या काम कर रही है और समस्याओं को हल करने में इस वितर्की सफलता मिली है। जहाँ वही मूल्यांकन करने की कोशिश की गयी है वहाँ भी आर्थिक विवाद, समाजसुधार, रूढ़ियों टी० बी०, अखबार आदि साधनों के प्रसार के उपायों का ही वर्णन कर दिया है। इस प्रकार उन्नत देशों की कुछ विशेषताओं को राजनितिक विवादों की बसोटी बना लिया गया है। अधिकतर विश्लेषक समाजविज्ञान की मुख्य विचारधारा से प्रभावित हैं, जिसमें यह समझा जाता है कि राजनितिक परिवर्तन, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों से प्रभावित होता है तथा पश्चिमी देशों के इतिहास को दृष्टि में रखा है, जहाँ अधिकतर (हमारा नहीं) राजनितिक विवाद समाज की मांग और दबाव का फलस्वरूप होता है। इसलिए इन लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि राजनितिक विवादों का समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है।^२ अभी हाल तक राजनितिक विवाद अर्थात् राजनितिक

^१ गेनियल ए. बालमंड-“पॉलि सिस्टम्स ऐंड पॉलि नेशन” (द अमेरिकन विदेवारियल साइ-टिस्ट ६ स १० जून १९६३ और बालमंड-“ए डेक्लरमेंट ऑफ अमेरिकन डी पॉलि सिस्टम्स” (वर्ल्ड पॉलि ८ स २ जनवरी १९६५)
^२ ऐस ही लखनौ का सब क्षेत्रों में बार है उदाहरण के नाम रजेलसर विलियम बार्नहार्ट, एस एस लिनने, बालमंड डेनियल लनर, वैरिगटन मूर। हेले-जोसफ ए पाथेम्परा “मैक्रोथियरी” ऐंड माइक्रो-अर्थोक्रैसी इन कम्परेटिव पॉलिटिक्स-ए नारडोनिंग चायन” (कम्परेटिव पॉलिटिक्स १ स १, अक्टू १९६८)। सामाजिक सिद्धान्त की दृष्टि से राजनीति और अधिकार के महत्त्व के लिए-रारनहाउस वैनिकस-“नेशन बिल्डिंग ऐंड मिटिगनशिप” (यूनाईटेड १९६४)।

केन्द्रीय सत्ता की स्थापना और उसका फैलाव, नयी राजनैतिक पद्धति की जनता द्वारा ग्रहण होने में सफलता या विफलता, राजनैतिक भाषा को पूरा करने में उसकी क्षमता, या सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हुए विवाग से सन्ध जाड़ने या तुलना करने की कोई विधियत कोशिश नहीं की गई। इन प्रश्नों पर और आर्थिक क्षेत्र में हुए काम पर बहस बहुत हुई है, फिर भी प्रवृत्ति दोनों को अलग अलग देखने की है। वैसे काम हुआ है, इस प्रश्न पर ध्यान देने का परिणाम यह हुआ है कि राजनीति की गमीगा गुटबंदी और उसाड़ पछाड़ का घणन बन कर रह गयी है।

अस्तु हमने भारत का राजनैतिक परिवर्तन को समझने के लिए, परंपरा और परिवर्तन अर्थात् प्राचीनता और नवीनता के तत्वा का मिश्रण का विश्लेषण किया है। नयी राजनैतिक व्यवस्था अमल में और समझाया जा सके तो हमें इस पर हम इस अध्याय और अगले दो अध्यायों में विचार करेंगे। नयी राजनैतिक व्यवस्था के जड़ जमाने और राष्ट्रीय एकता की समस्याओं, जनसंख्या और आर्थिक विकास की समस्याओं तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समस्याओं पर हम प्रथम इस अध्याय और अगले दो अध्यायों में विचार करेंगे। इसमें हम भूतकाल की और वर्तमान प्रवृत्तियों पर विचार करते हुए, कुछ धाना में निष्पत्ति की ओर संकेत करेंगे। पर यह संकेत होगा, भविष्यवाणी नहीं।

एकीकरण की समस्या

राजनैतिक विकास की बुनियादी समस्या एकीकरण की है जयान नये राजनैतिक केन्द्रबिंदु की स्थापना और दृढ़ीकरण, उसका बहिर्मुख प्रसार, विभिन्न समस्याओं का पल्लव, विविधता को एक सूत्र में ग्रहण कर एक राष्ट्र का निर्माण अर्थात् एकीकरण की क्षमता का विकास। यही समस्या हमारे राष्ट्र निर्माताओं का सामने सबसे बड़ी समस्या रही है। जैसा कि नेहरू ने कहा था मेरे जीवन का मुख्य काम भारत का एकीकरण है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि भारत एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया से गुजर रहा है। अगर मुख्य बात यह है कि एकीकरण के लिए तरीका क्या अपनाया गया। इस तरीके में दो बातें हैं। एक सरकार और सरकारी या शासन दल की गतिविधियों के द्वारा देश में एकता की स्थापना और उसका दृढ़ीकरण। दूसरे देश के विभिन्न तत्वों के अधिकारों और हिता का संरक्षण और भावना देकर उनको राष्ट्रीय जीवन और राजनैतिक व्यवस्था में शामिल करना। भारत की राजनैतिक एकता में राष्ट्रीय सरकार की प्रधानता और अन्य हिता का व अल्पसंख्यकों के प्रति सम्योक्ति और निष्ठा की भावना इन दो प्रवृत्तियों का मुख्य योग है।

इस तरीके से समाज के राजनैतिकीकरण का बड़ा महत्व है। इसमें राजनैतिक

गतिविधि के द्वारा समान का बदलने की कोशिश की जाती है। इसमें भारतीय नेताओं को जो सफलता मिली उसका श्रेय कुछ अंश में इस बान को है कि यहाँ जनसाधारण राजनीति से उदासीन था और नेताओं तथा राष्ट्रीय सरकार से ज्यादा मांग नहीं करना था। इसके साथ ही यहाँ का प्रशासननय, नेता तथा कांग्रेस दल भी अत्यन्त प्रभावशाली और शक्तिशाली था। लेकिन नेताओं के प्रयत्न का उद्देश्य जनता की राजनीति की ओर से उदासीनता को दूर करना था। परिवर्तन की प्रक्रिया का प्राप्ताह देना था और नये दल और हिता का मैदान में लाना था।

जब सत्ताधारी दल परिवर्तन लाने का प्रयत्न करता है तो उसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि उसके विरोधी या प्रतिपक्षी दलों का उदय हो। राजनैतिकीकरण की सफलता को आते समय इस बात का विचार करना होगा कि यह प्रक्रिया कितनी शांतिपूर्ण और सोहेद्य रही। सत्ता के टांचे में देश के विविध तत्वों का कितना प्रतिनिधित्व मिला और उममें जड़ जमाने और देश के लोगों द्वारा अंगीकरण में कितनी मदद मिली।

इसकी समस्या

भारत में सत्ताहठ दल ने नए राजनीति के ढांचे के लिए संसदीय लोकतंत्र का नमूना स्वीकार किया। इस पद्धति में दो प्रतिद्वंद्वी दलों का होगा जरूरी है, जिनमें अपने समर्थक बग हों। परन्तु देश में ऐसे प्रतिद्वंद्वी दलों का अभाव था। यहाँ एक कांग्रेस दल की प्रधानता थी। इसलिए प्रतिद्वंद्विता का तत्त्व इसी दल के भीतर से जाना था। इसके लिए कांग्रेस दल को अपनी रीति नीति में परिवर्तन करना जरूरी था। अब तक दल में अनुशासन और एकमत पर चला दिया जाता था। अब विरोध या मतभेद और नेतृत्वपरिवर्तन की गुंजाइश करनी जरूरी हुई। अवश्य ही कांग्रेस का संगठन पहले से ही काफी व्यापक था और उममें अनेक विचारों और बगों का लोग थे। फिर भी मोटे तौर पर ये एक श्रेणी के अर्थात् अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे। अब तक इस बग से ही कांग्रेस की नेता मंडनी आती थी। बालिग मताधिकार से राजनीति जो सामूहिक रूप धारणा करती है और जिससे पद और अधिकार के नए दावेदार पैदा होते हैं, इस स्थिति से अब तक इसका सामना नहीं पड़ा था।

देश में दूसरे मजबूत प्रतिद्वंद्वी दल के अभाव के कारण कांग्रेस को अपने संगठन के भीतर गुटबंदी को सहन करना पड़ा। यह गुटबंदी किसी सिद्धान्त या कार्यक्रम के आधार पर नहीं थी। जब तक कांग्रेस की सत्ता निर्वाह रही तब तक इससे देश की राजनीति में निरंतरता और एकरा बनी रही। लेकिन जहाँ तक व्यापक व्यवस्था का प्रश्न है, कांग्रेस की आंतरिक गुटबंदी, कांग्रेस के दूसरे दलों द्वारा सत्ताच्युत कर दिए जाने में ज्यादा हानिकारी है। इसी प्रकार की आंतरिक गुटबंदी, पद की यही लड़ाई अनेक नए देशों में लोकतंत्री व्यवस्था के टूटने का कारण सिद्ध हुई है।

शुरू से ही भारतीय राजनीतिज्ञों ने अल्प या भिन्न मतां से समझौता करने और विभिन्न तत्त्वों को साथ लेकर चलने पर जोर दिया। कांग्रेस के नेता यह जानते थे कि अभी बहुत दिनों तक कांग्रेस की एकछत्रता कायम रहेगी, इसलिए उन्होंने देश की एकता और स्थिरता की खातिर राजनैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी समझौतों का साथ लेकर चलने का प्रयत्न किया और समझौते की भावना से काम लिया। भारत का संविधान त्रिपक्ष अपने अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ में ग्रेनविल आर्स्टिन ने लिखा है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान की रचना मंदार सिद्धांत से काम लिया। एक यह है कि सभी निर्णय सहमति से किए जाएं, बहुमत के जोर पर नहीं। दूसरा, समझौते की भावना अर्थात् अल्पमत या भिन्न मतवालों का अधिकार से अधिक रखा। ये दोनों बातें भारत की मौलिक देन हैं।^३ राजनैतिक पक्ष का दुराश परिणाम देश के नेता इन चारों के थे। उनको यह भी समझ थी कि बहुमत के जोर से फैसला लादना नए लोकतंत्र के लिए अच्छा न होगा। इसलिए दुनिया की मुद्रा पर कांग्रेस के नेताओं ने विरोधियों की सहमति प्राप्त करने की काशिश की। किन्तु अल्पमत की भावनाओं का उचित ग्याल रखा हुआ भी उन्होंने आनुपातिक प्रतिनिधित्व अप्रत्यक्ष चुनाव अल्पसंख्यक मजहूरा की विशेष प्रतिनिधित्व और स्विटजरलैंड जैसे मजिस्ट्रेट आदि अल्पमतों के संरक्षण के विशेष उपायों को नहीं अपनाया क्योंकि वे ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था करना चाहते थे जो भारतीय समाज की अनगढ़ वाली प्रवृत्तियों को काबू में रख सके।^४ भारतीय नेताओं के मामले यह बात स्पष्ट थी कि राज्य का जो ढांचा उन्हें विरासत में प्राप्त हुआ, उसीके भीतर उन्हें एक राष्ट्र का निर्माण करना है और उन्होंने अपनी सांस्कृतिक परंपरा और राजनैतिक साधन दोनों का उपयोग इस उद्देश्य से किया कि जिस वास्तव की रचना की जा रही हो, उस लोग दिल से स्वीकार करें।

कांग्रेस पार्टी की रीति नीति में भी इसी प्रकार समझौते की भावना और देश की स्थिरता और दृढ़ता का ध्यान रखा गया। कांग्रेस का मुकाबला करने वाला कोई मजबूत देश में न था इसलिए भी उसे अल्पमत का ख्याल रखना जरूरी हो गया जिससे देश में द्रोह और असंतोष के कारण फूट और अलगाव की प्रवृत्ति न पैदा हो। प्रांतीय और स्थानीय कांग्रेस में जहां प्रतिस्पर्धी गुटों और नेतृत्व के लिए प्रतिद्वंद्विता का स्थान दिया गया, वहां इस बात पर भी जोर दिया गया कि नेताओं में कोई भी परिवर्तन हाइकमांड या सर्वोच्च नेतागण की अनुमति के

^३ ग्रेनविल आर्स्टिन—'द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कानर स्पेन ऑफ ए नेशन' (लंदन १९६६)—अध्याय १२।

^४ ग्रेनविल आर्स्टिन—'द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कानर स्पेन ऑफ ए नेशन' (लंदन १९६६)—अध्याय १३।

परिणाम यह होगा कि कुछ समय बाद उसको चुनाती देने वाले दल उत्पन्न हो और राजनैतिक विचारधाराओं के आधार पर विरोधी दल का संगठन हो। दखने की बात यह है कि सत्तारूढ़ दल इस प्रतिद्वंद्विता को बिना बटुता के स्वीकार करता है और सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार होना है या नहीं, और नए सत्ताधिकारी राजनैतिक व्यवस्था की बुनियादी बातों का स्वीकार करते हैं या नहीं। यदि सत्ता का परिवर्तन बिना शगड़ा झझट के हाता है तो राजनैतिक व्यवस्था और संवैधानिक प्रणाली मजबूत होगी और लोगों के जीवन में घर करेगी। यदि ऐसा नहीं होता और सत्तारूढ़ तथा विरोधी दल लोकतंत्री परंपरा का पालन नहीं करते तो राजनैतिक और संवैधानिक ढांचे के टूटने की क्रिया शुरू हो जाएगी।

इस प्रकार की स्थिति भारत में १९६२ और १९६७ के बीच उपस्थित हुई। दो लड़ाईयां, और आधिकारिक सफाई के बाद चुनाव हुआ जिसने कांग्रेस की एकछत्रता और स्थिर सरकारों के युग का अंत कर दिया। ५ वर्षों के अंदर इतनी घटनाओं के घटने से एक सफाई का सा वातावरण मालूम पड़ा।

१९६७ के चुनाव एक बड़े राजनैतिक परिवर्तन का द्योतक समझा गया। इसने इतने दिनों से चली आयी कांग्रेस की प्रधानता का अंत कर दिया। परंतु राज्यों में निर्वाचन के दल और आम चुनाव के बाद की घटनाओं का हमारा विश्लेषण इस धारणा की पुष्टि नहीं करता। फिर भी यह समझने के लिए कि राजनैतिक व्यवस्था में नई स्थिति के अनुसार चलने की क्षमता है या नहीं, हम यह मान लेते हैं कि १९६७ में जिस प्रक्रिया का आरंभ हुआ वह बाद के चुनावों में भी कायम रहेगी और हम यह देखेंगे कि यदि कांग्रेस की प्रधानता सचमुच समाप्त होगी, तो राजनैतिक व्यवस्था किस ओर जाएगी।

(१) चुनाव में विफलता होने और शक्ति घट जाने के बाद भी कांग्रेस खतम नहीं हुई बल्कि अनेक राज्यों में मयावधि चुनाव और स्थानीय संस्थाओं के चुनावों में इसने खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। इसने समान विचारधारा वाले दूसरे दलों से समझौता करने और स्थिति के अनुसार रीति नीति बदलने की तत्परता दिखाई है। अभी भी कांग्रेस देश की सबसे संगठित पार्टी है जिसका संगठन देश भर में फैला है। परिणामस्वरूप वेदों में इसका बहुमत बना रहेगा और संयुक्त सरकार या अल्प दल के साथ गठजोड़ में इसका पल्ला भारी रहेगा। दूसरे जिन राज्यों में इसकी सरकार नहीं भी रहेगी, वहां भी स्थानीय संस्थाओं में इसके हाथ में काफी शक्ति और लोगों को लाभांवित करने के अवसर रहेंगे।^५

(२) जहां जय वामपंथी या दक्षिणपंथी दल या संयुक्त दलों की सरकार है वहां भी इन्होंने कांग्रेस द्वारा स्थापित की गयी बुनियादी संवैधानिक और राजनैतिक

^५ माइल वाइलर - 'पार्टी डिस्मिशन इन ए नेशन - द इन्डियन नेशनल कांग्रेस (शिमागो - १९६७)।

बिना न हो। कांग्रेस के जदरूनी सगडो को निपटाने के लिए दोना पम्पो में समझौता कराने के साथ साथ ऊपर से मध्यस्थता या निणय की बाकायदा व्यवस्था की गई। यद्यपि कानून में यहा प्रारम्भिक चुनावो की कोई व्यवस्था नही है फिर भी जिला और प्रातीय कांग्रेस और अन्त में सर्वोच्च मटली द्वारा चुनाव के लिए उम्मीदवारो के चयन की विस्तृत पद्धति बनी, जिससे बाहरी दलो की स्पर्धा न होते हुए भी कांग्रेस के भीतर लोकतन्त्री स्पर्धा की पूरी गुजाइश रही।

हम देख चके हैं कि कांग्रेस जैसे व्यापक संगठन को दल का रूप देने के कारण इसमें दो विशेष प्रवृत्तिया दीव पडी। एक तो कांग्रेस के अंदर के गुटो में बाहर के मुख्य दलो का प्रतिनिधित्व हुआ। दूसरी प्रवृत्ति थी स्थानीय लोकतन्त्र पर कम्युनिस्ट गुट आदि अनेक घडे बन गए। दूसरी प्रवृत्ति थी स्थानीय लोकतन्त्र पर कांग्रेस नेताओ का आग्रह। पचायती राज और विकास काय के लिए स्थानीय सलाहकार समितिया आदि की पूरी प्रणाली की स्थापना ऊपर के नेताओ द्वारा की गई। इनके फलस्वरूप न केवल कांग्रेस का प्रभाव बढ़ा और उसे अपने समयका को अधिकार और लाभ के पद बांटने के अवसर मिले, बल्कि इसके साथ ही सर्वोच्च नेताओ और नीचे के लोगो के बीच संपर्क की बड़िया बनी, और असतोष व फूट की प्रवृत्ति को अकुशित करने की व्यवस्था हुई। जमींदारी उन्मूलन और दबी व पिछडी जातिया को विशेष संरक्षण देकर असतोष और संपर्क की जड़ बांटने की कोशिश की गयी और राजनैतिक व्यवस्था की दृढ़ता और स्थिरता बढ़ाने का उपाय किया गया।

कांग्रेस की प्रधानता के साथ साथ उसका जदरू प्रतिद्वंद्विता की गुजाइश में एक बात और नदय करने की है। यह है नेताओ के व्यक्तिगत अनुयाइयो का जाल। जहा इन व्यक्तिगत गुटबंदियो से राजनीति में कुछ स्थिरता आई बहा इसका एक अच्छा नतीजा यह हुआ कि इनके माध्यम से स्थानीय गुटबंदी को राजनैतिक रूप मिल गया और वे खतरनाक या घातक रूप न धारण कर सकी। इनके कारण ऊपर के नेताओ को स्थानीय हालता की सही सूचना भी मिलनी रही और ऊपर की बात नीचे तक फलती रही।

इस प्रकार प्रतिस्पर्धी पार्टी या दल के अभाव में भी एक दशक तक सत्तदीय लोकतन्त्र चलता रहा और कांग्रेस दल के अंदर के गुट प्रतिद्वंद्वी दलो की भूमिका बढ़ा करते रहे। तथा व्यापक अगिदा और बलवार आदि जानकारी के बहुत कम साधनो के बावजूद जनता और नेता में संपर्क कायम रहा।

चुनाव की प्रणाली

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है जब मतदाता और शक्तिशाली दल लोकतन्त्री प्रवृत्तिया और गतिविधिया का पूरा प्रोत्साहन और छूट देता है, तो इसका स्वाभाविक

परिणाम यह होगा कि कुछ समय बाद उसको चुनौती देने वाले दल उत्पन्न हो और राजनैतिक विचारधाराओं के आधार पर विरोधी दल का संगठन हो। दबने की बात यह है कि सत्तारूढ़ दल इस प्रतिद्वंद्विता का प्रिना बटुता के स्वीकार करता है और सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार होता है या नहीं, और नए सत्ताधिकारी राजनैतिक व्यवस्था की बुनियादी बातों का स्वीकार करने हैं या नहीं। यदि सत्ता का परिवर्तन बिना बगड़ा झगड़ के हाता है तो राजनैतिक व्यवस्था और संवैधानिक प्रणाली मजबूत होगी और लोगों के जीवन में घर बरगी। यदि ऐसा नहीं होता और सत्तारूढ़ तथा विरोधी दल लोकतंत्री परंपरा का पालन नहीं करते तो राजनैतिक और संवैधानिक ढांचे के टूटने की क्रिया शुरू हो जाएगी।

इस प्रकार की स्थिति भारत में १९६२ और १९६७ के बीच उपस्थित हुई। दो सड़कियाँ, और आर्थिक संकट के बाद चुनाव हुआ, जिसने कांग्रेस की एकलपक्षता और स्थिर सरकारों के युग का अंत कर दिया। ५ वर्षों के अंदर इतनी घटनाओं के घटने से एक संकट का सा वातावरण मालूम पड़ा।

१९६७ के चुनाव एक बड़े राजनैतिक परिवर्तन का द्योतक समझा गया। हमने इतने दिनों से चली आयी कांग्रेस की प्रधानता का अंत कर दिया। परंतु राज्यों में निर्वाचन के रुख और आम चुनाव के बाद की घटनाओं का हमारा विश्लेषण इस धारणा की पुष्टि नहीं करता। फिर भी यह समझने के लिए कि राजनैतिक व्यवस्था में नई स्थिति के अनुसार चलने की क्षमता है या नहीं, हम यह मान लेते हैं कि १९६७ में जिस प्रक्रिया का आरंभ हुआ वह बाद के चुनावों में भी कायम रहेगी और हम यह देखेंगे कि यदि कांग्रेस की प्रधानता संवैधानिक समाप्त होगी, तो राजनैतिक व्यवस्था किस ओर जाएगी।

(१) चुनाव में विफलता होने और शक्ति घट जाने के बाद भी कांग्रेस खतम नहीं हुई बल्कि अनेक राज्यों में मजबूत चुनाव और स्थानीय संस्थाओं के चुनावों में इसने खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। इसने समान विचारधारा वाले दूसरे दलों से समझौता करने और स्थिति के अनुसार रीति नीति बदलने की तत्परता दिखाई है। अभी भी कांग्रेस देश की सबसे संगठित पार्टी है जिसका संगठन देश भर में फैला है। परिणामस्वरूप केन्द्र में इसका बहुमत बना रहेगा और संयुक्त सरकार या अल्प दल के साथ गठजोड़ में इसका पल्ला भारी रहेगा। दूसरे जिन राज्यों में इसकी सरकार नहीं भी रहेगी, वहाँ भी स्थानीय संस्थाओं में इसके हाथ में काफी शक्ति और लोगों को लाभांशित करने के अवसर रहेंगे।^५

(२) जहाँ जय वामपंथी या दक्षिणपंथी दल या संयुक्त दलों की सरकार है, वहाँ भी इन्होंने कांग्रेस द्वारा स्थापित की गयी बुनियादी संवैधानिक और राजनैतिक

^५ माइकल वाइजर - 'पार्टी बिहिंग इन ए नेशन - द इंडियन नेशनल कांग्रेस (गिगागो - १९६७)।

परपरा और नियम का अस्वीकार नहीं किया। इनके कार्यक्रम और नीतियाँ भी कांग्रेस से कोई खास भिन्न नहीं हैं। बल्कि अनेक पार्टियों का तो यह भी दावा है कि वे कांग्रेस की नीतियों को कांग्रेस की अपेक्षा ज्यादा अच्छी तरह से कार्या-
वित कर रही ह।

(३) कांग्रेस की प्रधानता के युग में जो दलबन्दी और गुटबन्दी दिखाई पड़ी, वे १९६७ के बाद भी कायम रही। अनेक राज्यों में कांग्रेस में फूट पड़ने पर कांग्रेस के दलबन्दीवादी की महायत्ना से नई सरकारें बनीं। द्र० मु० व०, जनसंघ और वामपक्षी दला में भी कांग्रेस जैसी ही दलबन्दी देख पड़ी। जिस प्रकार कांग्रेस के अंदर दक्षिण और वाम पक्ष थे उसी तरह गैर कांग्रेसी दला या समुक्त दला में भी कांग्रेसी गुट या पक्ष देखने में आए। दक्षिण और वाम पक्ष के बीच का मांग पकड़ने की प्रवृत्ति समित्त हुई जिससे दला की परिधि के बाहर जाकर सीढ़ा करने और नए गठजोड़ करने की क्रिया चालू रही। इस प्रकार राजनीतिक स्थिति बदलने और नए दला तथा नई राजनीतिक पीढ़ियाँ के आगे आने पर भी पुराना राजनीतिक लहजा कायम रहा।^६

(४) कुछ नई प्रवृत्तियाँ देख पड़ीं जिससे पता चलता था कि राजनीतिक परि-
पाटियाँ जड़ पकड़ रही हैं। पहले कांग्रेस के नेता सभी मला और हिता को समूठन में स्थान देने को तैयार रहते थे। अब उद्देश्य और समूठन की एकता पर जोर दिया जाने लगा और मतभिन्नता के कारण पार्टियाँ छोड़ने वाला को रोका नहीं जाता था।^७ इसी अवधि में भिन्न मत वाले गैर कांग्रेसी दला में जा गठबन्धन हुए व टिकाऊ नहीं सिद्ध हुए और उन्होंने यह अनुभव किया कि सिर्फ कांग्रेस-विरोध की राजनीति से कोई नतीजा नहीं निकलेगा और उ ह निर्वाचन क्षेत्रों में या जनता के बीच में काम करना चाहिए। अनेक दला ने विशेष क्षेत्रों में अपने पांव जमा लिए और उन्होंने धीरे धीरे अपना प्रभावक्षेत्र बढ़ा कर कांग्रेस से टक्कर लेने की नीति अपनाई।

(५) राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों की स्थापना से यह आशंका हुई थी कि वेदों की कांग्रेस सरकार से इनका सघष हागा और सघीय व्यवस्था टूट जायगी। यह आशंका गलत सिद्ध हुई। देखने में यह आया कि जिन राज्यों में अपेक्षाकृत टिकाऊ गैर कांग्रेसी सरकारें थी उनसे बरतने में केन्द्रीय सरकार को ज्यादा आसानी हुई, बजाय कांग्रेसी राज्य सरकारों से। हा, जहां वामपक्षी मोरच की सरकार थी

६ उदाहरण के लिए मद्रास में द्र मु क में अन्तर्द्वन्द्व उठने पर वहा भी मांग हुई कि कुछ मंत्री नेतापद त्याग करके पार्टी का काम करें पैसा कांग्रेस में कामरान प्था में हुआ था।

७ १९६७ के चुनाव के पहले भी इस बात को स्पष्ट किया गया था—इन्क. एच मारिस - तोस द इंडियन कमिनि पार्टी - ए डिडेमा आफ टाभिनेस - मार्न प्रशियन स्थीन १ स २ १९६७।

जैसे बेरल और बगाल में, वहाँ ज्यादा उग्र दला को बावू में रखने में कठिनाई हुई। किंतु मोरचे की इन सरकारों ने एक आर ऐसी रियायतें दी जिससे उग्र-पणियों को कुछ सन्तोष हो और प्रीवेनेन्स या प्रचार का लाभ हो। दूसरी ओर इन्होंने केन्द्र से बातचीत में यथावधानी दृष्टिकोण अपनाया। समुक्त दल या मोरचे में सकट आने या उनके भंग होने की स्थिति में केन्द्र ने हस्तक्षेप किया और अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग किया। आर्थिक क्षेत्र में बैंक के राष्ट्रीयकरण और पूजा नियोजन व ऋण का नियमन करके केन्द्र सरकार ने बड़े कदम उठाए। आर्थिक शक्ति और साधन केन्द्र के हाथ में ह, और राज्या की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति, केन्द्र के द्वारा हाथी इम बात का अनुभव किया गया। इसके साथ ही यह भी प्रत्यक्ष था कि ठीक वाम न करने पर चुनाव में हार खानी पड़ेगी। इन सबम केन्द्र की शक्ति की पुष्टि हुई और गैरकांग्रेसी दला की सरकारों ने भी केन्द्रीय सरकार के मन्त्र का स्वीकार किया।

(६) जहाँ इन प्रवृत्तियों से राजनतिक व्यवस्था और लोकतन्त्री पद्धति को बल मिला वहाँ कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ भी दोग पड़ीं जो इसका कमजोर करती ह। ऐसी एक प्रवृत्ति है सरकार की अस्थिरता। सीमाश्रयित राजनतिक दलों ने यह अनुभव कर लिया कि बार बार दल बदलने का जनता पसंद नहीं करती और इससे चुनाव में दल बदलने वाला को चुनसान उठाना पड़ सकता है। राज्यपाल और केन्द्र सरकार दलबदल और सरकार टूटने की हालत में हस्तक्षेप कर सकते ह, और राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, इससे भी सरकार जलटने वाला को निरुत्साह मिला। फिर भी समुक्त दला की सरकार की अस्थिरता की समस्या बनी हुई है। गैर कांग्रेसी दल अभी भी अपने पर नहीं जमा पाए ह। " प्रश्न यह है कि यदि मध्यावधि और आम चुनाव के बाद भी टिकाऊ सरकार न बन सकी और मजबूत दल आगे न जा सके तो क्या होगा। ऐसा लगता है कि यदि हरियाना की तरह मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस वापस न आ सकी या मद्रास उड़ीसा, पश्चिम बगाल और बेरल की भाँति मजबूत गैरकांग्रेसी सरकारें न कायम हो सकी, तो राज्या में अस्थिरता, नए गठबंधन और बीच बीच में राष्ट्रपति शासन का दौर चलता रहेगा।"

८ देखें अ. पाय - में दलों की सारणी। ध्यान रहे कि भारत में गैरकांग्रेसी दलों का गठन (कीआलशन) यूरोप की समुक्त दल सरकारों से भिन्न है। फ्रान्स आदि यूरोपीय देशों में मोरचे में शामिल विभिन्न दल अपने अपने क्षेत्रों में काफी मजबूत ह, भारत के दल अभी भी पक्की तरह पर नहीं जमा पाए ह, और चुनावों में उनकी शक्ति घटता बढ़ता रहती है। कम्युनिस्ट और कुछ हद तक जनमध को छोड़ कर कांग्रेस ही ऐसा दल है जो मतदाताओं के प्रति जिम्मेदारी अनुभव करता है या जिसे निर्वाचकों की नाराजी का मय है।

९ केरल में म. प्रावधि चुनावों में स्थिति बदली है। यहाँ कांग्रेस और कम्युनिस्ट मोरचे ने [अगले पृष्ठ पर]

दूसरी बात यह है कि गैरवाग्रेसी सरकारों के टिक न सकने के कारण, सब दलों में निराशा उत्पन्न हो सकती है और वे अगवैधानिक तरीकों पर उतर सकते हैं। इंदिरा गांधी के बढ़ते हुए प्रभाव से यह निराशा और तीव्र हो सकती है। जब तक यह दल सत्ता में नहीं आ सकने थे तब तक वे विधान सभा में कांग्रेस की टीका टिप्पणी और चुनौती में उस हराने की आशा से मनोप कर सकने थे पर एक बार सत्ता में आकर पुनः उससे वंचित होनेसे इनमें गहरी निराशा और कुठाग्र उपद्रवितता उत्पन्न होती है। भारत में दल पद्धति की प्रवृत्ति मजबूत क्षेत्रीय दलों का विकास में है जो केन्द्र में मताच्छेद दल के विरोधी हैं। इससे जनता के राजनैतिक संगठन में सहायता मिली है। साथ ही इसमें खतरा यह है कि यदि इन क्षेत्रीय दलों की सरकार में म्यान न मिला तो ये उपद्रव का मूल अस्तिपार कर सकने हैं।

तीसरे, राज्या में समुक्त दलों की सरकारों की अस्थिरता इसी तरह बनी रही और बार बार केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप करना पड़ा तो सारा ध्यान सरकार की अस्थिरता और राजनैतिक एकाकीता की हिफाजत पर ही केंद्रित हो जाएगा और आर्थिक समस्याओं तथा सामाजिक प्रश्नों की उपेक्षा हो जाएगी यद्यपि अभी तक इसका कोई निश्चिन्त सूत्र नहीं है। १० इस प्रश्न पर हम अगले अध्याय में विचार करेंगे।

इससे एक प्रश्न और उठता है। क्या विभिन्न दल राजनीति के बुनियादी नियमों का पालन कर रहे हैं? राजनैतिक दलों को जिस प्रकार आचरण करना चाहिए, क्या वे उस ढंग से आचरण कर रहे हैं? सविधान में दलों की प्रतिद्वंद्विता निहित है। मूल में मजबूत प्रतिद्वंद्वी दलों का अभाव था। १९६७ के बाद कांग्रेस के विरोधी दलों ने जोर पकड़ा और दल या पार्टी पद्धति सविधान के मजदीक आती दिखाई पड़ी। किंतु अभी भी एक पार्टी की प्रधानता अत्यंत नहीं हुई थी। इससे सविधान और राजनैतिक प्रक्रिया के द्वार में कुछ विवाद लगे हुए। कांग्रेस के केन्द्रीय नेताओं में फूट के लक्षण दिखाई पड़ने से केन्द्रीय सरकार का स्थायित्व अदिग्ध हो गया और इससे तोड़फोड़, दलबदल आदि की अनुचित प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला।

विवाद के मुख्य मुद्दे ये थे—विधान सभा में बहुमत और सरकार बनाने का दावा करने वाले दलों की शक्ति की परीक्षा किस प्रकार हो, खाम कर जब दलबदल

[विच्छेद से]

माकमवादी कम्युनिस्टों की अपेक्षा कर दिया है। १९७१ के चुनाव में उद्देश्य और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने पुनः काशी हार तक शक्ति प्राप्त की है, और उसकी प्रतिद्वंद्वी स्वतंत्र और पश्चिम बंगाल में माकस कम्युनिस्ट समुक्त सरकार बनाने की क्षमता में नहीं है।

१० इंदिरा गांधी ने राजनैतिक दलों का आर्थिक प्रश्नों की आधार देने की काशिश की। यद्यपि उनकी यह चाल राजनैतिक थी और इसका उद्देश्य राजनीति के चुनाव में कांग्रेस के पुराने नेताओं की मात देना था।

की घटनाएँ हा रही हैं, राज्य का शासन संविधान के अनुसार चल सकता है या नहीं और राष्ट्रपति का शासन लागू हो या नहीं इस विषय में सत्ताह देने का राज्य पाल का अधिकार, विधानमंडल के अध्यक्ष के अधिकार, विधानसभा किस स्थिति में भंग हो और सत्रों से बड़ा प्रश्न संवैधानिक सत्र के समय राष्ट्रपति के अधिकार इन सब विषयों पर संविधान में कुछ न कुछ कहा गया, परंतु इन पर स्पष्टीकरण होना और एक परिपाटी का स्वरूप होना आवश्यक है। इन प्रश्नों पर अभी अनिश्चित की स्थिति है।

राजनैतिक परिवर्तन की स्वीकृति

राजनैतिक विकास की एक बड़ी बात यह है कि सरकार का परिवर्तन कितनी आसानी से होता है। अनेक देशों में राजनैतिक परिवर्तन के समय बड़ी उथल-पुथल मची और इस प्रश्न पर अनेक राज्य-व्यवस्थाओं का भाग्य निर्भर है।^{११} छोटे ही देश ऐसे हैं जहाँ सत्ता-परिवर्तन की प्रकृति सुस्थिर हो गई है और लोगों में ग्राह्य हो चुकी है। भारत के लिए भी कहा गया कि इस प्रश्न पर संविधान का भविष्य निर्भर है। जब तक कांग्रेस की प्रधानता और जवाहरलाल नेहरू जैसे चमत्कारी व्यक्तित्व मौजूद हैं तब तक राजनीतिक स्थिरता की कोई खतरा नहीं। किंतु इसके बाद क्या होगा? नेहरू और उनकी पीढ़ी के प्रभावशाली नेता एक एक करके उठने लगे और कांग्रेस हाइवामान में फूट और खगड़े पैदा होने लगे। हमारे १९५० के दशक के उत्तरार्ध से लेकर ६० के दशक तक, भारत में क्या होता है, इस पर ध्यान लगा रहा और अनिश्चित बना रहा।^{१२}

१९६४-६७ के बीच तीन बार उत्तराधिकार का प्रश्न उठा। इन्हीं वर्षों में देश की विपक्ष बाहरी और आंतरिक सत्र भी झेलने पड़े। इस विषय में कुछ बातें ध्यान योग्य हैं जिनसे भारतीय व्यवस्था के परिवर्तन कर सकने की क्षमता और परिपाटी पर प्रकाश पड़ता है।

११ सोवियत संघ, युगोस्लाविया, फ्रांस, चीन, क्यूबा, पाकिस्तान और मित्र इन सब देशों की अर्ध-रक्त कमीटी पर गहरा छतरना बाका है, यद्यपि और तरह से इनकी राजनैतिक व्यवस्था काफ़ी सफल सिद्ध हुई है। रोज़गार देश में मरुभूमि का संचयन धनिया और कुछ हद तक श्रीलंका का भी अभी पराक्षा बाका है। इजरायल में बैन गुरियन के बाद लेवी इसकोल और उसके बाद गोल्डा मायर का चुनाव इसका चोकर है कि वह इस पराक्षा में खरा उतरा। मेक्सिको में भी उत्तराधिकार या सरकार बनने की अपनी एक प्रकृति बन गयी है।

१२ नेहरू के बाद क्या? इस प्रश्न पर विदेशी लेखकों ने काफी अटकल-बातियाँ कीं। दूरें-आफ़टर नेहरू हूँ (न्यूयार्क १९८२) के वेल्स हैंगन। भारत में नेहरू की बामरा के बाद १९६३ में जनमत की पटताल की गई। 'आफ़टर नेहरू हूँ' मथली पब्लिश औपनिवेशिक सर्व न १०१, १९६३ (इंडियन इस्टी पब्लिक ओपिनिशन)।

नेहरू ने अपना उत्तराधिकारी चुनने से दबतापूर्वक इन्कार किया। उनका कहना था कि मुझे लोकतंत्री पद्धति पर पूरा विश्वास है और मैं नेता के चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। मुझे विश्वास है कि भारत की राजनैतिक व्यवस्था इतनी प्रौढ़ हो चुकी है कि वह मेरी छति को सहन कर लेगी और कांग्रेस पक्ष में इतनी समझदारी है कि वह इस ऊँचे पद के उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव कर लेगा। यही नहीं यदि मैं किसी व्यक्ति का अपना उत्तराधिकारी बनाऊँगा, तो लोग उससे जलज, उसका विराय करेंगे और वह कदापि प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा।^{१३} इसलिए नेहरू ने कोई उपप्रधान मंत्री भी नहीं नियुक्त किया और मंत्रियों की घरिष्ठता का श्रम भी निर्धारित नहीं होने दिया।^{१४} इससे प्रतिकूल गांधीजी ने स्पष्ट रूप से नेहरू का अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इन दोनों नेताओं के व्यवहार ने इस अन्तर से देश में राजनैतिक पद्धति का विकास का क्रम स्थानित होता है।

(२) लेकिन नेहरू को उत्तराधिकार के बारे में चिंता थी। उत्तराधिकारी नियुक्त न करने में उनकी यह भावना भी थी कि दल में जोर के शीघ्र सरकार में गहरी फूट न पड़ जाए। वह देश और कांग्रेस दल के सघीय या सावधानिक रूप को समझते थे और यह भी समझते थे कि बिना सब लोगो की राय लिए ऊपर से कोई निश्चय लादना घातनाक है। उनका प्रभाव दल पर इतना अधिक छा गया था कि उसमें स्वतंत्र विचारविनिमय की श्रिया रुक सी गई थी और वह उनका ही उलगा बन गया था। इसलिए उन्होंने कामराज योजना या सक्रिय समर्थन दिया जिसका उद्देश्य यह था कि प्रमुख मंत्री अपना सवारी पद छोड़ कर दल का काम में लग जाय पर जिसका असली उद्देश्य कांग्रेस के सघीय ढाँचे को फिर न गिराणी करना था। उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के महत्त्व और तात्त्विक सक्त या आवश्यकता के समय उस के अधिकार की पुन स्थापना की। उन्होंने इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि देश के प्रधानमंत्री के चुनाव में राज्या के मुख्यमंत्रियों में राम नेता जरूरी है। उन्होंने कामराज को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया और श्री लाल बहादुर शास्त्री को बीमार प्रधानमंत्री को सहायता देने के लिए अविभागीय मंत्री

१३ नेहरू के साथ अन्तान्ध साधनेरिस्त की देखाविज्ज सुलगात। भारतेर आचार-नेहरू मेंटि-पाठिक्ता और सम्मेशन इन श्रिया (न्यूयार्क १९९९)।

१४ सन १९४७ से १९५० तक सरदार वल्लभभाई पटेल उपप्रधान मंत्री थे और नेहरू के साथ सत्ता की साझादार थे। उनकी मृत्यु के बाद वह पद खाली रहा। १९६० में इस पद पर कांग्रेस समर्थी दल में को लिये गये किंतु इस पर राजनीति मन्त्रिमंड प्रकाश हुआ कि नेहरू ने किसी को इस पद पर नहीं नियुक्त किया। नेहरू की बीमारी के समय, उपप्रधान मंत्री की नियुक्ति की मांग की गयी, किंतु नेहरू ने ने स्वीकार नहीं किया। क्योंकि वह समझते थे कि इस समय में उपप्रधान मंत्री होगा, वह स्वतः प्रधानमंत्री बन जाएगा। इस विषय में देखिए-पूर्वोक्त पृ १४-१०३।

नियुक्त किया। इस प्रकार उन्होंने दल की आम राय से प्रधानमन्त्री के चुनाव का पथ प्रशस्त किया। उन्होंने अतः तब अपनी पसन्द नहीं जाहिर की और लालबहादुर शास्त्री को उपप्रधानमन्त्री का पद नहीं दिया।

नेहरू की मृत्यु के बाद नेता या प्रधानमंत्री के चुनाव का कोई नियम नहीं हुआ था। किन्तु यह सिद्धांत मान लिया गया था कि ऐसा तरीका निकाला जाना चाहिए जो सबका स्वीकार्य हो। दल के नेताओं ने यह तरीका तुरंत ही निकाल लिया। यह समझा जाता हुआ कि दल के मुख्य लागा की जो आम राय हो, उसी को दल का नियम माना जाए। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस कार्यकारिणी, संसदीय दल के पदाधिकारी दल के अध्यक्ष नेता और संसदीय दल के २०० सदस्यों से मशविरा करके लालबहादुर शास्त्री के पक्ष में आम राय घोषित की।^{१५} यह नियम वास्तव में दल के सबसे शक्तिशाली लोगों का नियम था और इसका कराने में कांग्रेस अध्यक्ष का मुख्य हाथ था। इस प्रकार उन्होंने इस प्रश्न पर पार्टी में फूट को टालने का यत्न किया। इसके बाद कांग्रेस संसदीय दल की बैठक ने रस्मी तौर पर हाइकमान के फैसले पर मुहर लगा दी गयी। कांग्रेस अध्यक्ष की सदारत में संसदीय दल की बैठक हुई, इसमें शास्त्री सर्वमत से नेता चुने गए और राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का निमन्त्रण दिया। आम राय की सारी कारवाइ बहुत कम समय में पूरी हो गयी यद्यपि उसमें इतने आदमिया से मशविरा किया गया।

२ जून १९६४ को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के केवल ५ दिन और १६ घंटे बाद संसद के संसदीय दल में कांग्रेस संसदीय दल की असाधारण बैठक में लालबहादुर शास्त्री सर्वसम्मति से दल के नेता चुने गए। सात घंटे बाद राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने उन्हें नयी सरकार बनाने का योता दिया। इसके साथ नेहरू के उत्तराधिकारी के चयन की कारवाइ पूरी हो गई। जिन लोगों ने इन ६ दिन की घटनाओं में भाग लिया और जिन्होंने इसका देखा, उन सब के लिए एक युग का यह बड़ा शांतिपूर्ण अन्त था। संसार में बहुत से लोग थे जिन्होंने नेहरू के बाद भारत में होनेवाली अव्यवस्था का बड़ा डरावना चित्र खींचा था। उनकी आशंकाएँ निरावार सिद्ध हुई। लेकिन जिन लोगों ने ऐसी आशंका नहीं की थी उन्हें भी सत्ता के इतनी सरलता और शांतिपूर्ण परिवर्तन से सुन्दर आश्चर्य हुआ।^{१६}

१५ शास्त्रीजी के मुख्य प्रतिस्पर्धी मुरारजी देसाई थे, जिनका नेहरू से मनभेद सर्वजिदित था। वह दक्षिणपंथी समझे जाने थे और अधिकतर मुख्यमंत्री उनके विरुद्ध थे। कामरान और शास्त्री दोनों दक्षिण और वाम पक्ष के बीच के समझे जाते थे और उनमें आशा की जाती थी कि वे नेहरू के वायव्य पक्षी चालू रखेंगे। कामरान ने आग के दो चुनावों में भी प्रधानमन्त्री निर्वात का पार्श्वभूमि किया और वह तटस्थ माने जाते थे। ग्रेटिफ, पूर्वोक्त अध्याय दो, तीन तथा चार के वैकटश्वरन्, 'केबिनेट गवर्नमेंट इन इंडिया' (लंदन १९६७) अ १०।

१६ ग्रीचर-पूर्वोक्त, पृ ६ में आम राय मान्य करने के कामराज के तराई पर विचार किया गया है।

इस प्रकार उत्तराधिकार का पहला सबूत सम्पादित हुआ। इस समय कांग्रेस के नेताओं का सबसे अधिक ध्यान इस बात पर था कि कांग्रेस की ओर देश की एकरा बनी रहे और नेता का चुनाव लोकतंत्री तरीके से हो, साथ ही नेतृत्व का द्वय या सघन अनुचित रूप न धारण करने पाए। इस प्रश्न का निपटारा कांग्रेस के मुखिया ने सगठन और दल के सदस्यों की आम भावना को रपाल में रखते हुए किया। नेतृत्व का निपटारा इस तरीके से हुआ, इसमें नेहरू को भी श्रेय था।

(३) १६ महीने प्रधानमंत्री रहने के बाद जब लालबहादुर शास्त्री का निधन हुआ, तब पहले जैसी सकट की स्थिति नहीं थी। देश की एकता भंग होने का डर न था। यह सिद्ध हो चुका था कि देश में नेता के शून्य स्थान को भरने की क्षमता है। जिस प्रकार नेहरू का निधन एक युग के अंत का द्योतक था उस प्रकार शास्त्री का देहांत नहीं। बल्कि नए नेता के चुनाव का प्रश्न एकाएक पहले से आम राय या समझौते की कोशिश का बिना मौका दिए आ खड़ा हुआ था। शास्त्री की मृत्यु भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ताश्कंद सम्मेलन के बाद अचानक हा गयी। शास्त्री के बाद क्या होगा इस पर विचार की जरूरत ही नहीं हुई थी और शास्त्रीजी ने अपने उत्तराधिकारी के लिए रास्ता बनाने की कोई कारवाई ही नहीं की थी। उत्तराधिकारी कौन है यह स्पष्ट न था, क्योंकि शुरू में इंदिरा गांधी का नाम सामने आया ही नहीं था। चव्हाण, मोरारजी, नंदा, श्रीमती गांधी, जग जीवनराम, स्वयं कामराज अनेक नाम आए। कांग्रेस की हाइकमान में किसी भी नाम पर सहमति न थी सिवा इसके कि मोरारजी न हो। कई प्रश्न उठाए गए, जैसे अगले चुनाव में दल का सबसे अच्छी तरह कौन नेतृत्व कर सकता है। पर कुछ निश्चय न हो पाया।

इस बार पहले वाला तरीका काम में नहीं लाया गया। अब खुले सघन से उतना डर न था। अंत में मामले पर ससदीय पार्टी में गुप्त मतदान हुआ। इस मतदान पर मुख्य मंत्रियों ने बहुत प्रभाव डाला। उनकी साधारण राय इंदिरा गांधी के पक्ष में थी। फिर भी मुकाबला सख्त हुआ। इंदिरा गांधी के पक्ष में, ३५/ और मोरारजी के पक्ष में १६६ वोट आए। मुकाबला शिष्टता के साथ हुआ और अनेक सदस्यों ने अपने राज्य के मुख्य मंत्री की राय न मान कर मोरारजी को वोट दिया। इस प्रकार इस बार चुनाव की पद्धति ज्यादा सुव्यवस्थित और सुस्थित थी और यह बात स्पष्ट हो गयी कि व्यवस्था में नेता का शून्य स्थान भरने की क्षमता है। इसके साथ ही चुनाव में सब धमा या राज्या की ओर कांग्रेस सगठन की इच्छा का ध्यान रखने का महत्त्व भी स्पष्ट हो गया। अंत में आम राय में ही फैसला हुआ पर यह आम राय खुले तरीके से स्थिर हुई, गुप्तचुप नहीं।

(४) जब तक नेहरूजी जीवित थे, हर चुनाव के बाद नेता का निर्वाचन एक रस्म अदायगी थी। परंतु सन १९६७ के आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा

गांधी का फिर से इस पद पर चुना जाना तब बान नहीं मानी जा सकती थी। सन् १९६६ में जब यह नेता चुनी गयी थी, उस समय यह स्पष्ट था कि आम चुनाव के बाद इस प्रश्न पर फिर ग विचार होगा। इस बार राजनैतिक स्थिति यह न थी, जो नेहरूजी और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद थी। इस बार कांग्रेस की शक्ति बहुत कम हो गयी थी। १२१ सदस्या के मदन में उसका बहुमत केवल ८४ का था। कांग्रेस दल में कोई भी फूट पड़ने से सरकार उलट सकती थी। मात राज्या म कांग्रेस की पराजय हो चुकी थी। मद्रास में स्वयं वामराज हार गए थे, और कांग्रेस की गहरी हार हुई थी। इसका यह था कि सन् १९६६ की तरह इस बार कांग्रेस मुख्यमंत्रियों की मंडली नेता के चुनाव को प्रभावित न कर सकती थी। कांग्रेस के अंतरंग गुट के पास रास आदमी हार गए थे। कांग्रेस अध्यक्ष वामराज पहले की तरह आम राय या सहमति को लागू कराने की स्थिति में न थे।

१९६६ का नेता के चुनाव से पता चल गया था कि अल्पमत काफी गतिशील था। भूजि चुनाव कांग्रेस समर्थीय दल का करना था, इसलिए यह भी आशंका थी कि यदि फूट पड़ गयी तो कांग्रेस की सरकार ही उलट सकती थी। दलबदल की जितनी घटनाएं चुनाव के पहले और बाद में हो रही थी, उसका दखते हुए यह आशंका निराधार न थी।

नतीजा यह हुआ कि मुख्य प्रतिद्वंद्वियों में गहरी सीदेवाजी चली। वामराज और कुछ मध्यस्थ लोगों ने वाशिंग की बि बाट लेने की नीयत न आए। इस समय एक नया आर बड़ा गुट सामने आया। यह नेहरू के अनुयायियों का था। यह नहीं चाहता था कि इंदिरा देवें या चुनाव से हटें। दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को अंत में कुछ दबना पड़ा। तब हुआ कि इंदिराजी नेता रहे और दूसरा स्थान मोरारजी को मिले। उन्हें उपप्रधान मंत्री का पद दिया जाए, पर उनको यह विभाग नहीं मिला। यह विभाग च हाण के पास रहा। मोरारजी ने बड़ी उदारता और मदाशयता दिखाई तथा न तो मन्त्रिमंडल के चुनाव में इंदिरा पर कोई बर्दाश लगाने की कोशिश की, न उपप्रधानमंत्री के अधिकारों का स्पष्टीकरण माना।

नतीजा यह हुआ कि जो मन्त्रिमंडल बना, उसमें सभी मंत्रों का प्रतिनिधित्व था। दल की एकता बनी रही और उसने सामूहिक नेतृत्व स्वीकार किया। मोरारजी अनुशासन के पात्र थे और सरकार के अधिकार पर किसी विस्म की बर्दाश लगाने के विरोधी थे। उन्होंने प्रधान मंत्री को पूरा समर्थन दिया। श्वर इंदिराजी को भी अपन गुट (क्वचन कैबिनेट) या दल के प्रमुख व्यक्तियों पर निर्भर रहने की उतनी जरूरत न थी। देश में राजनैतिक अस्थिरता के वातावरण में केन्द्र में एक

मजबूत और मयुक्त नेतृत्व की स्थापना कोई मामूली बात न थी। १०

१९६७ के प्रधानमंत्री या नेता के चुनाव की एक बात उल्लेखनीय है। प्रतिद्वंद्वी गुटा का सारा मोलभाव या सौदेबाजी मुले खजाने हुई। दोनों प्रतिद्वंद्वी कई बार मिले और दोनों ने अपनी बाते स्पष्ट रूप से एक दूसरे के सामने रख दी। दूसरे लोग भी बीच बिचाव कर रहे थे, किंतु इन्होंने मध्यस्था को यह मौका न दिया कि वे जबरदस्ती अपनी शर्तें मनवाए या ज़िच पैदा कर दें। इस प्रकार की मुली बातचीत और विचार विनिमय पहले की अपरत्यक्ष या गुप्त सौदेबाजी से भिन्न था और इससे धागे की आपसी गुटबंदी या मतभेद को निपटाने और समझौता करने की शक्ति बढ़ी। १०

राजनैतिक पद्धति के विकास में भी यह एक महत्वपूर्ण अध्याय था। पहले की तरह एक चमत्कारी व्यक्तित्व के नेतृत्व का स्थाय अब एक सामूहिक नेतृत्व ने लिया। ११

साथ ही राजनैतिक पद्धति के विकास की क्रियाओं भी जारी थी, और स्थिति अस्थिर तथा परिवर्तनशील बनी रही। चौथे चुनाव के पहले और बाद भी कांग्रेस के नेता अपनी जोड़ताड़ बिठाने में लगे रहें। १९६७ के चुनाव के लिए उम्मीदवारों को छोटने में नेताओं का ध्यान नेता व प्रधानमंत्री पद के चुनाव की तमारी

१७ इस समझौते की सरकार का मजबूती १९७७ के राष्ट्रपति के चुनाव में प्रगट हुई। निवाचक मंडल में गर कांग्रेस दलों का बहुमत था। (इसमें राज्यों के विधान मण्डलों और संघ के निवाचित सदस्य होते थे) इन लोगों ने सत्ता के न्यायालय के जज श्री हम्भाराव को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने ए. वाविर हुसैन को। कांग्रेस और खासकर इंदिरा गांधी ने एक मुसलमान को खाना का के बना जोरिय उठाया था। उसने भूमिनिरेक्षता के सिद्धांत को बमोटी बनाकर कांग्रेस के सभी गुणों को एकजुट किया और चुनाव जीत लिया। इसने कांग्रेस की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गया। दूसरी ओर गर कांग्रेस दलों की पूरा आदर हो गई।

१८ भारत के अंतरालों में समझौते की प्रत्येक गतिविधि की पूरी खबर छपती रही। कौन किससे किसके घर पर मिला, उस समय कौन से लोग उपस्थित थे। साधारणतः धारणा यह थी कि भारतीय लोग साफ और सच्चे बात करने में कनराने हैं। इस बातचीत में यह बात नहीं दाख पड़ी। पूरे विवरण के लिए देखें—मार्गरेट टाचर—‘कंसिडरेशन इन इंडिया १९७७—द रोमिनारेशन ऑफ पोलि बैज’ (पब्लिशिंग सॉल, सात, स ७ जुलाई १९६७)।

१९ दूसरी ओर सामूहिक नेतृत्व में परस्पर अविश्वास भा रहता है और सरकार तथा दल के बीच में बाधा पड़ती है। इसी कारण १९६७ के दो वर्ष बाद इंदिरा गांधी ने अपने हटाए जाने के आशयित प्रयत्न को विफल करने के उद्देश्य से कुछ राजनैतिक और आर्थिक कदम उठाए। उन्होंने मोरारजी देसाई को अवदस्त्र कर लिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और दल तथा सरकार से विरोधी गुं का सफाया करने का प्रयत्न किया। १९७१ के मध्य चर्च चुनाव से ‘धरमाली व्यक्ति’ का नेतृत्व फिर से स्थापित होता लभित होता है।

में ही लगा था २० और इस प्रक्रिया में काफी गहरे मतभेद प्रकट हुए । १९६६ में सामूहिक नेतृत्व में दरार पड़ने लगी आर सत्ता का सघन शुरू हुआ । इस समय अविश्वास और सदेह का वातावरण था, इसलिए दोनों पक्षों में वह खुला विनिमय न रहा जो १९६७ में देखने में आया और केन्द्रीय नेतृत्व में फूट पड़ गई ।

१९६६ का राष्ट्रपति का चुनाव

भारतीय दल पद्धति में सरकार और सगठन का द्वंद्व निहित है । परन्तु यह द्वंद्व नीचे के स्तर पर देखने में आता था । कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व (हाइकमान) दल की एकता को बनाए रखता था और नीचे के झगड़ों को निपटाता रहता था । लेकिन प्रधानमंत्री के उत्तराधिकार के दो सघर्षों से आरम्भ होकर सरकार और सगठन का द्वंद्व ऊपर तक पहुंच गया और १९६६ के बंगलूर कांग्रेस अधिवेशन में इसकी पराकाष्ठा हो गई जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष निर्जलि गण्पा तथा सगठन के मुखियों में खुली टक्कर हुई । इस सघर्ष में व्यक्तिगत, क्षेत्रीय और कार्यक्रमगत स्पष्ट मतभेद देखने में आया । परिणामस्वरूप नेतृत्व के लिए जो सघर्ष हुआ, उससे तीन बात सामने आयी । एक तो कांग्रेस सगठन में प्रधानमंत्री और उसकी सरकार के स्थान और शक्ति का प्रश्न, जिसे कामराज याजना द्वारा टालने का प्रयत्न किया गया था । दूसरे, प्रतिद्वंद्वी गुटों ने बाहर से शक्तिसंघर्ष का प्रयत्न किया । श्रीमती गांधी ने वामपक्ष, द्रमुक और अन्य क्षेत्रीय दलों का समर्थन लिया और सगठन के नेताओं ने स्वतंत्र और जनसंघ का । तीसरे, इस द्वंद्व ने क्षेत्रीय रूप ग्रहण किया । उत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, केरल और मद्रास इंदिरा गांधी के साथ रहा और पश्चिम भारत राजस्थान और मैसूर सगठन नेताओं के साथ । इस मोर्चेबंदी ने कांग्रेस को गूँझोर दिया । दक्षिण और वाम पक्ष के बीच कांग्रेस की मध्य स्थिति को खतम कर दिया और देश में नई राजनैतिक गुटबंदी और मोरचेबंदी को जन्म दिया ।

कांग्रेस की अदरुनी खींचतान राष्ट्रपति पद के उम्मेदवारों के चुनाव पर सीमा पार कर गई । श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस संसदीय बोर्ड में अल्पमत में आ गईं । श्रीमती इंदिरा गांधी ने समझा कि यह उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने की चाल है । जवाब में उन्होंने मोरारजी भाई का हटा दिया, जिन्हें उन्होंने खुद कांग्रेस की फूट बचाने के लिए उपप्रधान मंत्री बनाया था । इसके बाद उन्होंने अध्यादेश के जरिए वैका का राष्ट्रीयकरण कर दिया और आर्थिक नीति को वामपक्षी तथा प्रातिकारी रूप दिया । फिर उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस सदस्यों को अपने अंत-

२० १९६७ के चुनाव के उम्मीदवारों की छयाई के बारे में देखें - रजनी कोठारी - ' कांग्रेस मिथम आनंदराव ' (एशियन सर्वे साप्ताहिक २ फरवरी १९६७) तथा स्टेनली ए. कोचनेर - ' द कांग्रेस पार्टी आफ इंडिया - द डायनेमिक ऑफ वन पार्टी डेमोक्रेसी ' (प्रिन्सटन १९६८) ।

चरण के अनुसार वोट देने की आजादी की मांग थी, अर्थात् प्रतिपक्षी उम्मीदवार श्री गिरि का वोट देने की आजादी। कांग्रेस अध्यक्ष ने इसका विरोध किया और दोनों ओर से प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों के लिए जोर लगाया। यह चुनाव अभूतपूर्व था। इसमें दल का विभाजन रेखा टट गई और अधिवृत्त कांग्रेस उम्मीदवार श्री सतीश रेड्डी की हार हुई। पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। यह कांग्रेस गठन और प्रधानमंत्री के गुटा की टक्कर थी। इसमें प्रधानमंत्री की विजय हुई और वह गठन के मुकाबले तत्काल या सरकारी गुट की प्रधानता स्थापित करने में सफल हुई। साथ ही कांग्रेस में वामपंथी प्रवृत्ति की प्रधानता स्थापित हुई।

साथ ही १९६६ के राष्ट्रपति के चुनाव ने भारतीय दल पद्धति के मुले रूप को भी प्रकट किया। एक ओर कांग्रेस के छोटी के नेताओं में परस्पर बमनस्य इतना बढ़ गया था कि उनमें बातचीत बंद हो गई, दूसरी ओर राष्ट्रपति के चुनाव के आंदोलन में सभी प्रमुख दल और कांग्रेस के गुट बूढ़ पड़े। जिस प्रकार कांग्रेस के अंदरूनी गुट दल के अंदर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बाहरी दल का सहारा लेते उसी तरह एन और कम्युनिस्ट और दूसरी ओर स्वतंत्र और जनसम दल ने भी कांग्रेस की गुटबंदी का सहारा लेकर नई राजनैतिक मोर्चेबंदी कायम करने की कोशिश की। दोनों ओर में पूरा जोर लगाया गया और खुल कर समय हुआ। यह मोर्चेबंदी राजनैतिक और वैचारिक मतभेद के साथ साथ क्षेत्रीय और साम्प्रदायिक भेद के आधार पर हुई। यद्यपि इस फूट व कारण केन्द्रीय कांग्रेस के छूटने की आशंका उपस्थित हुई, किंतु राजनैतिक व्यवस्था के टूटने की आशंका नहीं उठी। चुनाव के बाद कांग्रेस में फूट को बचाने की कोशिश हुई और कांग्रेस कायम गति में एकता का प्रस्ताव पास हुआ।

साथ ही दूसरे दल में भी बहुत फट दिखाई पड़ी। मध्यावधि चुनाव और संयुक्त मोर्चा सरकार की स्थापना और पना के समय यह फूट उभर कर सामने आयी। गरवाग्रेसी दल के गठजोड़ का चयन या दिक्कत बड़ा बठिन सिद्ध हुआ। व्यक्तिगत सद्भाव और वर्गहिता पर विरोध सामने आए। इन दोनों में भी उत्तराधिकार के संकट उपस्थित हुए। संयुक्त समाजवादी पार्टी गैरकांग्रेसी दल में सबसे गतिशील थी। डा० लोहिया की मृत्यु से इसका गहरा धक्का लगा और इस में फूट पड़ गयी। सन ६० के बाद सद्भाव और मतभेद के कारण कम्युनिस्ट पार्टी की एकता और संगठन छिन्न भिन्न हो गया। जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय में चले जाने और अशोक मेहता के 'पिछड़ी जनजातों की मजदूरिया' अनुभव करने (और कांग्रेस में जाने) के बाद प्र सो पा भी नेतृत्वविहीन हो गयी। स्वतंत्र पार्टी तो ऐसा जान पड़ता है, अखिल भारतीय नरत्व में बिदवांस ही नहीं करती। कांग्रेसवादी गुटा में भी नेता अधिक और अनुयायी कम दीखते हैं। केवल जनसम

में कुछ एकता और अनुशासन दीख पड़ता है यद्यपि उसमें भी कांग्रेस व ही समान नरम और गरम गुट मौजूद हैं। परन्तु जनसघ मुख्यत उत्तरभारत का संगठन है, जैसे द्र मु व केवल दक्षिण वा। इससे पता चलता है कि नेहरूवाद और कांग्रेस ह्रास के युग में दला की स्थिति कितनी कच्ची और अस्थिर है। इस अस्थिरता के युग में भी राजनैतिक व्यवस्था की बनाए रखने में कांग्रेस सहायक हुई। नेहरू और अय महान नेताओं के उठ जाने के बाद भी उमने टिके रहने और पुन शक्ति प्राप्त करने की क्षमता प्रदर्शित की है।

नौकरशाही की भूमिका

भारतीय राज्यव्यवस्था को बनाए रखने में नौकरशाही या प्रशासन तंत्र का भी बड़ा हाथ है। राजनैतिक परिवर्तन के समय तो न केवल नौकरशाही सरकार या शासन की निरंतरता को बनाए रखती है, बरन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम कर दिखाने की जिम्मेदार होती है जिम पर सरकार की सफलता या विफलता निर्भर होती है। राजनैतिक नेता अर्थात् मंत्रियों का सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ के निकट सहयोग से काम करना होता है और ऊँचे स्तर पर नीतिनिर्णय में अधिकारियों या सचिवों का हाथ बढ़ता जा रहा है। लालबहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के अत्यंत महत्वपूर्ण राजनैतिक निर्णयों में भी उच्च अधिकारियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। पाकिस्तान से युद्ध और ताश्कंद समझौते के समय यह बात स्पष्ट हो गई, ^{२१} और अब भी यही स्थिति है। लक्ष्मीकांत या, लल्लनप्रसाद मिश्र और पी एन हक्सर जैसे उच्च अधिकारियों का महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयों में बहुत अधिक हाथ रहा है। मंत्रिमंडल सचिवालय और प्रधानमंत्री के सचिवालय का बढ़ता हुआ महत्व किसी से छिपा नहीं। ये प्रधानमंत्री के आस और बाँध हैं। इनके द्वारा उनकी पूरी राजनैतिक जानकारी मिलती है। उच्च स्तर की समितियों में इन अधिकारियों की उपस्थिति सरकारी निर्णयों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका की परिचायक है। इस स्थिति का मुकाबला उस जमाने से करिए जब मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की भी नेहरूजी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी।

अब तक हमने केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय राजनैतिक नेतृत्व, राजनैतिक गठजोड़ या योग, राजनैतिक उत्तराधिकार, वैचारिक या सैद्धांतिक सहमति की समस्याओं पर विचार किया है। यह सबविदित है कि जैसे जैसे राजनैतिक व्यवस्था जड़ पकड़ती है और इसकी पद्धतियाँ या संस्थाओं का विकास होता है, नयी समस्याएँ पैदा होती हैं। विकास के द्वारा देश की एकता को किस प्रकार बढ़ाया जाए, राजनैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा बरखे और सरकारों प्रशासन का लाभ पहुँचा कर किस प्रकार राज्यतंत्र या व्यवस्था को मजबूत बनाया जाय, स्थानीय या

^{२१} याचर-‘नेहरू मैटल’-पूर्वोक्त पृ ११५-२०, १६७-६८।

वरण के अनुसार वोट देने की आजादी की मांग की, अर्थात् प्रतिपक्षी उम्मीदवार श्री गिरि का वोट देने की आजादी। कांग्रेस अध्यक्ष ने इसका विरोध किया और दोनों ओर से प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों के लिए जोर लगाया। यह चुनाव अभूतपूर्व था। इसमें दल की विभाजन रेखा टूट गई और अविभक्त कांग्रेस उम्मीदवार श्री सचीव रेड्डी की हार हुई। पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। यह कांग्रेस मगठन और प्रधानमंत्री के गुटा की टक्कर थी। इसमें प्रधानमंत्री की विजय हुई और वह मगठन के मुकाबले मत्तारूढ़ या सरकारी गुट की प्रधानता स्थापित करने में सफल हुई। साथ ही कांग्रेस में वामपक्षी प्रवृत्ति की प्रधानता स्थापित हुई।

साथ ही १९६९ के राष्ट्रपति के चुनाव ने भारतीय दल पद्धति के खुले रूप को भी प्रकट किया। एक ओर कांग्रेस के चोटी के नेताओं में परस्पर ईर्ष्या इतना बढ़ गया था कि उनमें घातकीय बद हो गई, दूसरी ओर राष्ट्रपति के चुनाव के आंदोलन में सभी प्रमुख दल और कांग्रेस के गुट बूढ़ पड़े। जिस प्रकार कांग्रेस के अंदरूनी गुट दल के अंदर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बाहरी दलों का सहारा लेने थे उसी तरह एन और कम्युनिस्ट और दूसरी ओर स्वतंत्र और जनसंघ दलों ने भी कांग्रेस की गुटबंदी का सहारा लेकर नई राजनैतिक मोर्चेबंदी कायम करने की कोशिश की। दोनों ओर से पूरा जोर लगाया गया और खल बर सघष हुआ। यह मोर्चेबंदी राजनैतिक और वैचारिक मतभेद के साथ साथ क्षेत्रीय और सांप्रदायिक भेद के आधार पर हुई। यद्यपि इस फूट के कारण केन्द्रीय कांग्रेस के डटने की आशंका उत्पन्न हुई, किंतु राजनैतिक व्यवस्था के टूटने की आशंका नहीं उठी। चुनाव के बाद कांग्रेस में फूट को बचाने की कोशिश हुई और कांग्रेस कार्य समिति में एकता का प्रस्ताव पास हुआ।

साथ ही दूसरे दलों में भी बहुत फूट गिराई पड़ी। मध्यावधि चुनावों और संयुक्त मोरचा संघारों का स्थापना और पतन के समय यह फूट उभर कर सामने आयी। गुरुकांग्रेसी दलों के गठजोड़ का चाना या टिकना बड़ा कठिन सिद्ध हुआ। व्यक्तिगत सैद्धांतिक और बगहिता पर विरोध सामने आया। इन दोनों में भी उत्तराधिकार के संकट उत्पन्न हुए। संयुक्त समाजवादी पार्टी गुरुकांग्रेसी दलों में सबसे गतिशील थी। डा० लोहिया की मृत्यु से इसको गहरा धक्का लगा और इस में फूट पड़ गयी। सा० ६० के बाद सैद्धांतिक मतभेद के कारण कम्युनिस्ट पार्टी की एकता और मगठन छिन्न भिन्न हो गया। जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय में चले जाने और अशाक मेहता के 'पिछड़ी अव्यवस्था की मजबूरिया' अनुभव करने (और कांग्रेस में जाने) के बाद प्र मो या श्री नेतृत्वविहीन हो गयी। स्वतंत्र पार्टी तो ऐसा जान पड़ता है, अखिल भारतीय नेतृत्व में विश्वास ही नहीं करती। कांग्रेसत्यागी गुटा में भी नेता अधिक और अनुयायी कम दोखते हैं। केवल जनसंघ

में कुछ एकता और अनुशासन दीख पड़ता है यद्यपि उसमें भी कांग्रेस के ही समान नरम और गरम गुट मौजूद हैं। परन्तु जनसभ मुख्यतः उत्तरभारत का संगठन है, जैसे द्र मु क केवल दक्षिण का। इससे पता चलता है कि नेहरूवाद और कांग्रेस हास के युग में दलों की स्थिति किननी बची और अस्थिर है। इस अस्थिरता के युग में भी राजनैतिक व्यवस्था को बनाए रखने में कांग्रेस सहायक हुई। नेहरू और अन्य महान नेताओं के उठ जाने के बाद भी उगने टिके रहने और पुनः शक्ति प्राप्त करने की क्षमता प्रदर्शित की है।

नीकरशाही की भूमिका

भारतीय राज्यव्यवस्था को बनाए रखने में नीकरशाही या प्रशासन तंत्र का भी बड़ा हाथ है। राजनैतिक परिवर्तन के समय तो न केवल नीकरशाही सरकार या शासन की निरंतरता को बनाए रखती है, बरन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम कर दिखाने की जिम्मेदार होती है, जिस पर सरकार की सफलता या विफलता निर्भर होती है। राजनैतिक नेता अर्थात् मंत्रियों का सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ के निकट सहयोग से काम करना होता है और ऊँचे स्तर पर नीतिनिर्णय में अधिकारियाँ या सचिवों का हाथ बढ़ता जा रहा है। लालबहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के अत्यंत महत्वपूर्ण राजनैतिक निर्णयों में भी उच्च अधिकारियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। पाकिस्तान से युद्ध और ताश्कंद समझौते के समय यह बात स्पष्ट हो गई,^{२१} और अब भी यही स्थिति है। लक्ष्मीकांत या, लालनप्रसाद मिह और पी एन हक्सर जैसे उच्च अधिकारियों का महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयों में बहुत अधिक हाथ रहा है। मंत्रिमंडल सचिवालय और प्रधानमंत्री के सचिवालय का बढ़ता हुआ महत्व किसी से छिपा नहीं। ये प्रधानमंत्री के आस और बाँह हैं। इनके द्वारा उनकी पूरी राजनैतिक जानकारी मिलती है। उच्च स्तर की समितियों में इन अधिकारियों की उपस्थिति सरकारी निर्णयों में इनको महत्वपूर्ण भूमिका की परिचायक है। इस स्थिति का मुकाबला उस जमाने से करिए जब मंत्रिपरिषद् के मंत्रियों की भी नेहरूजी के सामने वागने की हिम्मत नहीं पड़ती थी।

अब तक हमने केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय राजनैतिक नेतृत्व, राजनैतिक गठजोड़ या योग, राजनैतिक उत्तराधिकार, वैचारिक या सैद्धांतिक सहमति की समस्याओं पर विचार किया है। यह सबविदित है कि जैसे जैसे राजनैतिक व्यवस्था जड़ पकड़ती है और इसकी पद्धतियाँ या संस्थाएँ का विकास होता है, नयी समस्याएँ पैदा होती हैं। विचार के द्वारा देश की एकता को किस प्रकार बढ़ाया जाए, राजनैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करके और सत्ता को प्रशासन का लाभ पहुँचा कर किस प्रकार राज्यतंत्र या व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए, स्थानीय या

^{२१} आचार-नेहरूज मैटल-पूर्वोक्त पृ ११५-२०, १६७-६८।

और इडोनीशिया में मुकानों, अधिकारमद के उदाहरण हैं। इसी तरह पश्चिम एशिया में नासिर का प्रभाव इस बात का चोतक है कि ऐतिहासिक घटनाओं का राष्ट्रीय भावना पर जो प्रभाव पड़ता है वह स्थायी नहीं होता। दूसरी ओर बागो और नाइजीरिया में जो गह्रयुद्ध हुए उससे संभवतः उन देशों को समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रीय एकता का बनाए रखने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है और कितनी सावधानी रखनी पड़ती है। जो हा, भारत में विभाजन के फलस्वरूप राष्ट्रीय एकता का महत्त्व और उसका बनाए रखने के लिए सभी वर्गों का ख्याल रखने की आवश्यकता राजनीतिज्ञों का समय में आ गयी।

स्वतंत्र भारत में जाति और मजदूर-बहुतर राजनैतिक संगठना या गठजोड़ के अंग हैं। इनके मुकाबले भाषा या प्रांत के विभाजना से राष्ट्रीय एकता को ज्यादा खतरा है।

राष्ट्रीय एकता और भाषागत विभिन्नता

भारत में भाषा की समस्या निराली है। बर्नाडो, बेलजियम, स्विटजरलैंड या स्वीडिश रूम का उदाहरण यहां लागू नहीं होता। १९ वीं सदी के यूरोप में भाषा का आधार पर जिस प्रकार जर्मनी, इटली आदि राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ, वह बात भी भारत पर लागू नहीं हो सकती।^{२२} यह समझना चाहिए कि भारत में सदा से अनेक भाषाएँ रही हैं किन्तु इन भाषाओं को जोड़ने वाली संस्कृति जैसी सावदेशिक भाषाएँ रही हैं। स्थानीय यात्रियाँ, प्रादेशिक भाषाओं और सावदेशिक भाषाओं में निरंतर आदान-प्रदान और घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। इतिहास के विभिन्न युगों में भाषा का विकास अनेक तत्त्वों से प्रभावित हुआ है। धर्म या शासक-जाति की मरुति का अनुकरण, राजनैतिक सुविधा और जातीयता सभी बातों ने विभिन्न युगों में विभिन्न सावदेशिक भाषाओं के उदय और प्रांतीय भाषाओं के विकास में योग दिया है। इस समय भी भाषासंबंधी नीति में जो अनिश्चितता देखने में आ रही है उसका कारण यह है कि सबकी सहमति से भाषा समस्या का समाधान करना आसान नहीं है।^{२३}

राष्ट्रीय एकता के लिए एक राष्ट्रभाषा या सावदेशिक भाषा आवश्यक है यह सिद्धान्त भारत पर लागू नहीं होता। यह बात अब कांग्रेस, स. सो. पा. और जन-संघ तथा दूसरी ओर द्र. मु. क. के कट्टरवादी भी अनुभव कर रहे हैं। भाषा की समस्या भारतीय एकता के लिए निस्संदेह एक कसौटी या चुनौती है, किन्तु इधर

२२ देखिए-एली बेदुरी- नेशनलिज्म (२९६०)।

२३ गजेन्द्रगडकर 'ए. ए. डी. डी. कमिटर प्रान्शियल रिजल्ट्स ऑफ़ हेसेन स्कोली (क. वोकेशन भाषण, बर्दादा, अक्टूबर १४, १९६७ मीडियम आफ़ एजुकेशन, बर्दादा युनि, प्रकाशित)।

व्यगत्त मागो का किस प्रकार सतुष्ट किया जाए और उनको भी राजनतिक व्यवस्था और राष्ट्रीय जीवन में शामिल किया जाए, ये व्यावहारिक समस्याएँ हैं, जिनके समाधान से राजनैतिक व्यवस्था की परीक्षा होती है। ये राजनतिक तन्त्र के नेताओं की योग्यता की कसौटियाँ हैं। जैसे जैसे राज्यतन्त्र अनेकता में एकता की एक एक मजिल पार करता है उसे अपने राजनैतिक माधन और शक्ति नाजुक समस्याओं की सुलझाने में लगानी पड़ती है।

अनेकता में एकता की स्थापना

भारतीय सम्यता को प्रभावित करने वाले तत्त्व हैं देश की विशालता, प्राचीनता और यहाँ अनेक जाति या नृवश की विद्यमानता। मजहब या संप्रदाय, जाति भाषा और प्रांत यहाँ राजनीति के आधार रह हैं। बालिग मताधिकार के प्रभाव से जाति ने क्या राजनैतिक रूप ग्रहण किया है, इसका विश्लेषण हम पूरे एक अध्याय में कर चुके हैं। अध्याय दो में हमने यह देखा कि किस प्रकार नए भारत का जन्म सांप्रदायिक विभाजन से हुआ और उस समय कितनी खून खराबी मची। हमने सांप्रदायिक समस्या पर भी काफी विस्तार से विचार किया है। यहाँ हम यह देखेंगे कि राष्ट्र के निर्माण के लिए इसका क्या महत्त्व है।

जहाँ देश के बंटवारे से इतनी हानि हुई वहाँ इससे कुछ सन्तुष्ट भी मिला। पहला सबक यह है कि देश ने एकता के महत्त्व का समझा और यह अनुभव किया कि चाहे जैसे भी हो, राष्ट्रीय या केन्द्रीय सत्ता का बनाए रखना है और देश के विविध तत्त्वों को एक सूत्र में बाँधे रखना है। संविधान सभा के विचारविमर्श में इन सिद्धान्तों का प्रभाव स्पष्ट है और इसीलिए हमारे संविधान में केन्द्रीय सत्ता की प्रधानता और राज्य की एकात्मकता को कायम रखने के साथ साथ देश के विभिन्न भागों को पूरी छूट और अधिकार देने का यत्न किया गया है। फलतः हमारी राजनीति में एकता को महत्त्व गुरु से दिया जा रहा है। बंटवारे का दूसरा प्रभाव और भी व्यापक रहा। देश का बंटवारा और उससे फलस्वरूप होने वाली हिंसा का समाप्त हो और राष्ट्र की राजनैतिक इमारत सखी बनने की जिम्मेदारी ने हमारे राजनीतिज्ञों में राजनैतिक समझदारी या नीतिमत्ता का संचार किया और उन्हें यह अनुभव कराया कि देश की राजनैतिक स्वतंत्रता और गति कायम रखने के लिए क्या करना पड़ता है।

राष्ट्रनिर्माण के लिए एकता की समस्या बड़ी महत्त्वपूर्ण है। एगिप्ता और अफ्रीका के अनेक नव स्वतंत्र देशों को अपने विन्नी भागों से बनाया गया एक ही राष्ट्र मिल गया। उन्हें राष्ट्रनिर्माण के लिए प्रयत्न करना पड़ा, इसलिए उन्होंने एकता ऊँची सिद्ध की। इन नेताओं को जो अधिकार मिल गया, उससे उनका दिमाग हो गया। उन्होंने देश के विभिन्न तत्त्वों को साथ ले चलने या उनकी राजमंदी व समझन प्राप्त करने की चिन्ता नहीं की। भारत में एगिप्ता

और इंडोनीशिया में मुकानों, अधिकारमंद के उदाहरण हैं। इसी तरह पश्चिम एशिया में तासिर का प्रभाव इस बात का द्योतक है कि ऐतिहासिक घटनाओं का राष्ट्रीय भावना पर जो प्रभाव पड़ता है वह स्थायी नहीं होता। दूसरी ओर कांगो और नाइजीरिया में जो गहरे दुःख उससे सम्भवतः उन देशों का समय में आ जाएगा कि राष्ट्रीय एकता का बनाए रखने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है और कितनी सावधानी रखनी पड़ती है। जा हा, भारत में विभाजन के फलस्वरूप राष्ट्रीय एकता का महत्त्व और उसका बनाए रखने के लिए सभी वर्गों का ख्याल रखने की आवश्यकता राजनीतियों का समझ में आ गयी।

स्वतंत्र भारत में जाति और मजदूर वर्गों के राजनैतिक संगठन या गठजोड़ों के जग हैं। इनके मुकाबले भाषा या प्रांत के विभाजन से राष्ट्रीय एकता को ज्यादा खतरा है।

राष्ट्रीय एकता और भाषागत विभिन्नता

भारत में भाषा की समस्या निराली है। बड़ा बेलजियम, स्विटजरलैंड या माक्सिम रूम का उदाहरण यहां लागू नहीं होता। १९ वीं सदी के यूरोप में भाषा के आधार पर जिस प्रकार जर्मनी, इटली आदि राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ, वह बात भी भारत पर लागू नहीं हो सकती।^{२२} यह समझना चाहिए कि भारत में सदा से अनेक भाषाएँ रही हैं किन्तु इन भाषाओं को जाड़ने वाली संस्कृति जैसी सावदेशिक भाषाएँ रही हैं। स्थानीय बोलियाँ, प्रादेशिक भाषाओं और सावदेशिक भाषाओं में निरन्तर जादान-प्रदान और घनिष्ठ सम्पर्क रहा है। इतिहास के विभिन्न युगों में भाषा का विकास अनेक तत्वों से प्रभावित हुआ है। श्रेष्ठ या शासक जाति की संस्कृति का अनुकरण, राजनैतिक सुविधा और जातीयता सभी बातों ने विभिन्न युगों में विभिन्न सावदेशिक भाषाओं के उदय और प्रांतीय भाषाओं के विकास में योग दिया है। इस समय भी भाषासंबंधी नीति में जा अनिश्चितता रखने में आ रही है उसका कारण यह है कि सबकी सहमति से भाषा समस्या का समाधान करना आसान नहीं है।^{२३}

राष्ट्रीय एकता के लिए एक राष्ट्रभाषा या सावदेशिक भाषा आवश्यक है, यह सिद्धांत भारत पर लागू नहीं होता। यह बात अब कांग्रेस, स. सो. पा. और जन-संघ तथा दूसरी ओर द. मु. क. के कट्टरवादी भी अनुभव कर रहे हैं। भाषा की समस्या भारतीय एकता के लिए निम्नलिखित एक कसौटी या चुनौती है, किन्तु इस

२२ देखिए-एली वेदूरी- नेशनलिज्म (लंदन १९६०)।

२३ मन्नेन्द्रगुप्तकर 'एली ड्रु कमिंडर प्रालम रेशनली, डिस्टाइंड वाइली' एंड हेसेन स्लोडी (कॉन्फेक्शन भाषण, बंगाल, अक्टूबर १४, १९६७ मीडियम आफ एजुकेशन, बंगलूरु, प्रकाशित)।

व्यवहार में चलती रही। (मारणी जाठ-१)। पहले संस्कृत, फिर फारसी, फिर उर्दू और १६ वीं शती से अंग्रेजी और बाद में हिंदुस्तानी (हिंदी उर्दू की लिचडी)। इस समय विवाद इस बात पर है कि राजभाषा अंग्रेजी हो (जो ब्रिटिश हुकूमत की देन है) या संविधान में स्वीकृत हिंदी।

आधुनिकता के प्रसार का शुरु में असर यह हुआ कि शिक्षित या उच्चवर्ग और जनसाधारण के बीच गहरी खाई पैदा हो गई। अंग्रेजी शिक्षा सरकारी नौकरी, डाक्टरा, वकालत, अध्यापन आदि सफेदपेशों में तथा राजनैतिक क्षेत्र के लिए प्रवेश थी। मगर अंग्रेजी पढ़े लोग भाषा और संस्कृति की उपेक्षा करने लगते थे और देश के लोग से बट जाते थे। बाद में गांधी के प्रभाव और राजनीतिक आंदोलन के जन आंदोलन का रूप धारण करने के कारण, हिंदी और प्रादेशिक भाषाएं भी आगे आईं। इन भाषाओं में साहित्य की रचना होने लगी। इनके माध्यम से जनता में राजनैतिक विचारों और शिक्षा का प्रसार होने लगा और गांधी से उच्च वर्गों का संबंध जुड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अंग्रेजी की जगह हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं की प्रतिष्ठित करने की मांग उठी। सिद्धांत रूप में ये मांगें स्वीकार की गयीं, किंतु इनका व्यवहार में लाने की समस्याओं पर न उस समय ध्यान दिया गया न स्वतंत्रता के बाद। बल्कि नेहरू तथा अन्य नेताओं ने तथाकथित 'प्रांतीय या संकीर्ण प्रवृत्तियों' का जो अनुचित विरोध किया, उसके कारण इन समस्याओं का समाधान टल गया। बाद में दबाव और आंदोलन के कारण केन्द्रीय नेता इन समस्याओं का सुलझाने को बाध्य हुए।

हम पहले देख चुके हैं कि यद्यपि कांग्रेस भाषा के आधार पर प्रांतों की रचना के सिद्धान्त को मान चुकी थी, पर जब एक आदमी ने अनशन करके प्राण दे दिए और गहरा उपद्रव हुआ, तभी कांग्रेस सरकार इस सिद्धान्त पर अमल करने का तैयार हुई। इसके फलस्वरूप देश का बहुत बड़ा पैमाने पर राजनैतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन हुआ। इससे राजनैतिक एकीकरण हुआ, स्थिरता बढ़ी और सरकार और जनता में संपर्क बढ़ा। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त उच्चवर्ग और जनसाधारण में जो खाई थी, वह कम हुई, गांधी के लोगों में राजनैतिक चेतना बढ़ी, उनको सरकार की नीति नीति की ज्यादा जानकारी हुई। प्रांतों का यह विभाजन जनसंख्या के स्वाभाविक वर्गीकरण या विभाजन से मिलता था। इससे विकास के कार्यक्रमों और सरकार की कार्यविधि और पद्धति के बारे में भी सहमति पैदा हुई।

पर भाषा के अनुसार प्रांतों का पुनर्गठन तो समस्या का एक पहलू था। इतना ही महत्वपूर्ण सवाल यह था कि सारे देश के लिए व्यवहार और संपर्क के लिए एक भाषा क्या हो। अंग्रेजी का स्वीकार करना राष्ट्रीय भावना के प्रतिकूल पड़ता था। दूसरा विषय हिंदी ही हो सकती थी। परंतु संविधान में हिंदी का चानू करने के लिए १५ वर्ष की जा अवधि रखी गयी थी उसमें गैरहिंदी क्षेत्रों में हिन्दी

कांग्रेस सरकार और कांग्रेस दल के विभिन्न गुटा में लम्बी बातचीत के बाद त्रिभाषा सूत्र अपनाया गया। इसका मतलब यह था कि प्रत्येक राज्य अपने राज्य की भाषा में काम करने के लिए स्वतंत्र होगा। राज्य के विश्वविद्यालयों में यही भाषा पढ़ाई का माध्यम होगी। अन्तरराज्य व्यवहार में अंग्रेजी भाषा से काम लिया जायेगा, यदि यह व्यवहार हिंदी में होगा तो उसके साथ अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा जायेगा।

अहिंदी भाषी राज्य केन्द्र से अंग्रेजी में लिखा पढ़ी करते रहेंगे। केन्द्र में और संसद में अंग्रेजी में कामकाज चलता रहेगा। सरकारी नौकरियों की परीक्षाएँ अंग्रेजी, हिंदी तथा सभी प्रादेशिक भाषाओं में ली जायेंगी और हिन्दी के विकास के लिए त्रिभाषा कार्यक्रम बनाया जायेगा। यद्यपि इस समझौते से कोई वग पूरा तरह सन्तुष्ट नहीं हुआ फिर भी यह भाषा के प्रश्न पर धीरे धीरे सहमति का आधार बना। उपयुक्त बातों की घोषणा राष्ट्रपति ने संसद में अपने अभिभाषण में और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने अपने प्रस्ताव में की।

मतभेद इस बात पर था कि ये आश्वासन संविधान में संशोधन करके लागू किये जाय या संसद में केवल एक प्रस्ताव द्वारा। पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ जाने से यह प्रश्न इस समय टल गया। अन्त में संसद में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें ये सब आश्वासन शामिल किए गए थे। यद्यपि मद्रास विधान सभा ने इसके बाद भी एक प्रस्ताव द्वारा हिंदी का किसी भी काम के लिए स्वीकार करने से इनकार किया। पर यह अनुभव किया गया कि यह प्रस्ताव उपद्रव या आंदोलन रोकने के लिए किया गया। द्रमुक नेताओं ने इसके बाद तीन भाषा सूत्र की अमल में लाने के बारे में दूसरे दला से बातचीत करना स्वीकार किया। जनसंघ ने भी, जो हिंदी का कट्टर समर्थक था, दक्षिण और पूर्व (बंगाल) में अपने पैर जमाने के लिए अपने रुढ़ को नरम किया। सत्ता में आने के बाद द्रमुक का रुख भी समझौते का हो गया। इससे पता चलता है कि सत्ता के साथ ज्यादा नरमी या परिपक्वता आ जाती है।

सन ५० के दशक में भाषावाद प्रायः के निर्माण और ६० के दशक में राजभाषा के प्रश्न पर जा विवाद छिड़ा, उससे लगता था कि देश की एकता भंग हो जाएगी। पर इससे मतभेद खुले में आ गया और खुलकर वादविवाद से एक रास्ता निकल आया। देश दोनों सक्लों को पार कर गया और आगे भाषावाद से पैदा होने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए ज्यादा तैयार हो गया। इस बीच हुए अध्ययन से पता चला कि शिक्षा, व्यापार, रेडियो, मिनेमा, पत्र पत्रिकाओं आदि साधना से अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी काफी फैली है (१९६१ की जनगणना के अनुसार द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी व उर्दू अंग्रेजी से कुछ जागे थी) अंग्रेजी भी तेजी से बढ़ रही है (माध्यमिक विद्यालयों में यह अनिवार्य

विषय है वैद्रीय शिक्षा सस्याओं में—और इनकी सरया बढ रही है—यह शिक्षा का माध्यम है, जोर पुस्तका तथा समाचारपत्रा मे इसकी प्रधानता है । सभी उनति काशी समूह इन दोनो भाषाजा का प्रयोग कर रह हैं । २० यह स्थिति भारत म नयी नही है । यहा हमेशा से विशिष्ट या उच्चवर्ग की एक भाषा रही है (जस अंग्रेजी) साधारण बोलचान की एक भाषा देश मे काफी व्यापक रूप मे चलती रही है, इसके प्रादेशिक रूपों में अतर हो सकता है (जैसे हिंदी) और विभिन्न प्रदेशों में छोटी छोटी स्थानीय बोलियों के ऊपर परिनिष्ठित प्रादेशिक भाषाए रही ह । फर इतना है कि प्रादेशिक भाषाए अब राज्य के व्यवहार की भाषा के रूप में और महत्व प्राप्त कर रही ह तथा स्थानीय बोलिया इनमें समाती जा रही ह । अब ऐसा लगता है कि सावदेशिक भाषाजा के रूप म अंग्रेजी और हिंदी दोना ही हमेशा चलती रहगी ।

प्रादेशिकता और विघटन का खतरा

देश के सामने एक खतरा राज्यों के सघ से अलग हो जाने का था । कुछ लोगो ने आशका प्रकट की थी कि प्रातीयता की भावना या प्रदेश के लिए अधिक अधिकार या स्वायत्ता की माग बढती गई ता इससे या तो देश अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों मे बट जाएगा या यहा तानाशाही कायम हो जाएगी । २० पहले भी देश मे ऐसे आंदोलन हुए ह और वर्तमान में भी हो रहे हैं । कुछ हद तक पुरानी क्याआ के आधार पर और कुछ उत्तर-दक्षिण, ब्राह्मण-अब्राह्मण, आय-द्रविड के भेदभाव के आधार पर । दक्षिण मे, मुख्यतः पुराने मद्रास राज्य मे स्वतंत्रता या स्वायत्ता का बौद्धिक आंदोलन जोर पकड़ता रहा है । सन १९१७ में द्रविडियन असोसिएशन और साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन (जस्टिस पार्टी) ने मद्रास में सरकारी नौकरिया और राजनीतिक क्षेत्र में ब्राह्मणों के एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन छेडा था । इसी ब्राह्मण विरोधी आंदोलन की नींव पर सन १९४१ मे द्रविड कजगम की स्थापना हुई जिसने द्रविड लोगो का आह्वान किया कि वह अंग्रेजों के हाथ से सत्ता आर्थों के हाथ में न जाने दें । उसने भारत स एकदम जलग द्रविडस्थान की स्थापना की माग की । २०

लेकिन १९५४ तक राजनैतिक अधिकार ब्राह्मणों के हाथ से निकल कर अब्राह्मण तमिल नेताओं के हाथ में आ गये और राजगोपालचारी के स्थान पर कामराज नाडार मुख्यमंत्री बने । तब द्र० क० ने कांग्रेस मन्त्रिमंडल का समयन किया । इस नीति से असंतुष्ट लोगो ने तब अलग होकर द्रविड मुन्नेत्र कजगम की स्थापना की ।

२६ देवेंद्र-चन्द्रावरण नायर - ' अंग्रेज आनिंग इन इन्डिया ' (न्यूयार्क १९६९) ।

२७ सेमिग हैरिमन - ' इन्डिया - द मोस्ट डेंजरस डिडेन्ड ' (प्रिन्सटन १९६०) ।

२८ राबर्ट एन हांग्रेव - ' द द्रविडियन मुवमेंट ' (बर्र १९६९) ।

इसने द्रविडस्तान का आंदोलन जारी रखने का प्रण किया। लेकिन एक जोर कांग्रेस में तमिल (अब्राह्मण) प्रभाव बढ़ा और दूसरी ओर द्र० मु० क० की शक्ति बनी। १९५६ में द्र० मु० क० ने मद्रास कारपोरेशन और अय्य नगर की शासन सम्वन्धों पर कब्जा कर लिया और १९६२ के चुनाव में यह सब से बड़े विराधी दल के रूप में आया। सत्ता के स्वाद ने द्र० मु० क० की उग्रता का कुछ नरम कर दिया। इसने आंदोलन का मार्ग छोड़कर चुनाव जीत कर सत्ता प्राप्त करने की नीति अपनायी। २० इस पर ई० वी० के सम्पत्त के नेतृत्व में एक पथक्तावादी गुट इससे अलग हो गया। अब्राहमुरे के नेतृत्व में द्र० मु० क० की शक्ति बढ़ी और इसका प्रभाव गांवों में फैला। इसने पथक्ता के बजाय जाति और जाति-पाति की विपरीतता को दूर करने और भाषा के मामले में स्वतंत्रता का नारा लगाया और अंत में १९६७ के चुनाव में मद्रास राज्य में विजयी हुई। द्र० मु० क० सरकार ने भाषा के मामले में केन्द्र से भिन्न रुख अपनाया है, किन्तु मद्रास (जिसका नाम बदल कर तामिलनाडु हो गया है) सबसे व्यवस्थित, शांत और भारत सच का वफादार राज्य साबित हुआ है। ३०

सन १९६७ में सत्ता में आने के बाद द्र० मु० क० के भीतर भी उन्नी प्रकार की गुटबंदी प्रकट होने लगी जैसी कांग्रेस में थी। तमिलनाडु में द्रमुक सत्ता में है और कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी दल के रूप में काम कर रही है। इस प्रकार जातीयता अर्थात् ब्राह्मण-अब्राह्मण की भावना ने राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता का रूप धारण कर लिया। ३१ और प्रवेश या प्राप्त की भावना पर आधारित प्रतिद्वंद्वी दल ने देश की लोकतंत्री सचीय पद्धति को चलाने में योग ही दिया। प्रादेशिक निष्ठा का इस प्रकार संगठन और बाव में उसका राष्ट्रीय राजनैतिक व्यवस्था का अंग बनना, राजनैतिक संगठन और मोरचेबंदी की ही प्रक्रिया सिद्ध हुई।

दूसरी ओर यह भी ध्यान रहे कि पथक्ता की भावना उन में ज्यादा चलवान और गतिरताक है, जहाँ ऐसी आर्येतर जातियाँ हैं, जो भारतीय संस्कृति की धारा में पूरी

२९ देश के दूसरे भागों के जनमत ने भी द्रमुक के रुख पर प्रभाव डाला। पृथक्ता की प्रवृत्ति को रोकने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद की उपसमिति का मिशनरिज पर सविधान में संशोधन किया गया। इसका उद्देश्य प्रातायता और भाषा की कसरत से देश की एकता, अखण्डता और प्रभुता की रक्षा करना था। इस संशोधन ने भी द्रमुक को अपना नाति बदलने को बाध्य किया, जिसमें वह देश के सविधान के दायरे में रहकर काम कर सके।

३० सन १९७१ के मध्यावधि चुनाव में द्र मु क ने इंदिरा गांधी की कांग्रेस से समर्थान किया और राज्य में पहले से भी अधिक बहुमत से पुन सत्तारूढ़ हुई। केन्द्राय समर्थ में और राष्ट्रीय राजनीति में द्र मु क सामान्य रूप से इंदिरा गांधी के साथ रहा है।

३१ हार्नबेव-दंडा एम के ऐंड द पार्लियामेंट ऑफ तमिल नेशनलियन पामि अरे, मैत्राम न ५, १९६४-६५।

तबह मिल नहा पाई ह। जैसे उत्तरपूर्व की आदिम जातियाँ का इलाका।^{३२} महा भी भारतीय लोकतंत्री व्यवस्था और सरकारी विनाश कार्यक्रमों का प्रभाव पड़ा है और धीमे धीमे इन क्षेत्रों के नाग भी देश की राजनीति में भाग लेने लगे ह। पर राजनैतिकीकरण की यह प्रवृत्ति अभी शुरू हुई ह। दूसरी ओर आनुत्कृता के प्रसार से अपने पथक अस्तित्व की भावना उभरती भी है। इसलिए इनको समालने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। इस प्रकार की व्यवस्था की भी जा रही है। इसी उद्देश्य से नागालैंड का अलग राज्य बनाया गया और नागा विद्रोहियों के प्रति नरमी का रुख अपनाया गया। इसी तरह आसाम के अलग पहाड़ी इलाकों का मेघालय नामक उपराज्य स्थापित किया गया। जम्मू-काश्मीर को विशेष दर्जा भी इसी उद्देश्य से दिया गया था।

कुछ क्षेत्रों में अभी भी असन्तोष है जैसे-उत्तरपूर्व में मीजो जाति, बिहार में छोटा नागपुर तथा मध्यप्रदेश व आदिवासी इलाकों और गुजरात व ओडिसा में आदिवासियों का स्वायत्तता का आंदोलन। राजनैतिक गतिविधि बढ़ने और शिक्षा तथा आर्थिक विकास के फलस्वरूप छोटे समूहों में जो अब तक दबे या पिछड़े हुए थे, अनिहार और स्वायत्तता की आकांक्षा का उठना स्वाभाविक है। समस्या इस बात से उत्पन्न गयी है कि कुछ आदिवासी इलाकों चीन और पाकिस्तान से लगे हुए हैं और वहाँ से असंतुष्ट तत्त्वों को छापा मार मुद्र की ट्रेनिंग देने की कोशिश की गई ह। यह सतर्कता काफी दिनों तक रहने वाला है और सीमांत इलाकों की राजनैतिक समस्या के समाधान के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। गृहमंत्रालय इस मामले में समझदारी से काम ले रहा है, परंतु यह समस्या-सीमांत इलाकों में असंतोष और सीमा पार से इस असन्तोष को प्रोत्साहन-ऐसी नहीं, जिस का हल आनन फानन निकल आए।^{३३}

इस प्रकार देश के एकीकरण की समस्या अभी बनी है। राज्यों के भीतर विशिष्ट क्षेत्रों के अलगवा के आंदोलन उठ रहे हैं। दबे हुए वर्गों और समूहों के

३२ इस नियम के तहत अल्पसंख्यकों के लिए - आर्बर जे डोनावन का लेख 'सेपरेटिस्म टर्नर्स इन इंडियन स्टेट्स' - एशियन सर्व - सात स १०, अक्टू १९६७।

३३ गर आदिवासी इलाकों के अलावा भी राज्यों के अंदर कुछ क्षेत्रों में एकरता की मांग उठी है। जैसे आंध्रप्रदेश में तेलंगाना के अलगवा का आंदोलन। आंध्रप्रदेश का स्थापना के समय किए हुए वायदा के पुराने नियमों के अंतर्गत और कामेस के अंतर की शुल्की को रोकने में मुद्रा मंत्रालय की विफलता के कारण तेलंगाना के कुछ नेताओं ने १९६९ में अलगवा का आंदोलन किया। इस आंदोलन ने काफी उग्र रूप धारण किया। अभी तक तेलंगाना के पृथक्तावादियों को संतुष्ट नहीं किया जा सका है। संभवतः उनको बाकी शिवाय देना पड़े और मुद्रा मंत्रालय को बदलना पड़े। १९७१ के समान आधारभूत चुनाव में तेलंगाना पृथक्तावादियों को उस क्षेत्र में अधिपतित साई मिली। महाराष्ट्र और मैसूर में भी इसी प्रकार के आंदोलन हुए हैं यद्यपि वे इतने उग्र नहीं थे।

राजनैतिक क्षेत्र में आने से अधिनार के लिए उनकी आकांक्षा से नयी समस्याएँ खड़ी हो रही हैं तथा केन्द्रीय सरकार का इन समस्याओं से निपटने के लिए नयी नीति और उपाय निकालने पड़ते हैं।

अल्पसंख्यकों का सवाल

एक समस्या राज्यों के भीतर भाषागत अल्पसंख्यकों और अल्पसंख्यक संप्रदायों की है। औसतन राज्य में १८ प्र० १० लोग ऐसे हैं, जिनकी मातृभाषा राज्य की भाषा में भिन्न है। केरल में यह संख्या केवल ५ प्र० ३० है ताँमसूर में ३५ प्र० ८० और आसाम में ४४ प्र० ८०। जहाँ शासन या उद्योग व्यापार में इस प्रकार के 'बाहरी' लोगों की प्रधानता होती है वहाँ इससे काफी असन्तोष होता है और इन लोगों का शोषण समझा जाता है जैसे महाराष्ट्र में गुजराती और दक्षिणियों को, आसाम में ओडिसा में बंगालियों को और बंगाल में मारवाड़ियों को। इनके खिलाफ शहरों में शिवसेना (महाराष्ट्र) और तत्त्वित सेना (आसाम) जैसे उग्र आंदोलन उठ खड़े हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महाराष्ट्रीय तत्त्वों ने भी इस प्रकार की भावना का उभाड़ा है। पश्चिम बंगाल में और तामिलनाडु के कुछ हिस्सों में मारवाड़ियों के खिलाफ भावना जोर पकड़ रही है। शिवसेना जैसे उग्र संगठन खतरनाक हैं, ये फासिस्ट मनोवृत्ति के छातक हैं। ये मध्यमवर्ग की निराशाओं और कुटाक्षों का दुरुपयोग करके बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्गों में स्वाभाविक प्रतिद्वन्द्विता का स्थायी शत्रुता और हिंसा में बदलने का प्रयत्न करते हैं। इनके खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करना आवश्यक है।

इसी प्रकार स्थानीय पगडों के कारण हिंदू-मुस्लिम विद्वेष भी भड़क उठता है। १९६७ में उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे नगरों में हिंदू-मुसलमानों में झगड़े हुए। १९६६ में इनसे ज्यादा गंभीर दंगे जहमदाबाद और गुजरात में हुए, जिनमें कई सौ आदमी मार गए और काफी लूटपाट व आगजनी हुई। यह समस्या स्थायी रूप से तब हल होगी जब सभी वर्गों में धर्मनिरपेक्षता की भावना का विकास होगा, लेकिन तात्कालिक रूप से न केवल सरकार को कड़ाई और सावधानी बरतनी होगी, अपितु राजनैतिक दलों और शिक्षा तथा सांस्कृतिक संगठनों का भी सांप्रदायिक भावनाओं को निमूल करने की कोशिश करनी होगी (अनौपचारिक में विश्व-विद्यालय में ही सांप्रदायिक पगडें हुए हैं)। राजनैतिक दल इस डर से सांप्रदायिकता से बचने की कोशिश करते हैं कि वे दूसरे संप्रदायों के वोट खो देंगे परंतु उनके स्थानीय संगठन स्थानीय पगडों का लाभ उठाने के प्रलोभन में पड़ जाते हैं। सांप्रदायिक झगड़े भले ही छिटपुट और स्थानीय हों, लेकिन उनसे देश की बदनामी होती है और उसका लोकतंत्रीय धर्मनिरपेक्ष स्वरूप कलंकित होता है।

है, उसमें पता चलेगा कि लोकतंत्री तरीके से विविध तत्त्वा का लेकर सघीय व्यवस्था के विकास में क्या समस्याएँ उठती हैं। इनसे पता चलता है कि केन्द्रीय राजनैतिक सत्ता के विकास में केन्द्रगामी और केन्द्रघाती दोनों प्रवृत्तियाँ किस प्रकार सामने आती हैं।

भारत की राजनीति में प्रांतीय जोर वगैरह भागों ने राष्ट्रीय राज्यव्यवस्था के सामने नई समस्याएँ खड़ी की हैं। राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास कोई आसान बात नहीं। जैसा कहा जा चुका है भारतीयता का रूप व्यापक होगा। इसमें अनेक प्रकार की पद्धतियाँ जापस में गुथी होंगी। इस सबब शकला के निमाण में राजनैतिक व्यवस्था का मुख्य हाथ होगा। इसमें जनता को राजनैतिक गतिविधि में खींचना होगा और राजनैतिक समस्याओं को जनता में फैलाना होगा विशेष प्रश्न व समस्याओं को मुलजनों को कोशिश करने होगी और सत्ता का विवेकीकरण करना होगा। इससे जनता के विभिन्न वर्गों को आकांक्षाएँ बढ़ेंगी और उनको सन्तुष्ट करने में राजनैतिक व्यवस्था की बड़ी परीक्षा होगी।

इस अन्वय में आर पूरी पुस्तक में हमारा कहना यही है कि भारत जैसा विशाल देश में जहाँ इतने विविध प्रकार के लोग रहते हैं, एकता की स्थापना इसी से हो सकती है कि सब तत्त्वा को राजनैतिक सत्ता व अधिकार में भाग दिया जाए और सब का साथ लेकर चला जाए (नई दिल्ली से सारे भारत का शासन करना असम्भव है)। इसके लिए जरूरी है कि समाज के सब वर्गों में राजनैतिक सत्ता का प्रवेश हो। राजनीति की इन रचनात्मक भूमिका से ही एकीकरण की प्रवृत्तियाँ को बल मिलता है।

~~~~~  
[ पिछले पृष्ठ में ]

‘शेनरट रीजन’ प्रो०-ड० “न” चौकली, अक्टूबर १९५०। १९५७ में नई दिल्ली में इति ऐतिहासिक कलशिंग अर इन्टरनेशनल मोडल साइंस कानि० की ओर से प्रादेशिक आर सामाजिक विप्लवता के विषय में एक सम्मेलन हुआ था। इस में पठित निबंध “जि” १६ ईस्टी वल्लभा के प्रो रामरुप गुप्ता से मिल सकते हैं।

### विक्रम की राजनीतिमूलक अर्थनीति

राजनित्य व्यवस्था के संस्थापन में सामाजिक और आर्थिक तन्त्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं की पूर्ति पर व्यवस्था की सफलता निर्भर रहता है। यह व्यवस्था जैसे जैसे जनता में प्रचलन करती है, आर्थिक और सामाजिक प्रगति स्पष्ट हो जाती है और जनता की अनास्थाओं का जन्म देता है। सामान्य भारत में जहाँ नागरिकों की आर्थिक और जनता की उन्नति का तन्त्र अपनाया गया है। राष्ट्रीय एकता और राजा का सहयोग प्राप्त करने पर यहाँ जा जाकर दिया गया है उन्नत आर्थिक विकास और महत्त्वपूर्ण बन गया है।

आर्थिक विकास और राजनीतिक विकास में परस्परिक संबंध का प्रश्न यहाँ सारल नहीं है। जो राजनैतिक प्रणाली गरीबी और अभाव का समस्या का सुलभ मानने का सुनिवार्य ढंग से प्रयत्न नहीं करती वही स्थिर व सफल नहीं बल्कि नाकाम होती। विद्यार्थ्यान् अर्थशास्त्री आर्थिक विकास में राजनैतिक प्रतिपक्षों का मध्यस्थ समझने वाले हैं और उक्त आर्थिक विकास की राजनीति का नाम '१९४'। इसी तरह राजनीति शास्त्री भी राजनैतिक व्यवस्था व आर्थिक पद्धति का मध्यस्थ अनुभव करत और राजनैतिक विकास की अवधारित का नाम '१९५'। वास्तव में ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे से मिलते हुए हैं और इस पर वातावरण, जनसंख्या, सामाजिक ऋण आदि बर्त और याता का प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन विषयों को विकास की राजनैतिक अवधारित का नाम देना उचित होगा।

आर्थिक विभाग की साधारण मर्ति

[illegible]

सबे प्रयत्न के बावजूद जो बदलने की वागिंगा की जा रही है। इन सबके फलस्वरूप विकास की गति एक सी गई है और नहीं बही पीछे हटी है। १९६७-६८ के बीच कुछ प्रगति हाती दीख पड़ी है और विकास का काम फिर चल पड़ा है, मगर कम यहाँ दस पांच वर्ष के काम पर ही विचार करने नहीं बैठें ह। प्राकृतिक आप-आप भारत में आती ही रहती हैं और हमें यह मान कर चलना चाहिए कि यह साधारण बात है। इसके साथ ही हाल में आर्थिक नीति और राजनितिक बावें जो परिवर्तन किए गए हैं उनसे भविष्य का कुछ संकेत मिल सकता है और हम आर्थिक क्षेत्र में भारत के काम का कुछ कामचलाऊ मूल्यांकन कर सकते हैं।

आर्थिक विकास के राजनितिक पहलू से सवधिा सबसे बड़ा सवाल है सामाजिक काम का-एक ओर उत्पादन और सचय और दूसरी ओर कामपूण और समान रूप स वितरण का। ये दोनों पहलू एक दूसरे के विरुधी नहीं ह ये दोनों ही लक्ष्य एक साथ सिद्ध होने चाहिए। पहले कहा जा चुका है कि नव स्वतंत्र देशों को एक साथ कई काम करने हैं। गुरु से ही भारत के सामने चार निश्चित लक्ष्य रह हैं। वेदेशों से बुनियादी वस्तुओं के आयात और विदेशी सहायता पर निर्भरता को दूर करना (स्वयं सपोषित विकास), साधना और पूँजी को जुटाना, जिससे ज्यादा पूँजी बचाकर उत्पादन व विकास में लगायी जा सके (विकास की दर बढ़ाना), समाज के विभिन्न वर्गों में विषमता घटाना (समता), जीवननिर्वाह के लिए न्यूनतम साधन प्रस्तुत करना (काम), इन लक्ष्यों के साथ साथ देश में एकता बढ़ाना, झगडा को रोकना और विविध वर्गों को राष्ट्रीय व्यवस्था में शामिल करना।

इन लक्ष्यों की पुष्टि राष्ट्रीय आंदोलन में और स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के प्रस्तावों में बार बार की गयी थी। कांग्रेस सरकार इनके लिए प्रतिबद्ध थी। इनकी दिशा में कई कदम उठाए गए। गांधी में अधिक कामपूण व्यवस्था काम करने के लिए जमींदारी और सामंती पद्धति का अंत किया गया। विकास के लिए साधन जुटाने और नियोजित प्रयत्न करने के लिए योजना संगठन काम किया गया। गांधी की उन्नति के लिए और सहकारी प्रयत्न को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक विकास और सहकार के विकास का कार्यक्रम शुरू किया गया। सन ५० के दशक के मध्य तक विकास कार्यों को चलाने का प्रशासनिक बाचा तैयार हो गया, और भारी उद्योगों में रुपया लगाने तथा बुनियादी मशीनों व सामान के आयात को बरीयता देकर रवावलवी विकास की तयारी की गयी। लेकिन भारी उद्योगों को चालू करने में एक तो समय लगता है दूसरे जा कारणों लगे के पूरी क्षमता से काम न कर सके, इस कारण एक ओर तो विकास की गति मद पड़ी, दूसरी ओर उपभोग्य वस्तुओं की कमी पड़ी जिससे जनता को कष्ट हुआ। परंतु



इस नीति वं पक्ष में यह कहा गया कि औद्योगिक माल के लिए विदेशों पर निर्यात देश की स्वतन्त्रता को कमजोर करेगी। इसलिए आयात की जाने वाली चीजों के बदले देश के माल से काम चलाने और मशीन बनाने की मशीनों को ही आयात करने पर जोर दिया गया।

पर यह नीति यथाथवादी नहीं। कलपुर्जों का आयात बढ़ करने के प्रयत्न में हमें सबसे बुनियादी आवश्यक चीज अन्न का आयात करने की जितनी ज़रूरत पड़ी। इस नीति की विफलता के कारणों पर हम बाद में विचार करेंगे। यहाँ इतना ही कहना काफी है कि आयोगों ने आर्थिक स्वतन्त्रता और अपने धन पर विकास करने और देश में जल्दी से जल्दी मशीन या पूँजीगत माल बनाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया।

### अपने धन पर विकास

प्रायः एक दशक तक आयोगों का वितरण और लोककल्याण पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्हें पूँजी जुटाने और भारी उद्योगों में उस लगाने का पूरा समय मिला। केवल बीच-बीच में गाँवों की उन्नति के और सूखे या बाढ़ की आपत्ति में कुछ सहायता कर देने के अलावा समाजवाद के समान वितरण के लक्ष्य की सिद्धि के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यद्यपि अभी भी भारी उद्योगों से पूरा उत्पादन नहीं मिल पाया है फिर भी विकास की गति बुरी नहीं रही। यदि सूखे और भूकम्प के दो वर्षों को छोड़ दिया जाए तो १९५१ (पहली योजना का आरम्भ) और १९६५ (तीसरी योजना का चौथा साल) के बीच (१९६०-६१) के स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय कुल ६६ प्र.श. बढ़ी। वार्षिक मिश्र. दर से यह वृद्धि ३.८ प्र.श. होती है। वृद्धि की दर हर योजना में कुछ बढ़ी है। पहली योजना की अवधि में ३.४ प्र.श. दूसरी योजना में ४ प्र.श. और तीसरी योजना के चार वर्षों में यह ४.२ प्र.श. रही। तीसरी योजना काल में अनेक बाधाएँ आईं—दो वर्ष फसल खराब हुई, दो युद्ध हुए और विदेशी मुद्रा की गहरी कमी पड़ी। प्र.श. औसत वृद्धि कोई बड़ी बात नहीं, पर इसके मुनाबजे यह याद रह कि इसके पहले के ५० वर्षों में देश की आर्थिक उन्नति प्रायः शून्य से करीब ५ से १ प्रतिशत कुल वृद्धि) फिर भी जो उन्नति हुई है भारत जैसा गरीब देश उस पर सताप नहीं कर सकता। इस बीच जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है उसको भी ध्यान में रखना होगा। (सन १९५१ से १९६१ के बीच दस वर्षों में जनसंख्या में २१.५ प्र.श. वृद्धि हुई) इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में करीब २ प्र.श. वार्षिक वृद्धि हुई।

इस अवधि में अन्न-उत्पादन में ५० प्र.श. वृद्धि हुई अर्थात् औसत ३.५ प्र.श. प्रति वर्ष। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसके पूर्व ५० वर्षों में न केवल

उत्पादन नहीं बढ़ा, बल्कि प्रति व्यक्ति हिसाब से घट गया, <sup>१</sup> यह वृद्धि अच्छी है। पर भारत की गरीबी और जनसंख्या के विस्फोट को देखते हुए, यह सताप-जनक नहीं कही जा सकती। योजनाओं के फलस्वरूप उद्योगों में उन्नति ज्यादा हुई। इन १४ वर्षों में औद्योगिक उत्पादन का सूचक जब १९५१ में ७४ से बढ़ कर १९६१ में १८७ हो गया (१९५६ को आधार मान कर) जो १५२ प्र० श० से अधिक होता है। (यह सूचक एक महत्वपूर्ण उद्योगों में हुई चमत्कारी उन्नति को सूचित नहीं करता)। इस अवधि में कोयले में १०० प्र० श०, इस्पात में ४०० प्र० श० और बिजली के उत्पादन में ६०० प्र० श० की वृद्धि हुई। पहले यहां मशीनी औजार बिल्कुल नहीं बनते थे, अब इनका बहुत अच्छा उद्योग चालू हो गया है। इसी तरह औद्योगिक उपयोग के और माल, मोटर ट्रक और पेट्रोल के उद्योगों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। इस अवधि में भारत रेल की पटरी बनाने में तीसरे, कपड़ा बनाने में तीसरे, कोयले की खुदाई में सातवें, लोह में नौवें, सीमेंट में नौवें, कोयले में दसवें और बिजली में बाहरवें नंबर पर आ गया। कुल राष्ट्रीय उत्पादन में यह सातवें आठवें नंबर पर था। यहां दुनिया में सबसे बड़ा लोह का खनिज भांडार है, मैंगनीज भांडार में तीसरे नंबर और कोयले में सातवें नंबर पर है। यहां ४१० लाख किलोवाट पनबिजली बन सकती है। (६० प्रतिशत लाड पर)।

देश की इस क्षमता का उपयोग अभी शुरू ही हुआ है। भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र में बुनियादी उद्योग शुरू किए हैं जो किसी निजी उद्योग की सामर्थ्य के बाहर थे। <sup>२</sup> पहली योजना में सरकारी क्षेत्र में ५५ करोड़ की पूंजी लगी थी जो तीसरी योजना में ५२० करोड़ हो गई। निजी उद्योगों में इसी अवधि में पूंजी नियोजन २३३ करोड़ से बढ़कर १०५० करोड़ हो गया। १९५१-५२ में शुद्ध वृद्धि राष्ट्रीय आय की ५३ प्र० श० हुई जो १९६५-६६ में १०५ प्र० श० हो गयी और विनियोग ५३ प्र० श० से बढ़कर १४ प्र० श०। <sup>३</sup> इसके साथ ही मूल्य

१ के मुताबिक 'लेबरिंग ऑफ इन्फ्लेमेटरी ऐक्टिविटीजेंड पब्लिक एन्सप्लेमेटिवर इन इंडिया' (न्यूयार्क १९६५)। १९०० के मुताबिक स्वतंत्रता के समय खेती के उत्पादन का सूचक अरु ६ प्र० श० ऊंचा था और १९३६-३७ के सबसे अच्छे फसल के वर्ष से १२ प्र० श० कम। इस अवधि में अन्न के बजाय नकदी फसलों की खेती बढ़ी और प्रति व्यक्ति खाद्य का उपलब्ध घट गया।

२ इन सरकारी उद्योगों में उल्लेखनीय हैं भारत एलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान केमिकल्स लिमिटेड, बाराकाला और पेराम्बूर के रेल इंजन कारखाने, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो में विदेशी सहयोग से स्थापित इस्पात कारखाने। यहां निजी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने के बजाय, जो उद्योग नहीं थे, उन्हें स्थापित किया गया।

३ ये आंकड़े चौथा योजना के मसौदे पर आधारित हैं। वर्तमान विनिमय दर— १ करोड़ ₹ = १३,५३, ३३३ डॉलर या ३ करोड़ ₹ = ४० लाख डॉ।

की वृद्धि १४ वर्षों में कुल ४० प्र० श० हुई। जबकि इस अवधि में चीन से युद्ध के कारण सेना का खच बड़ा और सरकार को घाटे की वित्तव्यवस्था करनी पड़ी। वर राष्ट्रीय आय के ७ प्र० श० से बढ़ कर १४ प्र० श० हो गए। इन सबके फल स्वरूप एक साल को छोड़ कर जब फमल खराब हो गई थी, सारी अवधि में राष्ट्रीय आय में लगातार, चाहे थोड़ी ही, वृद्धि होती रही।

यह देखाते हुए कि भूमि में भारत का नवर विश्व में सातवा जीर जनसंख्या में दूसरा है, यह प्रगति अधिक नहीं। मगर जिस पिछड़ी हुई हालत में भारत था उसको देखते हुए, इसकी प्रगति बुरी नहीं, खासकर उद्योग में। पूँजी एकत्र करने, और उसे उत्पादन में लगाने, उत्पादन बढ़ाने और महत्वपूर्ण सामान का आयात घटाने में काफी सफलता मिली, यद्यपि योजना के लक्ष्य पूरे नहीं हो सके।

### लोए अवसर

लेकिन अवसर का पूरा उपयोग नहीं किया गया। जमींदारों का उन्मूलन किया गया, लेकिन भूमि का उचित वितरण नहीं किया गया। इसी तरह सिंचाई के साधनों का उपयोग बजाय उपजाऊ क्षेत्रों में करने के सुलाग्रस्त क्षेत्रों में ज्यादा किया गया। निजी और सरकारी उद्योग सबधी विवाद में उबरकर उत्पादन की योजनाएँ बनी रही। अन्न की कमी से खेती की उपज बढ़ाने की प्रेरणा ग्रहण करने के बजाय विदेशों से अन्न मगाने का आसान रास्ता चुना गया।

औद्योगिक क्षेत्र में आयात का विकल्प निवालने की नीति का दुर्लभयोग देश में घटिया उद्योगों को संरक्षण देने में किया गया। बहुत शीघ्रता से बहुत-सी चीजों के कारखाने खड़े करने का नतीजा यह हुआ कि साधन बिखर गए और पूरी अर्थ-व्यवस्था में लागत बढ़ गयी।<sup>४</sup> साधनों को सायक उद्योगों में लगाने और नयी विधियाँ निवालने की प्रेरणा न रही। निहित स्वायों के दबाव के कारण साधनों को नए या आवश्यक कामों में न लगाया जा सका। मूल्यवृद्धि या मुद्रास्फीति से अनावश्यक रूप से डर कर यह कोशिश न की गयी कि मूल्यवृद्धि को उत्पादन बढ़ाने का औजार बनाया जाए। जबकि खेती की लागत अधिक पड़ रही थी, पैदावार का दाम नीचा रहा। इससे खेती की प्रगति रुक गई। सूखे के कारण जब मूल्य के बढ़ने की स्थिति पदा हुई तब सरकार ने घबड़ा कर अपनी योजनाओं में धन का नियोजन घटा दिया। इस

जिस माल की मांग हो उसी के उत्पादन में  
कि मशीनी जीजारों का उत्पादन होना रहे

<sup>४</sup> एक बरनसन-मनुष्यवर्ग माइल्स इन ई  
वर्ष १९६७ में इस पर  
नाने में क्या सम

क्याकि उद्योगों के लिए कच्चे माल तथा अन्य आवश्यक सामान की कमी थी। इस कारण मशीनी औजारों की मांग न रही। हि० म० टू० के माल के ग्राहक भी नहीं मिलते थे। अस्तु यद्यपि तीन योजनाओं के दौरान काफी तरक्की हुई, परन्तु सबसे जरूरी चीजों को प्राथमिकता नहीं दी गई, और कुछ चुने हुए क्षेत्रों में पूरे साधन और जोर नहीं लगाया गया। दिखावे के चक्कर में जो योजनाएं चालू की गईं उनमें साधनों की काफी बर्बादी भी हुई।

अधिक चिंता की बात यी खेती और उद्योगों के विकास में असंतुलन। खेती में देश की तीन चौथाई जनसंख्या लगी है, और इससे राष्ट्रीय आय का आधा भाग प्राप्त होता है तथा इसी से उद्योगों के लिए कच्चा माल भी मिलता है। इस पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया, जिसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर बुरा पड़ा।

इसका असर दिखाई पड़ा जब दो साल तक लगातार सूखा पड़ा, निर्यात की आमदनी घट गयी, पाकिस्तान में युद्ध के बाद बाहरी महायत्ना रुक गयी और पार-खाना के लिए कच्चे माल और कलपुर्जों की कमी पड़ गयी। इसमें दाम बढ़े और मदी आयी, राजनैतिक अस्थिरता और चारों ओर बढ़ा। तब उद्योगों के मुनाबले खेती की उपेक्षा करने का परिणाम सामने आया। इसके फलस्वरूप आर्थिक नीति पर पुनर्विचार हुआ, योजनाओं की प्राथमिकता बदली गई, प्रशासनिक तार-तरीके सुधारे गए तथा पूरी नीति नीति में परिवर्तन हुआ।

किन्तु असंतुलित विकास से हिम्मत हारने की जरूरत नहीं।<sup>१५</sup> इसमें जो सबट आता है उससे आलस खल जाती है और अपने तरीके बदलने का अवसर मिलता है। इससे जो धक्का लगता है, उससे नेतृत्व की गफलत दूर होती है और आगे बढ़ने के लिए नया बल मिलता है। जिन चीजों को पहले असंभव समझा जाता था, वे अब संभव लगने लगती हैं और सभी दल उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। जिन देशों को आलस और अकम्प्यता की आदत पड़ जाती है, उसे इस प्रकार का धक्का लाभ पहुंचाते हैं और काम में लगते हैं।

१९६१-६७ में भारत में जो साथ सबट आया उसके कारण सरकार का विकास कार्यक्रम को दिना बदल गई। खेती के विकास की नई नीति अपनाई गई। सिंचाई की छोटी योजनाओं पर जोर दिया गया। उपजाऊ जमीन में उन्नत बीज और उर्वरक का प्रयोग करने पर जोर दिया गया। जमीन की जांच पड़ताल करने के साथ वर्गीकरण करने पर जोर दिया गया। याजना की प्राथमिकताओं में फेर-बदल किया गया। नियंत्रण का ढीला किया गया। जायान का विस्तृत विवरण देने के बजाय नियामक बढाने पर ध्यान दिया गया और बहुत-सी नई नई योजनाओं

देखिए, एडवर्ड ओ हारमान 'डेवेलपिंग अर्थ इकोनॉमिक्स' १ (१९६४) तथा 'जर्नी टुवर्ड्स प्रोग्रेस' (न्यूयार्क १९६३)। इसमें एडवर्ड ने कहा कि १९६३-६४ विकास से भी विकास में मदद मिलनी है।

को शुरू करने के बजाय वतमान उपादन्यमना का पूरा-पूरा उपयोग करने पर जोर दिया गया ।

तरीका में इन परिवर्तना से ज्यादा महत्वपूर्ण था रुख में परिवर्तन । अनुभव किया गया कि मिफ उपदेश देने और हुसम रना देने से काम नहीं चलगा । इसके बजाय किसान और उत्पादन को मालम होना चाहिए कि उत्पादन बढ़ाने से उसको लाभ होगा । भाषण देने के बजाय किसान को खेती के लिए आवश्यक सामान उपलब्ध कराना जरूरी है । सीमित साधना को बहुत बड़े क्षेत्र में छिनराने की बजाय उनका प्रयोग उपजाऊ क्षेत्र में करना चाहिए जिससे उपज तुरत रहे । दामा को स्थिर रखने की बहुत ज्यादा चिन्ता न करनी चाहिए । जिससे दाम बढ़ने से उत्पादक का फायदा हो और वह ज्यादा मेहनत करे । सबसे बड़ी बात यह हुई कि कागजी घोड़े दौड़ाने के बजाय खेती को आर्थिक समस्या के रूप में देखा गया । और विशेषता तथा सरकारी अधिकारियाँ पर भरोसा करने के बजाय गाव के कायकर्ताओं और नेताओं को आगे आने दिया गया । गाव के इन नेताओं को भारत के प्रगतिशील किसानों के दृष्टिकोण की ज्यादा जानकारी है और उन्होंने माजना कमीशन के कागजी योजना बनाने वालों को प्रभावित किया ।

गासन अधिकारियों ने भी नई लगन और क्षमता दिखाई । मूवाग्रन्थ इलाका में राहत पहुँचाने में राज्य और केन्द्र के साथ मन्त्रालय के अधिकारियों ने जा तत्परता दिखाई वह इसका प्रमाण है । और क्षेत्रों में भी कितानी या कागजी बहस करने के बजाय व्यावहारिक समस्याओं पर ध्यान दिया गया । इस नई नीति और काम करने के नए तरीके की सफलता में अच्छी वर्षा और अच्छे मौसम ने भी योग दिया और इससे अनाज के उत्पादन में आवश्यकतक वृद्धि हुई । पहली बार सरकार में आत्मविश्वास पैदा हुआ और उसने घोषित किया कि १९७० से उसे बाहर से अन्न भगाने की जरूरत न पड़ेगी । यदि ऐसा न भी हो सके, तो इसकी पूरी आशा है कि कुछ ही वर्षों में यह लक्ष्य पूरा हो जाएगा और हम अपने रत्न पर विकाम कर सकेंगे । खेती का पिछड़ापन दूर होने के साथ साथ पहले की औद्योगिक योजनाएँ भी आरम्भ बाधाओं का पार करके फल देने लगेंगी ।

### राजनैतिक प्रश्न

वास्तव में मूपा पढ़ने से पहले ही विकास की रीति नीति बदलने की गुरात हो गयी थी । लेकिन जब साथ सफट उपस्थित हुआ तब सरकार ने सोच विचार या हिचकिचाहट का अंत हो गया और दबना से कदम उठाए गए । सरकार पर एक ओर उन राज्या का दबाव था, जहाँ साथ की अधिकता थी और दूसरी ओर उसे नमी देने राज्या की भाग की पूर्ति करनी थी । मोघाग्रन्थ से इस समय चि० मुग्रहाग्रन्थ जैसा कुशल प्रशासक और राजनीतिज्ञ साथ मन्त्री था । साथसफट,

पाकिस्तान मुद्ध और अमरिका द्वारा सहायता बंद करने से जो स्थिति उत्पन्न हुई उसका लाभ उठा कर उन्होंने लाभकारी नियम बनाने में सफलता पाई। यहाँ हमें साध की कमी की तात्कालिक समस्या और खेती की उपज बढ़ाने की लंबे समय की समस्या में भेद करना चाहिए। खेती की उपज बढ़ाने की समस्या तात्कालिक समस्या से कम बठिन थी। उसके लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से ज्यादा सक्रिय बंदम की जरूरत थी तात्कालिक समस्या वितरण की थी जिसमें राज्यों सहयोग की आवश्यकता थी। इन सबब में जो फैसले किए गए वे राज्या की महमति से और उही की सस्था राष्ट्रीय साध बौमिल द्वारा हुए, जिसमे सभी राज्या के मुख्य मंत्री और केन्द्रीय वित्त, साध और याजना मंत्री सदस्य थे और प्रधान मंत्री अध्यक्ष।

अभी अनेक प्रश्न हल नहीं हुए। राज्यों के स्वायत्त इसमें आडे आत है। उदाहरण के लिए अधिकतर मुख्यमंत्री साध क्षेत्रों की प्रणाली को खतम करने को तैयार नहीं है। इस प्रणाली में एक राज्य या एक क्षेत्र से दूसरे में अन्न नहीं ले जाया जा सकता। इससे मूल्य और वितरण की ठीक नीति निर्धारित करने में बाधा होती है। १९६४-६६ के सूखे के समय (फ़िर्तु १९६६-६७ में नहीं) यह कहा गया कि क्षेत्रीय प्रणाली भी साध संकट का एक कारण है। सरकार द्वारा अन्न की खरीद के लिए ऊँचा दाम देने का भी विराध उन दला द्वारा किया गया जो शहरवाला को सस्ता अन्न दिताना चाहते थे। इसी तरह उबरक और मिर्चाई की याजनाओं के बारे में भी सरकार असमजस में पड़ी है। कारखाने निजी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में, इस विवाद के कारण उबरक उत्पादन और जायात की याजनाएँ खटाई में पड़ी हैं।

परंतु खतरा इस बात का है कि खेती में मिनी इस सफलता से जाश्वस्त होकर भविष्य में उठने वाली कठिनाइयाँ की उपेक्षा कर दी जाय। दूसरी बाधा यह है कि खेती पर अधिक ध्यान देने में उद्योगों की अपेक्षा हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो इससे खेती के लिए आवश्यक सामान की सप्लाई में भी बाधा पड़ सकती है। १९६६ में बड़े ढोल-ढमाके से बैंका का जो राष्ट्रीयकरण किया गया, उसका उद्देश्य भी किसानों और छोटे दुकानदारों का मदद देना अधिक है, बजाय उद्योगों में बचत का धन लगाना। संकट से सबक लेने की जो क्रिया शुरू हुई थी, वह अभी भी जारी है और आता है कि उससे अनेक झुटियाँ दूर हो जाएगी पर नीति और अमल के सभी क्षेत्रों में ऐसा सुधार होगा यह नहीं कहा जा सकता। फिर भी आर्थिक

६ देखिए-क्याकेश मा' 'प्लानिंग फार फेब्ररी इन एशिया' इकनामिक्स ऐंड पोलिटिकल चान्ज बायिफ अफ जन १९६८।

७ मम्म एफ मिलिकन ने यह आशका प्रकट की है- 'शुटिया इन टानिशन इकनामिक डेवलप-मेंट-परफार्मेंस ऐंड प्रोस्पेक्ट्स फारेन अफेयर्स, ४६, न ३ अप्रैल १९६८।

नीति में मोटे तौर पर जो परिवर्तन हुआ है, वह शुभ है। हाँ सक्ता है कि भारत की सरकार फिर सुस्त पड़ जाए और फिर सक्ट पड़े। यदि ऐसा होगा, तो इससे देश में फिर सजगता आएगी। यहाँ हम विदेशी मुद्रा और विदेशी सहायता की वमी जैसी बाहरी बाता पर विचार नहीं कर रहे हैं। यह अगले अध्याय का विषय है।

### न्याययुक्त वितरण

आर्थिक विकास सबकी नीति पर विचार करने के बाद अब हम महत्व के प्रश्न पर आते हैं कि किसको क्या मिला। इस प्रश्न के भी दो पहलू हैं। एक तो यह कि स्वयं नेतावग का यह लक्ष्य है कि वितरण न्याययुक्त हो अर्थात् विकास का लाभ गरीब तबके को मिले। दूसरा पहलू है विकास के लाभ के विषम वितरण के कारण बर्चित और गरीब तबके का असंतोष और उसकी इस लाभ में उचित हिस्सा बटाने की मांग।

भारत में वितरण का प्रश्न 'गांव बनाम शहर' का सवाल बन गया है। जय बहुत से प्रश्न - बेकारी, जनसंख्या का दबाव, मूल्यनीति, करनीति, यहाँ तक कि शिक्षानीति भी इसी दृष्टिकोण से देखे जाते हैं। गाँवों में भी विभिन्न वर्गों में जो विषमता है उसकी भी उपेक्षा कर दी गयी है। राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर कांग्रेस के अनेक प्रस्तावों और संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत, सब में गाँवों की उन्नति, और जागृति पर खास ज़ोर दिया गया है। योजनाओं में साधारण और भारी उद्योगों के विकास के कार्यक्रम शुरू किए जाने के बाद 'ग्रामीत्यान' पर जोर कम नहीं हुआ।

जैसा कि आम तौर पर होता है, भारत में भी योजना में औद्योगीकरण और श्रमिक शक्ति को खेती से हटा कर शहरों में (उद्योगों में) लगाने का कार्यक्रम बनाया गया। यह उचित भी था, क्योंकि भूमि या खेती पर भार बहुत हो गया था और खेती के बजाय उद्योगधरा में श्रम और साधन लगाने से ज्यादा और जल्दी लाभ मिलता है। परंतु जनगणना से पता चलता है कि जनशक्ति को खेती के बजाय उद्योगों में लगाने का लक्ष्य सफल न हो सका। १९५१ और १९६१ दोनों बार की गणना में खेती में ७२ प्र.श. जनसंख्या लगी थी (यदि केवल पुरुषों को लें तो अनुपात कुछ घटा, अर्थात् ६९ प्र.श. से ६८ प्र.श. हो गया।) पूँजी की भी यही स्थिति रही। १९५०-५१ में देश की ४० प्र.श. उत्पादक संपदा खेती में लगी थी और १९६०-६१ में भी यही स्थिति थी, जबकि राष्ट्रीय आय में खेती की आय का अंश ४९ प्र.श. से घटकर ४६ प्र.श. हो गया। यह कमी भी खेती की गिरावट का द्योतक है। इस प्रकार श्रमशक्ति, आय और पूँजी के खेती से उद्योग में जाने की आशा पूरी नहीं हुई (स्मरण रहे कि प्रतिघटन न बढने पर भी कल-

कारवानों में लगे श्रमिका की सख्या और उनमें बनने वाले माल में बहुत वृद्धि हुई)।

गावा की अधिक

शुरू से ही सरकार गावा में ज्यादा धन लगा रही है। १९५१-६१ के दशक में गावों से कर की आय ८० प्र स बढ़ी, लेकिन उसी दशक में करो से प्राप्त आय जो गावा में लगायी गयी, १८० प्र स बढ़ी। मूल्यवृद्धि और रहन सहन के सूचक अब का हिसाब लगाने के बाद गाव में लगी करो से प्राप्त शुद्ध आय में १५० प्र स की वृद्धि हुई। दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों से करो से जितनी आय हुई, उससे कम उनमें खर्च किया गया। इन दोनों वर्षों में यह रकम २०० करोड़ रही। योजना के परिव्यय के हिसाब से भी प्रथम दो योजनाओं में ४५ प्र स और तीसरी योजना में ४० प्र स गावा में व्यय हुआ।<sup>८</sup> इस प्रकार यद्यपि सब मिला कर खेती पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया (पहली योजना को छोड़कर) परन्तु अन्य क्षेत्रों पर गावों में काफी रुपया खर्च किया गया।

दूसरी ओर कल-कारखानों और खेती से इतर क्षेत्रों में उत्पादकता अधिक होने के कारण बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय का ज्यादा लाभ, प्रति व्यक्ति और प्रति काम गार शहरो में ज्यादा हुआ। लेकिन शहरी क्षेत्रों पर कर का बोझ भी ज्यादा रहा। सरकार कृषक वर्ग पर प्रत्यक्ष कर लगाने से हिचकती है। खेती पर प्रत्यक्ष कर, भूमिकर हा है। द्वितीय महायुद्ध के बाद से इसकी दर नहीं बढ़ायी गयी है। इस लिए इसका वास्तविक बोझ काफी घट गया है। इसी बात को ध्यान में रख कर अनेक राज्या ने भूमिकर एकदम समाप्त कर दिया। अप्रत्यक्ष करों का भार भी गावों के मुकाबले शहरों पर ज्यादा है।

इधर खेती के घड़े में मुनाफा बढ़ गया है। इसलिए अब व्यवसायकुशल और साधनसंपन्न लोग भी इस में आ रहे हैं, और अच्छे बीज, खाद, सिंचाई और उन्नत औजारों व यंत्रों में रुपया लगा कर खेती को उद्योग की भाँति चलाने में तत्पर हैं। पचायती राज, सहकारी संगठन और राष्ट्रीयकृत बका से ऋण आदि की सुविधाओं के कारण इस प्रवृत्ति को और बढ़ावा मिला है। पुराने राजा व जमींदार, आरक्षित नेता जो पहले शहरों में ही छाये रहते थे अब गावों में फाम बना रहे हैं।<sup>९</sup> सरकारी और फौजी अधिकारी और ऊँची जातियों के लोग अब खेती के

<sup>८</sup> इसमें नेता तथा सामाजिक सेवा, सार्वजनिक और पुनर्वास आदि पर व्यय शामिल है। ये आंकड़े सरकार प्रकाशनों से लिए गए हैं - 'पैसि - सैमस ऑफ इंडिया १९६१-६२ फारनल पापुलेशन टोटल ( नद दिनी १९६२ )। तामरा योजना के परिणिष्ट ( नद दिनी १९६१ ) वेसिक स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स टु इंडियन इकनमी १०-५०-५१ से १९६५-६६ ( नद दिनी १९६६ ) तथा गान रोजन 'गिनोक्सा पेंन कनामिकु सैन इन इंडिया' ( बकले १९६७ )।

<sup>९</sup> तामन बार मे-काफ 'इंडियन विदाउंड लैंड द यू पा नमोशम दुडे' ( पैसि अके स १८२, १९६७ )।



आर्थिक और राजनैतिक लाभ का अनुभव कर रहे हैं। भारतीय राजनीति में सबसे नया शक्तिशाली दल बड़े किसानों, 'कुलकों' का है, जो समाज के सभी वर्गों से आए हैं। ये खूब मुनाफे की खेती कर रहे हैं और राजनीति में भी प्रवेश कर रहे हैं।<sup>१०</sup> ये लागू अपना पूरा जोर इसी बात पर लगाएंगे कि खेती पर न लगाने और ग्रामीण क्षेत्रों को तरजीह देने की नीति जारी रहे।

इस प्रकार भारत के नेताओं की साधारण नीति यही रही है कि गांवों के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। राजनैतिक शक्ति भी गांवों के नेताओं के हाथ में होने के कारण इसी नीति की पुष्टि हुई है। इस नीति का औचित्य भी है, क्योंकि सदियों से भारत के गांव उपेक्षित रहे हैं। दूसरे, खेती और गांवों के विकास पर ज्यादा ध्यान देने से भारत की गरीबी की समस्या सुलझाने की भी अधिक आशा है।<sup>११</sup>

### शहरीकरण की प्रवृत्ति

भारत के विकास का एक और रोचक पहलू है नगरीकरण की मद गति। यह कुछ हद तक गांवों के विकास पर अधिक ध्यान देने का परिणाम है। आलोच्य दशक में शहरों में रहने वाली जनसंख्या का अनुपात प्रायः ज्यों का त्यों रहा। १९५१ में १७.२६ प्र.श. जनसंख्या शहरों में रहती थी। १९६१ में यह १७.६७ प्र.श. थी। यद्यपि नगरों की जनसंख्या में १ करोड़ ६४ लाख की वृद्धि हुई (नगरों की पुनर्परिभाषा के फलस्वरूप यह वृद्धि २ करोड़ १२ लाख हो गयी) परन्तु कुल जनसंख्या में उसका अनुपात केवल ०.६८ प्र.श. ही बढ़ा (पुनर्परिभाषा के बाद १.७६ प्र.श.)। शहरीकरण की दर पहले दशक के मुकाबले धीमी पड़ गयी। पिछले दशक में यह २.४८ प्र.श. थी, जबकि इस दशक में यह सिर्फ ३.६ प्र.श. रही।<sup>१२</sup> जैसा कि सारणी नं. १ से पता चलेगा, १९२१ के बाद के दशकों में यह सबसे कम रही।

यह मद गति अविकारियों की आशा के विपरीत रही और इस धारणा के भी

१० इस दृष्टि में इस प्रकार के लोग आ रहे हैं, इसके लिए देखिए - जेनियल पार्नर, 'यू.एस.ए. में जनसंख्या का रुझान' (न्यूयॉर्क-ब्लक) १-४-१९६७।

११ चार्ल्स डी. लिंडब्लम, 'पोलिटेमोरेमा पेंडिंग डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट्स' (न्यूयॉर्क-ब्लक) १-४-१९६७।

१२ आशीष बोस 'सिस्टमैटिक्स ऑफ अर्थनाइजेशन इन इंडिया १९०१-१९६१' (नई दिल्ली-ब्लक) १-४-१९६७।

विपरीत कि आधुनिकीकरण के साथ नगरीकरण की दर बढ़ती है।<sup>१४</sup> १९५१-६५ के बीच भारत का तेजी से आधुनिकीकरण हुआ और शिक्षा, उद्योग व शिल्प का विकास हुआ। यद्यपि विकास के क्रम में शहरो में काम करने वाले श्रमिका की सत्यावृद्धि स्वाभाविक थी, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि जनसंख्या की गति गावों से शहरो की ओर हो।<sup>१५</sup> ऐसा प्रतीत होता है कि खेती के धंधे में लाभ बढ़ने से, गावा के आधुनिकीकरण से और राजनीति के विकेंद्रीकरण से नगरीकरण की गति मद रही। (सारणी नौ-१)

नगरों की जनसंख्या बढ़ने में दो कारण होते हैं। एक प्राकृतिक वृद्धि, दूसरा गावा से नगरों में आगमन। सारणी नौ २ और ३ में इस दशक में गावों से नगरों में आगमन का विवरण है। सारणी नौ २ से पता चलेगा कि बहुत कम श्रमिक शहरो या किसान नगरों में आए (आकड़े बड़े नगरों के हैं, पर छोटे नगरों में भी स्थिति यही थी)। सारणी नौ ३ से इस धारणा का खंडन होता है कि जहाँ जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होता है, वही से सबसे ज्यादा लोग नगरों में आते हैं। इसके विपरीत देखने में यह आया कि उन्हीं क्षेत्रों से ज्यादा लोग नगरों में आए जहाँ आबादी कम घनी थी (मद्रास, पश्चिम बंगाल और राजस्थान इसके अपवाद हैं)।<sup>१६</sup>

इस पक्ष में दो बातें ध्यान योग्य हैं। एक तो जैसा आशीश बास ने कहा है भारत में गावाजाही गती रहती है, लोग शहरो को जाते हैं और फिर गाव लौट जाते हैं। जबकि १९५१-६१ के दशक में शुद्ध आगमन या प्रवास ६० लाख रहा,

१४ यह धारणा इतनी दृढ़मूल है कि जब भारत में इससे विपरीत प्रवृत्ति दाख पड़ी तो किंग्सले डेविस ने इसका कारण यह बताया कि यहाँ आर्थिक विकास की गति अपेक्षाकृत मंद रही। किंग्सले डेविस, 'अर्बनाइजेशन इन इंडिया' पार्लियामेंट पब्लिकेशन (नवंबर १९६२) "सबसे विपरीत देखें, आशीश बास 'अर्बनाइजेशन इन फस और रैपिड पापुलेशन ग्रोथ एंड सरप्लस लेबर इन फस और इंडियन पापुलेशन मुलेटिन नं ३-१९६४।

१५ बड़े नगरों में नगराकरण ज्यादा तेज रहा (प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी अर्थात् २०,००० से ज्यादा आबादी वाले नगर) "नमो वृद्धि ४२ प्र. ३ में है (पिछले दशक में ५० प्र. ३)। मध्यम और छोटे नगरों में ७२ प्र. ३ की कमी हुई (जबकि पिछले दशक में २० प्र. ३ की वृद्धि हुई थी)। इसमें पता चलता है कि बड़े औद्योगिक नगरों में वृद्धि अधिक होता है और गावों से पत्र भरा भी कमतर नहीं हुई।

१६ सबसे ज्यादा चलाय देहात से देहात की ही होता है। १९०१ से १९६१ के बीच २७.५१ प्र. ३ देहात से देहात में गए १३.७१ प्र. ३ शहर से शहर की ६.१० प्र. ३ शहर से देहात और केवल ५.४६ प्र. ३ देहात से शहर में गए। ध्यान रहे कि गावों में गमन ज्यादातर व्यावसायिक स्वरूप का होता है। सेंसस आफ इंडिया १९६१, भाग २ सा माइग्रेशन टेबुल नं. दि १९६७) तथा - इन्डियन आइजेशन इन इंडिया (एन एम एन रिपोर्ट नं. ५३, १९६३)।

वष प्रतिवष गिाती २४० लाख पहुँच जाती है। दूसरी बात यह है कि यहा गमन गावा से शहरा का गही, बल्कि छोटे नगरा या बस्वा से बडे नगरा का होता है।

अत में एा बात यह भी ध्यान योग्य है कि जहाँ १९५१-६१ के बीच गावा की जनमाया २० प्र श बढ़ी, वहा रोती बरने वाला की ४३ प्र श बढ़ी। सन १९५१ म टुपका का प्र ग ७४४० था जबकि १९६१ में ७६४४ प्र ग हा गया।<sup>१०</sup> इस प्रकार नगर देहात अनुपात में एक स्थिरता रही। यह प्रवृत्ति ऐसे समय रही, जब राजनैतिक शक्ति शहरा से निबन्न बर गावा में जा रही है।<sup>१०</sup> (सारणी नो-२ और नो-३)।

मगर इस स्थिति में भी गनरे है। शहरा में जनसहवा की स्वाभाविक वृद्धि के कारण गावा के लोगा को उनमें स्थान मिलना कठिन हो जाता है। इसके फल स्वरूप गावा में भूमि पर भार बढ जाएगा और विपमता और सघष पैदा होगा। दूसरी ओर शहरा में विरोपकर सिधित वग में बेकारी बढेगी। इससे शहर और गाव के बेराजगार और विपन्न वर्गों का समुक्ता मोरचा बन सकता है और वग-सघष की स्थिति उत्पन्न हा सकती है।

### क्षेत्र के अंदर विपमता

टुपका वग में भी व्यापक विपमता है।<sup>११</sup> यह सही है कि जमींदारी के उन्मूलन और भूमि सुधारा के कारण, सामती वर्ग के हाथ से अधिकार छिने हैं और जमीन किमाता के स्वामित्व में गयी है। १९६१ की जनगणना के अनुसार ७७ प्र श टुपका परिवार अपनी जमीन के मालिक थे, ८ प्र श पक्के शिकमी थे और १५ प्र श मिश्रित वग के शिकमी या दर शिकमी। लेकिन कांग्रेस को बडे किसाना के समयन की जरूरत थी इसलिए भूमि सुधार (जोत की सोमाबदी, भूमिहीना को जमीन वितरण) ठीक ढंग से लागू नहीं किए गए, और विकास काय का लाभ भी बडे और धनी किसानो को ज्यादा मिला। रिजर्व बैंक की एक पडताल से पता

१७ जनगणना और योजना कमीशन के अलवा भारत के बदलने हुए यावसाधिक दांचे के और कई अध्ययन हुए। इनके साराश के लिए देखें-ने कृष्णमूर्ति 'सेकुलर नेजेन इन आकुरेशनल स्ट्रक्चर आफ द इंडि यूनियन १९०१-६१ (द इंडि इक ऐं सोशल हिस्ट्री रिव्यू, दो-स १, जन १०६५)।

१८ देहात के अतगत १०० आदिमियों से लेकर १००० तक की आवादी के गांव आ जाते हैं। ये गांव जिलों में वर्गीकृत होते हैं और ये जिले राजनैतिक सत्ता और आर्थिक शक्ति के तथा अनेक प्रकार का प्रशासनिक सुविधा के केन्द्र होते हैं। नगर या कस्बे में भी देशान के अनेक तत्व होते हैं। नगरी और देहाता क्षेत्रों में सत्ताबेन्द्र जिले के मुख्यालय और राज्य की राजधानियाँ होता हैं।

१९ देखें-पी सी जोशा 'फार्स ऐं फू-द प्राबलम' सेमिनार स ८१, मर १९६६ तथा रिजर्व बैंक और योजना कमीशन के मूल्यांकन संगठन की रिपोर्टें।

चलता है कि २५ प्र स सबसे धनी किसानों के पास ७५ प्र स जमीन है। इन धनी किसानों ने ही विकास कार्यों से सबसे अधिक लाभ उठाया है।<sup>१०</sup> अनेक पड़ताल से पता चला है कि अपने प्रभाव, शिक्षा और प्रबोधनशक्ति के कारण इसी वग का वका व सहकारिया से सत्रमे अधिक लाभ मिला और इसी ने कृषि विस्तार सेवा आर सामुदायिक विकास कार्यक्रम से भी सबसे अधिक लाभ उठाया।<sup>११</sup> इधर उपज बढ़ाने के लिए जो तकानिक साधन, सिंचाई उपकरण, बीज आदि खेती में लगाए गए, वे भी अधिकांश इसी वग को मिले। खेती की पैदावार के मूल्यो को ऊंचा रखने और सरकारी खरीद की नीति से भी इसी वग को ज्यादा लाभ है।

ध्यान रहे कि जब तक समाज में यह भावना रहती है कि बड़े लोग या बड़ी जाति हमेशा बड़ी रहगी और छोटी जाति छोटी, तब तक असतोष दवा रहता है। लेकिन जब एक बार छोटी समष्टी जानेवाली जाति या वग के लोग सरकारी विकास कार्यक्रम और जमींदारी उन्मूलन आदि कारवाइया का फायदा उठा कर ऊंचे घुड़ जात हैं, तब जीरा की आकांक्षा भी जागती है और सघन पैदा होता है।<sup>१२</sup> यदि संपन्नता से छोटे किसानों और भूमिहीनों को भी लाभ नहीं पहुँचता तो सामाजिक और राजनीतिक विक्षोभ की स्थिति पैदा होगी। १९६९ में वैश्वीय गृहमन्त्रालय की एक विशेष रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई कि उपजाऊ क्षेत्रों में भूस्वामी लोग बटाईदारों को हटाकर उनकी जगह खेत मजदूरों को रोजाता मजदूरी पर रण रह हैं इससे गाँवों में बेरोजगारी और असतोष बढ़ रहा है। इस प्रकार दुनियादी भूमि सुधार न हुए तो हरी क्रांति से विपन्नता और बढ़ेगी। कहा जा सकता है कि विकास के साथ विपन्नता जवसर बढ़ती ही है <sup>१३</sup> लेकिन विप-

२० यह पड़ताल था—आल इंडिया डेट एंड इनवेस्टमेंट सर्वे—रिजर्व बैंक इले जून ६५ और अक्टू १९६६। हर राज्य में भी अन्तर था। वितरण की विपन्नता सबसे कम था जम्मूकश्मीर में, ०.४८ प्र स आर सबसे ज्यादा था आंध्र में, ०.७३ प्र स। भूमि सुधार और आर्थिक विकास के सघन के विद्वेषण के लिए देख, राजदृष्टि का लेख—‘सम ऐस्पेक्ट्स आफ रैड रिफॉर्म एन्ड इक डेव आफ इंडिया—वास्टर प्रोविंस संपादित—लेड टेन्पोर, इन्स्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक सोशल स्टैटिस्टिक्स एन्ड पब्लिशिंग्स पेंड प्रारोफेस् इन् एशिया’ (मिलवाबी १९६१)।

२१ रिजर्व बैंक क्रेडिट फालोअप सर्वे, १९५८-१९५९ (वर्ष १९६१)। एन सी डुवे—‘इन्विया चंफा विजेजिन’ (इयाका १९५८)। डी और ए थानर—‘लेड ऐंड लेबर इन इंडिया’ (वर्ष १९६२)। डा के एन राज सम फाचम आफ द रन ग्रोथ आफ द लास्ट डिवेड इन इंडिया—द इक चानला १३, एनुअल नंबर १९६१।

२२ खेती म मुनाफा होने देख कर हर वर्ग के लोग—यापारी, मज्जानन, रिटायड शासन और फाग अधिकारियों ने इसमें प्रवेग किया है। कुछ तो काफी नाची जाति के हैं, जिससे वे इध्या के पात्र बने हैं।

२३ अलमर्ट ओ इशमैन—‘स्ट्रेटजी आफ इकनामिक डेवलपमेंट’।

मना उहुत बड़ेगी तो न केवल इससे विकास रहेगा बल्कि राजनैतिक विक्षोभ और अस्थिरता भी बढ़ सकती है।

यदि हम गावा के लोगो का बड़े और मध्यम धोणी के किसान, छोटे किसान और भूमिहीन ( जिनमें भूमिहीन मजूर भी है ) में बांट तो पहले वग को ऊपर बताये गए कारणों से सबसे ज्यादा लाभ हुआ। दूसरे वग का भी भूमिसुधार और खेती के विकास की योजनाओं से लाभ हुआ। १९६१ की जनगणना के अनुसार किसानों की संख्या में ४३ प्र० श० की जो वृद्धि हुई, उसका कारण भूमिसुधार, विशेषकर जाति की सीमा बाधना है। यद्यपि इन सुधारों पर अमल में काफी ढील दी गई। १९५०-५१ में १९५६-५७ में हुई दा जाचा में पता चला कि यद्यपि खेत - मजदूरों की आम हालत में सुधार नहीं हुआ, किंतु सरया घट गई। २४ ऐसा जान पड़ता है कि इन मजदूरों में जा कुछ अच्छे थे (जिनके पास कुछ जमीन थी) वे कुछ और जमीन प्राप्त करके किसान बन गए। १९६१ की जनगणना से पता चलता है कि खेत-मजदूरों की संख्या बढ़ने के बावजूद उसमें तुलनात्मक ह्रास हुआ है। जब कि गावों की जनसंख्या करीब २० प्र० श० और कृषकों की ४३ प्र० श० बढ़ी, खेत मजदूरों का प्र० श० २० से घट कर १७ हो गया। पंजाब, गुजरात और आंध्र ऐसी संपन्न खेती के इलाकों में तो खेत मजदूरों की संख्या घट गई, खास कर बटाई आदि के समय। चूंकि आधुनिक तरीकों के कारण खेती की उपज बढ़ी है इसलिए भूमिहीन बटाई पर खेती कराने के बजाय छुट्टा मजदूर रख कर खेती कराते हैं, इससे गावा की सबसे नीची जातियों का कुछ फायदा हुआ है।

लेकिन जनसंख्या बढ़ने के कारण, मजदूरों चाहते वाला की संख्या भी बढ़ी और खेत मजदूरों की मजदूरी या अन्य फायदों में कोई इजाफा नहीं हुआ। खेत मजदूरों में बढ़ी जाचा से पता हुआ कि उनकी आमदनी १० प्र० श० घट गई है। यद्यपि ये आंकड़े सरासरी के नहीं हैं फिर भी इसमें संदेह नहीं की खेत मजदूरों की हालत खस्ता है। २५ महत्त्व की बात यह है कि इनमें से कुछ की हालत सुधरी है इसलिए दूसरों की आकांक्षाएं जगी हैं। खेत मजदूरों ने निरवकाश वग, छोटे किसानों का। उनकी हालत भी सुधरी है और इज्जत बढ़ी है। क्रांति का यह मुनिष्ठ सिद्धान्त है कि जब तक कोई वग लगातार बंटे में रहता है, जिससे उठम की कोई बाधा नहीं दी जाती तब तक वह नाति के लिए उद्यत नहीं जाना। क्रांति की चिनगी तब सुगमनी है, जब उस उद्यति की जाना और सभावना दील जाओ

२४ रिपोर्ट ऑन द मेकेन एंडि सेक्टर एनक्वायरी १९५६-५७ ( शिमा १९६० )। विभिन्न कृषक वर्गों के लाभ क्षति की तुलना के लिए देखें बाज रोजेन, पूर्वोक्त, पृ १६५ १७२।

२५ देखें-डा वि क र राव संपादित ' एंडि सेक्टर इन इंडिया ( १९६१ १९६५ ) में 'नया और टा के एन राव केलेख और टी तथा ए थॉर्नर ७३ पेज रेफर इन इंडिया'।

है। २६ अगले १०-१५ वर्षों में समस्त भारत के गांवों में परिवर्तन की मांग तेज होगी। धनी किसानों को बटाईद्वारा तथा खेत मजदूरों को दोनों से संपर्क करना होगा यद्यपि कभी कभी बटाईद्वारा और मजदूर वर्गों में भी विरोध हो सकता है। तब ही सकता है कि भूमि सुधार और खेती की आय पर कर लगाने की योजनाएं सरकारी दफ्तरों में धूल खा रही हों कमल में लाई जाएं।

सारांश यह है कि शुरू में जब नई जमीन तोड़ी जाती है और भूमिसुधार द्वारा खेती करने वालों को मालिकाना हक दिए जाते हैं तब पैदावार बढ़ती है। उत्पादन की गति वृद्धि नए तरीकों पर और ऋण आदि की सुविधाओं पर निर्भर होती है जिसके लिए राजनैतिका और सरकारी नीतियां तक पहुंच सहायक होनी हैं, इस कारण उच्चवर्ग या बड़े लोग सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं, और आर्थिक विकास के साथ साथ विषमता बढ़ती है। इसमें उत्पादन और वितरण दोनों पर बुरा असर पड़ता है। इसे दूर करने के लिए ऊपर के नेता पंचायती राज आदि संस्थाओं को शुरू करके वे दहाती जनता को उत्साहित करने और लाभ का भागीदार बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें विफलता होने पर सरकार के विरुद्ध असंतोष बढ़ता है और चुनाव में सरकारी दल की हार होती है। इसके कारण आमूल परिवर्तन के लिए राजनैतिक दबाव बढ़ता है।

परंतु वर्तमान व्यवस्था के प्रति गांववालों का आम विरोध संभावित नहीं। क्योंकि पैदावार के मुकाबले खपत और मांग बढ़ने के कारण अभी कई वर्षों तक अनाज के भाव ऊंचे बने रहेंगे। जनसंख्या की वृद्धि और विदेश से आने का आयात घटने के कारण भी भाव ऊंचे बने रहेंगे। शहरवालों की गति से सस्ते अनाज की मांग उठेगी, लेकिन गांववालों के राजनैतिक जोर के कारण इसका माने जाने की आशा नहीं। इसलिए खतरा यह नहीं है कि गांववालों को सरकार की व्यवस्था से असंतोष हो, बल्कि यह है कि गांवों में ही बगमथप की तीव्रता आ जाए। (नक्सलवादियों का आंदोलन इसी प्रवृत्ति का द्योतक है।)

शहरों की स्थिति भी ठीक तौर पर यह है। कंपनी और कारखाने वालों का मुनाफा बढ़ा है। कारखानों में काम करने वालों का वास्तविक वतन भी बढ़ा है। निजी क्षेत्र के ऊंची श्रेणी के कर्मचारियों की अमल आमदनी भी बढ़ी है, और ऐसे पदा की सरप्रा भी बढ़ रही है। दूसरे वर्ग के कर्मचारियों की आमदनी तो नहीं बढ़ी लेकिन जगहों बढ़ी हैं। थोके गार सुदूर व्यापारियों की आमदनी भी बढ़ी है। दूसरी गार ऊंची और निचली श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की वास्तविक

२६ अर्थशास्त्र में टाकविल ने कर्म की राजस्वगत पर अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में लिखा है कि सदियों तक यह भ्रम रहने पर भी लोगों ने अनुभव नहीं किया कि निम्न व्यवस्था में वे घिस रहे हैं वह चिन्ता अत्यावृत्ती है। उन्होंने यह अनुभव तब किया जब आर्थिक उत्पत्ति होने लगी। यही बात अब देशों में भी दीर्घ पड़ी।

आय घटी है। सरकारी प्रतिष्ठानों के ग्रामिका का आमदनी में घट-उठ नहीं हुई, क्योंकि वेतन कमिशन की सिफारिश के अनुसार इनका महगाई के साथ उसका मुआवजा बढ़ता जाता है। इनकी सस्या भी काफी बढ़ी है। शायद सबसे अधिक कष्ट विश्वविद्यालय कालेज और स्कूलों के अध्यापकों को है, यद्यपि इनकी सस्या में भी बहुत वृद्धि हुई है।

निम्न मध्यम श्रेणी की नौकरियों में लगातार बढ़ती विकास का एक ठाम लाभ है। लेकिन दूसरी ओर यह बग मेहनतमजूरी करन वाले बग के निकट जाता जा रहा है और ऊपर के बगसे इसकी दूरी बढ़ती जा रही है। इस प्रकार निम्न मध्यम बग नीचे और ऊंचे दोनों वर्गों की तुलना में घाट में रहा। ऊंची आय वाले बग में यह इप्पा करता है और उसके मुकाबले नीचे जा रहा है। दूसरी ओर यह निचले बग के स्तर पर जा रहा है जिससे यह ऊपर रहना चाहता है। शहरो में सबसे अधिक असताप इसी बग में है। तरह-वादीक श्रेणियाँ और सरकारों नीरस को मान मर्यादा में भी काफी घटी हुई है और उनमें भी क्षीन और विराघ है। इस प्रकार भारत में फारखाने के मजदूरों की ओर से बगसपप का खतरा कम है और निम्न मध्यम बग की ओर से अधिक, इसके साथ असनुष्ट बौद्धिक बग भी हो गया है।

### बेरोजगारी की समस्या

बढ़ती हुई बेरोजगारी की दलते हुए, खामरर गहरा में निमित्त बेरोजगारी की बढ़ी सस्या की इस प्रकार के मोरचे की संभावना और बढ़ गयी है। सरकारी अनुमान के अनुसार १९५१-१९६१ के बीच श्रमिक सस्या में २१० लाख की वृद्धि हुई, जबकि बेरोजगार लोग की सस्या में केवल १७० लाख की वृद्धि हुई। द्वितीय योजना के अंत तक अनुमान है कि बेरोजगारों की सस्या ७० लाख थी। तीसरी योजना में काम करने योग्य लोगों की सस्या में १७५ लाख की बढ़ती हुई जबकि काम में नगे लोग की सस्या केवल १४५ लाख बढ़ी। इस प्रकार तीसरी योजना के अंत तक १०० लाख लोग का काम नहीं मिल गया था, जिनमें २५ लाख शहरो में थे। १० (कुछ लोगों का म्यान है कि बेरोजगारी की सस्या और अधिक, १५० लाख थी) अनुमान है कि चौथी योजना के अंत तक बेरोजगारों की सस्या १४० लाख (सरकारी अनुमान) से २०० लाख के बीच हो जाएगी। बेरोजगारी में इस वृद्धि का कारण कुछ ता जनसंख्या की अत्यधिक बढ़ती है कुछ अव्यवस्था का स्त्रावली बाधों के लिए पूजीगत सपन बढ़ाने का अधिक

२७ बेरोजगारों की संम सरा के सस्या करीब १-०-१०० लाख थेमे है, जिनको पूरा काम नहीं मिला है।

नीति है, और कुछ बच्चे माल की कमी आदि के कारण स्थापित उत्पादनक्षमता का पूरा काम न करना है।

रोजगार बढ़ाने के तीन उपाय हो सकते हैं — एक, पूँजी — थम अनुपात को घटा देना, दूसरा, कारखानों में ज्यादा आदमियाँ को रखना और तीसरा, बेकारक्षमता का पूरा उपयोग करना। पहला बठिन है क्योंकि इस समय पूँजी का नियोजन कुछ खास आर्थिक और प्रौद्योगिक तन्त्रों का सिद्ध करने के लिए हो रहा है। दूसरे उपाय से थम की उत्पादकता घटेगी। १९५१-६१ में उत्पादनवृद्धि का ६५ प्र.श. श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ने से आया और ३५ प्र.श. श्रमिकों की संख्या बढ़ाने से। इसलिए एक रास्ता यही रह जाता है कि वर्तमान उद्योग पूरी क्षमता से काम करे। इसके लिए विदेशों से जरूरी पुँज और सामान मंगाना होगा, और यह तभी हो सकता है जब निर्यात की जाय बड़े। यद्यपि बेरोजगारी की समस्या विशाल है, पर देश के आयातकों ने सीधेता से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने को प्राथमिकता दी है, और उन्हें आशा है कि इससे रोजगार भी बढ़ेगा। २८ इस बीच गाँवों में सामाजिक निर्माण के काम चालू करके कुछ हद तक बेरोजगारों को काम देने की कोशिश की जा रही है।

इधर हाल में इंदिरा गांधी ने आर्थिक नीति को राजनैतिक रत्न दिया है और गरीबी तथा विषमता घटाने की समस्या पर जोर दिया है। इससे दाहुरा में बारी गरी और शिल्पियों की तथा गाँवों में बटाईदारा और भूमिहीन मजदूरों की बेरोजगारी और अथ — बेकारी दूर होने में कुछ मदद मिलेगी।

भारत की अशिक्षित जनता में कष्ट सहने की बेहद क्षमता है। यहाँ परिवार और नाते रिश्तेदार भी बेकार की मदद करते हैं। बहुत से ग्रामीण मजदूर बीच बीच में काम मिल जाने से और निर्वहियोग्य मजदूरों मिलने से ही सन्तोष कर लेते हैं, इसलिए यहाँ सामाजिक विस्फोट नहीं हुआ। पर वास्तविक तौर पर दाहुरों में शिक्षित बेरोजगारों से है। मगर शिक्षितों को काम देने का प्रबन्ध नहीं हो पा रहा है। सारणी नं०-४ से पता चलेगा कि अनेक राज्यों में बेरोजगार शिक्षितों की संख्या अशिक्षितों और कम शिक्षितों से ज्यादा है। उदाहरण के लिए पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरल और दिल्ली जैसे अधिक उन्नत क्षेत्रों में। गुजरात और

---

२८ आय और संपत्ति की विषमता को जाँच करने के लिए भारत सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की थी। पर इसका रिपोर्ट से इस समस्या पर कोई खास प्रकाश नहीं पड़ा, क्योंकि कमेटी को आवश्यक आंकड़े नहीं मिल पाए। इसलिए हमने इस प्रश्न पर यहाँ विचार नहीं किया है। 'हमके बिना हमें यह समस्या राजनैतिक दृष्टि से ज्यादा महत्व की नहीं प्रतीत हुई। फिर भी देखें — रिपोर्ट आफ द कमेटी ऑन टिरडीम्ब्यूशन आफ इनकम ऐंड लेवेल्स आफ लिविंग' (महात्मा नवीन कमेटी रिपोर्ट) दिल्ली १९६४ तथा आर के हजारी — द 'स्ट्रक्चर आफ क्वाण्टिटी प्रा सेक्टर' (बदई — न्यूयार्क, १९६६)।





अधिकांश लोग पन्द्रह से चौतीस वर्ष की आयु के होते हैं (सारणी नौ-६) इसके साथ ही यह ध्यान में रहे कि सबसे ज्यादा बेकारी कम आयु के लोगों में है (सारणी नौ-७)। इससे पता चलता है कि नई पीढ़ी का असंतोष राजनीति पर गहरा प्रभाव डालेगा। हमने देखा है कि भारत में पश्चिम की तरह नई पीढ़ी अपने बड़े-बूढ़ों का निरादर नहीं करती। इससे अलावा भारत के नौजवान प्रस्तुत व्यवस्था को उलटने के बजाय, केवल अपने लिए काम और स्थान चाहते हैं।<sup>२९</sup> खेती में लाभ बढ़ने के कारण हो सकता है कि बहुत से नौजवान शहरों में काम तलाशने के बजाय खेती में लग जायें। यह भी प्रतीत होता है कि स्वतंत्रता के बाद जमीन पीढ़ी ज्यादा यथाव्यवादी है, बजाय पहले की पीढ़ी के जिनका लालन पालन लम्बे चौड़े आदर्श और सिद्धांत के बीच हुआ था।<sup>३०</sup>

मगर यह याद रहे कि आजकल की शिक्षा और अखबार, किताबें, फिल्म और रेडियो आदि पुगाने मूल्यों की जड़ काट रहे हैं। नई पीढ़ी ज्यादा व्यावहारिक और यथाव्यवादी है इसका अर्थ यह भी है कि उसे खयाली गुलामों से बचना नहीं जा सकता और वह ठोस चीजें चाहती है — नौकरी और अच्छी आमदनी। यदि इस वर्ग की आशाएं पूरी न हुई तो इसका क्षोभ वर्तमान व्यवस्था को ढहा सकता है। इसलिए अधिक से अधिक आमदनी के लिए रोजगार या काम के लिए साधन प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है।

इहीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जनसंख्या की वृद्धि का निरोध करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर परिवार नियोजन का कार्य चलाया है। इसका उद्देश्य जनसंख्या की वृद्धि की दर को चालीस प्रति हजार से घटाकर पचीस प्रति हजार करना है। इस कार्यक्रम के लिए तीसरी योजना में सत्ताईस करोड़ रुपये खर्च किए गए थे जबकि चौथी योजना में ३०० करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। (१) इस कार्यक्रम में लोगों में इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि छोटा परिवार अच्छा होता है। (२) लोगों को परिवार नियोजन की विधि बताई जा रही है। (३) इसका सामान दिया जा रहा है तथा डाक्टरों की सहायता दी जा रही है। (४) परिवार नियोजन कार्य के विशेषज्ञ बड़ी संख्या में तैयार किये जा रहे हैं। पर अभी यह कार्यक्रम बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में है और इसका असर केवल शहरों

२९. नोसफ लेन्की के ड-‘इंडियन स्टुडेंट डिमांड एसेसिंग इन एस्टिमेशन’ द न्यूयार्क टाइम्स मैगज़ीन मई १२, १९६८। इसका कहना है कि भारतीय विद्यार्थी पुरानी व्यवस्था को उलटना नहीं चाहता, वह उनमें स्थान पाना चाहता है।

३०. जोसेफ ट-नू एलडर ने पुरानी पीढ़ी के राष्ट्रवादियों और स्वतंत्रता के बाद की पीढ़ी के देशभक्तों में अंतर दिया है। देखें उनकी ‘नेशनल लायब्ररी इन ए न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन’—टविड पेंटर सभा ‘आस्ट्रियोलापा पेंड डिमंड-टेंट’ (न्यूयार्क १९६४)।

महाराष्ट्र में उच्च शिक्षा माता की शिक्षा अधीन है पर मध्यम दर्जे की शिक्षा माता में बहुत पराजयागी है। १९१७ में राजगार दफ्तर में दत्त नाम का माता की संस्था १८८१ में स्थापित की अवधि १९६१ में छ साल का है। माता की प्रार्थना कि कभी प्राथमिक शिक्षा ही माता ही दफ्तर में काम चलाते हैं। इसका अर्थ यह है कि १८६१ में दत्त नाम में अधिक शिक्षा पराजयागी से और बहुत सारा माता में बगल में था ही जा रही है। इस में राजगार दफ्तर में दत्त माता का पहला १८८१ की त्रिमास पता बता कि इनमें के माता लग से जा व्यावहारिक और प्राथमिक माता में प्राथमिक माता में माता में अधिक हार्दिकता पाय से और निम्नतर माता में अधिक शिक्षा पाय से द्वितीय माता से (दिए गए माता की-८)।

[illegible]

इधर वैवा के राष्ट्रीयकरण और एकाधिकार की प्रवृत्तियाँ को रोकने तथा गरीब वर्ग को लाभ पहुँचाने की राहवाई भी बड़ी है उससे आर्थिक नीति में परिवर्तन की सम्भावना है। मगर निधन और वित्त वर्ग की माँग को संतुष्ट करने का परिणाम यह न होना चाहिए कि निजी उद्यम का उत्साह मारा जाय। जिस हद तक सरकार प्रत्येक क्षेत्र के उन्नतिवादी लोगों को उत्साहक कार्यों में लगा सकेगी उस हद तक आर्थिक समस्या सुलझाने में मदद मिलेगी।

व्यक्ति जार्ज क्या होगी यह बहुत कुछ नीजवान वग पर निर्भर है। सन १९६१  
 में ५७७ प्रतिशत जनगणना चौबीस वष और उससे कम आयु की थी, ४१ प्रति  
 शत चौदाह साल से कम आयु की थी। इसी वष की शिक्षा का बेतहाशा विस्तार  
 हुआ है। हर साल वष में माध्यमिक स्कूला के विद्यार्थियों की और हर छ वष में  
 उच्चतर स्कूला के विद्यार्थियों की संख्या दूनी हो जाती है। सहर में आने वाले

अविकास लाग पद्रह से चौतीस वष की आयु के होने है (सारणी नौ-६) इसके साथ ही यह ध्यान में रहे कि सबसे ज्यादा बेकारी कम आयु के लोगों में है (सारणी नौ-७)। इससे पता चलता है कि नई पीढ़ी का असंतोष राजनीति पर गहरा प्रभाव डालेगा। हमने देखा है कि भारत में पश्चिम की तरह नई पीढ़ी अपने बड़े-बूढ़ा का निरादर नहीं करती। इसके अलावा भारत के नौजवान प्रस्तुत व्यवस्था को उलटने के बजाय, केवल अपने लिए काम और स्थान चाहते हैं।<sup>२९</sup> खेती में लाभ बढ़ाने के कारण हो सकता है कि बहुत से नौजवान शहरों में काम तलाशने के बजाय खेती में लग जायें। यह भी प्रतीत होता है कि स्वतंत्रता के बाद जमींदारी ज्यादा यथाव्यवस्था है, बजाय पहले की पीढ़ी के जिनका लालन-पालन लम्बे-चौड़े आदर्श और सिद्धांत के बीच हुआ था।<sup>३०</sup>

मगर यह याद रहे कि आजकल की शिक्षा और अवसर, किताबें, फिल्म और रेडियो आदि पुराने मूल्यों को जड़ काट रहे हैं। नई पीढ़ी ज्यादा व्यावहारिक और यथाव्यवस्था है इसका अर्थ यह भी है कि उसे खयाली पुलावों से बहकाया नहीं जा सकता और वह ठोस चीजें चाहती है — नौकरी और अच्छी आमदनी। यदि इस वर्ग की आशाएं पूरी न हुई तो इसका क्षोभ वर्तमान व्यवस्था को ढहा सकता है। इसलिए अधिक से अधिक आदमियों के लिए रोजगार या काम के लिए साधन प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है।

इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जनसंख्या की वृद्धि का नियंत्रण करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर परिवार नियोजन का कार्य चलाया है। इसका उद्देश्य जनसंख्या की वृद्धि की दर को चालीस प्रति हजार से घटाकर पचास प्रति हजार करना है। इस कार्यक्रम के लिए तीसरी योजना में सत्ताईस करोड़ रुपये खर्चे किए गए थे जबकि चौथी योजना में ३०० करोड़ रुपये खर्चे किए गए हैं। (१) इस कार्यक्रम में लोगों में इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि छोटा परिवार अच्छा होता है। (२) लोगों को परिवार नियोजन की विधि बताई जा रही है। (३) इसका सामान दिया जा रहा है तथा डाक्टरों की सहायता दी जा रही है। (४) परिवार नियोजन कार्य के विशेषज्ञ बड़ी संख्या में तैयार किए जा रहे हैं। पर अभी यह कार्यक्रम बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में है और इसका असर केवल शहरों

२९. गीमफ लेन्गफेन्ड- इंडियन स्टुडेंट्स डिमांड एसेसबल इन प्रसिडेंसमेंट 'द न्यूयार्क टाइम्स' में १०, १९६८। इसका कहना है कि भारतीय विद्यार्थी पुरानी व्यवस्था को खत्म करना नहीं चाहता, वह उसमें स्थान पाना चाहता है।

३०. जेम्स टर्नर एक्टर ने पुरानी पीढ़ी के राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता के बाद की पीढ़ी के देशभक्तों में अंतर किया है। देखें उनकी 'नेशनल लायटींग इन द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन'-टैब्लेट पेंपर में 'आरग्योलाजा ऐंड डिमंड-टैट (न्यूयार्क १९६४)।

में और उन जिला में पडा है जहा जोरो से काम किया गया है।<sup>३१</sup> कायक्रम की जाच पड़ताल से पता चला है कि अभी भी इसमें बहुत सी त्रुटिया हैं। लोगो को परिवार नियोजन की सामग्री ठीक ढंग से नहीं मिल रही है और अच्छे कार्यक्रम भी कम है। राजनीतिक नेताओं से इसे उत्साहपूर्वक समर्थन भी नहीं मिला है। इसका असर देर में होगा जबकि तात्कालिक समस्या का तात्काल समाधान जरूरी है।

## शिक्षा का प्रभाव

आधुनिक युग में शिक्षा का महत्व सामाजिक और आर्थिक विकास में बहुत अधिक है। शिक्षा मनुष्य के जीवन, आकांक्षा और रुख को बदल देती है। एक तरफ यह मनुष्य को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करती है तो दूसरी तरफ यह पुरानी परम्परा पर भी प्रहार करती है। शिक्षा से जो आकांक्षाएं पैदा हो जाती हैं, वे जब सतुष्ट नहीं होती तो समाज में निराशा का वातावरण बढता है और परिवर्तन की मांग उठती है।

लोकतन्त्र की यह एक बड़ी समस्या है कि यह अपने सब लोगो को शिक्षा का मुक्त अवसर देने के लिए बचनबद्ध है। साथ ही उसे यह ध्यान भी रखना है कि विभिन्न प्रकार के व्यवसायो में जितने आदमी तय सके उससे ज्यादा न प्रशिक्षित किए जावे। लेकिन शिक्षा अच्छी नौकरी और व्यवसाय पाने का साधन है। इसी लिए हर आदमी की यह आकांक्षा होती है कि वह शिक्षा प्राप्त करे और जब शिक्षा प्राप्त करने के बाद काम नहीं मिलता तो निराशा और क्षाभ बढता है। भारत में यही सब देखने में आ रहा है।

भारत की मुख्य समस्या शिक्षा का घीमा विकास नहीं, बहुत तेज विकास है। यह सही है कि अभी भी साक्षरता कम है (१९६१ में २४ प्रतिशत) परन्तु १९५१ और १९६१ के बीच पढने वाले लड़का की संख्या दुगुनी और लड़कियों की तिगुनी हो गई।<sup>३२</sup> माध्यमिक और उच्चतर स्कूलों में भी हर सात और हर छ बर के बाद विद्यार्थियों की संख्या दुगुनी हो जाती है। अनुमान है कि इस गति से १९८० तक माध्यमिक स्कूलों में ८० प्र. स. लड़के लड़कियां दाखिल हो जायेंगे और कॉलेज या विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कुल जनसंख्या की दस प्रतिशत हो जाएगी।

पढाई जारी रखने की प्रवृत्ति भी बढती जा रही। अनुमान है कि अगले दस-पंद्रह वर्षों में मिडिल क्लास पास करने वाले अधिकांश विद्यार्थी ऊंची कक्षाओं में

३१ महाराष्ट्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम में बड़ी सफलता मिली है और वह ज्यादा सतानो त्पत्ति को निरुत्साहित करने के कई उपाय सोच रही है जैसे जिसे तीन से ज्यादा सतान दो उस मुक्त या सती चिकित्सा शिक्षा आदि सुविधाओं से वंचित कर देना।

३२ ये सारे आँकड़े, शिक्षा बर्मीगन १९६४-६६ की रिपोर्ट से लिए गए हैं - 'एजुकेशन ऐंड नेशनल डेवलपमेंट' (दिली, १९६६)।

भरती होंगे और हाईस्कूल पास करने वाले साठ प्र श विद्यार्थी कालेजों में नाम लिखाएंगे। जिन लोगों को एक श्रेणी की पढ़ाई समाप्त करने पर काम नहीं मिलता वे आगे की श्रेणी की पढ़ाई में लग जाते हैं। लड़कियों में शिक्षा के अत्यधिक प्रसार का यही कारण है। यदि निचले स्तर की शिक्षा समाप्त करने पर लड़का को रोजगार मिलने लगेगा तो उच्च शिक्षा में भीड़ कम हो सकती है। लेकिन इसके खिलाफ नियोजक वर्ग की प्रवृत्ति यह है कि वह जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ भी उच्च शिक्षा या डिग्री वालों को रखना पसंद करता है। उसका नतीजा यह होगा कि अगले तीस वर्षों में हर स्तर पर—प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च—शिक्षा शत-प्रतिशत हो जाएगी।

शिक्षा के बेतहाशा विस्तार का नतीजा यह भी हुआ है कि उसका स्तर गिरा है और उसके व्यावसायिक बनाने पर ध्यान नहीं दिया जा सका है।<sup>१३</sup> साधारण शिक्षाप्राप्त लोगों की संख्या बहुत बढ़ी है लेकिन विशेषज्ञ की अब भी कमी है। इसका एक नतीजा यह भी हुआ है कि लड़कियों की शिक्षा पर खर्चा बढ़ाई हो रहा है क्योंकि बहुत कम लड़कियाँ काम-धंधा करती हैं।<sup>१४</sup>

फिर भी दो एक क्षेत्रों में विशेषज्ञों की भले ही कमी हो, साधारणतः प्रत्येक विषय में ज़रूरत से ज्यादा शिक्षित उपलब्ध है। शिक्षा-कमीशन ने इसलिए यह सिफारिश की है कि हाईस्कूल और कॉलेज में भर्तियों कम की जाय। फिर भी अनुमान है कि १९८६ तक हाईस्कूल पास ४० लाख और डिग्रीधारी पंद्रह लाख विद्यार्थी फालतू होंगे। उस समय तक अनुमान है कि कॉलेजों में भी ७०-८० लाख विद्यार्थी होंगे जो ज़रूरत से दुगुने होंगे।

शिक्षा का यह विकास सही ढंग से नहीं हुआ है। सारणी नौ-८ से पता चलेगा कि १९५०-५१ में संचित व्यय वगैरे जहाँ ६५ प्र श लड़के मिडिल कक्षाओं

३१ इस विस्तार से गांव और ग्रामीण वर्ग को कम लाभ हुआ है और सबसे मेहनती व अच्छे विद्यार्थी इसी तबके के होते हैं। गांव के लड़कों को व्यावसायिक और टेक्निकल संस्थाओं में केवल ४१४ प्र श स्थान मिलते हैं जबकि वे ८० प्र श हैं। वही तरह १५० रु से कम आय के वर्ग के छात्रों को इन संस्थाओं में केवल १०५ प्र श स्थान मिले जबकि वे भी जन संख्या के ८० प्र श हैं।

३४ प्रारंभिक में दाखिल होने वाली लड़कियों का अनुपात प्रति १०० लड़के १९०१ में १२, १९५० में ३९ और १९६५ में ५१ हो गया। माध्यमिक स्तर पर ये आंकड़े हैं ४, १५, और २६। उच्च शिक्षा में लड़कियों की प्रगति अत्यधिक है, १९०१ में इस स्तर में केवल २६४ लड़कियाँ थी जो १९५० में ४०,००० और १९६५ में २,४०,००० हो गई। दूसरी तरफ, शिक्षित लड़कियों को काम बहुत कम मिला। १९८१ में वैज्ञानिक और टेक्निकल कर्मचारियों की पट्टा से शान हुआ कि स्त्रियों में बेरोजगारी (३१ प्र श) पुरुषों से (८७ प्र श) बहुत अधिक है। मानविकी में यह अंतर और भी अधिक होगा क्योंकि इस पढ़ाई का उद्देश्य मुख्यतः शर्मा है काम नहीं।

11

सरकार स्थिति को समालने का उपाय कर रही है। गावों के गरीबों को ज्यादा दाखिला, व्यावसायिक और शिल्पिक स्कूलों में ज्यादा भर्ती, विभिन्न प्रदर्शों और गावों और शहरों में भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा और उद्योगधंधों की आवश्यकता के मुताबिक शिक्षा। पता चला है कि किसानों के लड़के अब पढ़ कर गावों में खेती व कामधंधा करने में प्रवृत्त हो रहे हैं। इस प्रवृत्ति में कृषि विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योग रहा है। वर्तमान उद्योगों की पूरी क्षमता का उपयोग करने से भी शिक्षितों को काम मिलेगा। सामाजिक सेवाओं के विस्तार से (जिनमें गावों में स्कूलों का खुलना भी शामिल है) बहुत से निम्न मध्यम वर्ग के विद्वान् और मानविकी विद्यार्थी के स्नातकों को काम मिलेगा। बड़े पैमाने पर गावों में स्थापित चालू हाने से इजीनियरों का रोजगार मिलेगा। इसके अलावा बहुत से लोगों को लगन या मौसम के समय जो काम मिल जाता है, और बहुत से कामगार शहर में थोड़े समय काम करके गाव लौट जाते हैं, तथा बर्माई और जाय परिवार की समझी जाती है एक आदमी की नहीं। इससे भी बेकारी का दबाव कुछ कम हो जाता है। फिर भी शिक्षितों की बढ़ती हुई संख्या (स्त्रियाँ भी इनमें शामिल हैं) के राजनैतिक प्रभाव की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।<sup>२६</sup>

खेद है कि अभी तक शिक्षित बेरोजगारों के राजनैतिक खतरे को नहीं समझा गया, न इन शिक्षित जनसंख्या का विकासकार्य के लिए उपयोग किया गया, न आर्थिक योजना में ऐसे परिणतन किए गए, जिससे बेरोजगारी घटे। विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम, अध्यापन और प्रशासन का ढांचा भी दक्षिणपूर्वी चला जा रहा है। इससे नवयुवक सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में अपना स्थान देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं।

## निष्कर्ष

जिन समस्याओं पर यहाँ विचार किया गया—उद्योगों की पूरी क्षमता का उपयोग, खेती के साधन जुटाना बेरोजगारों का उपाय करना, जनसंख्या वृद्धि को रोकना, और शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को देश के विकास और परिवर्तन में लगाना—इन सबका धुंधला आभास भारत सरकार को है और वह कुछ कर भी रही है। पर बहुत ढिलाई और सुस्ती से जो योजनाएँ स्वीकृत हो चुकी हैं, उनका काम भी सुस्त है। अभी अव्यवहृत क्षमता का उपयोग की बहुत गुंजाइश है। खाली बैठे शिक्षित युवकों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं, जिससे विकास में तेजी आ सकती है। प्रशासन को पुराने सड़े गले कार्यदो की जड़ से छुड़ा कर उसमें तेजी लायी जा सकती है। विकास कार्य को चलाने वाली मशीनरी में हर

२६ शिक्षा के प्रभाव के बारे में देखें—बलेस इवेलेस 'पार्टिमेंट मिनिजिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज' अमेरिका में पोली ग्रास रिपोर्ट। इसमें भारत पर भी विचार किया गया है।

२५३



मे पढते थे वहा १९६५-६६ में उनकी संख्या तिगुनी जयान १९१ प्रतिशत हा गई। मगर निचली माध्यमिक व्यावसायिक कक्षाओं में दाखिला १९५०-५१ में ३ प्र श से गिर कर १९६५-६६ में २२ प्र श हा गया। उच्चतर माध्यमिक व्यावसायिक स्कूलों में दाखिला १९५०-५१ में ४४ प्र श से घटकर १९६५-६६ में ६० प्र श हा गया। यदि शिक्षा कमीशन की यह आशा पूरी हो जाये कि १९८६ तक निम्न माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा में २० प्र श और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में ५० प्र श विद्यार्थी दाखिल होंगे, तब भी व्यावसायिक शिक्षा में कुल दाखिला विद्यार्थियों के पूरे दाखिले का केवल १० प्र श ही होगा, जो कि एक आधुनिक व्यवस्था के लिए बहुत कम है। पश्चिम जर्मनी में स्कूल में व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा का अनुपात ७० और ३० है, जबकि जापान में ६० और ४०। भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का अनुपात १९६५-६६ में कुल दाखिले का २३ प्र श था जो जरूरत से कम है।

लेकिन संस्था के हिसाब से उच्च व्यावसायिक शिक्षा में भारत में उल्लेखनीय उन्नति हुई है—सन १९५०-५१ में ५६००० से १९६५-६६ में २४६००० अर्थात् १५ वर्ष में साठे बार गुनी वृद्धि। (सारणी नं-८)। परंतु समस्या यह है कि अनेक प्रकार के व्यवसाय की शिक्षा की आवश्यकता होत हुए भी, प्रशिक्षित लोगों का काम नहीं मिलता हाल में ४०,००० इंजीनियर बेकार थे। इससे विज्ञान और इंजीनियरी कालेजों में विद्यार्थियों में घबराहट पैदा हुई और उन्होंने हड़ताल व प्रदर्शन किए। कुछ ता बात यह थी कि दो वर्षों के सूखे के कारण १९६७ में उद्योगों में मंदी आई। मगर मुख्य बात यह है कि बिना यह माने कि कितने

इंजीनियरों को काम दिया जा सकता है, अवागुण इंजीनियरिंग कालेज खोल दिए गए। सितंबर १९६६ तक पाली बटे इंजीनियरों की संख्या ६०,००० हो गई और अनुमान है कि दाखिला घटा देने पर भी यह संख्या १,००,००० पहुँच जाएगी। सरकार ने उच्च स्तर के टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कृषि विश्वविद्यालय साधनालाए और संस्थान खोल दिए हैं। शिक्षा कमिशन की सिफारिश के मुताबिक विभिन्न विषयों में ऊँचे दर्जे के मर्यादा भी खोले जा रहे हैं। मगर समस्या यह है कि इन संस्थानों से निकलने वाला को काम कहाँ दिया जाएगा।

शिक्षा पर इतना जोर देने के बाद, उसमें कमी करना तो संभव नहीं। लेकिन शिक्षा के विस्तार व साथ साथ काम देने का प्रयत्न नहीं हुआ तो राजनैतिक स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। यह समस्या बड़ी गंभीर है और इसने कारण सत्ता में अमनोपन्न अवश्यभावी है।<sup>३५</sup>

३ सारणी नं ४६ और ७ से प्रकट होगा कि शिक्षा, कम आय, बेगारी और शहरी का प्रभाव में उदास संभव है।

सरकार स्थिति को समझने का उपाय कर रही है। गांधी के तरीके का ज्यादा दायित्वा, व्यावसायिक और निष्पक्ष मूल्यों में ज्यादा भरोसा, विभिन्न प्रदत्तों और गांधी और गांधी में भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा और उद्योगधंधा की आवश्यकता का मुआयना किया। दत्त चला कि विज्ञान के लड़के अलग पढ़ कर गांधी में ऐसी व्यवस्था करने में प्रयत्न हो रहे हैं। इस प्रवृत्ति में श्रम विद्यालय का महत्व पूरा योग रहा है। वनमान उद्योगों की पूरी क्षमता का उपयोग करने से भी शिक्षा का काम मिलेगा। सामाजिक सेवाओं के विस्तार से (जिनमें गांधी में स्थायी मूल्यों को शामिल है) बहुत से निम्न मध्यम वर्ग के विज्ञान और मानविकी विभागों के स्तरों का काम मिलेगा। बड़े पैमाने पर गांधी में स्थापित कार्य चालू होने से इजीप्ट की राजधानी मिलेगा। इसके अलावा बहुत से लोगों को वन या मोगम के समय को काम मिल जाता है, और बहुत से कामगार शहर में पाठे समय काम करके गांधी चोट खाते हैं तथा बर्माई और आय परिवार को समझी जाती है, एक आदमी की नहीं, इससे भी बेकारी का दवाव कुछ कम हो जाता है। फिर भी निमित्तों की चर्चा हुई मरणा (स्त्रियाँ भी इसमें शामिल हैं) के राजनैतिक प्रभाव की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए।<sup>१९</sup>

लेद है कि अभी तक शिक्षित बेरोजगारी का राजनैतिक मतलब का नहीं समझा गया, न इस शिक्षित जनशक्ति का विकास के लिए उपयोग किया गया, न जायदा योजना में ऐम परियोजना लिए गए निमित्त बेरोजगारी घटे। विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम, अध्यापन और प्रशासन का ढांचा भी दक्षिणपूर्वी चला आ रहा है। इससे नवयुवक सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में अपना स्थान लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं।

## निष्पक्ष

जिन समस्याओं पर यहां विचार किया गया—उद्योगों की पूरी क्षमता का उपयोग, ऐसी के माध्यम जुटाना, बेरोजगारी का उपाय करना, जनसंख्या वृद्धि को रोकना और शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों का देश के विकास और परिवर्तन में लगाना—इन सबका धुंधला आभास भारत सरकार को है और वह कुछ कर भी रही है। पर बहुत ढिलाई और मुस्ती से जा योजनाएँ स्वीकृत हो चुकी हैं, उनका काम भी सुस्त है। अभी अव्यवहृत क्षमता के उपयोग की बहुत गुंजाइश है। खाली बंटे शिक्षित युवकों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं, जिससे विकास में तजी जा सकती है। प्रशासन का पुराने सड़े गले कायदों की कैद से छुड़ा कर उसमें तैजी लायी जा सकती है। विकास कार्य को चलाने वाली मशीनरी में हर

१९ शिक्षा के प्रभाव के बारे में देखें—अलेक्स इन्फेल्स 'पॉसिबिलिटी मिटिजनशिप इन डेवलपिंग कंट्रीज' अमेरिका में प्रकाशित। इसमें भारत पर भी विचार किया गया है।

धेनी पर ज्वाला योग्य आदमी जाए जाने चाहिए । पर इस ओर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है ।

ऐसा लगता है कि जैसे वृषि त्रासि के लिए साक्षसकट जरूरी था, उसी तरह आगे कोई गहरा संकट आने पर ही सरकार चेतेगी । पर खतग यह है कि मूल्य-वृद्धि से मध्यम वर्ग और श्रमिकों की वास्तविक आय बहुत घट जाए, निर्यात का माल महंगा हो जाए और निर्यात घटने से, औद्योगिक उत्पादन के लिए अनिवार्य सामान का आयात न हो सके, इससे कल कारखाना का उत्पादन घटे, परिणाम स्वरूप बेकारी बढ़े और शहरो में असंतोष व उपद्रव हो जाए स्थिति इतनी बिगड़ जाए कि वर्तमान व्यवस्था ठप हो जाए ।

भारत ने अब तक हर प्रकार के संकटों का सामना करने की विलक्षण क्षमता दिखाई है, परंतु इस संकट को हमेशा याद नहीं रखा है और तत्प्राप्त नहीं किया है । तत्त्व की दृष्टि यह है कि हमारे नेताओं में कितनी समझदारी और स्थिति के अनुसार अपना रवैया बदल सकने की क्षमता है ।

## अंतरराष्ट्रीय स्थिति

अब तक हमने मुख्यतः भारत की आंतरिक स्थिति का ही विवेचन किया है। अब हमें अंतरराष्ट्रीय सदन में भारत की स्थिति पर भी विचार करना चाहिए क्योंकि द्वितीय युद्ध के बाद दो महाशक्तियाँ हैं जो स्पर्धा चली और उससे कारण जो अंतरराष्ट्रीय गुटबंदी शुरू हुई उसका प्रभाव राष्ट्र की नीति पर पड़ना अनिवार्य था। प्रश्न यह था कि देश बड़ा तक गुटों में शामिल होने के दबाव का सामना कर सकता था और अपनी स्वतंत्र नीति पर चल सकता था। इधर सत्तार का दो गुटा में विभाजन भी टूटा है और भारत जैसे देशों को अपनी नीतियाँ पर पुनर्विचार करना पड़ा है।

यहाँ हम भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर मोटे तौर पर विचार करेंगे। भारत पर विदेशी सत्ता की स्थापना के फलस्वरूप इस पर बाहरी सत्तार की विचारधाराओं, औद्योगिक विधियों और सत्ताओं का प्रभाव पड़ा और कुछ हद तक इसका भी बाहरी दुनिया पर प्रभाव पड़ा और वर्तमान में भी यह प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा पड़ोस के देशों की शत्रुता और सत्तार में महाशक्तियों की मोरचेबंदी को देखते हुए देश की रक्षा का भी प्रश्न है। अतः देश के आर्थिक विकास और आर्थिक नीति पर विदेशी आर्थिक सहायता और विदेश से आर्थिक संबंधों का प्रभाव पड़ता है। इन अंतरराष्ट्रीय संबंधों का प्रभाव देश की आंतरिक नीतियों पर भी पड़ता है। जैसे राजनीति में सेना का स्थान, बाहरी देशों से लड़ाई का देश की एकाग्रता पर प्रभाव, रक्षा और आर्थिक विकास में संबंध, और विदेशों से सहायता का केवल देश के आर्थिक विकास पर ही नहीं, राजनैतिक रूप और परराष्ट्रनीति पर प्रभाव। इसके अलावा राष्ट्रीय अस्मिता, स्वाभिमान और मनोबल के बुनियादी प्रश्न भी उठते हैं। एक ओर हम अपनी राजनैतिक स्वतंत्रता को बनाये रखना चाहते हैं और अंतरराष्ट्रीय समाज में प्रतिष्ठा और अग्रता प्राप्त करना चाहते हैं, और दूसरी ओर हमें अपनी कमजोर औद्योगिक स्थिति के कारण आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस दृष्टि से हमारी परराष्ट्र नीति का मुख्य



## राष्ट्रीय स्वतन्त्रता

लेकिन यह आदशवाद खोखला न था, न राष्ट्रीय हितों के विपरीत था। नेहरू सत्सार की बदली हुई स्थिति का जोर लोगों से ज्यादा समझते थे। उन्होंने समझा था कि द्वितीय युद्ध ने सत्सार की व्यवस्था बदल दी है। उन्हें इसका भान था कि जिस समय उपनिवेशवाद के शिकार देश स्वतन्त्रता प्राप्त कर रहे हैं, उसी समय उनकी स्वतन्त्रता को सबसे अधिक खतरा है। न केवल नए देशों में अपनी आजादी की रक्षा की शक्ति न थी, बल्कि खतरा यह था कि सत्सार में बड़े राष्ट्रों की गुट-बंदी में पड़ कर वे उनके पुछल्ले बन जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र सभ की रचना भी नए राष्ट्रों के लिहाज से सतोपजनक न थी। इसने ऐसी व्यवस्था नहीं स्थापित की जिसमें प्रत्येक राष्ट्र समान रूप से स्वतन्त्र था, बल्कि इसने सत्सार को दो श्रेणियों में बांट दिया, एक बड़े राष्ट्रों का घम और दूसरा उनके अनुयायियों या पीछे चलने वालों का। भारत को ऐसा लगा कि बड़े राष्ट्र (विशेषतः संयुक्त राष्ट्रों) सत्सार (अमरीका) भूमध्यसागर से लेकर बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी चीन सागर तक के सारे क्षेत्रों पर हावी हो जाना चाहते हैं। इसका गहरा प्रभाव भारत पर पड़ता था।

नेहरू इसका प्रतिरोध करना चाहते थे। पर यह सैनिक ताकत के जोर से नहीं हो सकता था। यह प्रतिरोध वह वैचारिक स्तर पर करना चाहते थे। वह एक नया सिद्धांत प्रस्तुत करके, सत्सार के जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। उन्होंने जो विदेशनीति प्रस्तुत की उसके तीन उद्देश्य थे — (१) उन देशों को एक हद तक स्वतन्त्रता दिलाना जो बड़े राष्ट्रों का सामना करने में असमर्थ थे (इसी से उन्होंने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरोध पर जोर दिया)। (२) बड़े राष्ट्रों की शक्तिस्पर्धा से उत्पन्न गुटबंदी को रोकना जो सत्सार की व्यवस्था के कारण उत्पन्न हुई थी (इसीलिए उन्होंने फौजी गुटा का डट कर निरंतर विरोध किया)। (३) और उत्तरी अफ्रीका से लेकर इंडोनेशिया तक के भूभाग को बड़े राष्ट्रों के दबाव से मुक्त रखना (इसी उद्देश्य से उन्होंने एशियन कानफरेंस बुलाई और अफ्रीका — एशिया के राष्ट्रों के सम्मेलन शुरू किए)। उनकी यह नीति अमरीका के विरुद्ध जाती थी, इसलिए अमरीका के प्रभाव को रोकने के लिए उन्होंने इस क्षेत्र में एक प्रतिवारक शक्ति के रूप में रूस के प्रवेश की काशिश की और भारत की स्वतन्त्रता कायम रखने के लिए पूर्व (रूस) और पश्चिम (अमरीका) की कशम-कश से लाभ उठाने की कोशिश की।

इसकी नीति को विफल करने में नेहरू की सफलता उल्लेखनीय है। अगर राष्ट्रीय नीति का इतिहास जब निष्पदा होकर लिखा जाएगा, तो इसे स्वीकार किया जाएगा। उनकी दाद की विफलताओं के सामने इस सफलता को भुलाना नहीं चाहिए। नेहरू राजनैतिक स्वतन्त्रता को वास्तविक राष्ट्रीय स्वतन्त्रता या आत्म-

प्रश्न या प्रयोजन देना की रक्षा और परराष्ट्र संबंध ही नहीं, आर्थिक पिछेपन या विकास की समस्या भी है, जिसके कारण ससार में हमारी स्थिति कमजोर होती है।

## नीति का विकास

जिस समय हमें आजादी मिली उस समय ससार की स्थिति में यह स्वाभाविक था कि देश जवाहरलाल नेहरू की नीति अपनाए। ससार दो गुटों में बंटा हुआ था। एशिया और अफ्रीका में नए राष्ट्रों का उदय हो रहा था। हमारे सामने देश की राजनैतिक व्यवस्था को दृढ़ करने और परिवर्तन लाने की भारी समस्या थी। इसके लिए जरूरी था कि हम जहां तक हो सके बाहरी उत्पत्तियों से दूर रहें और अपने घर में दीया जलाकर मस्जिद में दीया जलाएं। हमारा लक्ष्य विश्वशांति, पराधीन राष्ट्रों की आजादी, पश्चिमी लोकतंत्रों से संबंध और साथ ही अंतरराष्ट्रीय गुटबंदी और झगडा से दूर रहने का था। यद्यपि प्रथम विश्वयुद्ध के समय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पश्चिमी राष्ट्रों का साथ दिया था और उसको सैनिक सहायता देने का समयन किया था, लेकिन दूसरे और तीसरे दशक में इस रुख में परिवर्तन हो गया। कांग्रेस ने अब खोलकर सब देशों की आजादी और आत्मनिर्णय के अधिकार का समयन किया। भारत का युवक वर्ग मार्क्सवाद और कम्युनिस्ट आंदोलन की ओर आकृष्ट हुआ। कुछ प्रमुख भारतीयों ने एशियाई देशों को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में शामिल करने का यत्न किया।<sup>१</sup> नेहरू ने एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों का नेतृत्व करने का भी प्रयत्न किया।

स्वतंत्रता के पहले के दशक में और बाद के वर्षों में भारत का रत्न, १८ वीं सदी के पुनर्जागरण और उदारता के आंदोलन से प्रभावित था। भारत का विश्व वधुत्व जा अब तब दया था अब प्रगट हो रहा था। नेहरू के दशक में भारत की स्वतंत्रता का आगमन ऐसी घड़ी थी जो ससार में कभी नहीं आती है। यह वह घड़ी थी, जब हम पुराने युग से नए युग में कदम रखते हैं, जब एक युग का अंत होता है और चिरकाल से रुद्ध राष्ट्रों की आत्मा बाल पड़ती है। परिणाम स्वरूप भारत ने विश्व और उसकी समस्याओं के प्रति एक आदर्शवाद और आशावाद का रुख अपनाया, जो ससार की वास्तविकता और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में व्याप्त अवसरवादिता और स्वाधेयता के विपरीत था।

१ इनके प्रमुख थे एन एन राव जो लेनिन के घनिष्ठ सहयोगी थे और एशिया में कम्युनिस्ट गठन के शक्ति थे। देवे-पल ए अवसरवादी थे जो मा १९३१-३२ में एशिया में शक्ति (१९३६)।

## राष्ट्रीय स्वतंत्रता

लेकिन यह भावभाव मोलला न था, न राष्ट्रीय हिता के विपरीत था। नेहरू समार की बदली हुई स्थिति को जोर लोका में ज्यादा समझते थे। उन्होंने समझा था कि द्वितीय युद्ध ने समार की व्यवस्था बदल दी है। उन्हें इसका भान था कि जिस समय उपनिवेशवाद के शिकार देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे हैं, उसी समय उनकी स्वतंत्रता को सबसे अधिक खतरा है। न केवल नए देशों में अपनी आजादी की रक्षा की शक्ति न थी, बल्कि खतरा यह था कि समार में बड़े राष्ट्रों की गुटबन्दी में पड़ कर वे उनके पुछल्ले बन जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संधि की रचना भी नए राष्ट्रा के लिहाज से सतोपजनक न थी। इसने ऐसी व्यवस्था नहीं स्थापित की जिसमें प्रत्येक राष्ट्र समान रूप से स्वतंत्र था, बल्कि इसने समार को दो ध्रेणियों में बाँट दिया, एक बड़े राष्ट्रा का वग और दूसरा उनके अनुयायियों या पीछे चलने वाला का। भारत को ऐसा लगा कि बड़े राष्ट्र (विशेषतः सबशक्तिशाली सं.रा. अमरीका) भूमध्यसागर से लेकर बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी चीन सागर तक के सारे क्षेत्रों पर हावी हो जाना चाहते हैं। इसका गहरा प्रभाव भारत पर पड़ता था।

नेहरू इसका प्रतिरोध करना चाहते थे। पर यह सैनिक ताकत के जोर से नहीं हो सकता था। यह प्रतिरोध वह वैचारिक स्तर पर करना चाहते थे। वह एक नया सिद्धांत प्रस्तुत करके, समार के जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। उन्होंने जो विद्वत्नीति प्रस्तुत की उसके तीन उद्देश्य थे — (१) उन देशों को एक हद तक स्वतंत्रता दिलाना जो बड़े राष्ट्रा का सामना करने में असमर्थ थे (इसी में उन्होंने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरोध पर जोर दिया)। (२) बड़े राष्ट्रों की शक्तिस्पर्धा में उत्पन्न गुटबन्दी को रोकना जो सं.रा. संधि व्यवस्था के कारण उत्पन्न हुई थी (इसीलिए उन्होंने फौजी गुटा का डट कर निरंतर विरोध किया)। (३) और उत्तरी अफ्रीका में लेकर इंडोनेशिया तक के भूभाग को बड़े राष्ट्रा के दबाव से मुक्त रखना (इसी उद्देश्य से उन्होंने एशियन बानफरेस बुलाई और अफ्रीका — एशिया के राष्ट्रा के सम्मेलन शुरू किए)। उनकी यह नीति अमरीका के विरुद्ध जाती थी, इसलिए अमरीका के प्रभाव को रोकने के लिए उन्होंने इस क्षेत्र में एक प्रतिकारक शक्ति के रूप में रूस के प्रवेश की कोशिश की और भारत की स्वतंत्रता कायम रखने के लिए पूव (रूस) आर पश्चिम (अमरीका) की कशमकश से लाभ उठाने की कोशिश की।

इसे ही नीति को विफल करने में नेहरू की सफलता उल्लेखनीय है। अन्तर-राष्ट्रीय नीति का इतिहास जब लिप्यक्ष होकर लिखा जाएगा, तो इसे स्वीकार किया जाएगा। उनकी वाद की विफलताओं के सामने इस सफलता को भुलाना नहीं चाहिए। नेहरू राजनैतिक स्वतंत्रता को वास्तविक राष्ट्रीय स्वायत्तता या आत्म-



निभरता में बदलना चाहत थे। यही उनका मुख्य लक्ष्य था। और तथ्य खान् पाणिक थे जैसे पड़ोस और देश में शांति रखना तथा पश्चिम और पूर्व के देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करना।

नेहरू की यह नीति ससार की स्थिति में उनकी गहरी पैठ पर आधारित थी। सबसे पहले नेहरू ने विश्व की बदली स्थिति का समझा और इस ऐतिहासिक सिद्धांत का उद्घाप किया कि, उपनिवेशवाद के दिन पूरे हो चुके हैं। नेहरू ही सबसे पहले गैर कम्युनिस्ट नेता थे जिन्होंने ससार का ध्यान सावित सभ की ठोस सफलताओं की ओर खींचा और १९२७ में ही मोवियत रूस की पहली यात्रा के बाद इस तथ्य का उन्धोप किया कि तकनीकी प्रगति के साथ सावित रूस में यह माग उठेगी कि उसकी आंतरिक नीति और व्यवस्था उदार बनायी जाए, दूसरे देशों के प्रति व्यावहारिक नीति अपनायी जाए और स० रा० अमरीका से मत किया जाए। भारत ही पहला गैरकम्युनिस्ट देश था, जिसने मोवियत नेताओं का दूसरे देशों की यात्रा करने का निमन्त्रण दिया और यह यात्रा भारत से ही शुरू हुई। बाद में पश्चिमी देशों ने भी अनुकरण किया। इस बात में तथ्य है कि रूसवोचो ने दूसरे देशों की जो यात्रा की, उसी के फलस्वरूप रूस के हल में नरमी आयी। इसी तरह दूसरा से बहुत पहले नेहरू ने इस बात को लक्ष्य किया कि मोवियत रूस और चीन के हितों में टक्कर अनिवार्य है, कम्युनिज्म से राष्ट्र बाँट ज्यादा शक्तिशाली है और कम्युनिज्म के भी कई रूप हो सकते हैं। अपनी इन्हीं धारणाओं के आधार पर नेहरू ने परस्पर विरोधी व्यवस्थाओं के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया, परमाणु शस्त्रों के निर्माण पर निमन्त्रण (यदि राक संभव न हो तो) का आग्रह किया, गुटों से अलग रहने की नीति का प्रतिपादन किया और कहा कि विकसित देश अविकसित देशों को सहायता देने में राजनैतिक शक्त न लगाए।<sup>२</sup>

### गुटों से पृथक्ता

नेहरू का कहना था कि उनकी गुटों से अलग रहने की नीति बारी सैद्धांतिक या आदर्शवादी नीति नहीं थी, बल्कि राष्ट्र के हित पर आधारित थी। भारत को पूर्वी और पश्चिमी दोनों देशों की मित्रता की दरकार थी। वह नहीं चाहता था कि उसने धरतू सामलों में बाहर से हस्तक्षेप हो और उसने यह अनुभव कर लिया था कि देश की राजनैतिक स्वायत्तता और पुनर्निर्माण के लिए जरूरी है कि बाहरी शक्तियाँ इस प्रदेश में पैर न जमाने पाए। इसी नीति के अनुसार नेहरू ने भारत के आर्थिक विकास के लिए संपन्न देशों से सहायता हासिल करने का

२ भारतीय अर्थ - नेहरू व शैक्षिक व व्यापारिक (पृष्ठ १०५०)।

यत्न किया। अपने उत्तर की दो महाशक्तियों चीन और रूस से संधि बचाया, नए देशों से मित्रता की और अंतरराष्ट्रीय परिपदा में उनकी पैरवी की।

इसी नीति के तहत भारत की स्वतंत्रता के छोड़े ही दिना बाद सन १९४८ में नेहरू ने नई दिल्ली में प्रथम एशियाई सम्मेलन किया, जिसमें हालैंड की अधीनता से इंडोनेशिया की आजादी का समर्थन किया गया। १९५५ में बाङ्गु सम्मेलन में भारत ने प्रमुख भाग लिया। १९५६ में चीन के साथ पंचशील संधि हुई। भारत ने १९५५ में स्वेज युद्ध के समय मित्र का प्रबल समर्थन किया और फ्रांस के विरुद्ध अलजीरिया का पक्ष लिया, कारिया में युद्धविराम और युद्धकदिया की बदला बदली कराने में तथा हिंद चीन और लाओस के मामले में जिनेवा सम्मेलन कराने में प्रमुख भाग लिया। कागा में गृहयुद्ध खतम करने के लिए समुक्त राष्ट्रसेना में भारतीय दस्ते भेजे। स० रा० संधि में चीन को स्थान दिलाने का निरंतर समर्थन किया। सन १९६१ में बेलग्राड में हुए गुटमुक्त देशों के सम्मेलन में भारत ने मित्र और युगोस्लाविया के साथ मिल कर सम्मेलन की गुटबंदी से बचाया।<sup>३</sup>

तुरत आजाद हुए देशों के लिए विश्व के मामलों में इतना हिस्सा लेना मामूली बात नहीं। भारत ने गुटा से अलग रहने के साथ ही साम्राज्यवादविराधी आदर्शों का सक्रिय समर्थन किया। पश्चिमी देशों के मुकाबले गुटमुक्त और समाजवादी देशों की ओर भारत का झुकाव ज्यादा रहा और उसकी भावनाओं का उसने अधिक ध्यान रखा, इसलिए उसकी नीति में कुछ दुरगमन आ गया और कुछ देशों में गलतफहमी पैदा हुई<sup>४</sup>। बाद में जब सीमाओं पर खतरा पैदा हुआ और विदेशी शक्ति का बोझ बढ़ा, तब इस नीति की कड़ी परीक्षा हुई। फिर भी भारत ने यही कोशिश की कि उसका पल्ला किसी एक गुट से न बंधने पाए। और अंत में जब नीति पर पुनर्विचार का समय आया, तब तक दुनिया की हालत बदल चुकी थी और पुरानी गुटबंदियां बहुत कुछ टूट चुकी थीं।

गुटा से अलग रहने की इस नीति से भारत को लाभ भी हुआ। इसके कारण उसे देशों का एकीकरण करने, दक्षी रियासतों को मिलाने, नेपाल, भूटान, सिक्किम आदि के साथ संबंध मजबूत करने का समय मिला। वह कश्मीर को भी रख सका और पश्चिमी राष्ट्रों की आलोचना के बावजूद १९६१ में गोआ को पुनर्गल

३ बेलग्राड सम्मेलन में इंडोनेशिया माली, गायना और क्यूबा जैसे राष्ट्र बड़ी उग्र नीति के समर्थक थे और नए रूप वाले देशों को अलग करना चाहते थे। नेहरू और कुछ अन्य लोग सम्मेलन को और व्यापक रूप देना चाहते थे और दुनिया भर के राष्ट्रों को स्थान देने के समर्थक थे। नेहरू के प्रभाव से भिन्न और युगोस्लाविया ने इस रुख का समर्थन किया और इसी की नीति हुई।

४ यह कहना पड़ेगा कि समाजवादी देशों ने शुभमुख नीति का पूरा समर्थन किया जबकि पश्चिमी राष्ट्रों का रुख उपहास और विरोध का रहा।

से मुक्त कर सका, कामनवेल्थ में भी बना रहा जो नए दशा का पक्ष समर्थन करके उनका आदर पा सका, दाना गुटा से आर्थिक सहायता पा सका और अपना फौजी खर्च कम रखकर, विवास के काम में खर्चा लगा सका। सब मिला कर इस नीति के कारण उसे देश के साधना का भण्डन करने में काफी सुभीता हुआ।

### राष्ट्रीय एकता को धुनीती

पर इस क्रम में चार कारणों से बाधा आयी। एक थी शीतयुद्ध की नीति, दूसरी चीन का प्रश्न जो अंगरेजी जमाने की विरासत थी, तीसरी कश्मीर का समस्या और चौथी आर्थिक आयोजन की समस्या।<sup>५</sup>

सबसे पहली बाधा पड़ी संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश मंत्री डेलेंस की कम्युनिस्ट शक्ति को रोकने के लिए दुनिया भर में फौजी अड्डे कायम करने के लिए फौजी संधि की नीति से। पाकिस्तान के सी. टो और सटो फौजी संधि में शामिल होने से भारत के दोना और फौजी अड्डे कायम हो गए और पाकिस्तान से खतरा पैदा हो गया।

### शीतयुद्ध की लपेट

भारत ने डेलेंस की इस नीति का और पाकिस्तान का इसके अनुरूप हथियार देने का घोर विरोध किया, पर उसकी एक न धुनी गयी। फलस्वरूप पाकिस्तान की ओर से सभावित खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत ने कई कदम उठाये। एक था फौजी तैयारी (१९५८ से पहले भारत का फौजी खर्च २०० करोड़ के आसपास रहता था, जब यह ५० प्र० स० बढ़ गया और आगे भी लगातार बढ़ता गया)। दूसरा काम था रूस से संधि बढ़ाना, इससे भारत की स्थिति मजबूत हुई आर्थिक सहायता का एक और स्रोत खुला, और कश्मीर के मामले में उसका समर्थन मिला। इससे भी महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम का काम था, चीन से सम्बन्धिता, जिसके अंतर्गत तिब्बत पर चीन का अधिकार मानना पड़ा और वहाँ भारत के विशेष अधिकार छोड़ने पड़े। हथियारों में विदेशों पर निर्भरता घटाने के लिए भारत ने अपने यहां हथियारों का निर्माण बढ़ाया। इन सबके कारण भारत को रख बदलना पड़ा। अमेरिकाने पाकिस्तान को हथियार देकर भारत के लिए जो खतरा उत्पन्न कर दिया था और इन चीन को शीतयुद्ध में लपेट दिया था, उसका वचाव करने के लिए भारत को सावियत रूस और चीन, अपने दो शक्तिशाली पड़ोसी देशों, के साथ संबंध बढ़ाना पड़ा।

<sup>५</sup> विनियमन का-रस-१ शिवा इन ट्रांजिशन प्रेंस पें-नेशन का अंक ४६, ३, अप्रैल, १९८८।

## सीमा युद्ध

दूसरी समस्या जो सबसे गंभीर है और जिसके कारण भारत का सबसे ज्यादा जिल्लन उठानी पड़ी है, उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा की समस्या है। चीन का कहना है कि यह सीमा अभी स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं हुई और वह अंग्रेजों के वक्त की साम्राज्यवादी सीमा संधियों का नहीं मानता।<sup>६</sup> शीतयुद्ध के प्रतिकार के उद्देश्य से भारत ने चीन से मित्रता की नीति अपनायी थी। परंतु एक ओर चीन का व्यवहार कुटिल था, और वह साफ साफ बात नहीं करता था, दूसरी ओर भारत की प्रवृत्ति अग्रिय या कटु यथाय से आस चुराने की थी। इसलिए दोनों में गठनफहमी बढ़ती गई।

१९५९ में तिब्बत में विद्रोह के बाद विरोध स्पष्ट हो गया। चीन से तिब्बत का सीधा रास्ता बड़ा दुगम था इसलिए उसे एक ओर रास्ते की जरूरत पड़ी (अक्साई चीन होकर लद्दाख से)। तिब्बत में चीन के अत्याचार के कारण भारत का जनमत चीन के खिलाफ हो गया था। सीमा के मामले में चीन का अब तक जो दुरगा व्यवहार रहा और जिस प्रकार उसने नक्शा में भारतीय इलाका का अपनी ओर दिखाया, उससे उसके साथ सीमा के मामले में कोई रियायत भारत की संसद की स्वीकार नहीं होती। चीन का कहना था कि तिब्बत के मामले में भारत अंग्रेजों की चाल चल रहा है। घटनाओं पर पुनर्विचार करने से अब ऐसा लगता है कि १९४४ में ही जब तिब्बत में चीन का प्रवेश हुआ था १९५०-५५ में जब चीन लद्दाख में अक्साई चीन के बदले उत्तरपूर्व में मैकमहान रेखा को मानने को तैयार था समझौता हा सकता था। लेकिन चीन ने टेढ़ी चालें चलनी शुरू कर दी, भारतीय प्रदेश को चीन के नक्शों में दिखाना, चुपके चुपके अक्साई चीन से सड़क निकालना और सीमा पर झड़प करना। भारत ने जवाबी कार्रवाई देर से शुरू की। उसने धीमे धीमे सीमा पर फाजी प्रबंध बढ़ाना शुरू किया और १९६१-६२ में लद्दाख में अग्रिम चाकिया कायम की। अप्रैल १९६० में दिल्ली में जब चाऊ एन लाई ने नेहरूजी से भेंट की, तभी उन्होंने उपर्युक्त समझौते का (अक्साई चीन के बदले मैकमहान रेखा मानने का) प्रस्ताव किया पर तब तक समय निकल चुका था। सीमा पर झड़पें हा चुकी थी और चीन ने (लद्दाख में भारत के बढ़ाव) और नेहरूजी के 'चीनिया का बाहर धकेल दो' वाले वक्तव्य से बिगड़ कर भारत पर भारी आक्रमण कर दिया। असंभव नहीं है कि मिता के दिखावे और भाईचारे के नाटक ने भी व्यावहारिक समझौते के माम में बाधा डाली।

इस अचानक आक्रमण में भारत की हार हुई और चीन से उसकी दुश्मनी हो गई। जिस प्रकार चीनी लद्दाख में विवादग्रस्त सीमा के आगे के इलाके से हट गए

६ च्यांग काइ शेक और उनकी सरकार का भी यही रुढ़ था।



## भारत-पाकिस्तान युद्ध

भारत का डर था कि अमेरिका से जो आधुनिक हथियार पाकिस्तान को मिले हैं उनका प्रयोग एक दिन भारत के विरुद्ध होगा। १९६३ में चीन और पाकिस्तान में सीमा समझौता हुआ जो भारत के विरुद्ध गठबंधन का सूचक था। यह आशका १९६४ में सत्य हुई। अप्रैल में पहली घटना हुई। पाकिस्तान ने कच्छ-सिंध सीमा पर भारत की चौकियां पर हमला किया। उसने १६ बटालियन सेना और अमेरिका से मिले टैंक तथा अमेरिका और ब्रिटेन से मिले अन्य हथियारों का प्रयोग किया।<sup>७</sup> तीस जून को ब्रिटिश प्रधान मंत्री की मध्यस्थता में युद्ध-विराम हो गया और कच्छ की सीमा का विवाद तीन जगहों की अंतरराष्ट्रीय पंचायत को सौंपने का समझौता हुआ। दोनों देशों ने इसका निणय स्वीकार करने का वचन दिया।<sup>८</sup>

पर पांच अगस्त १९६५ को कश्मीर में युद्ध विराम सीमा को पार करके पाकिस्तानी हथियारबंद उपद्रवियों ने घुस-पैठ की।<sup>९</sup> इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करके छत्र पर आक्रमण किया, इसके जवाब में भारतीय सेनाओं ने पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा के पार आक्रमण किया। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में हाजीपीर दर्रा जीर अन्य पाकिस्तानी चौकियां पर भी कब्जा कर लिया। युद्ध पचास दिन चला। पाकिस्तान ने अमेरिकन ब्रिटिश और जर्मन हथियारों और टैंकों का प्रयोग किया पर भारतीयों ने आक्रमण को पीछे धकेल दिया। भारत की स्थल और हवाई सेना ने अपने से कहीं ज्यादा अच्छे अमेरिकन विमानों और टैंकों का मुकाबला भारत में बने हथियारों और लड़ाकू विमानों से किया और उन्हें गहरी मार दी। भारतीय सेनानायकों ने युद्ध-कुशलता दिखाई और लाहौर पर आक्रमण करके पाकिस्तान को अनचिक्के में डाल दिया।

भारत के नेताओं ने भी बड़ी हिम्मत और धीरज से काम लिया। १६ सितम्बर को चीन ने अन्टीमेटम दिया कि भारत सिक्किम की सीमा पर अपनी मोर्चेबंदी तीन दिन के अंदर हटा दे वरना वह आक्रमण कर देगा। चीन ने यह भी आराप

७ प्रे. अय्यंगर ने इसे ४ मई १९६५ को स्व स्वीकार किया। घटनाओं के विवरण के लिए देखें इन्डिया १९६६ (दिसा १९६६)।

८ यह निणय घोषित हो गया और भारत ने इसे स्वीकार भी कर लिया यद्यपि दक्षिण पश्चिम द्वारा इसका घोर विरोध किया गया। पाकिस्तान ने भी इसे स्वीकारा।

९ १९४७ में कश्मीर के भारत में मिलने के प्रश्न पर पाकिस्तान से भारत का संपर्क हुआ। भारत ने इस विवाद को सारा संपर्क में ले लिया और उसकी मध्यस्थता में जन १९४९ को युद्ध विराम हुआ। युद्धविराम-रेखा या तब से दोनों देशों के बीच कश्मीर की विभाजन-रेखा हो गयी। इस विषय के सन्निवर्तन के लिए दोनों शिखर पुनः, कश्मीर पर स्थल से चला पाकि रिश्तन्त (अक्टूबर १९६६)।

और बाद में नेफा में भी हट और इसके पहले सीमा के बारे में उन्होंने प्रस्ताव दिए थे, इससे पता चलता है कि चीन का इरादा सीमित था परन्तु इस आक्रमण के बाद निवट भविष्य में किसी सम्मानजनक समझौते की आशा न रही।

इस पराजय से भारत को गहरा धक्का लगा और उसकी आर्से खुल गई। जैसा कि नेहरू ने कहा भारत अब पर्याप्त जैसा कभी नहीं हो सकता। भारत को अपनी रक्षा का प्रबंध बनाना पड़ा। १९६२-६३ में उसकी रक्षा का बजट ३०० करोड़ रुपये था जो अगले वर्षों में ८००-९०० करोड़ रुपये हो गया। अब यह १००० करोड़ रुपये है जो बुन राष्ट्रीय उत्पादन का पांच प्रतिशत होता है। यद्यपि रक्षा संबंधी व्यय से भी वारसाना के उत्पादन को कुछ प्रोत्साहन मिलता है परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि देश की दो हजार मील लंबी सीमा की रक्षा का राज से दूसरे विकास कार्यों में बाधा पड़ी है और मुद्रास्फीति हुई है। इसके अलावा देश को चीन और पाकिस्तान की ओर से हमेशा खटका लगा रहता है और देश के अंदर भी वामपंथी कम्युनिस्टों और अनेक मुस्लिम दलों पर चीन और पाकिस्तान का समर्थन होने का महसूस किया जाता है।

पर चीन के आक्रमण में लाभ भी हुआ। देश भर में दशप्रम की लहर दौड़ गई। देश की रक्षा के लिए धन और जन देन की होड़ लग गई और राष्ट्र में एकता बढ़ी। देश की परराष्ट्र नीति में वास्तविकता और व्यावहारिकता आई और रक्षा-समस्या का मजबूत करने का सक्ल किया गया। देश में सबूट की स्थिति की घाणना कर दी गई। मालिका और मजदूरों में औद्योगिक शांति रखने का समझौता हुआ जिससे कामगारों ने जोग से चल सके। रक्षा के लिए बचत की योजनाएं चालू की गई और फौजी महत्व के कारणों ने तेजी से चले गए।

बाहर भी लोकतंत्रीय और गुटा से अलग दशा में (इंडोनेशिया को छोड़कर) भारत के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। भारत का सबसे जोरो से समर्थन मित्र यूगोस्लाविया और मलाया ने किया। मलाया में लोकतंत्र रक्षा कोष खोला गया। कोनम्बो देशों ने (लका, घाना, बर्मा, इंडोनेशिया और मिथ) समझौते का प्रयत्न किया। भारत ने उनका प्रस्ताव पूरी तरह स्वीकार कर लिया, पर चीन ने केवल सिद्धांत रूप में पश्चिमी देशों ने खासकर समुक्त राज्य, ब्रिटेन और कनाडा ने भारत को तुरंत अस्त्रास्त्र की सहायता दी। इन देशों से और सोवियत रूस से भी हथियार और फौजी सहायता लेने के लिए दीर्घकालिक समझौते किए गए। अधिक सहायता की तरह फौजी सहायता भी दोनों गुटा से लेने की नीति अपनाई गई। भारत ने यह कोशिश की कि उसका विशुद्ध रूस और चीन का गुट न बनने पाए, साथ ही भारत में भी आधुनिक हथियार लड़ाकू विमान बेतार यंत्र और राडार का निर्माण तेजी से बढ़ाया गया और रक्षाउत्पादन का विभाग खोला गया। यह तैयारी १९६५ में पाकिस्तान से युद्ध के समय बहुत काम आई।

## भारत-पाकिस्तान युद्ध

भारत का डर था कि अमेरिका से जो आधुनिक हथियार पाकिस्तान को मिले हैं उनका प्रयोग एक दिन भारत के विरुद्ध होगा। १९६३ में चीन और पाकिस्तान में सीमा समझौता हुआ जो भारत के विरुद्ध गठबंधन का सूचक था। यह आशंका १९६५ में सत्य हुई। अप्रैल में पहली घटना हुई। पाकिस्तान ने कच्छ-सिंध सीमा पर भारत की चौकियां पर हमला किया। उसने १६ बटालियन सेना और अमेरिका से मिले टैंक तथा अमेरिका और ब्रिटेन से मिले अथ हथियारों का प्रयोग किया।<sup>७</sup> तीस जून को ब्रिटिश प्रधान मंत्री की मध्यस्थता में युद्ध-विराम हो गया और कच्छ की सीमा का विवाद तीन जजा की अंतरराष्ट्रीय पंचायत को सौंपने का समझौता हुआ। दोनों देशों ने इसका निणय स्वीकार करने का वचन दिया।<sup>८</sup>

पर पांच अगस्त १९६५ को कश्मीर में युद्ध विराम सीमा को पार करके पाकिस्तानी हथियारबंद उपद्रवियां ने घुस-पैठ की।<sup>९</sup> इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने अन्तरराष्ट्रीय सीमा पार करके छत्र पर आक्रमण किया, इसके जवाब में भारतीय सेनाओं ने पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा के पार आक्रमण किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी अधिभूत कश्मीर में हाजीपीर दर्रा पार कर अथ पाकिस्तानी चौकियां पर भी कब्जा कर लिया। युद्ध पचास दिन चला। पाकिस्तान ने अमेरिकन ब्रिटिश और जर्मन हथियारों और टैंकों का प्रयोग किया पर भारतीयों ने आक्रमण को पीछे धकेल दिया। भारत की स्थल और हवाई सेना ने अपने से कहीं ज्यादा अच्छे अमेरिकन विमानों और टैंकों का मुकाबला भारत में दूने हथियारों और लडाकू विमानों से किया और उन्हें गहरी मात दी। भारतीय सेनानायक ने युद्ध-कुशलता दिखाई और नाहौर पर आक्रमण करके पाकिस्तान का अनधिकृत में डाल दिया।

भारत के नेताओं ने भी बड़ी हिम्मत पार धीरज स काम लिया। १६ सितम्बर को चीन ने अन्टीमेमेट दिया कि भारत सिक्किम की सीमा पर अपनी मांचवदी तीन दिन के अंदर हटा दे वरना वह आक्रमण कर देगा। चीन ने यह भी जाराप

~~~~~

७ प्रे. अमृत गा ने इसे ४ मई १९६५ को स्वयं स्वीकार किया। घटनाओं के विवरण के लिए देखें, इण्डिया १९६६ (दिली १९६६)।

८ यह निणय घोषित हो गया और भारत ने इसे स्वीकार भी कर लिया तथापि पश्चिम पंथ द्वारा इसका घोर विरोध किया गया। पाकिस्तान ने भी इसे स्वीकारा।

९ १९४७ में कश्मीर के भारत में मिलने के प्रश्न पर पाकिस्तान से भारत का सपना हुआ। भारत ने इस विवाद को स रा सपने पेन किया और उसकी मध्यस्थता में जन १९४९ को युद्ध-विराम हुआ। युद्ध-विराम-रेखा ही तब से दोनों देशों के बीच कश्मीर की विभाजन-रेखा हो गयी। इस विषय के मॉनिटर वर्ग के लिए देखें शिशिर गुप्त कश्मीर पर क्या इन किया पाकि रिप्लेस (१९८१)।

लगाया कि भारत ने सीमा पार करके उसके कुछ नागरिक का और जानवरों का अपहरण किया है और उन्हें फौरन लौटा दिया जाये। प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने चीन की धमकी के आगे चुकने से इन्कार किया और कहा कि सीमा का समुक्त निरीक्षण कर लिया जाय। चीन की यह कोरी धमकी थी और भारत की दृढ़ता से इसकी पोल खुल गई। नई दिल्ली की जनता ने चीन के दूतावास पर जाकर उस भंडा का एक झुण्ड पेश किया पर चीनी अधिकारियों ने जैप क मार इस स्वीकार किया।

जतन म समुक्त राष्ट्र के महामंत्री ऊ चाट की वाशिंगटन और सावियत रूस के बीच म पड़ने से और ताश्कंद म पाकिस्तान के सदर अयूब खा और भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात का प्रवर्ध करने के कारण २३ सितंबर १९६५ को दोनों देशों म युद्ध-विराम हो गया। इस लेकर १० जनवरी तक ताश्कंद में यह तय हुआ कि दोनों पांच अगस्त के पक्ष की स्थिति पर वापस लौट जायेंगे, एक-दूसरे के मामले म हस्तक्षेप न करेंगे। आधिकार और दूतसम्बन्ध फिर से कायम बानचीत से हल करण और हिंसा से काम न लग। इस समझौते में रूस का मुख्य हाथ था। यद्यपि लालबहादुर शास्त्री का देहात अचानक समझौते पर दस्तखत होने के दूसरे दिन हो गया पर समझौते पर अमल किया गया और पाकिस्तानी कब्जे के कश्मीर में हाजीपीर की चौकी छोड़ने का भारत में बहुत विरोध हुआ, फिर भी भारत ने इन्हें छोड़ दिया। इसी तरह भारत ने दक्षिणपंथी दला के विरोध के बावजूद कच्छ नियंत्रण को स्वीकार किया यद्यपि यह उसका कुछ खिलाफ जाता था।

दोनों देशों की सीमाओं पर अब भी झड़पें हो जाती हैं, लेकिन स्थिति ज्यादा निगडने नहीं दी जाती। संचार और व्यापार चालू करने के बारे में बातचीत हुई है। दोनों ओर के फौजी तथा अन्य अधिकारियों में बातचीत होती है। प्रधानमंत्री न पाकिस्तानी अधिकृत इलाकों में मंगला पाघ का निर्माण पूरा होने पर सदर अयूब खा का बर्खास्त भेज कर सदभावना का हाथ बढ़ाया है। उनकी इस कारवाई की ससद में गहरी निंदा हुई, किंतु यह इस बात का इशारा है कि सरकार युद्ध विंगम रखा के आधार पर कश्मीर का वटवारा मानने को तयार है।

अंतरराष्ट्रीय स्थिति में परिवर्तन

पाकिस्तान से युद्ध में सफलता से भारत का हासला काफी बड़ा, क्योंकि अच्छे अमरीकी हथियारों और टंका के बावजूद भारत ने पाकिस्तान का पीछे ठकल लिया लेकिन युद्ध का दाम भी भारी चुकाना पड़ा। पाकिस्तान से युद्ध के कारण

न केवल देग में हिंदू-मुस्लिम तनाव बढ़ता है बल्कि इससे अंतरराष्ट्रीय पैच भी पड़ा होते हैं। इस युद्ध का प्रभाव न केवल भारत और पाकिस्तान पर ही पड़ा बल्कि अमरीका और रूस को भी अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा और कांशिंग करनी पड़ी कि भारत और पाकिस्तान का सतुलन बिगड़ने न पाए। अमेरिका ने लडाई के दौरान आर बाद में भी कुछ समय तक आर्थिक सहायता रोक दी। ताश्कंद सम्मेलन में तथा उसके बाद रूस ने भारत और पाकिस्तान के बीच ज्यादा तटस्थता का रण अपनाया ताकि दोनों देशों का सतुलन बना रहे और चीन का प्रभाव पाकिस्तान पर न बढ़ने पावे। बश्मीर और अन्य मामलों पर मोटे तौर पर और बातों का समर्थन करते हुए भी सोवियत रूस पाकिस्तान के प्रति समान रूप से मित्रता का व्यवहार कर रहा है और उसे फौजी सामान दे रहा है।

इस प्रकार १९६२ के चीन-युद्ध से भी अधिक पाकिस्तान युद्ध ने भारत को परराष्ट्र-नीति की स्वतंत्रता को घटाया जिससे देश में दोनों बड़े देशों की तरफ से विरक्ति का भाव पैदा हुआ। इससे भारत में इस भावना ने जोर पकड़ा कि हमें दुनिया के झगड़ा में दूर रहना चाहिए और युद्ध के बाद जा आर्थिक मंदी और राजनीतिक समस्याएँ उत्पन्न हुईं उनसे भी उपयुक्त मनोवृत्ति को बल मिला और भारत को अपनी स्थिति के बारे में शका हुई।

पाकिस्तान युद्ध में सफलता प्राप्त के बाद भी भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थिति बिगड़ी, यह बात नहीं। वास्तव में सत्ता की ही स्थिति बदल गयी है। शीतयुद्ध की स्थिति अब नहीं रही और दोनों महाशक्तियाँ ने 'तीसरे विश्व' (गुटों से बाहर) देशों के झगड़ा में अपना रुख बदल दिया है और स्वयं एक प्रकार की गुटों से तटस्थता अपना ली है। इस स्थिति में भारत की तटस्थता का महत्त्व नहीं रहा। जब कोई बड़ा राष्ट्र नहीं चाहता कि भारत उसके गुट में शामिल हो और सभी तटस्थता की बात करते हैं तो भारत की तटस्थता का अर्थ क्या रहा। परंतु भारत कोई दूसरी नीति नहीं निकाल पाया है।

यह बात नहीं कि भारत की बाहरी स्थिति कमजोर हुई हो। प्रत्युत उसकी फौजी और औद्योगिक शक्ति बढ़ी है, पर उसने अपने आदर्श और लक्ष्य में विश्वास खो दिया है और उसका रुख विश्व की समस्याओं में न उलझने का है। पर इसी समय भारत को विश्व — व्यवस्था के प्रति अपनी जिम्मेदारी स्वीकारने की जरूरत है। अपने क्षेत्र और विश्व के बारे में भारत की नीति सही साबित हुई है। यह नीति न केवल उसकी स्वतंत्रता का कायम रखने (आर दूसरे नए देशों द्वारा उसकी नीति की स्वीकृति) में बल्कि उस के क्षेत्र की स्वतंत्रता में भी सहायक हुई है। इसलिए उसका वर्तमान उदासीनता का रुख अस्थायी और अवास्तविक है। इस रण के दो कारण हैं, एक तो भारत को युद्ध का अनुभव न था। दोनों महा-

लगाया कि भारत ने सीमा पार करके उसके कुछ नागरिक का आर जानबग का अपहरण किया है और उन्हें फारन लाटा दिया जाये। प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने चीन की धमकी के आगे झुकने से इन्कार किया और कहा कि सीमा का समुक्त निरीक्षण कर लिया जाय। चीन की यह कोरी धमकी थी और भारत की दृढ़ता से इसकी पोल खुन गई। नई दिल्ली की जनता ने चीन के दूतावास पर जाकर उस भडा का एक बण्ड पश किया पर चीनी अधिकारिया ने बेंप व मार इमे स्वीकार न किया।

अत मे समुक्त राष्ट्र के महामंत्री ऊ थाट की काशिश् आर सावियत रूस व बीच मे पडने स और ताश्कद मे पाकिस्तान के सदर अयूब खा आर भारत व प्रधानमंत्री की मुताबात का प्रबध करने के वारण २३ सितबर १९६५ का दाना देशा मे युद्ध-विराम हा गया। इसे लेकर १० जनवरी तक ताश्कद में दाना नताजा में बातचीत हुइ आर ताश्कद समजाते पर दस्तखत हुए। इममें यह तय हुआ कि दाना पाच अगस्त के पडने की स्थिति पर वापस लौट जायेंगे, एक-दूसरे के मामले मे हस्तक्षेप न करेगे। आर्थिक आर दूतसम्बध फिर स कायम करेंगे और समुक्त राष्ट्र क घोषणापत्र के सिद्धांता के अनुसार आपसी बगडा का वातचीत से हल करेंगे आर हिंसा से काम न लेंगे। इस समझाते में रूस का मुख्य हाथ था। यद्यपि लालबहादुर शास्त्री का दहात अचानक समझात पर दस्तखत हाने के दूमरे दिन हो गया, पर समझात पर अमल किया गया आर पाकिस्तानी काने के कश्मीर में हाजीपीर की चौकी छाडने का भारत मे बहुत विरोध हुआ, फिर भी भारत ने इहे छाड दिया। इसी तरह भारत ने दक्षिणपथी दला के विराध के बावजूद कच्छ निणय को स्वीकार किया, यद्यपि यह उसके कुछ खिलाफ जाता था।

दोना देशा की सीमाआ पर अब भी झडपें हो जाती हैं, लेकिन स्थिति ज्यादा गिगडने नहीं दी जाती। संचार और व्यापार चालू करने के वार में बातचीत हुई है। दोना आर के फौजी तथा अन्य अधिकारियों में बातचीत होती है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी अधिकृत इलाके में भगला बाध का निर्माण पूरा हाने पर सदर अयूब खा का बघाई भेज कर सदभावना का हाथ बढाया है। उनकी इस कारबाई की ससद में गहरी निंदा हुई, किंतु यह इस बात का इंगारा है कि सरकार युद्ध निगम रणा के आधार पर कश्मीर का वटवारा मानने को तयार है।

अंतरराष्ट्रीय स्थिति में परिवर्तन

पाकिस्तान से युद्ध में सफलता से भारत का हासला बाफा बडा क्योंकि अच्छे अमरीकी हथियारा और टका व बावजूद भारत ने पाकिस्तान का पीछे ढकेल दिया लेकिन युद्ध का दाम भी भारा चुकाना पडा। पाकिस्तान से युद्ध के कारण

न केवल देश में हिंदूमुस्लिम तनाव बढ़ता है बल्कि इससे अंतरराष्ट्रीय पैच भी पैदा होते हैं। इस युद्ध का प्रभाव न केवल भारत और पाकिस्तान पर ही पड़ा बल्कि अमरीका और रूस को भी अपनी नीतियाँ म परिवर्तन करना पड़ा और काँग्रेस करनी पड़ी कि भारत और पाकिस्तान का सतुलन बिगड़ने न पाए। अमेरिका ने लडाई के दौरान जार बाद में भी कुछ समय तक आर्थिक सहायता रोक दी। नाइकन्द सम्मेलन में तथा उसके बाद रूस ने भारत और पाकिस्तान के बीच ज्यादा तटस्थता का रुख अपनाया ताकि दोनों देशों का सतुलन बना रहे और चीन का प्रभाव पाकिस्तान पर न बढ़ने पावे। कश्मीर जंग अथ मामला पर मोटे तौर पर और बातों का समयन करते हुए भी सोवियत रूस पाकिस्तान के प्रति समान रूप से मित्रता का व्यवहार कर रहा है और उसे फौजी सामान दे रहा है।

इस प्रकार १९६२ के चीन-युद्ध से भी अधिक पाकिस्तान युद्ध ने भारत की परराष्ट्र-नीति की स्वतंत्रता को घटाया जिससे देश में दोनों बड़े देशों की तरफ से विरक्ति का भाव पैदा हुआ। इससे भारत में इस भावना ने जार पकड़ा कि हमें दुनिया के झगडा से दूर रहना चाहिए और युद्ध के बाद जो आर्थिक मदी और राजनीतिक समस्याएँ उत्पन्न हुईं उनसे भी उपर्युक्त मनोवृत्ति को बल मिला और भारत को अपनी स्थिति के बारे में शका हुई।

पाकिस्तान युद्ध में सफलता पान के बाद भी भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थिति बिगड़ी, यह बात नहीं। वास्तव में ससार की ही स्थिति बदल गयी है। शीतयुद्ध की स्थिति अब नहीं रही और दोनों महाशक्तियाँ ने 'तीसरा विश्व' (गुटों से बाहर) देशों के झगडा में अपना रुख बदल दिया है और स्वयं एक प्रकार की गुटा से तटस्थता अपना ली है। इस स्थिति में भारत की तटस्थता का महत्व नहीं रहा। जब कोई बड़ा राष्ट्र नहीं चाहता कि भारत उसके गुट में शामिल हो और सभी तटस्थता की बात करते हैं तो भारत की तटस्थता का अर्थ क्या रहा। परंतु भारत कोई दूसरी नीति नहीं निकाल पाया है।

यह बात नहीं कि भारत की बाहरी स्थिति कमजोर हुई हो। प्रत्युत उसकी फौजी और औद्योगिक शक्ति बढ़ी है, पर उसने अपने आदर्श और लक्ष्य में विश्वास खो दिया है और उसका रुख विश्व की समस्याओं में न उलझने का है। पर इसी समय भारत को विश्व — व्यवस्था के प्रति अपनी जिम्मेदारी स्वीकारने की जरूरत है। अपने क्षेत्र और विश्व के बारे में भारत की नीति सही साबित हुई है। यह नीति न केवल उसकी स्वतंत्रता को बचाने (आर दूसरे नए देशों द्वारा उसकी नीति की स्वीकृति) में, बल्कि उस के क्षेत्र की स्वतंत्रता में भी सहायक हुई है। इसलिए उसका वर्तमान उदासीनता का रुख अस्थायी और अवास्तविक है। इस रुख के दो कारण हैं, एक तो भारत को युद्ध का अनुभव न था। दोनों महा

युद्धों की विभीषिका से बह बचा रहा, इसलिए इन दाना युद्धों में उसको गहरा मानसिक धक्का लगा। दूसरे, भारत की आर्थिक स्थिति अभी भी कमजोर है। बड़े देशों की गिनती में आने की संभावना उम्र में है, किन्तु बड़े देश का पद उसे प्राप्त नहीं, साथ ही वह छोटे देश की सुविधा नहीं भोग सकता। इस कारण उसे अपने में अविश्वास और संदेह पैदा हो गया है जो उसे बाहरी दुनिया के प्रति एक प्रभावशाली रण अपना देने में रोकता है। पर 'गोघ' हो उसका आत्मविश्वास लौटेगा।

मनिक दृष्टि में भारत ने लगातार तरक्की की है। उसकी फौजी व्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी है। और समग्रतः वह पाकिस्तान और चीन दोनों के आक्रमण का एकसाथ सामना कर सकता है। वह चाहे तो परमाणु अस्त्र भी बना सकता है। राजनैतिक दृष्टि से भी उसकी स्थिति पहले में अच्छी है। चीन सारे मसालों से और अफ्रीका के देशों से दूर होना जा रहा है। उसके गुरु समय के पक्के मित्र जर्मनी और इंडोनेशिया और प्रायः सारे अफ्रीकी देश भी उसके गिलाफ हो गए हैं। पाकिस्तान भी प्रायः पूरी तरह चीन पर निर्भर हो गया है। पाकिस्तान के भीतर भी लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि उसकी भारत विरोधी नीति से उसको ठोस लाभ नहीं हुआ और उल्टे उसकी आत्मनिर्भरता मारी गयी है।

भारत स्थिरता की शक्ति

अफ्रीकी—एशियाई देशों का भारत की नीति रीति, चीन के मुकाबले अधिक स्वीकार्य है। भारत का यही रुख है कि 'तीसरे विश्व' का सोवियत रुम और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों से सन्तुष्ट बनाए रखना चाहिए। अपनी सारी बठिनाइयों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत की आवाज समन्वयकारी की आवाज है।^{१०} उसने जिस प्रकार अपना लोकतन्त्री ढांचा कायम रखते हुए अपनी आर्थिक बठिनाइयाँ और अन्य समस्याओं का सामना किया है उससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी है। सोवियत रुम और अमेरिका की परमाणु अस्त्र नियंत्रण संधि पर दम्तस्त करने से इनकार करके उसने दिखा दिया है कि उसे दबाया नहीं जा सकता और जापान की तरह उसकी भी अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपनी राय है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

किन्तु भारत के सामने अनेक नयी बठिनाइयाँ आई हैं। एक तो यह कि भारत

^{१०} कोरिया और इन्डो-चीन में तथा बांग्लादेश में उसने शांति स्थापना में जो योग दिया उस दूसरे देश मानते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री लीन रस्किन ने स्वीकार किया कि भारत ने कई बार संयुक्त राष्ट्रों की ऐसी सेवा की है, जो हम नहीं कर सकते थे। देखें-सेमिन्ट्री ब्रैव जूनियर, 'द एशियन-रुस रिलेशंस' (न्यूयार्क १९६१)।

ऐसे प्रदेश में स्थिरता और शांति के लिए यत्न कर रहा है, जहाँ शांति की आवाज जोर पर है। सारे एशिया के देश चीन से भयभीत हैं। वह हर जगह शांति और मुक्ति के आंदोलन को उबसा रहा है। इन में भारत के सीमांत की आदिम जातियाँ भी हैं। पाकिस्तान घरेलू मामला में परिवर्तन और शांति विरोधी है, लेकिन वह कश्मीर में और संभवतः सारे भारत में गड़बड़ करना चाहता है। कहा जाता है कि यदि भारत और चीन में सीमा का विवाद न भी होता तो भी इन दोनों में संघर्ष अनिवार्य था।^{११} इसी प्रकार यह भी कहा जाता है कि यदि कश्मीर का विवाद तब भी हो जाए तो भारत और पाकिस्तान में मेल नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद ही भारत के विरोध पर है।^{१२}

साम्राज्यवाद विरोधी हाते हुए भी भारत की नीति स्थिरतावादी है। इस विरोधामास का कुछ प्रतिकार करने के लिए गुटा से तटस्थ होते हुए भी, व्यवहार में भारत ने दक्षिण एशिया में सोवियत प्रभाव की वृद्धि का समर्थन किया है। लाक्सन में आस्था रखने वाले और पश्चिम से हथियारों पर काफी निर्भर भारत के लिए रूस का समर्थन करना आसान नहीं है, खास कर चेकोस्लोवाकिया और पूर्वी यूरोप में साविएत नीति और पाकिस्तान को उससे हथियारों की मज्जाई को देखते हुए। भारत की तीसरी समस्या यह है कि वह आर्थिक विकास और जरूरी माल की सप्लाई के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। इस निर्भरता का मेल राजनैतिक स्वतंत्रता से कैसे बिठाया जाये ?

इन सब कारणों में और चीन व पाकिस्तान से समझौता न कर सकने के कारण अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत को दब कर और संभल संभल कर चलना पड़ता है। १९६६ में अरब और इसरायल के संघर्ष में उसे बाध्य होकर अरबों का पक्ष समर्थन करना पड़ा। जब कि वियतनाम में अमेरिका के युद्ध और चेकोस्लोवाकिया में रूस की फाजी कारवाँ का वह घुल कर विरोध न कर सका। वास्तव में तटस्थता की नीति अब स्पष्ट नीति के अभाव और फूँक फूँक कर कदम उठाने में ही रह गयी है। दो युद्धों से और दोना बड़े देशों से उसके संबंध में तनाव आने से जो सबक मिला है, उसको हृदयगम करने में अभी कुछ समय लगेगा। साथ ही आंतरिक स्थिति जब सुधरेगी तभी भारत का आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस बीच सब से बड़ी समस्या आर्थिक स्वावलंबन और स्वतंत्रता प्राप्त करने की है।

आर्थिक स्वतंत्रता

तभी से औद्योगीकरण के लिए मशीन और पूँजीगत माल की दरबार होनी है

११ जिओरोन- इंडिया चायना बेंड द अफ्रोएशियन 'लाक'-कंटेपोरेरी चायना, १९६७।

१२ देखिए, शिशिर गुप्त, इंडियन रिलेशंस सविथ पाकिस्तान १९४७-५७ (न दि १९५८)। शिशिर गुप्त अंतरराष्ट्रीय विषयों के प्रमुख आलोचक हैं।

और जब तक यह दश में नहीं जाने लगने तक बाहर से मगाना जाता है। इसके लिए कई उपाय करने होते हैं। जब अभावग्रस्त सामान या आयात राक कर जल्दी मानी और कच्चा माल मगाना, जो चीजें आयात हानी थी, उठ देना में बनाना, अधिन नियम कर के विदेशी मुद्रा कमजोर और आयात की अधिनता से होनेवाली विदेशी मुद्रा की कमी की पूर्ति के लिए विदेशों से ऋण और मन् लेना तथा विदेशी व्यवसायों को देश में बूझों लगाने का प्रेरित करता। भारत सरकार इन सभी उपायों से काम लिया है।

व्यापारिक घाटे की पूर्ति

आयातोंकरण के कम में बाहर से आयात जितने दान में विदेशी व्यापार का मतुान प्रतिबन्धन हुआ जाता है। भारत में आयात-नियम का यह अंतर आयातोंकरण के पहले से ही चला आ रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन में हमारा जो पौड पावना जमा हुआ था, वह खच होता जा रहा था। देश जब आजाद हुआ तो हमें अनाज और जट व कपास जैसे औद्योगिक कच्चे माल की कमी पड़ी क्योंकि देश की काफी गन्ध से उपजाऊ जमीन पाकिस्तान में चली गयी थी। दूसरी बार १९५१-५२ में कोरिया युद्ध की अवधि को छोड़ कर निर्माण में कोई बड़नी नहीं हुई थी। पहली योजना में खेती की उपज बढ़ाने पर जोर दिया गया, जिससे अन्न के आयात का खर्च घटे। इस लक्ष्य में काफी गहनता भी मिली। इसके बाद भारी उद्योगों की स्थापना पर ध्यान दिया गया। इस कारण दूसरी योजना की शुद्धता से ही मशीन, यातायात का सामान, रसायन, पानु और धातु के सामान का आयात बहुत घट गया। योजना के उत्तरार्ध में निर्यात भी कुछ बढ़ा, पर आयात और भी बढ़ गया और विदेशी विनिमय का पाटा १६५ करोड़ से बढ़ कर ४०० करोड़ रुपया हो गया।

तीसरी योजना में औद्योगिकीकरण और बड़े पैमाने पर चालू हुआ और देश में प्राविधिक क्षमता या मशीन बनाने वाली मशीनों के निर्माण का यत्न किया गया। इससे आयात और भी बढ़ा। इसी के साथ दो सान सुखा पड़ा और दो युद्ध लड़ने पड़े, जिससे उत्पादन के लक्ष्य पूरे न हो सके। कारखानों के लिए जल्दी सामान बाहर से आयात न हो सक्ने के कारण, वे पूरी क्षमता से काम न कर सके। एच और निर्यात घटा और दूसरी बार जल्दी और गैरजल्दी दोनों तरह का आयात बढ़ा। फीजी सामग्री का आयात भी बड़े पैमाने पर हुआ। जनसंख्या की वृद्धि के कारण सब तरह के माल की माग भी बढ़ी।

उपनिवेशी व्यवस्था में, अधीन दश केवल कच्चा जाग अन्न निर्मित माल बनाते हैं और तैयार माल 'ग्राहक' देश से खरीदते हैं। यद्यपि भारत जम मायासपन देश को, जहाँ औद्योगिक प्रगति की कमी न थी, अफ्रीका की तरह पूर्णतः कच्चा

माल देने वाला देश न बनाया जा सके, फिर भी यहाँ का अधिकतर निर्यात चाय, मसाला, तंबाकू, काफी, रनिज सूती वस्त्र, जूट और कायर के बने माल का था। इस प्रकार के प्राथमिक उत्पादन का निर्यात घाटे का सीढ़ा होता है क्योंकि तैयार माल बाहर से मगाना पड़ता है। साथ ही बच्चे माल का दाम भी गिरता गया है।

इसलिए भारत ने नए विस्म के इन्जीनियरी सामान मशीनी औजार, पेट्रोल पदार्थ, लोहा, इस्पात का कुछ सामान, रसायन आदि का निर्यात बढ़ाने का यत्न किया। आयात का माल भी देश में बनाने की कोशिश की गयी। मशीनी औजार, धातु का मान, रनिज इंधन और परिवहन सामान और कपास, जूट, वागज दफूती, रगई और चमड़ा कमाने की सामग्री का आयात घटा।^{१३} यह उल्लेखनीय है कि आबादी बढ़ने से माग भी बढ़ी, पर यह माग ज्यादातर देशी उत्पादन से ही पूरी हुई। अनुमान है कि चौथी योजना के अंत तक मशीनी औजार की ७५ प्र० श० माग और विशेष इस्पात और अलमुनियम की शत प्रतिशत माग देश से पूरी होगी और शायद निर्यात के लिए भी कुछ बच जाए।^{१४}

नए बाजार

विकासमान देश को अपने नए औद्योगिक माल की बिक्री में कठिनाई होती है। एक ओर उसे औद्योगिक उन्नत देशों का मुकाबला करना पड़ता है, दूसरी ओर चुगी और तटकर की बाधा का सामना करना पड़ता है। बने हुए मान की माग देश में भी काफी होती है और बाहरी आयात न होने से देशी उद्योग को संरक्षण मिल जाता है इसलिए निर्यात बढ़ाने की गरज भी कम होती है। दूसरी ओर पुराने प्राथमिक उत्पादन का निर्यात भी दूसरे अविकसित देशों के माल के मुकाबले के कारण गिर जाता है। इन सब कारणों से भारत ने अपने माल के लिए नए बाजार खोजने पर विशेषकर पूर्वी यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया अफ्रीका और दक्षिण अम

१३ १९५०-१ में ९१६ प्र श मशीनी औजार बाहर से मगाने गए थे। १९५४-६ में यह ४४५ प्र श हो गया और कुछ माल निर्यात भी होने लगा। शरकर बनाने की मशीन का आयात इसी प्रकार १०० प्र श से घटकर १४ प्र श हो गया, सूता वस्त्र मशीन का १०० से ५६५ प्र श, टंका का ३५७ से ०५ प्र श, पेट्रोल पदार्थ (किरोसीन के अलावा) ०१५ से १६ प्र श और अलमुनियम ७४८ प्र श से २९७ प्र श।

१४ धातु के मामले में आयात पर निर्भरता काफी घटा है। उदाहरण के लिए चौथा योजना के अंत तक देशी उत्पादन का उपयोग अस्ते में ५८ प्र श से बढ़कर ५३८, ब्लैक कार्बन का ५२ प्र श से ८९३ और तांबे का १२५ से २१४ प्र श हो जाने का आशा है। धातु और इन्जीनियरिंग माल का निर्यात एशिया अफ्रीका प यूरोप, रूस पूर्वी यूरोप और अमेरिकी देशों में बढ़ा है और व्यापार का अंतर कम हुआ है। सं रा अमेरिका को भी भारत निजल क तार के गेने और बच्चे तवा अन्य चार्ज भेज रहा है। स्ट्रुममैन वाकली-जन १८, फरवरी १, १९५८।

रीका को माल बेचने का विशेष प्रयत्न किया है। सोवियत संघ, युगोस्लाविया, हंगरी, चेकोस्लावाकिया, पोलंड, पूर्वी जर्मनी, अर्जेंटीना, चिली, समुक्त अरब गणराज्य, ईराक, वर्मा और जापान से जलम अलग व्यापार करार किये गये हैं। युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया आदि से सरकारी स्तर पर मापेदारी में व्यापार की योजनाएँ बनाई गयी हैं।

विदेशी और भारतीय फर्मों की साझेदारी के उद्योग भी बढ़ रहे हैं और भारतीय फर्मों ने वेनिया, तजानिया, ईरान, मलयेशिया, फिलीपीन, लका और जामरजेंड में उन देशों के व्यवसायों के साझे में उद्योग खोले हैं। अफ्रीका आदि पिछड़े देशों में भारतीय विशेषज्ञ, प्रशासन अधिकारी (नाइजीरिया पूर्वी अफ्रीका) और फौजी अधिकारी (इथियोपिया) काम कर रहे हैं। कांग्रेस में दक्षिण और वामपक्ष के विवाद के बावजूद भारत में अधिक विदेशी पूँजी लग रही है, खास कर उन उद्योगों में जो अब तक आयात पर ज्यादा निर्भर रहे हैं। साधारणतः यह पूँजी भारतीयों के साझे में लगी है।^{१५} इस प्रकार देश की आर्थिक व्यवस्था को फैलाने का और नये नये उद्योग चालू करने का यत्न किया गया है। यद्यपि इनका पूरा फल कुछ समय बाद मिलेगा।

इस बीच आधोपीकरण के लिए अभी भी बाहर से मशीन आदि का आयात जारी है। १९५०-५१ में मशीनरी का आयात कुल आयात का १४ प्रतिशत था जो १९६५-६६ में ३० प्रतिशत हो गया। पर सबसे भारी आयात अनाज का था, जो अब खेती का उत्पादन बढ़ने से कम हुआ है पर उर्वरक और खेती के लिए जलूरी और सामान का आयात भी हो रहा है। नए उद्योगों की मशीनरी और पुरानी मशीनरी को बदलने के लिए नई मशीनरी का आयात भी जरूरी है। देश में बनने वाली मशीनरी में लगने वाले विदेशी पूँजियों को घटाने की कोशिश की जा रही है, नए बाजार खोजने और नया माल निर्यात करने के साथ साथ यहाँ बनने वाले माल की क्वालिटी अच्छी रखने और उत्पादन खर्च घटाने की भी कोशिश हो रही है। नई विधियाँ निकाली जा रही हैं (जैसे आयातित धातु के बदले देशी धातु का प्रयोग)।

बिज्नी की कला में, चाहे वह अपने पक्ष का प्रचार हो, चाहे अपने माल का, भारतीय कुछ कमजोर पड़ते हैं। दूसरे, योजनाकारों ने नियामक बढाने के बजाय आयात घटाने और आत्मनिर्भर बनने पर ज्यादा जोर दिया था। मगर तीसरी

१५. विदेशी पूँजी को आकृष्ट करने में यह बाधाएँ हैं। परस्पर संदेह, भारत में विदेशी पूँजी की जोखिम का गलत प्रचार और सरकारी निर्णय में देर आदि के कारण विदेशी पूँजी निरस्त होती है। किंतु भारत की यह शर्त बिल्कुल ठीक है कि विदेशी पूँजी ५० प्रतिशत से ज्यादा न हो। देश की आर्थिक व्यवस्था पर विदेशी पूँजीपतियों का आधिपत्य स्थापित नहीं हो सकेगा, जो अनेक देशों में देखने में आता है।

योजना में विदेशी भुगतान के गहरे घाटे के कारण सरकार को निर्यात बढ़ाने पर ध्यान देना पड़ा। हर माल के लिए निर्यात सब्सिडी परिपक्व बनायी गयी, जो बाहरी वातावरण का अध्ययन करती है और माल की विस्म पर कंट्रोल रखती है। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन जैसे व्यापारिक संगठन के काम के नीवरशाही ढंग को सुधारा जा रहा है। कंट्रोल ढीले किए गए हैं। निर्यातकों को ऋण दिलाने और उनकी जोखिम की गारंटी देने का प्रबंध किया गया है, जो विदेशों में अपने माल के विज्ञापन व प्रचार के उपाय किए जा रहे हैं।^{१६}

मुद्रा का अवमूल्यन

इन सब उपायों के अलावा एक महत्वपूर्ण नीति निर्णय भी किया गया। यह था जून १९६६ में रुपये का अवमूल्यन। आशा की गई थी कि इससे निर्यात बढ़ेगा और आयात घट जाएगा। इस कदम की देश में तीव्र आलोचना की गई और कहा गया कि सरकार विदेशी दबाव के सामने झुक गयी। पर इस कारवाई का प्रत्याक्षित परिणाम नहीं निकला। कुछ इस कारण कि अभी भी हमारा ७० प्रतिशत निर्यात पुरानी प्राथमिक चीजों का था, जिनकी मांग पर दाम का अधिक असर नहीं पड़ता। दूसरे नए उद्योगों को काफी सामान आयात करना पड़ता था और इनका दाम बढ़ गया। तीसरे, अवमूल्यन का ही काफी समझ कर सरकार ने निर्यात वृद्धि की अन्य योजनाएँ खतम कर दीं। मगर सबसे बड़ा कारण यह था कि सहायता देने वाले देशों ने और विश्व बैंक ने आसान शर्तों पर सहायता देने का अपना वादा पूरा नहीं किया। इन देशों से पहले से पक्की बात नहीं कर ली गई थी। नतीजा यह हुआ कि बाहर से जरूरी सामान न मिलने के कारण उद्योगों की क्षमता बढ़ाई न जा सकी और अवमूल्यन का फायदा न उठाया जा सका।

सरकार का दावा है कि अवमूल्यन का असर हुआ है, और उन चीजों का निर्यात बढ़ रहा है जिनके बनाने में विदेशी सामान की कम जरूरत पड़ती है तथा देशी कच्चे और औद्योगिक माल की खपत बढ़ रही है। लेकिन अर्थशास्त्री इससे सहमत नहीं हैं। जो हो, अवमूल्यन का निर्णय विदेशी दबाव से और बिना उनसे सौदा पटाए जल्दीबाजी में किया गया और उसके साथ और जो कारवाइयाँ जरूरी थी, व नहीं की गयी। इसके विपरीत सी सुत्रमयम द्वारा 'नयी वृत्ति नीति' बनायी और मुस्तीदी से अमल में लाई गयी।

१६ लेकिन अभी भी निर्यात के मामले में भारत बड़ी सुर्ती और कल्पना का अभाव दिखा रहा है। पश्चिम और अमेरिका आदि सभ्य देशों में भारतीय और एशियाई माल का खपत का वेहद गुनाश है। भारत में कृषि कौशल की कमी नहीं और कोई कारण नहीं कि वह और देशों से पीछे रहे। नेहरू बैक्रेड की मांग दक्षिण कोरिया, जापान और वेनेजुएला से पूरा हो, और भारत पीछे रह जाए, यह अजीब बात है।

विदेशी सहायता

देश की राजनैतिक व्यवस्था का निमाण उतना कठिन नहीं जितना उसका आर्थिक व्यवस्था का निर्माण। राजनैतिक निमाण देश के लोग की योग्यता, चरित्रबल, सस्था निर्माण की क्षमता पर निर्भर है, जबकि आर्थिक निर्माण के साधन पिछड़े देश में दुर्लभ होते हैं और उन्हें बाहर से लेना पड़ता है। इस कारण विदेशी सहायता परराष्ट्र नीति की एक नयी शाखा बन गयी है। इसका राजनैतिक और आर्थिक प्रभाव केवल पिछड़े देशों पर ही नहीं पूरी विश्वव्यवस्था पर पड़ता है।

विदेशी सहायता से एक बड़ा प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। यह है राजनैतिक स्वतन्त्रता बनाम आर्थिक परनिर्भरता का। विकसित और अर्धविकसित, या विकासमान देशों को स्वतन्त्र और परनिर्भर, दाता और गृहीता देश भी कहा गया है।^{१७} सीधा सवाल यह है कि राजनैतिक स्वतन्त्रता का सामंजस्य आर्थिक निर्भरता से कैसे हो सकता है। विदेशी सहायता से होने वाले लाभ जाहिर हैं। इसमें अभाव की तात्कालिक समस्या में राहत मिलती है, सरकार को मौका मिलता है कि वह राजनैतिक समस्याओं पर कुछ ध्यान दे सके, सामाजिक और आर्थिक सुधारों की योजनाएँ चालू कर सके और इस प्रकार जनता को धीरे-धीरे और आश्वासन दे सके कि भविष्य में उसकी मांगें पूरी हो सकेंगी। दूसरी ओर इससे होने वाले नुकसान भी स्पष्ट हैं। इससे आर्थिक प्राथमिकताएँ गड़बड़ हो जाती हैं और बजाय उन कामों को उठाने के जो ज्यादा जरूरी हैं, वे काम शुरू कर दिये जाते हैं, जिनके लिए सहायता सुलभ होती है, बजाय मेहनत करके उत्पादन बढ़ाने के, बाहरी सहायता से काम चलाने की प्रवृत्ति पैदा होती है। इससे आर्थिक विपत्ति बढ़ती है और विशेष आर्थिक और राजनीतिक वर्गों को अधिक फायदा होता है, साधन विशेष कार्यालयों में फँस जाते हैं और नये काम करने या नीति बदलने की गुंजाइश कम हो जाती है और सबसे बड़ी बुराई यह है कि विदेशी सहायता का कभी भरोसा नहीं कि कितनी मिलेगी या न मिलेगी और उसके लिए गिड़गिड़ाता व जिल्लत उठाना पड़ता है, जिससे राजनैतिक सकट खड़े हो सकते हैं। इस तरह विदेशी सहायता से लाभ हानि दोनों हैं पर किसी भी नए देश का इसके बिना काम नहीं चलता।

भारत का भी विदेशी सहायता पर निर्भरता का कटु अनुभव हुआ है। फिर भी इसने इसे तब तक के लिए स्वीकार किया है जब तक उसकी आर्थिक व्यवस्था

^{१७} अल्बर्ट जो इशमान 'अडरदेवल्पमेंट अव्सुदेविल्स टु द प्रेसेन्स ऑफ चैन ऐन्ड अन्ट्राशिय' (डेणाल्स १९६८ पृ. २२५-२७)। इशमान स्वतन्त्र और निर्भर (परतन्त्र) शब्दों का प्रयोग करता है, जो दक्षिण अमेरिकी साहित्य से लिए गए हैं। दाता और गृहीता शब्दों के लिए दत्तें इशमान और रिचर्ड एम. बर्ग, 'फरिन एंड ड डिट्रिक एंड ड प्रोजेक्ल' (एमेरन शर् ने फादनेस न. ९९-प्रिन्सन्, १९६८)।

बनने से विकसित करने योग्य नहीं हो जाती। विदेशी अधिक सहायता लेने पर प्रायः सभी देश सहमत हैं। अतः केवल इस बात पर है कि सहायता पूर्वी नदी देशों से ली जान या बनाया जाये देशों से। और सहायता देने वाले देशों को किस हद तक उनके उनना या अन्य होने वाले कामों की देखरेख करने दिया जाय।^{१८} भारत ने विदेशी सहायता का अपनी अधिक योजना और अपनी निर्यात नीति का एक का समना। सहायता देने वाले देशों को लेख्य बना बनायी। कुछ हद तक यह अन्तरराष्ट्रीय व्यापार और विनिर्माण से प्रभावित थी तो कुछ हद तक गति युद्ध से था। कुछ हद तक अन्तराष्ट्रीय नीति से या अपनी विचारधारा का प्रभाव डालने के उद्देश्य से।

हमने देखा है कि जिस प्रकार द्वितीय विश्वयुद्ध और कोरिया युद्ध के समय भारत ने जो पाठ-पढ़ना उन दिनों या वरन् नये कारखाने खड़े करने के लिए बाह्य सहायता लेने में तब हो गया। द्वितीय योजना के समय में विदेशी मुद्रा की बहुत कमी पड़ी और बाकी बचत-मुबाहता हुआ कि किस योजनाओं को चालू करा जाय या किन्हीं छोड़ दिया जाय।^{१९} अतः यह तब हुआ कि देश में भारी बारिश के बाद मजदूरों बनाने की क्षमता स्थापित करनी चाहिए और इसके लिए ठूसु दान से जानाज उजार पर और कर्ज लेना चाहिए। यह कर्ज बाद में निर्यात बना कर चुका दिया जायेगा।^{२०} तब से हिन्दुस्तान ने परिकल्पित मात्रा में विदेशी सहायता ली है। पहली योजना में ३२२ करोड़ रुपये से बढ़ कर दूसरी योजना में यह २५३१ करोड़ और तीसरी योजना में २६३२ करोड़ रुपया हो गई। अनुमान है कि चौथी योजना में चार हजार करोड़ (नये विनिर्माण दर पर) की जरूरत पड़ेगी।

विदेशी सहायता का अधिकांश भाग भारत के सरकारी उद्योगों और प्रतिष्ठानों में गया है। पहली, दूसरी और तीसरी योजनाओं में सरकारी क्षेत्रों में विदेशी

१८ १९४८ से १९६४ तक विभिन्न देशों के प्रस्तावों के विवेचन से पता चलता है कि विदेशी सहायता का चर्चा, विदेश नाति मन्त्री काँग्रेस के केवल २ प्र. श. प्रस्तावों में है, जनता और स्वतंत्र में विद्युत् नहीं और कम्युनिस्ट पार्टी के केवल १२ प्र. श. प्रस्तावों में मुख्यतः उही मुद्दों पर चिन्तनी चर्चा उपर है। देखें, बोरन एफ. एल्वेन, 'ए पोपुलर इकनमी आफ फारेन एड द केम आफ इंडिया' (जनल ऑफ कामनवेल्थ पोपुलर स्टडीज-नं. २ स. १९६६)

१९ देखें-योजना कमीशन के 'अमेचर डेड ग्रामसेक्टर आफ द सेक्टर पारन इयर प्लान' (मई १९५८) तथा 'रिअमेचर ऑफ द फाइव ईयर प्लान-ए रिज्यूम' (जून १९५८)।

२० इस नीति के समर्थन के लिए देखें के एन राय और ए. के. सेन- 'आन्टि-इंफ्लेशन पैटर्न ऑफ ग्रोथ अन्डर कंडिशन ऑफ स्टैगनेट एक्मोड ऑर्गेनिज', आन्तर्गत ईकनामिक पेपर्स, बारह स. १, पर १९६१।

सहायता का जश क्रमश १२६, ३७ और ३६ प्र श रहा। देखिए सारणी दस १।

सारणी दस १ - विदेशी सहायता और सरकारी क्षेत्र

योजना काल	कुल खच	विदेशी सहायता	विदेशी सहायता
	करोड रु	करोड रु	कुल खच का प्रतिशत
प्रथम योजना	११६०	१६६	१२६
द्वितीय योजना	३६५०	१३५२	३७
तृतीय योजना	६३००	२४७६	३६

भारत सरकार - इकनामिक सर्वे १८६५-६६

कुछ तटस्थता की नीति के खातिर और कुछ अमरीका के बढ़ते हुए प्रभाव की राक करने के लिए विदेशी सहायता अनेक देशों से ली गई। सारणी दस २ से पता चलेगा कि पचास प्रतिशत सहायता समुक्त राज्य अमरीका से मिली है और सोवियत संघ तथा अन्य देशों तथा अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं से। जबकि पश्चिमी देशों की सहायता अनेक कार्यक्रमों में और शिक्षा आदि लोकहितकारी योजनाओं में लगी है। सोवियत सहायता इस्पात और बिजली जैसी विशेष योजनाओं में लगी। जब अमरीका ने बोकारो में इस्पात कारखाने के लिए सहायता के लिए इनकार किया तब सोवियत रूस ने इसके लिए सहायता दी।^{११}

कर्जों का बोझ

इस सहायता से जहाँ योजनाओं को पूरा करने में मदद मिली वहाँ इससे कर्ज का भारी बोझ भी बढ़ गया। सहायता गन्ध से भ्रम होता है कि यह दान है। वस्तुतः इसका अधिकतर भाग उधार सामान या रुपये के रूप में है। (देखिए सारणी दस ३) इसलिए इस कर्ज की अदायगी की रकम भी बराबर बढ़ती जा रही है। १९६०-६१ में यह निर्यात की आमदनी और विदेशी सहायता की राशि का ७८ प्रतिशत थी और १९६५-६६ में १८४ प्रतिशत तथा चौथी योजना में २८ प्रतिशत होगी। (चौथी योजना में जो विदेशी सहायता ली जायगी उसका

०१ पश्चिमी सहायता में भी प्रवृत्ति यह रही है कि अलग अलग देशों से सहायता की बातचीत के बजाय सभी पश्चिमी देशों और अन्तरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा एक सम्मिलित समझौता हो। तदनुसार 'भारत सहायता क्लब' बना जिसकी नियमित बैठक होती है और इसमें भारत की समस्याओं और पिछड़ी कारगुजारी की रोशनी में आगे सहायता देने पर विचार होता है। इसने विदेशी सहायता को एक सम्पात रूप मिला है और अलग अलग देशों से राजनैतिक मोनभाव की जरूरत कम हो गयी।

३६ प्रतिगत वज्र और सूद की अदायगी में लग जायेगा) भारत ने वज्र या सूद की अदायगी में कभी आनाकानी नहीं की। उसने केवल यही सुविधा चाही है कि सूद की दर कम रहे और अदायगी के लिए अधिक समय दिया जाय।

बहुत दिना तक विदेशी सहायता निदिष्ट कार्यक्रमों के लिए मिलती रही। इसके कारण बहुत से नये कार्य और उद्योग स्थापित हो सके लेकिन स्थापित उद्योगों के लिए कच्चा माल और बल-पुर्जों भगाने में दिक्कत पड़ती थी इस कारण जो उद्योग स्थापित हुए वे पूरी क्षमता से काम न कर पाए। फलतः निर्यात घटे पड़े मात्रा में न बढ़ सका और विदेशी मुद्रा की कमी पड़ने के कारण और विदेशी सहायता लेनी पड़ी जिससे भारत सहायता देनेवाले देशों से बंध गया। इधर दोनों ओर से इस कठिनाई का अनुभव किया गया है और विदेशी सहायता खास कार्यक्रमों के लिए बंधी न होकर भारत की जरूरतों के अनुसार खर्च करने के लिए मिल रही है।

मगर इससे एक नई समस्या खड़ी हो गई। पहले जब सहायता किसी खास कार्यक्रम के लिए दी जाती थी तो देने वाले देशों से उसी कार्यक्रम के बारे में विचार विमर्श होता था अब जो साधारण सहायता दी जाती है उसमें देश की पूरी नीति यहाँ तक कि सामाजिक और राजनतिक ढाँचे पर भी बहस होती है। १९४५ और अमेरिका दोनों ने बहुत से मामलों में हस्तक्षेप किया है। रूसिया ने बोकारो-योजना में भारतीय इंजीनियरों को शामिल करने पर एतराज किया है और रुपये के अवमूल्यन में अमेरिका और विश्व बैंक के विशेषज्ञों का हाथ भी रहा है। इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह हुई कि १९६१-६२ में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और बाद में भी अमेरिका ने विदेशी सहायता रोक दी जिससे बहुत-सी योजनाओं का काम रुक गया। आदमी और मशीनें बेकार हो गई जिससे आर्थिक मंदी और कष्ट बढ़ा। हाल में रूस ने ऐसे विमान बेचने की वाशिंग्टन की जो भारत के लिए उपयुक्त नहीं थे। इससे जाहिर होता है कि बाहरी सहायता लेने में, चाहे वह रूस से ली जाए या अमेरिका से कितना खतरा है।

सहायता का भविष्य

ऐसा जाना पड़ता है कि विदेशी सहायता के दिन बात गूँथे हैं। अब जो अमेरिका में शीतयुद्ध प्रायः बढ़ हो गया है। उन्नत देशों को भी विदेशी मुद्रा की कठिनाई पड़ रही है। उन्हें दूसरी अंतरराष्ट्रीय दिग्दर्शिका में निमानी है और उनके देशों के अन्दर यह भाव हो रही है कि वे सहायता देने के बजाय घर की समस्याओं पर ध्यान दिया करें। ऐसे दिनों में यह भावना भी है कि हम दूसरे की दृष्टि में कितना खतरा हैं।

स्याएँ सुलचनी नहीं उतनी पैदा हो जाती है और सहायता के बदले वृत्तता मिलने के बजाय बुराई और विरोध मिलता है। मुख्य बात यह थी कि विदेशी सहायता दो गुटों की स्पर्धा का परिणाम थी जो इसने द्वारा दूसरे देशों को अपनी ओर लाना चाहते थे। इन देशों में भारत मुख्य था। अब शीतयुद्ध खतम हो जाने से भारत की तटस्थता की नीति का महत्त्व कम हो गया है। भारत में भी अब यह विचार जोर पकड़ रहा है कि विदेशी सहायता से अपनी काम करने में अर्थात् आत्मनिर्भरता के प्रयत्न में बाधा पड़ती है।

अब रूस क्षेत्रीय सहयोग का है। जापान और भारत दोनों एक एशिया नीति पर चलना चाहते हैं। (यद्यपि यहाँ भी रूस सहयोग से ज्यादा स्पर्धा का है।) विदेशी व्यापारियों का उद्योग में पूँजी लगाने को प्रेरित किया जा रहा है (बिना बैंक जैसी संस्थाएँ भी उसमें योग दे रही हूँ) और देश के साधन के उपयोग पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। भारत में यह भावना भी है कि बड़े पैमाने पर विदेशी सहायता से विदेशी प्रभाव बढ़ता है। विदेशी ज़ातों की कारबाही से यह धारणा पुष्ट हुई और विदेशी संगठन के प्रति मदेह बढ़ा है। राजनीति रूप से भी अमरीका और रूस दोनों में निराशा मित्री है।

इस बीच दंग भी सतित और आधिक गति बढी है और आधिक य सामाजिक ढांचे का अनेक दिगा-या में बिस्तार हुआ है। अगले कुछ वर्षों में भी बिदेगी सहायता भी दरबार होगी किन्तु यह व्यापारिक सीमा होगा, राजनैतिक रियायत या मद नहीं।

सत्रमण थाल

अंतरराष्ट्रीय स्थिति भी बदली है। अब सवान बेबल दो गुटा का महा रहा। नए दगा का उज्जय है। रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में समथ पैदा हुए हैं। बने राष्ट्र भारत-पाकिस्तान चीन के क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। भारत की परमाणु क्षमता भी बढ़ रही है। भारत ने बड़े राष्ट्रा के दबाव के बावजूद परमाणु अस्त्र बनाने पर राक लगाने की समी पर दस्तपात करके ग इनकार कर दिया है, जब तक परमाणु अस्त्र की घमसी (विशेषकर चीन की) के सितारक पनबी गारटा न दी जाए। भारत के गामने मुख्य श्रदन यह होगा कि यह परमाणु अस्त्र बनाने या नही, उसमें दगसी दामता है। और दगसी आधिष और राजनैतिष बीमा बना दनी होगी।^{३३} भारत की सतार के बजाय थरने क्षेत्र की गारनेता हागा। जगान

[illegible]

इंडोनेशिया और आस्ट्रेलिया से समझौता करना होगा और चीन के प्रति नया रुख लेना होगा और इसी क्षेत्रीय सदम में परमाणु बम बनाने के प्रश्न पर विचार करना होगा। सबसे बड़ी जरूरत यह है कि भारत दोनों महाशक्तियों के दबाव को मना करने और उनकी इस क्षेत्र में नीति को अपने हित के लिए इस्तेमाल करने का तरीका निकाले। ऐसा न होने से इन दोनों महाशक्तियों की इस क्षेत्र में उपस्थिति—यह उपस्थिति हमारे चाहने मात्र से नहीं दूर हो सकती, भारत के लिए एक बंधन बन जाएगी।

७

भारत की भूमिका

इस समय सारे ससार में राजनैतिक और वित्तीय स्थितियाँ बदल रही हैं। इससे भारत को कुछ समय मिला है जिसमें वह अपनी राजनैतिक और आर्थिक समस्याओं को सुलझा सके। आंतरिक शक्ति बढ़ने से उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका अदा कर सकेगा। यह भूमिका स्पष्ट है और नेहरू ने इसकी परिभाषा कर दी थी। नेहरू की नीतियाँ विश्व की बदली हुई स्थिति में अनुपयुक्त हो सकती हैं किन्तु इससे भारत की भूमिका नहीं बदलती। भारत एक बड़ा देश है, विचारधारा और भूगोल दोनों दृष्टि से उसकी स्थिति महत्व की है, उसमें बड़े राष्ट्र की संभावनाएँ हैं और उसकी जिम्मेदारियाँ भी उठानी हूँ।

इस भूमिका को अदा करने के लिए औद्योगिक शक्ति और राजनैतिक स्थिरता और दृढ़ता ही नहीं, उडे पन की ओर निशानियाँ भी जरूरी हैं अर्थात् परमाणु अस्त्र और सटेललाइट या अंतरिक्ष कार्यक्रम अपने क्षेत्र में सक्रिय नीति और आत्म विश्वासी तथा निमल दृष्टि वाले नेता जो स्थिति को ठीक से समझकर उपयुक्त नीति निर्धारित कर सकें। यह स्थिति भारत की आंतरिक सफलता से प्राप्त होगी, विदेश नीति के दाव पेंचा से नहीं। यद्यपि दोनों ही क्षेत्रों में उसे कठिन कार्य करना है।

भविष्य

विभिन्न अध्यायों में हमने जो विवेचन किए हैं और निष्कर्ष निकाले हैं, उनका उपसंहार करते हुए हमें मुख्यतः इस प्रश्न का उत्तर देना है कि भविष्य की क्या संभावनाएँ हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने में हम इस बात से मदद मिल सकती है कि भारत में जिस राज्यव्यवस्था का विकास हुआ है उसने कैसा काम किया है। किंतु इस में एक कठिनाई यह है कि हो सकता है कि आगे जो समस्याएँ आए वे अब तक की समस्याओं से भिन्न हों। वास्तव में राजनैतिक व्यवस्था ज्यों ज्यों समस्या पित होती है, समस्याओं का दायरा भी उतना ही बढ़ता जाता है।

दूसरे शब्दां में इस प्रश्न को कि समस्याओं को सुलझा सकने की क्षमता व्यवस्था में बढ रही है या घट रही है इस प्रश्न से जोड़ना होगा कि समस्याएँ वही होंगी या भिन्न।

इस प्रश्न का उत्तर देने में हमें देखना होगा कि विकास का भारतीय ढाँचा कैसा रहा है। भविष्य की समस्याएँ क्या हो सकती हैं और इनका सामना करने में कौन-सी नीतियाँ कारगर हो सकती हैं।

भारतीय ढाँचा

हमने देखा है कि सदियों से भारत की पद्धति यह रही है कि यहाँ एक प्रधान राजनैतिक मता के अन्तर्गत अनेक प्रकार की व्यवस्थाएँ चलती रही हैं। इसी आधार पर आधुनिक भारत का ढाँचा खड़ा हुआ। इस प्रकार के राजनैतिक केन्द्र के विकास में विदेशी शासन, राजनैतिक विचार तथा आधुनिक शिक्षा के प्रभाव ने भी हाथ बटाया, लेकिन इसकी स्थापना तभी हुई जब देश में एक ऐसे शिक्षित नेता या अग्रणी वर्ग का उदय हुआ जो अपने को सारे भारत का प्रतिनिधि समझता था और इस सावदेशिक भावना का स्थापित करने के लिए उसने एक देशव्यापी संगठन का निर्माण किया, जिसमें हर तरह के लोग शामिल हुए। स्वतंत्रता के बाद इस राजनैतिक केन्द्र को और बल मिला। इस संविधान के द्वारा प्रतिष्ठित

किया गया और इसे हर स्तर तथा हर वर्ग में समाविष्ट किया गया। इस प्रकार भारतीय राज्य-व्यवस्था का रूप निम्नलिखित है।

तब से निरंतर विभिन्न विधियाँ, प्रक्रियाएँ और वायों से देश के विभिन्न तत्त्वों को इस प्रणाली या सर्वोपरी राजनैतिक षेड में समाविष्ट करने का यत्न किया जा रहा है। इस में समाविष्ट होने वाले विभिन्न वर्गों और तत्त्वों की अपनी विशेषता या स्वायत्तता का मिटाने की नहीं, बल्कि उनके मिलाने की कोशिश की जाती है। केन्द्रीय सत्ता को उनके ऊपर बाहरी और विजातीय सत्ता के रूप में नज़र आता नहीं जाता बल्कि यह वाणिज्य की जाती है कि विभिन्न वर्ग और लोग इस व्यवस्था में स्थान पा सकें। मुक्त या गुनी राजनीतिक व्यवस्था का भारत में यही अर्थ है। यह व्यवस्था प्रतिद्वन्द्विता और सपथ का अभाव ही नहीं है, इसमें विभिन्न वर्ग एक दूसरे से गठजोड़ कर सकते हैं और सत्ताधारी तथा प्रतिपक्षी दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन कर सकते हैं।

राजनैतिक व्यवस्था में विविध तत्वों का स्थान

हमने विस्तार से बताया है कि दलीय प्रणाली और यात्रिण सत्ताधिवार का समाज के विभिन्न स्तरों का अनुशासन करने और उनके समावेदन में क्या हाथ रहा है। इसमें शिक्षा, नगरीकरण, अखबार, रेडियो आदि प्रचार के साधन आदि से भी अधिक मदद मिली है विभिन्न वर्गों और समूहों के राजनैतिक व्यवस्था में भाग लेने से। भारतीय समाज के विभिन्न तत्वों के एकीकरण में राजनैतिक नेता वर्ग का बड़ा हाथ रहा है। इसने विभिन्न समूहों और वर्गों में समन्वित करके, उनके दावा को मान कर या आस्थापन देकर उन्हें राजनैतिक प्रक्रिया, चुनाव, शासन आदि में भाग लेने का प्रेरित किया है और इस प्रकार विभिन्न तत्वों को एक सूत्र में जोड़ा है। इस प्रक्रिया में भारतीय संविधान की व्यवस्था ने बहुत योग दिया है। संघीय शासन और दल की प्रणाली में एकीकरण और विवेकीकरण दोनों प्रक्रियाओं का काम करने की गुंजाइश है। प्रधानता या उच्च सत्ता की कल्पना केंद्रीकरण या एक तंत्र से भिन्न है और इसमें मतभेद और भिन्नता को स्थान है। भारतीय समाज के एकीकरण और आधुनिकीकरण के असंगत साधक हैं, स्थानीय या मध्यम स्तर के नेता। वे सभी प्रतिद्वन्द्वी दल और गठबंधनों में काम करते हैं। हमने अध्याय ५ और ८ में बताया है कि किस प्रकार यह नेतृत्व भारत में राजनैतिक दलों की खुली प्रणाली की मूर्ति बनता है, जिसमें सत्ताधारी और विरोधी दोनों समूह एक सामान्य वर्ग में रूपांतरित हो जाते हैं।

शासन या सत्ताधारी नेताओं ने अपनी नीतियाँ और कार्यों द्वारा राज्य व्यवस्था के प्रति विभिन्न वर्गों की निष्ठा प्राप्त करने में योग दिया है। विषमता और अन्धकार दूर करने के लिए निम्नलिखित कानून बनाये गये, गाँवों में विकास की वृद्धि

विज योजनाए चालू की गई, अनेक प्रकार की सघीय और स्थानीय स्वाशासन की मस्याएँ कायम की गयी। इस प्रकार की व्यवस्था अधिकांश मामला में स्वतः, नीचे से दबाव पडने या भाग उठाने के पहले ही की गई, पर इसका लाभ और श्रेय स्थानीय नेताओं को प्राप्त हुआ।

सरकार की इन कारवाइयो के फलस्वरूप पुराने सामाजिक वर्गों, जातियाँ और फिरका ने राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। एक नये नेता वर्ग का प्रादुर्भाव हो गया, जिन्होंने जातीय सभा, पंचायत और सहकारी संगठन पर धृष्टता करके प्रांतीय और राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कर लिया। नगरों के कुछ नेताओं को भी मिला कर इन्होंने आधुनिकतावादियों का अपदस्त कर दिया। हमने इसे आधुनिकीकरण के द्वारा आधुनिकतावादियों के अपदस्त किए जाने की प्रक्रिया की सत्ता दी है। इसी अर्थ में सत्ता शहरियों के हाथ से निकल कर गांव वालों के हाथ में गई है। इसे जनता के हाथ में शक्ति या जाना या शहर पर गांव की विजय न समझना चाहिए। वास्तव में जिन मूल्यों के पद्धतियों का प्रसार हो रहा है, वे ग्रामीण न होकर शहरी और आधुनिक ही हैं। यह प्रक्रिया भी देश के जीवन के राजनैतिकीकरण का अंग है।

भारत में ऐसा राजनैतिक ढांचा निर्मित हो सका, जिसमें देश की विभिन्न उप सभ्यताओं और अल्पसंख्यकों की जीवन-पद्धतियों का समाप्त करने की कोशिश नहीं की गयी और राजनैतिक क्षेत्र ने विभिन्नताओं में सामंजस्य करके, स्थानीय नेताओं के माध्यम से नीचे तक जड़ जमाने का यत्न किया। इस प्रक्रिया में इस बात से मदद मिली कि नए राज्य की स्थापना के पूर्व ही बुनियादी बातों पर मतभेद हो चुका था। इस मतभेद की स्थापना कांग्रेस आंदोलन द्वारा संभव हो सकी और कांग्रेस दल की रीति नीति द्वारा इसका क्रियान्वयन हुआ। भारत में समाज, मजदूर, नस्ल, भाषा आदि की जो विभिन्नता पाई जाती है और जिन्हें हम फूट और अलगाव और सक्तीयता की प्रवृत्ति समझते हैं, वे भी सहमतिक विकास और क्षेत्र की प्रधानता में सहायक हुई। नए भारत ने बहुत से लक्ष्यों को एक साथ सिद्ध करने का प्रयास किया, जैसे समाज का पुनर्गठन, आर्थिक विकास और अंतरराष्ट्रीय मामलों में सक्रिय भाग लेना। इनसे उसकी शक्तियाँ बिखर ताँ गयीं परन्तु दूसरी ओर राजनैतिक चेतना फैलने से राष्ट्र के विभिन्न वर्गों की ओर से जो भागे उठी, उन्हें संभालने में भी मदद मिली।

लोकतंत्र की भारतीय कल्पना

भारत की लोकतंत्र की कल्पना यह नहीं है कि शासक वर्ग एक अव्यवस्थित जनसमूह से शक्ति प्राप्त करे। भारत कई बातों में ऐसे सामूहिक जनराज्य से भिन्न है। साथ ही भारतीय यह भी नहीं मानते कि भारत जैसे पिछड़े देश के लिए

ऐसी मजबूत और तानाशाही सरकार ज्यादा अच्छी है, जो चुनाव और वोट की वजह से बरी हो। कुछ बुद्धिजीवी व्यक्ति ऐसे हैं जो लोकतन्त्री राजनीति की अस्थिरता से ऊपर कर मजबूत सरकार को अच्छा समझने लगते हैं। लेकिन ऐसी समसामयिक तानाशाही और मजबूत सरकारों का जो अनुभव हमें पास पड़ोस में हुआ है उससे पता चलता है कि ये सरकारें लोकतन्त्री सरकार से कम अयोग्य नहीं हैं। दूसरी तरफ, ये लोकतन्त्री सरकारों की तरह अपने का सुधार नहीं सकती। लोकतन्त्र में सरकार या शासक दल का चुनाव में हारने का डर लगा रहता है, और यह एकदम गरजिम्मेदारी और निरकुसता का रख नहीं अपना सकती। दूसरी और तानाशाही सरकार बौद्धिक वर्ग के असतोष के बल पर एक बार सत्तारूढ़ हो जाने के बाद बौद्धिकता का जामा उतार फेंकती है और निहित स्वार्थों की कठपुतली बन जाती है। फलतः जनता की स्वतन्त्रता तो मारी ही जाती है, शासन की कुशलता भी नहीं बढ़ती। घाना इंडोनेशिया और पाकिस्तान में यही देखने में आया है। नेपाल और थाई देग की राजाशाही सरकारों ने भी देश में असतोष शांत करने के लिए लोकतन्त्र की कुछ प्रणालियाँ को ग्रहण किया है। मजबूत सरकार का सबसे बड़ा नमूना चीन है। नातिकारी कम्युनिज्म को सत्थागत रूप देने में उनकी जमता को जो कष्ट उठाना पड़ रहा है वह सबविदित है। भारतीय प्रणाली, इनसे बेहतर भले ही न हो लेकिन वह इनसे खराब भी नहीं है और इनका अच्छा विकल्प प्रस्तुत करती है।

‘तीसरी दुनिया’ में दो प्रकार की नातियाँ हो रही हैं। एक वह है जिसमें एक व्यक्ति या बिचारधारा सभी विरोधों और मतभेदों का कुचल कर मारे देश को अपने ढंग पर चलाने की कोशिश करती है। दूसरा तरीका है भारत का, इसमें वर्तमान ढाँचे का बनाये रखते हुए परिवर्तन का स्वागत किया जाता है और इस प्रकार मूल व्यवस्था की संभावनाओं का विस्तार किया जाता है। इस क्रमिक नाति का नाम दिया जा सकता है। इस व्यवस्था में रचनात्मक परिवर्तनों की ज्यादा गुंजाइश होती है और यह तानाशाही या हिंसात्मक नाति से ज्यादा टिकाऊ होती है।^१

व्यवस्था की परीक्षा

इस प्रकार के लोकतन्त्री क्रमिक नाति की व्यवस्था की असली परीक्षा १९६२ और ६७ के बीच हुई। जब इसे एक के बाद एक लगातार सक्टा का सामना करना पड़ा। दो बार देग के सर्वोच्च पद के नए उत्तराधिकारियों का चुनाव हुआ। यह

^१ इस प्रकार के परिवर्तन को ‘गेमस रूल’ का नाम दिया जाता है—इसमें परिवर्तन पुरानी व्यवस्था की बनाए रखने में सहायक होता है। देख-चार्ल्स एफ हैकेट और रॉबर्ट एशर, ‘द धूमन रिवोल्यूशन’ कैरेब प्रोप्रायिटी प्रॉव, न ३, जून १९६४।

न केवल नेता या व्यक्ति का परिवर्तन था, बरन नतृत्व की शैली और उसकी शक्ति का भी परिवर्तन था। इसी के साथ दो पुरानी और महत्वपूर्ण नीतियाँ को भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये थी खेती और औद्योगिक विकास की नीति और दूसरी बापा नीति। ये दोनों नीतियाँ ठीक से कार्यान्वित न हो सकी थी और इनकी विफलता को नेमो ने अनुभव किया था। यह विफलता और गंभीर हो गयी, जब इसी के साथ देश में लगातार दो साल सूखा पड़ा, आर्थिक मंदी आई, जीवन की अनिवाय आवश्यकता की वस्तुओं के दाम बढ़े। इसके फलस्वरूप जनता में असंतोष बढ़ा विरोध और प्रदर्शन हुए और संसद पर भी घावा करने का प्रयत्न हुआ।^२ इन्हीं कठिनाइयों के दौरान देश को चीन और पाकिस्तान के आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा। पाकिस्तान युद्ध के बाद विदेशी सहायता बंद हो गयी, आयात में कठिनाई पड़ी और विदेशी शक्तियों के दबाव में आकर रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा। १९६७ में जब सूखे, अकाल और बाहरी आक्रमणों के प्रभाव से कठिनाइयाँ बढ़ रही थी, देश में आम चुनाव हुआ। इसमें कांग्रेस का एकाधिकार टूट गया और राजनैतिक अस्थिरता का युग आया। देश के नतृत्व की यह कठिन परीक्षा की घड़ी थी।

किसी भी व्यवस्था के लिए इन कठिनाइयों का सामना करना आसान न था, खाम कर एक नयी व्यवस्था के लिए जो भयानक गरीबी और पिछड़ेपन से झूझने में आकठ फंसी हुई थी। फिर भी उसने इन समस्याओं का सफलता से सामना किया। दोनों आक्रमणों का सामना किया गया। खेती और औद्योगिक विकास की नीतियाँ भी परिवर्तन किया गया। बापा के विवाद में भी समझौते से काम निकाला गया। नए प्रधान मंत्रियों का चुनाव शांतिपूर्वक हुआ। सब मिलाकर इन अभूत पूर्व संकटों का सामना करने में व्यवस्था सफल रही और उसका दुनियादी ढांचा टूटा नहीं।

इन समस्याओं पर हम विस्तारपूर्वक पिछले अध्याय में विचार कर चुके हैं। यहाँ हम नेतृत्व की शैली और राजनैतिक व्यवस्था के उन तत्त्वों का विश्लेषण करेंगे, जिनसे इन समस्याओं का मुकाबला संभव हुआ। इससे हमें इसकी कम जोरियाँ और मजबूरियों का पता चलेगा, जो भविष्य के लिए काम देगा (नीचे जो

२ ७ नवम्बर १९६६ को गौहत्या के विरोध में एक जनरल निडला, जिसमें शहर उधर के कई दल शामिल थे। इसमें ऐसे लोग भी थे जो देश में फैलते हुए अमनोप और उपद्रवों का लक्ष्य उठाना चाहते थे। इसने संसद पर आक्रमण किया। स्पष्टतः यह सवधानिक व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश थी। यह प्रयत्न विफल हुआ और प्रतिनिधियों की पोल खुल गयी। गृहमंत्री गुलनारीलाल नन्ना को साधुओं के उपद्रव को रोकने में विफलता के कारण हटना पड़ा। देखें—'कांग्रेस मिस्टम आन ट्रायल', एशिया सर्वे आठ, नं. २ पर १९६२।

कहा गया है, वह मोट तौर पर व्यवस्था की साधारण प्रवृत्तियाँ का सूचक है ।)^३

समस्याएँ अलग अलग

भारत में समस्याएँ विभिन्न क्षेत्रों को न ही एक साथ प्रभावित करती हैं, न ही उनकी तीव्रता एक जैसी होती है। यह उन समस्याओं पर भी लागू होता है, जो साथ साथ उठती हैं। अलग अलग समस्याओं पर विभिन्न राज्यों व दलों का अलग अलग रुख होता है इससे समस्याएँ एकजुट होकर खतरा पैदा करने के बजाय एक दूसरे को काट देती हैं। उदाहरण के लिए खेती और भापा सबंधी नीति के विषय में राज्यों का अलग अलग रुख था। जब केन्द्र इन दोनों समस्याओं में उलझा हुआ था उसी समय दो युद्धों और दो प्रधान मंत्रियों के सफलतापूर्वक चुनाव के कारण देश में एकता बढ़ी और केन्द्र की शक्ति भी बढ़ी। भापा के विवाद से देश की एकता को खतरा पैदा हुआ, किंतु उसी समय पाकिस्तान के आक्रमण के कारण यह विवाद गौण हो गया। इन दोनों समस्याओं में मुख्य पाना ने अलग अलग भूमिका अदा की। एक सफट दूसरे सफट से जुड़ न सका।

बदलता पक्ष

दूसरी बात यह थी कि हर समस्या या विवाद में मुख्य पक्षों की स्थिति बदलती रही। एक ही बात पर अड़ने की प्रवृत्ति न थी। हर प्रश्न को पुनः पुनः परिभाषित करने का प्रयत्न किया गया जिससे मतभेद कम होता गया। और सहमति का क्षेत्र व्यापक करने को प्रोत्साहन मिला। भापा, खेती और उत्तराधिकार (प्रधानमंत्री के) सबंधी प्रश्नों पर अलग अलग नेताओं ने मुख्य भूमिकाएँ अदा कीं। हर प्रश्न पर बातचीत के नए ढंग और समझौते के नए सूत्र निकाले गए। और जैसे ही एक सूत्र अव्यावहारिक जान पड़ा, उसे छोड़ दिया गया और दूसरा निकाला गया, जैसे भापा सबंधी विवाद में। हर बार परिस्थिति के अनुसार निणय की नई परिपाटी अपनाई गयी। जैसे प्रधानमंत्री के चुनाव में दो बार अलग अलग तरीके काम में लाए गए। इस विषय में एक रूढ़ परंपरा का न होना लाभप्रद सिद्ध हुआ। समस्या का समाधान ढूँढ़ने में मुख्य प्रश्न को प्रक्रिया सबंधी प्रश्नों से अलग करने की सद्प्रवृत्ति दीख पड़ी।

३ देखें-रजना कोठारी और थामस हेड्रिक 'राश्ट्रियम एण्ड नानराश्ट्रियम डेवलपमेंट इण्डिया १९६२-६७' (अमिनेस-मैंगर फार स्टडी आफ डेव सोसा टिया और इस्टी आफ पोलि स्ट्रान, स्टैनफोर्ड १९६९)। यह निबंध स्टैनफोर्ड युनि में मैमिफिल आमट द्वारा आयोजित राजनैतिक विकास सभा सेमिनार में पढ़ा गया था।

हठवादिता का अभाव

तीसरी बात यह है कि सौदा पटाने या बातचीत करने में कट्टरता और हठ वादिता का रूख नहीं अपनाया जाता। किसी भी विवाद या संकट के समय विरोधी और सत्तारूढ़ नेताओं में काफी भोलभाव होता है। दोनों ही पक्षों के दावा में, उनके दावा में भी जो हिमा पर उतारू हा, उनके दावा में भी कुछ भीक्ष्य होता है। सौदा करने वालों के हाथ बंधे नहीं रहते, उनके पक्ष अपरिवर्तनीय नहीं होता। मागें बढ़े और से की जाती हैं पर भीघ ही स्वर धीमा हो जाता है। मागों के ममथन में प्रदर्शन और उपद्रव भी होते हैं, लेकिन वे व्यवस्था को चुनौती का रूप नहीं लेते। साथ ही यह सादेबाजी और दबाव और उपद्रव एवं खास प्रश्न को ले कर होते हैं। अलग अलग प्रश्नों को जोड़ कर सरकार को उलटने के लिए स्थायी मोरचेबंदी नहीं की जाती। वस्तुतः मोरचे और गठबंधन टूटते और बनते रहते हैं। कहा जा सकता है कि किसी एक समय में अनेक संकट हो सकते हैं, मगर ये वास्तविक संकट का रूप नहीं ले पाते।

दलबदल

इन सभी में अतर्निहित निष्ठा में तीव्रता का अभाव है। किसी दल या मोरचे के प्रति अडिग निष्ठा की आज्ञा या भाग नहीं की जाती। हर श्रेणी के राजनैतिक नेता अपना दल या मोरचा आसानी से बदल देते हैं। विचारधारा या सिद्धांत की उपेक्षा कर दी जाती है। जहां १९६७ में कांग्रेस की शक्ति में कमी का कारण आंतरिक फूट और बहुत से लोगो का उससे अलग हो जाना था, वहां गैर-कांग्रेसी मोरचे में परस्पर विरोधी विचारों के दल भी शामिल थे। दलबदल और विरोधी विचारों के दलों के गठबंधन की त्रिया को इस बात से भी मदद मिलती है कि भारत के गांवों में रहने वाली अधिकांश जनता राजनीति से अछूती है और राजनैतिक लोगों के दावपेच से ज्यादा मतलब नहीं रखती। इस कारण यहां संकट बहुत गंभीर रूप नहीं धारण करने पाते। जनता के विभिन्न वर्गों या श्रेणियों में काफी दूरी रहती है और किसी प्रश्न पर प्रभावित हिता का संगठन करना कठिन होता है। इस प्रक्रिया में मध्यवर्ती समुन्चायकों का भी बड़ा हाथ है। इस कारण राजनैतिक व्यवस्था, सामाजिक दबाव से साधारणतः मुक्त रहती है। दूसरी ओर इस कारण यहां एकता पर बहुत जोर दिया जाता है। राजनैतिक नेता एकता की अपील करते थकते नहीं। चाहे युद्ध हो या प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी चुनना हो, या कांग्रेस के सामने संकट हो, सब में एकता की दुहाई दी जाती है और इनसे एकता की प्रवृत्ति होती भी है। इन स्थितियों में राजनैतिक व्यवस्था का वास्तविक चुनौती देना आसान नहीं। सहमति या एकरूपता के आग्रह से मांगें दब जाती हैं। संकटों से परिवर्तना और सुधारों को प्रेरणा मिलती है पर उनसे व्यवस्था के बुनियादी

ढाँचे को ओर उसकी जाधारभूत सहमति को नुकसान नहीं पहुँचाने पाता। व्यवस्था को कायम रखते हुए उसे परिवर्तित स्थितियाँ के अनुकूल बना लिया जाता है।

व्यवस्था की नुदिया

जिस प्रकार व्यवस्था सक्ता को पार कर सकी उससे भविष्य के लिए आशा वधती है। लेकिन ऊपर हमने व्यवस्था की जिन विशेषताओं को दखा, वे ही उसकी कमजोरियाँ भी साबित हो सकती हैं। व्यवस्था पर सामाजिक दबाव न होने का ही यह नतीजा हुआ कि देश के आधुनिकीकरण या नवनिर्माण की समस्या को व्यावहारिक दृष्टि से न देख कर किताबी दृष्टि से देखा गया और उसकी योजनाओं पर अमल करने में नीकरशाही ढंग से काम लिया गया। भारत के इतिहास में पूट और पूथकता की जो प्रवृत्ति रही है, उसे देखते हुए हर बात में एकता और सहमति पर अत्यधिक जोर देना उचित था, किंतु इसमें जनता के विभिन्न वर्गों से लगातार संपर्क रखने और उनकी भावनाओं को जानने समझने पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया। राजनैतिक दलों और विशिष्ट हितों की समस्याओं का मजबूत मगठन न होने का नतीजा यह हुआ कि गठबन्धन और मोरचे मजबूत नहीं होते। जनता की मांगा का दबाव कम होने का एक नतीजा यह भी है कि यहाँ समस्याओं और मतभेदों का छट कर सामना नहीं किया गया और प्रशासन तथा अर्थ क्षेत्रों में सरकार का काम ढीलाढाला रहा।

अब भारतीय राजनीति के क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, नये समूह और दल मैदान में आ रहे हैं और नए मोरचे तथा व्यूहों की संभावनाएँ पैदा हो रही हैं। इस कारण अब तक जो सामाजिक और आर्थिक सघर्ष नीचे दबे रहते थे, वे अब उभड़ कर ऊपर आएँगे और नीतियों को प्रभावित करेंगे। साथ ही जो शहरी मध्यम वर्ग अब तक राजनीति पर हावी था, वह अपदस्थ हो रहा है और उसका असंतोष बढ़ रहा है। फलस्वरूप राजनैतिक विरोध और विभिन्न वर्गों के असंतोष को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। पुराने ढंग से असंतुष्टों की व्यवस्था में स्थान देकर इस विरोध को नहीं संभाला जा सकता। अब समस्याओं और प्रश्नों पर ध्यान देना होगा। इसी के साथ इन विषयों में ठोस कारवाइ पर ध्यान देना होगा और देखना होगा कि सरकारी योजनाएँ व नीतियाँ कागज पर न धरी रह जाएँ, वरन ठीक से कार्यावित्त हों। इसके पहले कि शिकायत और समस्याएँ बढ़ कर सामाजिक मांग और आंदोलन का रूप धारण करें, उन्हें देखना होगा और ठोस कारगर कारवाइ करनी होगी।

हमने ऊपर कहा था कि भारत ने क्रमिक क्रांति का तरीका चुना है। यह तरीका हिंसक क्रांति और तानाशाही प्रतिक्रांति दोनों का विकल्प है। मगर इसकी सफलता हमेशा इस बात पर निर्भर नहीं रह सकती कि राजनैतिक विरोध बढ़ा रहे

और मार्गे उग्र न हा तथा सहमति व मर्तक्य का आग्रह पहले जैसा बना रहे। इसकी सफलता अब इस बात पर निर्भर होगी कि व्यवस्था या सरकार लगातार (रुक रुक कर नहीं) अच्छा काम करती रहे नेता बड़ी समझदारी से काम ले^४ और अब तक जा उपलब्ध हुई है, उसको नुबसान पहुँचाए बिना परिवर्तन की गति को तेज कर। भारत में स्थिरता व परंपरा को कायम रखते हुए परिवर्तन की जो प्रतिभा है उसको देखते हुए यह काम असंभव नहीं। पर इसे करने के लिए ऐसी भावना जगानी पड़ेगी और ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा, जिसमें ऐसा मालूम पड़ सकता है कि पुरानी व्यवस्था और परंपरा व स्थिरता के मूल्य नष्ट हो रहे हैं।

नए प्रश्न

भविष्य में जो समस्याएँ उठेंगी वे पुरानी समस्याओं से बिल्कुल भिन्न होंगी। इनको हल करने में अब तक जो क्षमताएँ उत्पन्न हो चुकी हैं, वे सहायक हाथी पर उनसे पूरी तरह काम न चलेगा।

पिछले अध्यायों में हमने नयी समस्याओं की ओर संकेत किया है। जैसा कि हमने देखा, कांग्रेस को मिलने वाले पक्के वोट ४० प्र० श० हैं, यह स्थिर सरकार के लिए काफी नहीं। अन्य मुख्य दलों का आधार भी ६ से ८ प्र० श० है। जब तक कि ये दल जनता में और गहरे जाने की कोशिश नहीं करते इस स्थिति में परिवर्तन होना कठिन है। कांग्रेस भी अब दो कांग्रेसों में बंट गयी है^५ एक की नेता इंदिरा गांधी हैं, यह पार्टी को सरकार के प्रभाव में रखना चाहता है, और नयी नीतियों के प्रचार का साधन बनाना चाहता है। दूसरा दल कांग्रेस के पुराने सरदारों का है जो संगठन को सर्वाधिक मानता है। कांग्रेस का यह विग्रह अन्य दलों को भी प्रभावित करेगा और संभावना यह है कि यह देश में दो प्रतिस्पर्धी गठबंधनों को जन्म देगा, जिनकी विचारधारा और कार्यक्रम भिन्न होंगे। जागे चल कर इसका परिणाम अच्छा हो सकता है, क्योंकि इससे प्रश्न और नीतियों में स्पष्टता आ सकती है और देश की शिथिलता दूर हो सकती है, पर तात्कालिक रूप से इसने सत्ताछद्म दलों के सामने अपनी सत्ता को बनाए रखने की समस्या खड़ी कर दी है। (१९७१ का मध्यवर्षीय चुनाव स्थिरता में सहायक हुआ है, इसमें इंदिरा गांधी के नेतृत्व की कांग्रेस और उसके साथी दलों की उत्प्रेक्षणीय जीत हुई है)।

४ इन मुद्दों पर मुझे अलबर्ट ओ हर्शमैन और चार्ल्स ई लिन्गमैन के साथ विमर्शों से लाभ हुआ है। ये विद्वान आर्थिक विज्ञान पर राजनैतिक और संस्थागत प्रभावों का अध्ययन करते रहे हैं। देखें-लिंडा लिन्गमैन 'इंडियन प्रास्पेक्ट्स' (मीमियो, दिस १९६७)। इन अध्यायों को लिखने में मैने गैरी आन्समन से भी विचारविमर्श किया है।

५ देखें, रजनी बोठारा, 'पोलिटिकल चेंज्स इन इंडिया दिहाशन एंड रीकन्स्ट्रक्शन', इना पेंट पोलिटी काली चार, स ४१, अक्टू ११, १९६०।

सेती के आधुनिकीकरण व वारण गावा में आर्थिक विपन्नता बढ़ी है और इस कारण वहाँ भूमिहीन व गरीब तथा गणन विमानों में सघर्ष बढ़ेगा तथा राजनैतिक रूप होगा। अब तक राजनीति से गांव वालों की अपेक्षाकृत उदासीनता के कारण सरकार की स्थिरता में जो योग मिलता है वह अब न मिल पाएगा। यद्यपि भारत में अभी बहुत दिनों तक गावा की प्रधानता रहेगी और शहर का मध्यम वर्ग अल्प संख्या में रहेगा, फिर भी जैसा नव अध्याय में संकेत किया गया है शहर और गांव के अमनुष्ट तन्त्रों में सहयोग की प्रवृत्ति बढ़ेगी।

दूसरी प्रवृत्ति शिक्षा का अभूतपूर्व प्रसार हो रहा है, किन्तु उसी अनुपात में राज-गार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं। मतोंप और स्थापित व्यवस्था के प्रति निष्ठा व प्राचीन मूल्यों का शिक्षा नष्ट भी कर देती है। परिणामस्वरूप बेरोजगार और अमनुष्ट शिक्षित युवक वर्ग विद्रोह और उपद्रव के भाग का अपना सकता है तथा प्राप्तिता और उपवादिता को बढ़ावा दे सकता है। यह प्रवृत्ति राजनैतिक दत्ता का भी प्रभावित करेगी।

राजनैतिक दत्ता में अमनुष्ट और उग्र युवजन के प्रवर्ग से उनके हस्त में महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। राष्ट्रीय मामलों में उनकी नीति ज्यादा उग्र होगी, और लक्ष्य भिन्न होंगे, इसका असर विदेश नीति पर भी पड़ेगा। हो सकता है, इस परिवर्तन से व्यवस्था के उलटने की नीयत न आए (विरोधित जब तक उस का काम मामूली रूप से अच्छा हो और राजनैतिक आचारण का स्तर गिर न जाए)। फिर भी व्यवस्था की केन्द्रीय संस्थाओं पर भीतरी और बाहरी बोझ बढ़ जाएगा। अब तक मकड़ों से व्यवस्था का सुधरने का मौका मिलता था, हो सकता है अब यह नष्ट उलट जाए क्योंकि मकड़ा से विफलता, पराजय और निराशा की भावना उत्पन्न हो सकती है और इस के फलस्वरूप हताश और दुःखी तन्त्र व्यवस्था को उलटने का, तोड़ फोड़ का, असामाजिक भाग ग्रहण करें।

व्यक्तिगत भीमासा

इन प्रवृत्तियों का एक ऐसा परिणाम हो सकता है जो मार्क्स के दृष्टान्त विमान-मिद्वान्त के विपरीत हो। मार्क्स के अनुसार दृढ़ तब उदय होगा जब उत्पादन की विधियाँ और तंत्र बदल जाएँ और राजनैतिक तंत्र उदय होगा। भारत में स्थिति उलटी है। यहाँ राजनैतिक तन्त्रों का उदय और राजनीति का कमजोर और जड़ आधार पर टिका है। तब तक कि वह विमान-मिद्वान्त के विपरीत है। किन्तु यह भी स्पष्ट है कि एकाएक आधुनिकीकरण और उदय के दृष्टान्त का प्रयोग हो जाने के साथ साथ यदि राजनैतिक व्यवस्था उदय के तन्त्रों को न बदल सके।

राजनैतिक ह्रास शुरू होने लगता है।^६ लेकिन भारत की समस्या यह है कि यहाँ जो अति आधुनिक और नए तत्वा को ग्रहण करने में सक्षम व्यवस्था निर्मित हुई है, उसी के अनुसार यदि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों का आधुनीकीकरण न हुआ, तो इस राजनैतिक व्यवस्था के टूटने का खतरा है।^७ भारत में राजनैतिक गठबन्धन टूटते और बनते रहे और सरकारें बदलती रहें, पर इसमें हो सकता है कि जनता की मुखसुविधा और सामाजिक व आर्थिक विकास में कोई वृद्धि न हो। जनता के असंतोष बढ़ने और उसका दबाव पड़ने से पहले ही यदि इनमें (जनता की भलाई और आर्थिक विकास में) वृद्धि न हुई तो व्यवस्था का टिकना असंभव हो जाएगा। हो सकता है कि जैसे-जैसे इस के सीमित साधना पर भार बढ़ने लगे, व्यवस्था की वे नुटियाँ जाहिर हो जाएँ जो अब तक छिपी थीं।

जसा कि हमने तीसरे और चौथे अध्याय में देखा भारत में बहुत से क्षेत्रों में जनता के दबाव के बिना ही प्रगतिशील नीतियाँ शुरू कीं, इससे राजनैतिक व्यवस्था को जनता का समर्थन भी प्राप्त हुआ। तब से व्यवस्था इसी पूँजी से काम चला रही है। लेकिन पिछड़ी उपबन्धियाँ पर सतोष करने से काम न चलेगा। अब फिर आगे बढ़ने, नई नीतियाँ शुरू करने, नया समर्थन प्राप्त करने और नये गठबन्धन करने की जरूरत है। निरंतर स्थिति का जायजा लेते रहने और नयी समस्याओं के लिए नई नीति और नये कदम उठाते रहने से ही व्यवस्था कायम रह पाएगी। यदि राजनैतिक स्थिरता नयी सफलता को जन्म नहीं देती और व्यवस्था नए परिणाम नहीं दिखाती, तो यह जनता का समर्थन खो देगी जो अब तक उसे प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ है। राजनैतिक व्यवस्था यदि गतिशील न रही तो इसकी जड़ता अंत में प्रतिक्रिया को जन्म देगी।

६. सैमुअल पी. हार्टिंग्टन, पोलिटिक्स आउट इन चेंजिंग सोसाइटीज़ (न्यू हवेन और लंदन १९६८)। उसने भारत को अपवाद माना है और उसकी बड़ी प्रशंसा की है - "राजनैतिक रूप से अत्यंत उन्नत देश भी अन्य बातों में पिछड़ा हो सकता है। भारत को पिछड़े देशों का नमूना समझा जाता था—किंतु राजनैतिक संस्थाकरण में भारत ने केवल एशिया अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से, बल्कि अनेक उन्नत पश्चिमी यूरोपीय देशों से भी आगे था—भारत की स्थिर, कुशल और लोकप्रणी सरकार अपनी स्वतंत्रता के प्रथम २० वर्षों में अपनी विकसित राजनैतिक संस्थाओं की विरासत पर अधिक आश्रित थी, नेहरू के चमत्कारी नेतृत्व पर कम।" ध्यान रहे कि हार्टिंग्टन भूत काल में बात करता है। मानो उसे आशा है कि १९६७ के बाद से स्थिति खराब हो रही है।

७. भारत के अर्थ-व्ययन से पता चलता है कि आर्थिक आधुनिककरण राजनैतिक संस्थाओं की उन्नति और स्थिरता में सहायक है, जबकि पिछड़ापन राजनैतिक अस्थिरता का कारण न होकर भी उसके साथ चलता है। पहला बात का उदाहरण मद्रास और दूसरी का उत्तरप्रदेश है। जेम्स-पॉल बार ग्राम, 'पोलि पार्दिमिशन, इन्स्टीट्यूशनल इवोल्यूशन एंड स्ट्रेटिजी इन इंडिया'—गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नं. १—वर्ष १९६०।

भविष्य की नीतियाँ

हमें अब भविष्य की नीतियों के मबध में भी विवेचन करना है। हम जानते हैं कि बौद्धिक (या वैज्ञानिक) विवेचन राजनैतिक नेता की सूझ और अनुभवजन्य निर्णय का स्थान नहीं ले सकता। अक्सर यह देखा गया है कि राजनैतिक कार्यकर्ता या नेता वास्तविकता के अधिक संपर्क में रहता है और लोगों की आवश्यकताओं और भावनाओं को ज्यादा समझता है।^८ फिर भी अक्सर ऐसा हुआ है कि नेता की जानकारी पुरानी पड़ जाती है और उसके निर्णय गलत निकलते हैं, और वह नई परिस्थिति का अनुमान करने में खूब जाता है। इसलिए तटस्थ आलाचक्र का विवेचन भी उपयोगी है।

सुदृढ़ राजनैतिक केन्द्र

व्यवस्था के सुचारु ढंग में चलने के लिए सुदृढ़ और कारगर केन्द्र का होना जरूरी है। यदि सत्तारूढ़ कांग्रेस को अपनी स्थिति बनाये रखना है तो इसे नए माथियों की तलाश करना है और अपने मतदाताओं की संख्या बढ़ानी है। अध्याय ८ में हमने जा विवेचन किया है उससे दो बातें स्पष्ट होती हैं — एक तो निर्वाचन क्षेत्र में अपना संगठन बढ़ाता (केवल वोट दिवाने वाला पर भरोसा न करना) और दूसरे, ऐसी नीति अपनाना, जिससे वचित और गरीब जनता आकृष्ट हो। पर १९६७ के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है, उसे देखते हुए कुछ और कदमों की भी जरूरत है। भारत में केन्द्र तभी प्रभावी हो सकता है जब वह सघीय सिद्धांत पर अमल करे, राज्यों के प्रति उचित नीति का पालन करे और राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए समान विचार वाले समूहों और दलों से हाथ मिलाने को तैयार हो। अध्याय ९ में हमने भारतीय व्यवस्था में केन्द्र और राज्यों में सहयोग के महत्त्व पर प्रकाश डाला है। केन्द्र के लिए आवश्यक है कि वह राष्ट्रीय नीतियों और समस्याओं के लिए राज्य या प्रदेश कदमों से साथ या गठ-बन्धन करने का तैयार हो। इससे सत्ता का सघम नीतियों के सघम का रूप धारण करेगा और प्रादेशिक पार्टियाँ और राज्यों की विपक्षी दलों की सरकारें केन्द्र से ऐसे मामलों में सहयोग करने को तैयार हो जाएंगी जिनका सबब एक राज्य या प्रदेश से न होकर सारे देश से हो। ऐसा होने से केन्द्र और राज्यों के बीच समझौता और लेन देन होगा और राज्यों का केन्द्रविरोधी रुख नरम हो जाएगा। ऐसा न होने से केन्द्र की सत्ता कमजोर हो जाएगी।

^८ राजनैतिक की सूझ के मुकाबले आर्थिक के निष्कर्ष का क्या भूय है इस पर विचार के लिए देखें—माइकेल ओ'कशाट—'पोलिटिकल एजुकेशन'—लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में उद्घाटन भाषण (वैत्रिज १०५१)।

राज्यों के प्रति नीति

राज्या का किन दावा पर केन्द्र से विरोध हो सकता है, इसकी काफी जानकारी उपलब्ध है और गृह मंत्रालय या मंत्रिमंडल सचिवालय में एक विशेष विभाग होना चाहिए, जो इन दावा का अध्ययन करके राज्या के प्रति उचित नीति तैयार करें। इसी के साथ ऐसी प्रणाली आर सस्थाए बनाने की जरूरत है जिससे सभी प्रमुख दला को सरकारी प्रक्रियाआ में भाग लेने का अवसर मिले। न केवल इस दावा की उपेक्षा की गयी है अपितु अक्सर अपने दल वालो के दबाव से केन्द्र ने राज्या के प्रति विरोध का रुख ग्रहण किया है, जिससे इस प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप किए गए हैं कि अमुक वामपन् या दक्षिण पक्ष सविधान की व्यवस्था की जड़ खोदने की कुचष्टा कर रह है।^१ व्यवस्था को कायम रखने की खातिर भी यह जरूरी है कि चुनाव में सफल होने वाली पार्टी को संबैधानिक तरीका से अपदस्थ करने या मत्ता से दूर रखने का प्रयत्न न किया जाए, जैसा १९५६ में केरल में आर १९६७ में बंगाल में हुआ। दल के हित का ध्यान न रखने की आशा न करते हुए भी, इतना तो कहा जा सकता है कि बिपक्षी दला की सरकार के प्रति केन्द्र न केवल काय आर ईमानदारी का बर्ताव करे वरन ऐसा प्रतीत भी हो कि ईमानदारी की जा रही है। यह आदर्श की नहा समझदारी की बात है और इसी प्रकार के द्र की शक्ति व प्रतिष्ठा बढ़ सकती है।

भारत की राजनैतिक व्यवस्था में एकात्मक शासन की प्रवृत्ति अतर्निहित है। केन्द्र की कमजारी राज्यों के दबाव के कारण न होगी, वरन उनकी उपेक्षा करने स हांगी। अब तक व्यवस्था ने निचले स्तरों पर नए कायकर्ताआ या समूहों को राजनीति में आने का मौका दिया है और इस प्रकार राजनैतिक ढांचे का विस्तार हाता रहा है। इससे भी बड़ा और कठिन काय है, विरोधी तत्त्वा का व्यवस्था में विभिन्न स्तरों पर स्थान देना। ये विरोधी तत्त्व केन्द्र और राज्या में कांग्रेस व विरोधी गुटा से लेकर 'नक्सली' और दक्षिणपन्ी सप्रदायवादी हैं। भारत की सघीय या सबदल व्यवस्था में, इनको स्थान देने की जितनी शक्ति होगी उतना ही इनस खतरा कम होगा। भारत की ऋमिक विकास पद्धति की यही असनी कसौटी है।

इसके लिये ऐसे राजनैतिक केन्द्र की आवश्यकता है जिस प्रदेशों में समयन प्राप्त हो। १९६७ से इस केन्द्र पर दबाव बढ़ता रहा है। कांग्रेस के अंतर्विरोध स यह नाभ हुआ कि उससे नीतिया के स्पष्ट होने का मौका मिला, पर केन्द्र या

१. इसी कारण मार्क्स कम्युनिस्टों ने अपने चुनाव कार्यक्रम में केन्द्र-राज्य संबंध के प्रश्न को भी शामिल किया है। कोई कारण नहीं कि यह समस्या व्यक्तिगत बातचीत और मेनमेन से हल न हो सके। १९६७ के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गैर-कॉमेनी मुख्य मंत्रियों को सहयोग का आश्वासन दिया था। यह प्रस्ताव कुछ ठंडा पड़ गया है, इसे जारी रखना चाहिए।

सर्वाच्च स्तर पर इस प्रकार का विरोध अधिक दिना तक चलता रह तो उससे अनिश्चितता पैदा हो जाती है। इसका सबसे अच्छा उपाय है, समान विचार के या निष्ठा के गुटा व दलो का गठबधन। इससे सरकार में स्थिरता आती है और महत्वपूर्ण नियम करने और उनको लागू करने की शक्ति प्राप्त होती है। लाकतनी राजनीति सबन यही गठबधन की नीति है। इसमें कठिनाइया भी आती है। एक तो गठबधन के नेताओं का मिल कर 'टीम' की तरह काम करना, दूसर, इस टीम पर विभिन्न स्तरों और वर्गों से दबाव को समालना। ये कठिनाइया स्वाभाविक हैं और यदि सामूहिक नेतृत्व या टीम की भावना कायम रही, तो दूसरी कठिनाई भी सभल जाती है। इस प्रकार प्रदेशों का मिला कर चलने के लिए एक प्रभावशाली केन्द्र का होना आवश्यक है।

सामाजिक एकीकरण

यही बात सामाजिक एकीकरण पर भी लागू होती है। भारतीय राजनीति की एक कठिन समस्या जो लोकतन्त्र के विस्तार के साथ-साथ और कठिन होती जायेगी, अल्पसंख्यक संप्रदायों की विशेषतः मुसलमानों की समस्या है, कि वे बराबरी के दर्जे पर सक्रिय नागरिक के रूप में देश की राजनीति में स्थान ग्रहण करें। गांवों के मुकाबले शहरों में यह समस्या ज्यादा कठिन होती है। जैसा हमने अध्याय ४ में देखा मुसलमानों में आत्मविश्वास बढ़ा है और उन्होंने अपना राजनैतिक संगठन करना शुरू किया है। पर इसके प्रतिक्रियास्वरूप साम्प्रदायिक तनाव और संघर्ष भी बढ़े हैं। जनसंघ से लेकर कम्युनिस्ट और कांग्रेस के एक वर्ग ने भी इसका लाभ उठाने की कोशिश की है। एक तो अभी मुसलमान स्वयं अपनी स्थिति निश्चित नहीं कर पाए हैं, दूसरे पाकिस्तान का भी उनके ऊपर खिचाव पड़ता है। इस स्थिति से राजनैतिक उलझन हुई है। स्थानीय असंतुष्ट और उपद्रवी गुटों के अलावा कुछ राजनैतिक गुट ऐसे भी हैं, जो राष्ट्रीय एकता का भंग करने और केन्द्र को कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी हालत में अल्पसंख्यकों की समस्या का भावधानी से अध्ययन करना, नौकरी आदि के मामले में उनकी उचित शिकायतों को दूर करना और राष्ट्रीय हित के लिए उनका सहयोग प्राप्त करना वांछनीय है।

देश में जो और बुनियादी प्रवृत्तियाँ चालू हैं उनको ओर ध्यान देना और उनके संबन्ध में उचित नीतियों को तैयार करना भी जरूरी है। ये प्रवृत्तियाँ जनसंख्या के वितरण, शहरों और गांवों के विकास, युवा वर्ग के उपयोग, आर्थिक नीति और विदेश नीति और विदेशी आर्थिक नीति सबंधी हैं।

देश की जनसंख्या के नगरों और गांवों में वितरण के संबन्ध में सावधानी से एक निश्चित नीति बनाना जरूरी है। भारत में गांवों की वर्तमान प्रधानता का बनाव

रखते हुए, आधुनिक साधनों से उनकी उन्नति करनी चाहिए और इस प्रकार उनके जरिये देश का तेजी से आधुनिकीकरण करना चाहिए। इसी के साथ साथ महा नगरा और नगरो का ऐसा विकास करना चाहिए कि वे आधुनिकीकरण और प्रगति के केंद्र बन जाए। आधुनिकीकरण के बारे में कुछ लोगो की धारणाओं के प्रति कूल औद्योगिक समाज से उन्नतिशील और संपन्न ग्राम व्यवस्था का कोई विराघ नहीं है। बल्कि ऐसे ग्राम औद्योगिक व्यवस्था के सुदृढ आधार हो सकते हैं। १८ वीं और १९ वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यूरोप में नगरो में अफ्रीका की भीड़भाड़ हो गयी और उसमें उनकी जो दुदगा और आर्थिक शोषण हुआ, जो परिणामस्वरूप जो उथल पुथल हुई, उसे यहा बचाया जा सकता है, और सरकार को उपलब्ध आधुनिक साधनों से नगरा का ऐसा आयोजन किया जा सकता है जिससे देश की शक्ति बढ़े। अगले दो दशको में भारत में जनसंख्या के वितरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। यह हमारे ऊपर है कि हम इनको ठीक दिशा में ले जाए या इन्हें अपना खतरनाक रास्ता पकड़ने दें।

गावों का ढांचा

खेती में जो क्रांति हुई है उससे एक प्रश्न यह उठता है कि क्या अग्रगामी ढांचाको से पिछड़े इलाका में इस क्रांति का प्रसार हो रहा है? दूसरा प्रश्न सामाजिक न्याय का है। क्या विकास के इन कार्यक्रमों से गावों के सभी लोगो का, भले ही कम या ज्यादा फायदा पहुंच रहा है? जहा ज्यादा और जल्दी नतीजा निकलने की संभावना हो, ऐसे क्षेत्रों में भरपूर खेती के साधन जुटाने की नीति में परिवर्तन न करत हुए भी, ऐसी कागवाई करनी चाहिए कि गावों में विपत्तियां और सघप घटे। छोटे किसानों को बड़े किसानों से कुछ ज्यादा बढ़ावा और साधन देने की नीति अपनाई जानी चाहिए और वितरण की ऐसी नीति चालू करनी चाहिये, जिससे बहुसंख्यक भूमिहीन, मजदूरी करने वाला और अधबेकारों को लाभ हो। समाज के गरीब वर्गों पर विकास का क्या बोझ पड़ता है इस ओर ध्यान न देने और सरकारी नीति पर संपन्न वर्गों का प्रभाव होने से अन्य देशों में घटा जनविद्रोह और आंदोलन हुए हैं। क्रमिक विकास की नीति पर काम चलत हुए भी सरकार को समय रहते इस ओर ध्यान देना चाहिए। चलता अनेक तलपाना और नकमलवाडिया सामने आयेगी,^{१०} गावा में दुध और बचित वर्गों की भीड़ गहरा

१० स्वतंत्रता के तुरंत बाद अर्थ के तेलपाना होने में कम्युनिस्टों के नेतृत्व में सशस्त्र विद्रोह हुआ था। इसे दबा दिया गया। वर्तमान तेलपाना आर्थिक से अर्थ का कोई संबंध नहीं। इस प्रकार १९६७ में वामपंथी मोरचे की विजय के बाद पश्चिम बंगाल के अत्यंत उग्रवादी कम्युनिस्टों ने नक्सलवादी में भूमिहीनों के ऊपर धनी जोगेदारों की ज़्यादती से उत्तराग्र शोष का काम उठा कर सशस्त्र विद्रोह कर दिया। इसे मृत्यु मोरचा सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की मदद से दबा दिया।

में आएगी और सामूहिक हिंसा की संभावना बढ़ेगी ।

नगरों का विकास

नगरों का विकास भारतीय आयोजन का सबसे उपमित अंग रहा है । कांग्रेस के ऊपर शुरू से ग्राम विकास का आदर्श हावी रहा है और उसे गाँवों के बंटो की भी चिन्ता रही है, इस कारण शहरों की निरंतर विगड़ती हुई हालत पर वह ध्यान नहीं दे सकी । यह सही है कि गाँवों के मुकाबले शहरों जनसंख्या बहुत थोड़ी है फिर भी यह कम नहीं । दूसरे शहर राजनीतिक गतिविधि के केंद्र हैं । गाँवों के संगठना और जातीय संघों के मुख्य केंद्र शहरों में ही होते हैं । प्रादेशिक पार्टियों के मुख्यालय भी यहीं होते हैं । यहाँ थोड़ी संख्या के आदान-प्रदान भी बड़ा उग्र रूप और शक्ति प्राप्त कर लेते हैं (जैसे बर्बई में गिबमोना) । यह सर्वविदित है कि बलवत्ता में केंद्रीय सरकार के विरोध का सबसे बड़ा कारण वहाँ की भयानक समस्याओं की लगातार उपस्थिति है । इधर छोटे नगरों में जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, उनमें भी बहुत कुछ हाथ उनकी गिरती हुई आर्थिक स्थिति और कामकाज के अवसरों का अभाव है ।

पहले तो जरूरत शहरों के गरीब तबकों की दवा मुधारने की है-निम्न मध्यम वर्ग गरीब घरों के विद्यार्थी, अनुसूचित जाति के लोग और बालकों के मजदूरों के अलावा अन्य प्रकार के मेहनत मजदूरी करने वाले । इसका भार शहरों के अधिक संपन्न वर्गों पर पड़ना चाहिए । दूसरी जरूरत नगरों की स्वशासन संस्थाओं को बड़ावा देने की है । इन संस्थाओं को विशेषकर बड़े नगरों की संस्थाओं को राज्य सरकारों से स्वायत्तता मिलनी चाहिए और योजना के साधनों में सीधा भाग मिलना चाहिए । नगरों संस्कृति का विकास तभी हो सकता है जब नगर निवासियों का जीवन की सुविधा हो और उनमें अपने नगर के प्रति प्रेम और गौरव का भाव हो । ऐसी नगर संस्कृति राष्ट्र की उन्नति में महत्वपूर्ण योग दे सकती है ।

शिक्षण

भारत के कालेजा व विश्वविद्यालयों की हालत देखकर बड़ी निराशा होती है । उनमें विद्यार्थियों की भीड़, पढ़ाई, खेल-कूद चरित्रगठन के साधनों का घोर अभाव, घटिया और मुर्दाबिंद शिक्षक और दक्षिणानसी पाठ्यक्रम और पढ़ाई का नीचा स्तर । शिक्षा कमीशन की भारी भरकम रिपोर्ट को अनग-अनग भागों में बांट कर एक-एक सिफारिश पर कार्रवाई करनी चाहिए । इसी से संबंधित विषय स्कूलों और कालेजों से निकलने वाले विद्यार्थियों का है (अध्याय नौ) । वास्तविकी की पड़ताल से पता होता है कि साधारणतया नया शिक्षार्थी वर्ग उत्साह और आकांक्षा से परिपूर्ण होता है । पास कर गरीब विद्यार्थी । परंतु उसके इस उत्साह और आकांक्षा

का जब कोई दिना नहीं मिलती तब वह हाथ गोर अगामाजित कारवाया में लग जाता है। वेन्द्र में एक गिन्ना और युवा सेवा भण्डालय मौजूद है किन्तु युवाओं की सेवा या उनकी शक्ति के उपयोग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। देश के हित में आवश्यक है कि युवाओं के उत्साह, समझता और प्रतिभा का उपयोग किया जाए। उनमें राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर मन मिलेगा।

आर्थिक विकास

मुख्य बात यह ध्यान रखने की है कि भारत की राजनैतिक व्यवस्था के भाग्य का निर्णय कारगराना और गेता में होगा। यह इस बात पर भी निर्भर है कि उसकी आर्थिक नीति के निर्माता राजनैतिक प्रश्नों को कितना समझते हैं।

मुख्य प्रश्न ये हैं — (१) आधुनिक टेक्नीक का किम तरह उपयोग करना कि गाँव और शहरों में एक-सा ढाँचा बना रहे। (२) आर्थिक योजनाओं के जरिये किस प्रकार अधिक से अधिक रोजगार बढ़ाया जाये। (३) शिक्षा के प्रसार के साथ साथ रोजगार के अवसर किम प्रकार बढ़ाए जाए। (४) आर्थिक विकास से गाँव और शहरों में जो विषमता उत्पन्न होती है उसे कैसे रोका जाए। (५) माधनता का किस प्रकार सचय और प्रयोग किया जाए जिससे ये राजनैतिक उद्देश्य सिद्ध हों।

इन प्रश्नों का बिना बिलंब दूरदर्शिता से मुलजाना चाहिए। भारत के अर्थव्यवस्था और आर्थिक प्रशासक समार में किसी से कम नहीं। शोध और जानकारी प्राप्त करने का उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयत्न किया है, और विकास काय के प्राविधिक ज्ञान का प्रयोग करने के लिए काफी कारगर कदम उठाये गये हैं। बस सिर्फ इस बात की है कि समस्याओं के उठने के बाद उनका उपाय करने के बजाय पहले से सावधि विचार कर लये या दीर्घकालिक विकास की नीति बनायी जाए। साथ ही इन समस्याओं का प्रशासन तंत्र के भरोसे न छोड़ दिया जाए। जब जल्दीबाजी में चालू ढंग का काम होता है तब जफमरा के भरोसे काम छानने की प्रवृत्ति और अधिक रहती है और सोचने या नए उपाय करने का कष्ट नहीं उठाया जाता। इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हर मुख्य योजना या प्रस्ताव की इस दृष्टि से परीक्षा की जाये कि पूरी व्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। योजना कमिशन के पसपेक्टिव प्लानिंग विभाग में या प्रधानमन्त्री के सचिवालय में इसके लिए एक राजनैतिक टुकड़ी होनी चाहिए। इसका जघनम आर्थिक विकास के राजनैतिक पक्ष का विशेषज्ञ होना अच्छा है।

विशेष वर्ग

एक तरीका यह हो सकता है कि जनमस्या के विशेष वर्गों के लिए विशेष योजनाएँ बनायी जाएं—जैसे शिक्षित युवा और शिक्षित बेरोजगार, शहरों का निम्न

मध्यम वर्ग, छोटे और भूमिहीन किसान, अनुसूचित और अल्पछाटी जातियाँ, आदिवासी और अल्पसंख्यक संप्रदाय। आर्थिक विकास से इन वर्गों पर विशेष दबाव पड़ता है, इनकी विशेष समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जिनसे असंतोष और विरोध बढ़ता है। इसलिए इन वर्गों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

गंभीर नुस्खा

देश के विकास की समस्याओं में शिक्षा और सावजनिक प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इन दोनों का ह्रास हो रहा है। सब से बुरा हाल है शिक्षा का। प्रायः हर स्तर पर और हर प्रदेश में दकियानुमी पाठ्यक्रम, अशिक्षित अध्यापक, घोर कुव्यवस्था और कल्पनाशून्य नीति है जो हर नयी बात का विरोध करती है। सुधार के उपाय भी सुजात हैं। शिक्षा बर्मीशन की रिपोर्ट में बहुत सी सिफारिशें हैं, मगर इनको कार्यान्वित करने का कोई ज़रिया नहीं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय नौकरशाही और अयोग्यता का नमूना है। विश्वविद्यालयों की हालत भी बुरी है। इनके ऊपर शिक्षा अनुदान आयोग की नौकरशाही हावी है। उत्तम अध्ययन का नमूना के रूप में जो अग्रतर शिक्षा केंद्र खोले गये थे वे भी विश्वविद्यालय के पिछड़े हुए विभागों के ही विस्तार—में हैं। स्कूली शिक्षा की हालत तो कहने लायक नहीं। इसमें तो आमूल परिवर्तन होना चाहिए। मगर जब तक कि शिक्षा मंत्रालय का ढाँचा और उसके कार्यक्रम की प्राथमिकताएँ एकदम नहीं बदल जाती सुधार की कोई आशा नहीं।

सावजनिक प्रशासन का हाल भी बुरा है। ऊपर से जो नई नीतियाँ और साहसिक प्रयोग किए भी जाते हैं वे नौकरशाही के दलदल में फँस कर ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं हो पाते। उदाहरण के लिए, बैंक के राष्ट्रीयकरण के समयको को भी आशंका थी कि इस कारवाई का लक्ष्य पूरा न होगा, क्योंकि बैंक सरकारी विभागों की तरह सुस्ती से काम करने लगेंगे। विदेशी राज्य के समय का प्रशासनिक ढाँचा देश के नवनिर्माण के लिए अनुपयुक्त है। इसके लिए प्रशासन का विकास के लक्ष्यों में विश्वास और सेवा की भावना हानी चाहिए। नौकरशाही का पूरा ढाँचा, मनोवृत्ति, प्रशिक्षण का ढंग बदलना चाहिए।

यहाँ भी सुधार के उपाय सुविद्ध हैं। प्रशासनिक सुधार बर्मीशन और अन्य अनेक जाच कमेटियों ने बुनियादी सुधारों की ओर इंगित कर दिया है। ज़रूरत यही है कि भारत सरकार अपनी पूरी शक्ति से इन में से सबसे ज़रूरी सिफारिशों को कार्यान्वित करे। गृह मंत्रालय ने कई क्षेत्रों में अच्छा काम किया है किन्तु इस अत्यावश्यक विषय पर उसका ध्यान नहीं गया है। मगर कई दृष्टियों से यह ज़रूरत सब जाना में ज्यादा ज़रूरी है।

विदेश नीति

बाहरी दुनिया में देश की प्रतिष्ठा में अन्तर्गत आन्तरिक मामला में तभी नीतिमाया का गुण बरने का उदाहरण या शिक्षा बन प्राप्त होता है। इस दृष्टि में परराष्ट्र मन्त्रालय का महत्त्व है।

हमने देश की नीति के युग में परराष्ट्रनीति में देश की स्वतन्त्रता और प्रतिष्ठा बढ़ाने में और पुर्तुगाल में विदेश-नीति मन्त्रालय गिद्ध हुई थी, यद्यपि हमारा आर्थिक और प्राविधिक आधार कमजोर था और बड़े राष्ट्रों की सहायता से एक सन्तुष्ट उत्पन्न हुआ गया था। मगर देश के बाह्य अन्तराष्ट्रीय स्थिति पर हमारी गलत नीति पड़ गयी है। हमने दम्बता का और अपनी गलत नीति का अपना लिया है। नीति और वास्तविकता से विराध, शांत युद्ध में सभी आने के बाद अमरीका और रूस दोनों सहायक मन्त्रालय में परिवर्तन और अन्तर्गत वस्तुओं के आयात के लिए इन पर निर्भरता, स अन्तराष्ट्रीय मामला में देश की स्वतन्त्रता कम हुई है। नीति द्वारा हमारी आन्तरिक स्थिति सुधरी है। राष्ट्र की समस्या अब इतनी विषम नहीं कि कोई देश हमारे ऊपर दबाव डाले, हमारी रक्षा-अवस्था भी उन्नत मन्त्रालय हुई है, बड़े राष्ट्रों की ओर सहायक गुणवत्ता हमें दूर हुई है हमें वास्तविकता का बोध हुआ है, और आगे ऊपर भरावा करने की प्रवृत्ति पैदा हुई है।

मगर वास्तविकता का बाध होने का यह मतलब नहीं कि हम डर डर कर चले। हम आत्मनिर्भरता और परराष्ट्र सहायता में स्वतन्त्रता का मूल्य चुकाने का तयार होना चाहिए और अपना प्रभावशाली बनाने का यत्न करना चाहिए। भारत जैसा देश सबसे अलग नहीं एक सन्तुष्ट। हम अभी विदेश-नीति का पद प्राप्त न कर पाए हैं, किन्तु हमारी औद्योगिक और सैनिक क्षमता का विकास हुआ है और चारा और जो गतिशीलता की स्थिति है, उसे दगाव हुआ, हम अपने क्षेत्र में अपना प्रभाव डाल सकते हैं।

ऊपर हमने कहा है कि बाहरी दुनिया में प्रतिष्ठा स आन्तरिक मामला में बल प्राप्त होता है, उसी तरह आन्तरिक नीतिमाया स भी बाहरी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसलिए आन्तरिक क्षेत्र में हमें जो काम करने हैं, उनका हमारी विदेश नीति से भी सीधा संबंध है।

विदेशी सहायता

विदेशी सहायता के बारे में भी हम अपना रुख बदलना होगा। अब तक हमारा रुख दूसरे देशों का मुँह जोड़ने का रहा है। वास्तव में जापिक और टेकनीकी दृष्टि से अब हम इतने परमुत्पादक नहीं रहें। हमें देश की प्रौद्योगिक क्षमता के विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए और इसी के बल पर अपना आर्थिक विकास करना चाहिए। इसमें विदेशी व्यापार की आमदनी अवश्य सहायक होगी। इसलिए

हमें विदेशों में अपने माल का बाजार राजना चाहिए । (इससे आंतरिक व्यापार व उद्योग का भी बल मिलेगा ।) अब तक हम विदेशी सहायता की दृष्टि में अपना पायत्रम बनाते रहे हैं, देश की जरूरत का ख्याल रख कर नहीं । हम यह नहीं कहते कि विदेशी सहायता एवदम से बढ़ कर दी जाए पर हमारा यह जरूर कहना है कि हमें नींव मगाने की मनावृत्ति छोड़ देनी चाहिए और देश की जरूरत का अनुमान कर के उसी आधार पर विदेशी सहायता के लिए सोदा करना चाहिए, और इस व्यापक अंतरराष्ट्रीय नीति के सदम में देगना चाहिये ।

विदेशी सहायता लेते समय हमें देश पर पडने वाले उस के दूरगामी प्रभावों का भी मोचना चाहिए । विदेशी सहायता से हाने वाले तात्कालिक लाभ के फेर में हमें देश पर बज का भारी भार न लाद देना चाहिए जिसका चुकाते चुकाते नाक में दम आ जाए । आर्थिक विकास के लिए विदेशी सहायता से भी अधिक महत्व आत्मसम्मान का है । भारत का भविष्य बहुत कुछ उच्च योग और नेता वग के मनायन पर निर्भर है । सभी आर्थिक परनिभरता से यह मनोज्ञ और आत्मसम्मान क्षीण होता है । इसलिए विदेशी सहायता के साथ यदि ऐसा शर्तें लगानी जाएं जो हमारे आत्मसम्मान के विपरीत हों तो हमें उसे अस्वीकार कर देना चाहिए । यही बात रहतिया या पुराने पडे विदेशी हथियारों और मशीनों की खरीद के लिए दबाव पर भी लागू होती है ।

अगला धरण

ऊपर भविष्य की समस्याओं और उन के सदम में नीतियां पर जो विचार किया गया है उससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि विकास के दम में कोई अनिवायता नहीं है । यह बहुत-सी बातों पर निर्भर है, यदि अमुक बात न की गयी तो अमुक परिणाम निकल सकता है । जब समस्याओं का इस रूप में देखा जाता है कि हमें क्या क्या काम करने हैं तो पता चलता है कि इन में कोई काम असम्भव नहीं । इसलिए हमने जो श्रुतियां दिखाई हैं, उससे यह न समझना चाहिए कि हम स्थिति को निराशाजनक समझते हैं । हमारी आलोचना को इस पुस्तक में किए गए व्यापक विवेचन के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिये । हमारे विवेचन में भारतीय व्यवस्था की महान क्षमता की ओर इंगित किया गया है और दिखाया गया है कि किस प्रकार १९४७ में भारतीय समाज ने अपने लगे इतिहास का एक नया अध्याय शुरू किया है और अब तक काफी कर दिखाया है । मगर इस विवेचन में यह भी जाहिर होता है कि अब हम राजनैतिक विकास के एक नए नाजुक दौर में प्रवेश कर रहे हैं, तथा स्थिति पर नए सिरे से विचार करने और नई नीतियां शुरू करने की जरूरत है ।

भारत की राजनैतिक पद्धति बुनियादी तौर पर सही है । भारतीय व्यवस्था की

विशेषता और मजबूती उस की विविधता और विभिन्न वर्गों की विशेषता का कायम रखते हुए उनका राष्ट्रीय धारा में सम्मिलित करने की नीति है। यह उदारता और मनुष्यता की नीति है। मनुष्य को राज्य की मर्जी का पुर्जा बना देने और एक साथ में दालने की पद्धति की नीति का अनुकरण हमारे भारताप जाधुनिक्वर्ताओं को न करना चाहिए उनको अपना रास्ता स्वयं निभालना चाहिए। सरक्षण और नवीनता एक ही त्रिधा के दो पहलू हैं। बिना नवीनता लाए और परिवर्तन किए, परंपरा का संरक्षण संभव नहीं।

विशिष्ट धर्म की भूमिका

भारतीय राजनैतिक व्यवस्था की जड़ें काफी पुरानी चुकी हैं, फिर भी इसका नविष्य इसके राजनैतिक प्रशासित और बौद्धिक नेताओं की रचनात्मक प्रतिभा पर निर्भर है।

इसी विशिष्ट धर्म का यह काम है कि वह स्थिति की समीक्षा करता रहे और नयी स्थितियों के अनुसार नीतियों को बदले और परिवर्तन की गति को तेज करे, तथा देश के विभिन्न वर्गों को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करे। इस काम में नेताओं को परिवर्तन के लिए जातुर और विद्रोह पर उन्मुख बौद्धिक धर्म, शिक्षित बेरोजगारों की बहुसंख्या भूमिहीन और छोटे किसान और मजदूरों के लिए छान और युवजन से सहयोग मिल सकता है। सत्ता बनाए रखने के लिए दल के अंदर जोड़तोड़, विद्वत्ता शक्ति और बौद्धिक से परंपरागत और साधन की याचना और धृष्टता में हार का डर छोड़ कर नेताओं को अधिक आत्मविश्वास के साथ काम करना चाहिए।

हमने देखा है कि समय समय पर उठने वाले संकटों से व्यवस्था को कुछ बदलवाने की प्रेरणा मिली है, किंतु संकटों के अंदर ही बैठे रहने से समाज में निराशा और व्यवस्था पर अविश्वास बढ़ेगा। जैसा स्वतंत्रता के पहले कुछ वर्षों में किया गया था, आने वाली कठिनाइयों का पहले से अनमान सहाय्य कर उपयुक्त नीति बनानी चाहिए और उसपर अमल करना चाहिए। इससे जब संकट उठने हैं तो नीति में व्याधान नहीं आता, और राजनीतिक जुआ खेपने की प्रवृत्ति दबती रहती है।

नेतृत्व की बसोटी

ऊपर जिन समस्याओं का संकेत किया गया है और उनसे निबटने के लिए जिस सक्रिय नीति का और शासन की रीतियों में परिवर्तन का सुझाव दिया गया है, क्या ऐसा करनेकी क्षमता सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेताओं में है? क्या वे नयी नीतियों के लिए संसद और जनता से समर्थन प्राप्त कर सकते हैं? या कांग्रेस में और फूट बढ़ेगी और इससे सरकार में अस्थिरता आएगी? क्या इंदिरा गांधी नहीं

गोरे के बालों के नीचे से निकलने वाले तेल के कारण
मुँह के चारों ओर से निकलने वाले तेल के कारण

उदासीनता के कारण से निकलने वाले तेल के कारण
हमें ऐसा दिखता है कि चेहरे पर तेल के कारण से निकलने वाले तेल के कारण
उम्र बढ़ने के कारण से निकलने वाले तेल के कारण
१९६३ में दूध के कारण से निकलने वाले तेल के कारण
वर्किक रोग के कारण से निकलने वाले तेल के कारण
उन्हीं के नेत्रों के कारण से निकलने वाले तेल के कारण
चलने में आसानी के कारण से निकलने वाले तेल के कारण
का निम्नलिखित कारण से निकलने वाले तेल के कारण

बिना समझ के निकलने वाले तेल के कारण
चुनौती देने के कारण से निकलने वाले तेल के कारण
मालूम देने के कारण से निकलने वाले तेल के कारण
बच्छा मारने के कारण से निकलने वाले तेल के कारण
इसके लिए निकलने वाले तेल के कारण
में बाधने के कारण से निकलने वाले तेल के कारण
है। प्रत्यक्ष के कारण से निकलने वाले तेल के कारण
नेत्रों के कारण से निकलने वाले तेल के कारण
के कारण से निकलने वाले तेल के कारण

इसके कारण से निकलने वाले तेल के कारण
इसके कारण से निकलने वाले तेल के कारण
इसके कारण से निकलने वाले तेल के कारण
इसके कारण से निकलने वाले तेल के कारण
इसके कारण से निकलने वाले तेल के कारण
इसके कारण से निकलने वाले तेल के कारण
इसके कारण से निकलने वाले तेल के कारण
इसके कारण से निकलने वाले तेल के कारण
इसके कारण से निकलने वाले तेल के कारण
इसके कारण से निकलने वाले तेल के कारण

रह है। हर जगह विवेक और परिवर्तन की शक्तियों की टक्कर अविवेक और प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियों से हो रही है। इस विश्व-सदभ में भारत की राजनैतिक चुनौती एक व्यापक महत्त्व प्राप्त कर लेती है। यदि जो व्यवस्था इसने अपनायी है वह इन चुनौतियों का सफलता से सामना करती है तो दूसरे देशों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार यदि यह विफल होती है तो संभव है कि दूसरे स्थानों में भी विवेक और सुधार के समर्थकों की हार हो जाए।

आदर्श व्यवस्था की ओर

भारत में जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है, उसकी प्रेरक शक्ति परिवर्तन का आदर्श है। इस आदर्श के प्रति उत्साह को कैसे जीवित रखा जाए, यही प्रश्न है। भारत के महान नेता जवाहरलाल नेहरू के हृदय में यही आग जलती थी कि किस प्रकार राष्ट्र का नवनिर्माण हो, जिससे वह अपने लक्ष्य को पा सके। उनकी मृत्यु के बाद उनकी मेज पर पायी गयी राइट फ्रास्ट की इन पंक्तियों में उनकी यही भावना प्रतिध्वनित होती है—

बुलाता सघन वन ये सुन्दर मुहाना
मुझे किंतु वादे हैं अपने निभाना
जो सोने से पहले बहुत दूर जाना
औ सोने से पहले बहुत दूर जाना ।^{११}

पश्चिम ने पहले लक्ष्य को पा लिया है और अब इसे इनकी सहायता पर सदेह हो रहा है, किंतु भारत को अभी बहुत दूर चलना है। मजिल कठिन और दूर है, समय कम है और ठाकरें भी लग सकती हैं, मगर इसमें रुकने या सुस्ताने का समय नहीं। नेहरू के शब्दों में, “हमें भारत के भविष्य का निर्माण करना है। भेरे ऊपर, हमारे ऊपर, और इस संसद के ऊपर इतिहास न यह भार डाले। इसी भावना से मैं इस समस्या का सामना करता हूँ।”^{१२}

नेहरू के बाद की पीढ़ी पर भी इतिहास का यह भार है। बुजुर्गों के इस महान स्वप्न का साकार करने के लिए इसको इस रूप में देखना होगा कि क्या काम करना है, किन लोगों को साथ लेना है, और फिर मूल-मूल स इनको कार्यान्वित करना है तथा इस प्रकार देश ने जिस व्यवस्था का अपना भाग्य सौंपा है, उसका सफल बनाना है। अतीत का अनुभव इस कार्य में बहुत सहायक होगा, पर वह भविष्य के लिए पूरी तरह पर्याप्त नहीं कर सकेगा।

^{११} कप्टीट पोपमस अथ राइट फ्रास्ट, 'स्टायिंग नाइ उन्स आन द स्नोइ इवनिंग' कापी राइट १९२३, होन्, रीना^१ एड विंस्टन इन कापीराइट १९५१ राइट फ्रास्ट, होन् रीना^१ एड विंस्टन इन तथा एरिक्स पोल्नर लि की अनुमति से पुनमुद्रित।

^{१२} 'द न्यू श्वाय्या प्रोग्रेस थ्रू डेमोक्रेसी' (दिली-१९५७)।

[illegible]

सारणी पाच ४-१९५२ से १९६६ तक कांग्रेस सरकारा में मंत्रियों में परिवर्तन

राज्य	व्यक्तियों में परिवर्तन (क)		अवधि
	मुख्यमंत्री	मंत्रिपरिषद् के मंत्री	
आंध्र प्रदेश	१	६	१०
उड़ीसा	३	२६	१
उत्तर प्रदेश	४	२०	५
बंगाल (स)	३	१५	३३
गुजरात	४	२६	—७
जम्मू-काश्मीर	५	१८	२६
पंजाब	३	१६	१२
प. बंगाल	२	१८	२४
बिहार	१	१६	३४
मद्रास	२	१५	२१
मध्य प्रदेश	२	१२	—७
महाराष्ट्र	३	१७	२०
भारत	३	२८	३०
राजस्थान	२	३०	८
संघ	१	१८	१८

क-संविधान के तहत चुने गए या मंत्री के चुने जाने पर पुनः उक्त पद पर चुने गए हैं।
 ग-संविधान के तहत चुने गए या मंत्री के चुने जाने पर पुनः उक्त पद पर चुने गए हैं।
 ग-संविधान के तहत चुने गए या मंत्री के चुने जाने पर पुनः उक्त पद पर चुने गए हैं।

(१९५२-५३ से १९६६ तक)

सारणी पाच ५ - पाच राज्यां मध्ये मध्यावधि च्या नाव १९६७ खीर १९६८-६९

२०

राज्य	काग्रिस	वन्धुनिस्ट	सोसनिस्ट	जनसंघ	अयदल	निदल
	६७ -- ६६	६७ -- ६६	६७ -- ६६	६७ -- ६६	६७ -- ६६	६७ -- ६६
हरियाणा स्थान	४८	४८	४८	४८	४८	४८
वोट प्र	४१ ३३	४३ ८८	४४ ० ४६	४४ ३६	४४ ३६	४४ ३६
उत्तर प्रदेश स्थान	१६६	१४	४	४	४	४
वोट प्र	३२ २०	३३ ६८	३४ ५०	३४ ५०	३४ ५०	३४ ५०
विहार स्थान	१२८	११८	११८	११८	११८	११८
वोट प्र	३३ ०६	३० ३०	३१ ३१	३१ ३१	३१ ३१	३१ ३१
पंजाब स्थान	१२७	१२७	१२७	१२७	१२७	१२७
वोट प्र	४१ १३	४१ ३३	४१ ३३	४१ ३३	४१ ३३	४१ ३३
पंजाब स्थान	४७	४७	४७	४७	४७	४७
वोट प्र	३७ ७४	३६ १६	३६ ७६	३६ ७६	३६ ७६	३६ ७६

नोट - हरियाणा में म न तुनाव १९६८ में हुए थे। वन्धुनिस्ट में मार्क्सवादी तथा मोसलिस्ट में स सो तथा प्र सो दोनों शामिल।

वि विराल हरियाणा १६ स्थान १४ ८६ वोट प्र

रव स्वतंत्र १२ स्थान ४ ७३ वोट, रिपब्लिकन पार्टी १० स्थान ४ १४ वोट

भा माओ २ ९९ स्थान २१ २२ वोट

ज क जन प्रगति दल १३ स्थान ३ ३३ वोट

जन जनता पार्टी १४ स्थान ० २८ प्र रा वोट

पा ४ गारवट्ट ब्लॉक १३ स्थान ४ ४३ प्र रा वॉगला कमिश्नर ३४ स्थान १० १६ प्र रा

रिव रिबोल्थनरी सोशलिस्ट पार्टी १२ स्थान

अ अकाली २६ सीट २४ ६८ वोट

अका अकाली ४३ सीट २९ ५९ वोट

आकडे - रिपोर्ट फोर्बे जेन एलेक्जान्डर १९६७ खंड २

(एलेक्जान्डर वमाराशन १९६७ नई दिल्ली)

पी आर बी भारत सरकार मध्यावधि चुनाव विज्ञापित।

२ गा.नं० गांव ६- गाढी पगड १६६७ (प्रतिगत)

शक्ति	जनसंख्या	स्वतंत्र	गामग्रिड	गामग्रिड	असुर	निदल	बोर्ड नहीं	पता नहीं
			दाता	दोनों				गात नहीं
								इनवार

गड गे गलाय गलाय ४३१ ७१ ५१ ४६ ४१ ३० २५ ३४ २६२ ०५

बोट नहीं दिया

गा १७ में शिग ४३१ ७१ ५१ ४६ ४१ ३० २३ ७० ११८ ६६

दा की बोट शिग
(गाम पुलाव)

१६९७ में गा. ४०० ८८ ६८ ८७ ८७ ४४ ६० १६७ -रा-
बोट बोट शिग
(क) (गाम पुलाव)

क-४४ भस्मा रेश दोने की रे।

ग-६६ ८८ भस्मा रेश दोने की रे रा पिर बोट न रेने गा.ने रेश सक्ता नहीं की गई। ४६ गा.पु गामपुलाओ मे बोट नहीं दिया।
पु-१०६ ८८ राली रे रेश शिग भस्मा रेश गरी १९९०।

सारणी पाच ७ — कांग्रेस के विरुद्ध शिकायत से सहमतिया असहमति
(१९६७)

शिकायत	जोर से हाँ	हाँ	नहीं	जोर से नहीं	नहीं जानता
कांग्रेस मूल्यवृद्धि नहीं रोक सकी	६१०	२३४	६८	१७	७१
कांग्रेस खाद्य का वितरण ठीक न कर सकी	५१८	२३७	१३४	३१	८०
कांग्रेस भ्रष्टाचार का उन्मूलन न कर सकी	५१५	२२६	७१	२०	१२८
कांग्रेस अमन कानून कायम न रख सकी	३६६	२८५	१५७	४५	१४४
कांग्रेस ने किसानों की मदद नहीं की	३८३	२१६	२१६	८०	१०२
कांग्रेस देश को दृढ़ नेतृत्व न दे सकी	३५४	२७५	१३७	३७	१६७

नोट — ये प्रारम्भिक आँकड़े हैं (अधिकतर उत्तरदाता मर्द थे)।

धन — से स्ट डेव सोमा दिही 'नेशनल एप्लेवशन स्टडी १९६७

सारणी पाच ८ - पार्टीवार तथा पेशेवार ससद मदस्यो का विवरण ।
चौथी लोकसभा, प्रतिशत मे

	जमीन	राजनैतिक सामा- जिक मजदूर संगठनवाय	बकालत	डाक्टर इजीनियर	शिक्षा पत्रकारी	व्यापार उद्योग	भूतपूर्व राजा	प्रशासन सेवा	अन्य
वाग्रेस	३६८	१७०	२२२	३८	८८	५१	२५	२८	१८
स्वतंत्र	४०५	२४	१२	४८	२४	१६७	७१	७१	७१
जनसघ	२२८	१८४	१३	३३	१२८	१२८	००	६५	६५
कम्यु इ	१०५	७३७	००	००	१५८	००	००	००	००
कम्यु माकम	००	८००	५०	००	१५०	००	००	००	००
ससापा	४२१	४२१	१३	००	१०५	००	००	००	००
प्रसोपा	२३१	१५४	३८५	००	१५४	००	००	७७	००
द्रमुक	३७५	८३	१६७	००	१६७	१६७	००	४२	८३
अन्यदल	१३	२१७	२१७	००	२६१	१७४	००	००	००
निदल	१८३	१२१	१८४	६५	१२१	१६१	१२८	३३	००
योग	३१३	२११	१७३	३२	११२	७८	२८	३०	२२

सूत्र—रत्ना दत्त, द पार्टी रिप्रेजेंटेशन इन फोर्थ लोकसभा इव देंट पोलि वीवरी,
पार, स १—२ जून १९६९।

सारणी पाच ६- पिछले अनुभव के हिसाब से सदस्यों का (४ थी लोकसभा) वर्गीकरण, प्रतिशत में

		नाग्रेस	स्वतन	जनसघ	कम्पु ई	कम्पु माक	ससोपा	प्रसोपा	प्रमुक	अय	निदल	योग
<hr/>												
पिछला अनुभव												
विधायक के रूपमें												
कुछ नही	१५६	६४३	४८४	४७४	४५०	४२१	३०८	३३३	३६१	३५५	२६३	
केवल केन्द्रीय स्तर पर	२६२	६५	६५	२६३	१००	५३	२३१	२५०	२६१	२६०	२३७	
केवल राज्य तथा केन्द्र	२०६	७१	१६४	१५८	४००	३१६	२३१	८३	१३१	२६०	२०१	
गाव जिला / म्युनिस												
राज्य तथा केन्द्र	३८३	१६०	२५८	१०५	५०	२११	२३१	३३३	२१७	१२६	२६६	
मजदूर संगठन												
नही	७६८	८८१	८७१	२६३	३५०	४७४	६१५	७५०	७६८	८७१	७५५	
हाँ	२१२	१२०	१२६	७३७	६५०	५२६	३८५	२५०	२०२	१२६	२४५	
सहकारी संगठन												
नही	७६४	८३३	६०३	६४७	६५०	८४२	१००	८७५	१००	६३६	८४७	
हाँ	२०६	१६७	६७	५३	५०	१५८	०	१२५	०	६५	२५३	

गूत्र — रत्ना दत्त, 'द पार्टी रिप्रेजेंटेशन इन पार्थ लोकसभा' इक पेंड पोति वीकली, चाट, स १-२ जुन १९६९।

सारणी पाच १०—पेशेवार पार्टीवार वोट (प्रतिशत में)

	कांग्रेस स्वतंत्र	जनसम	कम्युनिस्ट	वामपंथी	प्रजापा	द्रमुक	अन्य	निर्दिष्ट वोट नहीं दिया	मतभूल नहीं
पेशेवर	३८१ ००	१३२	२६	१३	७६	२६	२६	१३२	७६
ग्यापारी	४७० १७	७७	०८	१७	११	३६	६०	७७	३४
बुद्धिजीवी	३१२ १४	१२१	२८	२८	२८	३५	७१	७१	१०६
कुशल कामगार	३६६ १३	६८	१८	१३	३६	८३	५७	६१	५३
मामूली कामगार	६२६ २२	६६	३३	३८	११	२७	११	७७	६६
सुद धारत	६६१ ८६	८१	३६	१३	२०	५६	०७	६६	६७
खेत मजदूर	६४३ ६७	४०	३६	२०	१६	५७	०८	६७	५७
बेरोजगार	२६६ ३६	८८	२८	२६	६८	२०	६६	१४७	१४७

गुप्त—ये पार ४६ सेव सोमा दिने, 'नेशनल एन्क्वायर' स्टडी १९७७, पृष्ठ ७१६६।

सारणी आठ १ - भारत की भाषाएँ । १९६१

भाषाएँ	भाषाभाषी संख्या	वाले वाले	जनसंख्या का प्रतिशत
भारतीय आय	१७४	३२,१७,२१,०००	७३.३
भीतरी उपभाषा		२१,२४,८२,०००	
• हिंदी		१३,३४,३४,०००	
• उर्दू		२,३३,३३,०००	
• गुजराती		२,०३,०४,०००	
राजस्थानी		१,४६,३३,०००	
• पंजाबी		१,०६,४१,०००	
पहाड़ी		६१,६२,०००	
अन्य		४६,७४,०००	
बाहरी उपभाषा		१०,६२,३६,०००	
• बंगला		३,३८,८६,०००	
• मराठी		३,३२,८१,०००	
बिहारी		१,६८,०७,०००	
• उडिया		१,५७,१६,०००	
• असमिया		६८,०३,०००	
अन्य		३१,६६,०००	
द्रविड	१५३	१०,७४,११,०००	२४.५
• तेलुगु		३,७६,६८,०००	
• तमिल		३,०५,६३,०००	
• कन्नड		१,७४,१६,०००	
• मलयालम		१,७०,१६,०००	
अन्य		४७,४६,०००	
आस्ट्रो-एशियाई	६५	६१,६२,०००	१.५
तिब्बती-चिनी	२२६	३१,८४,०००	०.७

* सविधान की ८ वीं अनुसूची में उल्लिखित सैकड़ों भाषाओं में से १९६१, पाठ दो सी (२) भाषा सारणी । हजार से कम-ज्यादा सारणी हजार बना ली गई हैं ।

सारणी नं० १ - भारत में नगरीकरण की दर १९०१ से १९६१

संक्र	शहरों में जनसंख्या कुल का प्रतिशत	शहरी प्रतिशत में अंतर	शहरी प्रतिशत में अंतर का प्रतिशत
१९०१	१० ८४	-	-
१९११	१० २६	- ० ५५	- ५ ०७
१९२१	११ १७	+ ० ८८	+ ८ ५५
१९३१	११ ६६	+ ० ८२	+ ७ ३४
१९४१	१३ ८५	+ १ ८६	+ १५ ५२
१९५१	१७ २६	+ ३ ४४	+ २४ ८४
१९६१	१७ ६७ (१६ ०४) व	+ ० ६८ (+ १ ७६) व	+ ३ ६३ (+ १० १८) व

क-परिमाण में परिवर्तन के हिसाब से ठीक किया, यह मान पर कि शहरों की परिभाषा १९६१ में वही थी जो १९५१ में थी।

आर्चीस बोस, 'सिक्म डिकेड्स आफ् जर्नलाइजेशन इन इंडिया १९०१-१९६१' - द इण्डियन
इन् स्टेट सोशल विस्की रिव्यू, वोल १, जन १९६५।

सारणी नौ २ - बड़े नगरों में प्रवास पेशेवार (प्रतिशत)

नगर	कास्तकार	खेतमजदूर खेतिहर, मछुए	पेशेवर, नलकें, दुकान विक्रेता	खनिक, परिवहन, व्यापार, कारीगर	सेवा, खेल, मनोरंजन	अवर्गीकृत कामगार	गैर कामगार
१ बवई	० १०	० ६५	१७ ८५	२७ ०१	८ १०	० ०३	४६ २६
२ फलकता	० ०१	० ३४	२२ ८०	२१ २२	६ ३४	० १७	४६ १२
३ विल्ली	० १७	० ४६	१६ २६	१६ ५८	५ ०१	० ०८	१८ ४४
४ मद्रास	० ०१	० ७५	१६ ०५	१६ ०८	६ १२	० ११	५७ ८६
५ अहमदाबाद	० ०४	० ६३	११ ८०	२६ ८०	४ ३६	० ०१	५६ ३६
६ हैदराबाद	० २६	१ ०८	१८ ११	१५ ८७	६ ६७	० ०३	५७ ६५
७ बंगलौर	० ६१	१ १३	१६ ७३	१६ ६४	५ २०	० २२	५५ ८७
८ बानपुर	० २२	० ६३	१३ २७	२७ ६३	२ ६६	० ७६	५४ ५०

स्रोत: आर्य समाज १९५१, १ गार्ट दो सी (३) मासिक पत्रिका।

सारणी नो ३ - गावों में आबादी की घनता और नगरों को चाला

राज्य	गावा में घनता (१९६१) कामगार । १००० एकड़	शहरों में जानेवाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत
असम	६३५	२०१(२२०४६०)
आंध्र	४६७	६२०(१८४२३२८)
उड़ीसा	४०५	२०६(३३८२२१)
उत्तरप्रदेश	५०६	३२४(२०८१७८५)
केरल	४४०	३२०(४५६६३३)
गुजरात	२४२	८४७(१२६७१६३)
जम्मू-कश्मीर	७०६	२३३(६६२४२)
पंजाब	२४२	५७०(६२४७८३)
प. बंगाल	४६०	८०१(२११३१७६)
बिहार	७३७	२६४(१२४८६६१)
मद्रास	६०२	८०४(१६२६२७६)
मध्य प्रदेश	३३०	४२६(११८१८५२)
महाराष्ट्र	२८१	१२३४(३५०४८१६)
मैसूर	२८६	६६६(१२२०६८२)
राजस्थान	२२६	३४४(५८०८६३)
पूरा भारत	३८६	५४६(१६६७६७६७)

नोट— गावों में घनता का अर्थ है, बोई हुई भूमि से खेतिहरों का अनुपात । प्रतिशत है शहरों को जाने वाला संख्या या गावों की कुल संख्या का अनुपात । ये आकड़े सेंसर फार स्ट डेव सोसा दिल्ली में संकलित ।

सूत्र भारत सरकार— इण्डियन स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिक्स, १ (१९६०—६१) ।

संसम आफ इण्डिया १९६१—यूनिथन प्राइमरी सेंसस एक्स्ट्रेक्ट — इण्डिया पार्ट ० ६ ।

संसम आफ इण्डिया १९६१ एक, पार्ट २ सी (३) माइग्रेशन टेबुलम ।

सारणी नो ४ - शिक्षा के हिसाब से बेरोजगारों का (१५ वर्ष और ऊपर) प्रतिशत

राज्य	अशिक्षित	शिक्षित	प्राइमरी जूनियर	मैट्रिक और ऊपर
असम	५१ ०१	२२ ५१	१८ ६०	७ ८८
आंध्र प्र	६ २७	१३ २१	३३ २८	४४ २४
उड़ीसा	२२ ४३	३६ ११	२६ ६७	१४ ४६
उत्तर प्र	२६ ४८	२२ ७६	२२ १८	२५ ५८
केरल	७ ५४	२७ ३४	२० ६७	४४ ४५
गुजरात	२५ ७५	१६ ७४	४७ २६	१० २५
जम्मू-कश्मीर	२७ ००	२१ ७१	२१ १८	३० ११
दिल्ली	२० ८१	१६ ६१	१८ ८३	४० ४५
पंजाब	१६ ६६	८ २६	३० ६१	४४ १४
प बंगाल	२६ १३	२७ ६१	२६ ६८	१६ २८
बिहार	२६ ४२	२५ ४२	२२ ६२	२५ ५४
मद्रास	११ ५६	२४ १०	३१ ३७	३२ ६४
मध्य प्रदेश	२७ ६२	३२ ६४	२४ ६२	१४ ८२
महाराष्ट्र	२३ ३०	१६ ३६	४० ५७	१६ ७७
मैसूर	१६ ५७	२६ ०७	१६ ६६	३४ ७०
राजस्थान	३५ ६६	३६ ३७	७ ०६	१७ ६१
भारत	२२ २५	२४ ०३	२८ २१	२५ ४७

स्रोत: माफ इण्डिया १९६१, १ पाई २ बी (३) जनरल इकनामिक टेबुल।

सारणी नौ ५ - रोजगार दफ्तरो के चालू रजिस्टर में दर्ज उम्मेदवार पेशे के हिसाब से

	दिसंबर १३, १९६६ को दर्ज सख्या	कुल का प्रतिशत
पेशेवर, शिल्पिक आदि	१५३०५८	५८
प्रशासन, प्रबंध अधिकारी	४३६४	०२
कलक, विक्रेता आदि	६४३१६	३६
खेतिहर, दूधिया आदि	६७०२	०४
खनक	२४८१	०१
परिवहन, संचार	६२११६	२४
कारीगर, मिस्त्री	१६५३२३	७४
रसोइया चौकीदार जमादार	६६५३६	३८
भजदूर (अवर्गीकृत) किसी पेशे के अनुभव से रहित	१०३३७१	३६
क - मैट्रिक से कम तथा अपढ	११७३७६४	४४८
ख - मैट्रिक तथा अडर ग्रेजुएट	६५०८०२	२४८
ग - ग्रेजुएट और ऊपर	७३४६६	२८
योग	२६२२४६०	१०००

सारणी नं० ६ - बड़े नगरों में प्रवासी उम्र के हिसाबसे (प्रतिशत)

नगर	०-१४ वर्ष	१५-३४ वर्ष	३५-५६ वर्ष	६० वर्ष और ऊपर	उम्र नहीं बताई
१-बंबई	१५ ०२	५१ ४१	२६ ४६	४ ०६	० ०२
२-कलकत्ता	१४ २५	४८ ५८	३२ ८१	४ ३५	० ०१
३-दिल्ली	१६ ४०	४८ ५५	२६ ४०	५ ६३	० ०२
४-मद्रास	१५ ६२	४८ ३५	३० १४	५ ८८	० ०१
५-अहमदाबाद	१८ ६४	४६ २३	३० ७२	४ ४०	० ०१
६-हैदराबाद	२१ ०२	४८ ३०	२४ ८०	४ ८८	० ००
७-बंगलौर	१८ २१	४८ २४	२७ ६७	४ ८७	० ०१
८-कानपुर	१५ ५०	४६ ६०	२६ ६६	४ ६३	० ०१

संलग्न १९५१ ई. पार्ट २ से (३) माइग्रेशन टेबुल।

सारणी नो ७ - उम्र के हिसाब से बेरोजगारों का प्रतिशत १९६१

राज्य	१५-३४ वर्ष	३५-५९ वर्ष	६० और ऊपर	उम्र नहीं बताई गई
असम	७५ ६४	१९ ५४	४ ७८	० ०४
आंध्र प्र	८८ २०	१० ८२	० ९७	० ०१
उड़ीसा	८२ ४५	१५ ७२	१ ७४	० ०९
उत्तर प्र	८२ ७९	१४ ९४	२ २३	० ०४
पैरल	८९ ६६	९ ६४	० ६८	० ०२
गुजरात	७७ ४१	१९ ६५	२ ९२	० ०२
जम्मू-कश्मीर	८३ ६७	१५ ०१	१ २५	० ०७
दिल्ली	८५ ५०	१३ ०३	१ ४७	० ००
पंजाब	९० १७	७ ७०	२ १०	० ०३
प बंगाल	७६ ०८	२१ २९	२ ६२	० ०१
बिहार	८६ ४१	१२ ००	१ ५४	० ०५
मद्रास	८६ ६२	१२ १३	१ २४	० ०१
मध्य प्रदेश	८० ६१	१७ ०२	२ ३५	० ०२
महाराष्ट्र	८१ ०९	१६ ४३	२ ४६	० ०२
मैसूर	८७ ६५	११ ५६	० ७१	० ०८
राजस्थान	७१ ८२	२४ ००	४ ०१	० १७
भारत	८२ ३०	१५ ६५	२ ०३	० ०२

स्रोत: ऑफ इंडिया १९६१ १ पार्ट २बी (३) जनरल इकोनॉमिक टेबुलस पृ ५४०-१७६ और ६०१-६२१।

सारणी नौ ८ — माध्यमिक शिक्षा में छात्र-संख्या सामान्य और व्यावसायिक

वर्ष	संग्रहित वय वर्ष का प्रतिशत			कुल छात्र संख्या का प्रतिशत, व्यावसायिक शिक्षा में		
	लड़के	लड़कियाँ	जोड़	लड़के	लड़कियाँ	जोड़
वर्षा ८ — १०						
१९५०-५१	१० ६	१ ८	६ ५	२ २	८ ८	३ १
१९५५-५६	१४ ६	३ ३	६ ३	२ ०	७ ६	३ ०
१९६०-६१	२० ४	५ ४	१३ १	२ २	४ ७	२ ७
१९६५-६६	२८ ७	६ १	१६ १	१ ६	३ ३	२ २
१९७०-७१	३४ २	१२ २	२३ ४	३ ४	५ ०	३ ८
१९७५-७६	४० ८	१६ ६	२६ १	६ ०	७ ६	६ ४
१९८०-८१	४६ १	२२ ६	३६ ३	११ ०	१२ ४	११ ४
१९८५-८६	६० ४	३० ४	४६ ०	२० ०	२० ०	२० ०
वर्षा ११-१२						
१९५०-५१	३ ३	० ५	१ ६	४२ ७	५३ ६	४४ २
१९५५-५६	५ २	० ६	३ १	४१ ६	४६ ४	४२ ७
१९६०-६१	८ ०	१ ६	४ ६	४१ ७	४४ ६	४२ २
१९६५-६६	११ ५	२ ३	० ७	४० ७	३८ ५	४० ३
१९७०-७१	१४ ६	३ ५	६ २	४२ ५	४० २	४२ १
१९७५-७६	१७ ०	४ ८	११ ०	४६ ३	४४ ५	४५ ६
१९८०-८१	२१ ७	७ ४	१४ ८	४८ १	४७ २	४७ ६
१९८५-८६	२८ ८	११ ४	२० ४	५० ०	५० ०	५० ०

स्रोत: आर्य समाज के वकील (मिनिस्त्र आर्य समाज के वकील, फार्म ए १५०-५१ स १९६०-६१ के आधार पर)।

सारणी दस १ - विदेशी सहायतापर सरकारी क्षेत्र की निभरता

याजना अवधि	कुल विनियोग करोड रु में	काम में लगी विदेशी सहायता करोड रु	विदेशी सहायता कुल विनियोग के प्रतिशत में
पहली याजना	११६०	१२६६	१२६
दूसरी योजना	३६५०	१३५२	३७
तीसरी योजना	६३००	२४७६	३९

गवर्मेण्ट आफ इण्डिया इकनामिक्स सर्वे १९६५-६६।

सारणी दस २ - विदेशी सहायता के स्रोत

स्रोत	तीसरी याजना के अत तक स्वीकृत राशी वास्तविक कुल का करोड रु प्र न	तीसरी योजना के अत तक उपयोग वास्तविक कुल का प्र न
स रा अमेरिका	३०२७ १२	५१ ५५
मावियत सघ	४८६ २७	८ ३३
आइ बी आर डी	४६२ ८१	७ ८८
जमन सघीय गणराज्य	४४६ ६६	७ ६६
ब्रिटेन	३६६ ४३	६ २४
आइ डी ए	२७८ ५५	४ ७४
कनाडा	२२२ ४३	३ ७६
जापान	१७४ ०१	२ ६६
अन्य	४०२ ०६	६ ८१
योग	५८७२ ६४	१०० ००

गवर्मेण्ट आफ इण्डिया इकनामिक्स सर्वे १९६६-६७।

सारणी दस ३ - प्राप्त विदेशी सहायता, वापसी के तरीके के अनुसार

वापसी का तरीका	पहली योजना के अंत तक	अवमूल्यन के पहले की दर पर करोड़ रुपए में		योग
		दूसरी योजना के दौरान	तीसरी योजना के दौरान	
क - विदेशी मुद्रा में चुकाए जाने वाले ऋण	१२४.१३ (६१.१४)	६०७.६३ (४२५.१)	१७५२.०६ (६१०७)	३१४६.३८ (२६१४)
ख - रुपये में चुकाए जाने वाले ऋण	२२६ (११४)	११६.८२ (८१७)	१४६.३६ (५४५)	२८३.६६ (५१०)
ग - अन्य सहायता (अ)	१०७ (२१५)	५४६.८१ (३८०६)	८५३.२२ (२६७४)	१७२४.६० (३१००)
घ - अनुदान	७०.१८ (३४.८०)	१६०.६४ (११२३)	१०७.१७ (३७४)	४०६.५२ (७३६)
योग	२०१.६७ (१००.००)	१४३०.२० (१००.००)	२८६८.८४ (१००.००)	५१६४.४६ (१००.००)

अ - पी एल ४८०, पी एल ६६९ और थर्ड वर्ल्ड करेसी ऑसिस्टेंस

नोट - - - - - दोष्ठक की सख्या प्रत्येक योजना की अवधि में तुल्य सहायता का प्रतिशत है। मार्गरेट आफ इंडिया इन्वार्मिक सर्वे, १९६७-६८।

पुस्तक की मुख्य स्थापनाएँ हैं— “ राजनीति की स्वतंत्र
 मत्ता, भारतीय समाज में परिवर्तन लाने में गाउन की
 सक्रिय भूमिका, भारतीय राजनीति की अपनी अनम
 गैनी— जो पश्चिमी ढांचे के बाहिर के समुच्चयीकरण
 और आर्थिक शक्तियों की सावधोमता के मानववादी
 ढांचे, दावा से निम्न है—, इसके गा-दानिक विनोद
 की, जिसमें एक दल की प्रधानता की मुख्य स्थान है,
 देश में आनेवाले सफटा की चुनौती से राजनीति और
 गासन की कायप्रणाली में होनेवाले बड़े परिवर्तन,
 सांस्कृतिक पद्धति और राज्य की मुख्य नीति, की
 संरचना के बारे में आगावादी दृष्टिकोण ।
 पश्चिमी देशों में विकसित आधुनिकतम राजनीतिक
 पारणाशा तथा सिद्धान्तों का परीक्षण भारत के मा-न
 म किया गया है । तथा भारत जस नवीन राष्ट्रों की
 राजनीति का विस्तार करने में से पागाले तथा
 सिद्धांत किम तरह जगम है इसका विवेचन किया
 गया है ।